सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट । 2019-20

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट । 2019-20

विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग द्‌वारा तैयार किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट की डिजिटल कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट: www.mea.gov.in पर देखी जा सकती है। इस वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) देहरादून के सहयोग से एक ऑडियो बुक (हिंदी में) के रूप में भी प्रकाशित किया गया है।

Designed and Produced by
creativEdge
ce@aravalifoundation.in
www.creativedge.in

डॉ. एस. जयशंकर
विदेश मंत्री.

डॉ. एस. जयशंकर, पूर्व में मई 2018 से टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में अध्यक्ष - वैश्विक कॉर्पोरेट मामले।

वे 2015-18 से विदेश सचिव, 2013-15 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत, 2009-2013 तक चीन में राजदूत, 2007-2009 में सिंगापुर के उच्चायुक्त और 2000-2004 तक चेक गणराज्य में राजदूत रहे हैं।

उन्होंने मास्को, कोलंबो, बुडापेस्ट और टोक्यो दूतावासों में अन्य राजनयिक मामलों का निपटान किया है और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय में भी कार्य किया है।

डॉ. एस. जयशंकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में एम.ए. और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एम. फिल और पीएच.डी. की है।

उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उनका विवाह क्योको जयशंकर से हुआ है तथा उनके दो बेटे और एक बेटी है।

श्री वी. मुरलीधरन
विदेश राज्य मंत्री

श्री वी. मुरलीधरन का जन्म 12 दिसंबर 1958 को केरल के कन्नूर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गोपालन वीटिल और माता का नाम श्रीमती देवकी नाम्बल्ली वेल्ली है। उन्हें 30 मई 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्‌वारा केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

श्री वी. मुरलीधरन ने 31 मई 2019 को आधिकारिक तौर पर विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला।

आजीविका की शुरूआत

गवर्नमेंट ब्रेनन कॉलेज, थालासेरी, केरल से अंग्रेजी भाषा और साहित्य में स्नातक करने के बाद श्री मुरलीधरन ने सामाजिक-राजनीतिक मामलों में एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जीवन यात्रा शुरू की, जिसने उनके अनुभव को काफी समृद्‌ध किया। उन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित किया जैसे 1999-2002 तक नेहरू युवा केंद्र (युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत) के उपाध्यक्ष और बाद में 2002-2004 तक नेहरू युवा केंद्र के महानिदेशक।

राजनीतिक आजीविका

अप्रैल 2018 में, श्री मुरलीधरन को महाराष्ट्र से राज्य सभा के लिए चुना गया। जून 2018 में, उन्हें विदेशी मामलों संबधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था। जून 2018 में, उन्हें रेल मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। बाद में दिसंबर 2018 में, उन्हें नियम संबंधी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री मुरलीधरन का विवाह डॉ. के.एस. जयश्री से हुआ है।

विषय सूची

	प्रस्तावना और सारांश	8
1	भारत के पड़ोसी	38
2	दक्षिण-पूर्व एशिया और एशिया-प्रशांत	72
3	पूर्वी एशिया	90
4	यूरेशिया	96
5	खाड़ी और पश्चिम एशिया	110
6	अफ्रीका	124
7	यूरोप और यूरोपीय संघ	150
8	अमेरिका	188
9	बिम्सटेक, सार्क और नालंदा प्रभाग	224
10	भारत - प्रशांत	230
11	संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन	236
12	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	252
13	विकास भागीदारी	260
14	आर्थिक कूटनीति और राज्य	276
15	निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलें	288
16	विधिक और संधि प्रभाग	296
17	नीति आयोजना और अनुसंधान (सीमा प्रकोष्ठ और पुस्तकालय सहित)	306
18	आतंकवाद का मुकाबला	310
19	वैश्विक साइबर मुद्दे, ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी	312
20	कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं	318
21	प्रवासी भारतीय मामलें	334
22	प्रोटोकॉल	342
23	बाह्य प्रचार और लोक राजनयिकता प्रभाग	358
24	प्रशासन, स्थापना और आरटीआई मामलें	366
25	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार	370
26	वित्त और बजट	372
27	संसद और समन्वय प्रभाग	380
28	सम्मेलन प्रभाग	384
29	अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन	388
30	विदेश सेवा संस्थान	390
31	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्	400
32	विश्व मामलों की भारतीय परिषद्	408
33	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	422

प्रस्तावना और सारांश

वर्ष 2019 विदेश मंत्रालय के लिए निरंतरता और परिवर्तन का वर्ष रहा। मई, 2019 में आम चुनाव के बाद एक नई सरकार के गठन द्वारा पारंपरिक साझेदारियों और हालिया अतीत की कूटनीतिक पहलों को एक नया आयाम दिया गया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री और श्री वी. मुरलीधरन को विदेश राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।

फरवरी 2019 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए, जिसमें पुलवामा में 40 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और वर्ष भर भारत के उस हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था को अस्थिर करने और नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले अन्य प्रयासों को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रत्युत्तर दिया गया। पाकिस्तान द्वारा जैश-ए-मोहम्मद जैसे अंतरराष्ट्रीय रूप से निषिद्ध आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के अभाव में पाकिस्तान के अंदर उनके प्रशिक्षित और सशस्त्र करने के अकाट्य प्रमाणों के बावजूद, भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में विशेष रूप से जैश-ए-गैर-मोहम्मद कैंप पर पूर्व अधिकृत सैन्य कार्रवाई कर निशाना बनाया। मंत्रालय ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारतीय संकल्प के इस दृढ़ प्रदर्शन के राजनयिक आयाम और बाद के उपाए किए। यह संदेश कि भारत के पास

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह (30 मई, 2019)

अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ता और निर्णायक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है, किसी भी आक्रमण या सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के बारे में हमारे वार्ताकारों को सूचित किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय कूटनीति ने तेजी से वैश्विक परिवर्तन के समय में राष्ट्रीय हितों की अपनी उद्देश्यपूर्ण खोज जारी रखी। हमारे देश और दुनिया में व्यापक आर्थिक कल्याण, शांति और विदेशों में भारतीय हितों और भारतीयों की सुरक्षा एवं भारतीय प्रभाव व विचारों के उपाए इस अवधि के दौरान भारतीय विदेश नीति के संचालन के लिए मौलिक थे। विभिन्न एजेंडों पर कई साझेदारों के साथ काम करते हुए, इस मंत्रालय ने अपनी पड़ोसी देश प्रथम और एक्ट ईस्ट नीतियों को तैयार किया। संपर्क बढ़ाने और इन क्षेत्रों में सद्भावना और इरादे के ठोस अभिव्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करके प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों और बहुपक्षीय और बहुपक्षीय गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। घरेलू प्राथमिकताओं के लिए विदेश नीति का समायोजन उनके निरंतर संरेखण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवधि के दौरान बाहरी चुनौतियों में भू-राजनीतिक समीकरणों में काफी बदलाव शामिल थे, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों और देशों पर बड़ी शक्ति नीति, संभावित विघटनकारी प्रौद्योगिकियां और वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यवस्था और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों जैसे प्रवासन, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक व विकास व्यवस्था पर प्रतिक्रिया।

30 मई 2019 को नव निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों, किर्गिस्तान और मॉरीशस के नेताओं ने निकट पड़ोस में समान विचारधारा वाले मित्र देशों के साथ जुड़ने के लिए भारत के महत्व के साथ समनुरूप होकर भाग लिया। दूसरी बार पद ग्रहण करने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री अपने प्रथम विदेशी दौरे में 08-09 जून 2019 को दूसरी बार मालदीव गए। इसने हमें स्वास्थ्य, संपर्क, क्षमता निर्माण और समुद्री संचालन में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलकर मालदीव के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया। इसके बाद 09 जून को श्रीलंका का दौरा हुआ। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने 07-08 जून 2019 को अपने पहले विदेशी दौरे में भूटान की यात्रा की, जो

यह परिलक्षित करता है कि भारत एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में भूटान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को महत्व दिया।

मंत्रालय ने नई सरकार के पहले 100 दिनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया और आगे बढ़े। देश के हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक पीएसके या पीओपी एसके खोलने के मंत्रालय के प्रयासों के तहत 12 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (10 के लक्ष्य की तुलना में) खोले गए। अन्य मंत्रालयों और विदेशों में हमारे मिशनों और पोस्टों के साथ समन्वित प्रयास में हम इस अवधि में 15 अफ्रीकी देशों में ई-आरोग्य और ई-विद्याभारती परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम थे। इसने सभी 54 अफ्रीकी देशों को कवर करने के लिए इन नवीन, प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा प्लेटफार्मों में से अधिक को शुरू करने के लिए जमीन तैयार की, जिससे उनके साथ जुड़ने और मानव पूंजी के निर्माण में भारत की विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक नया प्रारूप मिला।

मंत्रालय बिश्केक, किर्गिज़स्तान में एससीओ में राज्यों के प्रमुखों की परिषद् की बैठक (13-14 जून), ओसाका, जापान में जी 20 की बैठक (27-29 जून), जापान-अमेरिका-भारत और रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय बैठक और जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अनौपचारिक ब्रिक्स सम्मेलन (28 जून) में प्रधान मंत्री के शिरकत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं में गति देना जारी रखा। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने 14-15 जून 2019 को दुशांबे में एशिया (सीआईसीए) में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों संबंधी 5वें सम्मेलन; 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक (09-11 जुलाई, यूके) में भाग लिया। विदेश मंत्री ने इस वर्ष मेकांग गंगा सहयोग, आसियान-भारत और पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलनों में मंत्रिस्तरीय बैठकों के संस्करणों में भी भाग लिया।

महाशक्तियों के साथ जुड़ाव ने निरंतरता बनी रही। संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव माइकल पोम्पियो ने जून 2019 में भारत का दौरा किया। रूसी उप प्रधानमंत्री यूरीबोरिसोव ने जुलाई में नई दिल्ली का दौरा किया। पारस्परिक यात्राओं ने भारत की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अत्यधिक सफल यात्रा की, जिसने भारत के अमेरिका के साथ मजबूत संबंध को पुष्ट किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में एक उपस्थित रहे। भारत ने सितंबर 2019 में प्रधान मंत्री की रूस की सफल यात्रा के साथ रूस के साथ अपने सहयोग की सीमा को भी आगे बढ़ाया, जहाँ भारत ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए रूस के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर में चेन्नई में प्रधान मंत्री के साथ दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया, वहीं विदेश मंत्री ने सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान पर द्वितीय भारत-चीन उच्च स्तरीय तंत्र के लिए चीन का दौरा किया। प्रधान मंत्री ने जी-7 शिखर सम्मेलन (जहां भारत को 'बिआरिट्ज साझेदार' के रूप में नामित किया गया था) में भाग लेने के लिए अगस्त 2019 में फ्रांस का दौरा किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण, जलवायु, महासागरों और डिजिटल परिवर्तन पर सत्रों को संबोधित किया।

मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वैश्विक वार्ता में हिंद-प्रशांत अवधारणा की बढ़ती हुई क्षमता को देखते हुए, विदेश मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में हिंद-प्रशांत के लिए एक नए डिवीजन की स्थापना की। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (आसियान), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम), मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) संघ जैसे विभिन्न हिंद-प्रशांत ढांचे के साथ भारत के जुड़ाव में तेजी आई। भारत एक विकास साझेदार के रूप में अय्यावाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (एसीएमईसीएस) में भी शामिल हुआ। मंत्रालय ने इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण

देशों के द्विपक्षीय दौरे का कार्यक्रम भी शुरू किया ताकि उनके साथ हमारा जुड़ाव बढ़ सके। इस क्षेत्र में पड़ोसियों के साथ रक्षा और समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई। विकास की पहल और संयोजकता/बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उच्च महत्व दिया गया। सितंबर 2019 में मालदीव में चौथे हिंद महासागर सम्मेलन में "हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा: पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियां" विषय पर अपने मुख्य भाषण में विदेश मंत्री द्वारा 'सागर' संबंधी प्रधान मंत्री के विजन का उल्लेख किया गया, जो इस क्षेत्र में भारतीय गतिविधि को रेखांकित करती है।

प्रधान मंत्री ने सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में 74 वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लिया। उन्होंने 27 सितंबर को महासभा को संबोधित किया। उनकी टिप्पणी ने भारत के सभ्यतागत योगदान और आतंकवाद से निपटने के लिए उसके वर्तमान प्रयासों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने पर प्रकाश डाला। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र में उपयुक्त रूप से मनाई गई थी। प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दौरान आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन शुरू करने की भी घोषणा की। सीडीआरआई को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है जहां ज्ञान सृजन होता है और बुनियादी ढांचे के आपदा और जलवायु लचीलापन के विभिन्न पहलुओं पर आदान-प्रदान किया जाता है और हितधारकों से तकनीकी विशेषज्ञता को एक साथ लाएगा। ऐसा करने पर, यह बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में देशों को उनकी क्षमताओं और प्रथाओं को उन्नत करने के लिए सहायता करने के लिए एक तंत्र बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सीडीआरआई जैसी संस्थाएँ भारत की घरेलू ताकत और क्षमताओं का दोहन करने और वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों का जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा प्रमुख पहल हैं।

2019 में विदेश मंत्रालय की एक प्रमुख गतिविधि भारतीय राजव्यवस्था में परिवर्तनों के अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक पहलुओं का प्रबंधन था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों में संशोधन और संसद द्वारा कानून पारित करने की मंजूरी पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ाने के लिए बहाने के रूप में किया गया। पाकिस्तान ने द्विपक्षीय संदर्भ में कई शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया जैसे कि राजनयिक संबंधों को कमतर करना। इसने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारतीय हितों और विदेशों में राजनयिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और शत्रुतापूर्ण कार्यों के आयोजन को प्रोत्साहित किया। इसे मंत्रालय और उसके मिशनों और पदों द्वारा निरंतर कूटनीतिक प्रयास से दूर किया गया ताकि संसद और सरकार के फैसलों के आगे के विधानों के औचित्य को समझाने के लिए वार्ताकारों और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके।

मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक और सार्वजनिक-सामना करने वाले कार्यों में अधिक उपयोगी, अनुकूल, जवाबदेह और पारदर्शी बनने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धताओं के प्रति चिंतनशील होकर, विदेश मंत्रालय ने अपना स्वयं का समर्पित कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड लॉन्च किया जो मंत्रालय के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का एक विजुअल डिस्प्ले है। पासपोर्ट और नागरिक-केंद्रित सेवाओं जैसे वीजा/ओसीआई कार्ड और व्यापार व वाणिज्य संबंधी अद्यतन आर्थिक आंकड़े अब सार्वजनिक रूप में इंटरनेट-सक्षम एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध है। मंत्रालय ने लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक समर्पित ई-ऑडिट पोर्टल भी विकसित किया, जो विश्व स्तर पर अपनी वेबसाइट के माध्यम से सुलभ होगा। लेखा परीक्षा जवाबदेही लाती है और इससे प्रशासनिक निगरानी और विवेकपूर्ण नियंत्रण को मजबूत करने की आशा की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय पटल महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती को उचित रूप से मनाने के लिए 2019 में मंत्रालय की गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें प्रधान

मंत्री, कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकार और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भाग लिया। इस मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग ने दुनिया भर की प्रमुख हस्तियों के योगदान के साथ 'व्हाट गांधी मीन्स टू मी' पर एक एंथोलॉजी प्रकाशित की। एक भारतीय सांस्कृतिक संबंध कार्यक्रम परिषद् ने 40 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं स्थापना की अगुवाई की। विश्व मामलों के भारतीय परिषद् मंत्रालय के साथ मिलकर फरवरी 2020 में 'गांधी और विश्व' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। दुनिया भर में स्थित भारतीय मिशनों और पोस्टों ने अपने यहां इसे उपयुक्त रूप से मनाया। वर्ष 2019 ने गुरु नानक देवजी की 550 वीं वर्षगांठ को भी मनाया। इस मंत्रालय और इसके मिशनों और पोस्टों ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन और शिक्षाओं को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। वृक्षारोपण, "गुरबीन कीर्तन/अरदास, रक्तदान और चिकित्सा शिविर, सिख मार्शल आर्ट/होलामोहल्ला के प्रदर्शन, श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर एक अकादमिक पीठ की स्थापना जैसे विशेष कार्यक्रम विश्व स्तर पर कई स्थानों पर किए गए। नानक की शिक्षाओं को कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करने में यूनेस्को की भागीदारी इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय निर्णय है जो अधिक से अधिक पहुंच और प्रभाव को उत्प्रेरित करेगा।

पूर्व विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज, जिनका अगस्त में नई दिल्ली में अचानक निधन हो गया था, ने 01 मार्च, 2019 को अबू धाबी में इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद् के 46 वें सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। श्रीमती सुषमा स्वराज ने मई 2014 से मई 2019 तक इस मंत्रालय का नेतृत्व किया और भारत और विदेश में इस मंत्रालय की गतिविधियों में नए आयाम जोड़े।

निम्नलिखित पृष्ठ वर्ष के दौरान भारत के विदेशी संबंधों के प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।

भारत के पड़ोसी

अफ़गानिस्तान

भारत-अफगानिस्तान की रणनीतिक साझेदारी सर्वांगीण विकास का गवाह बनी रही और पिछले एक वर्ष में इसे और मजबूत किया गया। राजनीतिक, रक्षा संबंध, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, विकास साझेदारी, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों, शिक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों सहित उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संपरकों में यह परिलक्षित हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत को अपना निर्यात शुरू किया, जिसका संचालन दिसंबर 2018 में एक भारतीय कंपनी ने संभाला है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से काम किया और अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लिया। भारत ने राष्ट्रीय शांति और सामंजस्य के ऐसे प्रयासों के लिए अपना समर्थन दिया, जो अफगान नेतृत्व, अफगान स्वामित्व और अफगान द्वारा नियंत्रित थे; इनमें प्रारंभिक शांति, सुरक्षा, स्थिरता स्थापित करना; स्वतंत्रता, संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करना और समावेशी अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक, युवाओं और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

पाकिस्तान

भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध रखने की इच्छा रखता है। भारत का सुसंगत दृष्टिकोण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह के मुद्दों को आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। ऐसा अनुकूल माहौल बनाने का दायित्व पाकिस्तान का है।

यह स्पष्ट किया गया है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा और हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को कम आंकने के सभी प्रयासों से निपटने के लिए दृढ़ और निर्णायक कदम उठाएगा।

पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) द्वारा पुलवामा में किए गए नृशंस आत्मघाती आतंकी हमले (14 फरवरी) के बाद, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जेईएम प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ आतंकवाद-रोधी हवाई हमले (26 फरवरी) को सफल बनाया। भारतीय बलों ने भी 2019 में सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ का समर्थन करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी बलों द्वारा 3000 से अधिक अकारण युद्धविराम उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया है।

आलोच्य वर्ष में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने सक्रिय आउटरीच के परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र में बार-बार इस क्षेत्र की चिंताजनक स्थिति को प्रस्तुत करने, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और द्विपक्षीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के पाकिस्तान के के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

भारतीय तीर्थयात्रियों की काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए कैबिनेट द्वारा 22 नवंबर 2018 को लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 नवंबर 2019 को, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था।

निर्दोष भारतीय नागरिक श्री कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने अपने फैसले में (17 जुलाई 2019) सर्वसम्मति से भारत के इस दावे को बरकरार रखा कि पाकिस्तान द्वारा कई मामलों में, राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1963 का उल्लंघन किया गया है और उन्हें तकाल राजनयिक पहुँच देने तथा पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा एक हास्यास्पद मुकदमा चलाकर उन्हें दी गई सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का आदेश दिया। इसके अलावा, 'हैदराबाद फंड' के 70 वर्ष पुराने मामले में ब्रिटेन उच्च न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला (02 अक्तूबर 2019) फैसला सुनाया।

बांग्लादेश और म्यांमार

भारत सरकार के अधिकांश मंत्रालयों द्वारा इन संबंधों को विशेष आधार पर प्राथमिकता देने के कारण बांग्लादेश और म्यांमार भारत के 'एक्ट ईस्ट' और 'पड़ोस पहले' नीतियों के क्रियान्वयन में केंद्रीय तव बने रहे, इसके क्रियान्वयन में रक्षा मंत्रालय और हमारी रक्षा सेवाओं के साथ-साथ हमारे बुनियादी ढांचे के मंत्रालय शामिल हैं।

वर्ष 2019 में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत के संबंधों में प्रगति जारी है। दोनों मामलों में, आलोच्य वर्ष में उच्चतम राजनीतिक स्तरों पर संपर्क जारी रहा, 2019 में मंत्रिस्तरीय और अन्य यात्राओं का भी आदान-प्रदान किया गया। बांग्लादेश और म्यांमार में भारत की विकास साझेदारी परियोजनाओं ने लगातार प्रगति दर्ज की, ये दोनों देश भारत के अनुदान और रियायती ऋण के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। दोनों देशों के साथ हवाई सेवाओं के विस्तार और यात्रा परमिटों के सरलीकरण के साथ-साथ नई यात्रा अवसंरचना के निर्माण से व्यापार और आर्थिक संबंध भी विकसित हुए।

वर्ष की शुरुआत में बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार के और वर्ष के मध्य में भारत में एनडीए के सरकार फिर से चुने जाने से बांग्लादेश के साथ संबंधों में निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद की। म्यांमार के साथ, एनएलडी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध जारी रहे और अन्य प्रमुख संस्थाओं ने सुनिश्चित किया कि द्विपक्षीय संबंध एक सकारात्मक दृष्टि और कार्यकाल बनाए रखें।

भूटान

भारत और भूटान में आपसी विश्वास, साझा इतिहास और सभ्यतागत संबंधों के आधार पर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त संबंध हैं। आलोच्य वर्ष में भारत और भूटान के पारंपरिक रूप से घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को समेकित किया गया, जिसमें जल विद्युत, संचार, सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति कृषि और अंतरिक्ष और डिजिटल और वित्तीय कनेक्टिविटी जैसे कई नए क्षेत्रों सहित सहकारिता के सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति देखी गई।

नवनिर्वाचित भारत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 30 और 31 मई, 2019 को भूटान के प्रधानमंत्री ल्योनचेन डॉ. लोटे त्शेरिंग की यात्रा के साथ दोनों देशों में नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं और संवाद की परंपरा जारी रही। श्री नरेंद्र मोदी ने 17 और 18 अगस्त 2019 को भूटान की एक राजकीय यात्रा की। इस यात्रा में अंतरिक्ष और युवा आदान-प्रदान के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा और विविधता पूर्ण बनाया गया। यात्रा के दौरान, 720 मेगावाट के मंगदेछु जल विद्युत परियोजना के साथ-साथ दक्षिण एशिया उपग्रह के उपयोग के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया। दोनों पक्ष भूटान के लिए संयुक्त रुप से एक छोटे उपग्रह का विकास करने पर भी सहमत हुए हैं।

भूटान के साथ भारत की व्यापक विकास साझेदारी है, जो भूटान की प्राथमिकताओं पर आधारित है। वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना (2018-23) के लिए, भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपये की संक्रमणकालीन व्यापार सहायता सुविधा के अलावा 4500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की है। दोनों पक्षों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कों और पुलों, क्षेत्रीय अस्पतालों, स्कूलों, सांस्कृतिक विरासत भवनों के निर्माण और आईसीटी, क्षमता निर्माण, उद्योग, कृषि, ई-गवर्नेंस, सिंचाई चैनलों, खेत सड़कों, ब्लॉक कनेक्टिविटी सड़कों, बुनियादी स्वास्थ्य इकाइयों, सामुदायिक विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में 400 से अधिक बड़ी और छोटी परियोजनाएं की गई है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दोनों पक्ष समय पर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं की कड़ी निगरानी करते हैं। समयबद्ध सहायता भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने वाली कई विकासात्मक परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहायक रही है।

द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्र पनबिजली में, 720 मेगावाट की मंगदेछु जलविद्युत परियोजना के उद्घाटन के साथ, संयुक्त रूप से विकसित पनबिजली क्षमता 2000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। दोनों सरकारों ने चल रही दो बड़ी परियोजनाओं - 1200 मेगावाट की पुनात्संगचू-I और 1020 मेगावाट की पुणतांगचू-II के कार्यान्वयन में निकट समन्वय बनाए रखा। मेगावाट संकोश जलाशय जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए द्विपक्षीय विचार-विमर्श के दो दौर आयोजित किये गये थे।

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध हैं। वर्ष 2019 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क और अधिक गहरा हुआ है। 'पड़ोसी पहले' की नीति को ध्यान में रखते हुए, उच्च-स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान तेज हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के पी शर्मा ओली 30 मई 2019 को भारत की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर अपने नेपाली समकक्ष के साथ संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए 21 और 22 अगस्त, 2019 को नेपाल की यात्रा पर गये थे। **इस वर्ष मंत्री, आधिकारिक और तकनीकी स्तरों पर 30 से अधिक यात्राओं के साथ गहन भागीदारी देखी गई।**

सरकार ने द्विपक्षीय कनेक्टिविटी, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की चल रही विकास परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन पर विशेष जोर

दिया है। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने 10 सितंबर 2019 को मोतिहारी (भारत) - अमलेखगंज (नेपाल) सीमा पार पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। भारत में रक्सौल को नेपाल के काठमांडू से जोड़ने वाली नई ब्रॉड गेज विद्युतीकृत रेल लाइन की प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मई 2019 में पूरी हो गई थी और रेल लाइन के अंतिम स्थान के सर्वेक्षण का काम चल रहा है। गोरी अनुदान सहायता के साथ बिराटनगर में बनाया जा रहा एकीकृत चेक पोस्ट पूरा होने वाला है। आवास निर्माण के क्षेत्र में भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार की सहायता से, गोरखा और नुवाकोट जिलों में लगभग 40,000 घरों (यानी 80% काम) का निर्माण पूरा हो चुका है। भारत सरकार द्वारा नेपाल को दिए जानेवाले 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर के चार रियायती ऋणों से, नेपाल में भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत हर वर्ष नेपाली उम्मीदवारों को लगभग 3000 छात्रवृत्ति (250 आईटीईसी स्लॉट सहित) प्रदान कर, नेपाल और भारत के प्रमुख संस्थानों में अध्ययन के अवसर प्रदान करता है।

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है, इसके अलावा नेपाल को तीसरे देशों से लगभग पूरे व्यापार के लिए पारगमन प्रदान करता है। कुल द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2017-18 के 7.05 अरब अमेरिकी डॉलर से 17% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.27 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। दोनों सरकारें व्यापार और आपसी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

दोनों पक्षों ने सहयोग के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूरंदेशी प्रक्षेपवक्र रखा है।

चीन

वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच 11-12 अक्तूबर 2019 को, चेन्नई में आयोजित किए गए दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के साथ भारत और चीन के बीच करीबी विकास भागीदारी के समग्र ढांचे के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंध मजबूत और गहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के अलावा, एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन, जी-20 शिखर सम्मेलन और ग्यारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर तीन और बैठकें कीं। 2019 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान पर उच्च स्तरीय तंत्र के लिए विदेश मंत्री श्री जयशंकर की बीजिंग यात्रा और सीमा के प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 22वीं बैठक के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा शामिल है। कुल मिलाकर, इस वर्ष भारत-चीन के द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर सकारात्मक गति देखी गई। 2020 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिह्नित करेगा और दोनों पक्ष भारत और चीन में 70 गतिविधियों का आयोजन कर इसे मनाने पर सहमत हुए हैं।

भारतीय महासागर क्षेत्र

प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) द्वारा निर्देशित होकर आईओआर देशों (श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स) के साथ भारत के संबंध सभी क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं, इन क्षेत्रों में वाणिज्य और व्यापार, सुरक्षा और रक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा शामिल हैं। भारत और आईओआर देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान द्वारा चिह्नित, इस वर्ष में काफी

संबद्धताएं और परिणाम देखे गये। इस अवधि के दौरान आईओआर डिवीजन के देशों के साथ भारत की विकास साझेदारी इस क्षेत्र के साथ उसके जुड़ाव का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

श्री लंका

वर्ष 2019-20 में श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों में और तेजी आई है। दोनों पक्षों की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक स्तर की लगातार यात्राओं ने भारत और श्रीलंका के बीच वाणिज्य, व्यापार, रक्षा, विकासात्मक सहयोग और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और समझ को बढ़ाया है। इसके अलावा, आपातकालीन एम्बुलेंस परियोजना और चेन्नई और जाफना के बीच उड़ानें शुरू करने जैसी लोक उन्मुख और मांग संचालित परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन ने दोनों देशों को और करीब ला दिया है। इस अवधि में, भारत ने अपनी पड़ोस पहले नीति और सागर के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए श्रीलंका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा।

मालदीव

इस अवधि के दौरान भारत-मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों का विभिन्न नए क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ। दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति सोलिह की भारत यात्रा ने इसका एजेंडा निर्धारित किया था, जिसे जून 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा से दिशा और महत्वाकांक्षा मिली। इस अवधि में विभिन्न एलओसी परियोजनाओं, अनुदान परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सुशासन, उड़ान सुरक्षा, अग्नि शमन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, विशेष सुरक्षा समूह, इत्यादि हितग्राही गैर-शासी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की नई पहलों की श्रृंखला देखी गई।

मॉरीशस

भारत मॉरीशस को एक करीबी समुद्री पड़ोसी मानता है। भारत और मॉरीशस के बीच के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पैतृक संबंध दशकों से निकटता की इस साझा भावना को पुष्ट करते हैं। मजबूत विकास सहयोग, रक्षा, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों, उच्च-स्तरीय यात्राओं, छात्रवृत्ति के माध्यम से क्षमता निर्माण और आईटीईसी उद्योग आदि के द्वारा इस संबंध को आगे बढ़ाया गया है। इस वर्ष कई उच्च स्तरीय यात्राओं, ई-टैबलेट परियोजना, ईएनटी अस्पताल, मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण, गहन रक्षा और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसी विकास सहयोग परियोजनाओं को पूरा किया गया।

सेशेल्स

घनिष्ठ मित्रता, समझ और सहयोग भारत-सेशेल्स के संबंधों की विशेषता रही है। यह विकास साझेदारी; सांस्कृतिक सहयोग; छात्रवृत्ति और आईटीईसी कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण सहित आतंकवाद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग से स्पष्ट है। भारत ने सेशेल्स की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में उसकी मदद कर सेशेल्स में अपनी विकास सहायता के दायरे और प्रसार का विस्तार किया है। भारत ने इस वर्ष सेशेल्स की सरकार और लोगों के साथ अपनी घनिष्ठ भागीदारी जारी रखी, जिसने हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया।

भारत-प्रशांत और आसियान

वैश्विक प्रवचन में भारत-प्रशांत अवधारणा की बढ़ती हुई क्षमता को देखते हुए, विदेश मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में भारत-प्रशांत के लिए एक नया प्रभाग स्थापित किया। ऐसा करने का दोहरा उद्देश्य था: जून 2018 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित तत्वों के अनुरूप, भारत सरकार के भारत-प्रशांत के दृष्टिकोण को मजबूत करने में मदद करना और उस दृष्टिकोण के लिए ठोस नीति तत्व और कार्यक्रम प्रदान करना।

भारत-प्रशांत के लिए भारत का दृष्टिकोण एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित भारत-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। भारत इस क्षेत्र में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, सभी देशों की समानता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, बल के उपयोग या धमकी से बचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों सम्मान और उनके पालन पर जोर देता है। भारत का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्थित और इसमें हित रखने वाले सभी देशों के साथ एक बहुआयामी जुड़ाव रखना है, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र शामिल हैं, जिसका उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास **(सागर)** है।

वर्ष 2019 में भारत-प्रशांत की विभिन्न संरचनाओं के साथ भारत के जुड़ाव की गहनता देखी गई, जिनमें अन्य, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम), मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) आदि शामिल हैं; जुलाई 2019 में हम एक विकास भागीदार के रूप में अय्यावाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (एसीएमईसीएस) में शामिल होने के लिए भी सहमत हुए हैं।

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2014 में म्यांमार में घोषित, एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी) द्वारा शासित है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) इसका प्राथमिक घटक था। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और रणनीतिक संबंध विकसित करना एईपी के प्रमुख तत्व हैं। इस दिशा में, 2019 में, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया के राष्ट्रपतियों से भेंट की। हमारे राष्ट्रपति ने नवंबर 2019 में फिलीपींस की राजकीय यात्रा की थी और उपराष्ट्रपति मई 2019 में वियतनाम गए थे। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) श्री वी. मुरलीधरन ने कंबोडिया और लाओस को छोड़कर सभी आसियान विदेश मंत्रियों से भेंट की थी। इस वर्ष ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ विदेशी कार्यालय परामर्श (एफओसी) और संयुक्त आयोग की बैठकों (जेसीएम) जैसी संरचित तंत्र बैठकें आयोजित की गईं। प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) के साथ भारत के संबंधों को ऐतिहासिक भारत-प्रशांत द्वीप विकासशील राज्यों (पीएसआईडीएस) के नेताओं की बैठक से एक मजबूती मिली, यह बैठक 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाशिये पर आयोजित की गई थी। 2019 को एक ऐसे वर्ष के रूप में चिह्नित किया गया जब भारत-प्रशांत अवधारणा की प्रतिक्रिया के रूप में आसियान ने 23 जून 2019 को भारत-प्रशांत के लिए अपना आउटलुक तैयार किया। वर्ष के अंत में, 2-4 नवंबर, 2019 को बैंकाक में 35वां आसियान/14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस)/16वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री ने आसियान नेताओं के साथ बातचीत की और ईएएस के समय भारत प्रशांत महासागरीय पहल (आईपीओआई) की घोषणा की।

पूर्वी एशिया

कोरियाई लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया)

भारत और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के बीच राजनयिक सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। डीपीआरके ने विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

जापान

भारत-जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों में बढ़ते अभिसरण द्वारा पूरे वर्ष कई उच्च-स्तरीय संपर्क के साथ जारी रखा गया। अक्तूबर, 2019 में जापान के सम्राट के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की जापान की यात्रा ने दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों को प्रतिबिंबित किया। 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री आबे शिंजो के बीच हुई त्रि शिखर-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें साझेदारी को दिशा और प्रेरणा प्रदान करती हैं। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का वार्षिक शिखर सम्मेलन और 2+2 मंत्रिस्तरीय तंत्र है। नवंबर 2019 में भारत-जापान की 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय उद्घाटन बैठक हुई थी। 2019 में जापान की जी-20 की प्रेसिडेंसी ने पूरे वर्ष जी-20 आयोजनों के अवसर पर जापान के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय जुड़ाव रखने के लिए कई अवसर प्रस्तुत किए।

कोरिया गणराज्य

भारत और कोरिया गणराज्य के द्विपक्षीय संबंधों को, 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कोरिया यात्रा में "विशेष रणनीतिक साझेदारी" के स्तर पर उन्नत किया गया, एक वर्ष की अवधि के भीतर दोनों पक्षों से तीन अति महत्वपूर्ण यात्राओं से इसे और बढ़ावा मिला। राष्ट्रपति मून जे-इन (एमजेआई) और प्रथम महिला किम जंग-सूक ने क्रमशः जुलाई और नवंबर 2018 में भारत की राजकीय यात्राएं कीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए फरवरी 2019 में सियोल की राजकीय यात्रा की। 2019 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में सितंबर 2019 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की सियोल यात्रा शामिल थी।

मंगोलिया

ऐतिहासिक रूप से, भारत और मंगोलिया में एक मैत्री और सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। हालाँकि, 2015 में हमारे प्रधानमंत्री की मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा से मंगोलिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव लाया। पारंपरिक मित्रता को बढ़ावा मिला और मंगोलिया के साथ हमारा रिश्ता "सामरिक भागीदारी" में बदल गया। अधिकांश मंगोलियाई भारत को अपना "तीसरा" और "आध्यात्मिक पड़ोसी" मानते हैं और हमारे साथ विशेष संबंध के बारे में गहराई से जानते हैं। दोनों पक्षों से नियमित उच्च-स्तरीय यात्राओं के माध्यम से हमारे संबंधों में प्रगति और गति बनी हुई है। राष्ट्रपति कल्तमैगिन बतूल्गा ने 19-23 सितंबर, 2019 को भारत की राजकीय यात्रा की। लगभग एक दशक में मंगोलियाई पक्ष की ओर से यह पहली राष्ट्रपति यात्रा थी। 2019 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में मंगोलियाई पक्ष से मंगोलिया के विदेश मंत्री श्री डी. तोगतबातर और मंगोलिया के खनन और भारी उद्योग मंत्री की यात्रा शामिल थी। भारत की ओर से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री अक्तूबर 2019 में भारत की सबसे बड़ी ऋण (एलओसी) परियोजना-'ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट (ओआरपी)' से संबंधित बुनियादी ढांचे के कार्यों का उद्घाटन करने के लिए मंगोलिया गए थे। कुल मिलाकर इस वर्ष भारत-मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर सकारात्मक गति देखी गई।

यूरेशिया

भारत और यूरेशियाई क्षेत्र के देशों के बीच के संबंधों में इस वर्ष सकारात्मक वृद्धि जारी रही। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के अलावा, भारत-यूरेशियाई आर्थिक संघ वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और एक संभावित व्यापारिक व्यवस्था भारत-मध्य एशिया वार्ता से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से यूरेशियाई क्षेत्र के कई देशों के साथ संबंधों

को बहुआयामी महत्व प्राप्त हुआ।

किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सोरोनबाई जेनेबकोव को 30 मई 2019 को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में, एससीओ अध्यक्ष के रूप में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री 13-14 जून 2019 को बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिज़ गणराज्य के द्विपक्षीय दौरे पर बिश्केक गए। यात्रा में किर्गिज़ गणराज्य के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया था। रक्षा मंत्री के 1-3 नवंबर 2019 को एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक और द्विपक्षीय यात्रा के लिए उजबेकिस्तान के दौरे से उज्बेकिस्तान में भारतीय और उज़्बेक सशस्त्र बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। 19-23 अक्तूबर 2019 को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी के उज्बेकिस्तान के दौरे से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए, उज्बेकिस्तान के अंडीजोन क्षेत्र और गुजरात के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापन किए गए। उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री श्री अब्दुलअजीज कामिलोव ने 14-15 जनवरी 2020 को नई दिल्ली का दौरा किया, उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की, विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की और रायसीना वार्ता 2020 को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन ने 11-12 नवंबर, 2019 को अस्ताना क्लब की बैठक को संबोधित करने के लिए कजाकिस्तान का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने कजाक संसद के अध्यक्ष श्री निगमतुल्ली और विदेश मंत्री श्री मुख्तार टाइलूबेरडी से भी भेंट की।

जनवरी 2019 में समरकंद में आयोजित प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता के अवसर पर भारत द्वारा घोषित पहलों के अंतर्गत, 22-29 अप्रैल 2019 के बीच मध्य एशियाई पत्रकारों के लिए भारत का एक परिचय दौरा आयोजित किया गया था, जून-जुलाई 2019 में मध्य एशियाई देशों के राजनयिकों के लिए विदेश सेवा संस्थान द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था भारत और आईसीसीआर द्वारा 2-4 दिसंबर 2019 से एक केंद्रीय एशिया पर विशेष ध्यान के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य और संगीत समारोह के छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इन पहलों में सभी मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

यूरेशियाई देशों में स्थित भारतीय मिशनों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए चित्र प्रदर्शनी, साइकल चलाने के कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान और शाकाहारी भोजन उत्सव आयोजित किए गए। मिशनों ने गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती भी बड़ी धूम-धाम से मनाई।

रूस

प्रधानमंत्री ने 4-5 सितंबर, 2019 को 20वें भारत-रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए व्लादिवोस्तोक का दौरा किया और रूसी संघ के राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पाँचवें पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इससे पहले 12 अप्रैल 2019 को, रूस ने प्रधानमंत्री को रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, एपोस्टल देने की घोषणा की।

विदेश मंत्री (27-28 अगस्त 2019), श्री अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (21 अगस्त 2019) और श्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (29-30 अगस्त 2019) का रूस दौरा, प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तोक की द्विपक्षीय यात्रा में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों को संपन्न किया गया। रूस के सुदूर पूर्व में व्यापार के अवसरों की खोज के लिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल और गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्रियों के साथ 150 सदस्यों का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल 11-13 अगस्त 2019 तक व्लादिवोस्तोक गया और रूस के उप-प्रधानमंत्री यूरी ट्रुटनेव और रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के 11 राज्यपालों से भेंट की। व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया। रक्षा मंत्री, रक्षा और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह-

अध्यक्षता के लिए 26-29 नवंबर, 2019 को रूस का दौरा किया था।

रूस के उप-प्रधानमंत्री श्री यूरी बोरिसोव ने 22 जुलाई 2019 को भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग- तकनीकी और आर्थिक सहयोग की अंतर-सत्रीय बैठक के संचालन के लिए भारत का दौरा किया - और विदेश मंत्री के साथ उसकी सह-अध्यक्षता की। रूसी संघ के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव ने 15 जनवरी 2020 को नई दिल्ली का द्विपक्षीय दौरा किया, उन्होंने विदेश मंत्री से भेंट की और प्रधानमंत्री से भेंट की। विदेश मंत्री लावरोव ने रायसीना वार्ता 2020 में एक मुख्य भाषण दिया।

शंघाई सहयोग संगठन

अप्रैल-नवंबर 2019 की अवधि में, भारत के दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ-साथ एससीओ सदस्यों के साथ अपने जीवंत आधुनिक संबंधों के आधार पर भारत-एससीओ सहयोग की गति बढ़ती रही। भारत ने सक्रिय रूप से किर्गिस्तान के एससीओ की अध्यक्षता की और साथ ही एससीओ के सरकार प्रमुखों की परिषद् के प्रारूप में उज़्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न एससीओ संवाद तंत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 22 मई 2019 को बिश्केक (किर्गिस्तान) में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद् की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2019 को बिश्केक (किर्गिज़स्तान) में किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति श्री ई. सोरोंनबे जेनेबकोव की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ प्रमुखों की परिषद् की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेताओं ने बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए और डिजिटलीकरण और सूचना-संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संकल्पना और सहयोग के नियमों सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2 नवंबर 2019 को टेंकेंट (उज़्बेकिस्तान) में उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री अब्दुल्ला अरिपोव की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 8 नवंबर 2019 को आपातकाल की रोकथाम और समापन से निपटने के लिए एससीओ मंत्रियों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की।

खाड़ी और पश्चिम एशिया

खाड़ी क्षेत्र

हमारे विस्तारित पड़ोस में प्रमुख महत्व के क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के घनिष्ठ और मजबूत संबंध हैं। खाड़ी देशों में से प्रत्येक के साथ हमारे द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंध साझा इतिहास की गहराई में निहित हैं और बढ़ते बहुआयामी सहयोग और लोगों से लोगों के जीवंत जुड़ाव के माध्यम से इसका लगातार पोषण किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी क्षेत्र के साथ राजनीतिक और आर्थिक जुड़ाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। निरंतर प्रयासों और केंद्रित जुड़ाव के साथ, पारंपरिक खरीदार-विक्रेता संबंध (मूल रूप से ऊर्जा की आपूर्ति पर केंद्रित) को एक रणनीतिक जुड़ाव में बदल दिया गया है। खाड़ी क्षेत्र 2018-19 में 150 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह तेल और गैस की हमारी 50 प्रतिशत से अधिक जरूरतों का स्रोत है। इस क्षेत्र में 90 लाख से अधिक का भारतीय प्रवासी समुदाय विद्यमान है और 2018 में इस समुदाय ने 48 अरब अमेरीकी डॉलर से अधिक के वार्षिक प्रेषण (भारत के कुल प्रेषण 78.6 अरब डॉलर में से) का योगदान दिया।

वर्ष 2019-20 में, इस क्षेत्र के देशों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक जुड़ाव बढ़ता रहा है। फरवरी 2019 में सऊदी के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा ने

द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया और भारत के बुनियादी ढाँचे में सऊदी निवेश की वृद्धि के लिए सहयोग और संभावनाओं के रास्ते खोले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में बहरीन (किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस राष्ट्र की पहली यात्रा) और यूएई का दौरा किया, जहां उन्हें उन देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने सऊदी के शाह सलमान के निमंत्रण पर 28-29 अक्तूबर, 2019 को रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र में 'सम्मानित अतिथि' के रूप में भाग लिया। दोनों नेताओं ने, दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी परिषद् की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ईरान

वर्ष 2019 में सभी स्तरों पर द्विपक्षीय राजनीतिक और वाणिज्यिक आदान-प्रदान में गति देखी जा रही है। चार वर्ष के अंतराल के बाद विदेशी मामलों के स्तर पर संयुक्त आयोग का 19वां सत्र दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन में प्राप्त सफलता पर सहमति व्यक्त की। वितीय वर्ष 2017-18 के भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार में 23.8% की वृद्धि हुई है और वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह 17.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

वाना क्षेत्र

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (डब्ल्यूएएनए) क्षेत्र भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के साथ ही वैश्विक शांति और सुरक्षा के रखरखाव में इसके योगदान के लिए भी लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान, संस्थागत संवाद तंत्र और यात्राओं के उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के नियमित आयोजन के माध्यम से, वाना क्षेत्र के सभी देशों के साथ संबंधों को एक सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया गया। यह क्षेत्र रॉक फॉस्फेट और इसके व्युत्पन्नों और उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले पोटाश का एक प्राथमिक स्रोत है। भारत को अपने रॉक फास्फेट की आवश्यकता का 80% से अधिक इस क्षेत्र के देशों से प्राप्त होता है। यह क्षेत्र खनिजों से भी समृद्ध है। हम अपने ऊर्जा हितों को और सुरक्षित करने के इस क्षेत्र में अपने प्रयासों को तेज करना जारी रख रहे हैं। हमने खुफिया जानकारी, आतंकवाद विरोध; साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्रों के औपचारिक और अनौपचारिक तंत्र के माध्यम से इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ अधिक से अधिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग किया। हमने जिबूती, सोमालिया और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपनी समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती रोधी सहयोग को बढ़ाया है। भारत सरकार ने मार्च 2019 में, रिपब्लिक ऑफ जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

फिलिस्तीनी शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में, भारत ने संगठन के लिए अपना वार्षिक योगदान 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में भी योगदान जारी रखा। भारतीय सुरक्षाकर्मियों का एक बड़ा दल दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनआईएसआईएसएस) के हिस्से के रूप में शांति अभियानों में लगा हुआ है।

वाना (डब्ल्यूएएनए) देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी की चुनावी जीत पर बधाई दी और पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, सभी वाना देशों में हमारे सरकारी अधिकारियों, स्थानीय समुदायों और भारतीय समुदायों के प्रवासी संगठनों की साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, गुरु

नानक देवजी की 550वीं जयंती, आईसीसीआर का स्थापना दिवस, 55वां आईटीआईसी दिवस मनाया गया।

अफ्रीका

वर्ष 2019-20 में, अफ्रीका में देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार और विविधीकरण जारी रहा। भारत की अफ्रीका आउटरीच नीति के संदर्भ में, इस वर्ष नई सरकार के गठन के बाद, अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों की भारत और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की पहली विदेश यात्राएँ हुईं। इस वर्ष सितंबर 2019 में जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू अपनी पहली भारत यात्रा पर आए थे। भारत के राष्ट्रपति ने जुलाई-अगस्त 2019 में बेनिन, गाम्बिया और गिनी का दौरा किया। अक्तूबर 2019 में भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा कोमोरोस की पहली यात्रा हुई, उपराष्ट्रपति ने सिएरा लियोन का भी दौरा किया।

इस वर्ष के संसदीय आदान-प्रदान में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला की यात्रा शामिल थी, उनके साथ गए 84 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और 25 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य शामिल थे, जो सितंबर 2019 में कंपाला में संसदीय सम्मेलन आयोजित में भाग लेने के लिए गये थे। युगांडा के संसदीय आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2019 में भारत का दौरा किया। भारत ने जिम्बाब्वे के आम चुनावों के लिए पहली बार, चुनाव पर्यवेक्षक तैनात किए। जिम्बाब्वे के पर्यवेक्षकों ने भारतीय चुनावों को भी देखा। इस वर्ष नामीबिया के चुनावों में भारतीय ईवीएम का उपयोग किया गया था।

बहुपक्षीय बैठकों में नेताओं के बीच बातचीत और संपर्क जारी रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अवसर पर नामीबिया और नाइजर के राष्ट्रपतियों से भेंट की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जी-20 और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और सेनेगल के राष्ट्रपति के साथ बात की। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अवसर पर युगांडा के प्रधानमंत्री डॉ. रुहकाना रगुंडा और कोटे डी आइवर, सिएरा लियोन और इक्वेटोरियल गिनी के विदेश मंत्रियों से भेंट की। विदेश मंत्री एनएएम बैठक के समय कैमरून के उप विदेश मंत्री से भी मिले।

उच्च-स्तरीय राजनीतिक व्यस्तताओं को संस्थागत तंत्र की नियमित बैठकों द्वारा समर्थित किया गया, जिसमें मंत्री स्तर की बैठक भी शामिल है। भारत ने केन्या (मार्च 2019) के साथ संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक (जेसीएम) आयोजित की। विदेश राज्य मंत्री (वीएस) श्री वी. मुरलीधरन ने अक्तूबर 2019 में लुसाका में भारत-दक्षिणी अफ्रीका परियोजना भागीदारी कॉन्क्लेव पर सीआईआई-एक्जिम बैंक क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आधिकारिक स्तर की व्यस्तताओं में नई दिल्ली में, मई 2019 में बोत्सवाना के साथ पहला विदेशी कार्यालय परामर्श सलाहकार (एफओसीएस) और अक्तूबर 2019 में लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका के साथ एफओसी शामिल थे। भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति की नौवीं बैठक अगस्त 2019 में आयोजित की गई थी।

आलोच्य अवधि में इस क्षेत्र के साथ रक्षा और सुरक्षा जुड़ाव और समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। जुलाई 2019 में मोजाम्बिक में रक्षा मंत्री (आरएम) की पहली यात्रा के दौरान, हाइड्रोग्राफी और व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। **रक्षा मंत्री ने मोजाम्बिक की नौसेना के उपयोग के लिए दो फास्ट इंटरसेप्टर नावों का उपहार दिया।** नवंबर 2019 में मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के समय, मोजाम्बिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पहला भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आईएएफटीएक्स मार्च 2019 में आयोजित किया गया था। भारत ने अगस्त 2019 में जाम्बिया के साथ रक्षा सहयोग और अक्तूबर 2019 में कोमोरोस के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संपन्न किया। अब हमारे पास हिंद महासागर के तटवर्ती पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के सभी देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग का संस्थागत ढांचा है।

हमने जिबूती, सोमालिया और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती रोधी सहयोग को बढ़ाया है। भारत सरकार ने मार्च 2019 में, जिबूती गणराज्य के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

भारत मोनुस्को (डीआर कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन) के लिए सैन्य पर्यवेक्षकों और पुलिस कर्मियों सहित सैनिकों का योगदान दे रहा है। वर्तमान में, मोनुस्को के साथ 2,614 भारतीय कार्मिक तैनात हैं। एपएडीआर के मोर्चे पर, ऑपरेशन सहायता में, मार्च-अप्रैल 2019 में मोजाम्बिक में 204 से अधिक लोगों को बचाया गया और 3500 से अधिक लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।

आर्थिक मोर्चे पर, अफ्रीका के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है और इसमें विविधता आई है। वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा 69.7 अरब अमेरिकी डॉलर हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% अधिक है। इस क्षेत्र में हमारे मिशनों ने कई भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और संगठित व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और प्रदर्शनियों की यात्रा के लिए सुविधा प्रदान की। भारत-अफ्रीका क्षेत्रीय आर्थिक सम्मेलन ज़ाम्बिया (दक्षिणी अफ्रीका) और मिस्र (उत्तरी अफ्रीका) में आयोजित किए गए थे।

अफ्रीकी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर 2019 में भारत-अफ्रीका-फोरम शिखर सम्मेलन-III के सामरिक सहयोग ढांचे की समीक्षा बैठक के लिए भारत का दौरा किया। आईएएफएस-III के दौरान रेजिडेंट अफ्रीका एचओएमएस की आईएएफएस समिति के साथ प्रतिनिधिमंडल ने नेताओं द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया। बैठक में भारत और अफ्रीका के बीच समग्र जुड़ाव में शानदार वृद्धि का स्वागत किया गया। एयू प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय पक्ष द्वारा आईएएफएस-III के अंतर्गत ऋण, अनुदान और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से की गई विभिन्न प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रगति को स्वीकार किया। बैठक ने भारतीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन की स्थिति, विशेष रूप से इस तथ्य का स्वागत किया कि आईएएफएस-III के अंतर्गत की गई 10 अरब की समग्र प्रतिबद्धता/ जारीकरण में से भारतीय ऋण श्रृंखला के अंतर्गत 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर दिये जा चुके हैं, यह आईएएफएस-III के अंतर्गत की गई 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता/जारीकरण के लिए निर्धारित 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार कर चुका है और प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण के लिए 50,000 स्लॉटों में से 40,000 से अधिक स्लॉट का उपयोग किया गया है।

अगस्त 2019 में इस्वातिनी के एमबीबाने में एक नये निवासी मिशन के उद्घाटन के साथ, भारत ने पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। अफ्रीका के गणमान्य लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (अक्तूबर 2019) की दूसरी सभा में भाग लिया।

वर्ष 2019-20 में, भारत ने जाम्बिया के साथ 7, कोमोरोस के साथ 6 और मोजाम्बिक के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मलावी और युगांडा ई-विद्याभारती और ई-अरोग्यभारती परियोजना में शामिल हो गए।

दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के उपहार के साथ स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान बनाए रखा गया था, जिसमें भाभट्रॉन और एम्बुलेंस आदि शामिल हैं। भारत ने अनुदान-सहायता (दवाइयां, किताबें, वाहन आदि), रियायती ऋण, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और अल्पकालिक नागरिक और सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए तक अफ्रीकी देशों की सहायता करना जारी रखा।

भारतीय और अफ्रीका के लोगों के आवागमन को आसान बनाने और अफ्रीका के 33 देशों को आवृत करने के लिए ई-वीजा सुविधा का विस्तार किया गया।

2019-20 में, नवंबर 2019 में नैरोबी-मुंबई सेक्टर में एयर इंडिया की उड़ान को फिर से आरंभ करने के साथ-साथ एयर तंज़ानिया द्वारा दार एस सलाम से सीधी उड़ान और अदीस अबाबा और बेंगलुरु के बीच इथियोपिया एयरलाइंस की नई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र के साथ हवाई संपर्क बढ़ गया।

आलोच्य अवधि में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) की छात्रवृत्ति, आईटीईसी पहल और आईएएफएस के अंतर्गत इस क्षेत्र से छात्रों और अधिकारियों को कई छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए। हमने इथियोपिया के मानवीय कार्यक्रम के लिए भारत के अंतर्गत कृषि और संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अफ्रीकी उम्मीदवारों के लिए त्रिपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखा।

यूरोप और यूरोपीय संघ

इस वर्ष भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक मजबूती आई। भारत से कई महत्वपूर्ण यात्राओं के साथ उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की प्रवृत्ति जारी रही, जिसमें विदेश मंत्री की यात्रा भी शामिल थी। 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए नई दिल्ली में 8 नवंबर 2019 को भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 23 नवंबर, 2019 को नागोया में जी-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर भविष्य के भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों पर विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि/उपाध्यक्ष श्री जोसेफ बोरेल से भेंट की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 30 अगस्त 2019 को ब्रुसेल्स का दौरा किया और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष श्री डेविड मारिया सासोली, विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि सुश्री फेडरिका मोघेरिनी और यूरोपीय संघ के मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के आयुक्त श्री क्रिस्टोस स्टाइलिआइड्स से भेंट की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

डॉ. एस. जयशंकर और सुश्री फ़ेडेरिका मोघेरिनी ने 1 अगस्त 2019 को बैंकाक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के मौके पर और फिर 27 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर भेंट की।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे ने 12 सितंबर 2019 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से, यूरोपीय आयोग द्वारा आयोजित ग्लोबल टीकाकरण शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लिया। श्री चौबे ने अपने वक्तव्य में उन तरीकों का वर्णन किया, जिनसे भारत सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत कर रही है और सात टीकों से युक्त इतिहास के एक सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को लागू कर रही है।

भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा बैठक 8 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, सचिव (पूर्व) ने और यूरोपीय संघ का नेतृत्व यूरोपीय क्रिश्चियन एक्शन सर्विस के उप महासचिव क्रिश्चियन लेफ़लर ने किया। बैठक ने भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों के पूरे परिदृश्य को शामिल किया गया, जिससे सहयोग को मजबूत करने के क्षेत्रों को पहचानने के साथ-साथ 2020 के आरंभ में 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में संभावित व्युत्पन्नों को भी शामिल किया जा सके। दोनों पक्षों ने सामरिक भागीदारी की अप्रयुक्त क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय मंचों पर

सहयोग आदि क्षेत्रों में व्यस्तता बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

श्री संजीव अरोड़ा, सचिव (कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा और प्रवासी भारतीय मामले) और सुश्री परस्केवी मिचौ, महानिदेशक (प्रवास और गृह मामले), यूरोपीय आयोग ने 11 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता (एचएलडीएमएम) पर पाँचवीं उच्च स्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता की। बैठक में भारत-यूरोपीय संघ के गलियारे के साथ प्रवास और गतिशीलता के संदर्भ में पारस्परिक हित के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार-विमर्श शामिल है।

भारत-यूरोपीय संघ के उप-व्यापार आयोग की वार्षिक बैठक 4 जुलाई, 2019 को ब्रसेल्स में, सुश्री निधि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, डीओसी और श्री पीटर बेर्ज़, कार्यवाहक निदेशक, व्यापार महानिदेशालय, यूरोपीय आयोग की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उप आयोग ने इसके दायरे में फार्मास्यूटिकल्स, एसपीएस/टीबीटी (सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी/टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड), कृषि और समुद्री उत्पाद, आदि के संयुक्त कार्य समूहों की रिपोर्ट की समीक्षा की। इसमें जीएसपी (सामान्यीकृत प्रणाली), बाजार पहुंच के मुद्दे, डेटा संरक्षण, आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार), स्टील, जैसे व्यापार से संबंधित मुद्दों और व्यापार को प्रभावित करने वाले नियामक उपायों आदि पर भी चर्चा हुई।

आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) पर भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त कार्यकारी समूह की 12वीं वार्षिक बैठक 12-13 सितंबर 2019 को ब्रसेल्स में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता श्री राजीव कुमार, संयुक्त सचिव, मेइती और निदेशक, संचार नेटवर्क, सामग्री और प्रौद्योगिकी महानिदेशालय, यूरोपीय आयोग, श्री जेरार्ड ग्रेफाज ने की। चर्चा बाजार के मुद्दों, 5-जी, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), सुपरकंप्यूटिंग क्वांटम, मानकीकरण आदि सहित दूरसंचार पर केंद्रित रही। 12 सितंबर 2019 को डिजिटल यूरोप और नैस्कॉम द्वारा यूरोपीय संघ-भारत व्यापार संवाद भी आयोजित किया गया था।

रेल मंत्रालय और यूरोपीय आयोग (गतिशीलता और परिवहन महानिदेशालय) ने 3 सितंबर 2019 को रेलवे के क्षेत्र में सहयोग पर एक प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात्, दोनों पक्षों ने 19 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में, यूरोपीय आयोग के अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की।

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदार है जबकि भारत यूरोपीय संघ का नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2018 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 45.8 अरब यूरो (54.0 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। इसमें यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 91.5 अरब यूरो (107.97 अरब अमेरिकी डॉलर) था और 45.7 अरब यूरो (53.9 अरब अमेरिकी डॉलर) का आयात हुआ। यूरोपीय संघ के साथ जनवरी-सितंबर 2019 की अवधि के लिए भारत का द्विपक्षीय व्यापार 68.6 अरब यूरो (75.46 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा।

2018 में यूरोपीय संघ के साथ सेवाओं में भारत का द्विपक्षीय व्यापार 36 अरब यूरो (42.5 अरब अमेरिकी डॉलर) था, जिसमें भारत का निर्यात 19.3 अरब यूरो (22.7 अरब अमेरिकी डॉलर) और आयात 16.7 अरब यूरो (19.7 अरब अमेरिकी डॉलर) का था।

यूरोपीय संघ भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। अप्रैल 2000 से जून 2019 की अवधि के दौरान, यूरोपीय संघ से भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 100.35 अरब डॉलर था, जो कुल एफडीआई का लगभग 23% है।

मध्य यूरोप

विदेश मंत्रालय का मध्य यूरोप डिवीजन क्षेत्र के 30 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की आशा करता है। कुछ सीईं देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध सांस्कृतिक संबंधों में निहित हैं। रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे प्रमुख भारतीय व्यक्ति मध्य यूरोप के देशों में अत्यधिक सम्मानित हैं। स्विट्जरलैंड के लिए हमारे

राष्ट्रपति के हाल के एक दौरे में उन्होंने महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया।

राजनीतिक रूप से, सभी देशों के साथ भारत के संबंध किसी भी प्रमुख द्विपक्षीय अड़चन से मुक्त हैं। उनमें से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन करते हैं, जिसमें भारत की यूएनएससी और एनएसजी की स्थायी सदस्यता का दावा भी शामिल है। पिछले एक दशक में, विशेष रूप से क्षेत्र के देशों के स्थिर होने, यूरोपीय संघ में शामिल होने अपनी आला क्षमताओं को पाने के बाद से संबंध गहरे हुए हैं। हाल के वर्षों में उनकी बढ़ती वैश्विक उपस्थिति ने कई देशों का ध्यान आकर्षित किया है। यूरोपीय संघ के भीतर, मध्य यूरोप के देशों की एक मजबूत आवाज है और विसेगार्ड समूह (चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया) जैसे समूह हैं जो यूरोपीय संघ के भीतर एक मजबूत ताकत है।

वर्ष 2019 के दौरान, संबंधों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए करीब 20 उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुए। हाल ही में संपन्न वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मध्य यूरोप के देशों से तीन राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुखों की उपस्थिति हमारे बढ़ते आर्थिक सहयोग का परिचायक थी।

भारत - मध्य यूरोप आर्थिक जुड़ाव बहुआयामी, व्यापक आधार युक्त और पूरक है। मध्य यूरोप के देशों में आईटी और आईटीईएस, फार्मास्यूटिकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-गवर्नेंस, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं जो इन क्षेत्रों में भारत की बढ़ती मांग के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। 2019 में संपन्न आईईई29बीएफ के पाँचवें संस्करण में मध्य यूरोप के देशों की अच्छी भागीदारी देखी गई। ये देश भारत को भविष्य के सहयोग और निवेश के लिए एक वांछित गंतव्य के रूप में देखते हैं।

पश्चिमी यूरोप

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, अंडोरा और मोनेको सहित पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत की संबद्ध तेजी से बढ़ी है। इस वर्ष को उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्राओं की एक श्रृंखला से चिह्नित किया गया था जिसने यूरोपीय संघ (ईयू) सहित भारत और पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा किया। भारत से हुई कई महत्वपूर्ण यात्राओं के साथ उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की प्रवृत्ति जारी रही, जिसमें फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा और विदेश मंत्री द्वारा इन देशों का दौरा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने 08 अक्तूबर 2019 को पेरिस में पहला राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त किया।

इस वर्ष भारत ने पाँचवें अंतर-सरकारी परामर्श के लिए 1 नवंबर, 2019 को अपने मंत्रिमंडल और व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान सहयोग के बहुआयामी क्षेत्रों में 22 समझौतों/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्री ने 11 जुलाई 2019 को राष्ट्रमंडल के विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया और ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के कुछ अन्य सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए नई दिल्ली में 8 नवंबर 2019 को भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार भागीदार है, जबकि भारत यूरोपीय संघ का नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2018 में ईयू के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 45.8 अरब यूरो (54.0 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा, इसमें यूरोपीय संघ के लिए भारत का निर्यात 91.5 अरब यूरो (107.97 अरब अमेरिकी डॉलर) का था और 45.7 अरब यूरो (53.9 अरब अमेरिकी डॉलर) का आयात हुआ।

इटली के साथ, 2017 में प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी और 2018 में प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे की यात्राओं

से उत्पन्न गति 2019 में जारी रही, जिसमें उच्च-स्तरीय यात्राओं और राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न पहलों का नियमित आदान-प्रदान हुआ।

अक्तूबर 2019 में नीदरलैंड के राजा और रानी द्वारा भारत का पहला राजकीय दौरा किया गया, जिसके बाद विदेश मंत्री ने नीदरलैंड का दौरा किया था। मोनेको के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय ने 5 फरवरी, 2019 को भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिससे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में बहुआयामी साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर मिला।

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री एंतोनियो कोस्टा 19-20 दिसंबर को भारत आए थे, उन्होंने 19 दिसंबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया था। आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति ने की। इसके बाद फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने भारत की यात्रा की।

कुल मिलाकर, पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के जुड़ाव को व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, असैनिक परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष, रक्षा, शहरी प्रबंधन सहित स्मार्ट शहरों, छात्र आदान-प्रदान और पर्यटन प्रवाह में बढ़ाया सहयोग के साथ और गहरा किया गया है।

अमेरिका

उत्तरी अमेरिका

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) ने दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय संबंधों का विस्तार और विकास जारी रखा। रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद-प्रतिरोध, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और लोगों से लोगों के बीच संबंध बढ़े। भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए नेतृत्व के स्तर पर नियमित बातचीत और मार्गदर्शन जारी रहा। मंत्रिस्तरीय बैठकें और भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता जैसे उच्च स्तरीय संवाद तंत्र ने भविष्य के सहयोग के साथ-साथ आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार के लिए रूपरेखा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक दृष्टिकोण पर बढ़ते अभिसरण की सहायता से, भारत-अमेरिकी सामरिक साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

लैटिन अमेरिका

लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (एलएसी) क्षेत्र के साथ संबंधों ने 2019-20 में गति प्राप्त की, जिसमें दक्षिण और मध्य अमेरिका और कैरिबिया के 33 देश शामिल हैं। यह गति इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि भारत एलएसी देशों को अपनी आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपवक्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। इस क्षेत्र में भारत का व्यापार 2019 में 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंध हमें कैरेबिया में लगभग 10 लाख का जीवंत और गतिशील भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री स्तर पर पहली बार भारत-कैरिकॉम नेताओं की बैठक सितंबर 2019 में यूएनजीए के अवसर पर आयोजित की गई थी। बैठक ने कैरिकॉम के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री श्री राल्फ ई. गोंसाल्विस, सितंबर 2019 में भारत की आधिकारिक

यात्रा पर आने वाले सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस से सरकार के पहले प्रमुख बने। इससे पहले राष्ट्रपति जी ने अप्रैल 2019 में चिली का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नवंबर 2019 में ब्रासीलिया में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील गए थे। एलएसी देशों के साथ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर भारत के जुड़ाव में तेजी आई। कई एलएसी देशों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया और भारत ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विधिक एवं संधियां प्रभाग

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ संस्था द्वारा विश्व व्यवस्था में निभाई जाने वाली की केंद्रीय भूमिका के अनुसार अपना उच्च-स्तरीय जुड़ाव जारी रखा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय खंड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने *जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्च स्तरीय बैठक, और आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी प्रवचन की सामरिक प्रतिक्रियाओं* पर नेताओं की वार्ता में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधक संरचना (सीडीआरआई) के गठबंधन की शुरुआत और “लीडरशिप ग्रुप” पहल की घोषणा की, जो उद्योग-संक्रमण ट्रैक का एक परिणाम है, जिसका भारत ने स्वीडन के साथ जलवायु क्रिया शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में सह-नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री ने विकासशील प्रशांत द्वीप राज्यों के नेताओं और कैरिकॉम नेताओं से भेंट की। भारत ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया।

भारत ने सितंबर, 2019 में दिल्ली में, *मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन* के 14वें सम्मेलन (सीओपी14) का आयोजन किया, जिसमें उप महासचिव सुश्री अमीना मोहम्मद ने भाग लिया। विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों के लिए मानवाधिकार की उच्चायुक्त सुश्री मिशेल बाचेलेट के साथ उच्च स्तरीय जुड़ाव जारी रखा गया। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नवंबर 2019 में एफएओ रोम में आयोजित खाद्य और कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के पादप आनुवंशिक संसाधनों की शासी निकाय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने 10-21 जून, 2019 से जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 108वें शताब्दी सत्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचए) का 72वां सत्र 20-28 मई 2019 को जिनेवा में आयोजित हुआ, जिस में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को चार वर्ष की अवधि 2020-23 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया। आलोच्य वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन और खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के परिषदों में दुबारा चुना गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के कार्यकारी बोर्ड के लिए भी चुना गया था। भारत ने शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) की विभिन्न बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत प्रवासन और विकास (जीएफएमडी) पर वैश्विक फोरम के संचालन समूह के सदस्य के रूप में इसके साथने सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। विश्व विरासत समिति का 43वां सत्र 30 जून से 10 जुलाई 2019 तक बाकू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। इस सत्र में दी वॉल्ड सिटी ऑफ़ जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, इसके साथ भारतीय स्थलों की कुल संख्या 38 हो गई।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 25-26 अक्टूबर, 2019 को अजरबैजान के बाकू में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के प्रमुखों और राज्य सरकारों के 18वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री ने बाकू, अज़रबैजान में 23-24 अक्टूबर 2019 को आयोजित एनएएम मंत्रिस्तरीय बैठक भाग लिया। विदेश मंत्री ने 9-11 जुलाई, 2019 में लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल के विदेश मंत्रियों की बैठक (सीएफएएमएम) में भी भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष प्रो. तिजानी मुहम्मद-बंदे ने लिए 1-4 सितंबर 2019 को नई दिल्ली का दौरा किया। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने 13-17 अक्टूबर 2019 तक बेलग्रेड में आयोजित आईपीयू के 141वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने 'जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना' विषय पर एक आपातकालीन मद का प्रस्ताव रखा, जिसे आईपीयू के सभी सदस्य राज्यों ने सर्वसम्मति से अपनाया।s

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

वैश्विक शांति और सुरक्षा एक मजबूत निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला पर टिकी है। भारत निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और उसने विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर अपने अनुभवों और व्यस्तताओं के आधार पर एक मजबूत और विश्वसनीय स्थिति भी विकसित की है। निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर भारत का रुख अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की परंपरा से निर्देशित था, यह एक विकसित भू-स्थानिक वातावरण में वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देने पर आधारित था। वर्ष 2019 में, भारत ने सार्वभौमिक और भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण के साथ-साथ सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा।

बहुराष्ट्रीय आर्थिक संबंध

ब्रिक्स

प्रधानमंत्री ने 13 और 14 नवंबर, 2019 को "ब्रिक्स: आर्थिक विकास के लिए एक अभिनव भविष्य" विषय पर ब्रासीलिया में आयोजित ग्यारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने वैश्विक वित्तीय और सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के संस्थानों, इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, लोगों से लोगों के आदान-प्रदान पर चर्चा की। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी शिखर सम्मेलन में नेताओं को अपनी रिपोर्ट पेश की। शिखर सम्मेलन के परिणामों में ब्रासीलिया घोषणा शामिल थी जिसमें आतंकवाद पर ब्रिक्स नेताओं द्वारा मजबूत भावना व्यक्त की गई थी। ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी निंदा की। उन्होंने आतंकवादी नेटवर्क के खतरे और अपने देशों में इसके कार्यों को रोकने की सभी राज्यों की जिम्मेदारी को याद किया। ब्रिक्स नेताओं ने 28 जून 2019 को जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर अपनी प्रथागत अनौपचारिक बैठक भी की। नेताओं ने जी-20 बैठक के एजेंडे पर विचार-विमर्श किया और वैश्विक राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और

वैश्विक प्रशासन के मुद्दों और महत्व की पारस्परिक चिंताओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

जी-20

प्रधानमंत्री ने 28 और 29 जून 2019 को ओसाका, जापान में चौदहवें जी-20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। जी-20 शिखर सम्मेलन के विषय "वैश्विक अर्थव्यवस्था", "व्यापार और निवेश", "नवाचार", "पर्यावरण और ऊर्जा", "रोजगार", "महिला सशक्तिकरण", "विकास" और "स्वास्थ्य", सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सतत विकास था। जी-20 नेताओं ने शिखर सम्मेलन में एक विज्ञप्ति (जी-20 ओसाका नेताओं की घोषणा) जारी की है।

आईबीएसए

न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2019 को 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सभी प्रासंगिक बहुपक्षीय मंचों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग और समन्वय के माध्यम से बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार पर आईबीएसए संयुक्त वक्तव्य, जारी किया गया था।

जी 7 शिखर सम्मेलन, बिआरित्ज़, फ्रांस

प्रधानमंत्री ने 26 अगस्त, 2019 को फ्रांस के बिआरित्ज़ में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन 'सद्भावना के भागीदार - बिआरित्ज़ भागीदार' में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री डिजिटल परिवर्तन पर सत्र में मुख्य वक्ता थे, उन्होंने डिजिटल और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला।

बिम्सटेक, सार्क और नालंदा

बिम्सटेक के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ भारत की 'पड़ोस पहले नीति' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों में एक दृश्य आदान के रूप में कार्य करती हैं। मई 2019 में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक के नेताओं की उपस्थिति ने इस क्षेत्र में बिम्सटेक के बढ़ते कद को मजबूत किया। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक कार्यक्रमों को विकसित करने में लगातार प्रगति की।

विकास सहयोग

विकास भागीदारी भारत की बाहरी भागीदारी, विशेष रूप से सरकार की 'पड़ोसी पहले' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के अंतर्गत हमारे निकटवर्ती पड़ोस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत के विकास सहयोग की पहल का एक लंबा और स्थायी इतिहास है, हाल के वर्षों में, विकास सहायता की प्रकृति और प्रसार ने भौगोलिक और क्षेत्रीय दोनों रूप से विस्तार किया है। भारत का विकास सहयोग अपने सहयोगी देशों की विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है।

विदेश मंत्रालय की विकास भागीदारी प्रशासन (डीपीए) शाखा के निर्माण के आठ वर्ष बाद, परियोजना संस्थापन और कार्यान्वयन सहित विदेशों के साथ सरकार की विकास पहलों के लिए अधिक संस्थागत सुसंगतता पर ध्यान दिया गया है। मेजबान देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को प्रधानता देने वाले भारत के विकास सहायता मॉडल ने भारत को अपनी विकास की विकास यात्राओं में एक मूल्यवान भागीदार बनाया है। भारत की विकासात्मक सहायता में भारतीय अनुभव को साझा करने, क्षमताओं का निर्माण करने, लोगों में निवेश करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा तैयार करने और हमारे विस्तारित पड़ोस के साथ संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। भारत सरकार की अनुदान सहायता में बुनियादी ढांचा निर्माण शामिल है जो रेलवे संपर्कों, सड़कों और पुलों, जलमार्ग, सीमा-संबंधी बुनियादी ढाँचे, पारेषण लाइनों, विद्युत उत्पादन, जल विद्युत आदि विभिन्न क्षेत्रों में फैला है। भारत क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सामुदायिक विकास जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।

वर्ष 2019-20 में, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत 160 सहयोगी देशों को लगभग 12000 नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट की पेशकश की गई थी। इन क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों में, भागीदार देशों के विशिष्ट अनुरोधों पर आधारित विभिन्न देशों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

आईटीईसी कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा के कारण विभिन्न नई पहल हुई हैं, जिनमें ई-आईटीईसी, आईटीईसी-ऑनसाइट और आईटीईसी एक्जीक्यूटिव जैसे नए कार्यक्रम शामिल किये गये हैं, प्रतिभागियों की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, आईआईटी और आईआईएम जैसे नए प्रमुख संस्थानों को शामिल किया गया है, निजी संस्थानों के साथ साझेदारी, सोशल मीडिया आउटरीच, आईटीईसी के नए लोगो का आरंभ आदि को बढ़ाया गया है। आईटीईसी में मित्र देशों के साथ रक्षा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण सहयोग भी शामिल है, जो इनके रक्षा बलों के अधिकारियों और कर्मियों के लिए 2000 से अधिक स्लॉट प्रदान करता है। इसके अलावा, आईटीईसी कार्यक्रम ने विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति को शामिल किया है ताकि वे साथी क्षेत्रों द्वारा चुने गए और अनुरोधित क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता और विकास के अनुभव को साझा कर सकें।

साझेदार देशों की आवश्यकता के लिए प्रौद्योगिकी और कौशल बैठक के साथ अवसंरचनात्मक सुविधाओं, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में उत्कृष्टता केंद्र, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र (एसएमई) को स्थापित करने और पुरातत्व और विरासत संरक्षण परियोजना जैसे क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गईं।

भारत द्वारा डीपीआरके को खाद्य और टीबी विरोधी दवाई किटों की आपूर्ति करके मानवीय सहायता प्रदान की गई। नामीबिया, अल-सल्वाडोर और जिम्बाब्वे सहित अन्य देशों को भी चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।

आर्थिक कूटनीति और राज्य

ईडी और स्टेट्स प्रभाग ने देश की विदेश नीति के आर्थिक कूटनीति आयाम को एक केंद्रित दिशा देने के अपने प्रयासों के अंतर्गत 2019-20 में कई पहलें की। प्रभाग का प्रयास विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, व्यापार और उद्योग मंडलों और मिशनों/पोस्टों के बीच अधिक से अधिक समन्वय सुनिश्चित करना था ताकि भारत के निर्यात को बढ़ाया जा सके, विदेशों में भारतीय उद्यमों के लिए नए व्यापार के अवसर खोले जाएं, अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जाए, पर्यटन को बढ़ावा मिले और भारत में एफडीआई को बढ़ावा दिया जाए तथा तकाल पड़ोस में और उससे आगे, भारत की आर्थिक संबद्धता को बढ़ावा दिया जा सके।

भारतीय मिशनों/पोस्टों को अपनी “बाजार विस्तार गतिविधियां” बजट के अंतर्गत अपनी मान्यता, ईडी और स्टेट्स डिवीजन के देशों के साथ अपने आर्थिक जुड़ाव को तेज करने के लिए उनका वित्तपोषण *10 करोड़* रुपये तक बढ़ा दिया है। इस निधि का उपयोग कैटलॉग शो और क्रेता-विक्रेता की बैठकों के माध्यम से भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने, बाजार अध्ययन तैयार करने के लिए सलाहकारों को संलग्न करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार सेमिनार आयोजित करने और विदेशों में व्यापार के अवसरों की तलाश करने वाले भारतीय उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने के लिए पक्ष पोषण का काम करने में किया गया है।

प्रभाग ने विदेशों में मिशनों और पोस्टों के नेटवर्क और भारत में शाखा सचिवालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के माध्यम से बाहरी आर्थिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान की। मिशनों और पोस्टों ने राज्य सुविधा विदेश निधि के माध्यम से राज्य सुविधा गतिविधियों का संचालन किया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ उनके निवासी आयुक्तों के साथ नियमित बातचीत जारी रही और राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से आईएफएस अधिकारियों को

राज्यों के आवंटन की पहल पर प्रगति हुई। प्रभाग द्वारा सहयोगी-राज्य और शहर की साझेदारी स्थापित करने के लिए अपने विदेशी समकक्षों के साथ राज्य सरकारों और शहरों के बीच समझौता ज्ञापन की सुविधा भी की गई थी।

आतंकवाद का मुकाबला

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होने वाली आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं को देखते हुए आलोच्य वर्ष में आतंकवाद के मुद्दे का सभी स्तरों पर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में प्रमुखता से उल्लेख हुआ। इस तरह की सभी बातचीत के दौरान, भारत ने वैश्विक स्तर पर खतरे से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी कड़ी निंदा की। भारत ने संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से विभिन्न साझेदार देशों के साथ आतंकवाद प्रतिरोध पर संरचित परामर्श जारी रखा। वर्ष 2019 में, भारत ने चीन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, उज्बेकिस्तान, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी के साथ सीटी संवाद आयोजित किए और ब्रिक्स के आतंकवाद प्रतिरोध कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय साइबर मुद्दे, ई-शासन और आईटी

मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के लाभांश का उपयोग करने के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहल को अनुकूलित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। इससे मंत्रालय की आईटी परिसंपत्तियों के अनुपात में वृद्धि हुई है और आईटी अनुप्रयोगों पर निर्भरता बढ़ रही है, जिसके लिए साइबर खतरों के प्रबंधन की आवश्यकता है। ईजी एवं आईटी डिवीजन, मंत्रालय में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों और विदेशों में सभी मिशनों/पोस्टों में इसे लागू करने के लिए कदम उठा रहा है। ई-क्रांति की चार मिशन मोड परियोजनाएं (डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का चौथा स्तंभ) अर्थात् ई-ऑफिस, ई-प्रोक्योरमेंट, इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम (आईवीएफआरटी) और पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट (पीएसपी) वर्तमान में मंत्रालय और विदेश थित मिशनों/पोस्टों में कार्यरत हैं। डिजिटल इंडिया के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा ई-राजनीतिक मंजूरी प्रणाली, इंटीग्रेटेड मिशन अकाउंटिंग सिस्टम (आईएमएएस), प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए पोर्टल, प्रवेश से एलुमिनी (ए2ए), आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारत को जानो कार्यक्रम, कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे कई ई-गवर्नेंस और ऑटोमेशन परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं। विदेश मंत्रालय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड 14 अगस्त 2019 को आरंभ किया गया है। डैशबोर्ड तीन प्रमुख क्षेत्रों पर बनाया गया है जो सभी प्रमुख योजनाओं के कार्यक्रमों और मंत्रालय की पहलों पर कई प्रमुख संकेतकों के साथ जुड़े हुए हैं और यह पाँच समूहों (डायस्पोरा एंगेजमेंट, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इंटरनेशनल एंगेजमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सिटिजन सर्विसेज) में बंटा हुआ है। मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन के अलावा, साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है।

साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन को विदेश मंत्रालय में जून 2017 में एक स्वतंत्र प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया था ताकि साइबर संबंधित मुद्दों से गहराई और विशेष रूप से निपटा जा सके। प्रभाग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर मुद्दों से संबंधित है। इस तरह की व्यस्तताओं का मुख्य उद्देश्य बहु-हितधारक दृष्टिकोण का पालन करते हुए भारत के साइबर हितों की रक्षा करना है। साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन ने 2014 से अब तक की अवधि में एनएससीएस, एमएचए, एमईआईटीवाई, सीईआरटी-इन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना संरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी), डीआरडीओ, डीओटी जैसी अन्य एजेंसियों के परामर्श से साइबर सुरक्षा मुद्दों, डेटा

सुरक्षा कानूनों और इंटरनेट गवर्नेंस पर चर्चा के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्रवाई शुरू की।

नीति योजना और अनुसंधान (सीमा प्रकोष्ठ और पुस्तकालय सहित)

मंत्रालय के नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग ने प्रमुख सम्मेलनों, पूरे भारत में छोटे सम्मेलनों के आयोजन के लिए विभिन्न चिंतक और शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन देने और मंत्रालय की रुचि के नीति-उन्मुख अनुसंधान के आयोजन के माध्यम से वैश्विक और घरेलू रणनीतिक समुदाय के साथ मंत्रालय को रणनीतिक इंटरफ़ेस प्रदान करने के अपने जनादेश को जारी रखा। प्रभाग ने वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण, विशिष्ट मुद्दों के अधिक विस्तृत अध्ययनों के साथ-साथ निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संभावित प्रवृत्ति का आकलन भी किया; इसने भागीदार देशों के साथ नीति नियोजन संवाद किए।

प्रभाग ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन की स्थापना में राजनयिक आउटरीच समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ, इसके अंतिम कानूनी रूप और संरचना के लिए पर्याप्त नीतिगत आदान प्रदान कर भारत सरकार के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग ने एक वर्ष के अल्प समय में सीडीआरआई को विचार के स्तर से संयुक्त राष्ट्र में आरंभ करने के स्तर तक पहुँचाने और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे प्रमुख देशों का औपचारिक प्राप्त करने में सक्षम रहा। नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग अपने को प्रमुख प्रभाग के रूप में स्थापित करने में सक्षम रहा, जिसने आर्कटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते मुद्दों में मंत्रालय के नीति-उन्मुख प्रयासों का नेतृत्व किया।

नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग ने इस अवधि में स्वायत्त निकायों (यानी, आरआईएस और आईसीडब्ल्यू) के कामकाज को प्रभाग के आदेश के अंतर्गत पर्याप्त प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवधि में पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और डेटाबेसों की सदस्यता में महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए।

शिष्टाचार (प्रोटोकाल)

वर्ष 2019 में, प्रोटोकॉल-I अनुभाग ने राज्य प्रमुख, उपराष्ट्रपति, सरकार के प्रमुख और विदेश मंत्री (18 दिसंबर 2019 तक) के स्तर पर देश में आने/जाने वाली 100 यात्राओं को संभाला।

प्रोटोकोल-I अनुभाग ने जनवरी 2019 के रायसीना संवाद में 6 विदेश मंत्रियों की भागीदारी, रायसीना 2020 के लिए 11 विदेश मंत्रियों और 07 पूर्व राष्ट्र प्रमुखों/सरकार प्रमुखों, मई 2019 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 8 राष्ट्र प्रमुखों/सरकार प्रमुखों और दिसंबर 2019 में ग्यारहवें दिल्ली संवाद में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी का समन्वय किया।

इसके अलावा, प्रोटोकॉल-I अनुभाग ने 320 मनोरंजन कार्यक्रमों (18 दिसंबर 2019 को) को संभाला और हवाई अड्डे से पास, लाउंज (औपचारिक और आरक्षित) और फ्रिस्किंग से छूट के लिए प्रति सप्ताह औसतन 180 अनुरोधों को संभाला।

राजनयिक पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

पासपोर्ट जारी करना मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे उल्लेखनीय वैधानिक और नागरिक केंद्रित सेवाओं में से एक के रूप में उभरी है। मंत्रालय इसे नागरिकों को समय पर, पारदर्शी, अधिक सुलभ, विश्वसनीय तरीके से और आरामदायक वातावरण में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से और प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित और प्रेरित कार्यबल द्वारा नागरिकों तक पहुंचाने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन कर रहा है।

विदेश मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और 36 पासपोर्ट कार्यालयों के उनके अखिल भारतीय नेटवर्क, सीपीवी डिवीजन (केवल राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट) और अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट (साथ में अन्य यात्रा दस्तावेज जैसे कि राज्यहीन लोगों को पहचान के प्रमाणपत्र, भारत लौटने वालों के लिए आपात कालीन प्रमाणपत्र, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में नियंत्रण रेखा यात्रा परमिट) जारी किए जाते हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 36 पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखाओं के रूप में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओ पीएसके) (डाक विभाग के सहयोग से) को मिलाकर इस नेटवर्क का विस्तार किया गया है। देश में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की कुल संख्या 31 दिसंबर, 2019 तक 517 थी, जिसमें पीएसके और पीओपीएसके भी शामिल थे। विदेशों में स्थित 192 भारतीय मिशनों/डाक द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, पासपोर्ट और आपात कालीन प्रमाणपत्र प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रवासी भारतीय मामले

विदेश में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों का कल्याण और संरक्षण मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। एक सुरक्षित, व्यवस्थित, कानूनी और मानवीय प्रवासन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय ने गंतव्य के देशों के साथ-साथ वापसी पर पूर्व प्रस्थान सहित प्रवास चक्र के सभी चरणों में प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने वाले पर्यावरण-तंत्र को और मजबूत किया है। इसमें प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण (पीडीओ) कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और संरक्षण के लिए एक व्यापक-संस्थागत ढांचे की स्थापना शामिल है। प्रवासी श्रमिकों का एक सुरक्षित कौशल के साथ सुरक्षित रूप से प्रवास करना महत्वपूर्ण है। उन्हें "सुरक्षित जायें, प्रपरीक्षितत जायें, विश्वास के साथ जायें" का संदेश दिया जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में गंतव्य देशों के साथ जन शक्ति और श्रम मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने और फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और यूरोपीय संघ सहित देशों के साथ प्रवास और गतिशीलता संबंधी मुद्दों पर कदम उठाए गए हैं।

समन्वय और संसद

संसद प्रभाग मंत्रालय का संसद के साथ इंटरफेस और इस मंत्रालय के संसद संबंधी सभी कार्यों के लिए प्रमुख बिंदु है। प्रभाग ने विदेश मामलों की परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित कीं और अन्य संसदीय समितियों के साथ विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति और मंत्रालय की बातचीत से संबंधित कार्यों का समन्वय किया।

समन्वय विभाग ने मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और गैर-सरकारी संगठनों सहित स्वायत्त निकायों और निजी संस्थानों के बीच बातचीत का समन्वय किया। प्रभाग ने मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक/निजी यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी दी। इसने भारत में सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए विदेशी भागीदारी, भारत में विदेशी प्रतिभागियों को आमंत्रित किये जाने वाले खेल टूर्नामेंट और विदेश में खेल टूर्नामेंट आयोजित करने, विदेशी सैन्य उड़ानों का अवतरण, ओवरफ्लाइट क्लीयरेंस, विदेशी नौसैनिक जहाजों का आगमन, भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों और विभिन्न संस्थानों में फील्ड विजिट/प्रशिक्षण/निरीक्षण आदि के लिए भारत आने वाले विदेशी अध्येताओं के संबंध में छात्र वीजा के अध्ययन वीजा में रूपांतरण को भी प्रसंस्कृत किया।

मंत्रालय का शिक्षा अनुभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को आवंटित सीटों पर स्व वित्त

पोषण योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस, बी. आर्क., बीई, बी. फार्मेसी और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 57 मित्र पड़ोसी और विकासशील देशों से विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश से संबंधित है। भारत में रह रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासियों को भी इस योजना के अंतर्गत सीटें प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण प्रकोष्ठ को निरंतर प्रासंगिकता और स्थिति के कोण से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विदेशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/समझौतों की समीक्षा के समन्वय का काम सौंपा गया है।

प्रशासन, स्थापना और वित्त

प्रशासन प्रभाग राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने, आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने, भारतीय नागरिकों का समर्थन करने और संबंधित क्षेत्रों में आउटरीच करने के प्रयास के अंतर्गत लैटिन अमेरिका, भारत-प्रशांत क्षेत्र, यूरोप और अफ्रीका में 25 नए भारतीय राजनयिक मिशन खोलने के लिए मंत्रालय की योजनाओं को लागू कर रहा है। वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रभाग ने विदेशों में और भारतीय मंत्रालय के लिए कार्यालय और आवासीय भवनों के अधिग्रहण/निर्माण के माध्यम से सरकार के लिए पूंजीगत संपत्ति बनाने के अपने आदेश का सख्ती से पालन करना जारी रखा। संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने और राज्य प्रशासन और मंत्रालय के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को एक छत के नीचे रखने के उद्देश्य से राज्य की राजधानियों में विदेश भवन की स्थापना की गई थी। कई अधिग्रहण परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, चल रही निर्माण/नवीकरण परियोजनाओं को पूरा किया गया और कई नई निर्माण/नवीनीकरण परियोजनाओं को शुरू करने पर काम किया गया।

बाहरी प्रचार

बाहरी प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग ने अपने को भारत की बढ़ती वैश्विक प्रोफ़ाइल और घरेलू और वैश्विक दर्शकों के लिए उत्तरदायी और केंद्रित आउटरीच के माध्यम से तेजी से विकसित होते संचार वातावरण के लिए तेजी से अनुकूलित किया है। यह कार्य मीडिया के साथ हमारे व्यापक जुड़ाव और देश और विदेश दोनों में भारत की सार्वजनिक कूटनीति का विस्तार करने और परिणाम को अधिकतम करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य आधुनिक उपकरणों का लाभ उठाने के माध्यम से हासिल किया गया है। 2019 में, प्रभाग ने सार्वजनिक कूटनीति की तीन विशेष पहलों - स्कूल और विदेश मंत्रालय जुड़ाव कार्यक्रम **(एसएएमईईपी)** - भारतीय विदेश सेवा से संबंधित उस स्कूल के पूर्व छात्रों द्वारा छात्रों के लिए आउटरीच, विदेश आया प्रदेश के द्वार - भारत भर के विभिन्न शहरों में क्षेत्रीय मीडिया के साथ एक केंद्रित जुड़ाव और एक भारत एक परिचय - विदेशों के शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों में भारत की पुस्तकों के लिए एक कोने को प्रोत्साहन दिया। प्रेस संबंधों के मोर्चे पर, प्रभाग ने 'सुर्खियों के परे भारत' नामक एक नई पहल शुरू की - जो भारत में आधारित विदेशी पत्रकारों के लिए एक परिचितकरण कार्यक्रम है, जिसमें उन्हें कई विषयों पर भारत की समझ प्रदान की जा सकती है।

एक्सपीडी प्रभाग महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोहों के लिए प्रमुख बिंदु था। इस अवसर को मनाने के लिए प्रभाग ने हमारे मिशनों और पोस्टों द्वारा आयोजित कई गतिविधियों का समर्थन किया। इस अवसर पर दुनिया भर की प्रसिद्ध हस्तियों के योगदान के साथ 'मेरे लिए गांधी का क्या अर्थ है' पर एक संकलन निकाला गया। प्रभाग ने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के समारोहों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक नई पहल में, गुरु नानक की शिक्षाओं पर एक एलईडी फिल्म बनाई गई और दुनिया भर के विभिन्न शहरों में प्रदर्शित की गई। इन प्रयासों ने भारत की विदेश नीति को सक्रिय, प्रभावी और लोगों पर केंद्रित नीति के रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई, साथ ही दुनिया में भारत के कद को बढ़ाने के प्रयासों को सहायता प्रदान की।

आधिकारिक भाषा और विदेशों में हिंदी का प्रसार

भारत सरकार की आधिकारिक भाषा नीति का कार्यान्वयन मंत्रालय की प्राथमिकता है। इस दिशा में, मंत्रालय के पास विदेशों में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए एक व्यापक योजना है। विश्व हिंदी सम्मेलन और क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी पखवाड़े में हिंदी दिवस को चिह्नित करने के लिए हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय ने विशिष्ट भाषा व्याख्याताओं का एक भंडार बनाने और भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए अटल भाषांतर योजना (एबीवाई) बनाई है।

विदेश सेवा संस्थान

विदेशी सेवा संस्थान (एफएसआई) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दायरा और संख्या 2019 में लगातार बढ़ता रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) के अधिकारियों के लिए नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए। भारतीय पत्रकारों को विदेश नीति के मुद्दों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिया। विदेश मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी और उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों के लिए व्यापक पदोन्नति से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टेनोग्राफी टेस्ट आरंभ किए गए थे। विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण ऊर्ध्वाधर पर है, इस वर्ष लगभग 750 विदेशी राजनयिकों की रिकॉर्ड संख्या को प्रशिक्षित किया गया था। एफएसआई की नई पहलों में एक त्रैमासिक समाचार पत्र *विदेश सेवा* शामिल है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की स्थापना वर्ष 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को बढ़ावा और मजबूत करना था। पूरे भारत में इसके 19 क्षेत्रीय केंद्र और 37 सांस्कृतिक केंद्र हैं, जिनमें विभिन्न देशों में पीपीपी मॉडल के 2 केंद्र शामिल हैं। वर्ष 2019-2020 परिषद् के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 131 देशों के विदेशी नागरिकों को लगभग 3940 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान किए गए थे। विभिन्न देशों में कुल 69 सांस्कृतिक मंडलों को प्रायोजित किया गया, आने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों द्वारा 30 प्रदर्शन आयोजित किए गए, 40 देशों में महात्मा गांधी की 29 कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गईं, इसके अलावा कई अन्य गतिविधियों सहित पहली बार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का स्थापना दिवस और गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती का उत्सव मनाया गया।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

आईसीडब्ल्यूए ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और व्यापक वैश्विक भू-सामरिक वातावरण में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा विकास के अनुसंधान और अध्ययन को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा। निष्कर्षों को सप्रू हाउस पेपर्स, इश्यू ब्रीफ्स, पॉलिसी ब्रीफ्स एंड व्यूप्वाइंट्स, डिस्कशन पेपर्स, शोध लेख के रूप में प्रसारित किया गया और आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा, आईसीडब्ल्यूए ने अपने अकादमिक परिणामों का हिंदी में अनुवाद करने की प्रक्रिया जारी रखी जो नियमित रूप से इसकी वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है। इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने

के लिए परिषद् की वेबसाइट को संशोधित करने के प्रयास चल रहे हैं। अब यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। आईसीडब्ल्यूए ने अपनी लाइब्रेरी को आम जनता के लिए भी खोल दिया है और सदस्यता नियमों में ढील दी गई है। आईसीडब्ल्यूए ने अपने जनादेश के अनुसार बड़ी संख्या में व्याख्यान, चर्चा, सम्मेलन, चिंतक संवाद और आउटरीच गतिविधियों का संचालन किया।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), एक नई दिल्ली स्थित स्वायत्त चिंतक निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञ है। आरआईएस को वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावी नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में जाना जाता है।

कार्यक्रम का ध्यान दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर है और संस्थान विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों के साथ सहयोग करता है। आरआईएस कई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहलों की अंतरसरकारी प्रक्रियाओं में संलग्न है। आरआईएस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और चिंतकों के अपने गहन नेटवर्क के माध्यम से विकास भागीदारी कैनवास पर नीतिगत सामंजस्य को मजबूत करना चाहता है। इस जनादेश के हिस्से के रूप में, 2019 में आरआईएस द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख कार्यक्रम और सम्मेलन निम्नलिखित थे: दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर दिल्ली प्रक्रिया पांचवां सम्मेलन; कोच्चि में छठा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) अकादमिक फोरम; जी-20 शेरपा श्री सुरेश प्रभु द्वारा ओसाका शिखर सम्मेलन पर एक विशेष डी-ब्रीफिंग सत्र; और एक बहु-सत्रीय उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम 2019।

1

भारत के पड़ोसी

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के समीपस्थ पड़ोसी के रूप में भारत की अफगानिस्तान की शांति, सुरक्षा और स्थिरता में स्थायी रुचि है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक गहन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापक सामरिक संबंध है, जो पिछले एक साल में चौतरफा विकास, मजबूत और गहरा हुआ है। यह राजनीतिक, रक्षा सहभागिता, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, संपर्क, विकास साझेदारी, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों, शिक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों सहित निरंतर उच्च स्तरीय द्विपक्षीय गतिविधियों में परिलक्षित हुआ।

उच्च स्तरीय प्रतिदान

वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय यात्राओं और व्यस्तताओं की गति को बनाए रखा गया। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में 13 जून 2019 को एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। इससे पहले अफगान राष्ट्रपति ने मई 2019 में प्रधान मंत्री के पुन: चुने जाने पर उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। 24 दिसंबर को प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति गनी को राष्ट्रपति चुनाव के सफल आयोजन और प्रारंभिक परिणामों की घोषणा के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि भारत अफगानिस्तान के साथ मजबूत दोस्ती को महत्व देता है। भारत हमेशा अफगानिस्तान को उनकी विकास की जरूरतों में और अफगानिस्तान के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग करेगा।

अन्य प्रतिदानों में भारत के उपराष्ट्रपति ने अक्तूबर 2019 में बाकू में गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति डॉ. गनी से मुलाकात की; सितंबर,

2019 में माले में चौथे दक्षिण एशियाई स्पीकरों के शिखर सम्मेलन के दौरान लोक सभा अध्यक्ष ने वोलेसी जिरगा (अफगान संसद के निचले सदन) अल-हज मीर रहमान रहमानी से मुलाकात की; और रक्षा मंत्री ने नवंबर 2019 में ताशकंद में सरकार प्रमुखों के एससीओ परिषद् की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अब्दुल्ला से मुलाकात की।

वर्ष के दौरान अफगानिस्तान के वरिष्ठ नेताओं की भारत की यात्रा में अगस्त 2019 में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और दिसंबर 2019 में एनएसए डॉ. हमदुल्ला मोहिब की यात्राएं शामिल हैं। एनएसए मोहिब और पूर्व राष्ट्रपति श्री करजई ने जनवरी 2020 में रायसीना वार्ता में भाग लिया।

आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी

भारत और अफगानिस्तान के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 500 से अधिक उड़ानों ने सफलतापूर्वक समर्पित वायु मालवहन कॉरिडोर के माध्यम से 5000 टन से अधिक कार्गो का परिवहन किया, जिस कॉरिडोर को 2017 में शुरू किया गया था। यह भारत के लिए अफगान निर्यात को एक बड़ा बढ़ावा देने वाला साबित हुआ है और इसका लाभ सीधे अफगानी किसानों, और छोटे व्यापारियों और निर्यातकों को मिला है। भारत और अफगानिस्तान ने अब दोनों देशों में कई अन्य शहरों में इस कॉरिडोर का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2019 में भारत-अफगानिस्तान व्यापार और निवेश प्रदर्शनी का तीसरा संस्करण, 'समृद्धि का रास्ता' का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जिसमें 173 अफगानी व्यापारियों ने भागीदारी की। 33.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। परस्पर व्यापार बैठकों के परिणामस्वरूप भारत की महिलाओं और अफगान महिलाओं की स्वामित्व वाली कंपनियों और संगठनों के बीच छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

अफगानिस्तान ने शाहिद बिहेस्ती पोर्ट, चाबहार के माध्यम से भारत को अपना निर्यात शुरू किया। पहली खेप फरवरी 2019 में भेजी गई। इसके बाद चाबहार के जरिए पांच और खेप निर्यात की गई।

विकास सहयोग

विकास सहयोग द्विपक्षीय सहयोग की एक आधारशिला रही है। अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान भारत सरकार की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) स्कीम के अंतर्गत अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में 37 विकासात्मक परियोजनाएं पूरी की गईं।

वर्ष 2019-20 में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में आईटीईसी योजना के अंतर्गत 500 स्लॉट और टीसीएस कोलंबो योजना के 25 स्लॉटों का अफगानिस्तान में विस्तार किया गया है। अफगान नागरिकों के लिए आईसीसीआर विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्नातक, स्नात्कोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए 1000 छात्रवृत्तियां आफर की गयी हैं। अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के शहीदों के बच्चों/आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 500 स्लॉट की पेशकश की गई है। वर्ष 2018-19 में इन स्लॉटों में से 79 स्लॉटों का उपयोग किया गया है।

भारत ने सुशासन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अफगान अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। इसमें अफगानिस्तान राष्ट्रीय सांख्यिकी और सूचना प्राधिकरण तथा अफगानिस्तान केंद्रीय नागरिक पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल थे जिसे नवंबर और दिसंबर 2019 में एफआरआरओ, दिल्ली, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए थे। इनमें मृत्यु और जन्म के पंजीकरण की प्रणाली, आधार, जनगणना, आव्रजन प्रक्रिया, आदि का अध्ययन शामिल था।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, भारत में अफगान राष्ट्रीय सेना (एएनए) और अफगान वायु सेना (एएएफ) के कर्मियों का प्रशिक्षण भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में जारी रहा। 20 अफगान महिला अधिकारियों के तीसरे बैच का चेन्नई स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ है।

अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण के प्रयासों के लिए तीसरे देशों के साथ सहयोग के भाग के रूप में अफगान राजनयिकों के लिए दूसरा भारत-चीन संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम नवंबर 2019 में आयोजित किया गया। भारत ने लखनऊ में अफगान नेशनल क्रिकेट टीम के लिए घरेलू मैदान प्रदान किया है। भारत में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच एक द्विपक्षीय टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला 06 नवंबर-01 दिसंबर 2019 के दौरान खेली गई। इस श्रृंखला में 3 एक-दिवसीय मैच, 3 टी-20 और एक टेस्ट मैच शामिल थे।

अन्य द्विपक्षीय घटनाक्रम

24 नवंबर, 2019 को भारतीय गणराज्य और इस्लामी गणतंत्र अफ़गानिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू हुई।

जून 2019 में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख अफगान पत्रकारों के एक समूह ने भारत का दौरा किया।

अफगानिस्तान ने जनवरी 2020 में हैदराबाद में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोला। यह नई दिल्ली में उनके मौजूदा दूतावास और मुंबई में वाणिज्य दूतावास के अलावा है।

अफगानिस्तान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल किया है और अफगानिस्तान के संबंध में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मंचों में भाग लिया है। भारत और उज्बेकिस्तान ने जनवरी 2019 में समरकंद में भारत, पांच मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान के बीच पहले विदेश मंत्री स्तरीय बातचीत की सह-मेजबानी की। राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह ने इस्तांबुल में हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया की आठवीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति डॉ. गनी से मुलाकात की; भारत ने अप्रैल 2019 में बिश्केक में आयोजित अफगानिस्तान से संबंधित एससीओ संपर्क समूह की बैठक में भाग लिया; उप एनएसए राजिंदर खन्ना ने दिसंबर 2019 में तेहरान में आयोजित अफगानिस्तान संबंधी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में भाग लिया। अफगानिस्तान में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, उजबेकिस्तान और चीन के विशेष दूतों ने वर्ष के दौरान भारत का दौरा किया।

विभिन्न मंचों पर भारत ने एक अखंड, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए अपना समर्थन दिया है। भारत ने समग्र शांति और सामंजस्य के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया जो अफगान द्वारा स्वाधिकृत, अफगान नीत और अफगान-नियंत्रित हैं; संवैधानिक व्यवस्था और समावेशी लोकतंत्र का संरक्षण और संवर्धन; अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों सहित पिछले 18 वर्षों के लाभ को संरक्षित करना है। सितंबर 2019 में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भारत ने अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के सफल आयोजन का स्वागत किया और लोकतांत्रिक शासन में अपने विश्वास को दोहराने के लिए लोगों की सराहना की।

बांग्लादेश

भारत दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की आजादी के तुरंत बाद इसे मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत-बांग्लादेश संबंध इतिहास, संस्कृति, भाषा और धर्मनिरपेक्षता,

लोकतंत्र, और दोनों देशों के बीच अनगिनत अन्य समानताओं के साझा मूल्यों में है। दोनों देश संप्रभुता, समानता, विश्वास और समझ के आधार पर सभी प्रकार की चीजों को साझा करते हैं जो एक सामरिक साझेदारी से कहीं आगे जाती है।

राजनीतिक दौरा

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में 2019 में राजनीतिक और आधिकारिक स्तर पर गहन उच्च स्तरीय अनुबंधों के साथ पुन: मजबूती आयी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मो. अब्दुल हामिद ने 30 मई 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। प्रधान मंत्री शेख हसीना 03-06 अक्तूबर 2019 से आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आईं। दोनों प्रधान मंत्री सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र के अवसर पर महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भी मिले। प्रधानमंत्री हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संयुक्त रूप से 22 नवंबर 2019 को कोलकाता में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक गुलाबी गेंद वाले टेस्ट क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। इन उच्च स्तरीय यात्राओं ने दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने मार्च 2019 में बांग्लादेश में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चार द्विपक्षीय विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिनमें शामिल हैं- (i) ऋण सहायता के जरिये 500 ट्रकों, 300 डबल डेकर बसों और 200 एसी बसों की आपूर्ति (ii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का विस्तार बांग्लादेश में नेटवर्क (iii) बांग्लादेश के पांच जिलों में 36 सामुदायिक चिकित्सालयों की स्थापना और (iv) बांग्लादेश में 11 जल शोधन संयंत्रों की स्थापना तथा अक्तूबर 2019 में तीन और परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया जिनमें शामिल है- (i) ढाका में रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद भवन का उद्घाटन (ii) बांग्लादेश से थोक एलपीजी का आयात और (iii) डिप्लोमा इंजीनियर्स संस्था, बांग्लादेश (आईडीईबी), खुलना में बांग्लादेश-भारत व्यावसायिक कौशल विकास संस्थान (बीआईपीएसडीआई) का उद्घाटन।

भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अगस्त 2019 में ढाका का दौरा किया और बांग्लादेश के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नवंबर 2019 में दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) के शासी परिषद् की 15वीं बैठक में भाग लेने के लिए ढ़ाका की यात्रा की और बांग्लादेश के सूचना मंत्री, हसन महमूद से मुलाकात की।

बांग्लादेश की ओर से, महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय स्तर के दौरे में विदेश मंत्री डॉ. ए के अब्दुल मोमन की फरवरी 2019 में संयुक्त सलाहकार आयोग (जेसीसी) की बैठक में शामिल होने के लिए आना, गृह मंत्री असदुज्जमां खान का अगस्त 2019 में गृह मंत्री स्तर की वार्ता में शामिल होने के लिए आना और रेल मंत्री एम. नुरुल इस्लाम सुजान का अगस्त 2019 में रेलवे क्षेत्र में सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आना शामिल है।

उपरोक्त उच्च स्तरीय यात्राओं और दोनों देशों के बीच परस्पर बातचीत के अलावा विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर कई दौरे भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोगों में पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के पारंपरिक क्षेत्रों से लेकर परमाणु विज्ञान, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्र शामिल हैं। 2019 में विभिन्न अवसरों पर दोनों देशों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए दस समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर बांग्लादेश में समारोहों के उद्घाटन के अवसर पर मार्च 2020 में प्रधान मंत्री की बांग्लादेश यात्रा का अनुमान है। मार्च 2020 तक की अन्य प्रत्याशित घटनाओं में बांग्लादेश के सूचना मंत्री की भारत की यात्रा (14-16 जनवरी, 2020), वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता, व्यापार पर संयुक्त कार्य समूहों की बैठकें और

सुंदरवन के संरक्षण तथा भारत-बांग्लादेश वस्त्र उद्योग मंच (आईबीटीआईएफ) की पहली बैठक शामिल हैं।

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के बीच महानिदेशक (डीजी) स्तर की वार्ता 2019 में आयोजित की गई। इसके अलावा, बीजीबी के क्षेत्रीय कमांडरों और बीएसएफ के फ्रंटियर महानिरीक्षक के बीच सीमा भारत-बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर की भू-सीमा के प्रबंधन और सुरक्षा चर्चा के लिए हेतु भी सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित किए गए।

रक्षा समन्वय

वर्ष 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। भारतीय नौसेना, बांग्लादेश नौसेना और भारतीय वायु सेना के सेवाओं के प्रमुख के स्तर पर उच्च स्तरीय बातचीत, दूसरी वार्षिक रक्षा संवाद और उद्‌घाटन त्रि-सेवा कर्मचारी वार्ता, नौसेना और वायु सेना की सेवा विशिष्ट वार्ता एवं तट रक्षकों के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण सुधार में योगदान दिया है। भारतीय सेना बैंड ने भी पहली बार बांग्लादेश की राष्ट्रीय परेड में विजय दिवस समारोह के दौरान प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों देशों ने आपसी संबंधों को बनाए रखा एवं और बढ़ाया है।

2019 में विजय दिवस के अवसर पर मुक्तिजोध से संबंधित अनुबंध, मुक्तिजोधदास की वार्षिक पारस्परिक यात्रा और युद्ध दिग्गजों को मुक्तिदासदास के वारिसों को छात्रवृत्ति वितरित की गई।

कनेक्टिविटी :

दोनों सरकारें 1965 से पहले के रेल लिंक जो भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद था और अन्य कनेक्टिविटी लिंक को बहाल करने के लिए कई उपाय कर रही हैं। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए दो पैसेंजर ट्रेनों की आवृत्ति में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, अर्थात्, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस क्रमशः सप्ताह में 4 दिन से लेकर सप्ताह में 5 दिन और सप्ताह में एक दिन से लेकर सप्ताह में दो दिन। अक्तूबर 2019 में पीएम शेख हसीना की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान, दोनों सरकारों ने ढाका-सिलीगुड़ी-गंगटोक-ढाका और ढाका-सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग-ढाका बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध प्रगाढ़ हो और दिसंबर 2019 में ढाका-सिलीगुड़ी-गंगटोक-ढाका के ट्रेल रन भी हुआ।

अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार संबंधी प्रोटोकॉल (पीआईडब्लूटीटी) के लिए दूसरे परिशिष्ट में शामिल किए जाने हेतु दो नए भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (गोमती नदी पर सोनमुरा-दाउदकंडी और पद्मा नदी में धुलिया से गोदियागिरि से होते हुए अरगहा तक) विस्तार पर भी पर सहमति बनी है।

आर्थिक और वाणिज्य

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2018-19 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 9.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसी अवधि के दौरान बांग्लादेश से आयात 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थागत तंत्रों की बैठकें जिनमें सीमा हाट, शिपिंग, एलसीएस/आईसीपी अवसंरचना और भारतीय आर्थिक क्षेत्र की स्थापना आदि शामिल हैं, को 2019 में आयोजित किया गया। द्विपक्षीय व्यापार पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों प्रधान मंत्री व्यापार और निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत स्तर के इनपुट प्रदान करने और देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत-बांग्लादेश सीईओ का फोरम के गठन पर सहमत हुए।

बिजली क्षेत्र में सहयोग भारत-बांग्लादेश संबंधों की पहचान बन गया है। वर्तमान में बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली ले रहा है। 2019 में संयुक्त कार्य दल (जेडब्लूजी) / संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) की बैठकें भी हुईं।

विकास संबंधी साझेदारी

बांग्लादेश आज भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है। भारत ने पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 3 ऋण साख (एलओसी) प्रदान किया है। एलओसी के अलावा भारत सरकार बांग्लादेश में अखौरा-अगरतला रेल संपर्क के निर्माण, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों के ड्रेजिंग और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के निर्माण सहित विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रही है।

लघु विकास परियोजनाएं (एसडीपी) भारत के विकास सहायता का एक सक्रिय स्तंभ हैं। भारत सरकार ने 55 एसडीपी को वित्त पोषित किया है, जिसमें बांग्लादेश में छात्रावासों, शैक्षणिक भवनों, सांस्कृतिक केंद्रों और अनाथालयों आदि का निर्माण शामिल है और अन्य 26 एसडीपी को लागू किया जा रहा है।

क्षमता वर्धन और मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास बांग्लादेश में भारत के अपने कई चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और छात्रवृत्ति के माध्यम से विकास सहयोग प्रयासों का एक प्रमुख घटक है। भारत सरकार 2019 से 1800 बांग्लादेश सिविल सेवा के अधिकारियों को मसूरी के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के लिए प्रशिक्षित कर रही है। बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों को इस सूचना युग के विभिन्न आधुनिक पुलिसिंग और नई खोजी तकनीकों पर भारत के विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार, भारत सरकार राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में और भारत के विभिन्न राज्य न्यायिक अकादमियों में 2017 से 1500 बांग्लादेशी न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। बांग्लादेश भी एक महत्वपूर्ण आईटीईसी साझेदार देश है और प्रतिवर्ष बांग्लादेश से लगभग 800 प्रतिभागी आईटीईसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा आईआईटी और एनआईआईटी सहित भारत के शैक्षणिक संस्थानों में स्नातक और स्नात्कोत्तर और एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए बांग्लादेश से छात्रों को हर साल आईसीसीआर (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) द्वारा 200 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (आईजीसीसी) दोनों देशों के बीच आम सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग, कथक, मणिपुरी नृत्य, हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, भारत और बांग्लादेश के प्रसिद्ध कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम लोगों के बीच संपर्क में योगदान करते हैं।

वीजा

भारतीय वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को और अधिक उदार बनाने और भारत एवं बांग्लादेश के बीच लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसरण में 2019 में बांग्लादेश के कमिला, नोआखली, ब्राह्मणपुरिया, सथकिरा, ठाकुरगाँव और बोगुरा में छह नए भारतीय वीज़ा आवेदन केन्द्र (आईवीएसी) खोले गए जिससे आईवीएसी की कुल संख्या 15 हो गयी। 2019 में बांग्लादेशी नागरिकों को जारी किए गए वीजा की संख्या 15 लाख के पार हो गयी। 2019 में खुलना और सिलहट में दो नए सहायक उच्च आयोगों को खोलने से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए एक कुशल और त्वरित वीजा प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली है।

बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्मशती के अवसर पर बांग्लादेश में समारोहों के उद्घाटन के अवसर पर मार्च 2020 में प्रधान मंत्री की बांग्लादेश यात्रा की संभावना है। मार्च 2020 तक होने वाली अन्य संभावित घटनाक्रमों में बांग्लादेश के सूचना मंत्री की भारत की यात्रा (14-16 जनवरी, 2020), वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता, व्यापार और सुंदरबन के संरक्षण पर संयुक्त कार्य समूहों की बैठकें और भारत-बंग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री फोरम (आईबीटीआईएफ) की पहली बैठक शामिल हैं।

भूटान

भारत और भूटान आपसी विश्वास और समझ के आधार पर अद्‌वितीय और विशेष द्‌विपक्षीय संबंधों का आनंद लेते हैं और ये संबंध साझा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत और लोगों से लोगों के मजबूत जुड़ाव द्‌वारा प्रबलित हैं। वर्ष के दौरान भारत और भूटान के बीच पारस्परिक विश्वास और समझ की विशेषता वाले इस अनुकरणीय द्‌विपक्षीय संबंधों को समेकित किया गया।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

नवनिर्वाचित भारत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री ल्योनचेन डॉ. लोटे त्शेरिंग 30 और 31 मई 2019 को यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं और संवादों की परंपरा जारी रही।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 अगस्त 2019 को भूटान की राजकीय यात्रा पर गये थे अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ दर्शकों को संबोधित किया, और प्रधानमंत्री ल्योनचेन डॉ. लोटे त्सरिंग के साथ बातचीत की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने थिम्फू में दक्षिण एशियाई उपग्रह के उपयोग के लिए भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और भूटान के अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क के बीच के अंतर-संपर्क के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन, 720 मेगावाट की मंगदेछु जलविद्‌युत उर्जा परियोजना का औपचारिक उद्‌घाटन किया। भूटान में भारत द्‌वारा रुपे कार्ड जारी किया गया। रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ़ भूटान, और कानपुर, दिल्ली और मुंबई के आईआईटी और एनआईटी सिल्चर में शैक्षणिक आदान-प्रदान और एसटीईएम सहयोग बढ़ाने पर चार समझौता ज्ञापनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में दस समझौता ज्ञापनों/समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। भूटान की विस्तारित आवश्यकताओं के लिए दक्षिण एशिया उपग्रह के एक अतिरिक्त ट्रांसपोंडर पर बढ़ी हुई बैंडविड्थ देने और भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास और भूटान के लिए एक भू-पोर्टल के विकास के निर्णय के साथ भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग द्‌विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा। प्रधानमंत्री ने भूटान के रॉयल विश्वविद्‌यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भूटानी युवाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने द्‌विपक्षीय संबंधों के लोगों पर केंद्रित स्वभाव और दोनों देशों के बीच गहरे

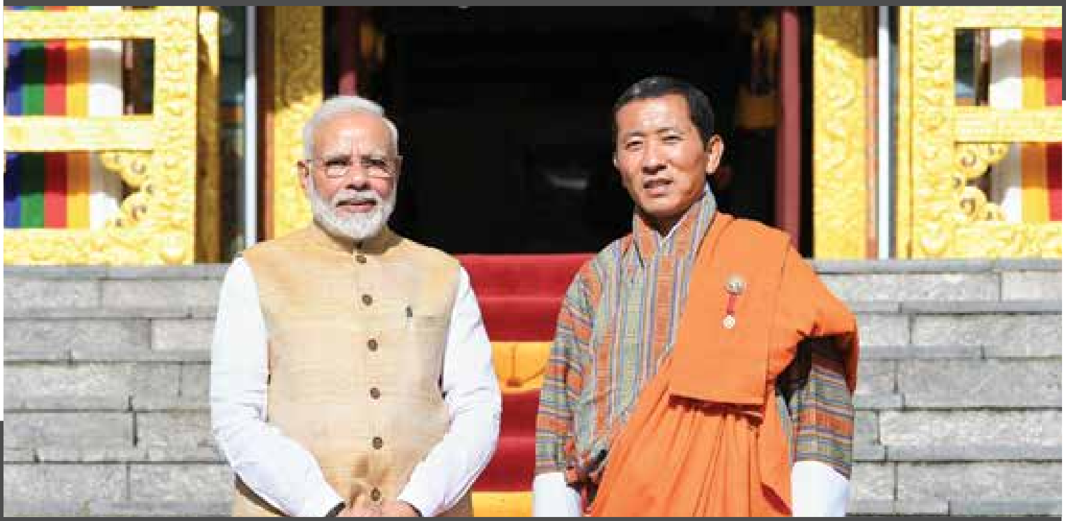

आध्यात्मिक और बौद्ध धर्म के संबंध पर प्रकाश डाला।

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद 7-8 जून, 2019 को अपनी पहली (विदेश) यात्रा पर भूटान गये। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने भूटान नरेश, महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के प्रधानमंत्री ल्योनचेन डॉ. लोटे तशेरिंग, और भूटान के विदेश मंत्री डॉ. टोंडी दोरजी से भेंट की।

भूटान के विदेशी मामलों के मंत्री ल्योनपो डॉ. तंदी दोरजी ने 17 से 23 नवंबर 2019 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और आर्थिक सहयोग, विकास साझेदारी और जल विद्युत सहयोग सहित भारत-भूटान संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने गृह मंत्री श्री अमित शाह से भी भेंट की। उन्होंने बोधगया, राजगीर और कोलकाता का दौरा भी किया। कोलकाता में उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ से भेंट की।

विदेश सचिव ने 04-05 जुलाई 2019 और 03-04 दिसंबर 2019 को भूटान की आधिकारिक यात्रा की।उन्होंने द्विपक्षीय मामलों की एक श्रृंखला पर भूटानी नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श किया, जिसमें उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान, आर्थिक और विकास सहयोग, जल-विद्युत सहयोग और लोगों से लोगों के संबंध शामिल हैं। सचिव (विद्युत) ने भूटान में चल रही और भविष्य की जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा के लिए 23-26 अप्रैल 2019 को भूटान का दौरा किया।

सचिव (पश्चिम) ने 25-27 अप्रैल 2019 को भूटान की शाही सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2018-23) की पहली योजना वार्ता आयोजित करने के लिए भूटान का दौरा किया। भूटान के विदेश सचिव ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की दूसरी योजना वार्ता के लिए 28 नवंबर से 02 दिसंबर 2019 तक भारत का दौरा किया।

विकास सहयोग

भारत सरकार ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2018-23) के लिए 4500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के सहज वितरण के लिए भारत और भूटान ने अप्रैल 2019 और नवंबर 2019 में योजना वार्ता के दो दौर के माध्यम से चर्चा जारी रखी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, कार्यान्वयन से पहले योजना वार्ता के दौरान सड़क और पुलों, क्षेत्रीय अस्पतालों, स्कूलों के निर्माण और आईसीटी, क्षमता निर्माण, उद्योग, कृषि,

ई-प्रशासन जैसे क्षेत्रों में 2556 करोड़ रुपये की लागत वाली 72 बड़ी और मध्यवर्ती परियोजनाओं की पहचान की गई है। अप्रैल 2019 और अक्तूबर 2019 में लघु विकास परियोजना समिति की दो दौर की बैठकें हुईं, जिनमें भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 573 करोड़ रुपये की लागत की 359 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) की पहचान की गई है, इनमें सिंचाई, खेत की सड़कों, ब्लॉक कनेक्टिविटी सड़कों, बुनियादी स्वास्थ्य इकाइयों जैसी सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

भारत भूटान में एक मल्टी डिसिप्लिनरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना में भी भूटान की सहायता कर रहा है।एम्स के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ टीम ने 7-9 अगस्त 2019 को भूटान का दौरा किया और भारत सरकार के माध्यम से भूटान की रॉयल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। भारत सरकार परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

जलविद्युत सहयोग

अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान 720 मेगावाट की मंगदेछु जलविद्युत परियोजना के उद्घाटन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी पनबिजली सहयोग में एक और उपलब्धि हुई। इसके साथ, संयुक्त रूप से विकसित जल विद्युत क्षमता 2000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर गई है। दोनों सरकारों ने चल रही दो प्रमुख परियोजनाओं - 1200 मेगावाट कीपुनात्संगचू -1 और 1020 मेगावाट की पुनात्संगचू-2 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निकट समन्वय बनाए रखा। 600 मेगावाट की खोलोंगछु संयुक्त उद्यम जलविद्युत परियोजना के लिए रियायत समझौते पर जल्द हस्ताक्षर करने और निर्माण कार्य शुरू करने और 2585 मेगावाट के संकोश जलाशय आधारित जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श जारी रहा।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। 2018 में, द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। दोनों सरकारें व्यापार और आपसी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 80 करोड़ रुपये की संक्रमणकालीन व्यापार सहायता सुविधा की पहली किश्त जारी की।

भूटान ने स्टैंडबाय स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय की सुविधा का लाभ उठाया है।

अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप से रुपे कार्ड की शुरूआत का पहले चरण यानि भूटान में भारत द्वारा जारी रुपे कार्ड का उपयोग आरंभ किया गया था। इससे भूटान जाने वाले भारतीय यात्रियों की नकदी ले जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी, साथ ही भूटान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भूटान की शाही सरकार की बढ़ती घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की बढ़ती पहुंच को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने भूटान को दी जाने वाली सब्सिडी वाली एलपीजी की मात्रा को 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1000 मीट्रिक टन प्रति माह कर दिया है।

संस्कृति और लोगों के बीच संबंध

लोगों से लोगों के संपर्क का सौहार्द्र और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को जीवंत बनाए रखना जारी रहा। विगत वर्षों की तरह, भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति से बहुत से भूटानी छात्र लाभान्वित हुए। भूटान सरकार के अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए कई अल्पकालिक तकनीकी पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए। भूटानी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एशियाटिक सोसाइटी,

कोलकाता द्वारा उधार दी गई धर्म राजा या झबद्रुंग (भूटान के आधुनिक राज्य के संस्थापक) की मूर्ति की अवधि को और पाँच साल के लिए बढ़ाने की सराहना की।

वर्ष के दौरान, भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय के 10 छात्रों ने चंद्रयान-2 की चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए भारत का दौरा किया। इन छात्रों ने नालंदा, गया और राजगीर सहित कई प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थलों के अलावा औद्योगिक इकाइयों (हीरो मोटर्स) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अटल टिंकरिंग लैब), टीईआरआईसंस्थानों का भी दौरा किया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, नेहरू-वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आठ छात्र (स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए) और स्नातक छात्रवृत्ति के अंतर्गत75 छात्र लाभान्वित हुए थे। आईटीईसी प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकारद्वारा 20 प्रशिक्षण स्लॉट दिए जाते हैं। भारत सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से नालंदा विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 5 कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, भूटान के कई सरकारी अधिकारियों को एलबीएसएनएए, एफएसआई, एनएसीएन और एसवीपी-एनपीए सहित प्रमुख सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति कर रहा है।

चीन

नेताओं के स्तर पर संबंध

भारत और के बीच निकट विकास साझेदारी के समग्र ढांचे के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंध 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच चेन्नई में 11-12 अक्तूबर 2019 को हुए दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के साथ मजबूत और गहरा होना जारी रहा। दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन ने एक सकारात्मक दृष्टि में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा का मूल्यांकन किया और वैश्विक मंच पर दोनों देशों की

प्रधानमंत्री में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ममल्लापुरम के ताज में होटल में मुलाकात की

बढ़ती भूमिका को प्रतिबिंबित करने के लिए भारत-चीन द्विपक्षीय बातचीत को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन ने माना कि भारत और चीन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थिरता के कारक हैं और दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को उचित प्रकार से दूर करना चाहिए और उन्हें विवाद नहीं बनने देना चाहिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को 2020 में तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए चीन आने का निमंत्रण दिया।

चेन्नई में अपने दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 13 जून 2019 को बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) लीडर्स समिट के मौके पर भी मुलाकात की, जो प्रधानमंत्री मोदी के दुबारा चुनाव जीतने, 30 जून 2019 को ओसाका में 14वें जी-20 शिखर सम्मेलन और 13 नवंबर 2019 को ब्रासीलिया में 11 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद उनकी पहली बैठक थी।

उच्च स्तरीय बातचीत

भारत और चीन के बीच नियमित उच्च स्तरीय अनुबंध के भाग के रूप में विदेश मंत्री (ईएएम) डॉ. एस. जयशंकर ने 11 से 13 अगस्त 2019 तक चीन की आधिकारिक यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने बीजिंग में स्टेट काउंसलर और चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच संवाद पर भारत-चीन उच्च-स्तरीय तंत्र (एचएलएम) की दूसरी बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक के बाद दोनों विदेश मंत्रियों ने खेल, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पारंपरिक चिकित्सा और संग्रहालय सहयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, दोनों विदेश मंत्रियों ने विदेश मंत्रालय और चीनी विदेश मंत्रालय के बीच वर्ष 2020 के लिए द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग पर प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के दौरान ईएएम ने चीन के उपराष्ट्रपति श्री वांग क्विशान से भी मुलाकात की।

सीमा मुद्दे पर बातचीत

दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने विशेष प्रतिनिधियों के काम की सकारात्मक रूप से पुष्टि की और उनसे राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर एक उचित, उपयुक्त और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निपटान के लिए पारस्परिक रूप से सहमति वाले ढांचे पर पहुंचने के अपने प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया जिस पर 2005 में दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। दोनों नेताओं ने अपनी इस बात को दोहराया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अक्षोभ सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

भारत-चीन सीमा मामलों संबंधी परामर्श और समन्वय के कार्य तंत्र (डब्लूएमसीसी) का 14 वां दौर 29 जुलाई 2019 को बीजिंग में आयोजित किया गया था और इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ स्थिति की समीक्षा की तथा आपसी विश्वास और समझ को और बढ़ाने के लिए विभिन्न आत्मविश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रगति हुई। डब्लूएमसीसी रूपरेखा के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों में शांति और अक्षोभ बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों ने सैन्य स्तर और राजनयिक स्तर पर नियमित बातचीत पर भी ध्यान दिया।

सीमा प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और चीन के राज्य पार्षद और विदेश मंत्री श्री वांग यी ने विशेष प्रतिनिधियों के 22वें दौर की वार्ता के लिए 21 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में बैठक की। अक्तूबर 2019 में चेन्नई में दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा प्रदान किए गए उनके कार्य के सामरिक मार्गदर्शन और समर्थन का स्मरण करते हुए भारत-चीन सीमा के प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया। विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत

हुए कि सीमा प्रश्न का अंतिम समाधान लंबित होने तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सीमा प्रश्न द्विपक्षीय संबंध के समग्र विकास को प्रभावित न करे।

अन्य उच्च स्तरीय बातचीत

नियमित द्विपक्षीय बातचीत की रूपरेखा के अंतर्गत वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के द्विपक्षीय संवाद तंत्र की बैठकें हुईं। निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर छठी भारत-चीन वार्ता 03 जून 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत और चीन के बीच शिक्षा पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक 16 अक्तूबर 2019 को बीजिंग में आयोजित की गई थी। वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 06 से 10 मई 2019 तक चीन की एक अभिज्ञता यात्रा की। अफगान राजनयिकों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम द्वितीय भारत-चीन संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसे 11 से 23 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली और 04 से 13 दिसंबर 2019 को बीजिंग में आयोजित किया गया था।

विदेश मंत्रालय और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के बीच उल्लिखित द्विपक्षीय बातचीत के एक भाग के रूप में सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और सीपीसी गुआंडोंग के प्रांतीय संगठन प्रांतीय समिति के सचिव श्री ली शी ने 05-08 जून 2019 तक नई दिल्ली और गुजरात का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री और अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की। उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी निवेश और पर्यटन प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए चीन की यात्रा की। चीन से श्री झांग झिनान, फ़ुज़ियान के कार्यकारी उप-राज्यपाल और श्री किन रूपी, स्थायी समिति के सदस्य और गुआंग्शी के कार्यकारी उप-गवर्नर ने भी क्रमश: जून और नवंबर 2019 में भारत का दौरा किया।

अगले वर्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ मनायी जाएगी। इस अवसर को मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन दोनों में 70 कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए चेन्नई में अपने दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान सहमति व्यक्त की थी। 70 कार्यक्रमों की एक सूची, जिसे दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से पहचाना गया, 22 नवंबर 2019 को प्रकाशित किया गया। ये कार्यक्रम, जो 2020-21 के दौरान आयोजित की जाएंगी, दोनों सभ्यताओं के साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों में उनके बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव को प्रदर्शित करेगें। वे दोनों देशों के बीच सभी स्तरों पर लोगों से लोगों के बीच परस्पर संबंधों को और गहरा करेंगे, जिसमें उनके संबंधित विधानसभाओं, व्यवसायों, शिक्षाविदों, सांस्कृतिक और युवा संगठनों के साथ-साथ रक्षा बल भी शामिल हैं।

दोनों पक्षों के विद्वानों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और सामरिक विचारकों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाते हुए 28-29 नवंबर, 2019 से चौथा भारत-चीन थिंक टैंक फोरम आयोजित की गई थी। विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्लूए) के महानिदेशक राजदूत टी.सी.ए. राघवन के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने फोरम में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया, जिसे आईसीडब्ल्यूए और चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज (सीएएसएस) द्वारा सह-आयोजित किया गया था। छठी आईसीडब्लूए - चीनी पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (सीपीआईएफए) वार्ता भी नई दिल्ली में 06 से 07 नवंबर 2019 तक आयोजित किया गया था।

जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग

भारत और चीन दोनों ने जल संसाधनों में सहयोग पर नियमित बातचीत जारी रखा है। 12-13 जून 2019 से सीमा पार नदियों पर भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ईएलएम) की 12 वीं बैठक अहमदाबाद में हुई। बैठक के दौरान, ब्रह्मपुत्र नदी की जल विज्ञान संबंधी

जानकारी के प्रावधान के लिए समझौता ज्ञापन के अनुपालन में दोनों पक्षों ने "बाढ़ के मौसम में यलुज़ंगबु / ब्रह्मपुत्र नदी की जल विज्ञान संबंधी जानकारी के प्रावधान पर कार्यान्वयन योजना" पर हस्ताक्षर किए। सतलुज नदी की जल विज्ञान संबंधी जानकारी के प्रावधान के लिए इसी तरह का समझौता ज्ञापन भी लागू है। मौज़ूदा समझौता ज्ञापनों के अनुसार, चीन ने 2019 में बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के लिए जल विज्ञान जानकारी प्रदान की।

रक्षा संबंधी आदान-प्रदान

भारत और चीन के बीच सैन्य रक्षा के लिए द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य सहयोग वर्ष भर जारी रहा। दोनों रक्षा मंत्रालयों के बीच एक भारत-चीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक 13-14 अगस्त 2019 को चीन में आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्ष 2019 के लिए विशिष्ट रक्षा आदान-प्रदान पर सहमत हुए। इस बैठक में भारत की ओर से संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) श्री आनंद राजन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और चीनी पक्ष से अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग कार्यालय के उप प्रमुख मेजर जनरल सांग यानचो ने भाग लिया। दो भारतीय नौसैनिक जहाज, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति ने अप्रैल 2019 में शेडोंग प्रांत के क्विंगडाओ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया, जो पीएलए नौसेना की 70 वीं वर्षगांठ का अवसर था। भारत-चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास (हैंड-इन-हैंड 2019) का 8वां जोड़ 06 से 20 दिसंबर, 2019 तक भारत के उमरोई में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 130 सैनिकों ने संयुक्त रूप से आतंकवाद-रोधी सहायता और मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया।

वर्ष के दौरान अन्य आदान-प्रदान में मार्च 2019 में मध्य-स्तर के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा चीन के दौरे और मई 2019 में 15-सदस्यीय राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) के अध्ययन दौरे के प्रतिनिधिमंडल के चीन दौरे शामिल थे। वर्ष के दौरान भारत और चीन के बीच बहुपक्षीय मंच पर रक्षा अनुबंधों में कोरला, झिंजियांग प्रांत में 03 से 17 अगस्त 2019 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी, बीजिंग में 20 से 22 अक्तूबर 2019 तक आयोजित 9 वें जियांगशान फोरम, 18 से 27 अक्तूबर 2019 तक वुहान में आयोजित 7 वीं अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद (सीआईएसएम) विश्व सैन्य खेल, 28 अक्तूबर से 03 नवंबर 2019 तक नानजिंग में आयोजित 7वां अंतर्राष्ट्रीय सेना कैडेट्स सप्ताह, 13 से 22 नवंबर 2019 तक गुइलिन में आयोजित आसियान रक्षा मंत्री बैठक सहित क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, और 09 से 12 दिसंबर 2019 तक बीजिंग और गुआंगझो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग प्रभाग के नेताओं की एससीओ समीक्षा शामिल थे।

व्यापार और आर्थिक संबंध

वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने अगस्त 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए चीन हेतु एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा आरसीईपी करने एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक मुद्दों से संबंधित चर्चा के लिए चीन के वाणिज्य मंत्रालय के उपाध्यक्ष श्री वांग शॉवेन के साथ बैठक की। इन मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय वाणिज्यिक मुद्दों पर वाणिज्य सचिव ने चीन के शंघाई में दूसरे चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो (सीआईआईई) में भाग लेने के लिए 04 से 08 नवंबर 2018 तक एक और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें भारत ने अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले 80 से अधिक भारतीय व्यवसायों के साथ अतिथि देश के अतिथि के रूप में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने आरसीईपी के साथ-साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर और चर्चा करने के लिए चीन के वाणिज्य मंत्रालय के सहायक मंत्री श्री ली चैंगगांग के साथ बैठक की। इन बैठकों के दौरान भारत ने बढ़ते व्यापार असंतुलन पर अपनी चिंता दोहराई और रेखांकित किया कि कृषि उत्पादों, औषध निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में जिनमें भारत ने ताकत और महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति साबित की है लेकिन

चीन में इनकी बहुत कम उपस्थिति है, को द्विपक्षीय व्यापार में प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

भारत और चीन के बीच 9 वीं वित्तीय वार्ता 25 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव डॉ. अतनु चक्रवर्ती और चीन के वित्त मंत्रालय के उपाध्यक्ष सुश्री ज़ू जियायी ने आपसी हित के मुद्दे पर व्यापक बातचीत की। छठी सामरिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) बैठक नई दिल्ली में 07-09 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी। चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) के अध्यक्ष श्री हे लिफ़ेंग के नेतृत्व में एक 50-सदस्यीय चीनी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की, जिसका नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने किया। 07 सितंबर 2019 को नीति समन्वय, अवसंरचना, संसाधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और हाई-टेक पर एसईडी कार्य समूहों की बैठकें भी हुईं। कार्य स्तर पर फार्मा के अंतर्गत फार्मा सहित विभिन्न संयुक्त कार्य समूहों/कार्य समूहों की बैठकें हुईं (07 मई 2019, बीजिंग) और सेवाओं में व्यापार (18 नवंबर 2019, नई दिल्ली) आयोजित किए गए थे। सामाजिक सुरक्षा समझौते पर वार्ता 13-15 नवंबर 2019 से नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

भारतीय चावल, रेपसीड भोजन, मछली के भोजन और मछली के तेल और तंबाकू के पत्तों के निर्यात के लिए भारत से चीन में पिछले साल तकनीकी बाजार पहुंच बाधाओं को हटाने के बाद चीन के लिए भारतीय मिर्च युक्त भोजन के निर्यात पर प्रोटोकॉल पर 07 मई 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय अंगूर, चीनी, समुद्री उत्पादों, भेषज और भारतीय आईटी और आईटीईएस सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ष प्रयास किए गए। 21 जून 2019 को शंघाई में भारतीय दवा कंपनियों के लिए चीन में औषध नियमों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। भारतीय मत्स्यपालक निर्यातकों ने अक्तूबर 2019 में क्विंगडाओ में क्विंगडाओ मरीन एक्सपो और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में भाग लिया। नैस्कॉम के नेतृत्व में एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधियों ने बीजिंग में 31 मई 2019 को एक निवेश सेमीनार में भाग लिया। 27 नवंबर 2019 को वुहान में भारतीय आईटी और भेषज निर्माण के प्रचार के लिए गोलमेज वार्ता का आयोजन किया गया। शेन्ज़ेन, शंघाई और बीजिंग में एक स्टार्टअप निवेश रोडशो आयोजित किया गया था जिसमें 15 भारतीय स्टार्टअप ने भाग लिया और अपने उत्पादों को चीनी जोखिम पूंजी निवेशकों को प्रदर्शित किया।

चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार अंगूर के निर्यात में 150% से अधिक की वृद्धि हुई जो जनवरी-अक्तूबर 2019 तक 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। समुद्री उत्पादों के निर्यात में भी 250% से अधिक की मजबूत वृद्धि देखी गई और जल्द ही 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर सकता है। अन्य कृषि वस्तुओं जैसे चीनी और चाय का निर्यात भी बढ़ा था।

सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर बातचीत

भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास करना जारी रखा। 12 अगस्त 2019 को बीजिंग में एचएलएम की सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान पर हुई दूसरी बैठक के दौरान ईएएम और विदेश मंत्री वांग यी ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, फिल्म और मीडिया सहयोग, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, राज्य और शहर स्तर के आदान-प्रदान, पारंपरिक चिकित्सा, योग और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। दो पक्षों ने सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए चार सहयोग दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए। इनमें शामिल हैं: खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान का कार्यक्रम, पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन और चीन के हुबेई प्रांतीय संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के बीच समझौता

ज्ञापन। एचएलएम की बैठक के मौके पर एक फिल्म समारोह और सांस्कृतिक प्रदर्शन सहित लोगों से लोगों के बीच संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

विदेश मंत्रालय और चीन पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन ऑफ चाइना के विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा सह-आयोजित चौथा भारत-चीन उच्च स्तरीय मीडिया फोरम, बीजिंग में 12 अगस्त 2019 को दूसरी एचएलएम के अवसर पर आयोजित किया गया था। फोरम मे दोनों देशों की प्रमुख समाचार एजेंसियों के पत्रकारों की भागीदारी देखी।

चीन के विभिन्न शहरों में जून 2019 में योग का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया जैसे गुइयांग में तियानहे पार्क, वुहान में येलो क्रेन टॉवर, हेनान में शाओलिन मंदिर और शंघाई में जेड बुद्ध मंदिर। इनका आयोजन अन्य स्थानों यथा क्िंगदाओ, वूशी, गुआंगज़ौ में भी किया गया। सभी कार्यक्रमों में चीनी योग उत्साही लोगों द्वारा बड़ी भागीदारी देखी गई। सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह का समापन बीजिंग में इंडिया हाउस में एक योग कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए चीन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। 02 अक्तूबर 2019 को गांधी जयंती के समारोह के दौरान चीन के प्रतिष्ठित चित्रकारों द्वारा महात्मा गांधी के बारह चित्रों को अनावरण किया गया था। दूतावास चीनी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गांधी- विषय पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा, उनकी आत्मकथा सहित चीनी भाषा में गांधीवादी साहित्य का वितरण और अमर चित्र कथा से महात्मा गांधी पर एक कॉमिक पुस्तक का चीनी संस्करण वितरित किया गया। शंघाई, गुआंगज़ौ और हांगकांग में वाणिज्य दूतावास ने भी सालगिरह के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें साइकिल चलाना, विद्यालय पहुंच गतिविधियां, वृक्षारोपण और रेडियो श्रृंखला शामिल हैं।

दूतावास द्वारा गुरु नानक की 550वीं जयंती स्थानीय सिख समुदाय के सहयोग से मनाई गई जिसमें कीर्तन कार्यक्रम, बच्चों द्वारा शबद का पाठ और एक लंगर शामिल था। शंघाई, ग्वांगझू और हांगकांग में वाणिज्य दूतावासों ने भी वृक्षारोपण, शबद कीर्तन सभा और गुरु नानक की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में टिकटों के वितरण जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कीं।

2006 से भारत और चीन के बीच युवा आदान-प्रदान की परंपरा को जारी रखते हुए युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार सुश्री किरण सोनी गुप्ता के नेतृत्व में 200 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने 02 से 09 जुलाई 2019 तक के साथ चीन में बीजिंग, लान्चो और दुनहुआंग का दौरा किया। ऑल चाइना यूथ फेडरेशन के नेतृत्व में एक चीनी युवा प्रतिनिधिमंडल भी 20 से 27 नवंबर 2019 तक भारत आया।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली और हुबेई प्रांतीय संग्रहालय, वुहान के बीच दूसरी एचएलएम बैठक के दौरान हुए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में हुबेई प्रांतीय संग्रहालय ने नवंबर 2019 में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में प्राचीन चीन से सांस्कृतिक अवशेष पर एक प्रदर्शनी लगाई।

कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल जून से सितंबर के दौरान राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। 2019 में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से 1005 यात्रियों के कुल 18 बैचों और नाथू-ला दर्रे के माध्यम से 341 यात्रियों के 10 बैचों ने यात्रा की।

मालदीव

विचाराधीन अवधि के दौरान भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों की कई नए क्षेत्रों में तेज प्रगति सुनिश्चित हुई। दिसम्बर 2018 के दौरान राष्ट्रपति सोलिह की भारत यात्रा के फलस्वरूप संबंधित कार्यक्षेत्र के कई नए आयाम उभरकर सामने आए जिन्हें जून 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मालदीव की यात्रा किए जाने के दौरान नई दिशा और गतिशीलता प्राप्त हुई। विचाराधीन अवधि के दौरान विभिन्न एलओसी परियोजनाएं, अनुदान परियोजनाएं और नई क्षमता निर्माण पहलें शुरू की गईं जिनके अंतर्गत सुशासन, विमानन सुरक्षा, अग्निशमन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, विशेष संरक्षा समूह आदि जैसे नए क्षेत्रों में पदार्पण किया गया। भारत ने परस्पर प्रगति और समृद्धि की आकांक्षाओं सहित मालदीव सरकार और वहां की जनता के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ किया। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, मुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाने संबंधी इच्छा का सम्मान करते हुए दोनों देशों ने एकजुटता और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय यात्राओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए।

प्रधान मंत्री को माले में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह द्वारा निशान इज़ुद्दीन विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया (8 जून, 2019)

राष्ट्रपति सोलिह ने 21-22 अप्रैल 2019 को बैंगलुरू में गैर सरकारी यात्रा की। दोनों देशों के बीच मालदीव में क्रिकेट के प्रति क्षमता निर्माण और अवसंरचनात्मक विकास पर विशेष जोर दिया गया जिसके फलस्वरूप नवम्बर 2019 में मालदीव में कोचों और अम्पायरों के लिए दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद 8-9 जून 2019 को मालदीव की पहली राजकीय यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की हाल ही में गठित पीपुल्स मजलिस को संबोधित करने के साथ-साथ मालदीव सरकार और वहां के राजनीतिक नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच (i) हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (ii) स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (iii) समुद्र के रास्ते यात्रा एवं कार्गो सेवा की स्थापना (iv) सीमाकर क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (v) मालदीव

सिविल सेवा आयोग एवं एनसीजीजी, मसूरी के बीच समझौता ज्ञापनों और (vi) आईएन और एमएनडीएफ के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान तक तकनीकी करार पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों ओर से नेताओं ने दूरस्थ संबंधों के द्वारा तटीय निगरानी रडार प्रणाली और माफिलाफुशी में एमएनडीएफ से संबंधित सीटीसी सुविधाओं को संयुक्त रूप से शुरू किया। प्रधानमंत्री द्वारा मालदीव की यात्रा किए जाने से दोनों देशों के बीच संबंधों को नए आयाम प्राप्त हुए। मालदीव सरकार ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बार-बार जतलाया।

विदेश मंत्री ने हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 3-4 सितम्बर,2019 को मालदीव की यात्रा की। विदेश मंत्री ने यात्रा के दौरान स्पीकर मौ. नशीद, विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और राष्ट्रपति सालिह से भेंट की। भारत के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री शाहिद ने संयुक्त रूप से नई परियोजना की बुनियाद रखी।

लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम विरला और राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरीवंश ने माले में आयोजित दक्षिण एशिया संसद अध्यक्ष महासम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया।

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को संयुक्त रूप से आमंत्रित किए जाने के बाद मालदीव की संसद के अध्यक्ष मौहम्मद नशीद ने 8-13 दिसम्बर 2019 के दौरान भारत यात्रा पर आने वाले मालदीव के 10 सांसदों के एक दल का प्रतिनिधित्व किया। इस शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद अहमदाबाद का भी दौरा किया। इस यात्रा के दौरान पीपुल्स मजलिस और लोकसभा के बीच संसदीय सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

13 दिसम्बर 2019 को भारत और मालदीव के बीच छठे संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से भारत के विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा की गई। इस छठे संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) में दोनों देशों की द्विपक्षीय कार्यसूची के कार्यान्वयन में अर्जित की गई उपलब्धियों की समीक्षा करने के साथ-साथ सहयोग के नए क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया। जेसीएम के दौरान दोनों देशों की वित्तीय आसूचना इकाइयों, दोनों देशों के चुनाव आयोगों और परस्पर विधिक सहायता के लिए पुनरीक्षा स्रोतों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए तथा उनका आदान प्रदान किया गया।

4 दिसम्बर 2019 को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सोलिह द्वारा एक डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस की गई। इस कांफ्रेंस के जरिए सीजीएस कामयाब के उपहार, माले में स्ट्रीट लाइटों को लगाने, मालदीव में रूपे कार्ड को शुरू करने, अददू अटोल में मछली प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने के संबंध में तीन एचआईसीडीपी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने सहित मालदीव सरकार/वहां की जनता के लिए 4 परियोजनाएं शुरू की गईं। उन्हें मालदीव को उपहार में दिया गया। थल सेना अध्यक्ष जर्नल विपिन रावत ने सितम्बर 2019 में मालदीव की यात्रा की। सितम्बर 2019 में मालदीव में संयुक्त हाइड्रोग्राफी आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई जिसकी सह-अध्यक्षता भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के तटरक्षक कमांडर ने की। मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के प्रमुख मेजर जरनल अब्दुल्ला शामाल ने जुलाई 2019 में भारत की यात्रा की। जुलाई 2019 में वार्षिक संयुक्त मिल-टू-मिल स्टाफ वार्ता का चौथा दौर शुरू किया गया।

सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अध्ययन संस्थान (आईएसएलईएस), तटीय निगरानी रडार प्रणाली (सीएसआरएस) और विदेश मंत्रालय मुख्यालय के निर्माण कार्य सहित संयुक्त ईईजेड निगरानी कार्यक्रम भी जारी रखे गए।

मालदीव के लिए 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इसके अलावा, मालदीव की बजटीय सहायता के लिए 50 मिलियन

अमेरिकी डॉलर दिए गए। 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए टी-बिल की खरीद और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से करेंसी स्वैप करार पर हस्ताक्षर किए गए तथा संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा किया गया। 34 द्वीपों पर जल और सफाई से संबंधित दो बड़ी परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं को तैनात किया गया, अद्दू अटोल में सड़क और भूमि सुधार का कार्य चिन्हित किया गया तथा संबंधित संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एचआईसीडीपी से संबंधित आईएनआर की 40 करोड़ रूपए की अनुदान परियोजना के अंतर्गत 3 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। आईएनआर की 50 करोड़ रूपए की नकद अनुदान परियोजना के अंतर्गत 16 परियोजनाओं के पूरा होने का कार्य विभिन्न चरणों में प्रवेश कर चुका है। इन्हें समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सिविल सेवा, पुलिस और एमएनडीएफ के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण का कार्य चल रहा है। मालदीव से संबंधित आईटीईसी स्लोटों को प्रतिवर्ष के आधार पर बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग 40 आईसीसीआर छात्रवृत्तियों की भी पेशकश की गई है।

भारत और मालदीव के बीच ऐतिहासिक आधार पर सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा माले में हुकुरू मिस्की/जुमा मस्जिद के बहालीकरण का कार्य भी शुरू हो चुका है।

मॉरीशस

भारत मॉरीशस को अपना नजदीकी समुंद्री पड़ोसी मानता है। निकट होने की इस अनुभूति को भारत और मॉरीशस के बीच स्थापित दशकों पुरानें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पूर्वज उन्मुखी संबंधों के कारण और मजबूती प्राप्त हुई है। दोनों देशों के बीच सुदृढ़ विकासगत सहयोग, रक्षा संबंधों व्यापार, वाणिज्यिक मामलों, उच्चस्तरीय यात्राओं और स्कोलरशिप और आईटीईसी कार्यक्रमों आदि के जरिए और अधिक मजबूती प्राप्त हुई है। विचाराधीन वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच कई उच्चस्तरीय यात्राएं होने के साथ-साथ ई-टेबलेट जैसी परियोजनाओं, इएनटी अस्पताल, मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के प्रथम चरण, गहन सुरक्षा और सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि को भी पूरा किया गया है।

नवंबर 2019 में मॉरीशस में चुनाव होने के बाद श्री परविन्द जुगनाथ दूसरी बार मॉरीशस के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई देते हुए भारत की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया।

विचाराधीन वर्ष के दौरान भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों में और मजबूती आई है। इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान प्रदान हुआ जो दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और तालमेल का स्पष्ट प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किए जाने के बाद मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री परविन्द कुमार जुगनाथ ने 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रीपरिषद् के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। मॉरीशस वह अकेला देश था जिसे इस अवसर पर बिम्सटेक देशों के बाहर से आमंत्रित किया गया।

भारत द्वारा मॉरीशस में दो परियोजनाएं शुरू की गईं। पहली परियोजना ईएनटी अस्पताल है और दूसरी परियोजना मैट्रो एक्सप्रेस का पहला चरण है जिनका उदघाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 3 अक्तूबर 2019 को डीवीसी के जरिए किए।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल ने मॉरीशस में भारतीय श्रमिकों के आगमन की 185वीं जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में 2 नवम्बर, 2019 को मॉरीशस का दौरा किया। यह दिन प्रतिवर्ष मॉरीशस में "अप्रवासी दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री श्री परविन्द जुगनाथ ने नवम्बर 2019 में दूसरी बार मॉरीशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद 3-10 दिसम्बर 2019 के दौरान अपनी पत्नी के साथ भारत की निजी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर के साथ परस्पर बैठकें कीं। विचाराधीन वर्ष के दौरान श्री जुगनाथ की यह तीसरी भारत यात्रा थी। मई और दिसम्बर में की जाने वाली अपनी यात्राओं के अलावा उन्होंने 20-28 जनवरी 2019 के दौरान वाराणसी में मुख्य अतिथि के रूप में 15वें प्रवासी दिवस (पीबीडी) में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा की।

मॉरीशस में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 9 अप्रैल 2019 को आईसीसीआर प्रतिष्ठान दिवस मनाया। इस अवसर पर माननीय शिक्षामंत्री श्रीमती लीला देवी डुकुन मुख्य अतिथि थीं। आईटीसी दिवस 2019 का आयोजन 17 सितम्बर 2019 को किया गया। गांधी जी की 150वीं जन्मशती के अवसर पर मिशन ने महात्मा गांधी संस्थान में एक समारोह का आयोजन किया जिसमें अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ माननीय माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमति लीला देवी डूकुन और कला एवं संस्कृति मंत्री श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन ने भाग लिया। 12 नवम्बर 2019 को भारतीय उच्चायोग द्वारा गुरूनानक देव जी की 550वीं जन्मशती भी मनाई गई।

भारत और मॉरीशस के बीच 19-23 अगस्त 2019 के दौरान नई दिल्ली में हाइड्रोग्राफी संयुक्त समिति की 12वीं बैठक का आयोजन किया गया। विचाराधीन वर्ष के दौरान आईएनएस शार्दुल ने 26-28 अक्तूबर 2019, आईएनएस दर्शक ने 25-28 नवम्बर 2019, 9-12 दिसम्बर 2019 और 23-26 दिसम्बर 2019 को मॉरीशस सरकार के अनुरोध पर संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मॉरीशस की मैत्रीपूर्ण यात्राएं कीं। आईएनएस शार्दुल और आईएनएस दर्शक दोनों ही जलपोत हैं।

353 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत मॉरीशस में भारत द्वारा सहायता प्राप्त कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 3 अक्तूबर 2019 को डीवीसी के जरिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा ईएनटी अस्पताल परियोजना और मैट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। हाल ही के वर्षों में मॉरीशस में जन उन्मुखी विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं जिनके जरिए दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में और मजबूती आई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डीबीसी के संयुक्त उद्घाटन के दौरान दो नई परियोजनाओं के लिए सहायता, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रैनल ट्रांसप्लांट यूनिट, चार मैडिक्लीनिक और दो क्षेत्रीय स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की घोषणा की गई। अक्तूबर 2019 में भारत और मॉरीशस के बीच ई-विद्याभारती, आरोग्य भारती (ई-वीबीएबी) नेटवर्क परियोजना में प्रतिभागिता के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए।

म्यांमार

म्यांमार और भारत के बीच एक साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत और मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। म्यांमार एकमात्र ऐसा आसियान देश है जिसके साथ भारत की 1600 किलोमीटर से अधिक की साझी भूमि सीमा है, जिससे यह आसियान देशों का प्रवेश द्वार बन जाता है। म्यांमार भारत के दो प्रमुख विदेश नीति उद्देश्यों के संगम पर है: 'एक्ट ईस्ट' और 'पड़ोसी देश प्रथम'। इस संबंध को उच्च स्तरीय यात्राओं, एमओयू पर हस्ताक्षर करने, चल रहे विकास सहयोग, नियमित आईटीईसी और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाकर और रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर मजबूत किया गया है।

म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट की भारत की यात्रा 2020 की पहली छमाही में होने की आशा है। अन्य प्रत्याशित आयोजनों में भारत में म्यांमार के केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष की यात्रा और 2020 की पहली छमाही में उप एनएसए द्वारा म्यांमार की यात्रा शामिल है।

राजनीति

उच्च स्तरीय दौरे: भारत के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने 29-30 मई 2019 को नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। इसके बाद जुलाई 2019 में म्यांमार रक्षा बलों के कमांडर-इन-चीफ, जनरल जनरल मिन औंगलाइंग की भारत यात्रा हुई। पीएम ने 3 नवंबर 2019 को बैंकाक विदेश कार्यालय में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर स्टेट काउंसलर से मुलाकात की। नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2019 को विदेश सचिव के स्तर पर भी परामर्श आयोजित किए गए।

नै पेई ताव में भारत संपर्क कार्यालय का उद्घाटन: 1 अक्तूबर 2019 को भारत ने म्यांमार की राजधानी नै पेई ताव में एक नया संपर्क कार्यालय खोला। इस नए कार्यालय के खुलने के साथ, भारत का अब म्यांमार के 4 प्रमुख शहरों में प्रतिनिधित्व है यथा यंगून में दूतावास, मांडले और सिटवे में दो वाणिज्य दूतावास और नै पेई ताव में एक संपर्क कार्यालय।

म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट की भारत की यात्रा 2020 की पहली छमाही में होने की संभावना है। अन्य प्रत्याशित आयोजनों में भारत के म्यांमार के केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष की यात्रा और 2020 की पहली छमाही में उप एनएसए द्वारा म्यांमार की यात्रा शामिल है।

विकास संबंधी सहयोग

म्यांमार के साथ भारत के समग्र द्विपक्षीय सहयोग में विकास सहयोग एक प्रमुख विशेषता है। इस क्षेत्र में हमारी भागीदारी और सहायता कृषि अनुसंधान और शिक्षा, आईटी और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए दीर्घकालिक, स्थायी और प्रासंगिक संस्थानों की स्थापना के लिए प्रमुख कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे की स्थापना से लेकर महत्वपूर्ण पहल तक है। इन पहलों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे अधिकांशत: पूरी तरह से अनुदान-पोषित हैं, हालांकि भारत परिवहन और संचार से लेकर कृषि और खेत मशीनीकरण और राजमार्ग विकास तक की परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त के माध्यम से बड़ी सहायता का विस्तार है। भारतीय सहायता से जुड़ी परियोजनाओं का कुल संभाग लगभग 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें से लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाएं पूरी तरह से अनुदानित हैं।

सिटवे पोर्ट के लिए पोर्ट ऑपरेटर : कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिटवे पोर्ट के लिए पोर्ट ऑपरेटर को नवंबर, 2019 में नियुक्त किया गया था। जलमार्ग घटक पर काम पूरा हो गया है, हालांकि, पलेत्वा से ज़ोरिनपुई तक सड़क घटक का कार्य चालू है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) : सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का तीसरा वर्ष पूरा हो चुका है। चौथे वर्ष बीएडीपी के लिए 28 परियोजनाएं 2019 में शुरू हो गई हैं।

रखाईन राज्य विकास कार्यक्रम (आरएसडीपी) : रखाईन राज्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने राज्य में विकास कार्यक्रमों के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। जुलाई, 2019 में, 250 पूर्वनिर्मित घर रखाइन राज्य में म्यांमार को सौंपे गए। दिसंबर 2019 में रखाइन राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को 20,000 राहत सामग्री किट प्रदान की गई।

रक्षा सहयोग

भारत-म्यांमार रक्षा संबंध में 2019 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ

और मजबूती आयी। पर्याप्त उच्च-स्तरीय दौरे, सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और स्थापित परस्पर अभिक्रिया वाले तंत्र ने बेहतर तरीके से कार्य किया।

उच्च स्तरीय दौरे

- जहां कार्यात्मक स्तर की सद्भावना यात्रा नियमित रूप से जारी रही, वहीं 1 अप्रैल 2019 से महत्वपूर्ण दौरे आयोजित किए गए। तकालीन रक्षा सचिव, श्री संजय मित्रा ने मई 2019 में म्यांमार का दौरा किया, जो रक्षा क्षेत्र में अनुबंधों और नियमित आदान-प्रदान की सूची में शामिल हैं। जुलाई 2019 में, म्यांमार के रक्षा बलों के कमांडर-इन-चीफ वरिष्ठ जेनरल मिन औंगहि्लंग ने भारत का दौरा किया जिसके दौरान रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन और व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान-प्रदान पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरे एमओयू के अनुसरण में अभिसमय बातचीत सूचना फ्यूजन सेंटर हिंद महासागर क्षेत्र, नई दिल्ली और समुद्री क्षेत्रीय सहयोग केन्द्र, यंगून के बीच शुरू हुआ है, जो क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र में बहुत अधिक पारदर्शिता ला रहा है।
- गोवा समुद्री सभा, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पारस्परिक यात्रा और उच्च कमान पाठ्यक्रम जैसे दौरे/ संगोष्ठी मध्य और वरिष्ठ स्तर पर दोनों सशस्त्र बलों के अधिकारियों के बीच समझ को मजबूत करने में सहायता करते हैं।

नौसेना सहयोग

समुद्री सुरक्षा सहयोग संबधी समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता सितंबर 2019 में हुई थी। समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, जलविज्ञान आदि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई।

समुद्री गश्ती विमानों को शामिल करने और साल में दो बार समन्वित गश्त की आवृत्ति में वृद्धि जैसी पहल ने इन गश्तों की प्रभावकारिता में वृद्धि की है। 18-22 अक्तूबर 2019 से आईएनएमईएक्स के दूसरे संस्करण के लिए विशाखापत्तनम में दो म्यांमार नौसेना के जहाज तैनात किए गए थे। इन पहलों का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री व्यापार के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना था।

सैन्य प्रशिक्षण : पिछले एक वर्ष में, आईटीईसी-1 योजना के अंतर्गत 126 प्रशिक्षुओं को भारत के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त किया गया था। संरचित पाठ्यक्रमों के अलावा भारतीय सशस्त्र बल मोबाइल प्रशिक्षण टीमों (एमटीटी) ने संयुक्त राष्ट्र शांति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया और फरवरी और सितंबर-अक्तूबर, 2019 में दो पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। एमटीटी द्वारा 5 अन्य पाठ्यक्रम भी भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किए गए। अप्रैल, 2019 में म्यांमार वायु सेना के पायलटों के लिए ऑब्जर्वर सॉर्टी के साथ मिग-29 लड़ाकू एयरक्रू के लिए विषय विशेषज्ञ एक्सचेंज आयोजित किया गया। अक्तूबर, 2019 में म्यांमार की लड़ाकू टीम को प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर सहयोग के साथ अंग्रेजी भाषा, जलविज्ञान, चिकित्सा में प्रशिक्षण दिया गया है।

क्षमता निर्माण : एक भारतीय वायु सेना की मेट स्क्वाड्रन टीम ने अगस्त-नवंबर, 2019 से म्यांमार वायु सेना के दो मेट स्क्वाड्रन की स्थापना की और प्रशिक्षण प्रदान किया। म्यांमार में एक तटीय निगरानी प्रणाली की स्थापना की जा रही है।

स्थापित तंत्रों के अंतर्गत बातचीत : चौथी सेना और चौथे वायु सेना के कर्मचारी वार्ता क्रमश: 13-15, मार्च 2019 को नै पै ताव और 18-20 सितंबर 2019 को यंगून में हुई। 15वीं क्षेत्रीय सीमा समिति की बैठक 9-12 दिसंबर 2019 के बीच हुई।

वाणिज्य

2018-19 में भारत-म्यांमार द्विपक्षीय व्यापार 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2017-18 के 7.53% की वृद्धि है। भारत म्यांमार का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2018-19 के दौरान म्यांमार

को भारत का निर्यात 1205.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और म्यांमार से आयात 521.49 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। निवेश के संदर्भ में, भारत अक्तूबर, 2019 तक 31 भारतीय उद्यमों *(1846 उद्यमों द्वारा 50 देशों से 81.598 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल अनुमानित निवेश में से)* से 768.567 मिलियन डॉलर के स्वीकृत निवेश के साथ 11 वें स्थान पर है। भारत में म्यांमार का निवेश 8.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। म्यांमार से प्रमुख आयात वस्तुएं सेम और दालें, लकड़ी, धातु आदि हैं। म्यांमार में भारत का निर्यात कृषि-वस्तु, रसायन, ईंधन, दवा आइटम, मशीनरी आदि हैं। 2018-19 के दौरान म्यांमार के साथ सीमा व्यापार 154.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है जो दो भूमि सीमाओं को पार करने वाले बिंदुओं - मणिपुर में मोरेह-तमू और मिज़ोरम में ज़ोखथर-रिखावदार के माध्यम से हुआ। म्यांमार में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों के प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

उच्च स्तरीय दौरे : कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जुलाई 2019 में बिम्सटेक मंत्रियों की कृषि बैठक के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त, उद्योग और वाणिज्य मंत्री, असम सरकार, श्री चंद्र मोहन पटोवरी ने भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के बारे में बोलने के लिए विधायक और वरिष्ठ अधिकारी के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

संयुक्त कार्य समूह : स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग में पहली संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के नए कार्यक्रम (2018-2021) के अंतर्गत पहली जेडब्लूजी जैसी महत्वपूर्ण बैठकें क्रमशः अप्रैल 2019 और सितम्बर 2019 में हुईं।

कारोबारी प्रतिनिधिमंडल का दौरा : जून, 2019 में भारतीय कंपनियों ने कोमप्लास्ट प्रदर्शनी में भाग लिया; 40 भारतीय स्वास्थ्य सेवा कंपनियों ने अक्तूबर 2019 में यंगून में मेडेक्स 2019 में भाग लिया और लगभग 74 भारतीय प्रतिभागियों ने नवंबर 2019 में मेनफूड में अपने उत्पादों का प्रदर्शन भारत के व्यापार संवर्धन परिषद, एसोचैम और वाणिज्य विभाग, भारत के संरक्षण में किया।

स्वास्थ्य मंत्रालय को एंटी-रैबीज टीके का दान : भारत ने सितंबर 2019 में म्यांमार को एंटी-रेबीज वैक्सीन के 10,000 शीशियां प्रदान किया।

प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन

वर्ष 2019-20 में नागरिक पक्ष के संबंध में 240 स्लॉटों का उपयोग आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। अक्तूबर 2019 में यंगून विश्वविद्यालय में नया **हिंदी भाषा पाठ्यक्रम** शुरू किया गया था।

विदेश मंत्रालय ने 7 अक्तूबर 2019 को मांडले में म्यांमार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईआईटी) में **बिग डेटा एनालिटिक्स संबंधी ई-आईटीईसी कार्यक्रम** का रिमोर्ट से उद्घाटन किया।

भारत ने म्यांमार के अधिकारियों जैसे प्रशासकों, टाउन प्लानर्स; चुनाव अधिकारी; पुलिस अधिकारी; सांसदों; न्यायपालिका के अधिकारी और अन्यों को अंग्रेजी, आईटी, लेखा और वित्त, आदि में प्रशिक्षण देना जारी रखा, इनमें से कुछ निम्न थे:

चुनाव अधिकारी: म्यांमार के केंद्रीय चुनाव आयोग (यूईसीएम) हेतु सात पाठ्यक्रमों को नई दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग और 2019 में यूईसीएम अधिकारियों के लिए नै पे ताव द्वारा संचालित किए गए थे। दो पाठ्यक्रमों को पहले 2018 में पूरा किया गया था।

23 से 29 अगस्त, 2019 तक भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेएआई), भोपाल में **40 जजों/न्यायिक अधिकारियों** के पहले बैच ने प्रशिक्षण लिया। सभी 400 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशासक : शासन व्यवस्था और नेतृत्व प्रशिक्षण में 34 टाउनशिप प्रशासक (15-27, जुलाई 2019) और

28 टाउनशिप प्रशासक (18-30 नवम्बर, 2019) के लिए दो मध्यावधि कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी), लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), नई दिल्ली द्वारा 1-23 नवंबर, 2019 से म्यांमार शैक्षिक प्रशासकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

पुलिस प्रशिक्षण : वर्ष 2019 में 250 से अधिक म्यांमार पुलिस अधिकारियों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

भारत में म्यांमार के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण : हॉकी, बैडमिंटन और निशानेबाजी में खिलाड़ियों के एक दल को 29 सितम्बर से 28 अक्तूबर 2019 तक 30वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के लिए भारत में प्रशिक्षित किया गया। भविष्य में इस तरह के प्रशिक्षण के फ्रेमवर्क को औपचारिक बनाने के लिए खेल में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर चर्चा हो रही है।

भारत 23 आईआईटी में म्यांमार सहित आसियान छात्रों के लिए 1000 एकीकृत पीएचडी फैलोशिप भी प्रदान कर रहा है। आईआईटी-मद्रास प्रतिनिधिमंडल ने यंगून का दौरा किया और अक्तूबर 2019 में प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और भावी छात्रों के साथ बातचीत की। आईआईटी दिल्ली के एक और प्रतिनिधिमंडल ने 15-18 दिसंबर 2019 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्रों में अपने अनुभवों को शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और प्राचार्यों के साथ साझा करने के लिए म्यांमार का दौरा किया।

संस्कृति

इस वर्ष कई कार्यक्रम जैसे कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती, गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती, और म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

एक पूर्ण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र 2020 के मध्य तक यंगून में शुरू हो जाएगा। भारतीय संस्कृति, हिंदी और नृत्य के एक शिक्षक के अलावा एक पूर्णकालिक निदेशक की तैनाती के कारण इस क्षेत्र में जुड़ाव का स्तर भी बढ़ गया है और वर्तमान केंद्र हिंदी, योग और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए नियमित कक्षाएं संचालित करता है।

नेपाल

भारत और नेपाल सदियों पुराने सभ्यता के संबंधों के आधार पर मित्रता और सहयोग के घनिष्ठ संबंध सहभाजित करते हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्राओं और बहुआयामी आर्थिक और विकास सहयोग से यह जन केंद्रित साझेदारी को सुदृढ़ हुई है। घनिष्ठ आर्थिक एकीकरण, बृहत्तर संयोजकता, सशक्त विकास साझेदारी और नेपाल के साथ लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्क, प्रमुख द्विपक्षीय उद्देश्य हैं। नेपाल के साथ निरंतर विस्तारित साझेदारी भारत सरकार की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के अनुरूप है।

उच्च स्तरीय यात्राएं

भारत सरकार के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। विदेश मंत्री, डॉ. एस. जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली के साथ भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 21 और 22 अगस्त 2019 को नेपाल का दौरा किया। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों

देशों के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को और सशक्त करने के कारकों का पता लगाया गया। संयुक्त आयोग की 21 अगस्त 2019 को हुई बैठक से इतर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग नेपाल के बीच तकनीकी सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस वर्ष मंत्रिस्तरीय, अधिकारी और तकनीकी स्तरों पर 30 से अधिक विनियमों में गहन संबंध देखे गए। वर्ष भर में कार्यात्मक/तकनीकी स्तर पर लगभग 20 द्विपक्षीय तंत्रों की बैठक हुई जिसमें आर्थिक और विकास सहयोग, जल संसाधन और बिजली सहयोग, संस्कृति, रक्षा और सुरक्षा और संयोजकता परियोजनाओं जैसे मुद्दे शामिल थे। इसी प्रकार दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मंत्री/ वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर एक दर्जन से अधिक आदान-प्रदान हुए।नेपाल के महान्यायवादी श्री अग्नि प्रसाद खारेल ने 25-30 अगस्त 2019 को भारत की एक अवलोकन यात्रा पर 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और उन्होंने भारत के महान्यायवादी से भेंट की और भारत के विधि और न्याय मंत्री से भी भेंट की। ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री (आईसी) श्री आर.के. सिंह ने काठमांडू में 11-12 सितंबर 2019 को आयोजित तीसरे नेपाल अवसंरचना शिखर सम्मेलन में मुख्य अभिभाषण दिया। नेपाल के विदेश सचिव श्री शंकर दास बैरागी ने भारत की यात्रा की और 17 जुलाई 2019को भारत के विदेश सचिव श्री विजय गोखले से भेंट की और परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत और नेपाल के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दीघर्काल से और व्यापक पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग है। बटालियन स्तर का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' भारतीय सेना और नेपाल सेना द्वारा नियमित रूप से भारत और नेपाल में आयोजित किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' का 14वां सत्र 03-16 दिसंबर 2019 को नेपाल के सालझांदी में आयोजित किया गया था।

नेपाल सेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने 22-25 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में प्रमुख आपदा प्रबंधन संस्थानों का दौरा किया और नेपाल सेना के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने भारत में 13-20 अक्तूबर 2019 को रक्षा उत्पादन उद्योगों का दौरा किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित 59 वें पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में, वाइस एडमिरल श्रीकांत, एवीएसएम, कमांडेंट, एनडीसी ने 26-28 अगस्त, 2019 को नेपाल के अध्ययन दौरे पर भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित 16 सदस्यीय बहु-राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नेपाल के मकालू पर्वत के लिए भारतीय सेना का पहला पर्वतारोहण अभियान 29 मार्च से 30 मई 2019 तक चलाया गया था। इसके अलावा, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने नेपाल अधिवासित गोरखा पूर्व सैनिकों की कल्याणकारी गतिविधियों की समीक्षा के लिए सितंबर और नवंबर 2019 में नेपाल का दौरा किया था। नेपाल के सेनाध्यक्ष ने जनरल अधिकारियों से परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा के लिए अमंत्रित किया।

दोनों पक्षों की सुरक्षा एजेंसियों ने सूचनाओं के आदान-प्रदान सहित घनिष्ठ सहयोग भी साझा किया। कानून प्रवर्तन एजेंसियां सीमा प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करती हैं। महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल और महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस बल के बीच चौथी समन्वय बैठक 20-22 नवंबर 2019 तक नेपाल में आयोजित की गई थी। नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए सात (07) प्रशिक्षण और अध्ययन दौरे अप्रैल से नवंबर 2019 तक भारत में आयोजित किए गए थे।

संयोजकता और विकास भागीदारी

विकास में सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का एक प्रमुख क्षेत्र है। पहले से ही प्रतिबद्ध परियोजनाओं

को पूरा करना, अनुदान और ऋण सहायता पर ध्यान दिया गया। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में संयोजकता के महत्व का संज्ञान लेते हुए, बुनियादी ढांचे के विकास और संयोजकता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रेल संपर्क, सड़क, एकीकृत चेक पोस्ट, पॉलिटेक्निक, पुलिस अकादमी, लिंक नहर और 900 मेगावाट की अरुण-3 जल विद्युत परियोजना जैसी सीमा पार संयोजकता और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा नेपाल को दिए गए 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की चार क्रेडिट लाइनों के अंतर्गत नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्य सहित अनेक पनबिजली, सिंचाई और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।

सरकार ने कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया है। परियोजनाओं की प्रगति पर दो विदेश सचिवों के स्तर पर बारीकी से नजर रखी जाती है, जिन्होंने 11 जुलाई 2019 को अपनी पांचवीं वीडियो-कांफ्रेंस की थी। नेपाल में भारत के राजदूत और नेपाल के विदेश सचिव की सह-अध्यक्षता में 'निगरानी तंत्र' ने परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने और बाधाओं को दूर करने के लिए 08 जुलाई 2019 को सातवीं बैठक की। नियमित समीक्षा के परिणामस्वरूप परियोजना कार्यान्वयन में बेहतर प्रगति हुई है।

भारत में मोतिहारी को नेपाल में अमलेखगंज से जोड़ने वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित और वित्त पोषित दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का 10 सितंबर 2019 को दोनों प्रधानमंत्रियों ने रिमोट द्वारा उद्घाटन किया था। बीरतनगर में एकीकृत चेक पोस्ट का 21 जनवरी 2020 को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने रिमोट द्वारा उद्घाटन किया था। भारत में रक्सौल को नेपाल में काठमांडू से जोड़ने वाली नई ब्रॉडगेज विद्युतीकृत रेल लाइन की प्रारंभिक इंजीनियरिंग-सह-यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मई 2019 में पूरा किया गया था और भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता से रेल लाइन के अगले कदम के रूप में अंतिम स्थान के संचालन के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है। उत्तराखंड के टनकपुर बैराज को भारत-नेपाल सीमा से जोड़ने वाली लिंक नहर परियोजना पर 2019 में काम शुरू किया गया।

भारत सरकार की सहायता से संपन्न सर्वोत्कृष्ट परियोजना नेपाल-भारत मैत्री पॉलिटेक्निक संस्थान का भव्य समारोह 05 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था। वर्ष के दौरान तराई सड़क परियोजना पर काफी प्रगति हुई; 14 सड़क पैकेज में से सात (07) पूर्ण होने वाले हैं। वर्ष 2019 में, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संयोजकता और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्रों में लगभग 20 उच्च प्रभावकारी सामुदायिक विकास परियोजनाएं (पूर्व में लघु विकास परियोजनाएं) पूरी की गई। भारत सरकार ने नेपाल में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में काम करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को 60 एंबुलेंस और 12 स्कूल बसें भी भेंट कीं।

नेपाल में आवास क्षेत्र में भूकंप के बाद भारत सरकार की सहायता से पुनर्निर्माण कार्य तेजी से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार को आवंटित नेपाल के गोरखा और नुवाकोट जिलों में भूकंप प्रभावित 50,000 लाभार्थियों में से 45,000 से अधिक भारत सरकार समर्थित घरों (अर्थात् 90 प्रतिशत कार्य) पूरे हो चुके हैं। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने 21 जनवरी 2020 को आवास पुनर्निर्माण में की गई प्रगति का अवलोकन किया। भूकंप के बाद शिक्षा क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में मार्च 2019 में सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की नियुक्ति के बाद नेपाल के गोरखा और नुवाकोट जिले में आठ (08) स्कूलों का निर्माण शुरू किया गया था और यह कार्य जारी है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटैच) को दिसंबर 2019 में सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य के लिए नियुक्त किया गया था और स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति पर कार्रवाई की जा रही है।

भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू की गई 'कृषि में नई साझेदारी' के तत्वाधान में फरीदाबाद के केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान में नेपाली वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के लिए 25 नवंबर से 24 दिसंबर, 2019 को एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

काठमांडू और सिलीगुड़ी के बीच नियमित बस सेवा को भारत के राजदूत श्री एम.एस. पुरी और नेपाल के भौतिक अवसंरचना ढांचे और परिवहन मंत्री श्री रघुबीर महासेठ ने संयुक्त रूप से 26 अगस्त 2019 को काठमांडू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत नेपाल के लगभग पूरे तीसरे देश के व्यापार के लिए पारगमन प्रदान करने के अलावा नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। वित्त वर्ष 2017-18 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 17% से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2018-18 में 8.27 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। दोनों सरकारें व्यापार और पारस्परिक निवेश को सुगम बनाने के लिए संलग्न और उपाय करती रहती हैं।

भारतीय बाजारों तक नेपाल की अभिगम्यता को और अधिक सुगम बनाने के लिए, समग्र द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए और नेपाल के पारगमन व्यापार को सुगम बनाने के लिए दोनों पक्षों ने भारत-नेपाल संधि व्यापार और पारगमन संधि की समीक्षा करने के लिए द्विपक्षीय विचार-विमर्श शुरू किया। इस संबंध में सितंबर और नवंबर 2019 में दो द्विपक्षीय बैठकें हुई थीं।

भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के बीच अप्रैल 2018 में हुई सहमति के अनुसार नेपाल जाने वाले द्विपक्षीय और पारगमन कार्गो की आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क के विकास कार्य संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करके बहु-मॉडल मार्गों के संचालन के लिए विचार-विमर्श चल रहा है।

संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंध

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और नेपाल का सुदृढ़ सहयोग है। भारत प्रतिवर्ष नेपाली छात्रों को भारत में अध्ययन के अवसर प्रदान करने हेतु लगभग 3000 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत अंतर्गत में तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नेपाल के सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 250 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। नेपाल सरकार के लगभग 60 अधिकारियों को काले धन को वैध बनाने विरोधी और आतंक वित्तपोषण के मामलों का प्रतिकार करने के लिए 2019 में फरीदाबाद और बेंगलुरु में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और मादक पदार्थ प्रतिकार अकादमी में प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अलावा नेपाल के प्राधिकार दुरुपयोग जांच आयोग के 42 अधिकारियों ने 2019-20 में गुजरात फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, गांधीनगर में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर काठमांडू में भारतीय दूतावास ने 'माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में योग' और 'माउंट एवरेस्ट के गेटवे, स्यांगबोचे में योग', सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती के उपलक्ष्य में नेपालराष्ट्र बैंक ने 23 सितंबर 2019 को नेपाली रूपए 100/- नेपाली रूपए 1000/- और नेपाली रूपए 2500/- के मूल्यवर्ग में चांदी के स्मारक सिक्के जारी किए। भारतीय दूतावास द्वारा 'सिख हेरिटेज ऑफ नेपाल' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के आठ स्कूलों के छात्रों को लगभग 200 सौर लैंप किट वितरित करने सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।

क्षेत्रीय सहयोग

भारत और नेपाल परस्पर हितों के उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर सहयोग करते हैं।

वर्ष 2019 में, संयुक्त राष्ट्र और बिम्सटेक सहित बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंच पर सहयोग जारी रहा।

नेपाल के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री, श्री उपेंद्र यादव ने "दक्षिण पूर्व एशिया के लिए डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति के 72 वें सत्र" के लिए 02-06 सितंबर 2019 को दौरा किया और भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 19-21 नवंबर 2019 को आयोजित "चिकित्सा उत्पादों की अभिगम्यता पर 2019 विश्व सम्मेलन" एसडीजी 2030 को अधिप्राति में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. युबा राज खातीवाड़ा ने 03 और 04 अक्तूबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित "33 वें भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन" में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था।

नेपाल के वन और पर्यावरण मंत्री श्री शक्ति बहादुर बसनेट ने 23-25 अक्तूबर 2019 को वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण की संचालन समिति की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए 08-11 सितंबर 2019 को भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित कन्वेंशन टू कॉम्बैट मरुस्थलीकरण सीओपी-14 के प्रतिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

नेपाल सेना के एक प्रतिनिधिमंडल (एससीओ के संवाद सहयोगी के रूप में नेपाल की क्षमता में) ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर 2019 को आयोजित ''शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य राष्ट्रों के लिए सैम्य चिकित्सा पर प्रथम सम्मेलन'' में भाग लिया।

पाकिस्तान

भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत की सुसंगत स्थिति यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह कोई भी आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में मुद्दा द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल हो।

द्विपक्षीय बातचीत

प्रधानमंत्री मोदी को 26 मई 2019 को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने फोन कर उन्हें चुनावी जीत की बधाई दी गई। प्रधान मंत्री मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया और संयुक्त रूप से गरीबी से लड़ने के लिए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के अपने पूर्व सुझाव को याद किया। प्रधान मंत्री मोदी ने यह भी बल दिया कि क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्वास और हिंसा से मुक्त वातावरण बनाना आवश्यक था। प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर के जल्द परिचालन की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

सीमापार आतंकवाद

पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध बनाने के भारत के प्रयासों को सीमा पार आतंकवाद और भारत के खिलाफ हिंसा के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन से कमजोर किया जा रहा है। 14 फरवरी 2019 को, पाकिस्तान स्थित और समर्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में सीमा पार आत्मघाती आतंकी हमले में भारतीय सुरक्षा बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत बार-बार पाकिस्तान से आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने और पाकिस्तान के अंदर हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए जैशे मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करता रहा है। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैशे मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ गुप्तचर नीति एक आतंकवाद-रोधी प्रथम हवाई हमला किया। पुलवामा सीमा पार आतंकी

हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान को दिए गए तरजीही देश (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तान से आने या निर्यात होने वाले सभी सामानों पर 200% का सीमा शुल्क लगा दिया। भारत ने 19 अप्रैल 2019 को एलओसी के पार होने वाले व्यापार को भी बंद कर दिया, जिसमें रिपोर्ट मिली थी कि अवैध हथियार, मादक पदार्थ और नकली मुद्रा की फंडिंग के लिए पाकिस्तान आधारित तत्वों द्वारा एलओसी पर व्यवसायिक मार्गों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का अकारण ही उल्लंघन किया, जिसमें भारत में सीमा पार आतंकवादी घुसपैठ के लिए कवर-फायर प्रदान करना शामिल था। पाकिस्तान बलों द्वारा अकारण गोलीबारी की 3000 से अधिक घटनाओं में अब तक 31 भारतीयों की मौत हुई। भारत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक चैनलों और सैन्य परिचालन निदेशकों के माध्यम से कठोर विरोध दर्ज किया। सीमा पर शांति और शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को 2003 के संघर्ष विराम की समझ का पालन करने के लिए कहा गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान की सभी तरह की दी जाने वाली सहायता बंद नहीं होता तब तक भारतीय सेना सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ के सभी प्रयासों का करारा जबाव देती रहेगी।

पाकिस्तान द्वारा शत्रुतापूर्ण दुष्प्राचार और एकतरफा कार्रवाई

संविधान के अनुच्छेद 370 के बारे में भारतीय संसद के निर्णय के बाद, पाकिस्तान भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार में लगा हुआ है और दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों की एक खतरनाक तस्वीर पेश करने के प्रयास में लगा हुआ है। 7 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने एकतरफा उपायों की घोषणा की, जिसमें राजनयिक संबंधों को निम्नतर करना, द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करना और भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी बस, ट्रेन और डाक सेवाओं को निलंबित कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार और लोगों के बीच संबंध में कमी आयी। भारत के खिलाफ 'जिहाद' के आह्वान समेत कई गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए गए हैं, जो पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा भारत के लिए पूरी तरह से आंतरिक मामलों में किए गए हैं।

भारत ने इस तरह की सभी कार्रवाइयों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पाकिस्तान के तथ्यों और मनगढ़ंत बयानों को गलत बताया। भारत के प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक सक्रियता के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने, क्षेत्र की चिंताजनक स्थिति को पेश करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके दुरुपयोग की कोशिशों को सफलतापूर्वक और प्रभावी रूप से विफल किया गया है। देशों ने यह माना है कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामले, जो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का आंतरिक मामले हैं। देशों ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि वह अपने क्षेत्र को आतंकवाद के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल न होने दे।

पाकिस्तान से शुरू होने वाले आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय फोकस

पाकिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद के खतरों को अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में सरकार के प्रयास सफल रहे। 1 मई 2019 को, संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध समिति ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी के रूप में जेएसएम के नेता मसूद अज़हर को नामित किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने अक्तूबर 2019 में प्लेनरी ने आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित चिंताओं को जारी रखने के कारण ग्रे सूची में पाकिस्तान को बनाए रखने को अधिसूचित किया। एफएटीएफ ने पाकिस्तान द्वारा अपने आतंकी वित्तपोषण जोखिम को समाप्त करने के लिए प्रगति में कमी के साथ गंभीर चिंता व्यक्त की और फरवरी 2020 तक पाकिस्तान को अपनी पूर्ण कार्य योजना को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव का मामला

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 17 जुलाई 2019 को अपने सर्वसम्मत फैसले में पाया कि जाधव मामले पर उसका अधिकार क्षेत्र था और 15-1 के मत से यह निर्णय दिया कि पाकिस्तान ने वियना समझौते के अंतर्गत प्रासंगिक दायित्वों का उल्लंघन किया था। असंतुष्ट एकमात्र न्यायाधीश पाकिस्तान से था। अदालत ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह श्री जाधव तक तकाल कूटनीतिक पहुंच प्रदान करे और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करे। विदेश मंत्री ने जुलाई 2019 में इस मामले पर संसद में अपने आप ही वक्तव्य दिया।

हैदराबाद फंड मामला

2 अक्तूबर 2019 को, यूके उच्च न्यायालय ने 70 साल पुराने हैदराबाद फंड मामले में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें लंदन में नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक द्वारा 35 मिलियन पाउंड फंड के पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया गया। दावों के कारण यह फंड लंदन में नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक के पास पड़ा हुआ है। भारत के पक्ष में फैसला देते हुए अदालत ने पाकिस्तान के उन दावों को खारिज कर दिया कि फंड का उद्देश्य हथियारों के शिपमेंट के लिए भुगतान या तकालीन निजाम द्वारा पाकिस्तान को एकमुश्त उपहार के रूप में दिया गया था। न्यायालय ने पाकिस्तान को भारत द्वारा लागत के आधार पर भारत को 2.8 मिलियन पाउंड का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

परमाणु प्रतिष्ठानों और केन्द्रों की सूची का आदान-प्रदान

01 जनवरी 2020 को, भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के खिलाफ समझौते के अंतर्गत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और केन्द्रों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह दोनों देशों के बीच इस तरह की सूची का 29 वां लगातार आदान-प्रदान था, पहला 01 जनवरी 1992 को हुआ था।

धार्मिक तीर्थस्थल

करतारपुर कॉरिडोर: गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में एक आसान और सुगम पहुंच और श्री गुरु नानक देवजी की 550 वीं जयंती मनाने के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों की दीर्घ काल से लंबित मांग को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री ने 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इससे पहले, भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्तूबर 2019 को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, नरोवाल की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष भर दैनिक आधार पर पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा साहिब, करतारपुर में भारतीय और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) तीर्थयात्रियों की वीजा-मुक्त यात्रा की व्यवस्था है। 5000 से अधिक तीर्थयात्री किसी भी दिन कॉरिडोर के माध्यम से गुरुद्वारा साहिब करतारपुर जा सकते हैं। 31 दिसंबर 2019 तक, 30,000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्रियों ने गलियारे के माध्यम से सफलतापूर्वक तीर्थयात्रा की है।

1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत तीर्थयात्रा : धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्राओं के संबंध में 1974 के भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत तीर्थयात्रियों के दौरे का नियमित आदान-प्रदान की सुविधा दी गयी। 2019 में भारतीय तीर्थयात्रियों के सात समूहों/जत्थों ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के तीर्थयात्रियों के पांच समूहों ने भारत का दौरा किया। इनमें शामिल हैं- 1898 भारतीय तीर्थयात्री बैसाखी (अप्रैल, 2019) के दौरान पाकिस्तान गए; 416 तीर्थयात्रियों ने महाराजा रणजीत सिंह जी की शहादत के दौरान दौरा किया (जून-जुलाई 2019); 476 तीर्थयात्रियों ने नगर कीर्तन (जुलाई-अगस्त 2019 के महीने में श्री गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर) का दौरा किया; और 3529 भारतीय

तीर्थयात्रियों ने श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती मनाने के लिए नवंबर 2019 के महीने में पाकिस्तान का दौरा किया।

कैदियों और मछुआरों संबंधी मानवीय मुद्दे

सरकार पाकिस्तान की हिरासत में बंद कैदियों के मुद्दे को अधिक महत्व देती है और भारत उनकी जल्द रिहाई और प्रत्यावर्तन के मामले को लगातार उठाती रही है। कूटनीतिक पहुंच के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत 2008 में हुए समझौते के अनुसार, 1 जुलाई 2019 और 1 जनवरी 2020 को एक-दूसरे की हिरासत में कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया गया। 01 जनवरी 2020 को आदान-प्रदान की गई सूचियों के अनुसार, भारत की हिरासत में 267 पाकिस्तानी नागरिक कैदी और 99 मछुआरे हैं। पाकिस्तान ने माना है कि उनके यहां 55 नागरिक कैदियों और 227 भारतीय मछुआरों के हिरासत में हैं।

लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत 2014 से पाकिस्तान की हिरासत से मछुआरों सहित 2132 भारतीयों की रिहाई और प्रत्यावर्तन करने में सफल रहा है। इसमें शामिल 364 भारतीय वे हैं जो 2019 में वापस आ गए और 20 भारतीय मछुआरे जिनकी रिहाई और प्रत्यावर्तन 6 जनवरी, 2020 को हुई। सरकार ने 4 भारतीय नागरिक कैदियों और 106 शेष भारतीय मछुआरों को रिहा करने की मांग की है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन वे अभी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। भारत ने जल्द ही कूटनीतिक पहुंच और पाकिस्तान की हिरासत में शेष भारतीय नागरिकों की रिहाई और प्रत्यावर्तन की मांग की है।

इसके अलावा, भारत ने 83 लापता भारतीय रक्षा कर्मियों के मुद्दे को उठाया है, जिनमें युद्ध बंदी भी शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पाकिस्तान की हिरासत में हैं। हालांकि, पाकिस्तान ने अब तक उनकी हिरासत को अस्वीकार करता रहा है। भारत एक-दूसरे की हिरासत में मानसिक रूप से अस्वस्थ्य कैदियों के मुद्दे को हल करने के लिए एक मेडिकल टीम भेजने का मुद्दा भी उठाता रहा है। पाकिस्तान को कैदियों के लिए पुनर्जीवित संयुक्त न्यायिक समिति की शीघ्र यात्रा आयोजित करने के लिए भी कहा गया है।

सेशेल्स

भारत और सेशेल्स के बीच निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हैं। संबंधों की यह प्रगाढ़ता आंतकवाद और सीमापार के अन्य अपराधों के विरूद्ध लड़ाई, विकासगत भागीदारी, सांस्कृतिक सहयोग, छात्रवृत्ति और आईटीईसी कार्यक्रमों के जरिए क्षमता निर्माण सहित सुदृढ़ रक्षा और सुरक्षा सहयोग से भी परिलक्षित है। भारत ने अपनी राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में सेशेल्स की सहायता करके सेशेल्स में अपनी विकासगत सहायता के कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया है।

भारत ने सेशेल्स सरकार और वहां के लोगों के साथ अपने निकट संबंधों को जारी रखा है जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए हैं।

विचाराधीन वर्ष के दौरान सेशेल्स के पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री वालेस कांसग्रो ने 30 अगस्त से 3 सितम्बर 2019 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ काम्बैट डी सर्टिफिकेशन कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) से संबंधित कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी14) के चौदहवें सत्र में भाग लिया। मॉरीशस के स्वास्थ्य मंत्री श्री जीनपाल एडम ने 23-28 सितम्बर 2019 के दौरान भारत की यात्रा की। भारत आने के बाद उन्होंने चैन्नई और बैंगलूरू के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंन भारत के स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा की गई।

सेशेल्स के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मामले में विकासगत सहयोग कार्य एक सशक्त आधार है। परस्पर सहयोग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने के प्रयोजनार्थ जून 2018 में लघु विकास परियोजनाओं पर किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत हस्ताक्षरित कई छोटी और जन अनुकूल परियोजनाएं चल रही हैं। इस वर्ष के दौरान इनमें से अनेक परियोजनाओं को शुरू किया गया जिनमें से कई परियोजनाएं कार्यान्वयन चरण से गुजर रही हैं। छोटी परियोजनाओं के अलावा सौर पी.वी. परियोजना जैसी अन्य परियोजनाओं का कार्य भी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। जून 2019 में सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा में सौर पीवी के प्रतिष्ठान और प्रचालन का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा अक्तूबर 2019 में 46 सोशल हाउसिंग यूनिट, नवंबर, 2019 में तीन आंतरिक द्वीपों में विक्टोरिया अस्पताल और 6 अन्य अस्पतालों का कार्य भी पूरा हो चुका है।

भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग का दायरा पर्याप्त रूप से आगे बढ़ा है। पिछले वर्षों में भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डाकुओं और अन्य आर्थिक अपराधों के कारण इस सहयोग का महत्व बढ़ गया है। यह सहयोग कार्य भारत सरकार की “सागर” नीति (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) पहल के एक भाग के रूप में हिंद महासागर के देशों के बीच बेहतर सहयोग के लिए सरकार की नीति के अनुरूप है। निम्नलिखित जलपोत अर्थात् आईएनएस शार्दुल, सुजाता मागर, तरंगिणी/सुदर्शिनी और भारतीय तटरक्षक पोत सारथी ने 6-10 अप्रैल 2019, आईएनएस कोच्ची ने 23-30 जून 2019, आईएनएस शार्दुल ने 21-22 अक्तूबर 2019, भारतीय तटरक्षक विक्रम ने 12-15 दिसंबर 2019 और आईएनएस दर्शक ने 30 दिसंबर 2019 से 18 जनवरी 2019 के दौरान सेशेल्स की यात्राएं कीं।

अन्य कार्यक्रमों के अलावा सेशेल्स स्थित भारतीय उच्चायोग ने 9 अप्रैल 2019 को आईसीसीआर स्थापना दिवस के अवसर पर और 6 सितम्बर 2019 को आईटीईसी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें आईटीईसी अलुमनी, स्थानीय सरकार के पदाधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मिशन द्वारा 2 जून 2019 को “गांधी @150” मनाने के लिए साइकिल रेस और रैली का आयोजन किया गया। मिशन ने पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से 5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 150 पौधे लगाए। मिशन ने 15 जून 2019 को 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) का आयोजन किया जिसमें सेशेल्स की कुल आबादी के एक प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। 2 अक्तूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मिशन ने मालार्पण समारोह के साथ उस दिन को मनाया। इस अवसर पर भारतीय उच्चायोग और सेशेल्स डाक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से महात्मा गांधी का डाक टिकट भी जारी किया गया।

एक 9 सदस्यी लवानी समूह (महाराष्ट्र का लोक नृत्य) ने सेशेल्स में “कैरोल उत्सव” और दीवाली के समारोह में भाग लेने के लिए 24-28 अक्तूबर 2019 के दौरान सेशेल्स की यात्रा की।

12 नवंबर 2019 को उच्चायोग द्वारा गुरूनानक देव की 550वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गुरूनानक देव जी पर एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरूनानक देव जी के जीवन पर एक लघु डिजिटल विडियो दिखाया गया इसके बाद उनके बारे में एक वृतचित्र भी दिखाया गया।

श्रीलंका

वर्ष 2019-20 में श्रीलंका के साथ भारत के संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों यथा वाणिज्य, व्यापार, रक्षा, विकासगत सहयोग और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत और श्रीलंका के बीच उच्चस्तरीय बारम्बार

राजनीतिक यात्राओं के होने से परस्पर सहयोग और समझबूझ में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आपात एंबुलेंस परियोजना और चैन्नई तथा जाफना के बीच उड़ानों के शुरू करने जैसी जनउन्मुखी और मांग प्रचालित परियोजना के सफल कार्यान्वयन के कारण भी दोनों देश एक दूसरे के अधिक निकट आए हैं। इस अवधि के दौरान भारत अपनी "पहले पड़ोस" नीति और "सागर" नामक सिद्धांत के अनुसार श्रीलंका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता रहा है।

2019-20 में उच्च स्तरीय बारम्बार यात्राओं, जन उन्मुखी परियोजनाओं के कार्यान्वयन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में निकट सहयोग के कारण श्रीलंका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए हैं।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाल श्रीसेना ने 30-31 मई, 2019 के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रीमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। 16 नवम्बर को राष्ट्रपति के पद का चुनाव होने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोटावापा राजपक्षे ने 20-30 नवम्बर, 2019 को भारत की राजकीय यात्रा की। राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। श्रीलंका के विकास कार्य नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री मलिक समरविक्रमा ने व्यापार संबंधी मुद्दों पर परिचर्चा करने के लिए 6-8 अगस्त 2019 के दौरान भारत की यात्रा की।

भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में श्रीलंका के प्रति अपनी एकजुटता अभिव्यक्त करने के लिए अप्रैल, 2019 में ईस्टर डे आतंकी हमले के बाद 9 जून, 2019 को श्रीलंका की यात्रा की। भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के साथ-साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति को भारत आमंत्रित करने के प्रयोजनार्थ श्रीलंका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के फौरन बाद प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 18-19 नवंबर, 2019 के दौरान श्रीलंका की यात्रा की। संचार, इलैक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून और न्यायमंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कोलंबो में राष्ट्रमण्डल विधि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 5-7 नवम्बर, 2019 के दौरान श्रीलंका की यात्रा की।

जहां तक परस्पर विकास के मामलों में सहयोग का संबंध है, वर्ष 2019-20 के दौरान श्रीलंका भारत में विकासगत सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में से एक था। 4000 शेष मकानों में से महत्वकांक्षी भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 50 हजार मकानों की आंशिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में 2200 से अधिक मकान बन चुके हैं। मई, 2017 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान घोषित दस हजार मकानों के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। इस प्रकार श्रीलंका में मकान बनाने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता के अंतर्गत 60,000 मकान बनाए जाने हैं जिसमें से अब तक 48,200 से अधिक मकान बन चुके हैं।

23 जून, 2019 को श्रीलंका के पूर्वी राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 15.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के अंतर्गत श्रीलंका भर मे आपात एंबुलेंस सेवा के प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया गया। इस संबंध में प्रायोगिक चरण की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीलंका की सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि इस सेवा को उनके पूरे देश में विस्तारित किया जाए।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई उच्चस्तरीय समुदाय विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपीएस) को कार्यान्वित करने का कार्य जारी रखा। उसे लावा में सरस्वती केन्द्रीय कॉलेज के उन्नयन का कार्य, उत्तरी राज्य में स्कूलों के पुनरूद्धार, डाम्बुला में गोदामों के निर्माण और जाफना सांस्कृतिक केन्द्र का कार्य पूरा हो गया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान बट्टीकालाव में उध्यापन अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के साथ-साथ सर्जिकल यूनिट के निर्माण कार्य, पूर्वी राज्य में "ग्राम शक्ति" परियोजना के अंतर्गत छह सौ मकानों के निर्माण तथा दक्षिण राज्य में ग्राम शक्ति परियोजना-II के अंतर्गत छह सौ मकानों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

नवम्बर, 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत ने श्रीलंका में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को शुरू करने (400 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और सुरक्षा एवं आतंकवाद से लड़ने (50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्जे की घोषणा की थी। भारत की ओर से 318 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा दिए जाने के अंतर्गत 18 जुलाई, 2019 को कोलम्बों में 91.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत माहो से लेकर ओमान थाई तक उत्तरी रेलवे लाइन के उन्नयन का कार्य किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध सुदृढ़ रहे। श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत भी वैश्विक आधार पर श्रीलंका के सर्वाधिक बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2018 के दौरान दोनों देशों के बीच परस्पर व्यापार की कीमत बढ़ाकर 4.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई थी। 2018 में भारत की ओर से श्रीलंका को किए जाने वाले निर्यात की कीमत 4.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जबकि श्रीलंका से भारत को किए जाने वाले निर्यात की कीमत 0.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। भारत 2018 के दौरान लगभग 173 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश के साथ श्रीलंका की एफडीआई में सहयोग देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत श्रीलंका आने वाले पर्यटकों (18% पर्यटक अंतर्प्रवाह) का स्रोत बाजार भी है। इसके अलावा बंदरगाह क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए 28 मई, 2019 को भारत, जापान और श्रीलंका के बीच कोलंबो साउथ पोर्ट के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल के विकास पर एक त्रिपक्षीय सहयोग ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक दल, महानिदेशक आयुद्ध उपकरण निर्माण सेवा, महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, श्रीलंका के नौसेना अध्यक्ष, उपनौसेना अध्यक्ष, नौसेना कमांडर और तटरक्षक बल के महानिदेशक द्वारा भारत की यात्रा किए जाने सहित दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तरीय यात्रा किए जाने से भारत और श्रीलंका के संबंधों में और प्रगाढ़ता आई। 8-9 अप्रैल 2019 को कोलंबों में रक्षा सचिव स्तर पर भारत और श्रीलंका के बीच छठी वार्षिक रक्षा वार्ता हुई। इसके अलावा स्लीनेक्स (7-12 सितंबर, 2019), मित्र शक्ति (1-14 दिसंबर, 2019), मिलन, (18-28 मार्च, 2019) जैसे सशस्त्र बल अभ्यास संचालित किए जाने के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच समन्वयन और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच परस्पर सहयोग और एकजुटता बढ़ाने संबंधी प्रयासों के एक भाग के रूप में 15-18 जून 2019 को श्रीलंका के सशस्त्र बलों के 160 कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए बोध गया की विशेष तीर्थयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया गया।

दोनों देशों के बीच विचाराधीन अवधि के दौरान सांस्कृतिक संबंधों और जनता के बीच परस्पर संबंधों को सुदृढ़ किया गया। यह प्रयास दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी थे। इस अनुक्रम में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती, गुरूनानक देव की 550वीं जन्मशती, चैन्नई और जाफना के बीच हवाई उड़ानों की शुरूआत सहित विभिन्न कार्यकलाप संचालित किए गए।

श्रीलंका के विदेश संबंध, कौशल विकास, रोजगार और श्रम संबंध मंत्री श्री दिनेश गुनावरना ने 08-10 जनवरी, 2020 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। नवंबर 2019 में कार्यभार संभालने के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री की यह पहली विदेश यात्रा थी।

विदेश मंत्री श्री दिनेश गुनावरना की यह यात्रा नवंबर 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री गोटाबाया राजपक्षे की भारत यात्रा के बाद है।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने 09 जनवरी 2020 को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के लिए श्रीलंका के विदेश मंत्री की मेजबानी की। इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के विदेश मंत्री ने हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडेय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार से भी भेट की।

2

दक्षिण-पूर्व एशिया और एशिया-प्रशांत

आस्ट्रेलिया

वर्ष 2019 के दौरान शीर्ष स्तर पर दोनों देशों के बीच अक्सर बातचीत होती रही जिसमें 29 जून, 2019 को ओसाका में जी 20 शिखर सम्मेलन के मौके पर और 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों (पीएम) की मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया एक संस्थापक सदस्य के रूप में डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के लिए भारत के नेतृत्व वाली पहल गठबंधन में शामिल हो गया। इसने भारत की हिंद-प्रशांत महासागरों की पहल (आईपीओआई) का भी समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2019 में अजहर मसूद को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए यूएनएससी के प्रस्ताव को भी सह-प्रायोजित किया।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष सीनेटर मारिज पायने से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय बैठकों के लिए चार बार मुलाकात की- 10 जुलाई 2019 को लंदन में राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक के मौके पर; 2 अगस्त 2019 को बैंकॉक में आसियान संबंधित बैठकों के मौके पर; 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर और 23 नवंबर 2019 को जापान के नागोया में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर। ऑस्ट्रेलिया के विदेश सचिव सुश्री फ्रांसिस एडम्सन और रक्षा सचिव ग्रेग मोरीर्ट ने 9 दिसंबर 2019 को तीसरी 2+2 विदेश और रक्षा सचिवों (2+2) वार्ता के लिए नई दिल्ली का दौरा किया।

गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी 7-8 नवंबर 2019 को 'आतंकवाद का वित्तपोषण नहीं हेतु मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' में भाग लेने के लिए मेलबर्न गए। एमओएस ने ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। ऑस्ट्रेलिया के संसाधन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मंत्री मैट कैनावन ने 26-29 अगस्त 2019 को भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने मंत्रिस्तरीय समकक्षों और संसाधन उद्योग के नेताओं के साथ मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री डेन तेहन ने 19-21 नवंबर, 2019 तक शिक्षा क्षेत्र से भारत में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के साथ बैठक की। उन्होंने नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष के साथ 5 वीं ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद् की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

2019 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में 19 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय समुद्री वार्ता; 19 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय वार्ता; 4 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता, 13 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हिंद-प्रशांत पर भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्ता, 2 मई 2019 को कैनबरा में आतंकवाद से निपटने पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक; 30 अप्रैल 2019 को मुंबई में नागरिक परमाणु सहयोग पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त समिति की बैठक; और 15 अप्रैल 2019 को सिडनी में पर्यटन पर जेडब्लूजी शामिल है।

व्यापार और निवेश बढ़ता रहा। पहली ट्रेजरी-नीति आयोग आर्थिक नीति वार्ता अप्रैल 2019 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की भारत आर्थिक रणनीति के जवाब में, भारत सरकार (जीओआई) ने सीआईआई को दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरक का लाभ उठाने के लिए एक दर्पण रणनीति तैयार करने का काम सौंपा है जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध तीव्रता से बढ़े। नौसेना कर्मचारियों के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए 2-4 सितंबर 2019 तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। एयूएसआईएनडीईएक्स की तीसरा पुनरावृत्ति, दोनों देशों के बीच प्रमुख द्विवार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास अप्रैल 2019 में विशाखापत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। द्विपक्षीय विशेष बल अभ्यास एयूएसटीआरएएचआईएनडी ऑस्ट्रेलिया में सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ सेवा कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से वार्षिक द्विपक्षीय सेवाओं को आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक जहाज शौर्य ने नवंबर 2019 में डार्विन का दौरा किया।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या लगभग सात लाख (जनसंख्या का 2.8%) है और इसका आकार और महत्व बढ़ रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया में कुशल प्रवासियों के शीर्ष स्रोत के रूप में उभरा। वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 90,000 छात्रों के साथ भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है।

विदेश मंत्री सीनेटर मैरीसे पायने ने 15-16 जनवरी 2020 को भारत का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने रायसीना वार्ता-2020 में भाग लिया था और माननीय विदेश मंत्री और माननीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थीं। अन्य प्रत्याशित यात्रा हैं :

(ii) संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) में भाग लेने के लिए फरवरी 2020 (24-28 फरवरी) में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री श्री साइमन बर्मिंघम की यात्रा। मंत्री बर्मिंघम को ऑस्ट्रेलिया-भारत बिजनेस एक्सचेंज के हिस्से के रूप में फरवरी में अपनी यात्रा के दौरान भारत में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की भी आशा है, जिसका समन्वय ऑस्ट्रेड कर रहा है।

(iii) सीनेटर मैट कनावन, संसाधन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया मंत्री के मार्च 2020 में भारत आने की आशा है। यह यात्रा 26-29 अगस्त 2019 को सीनेटर कैनवन की

भारत यात्रा का अनुसरण करेगी, जहां उन्होंने अपने मंत्रिस्तरीय समकक्षों और संसाधन उद्योग जगत के नेताओं के साथ मुलाकात की थी।

ब्रुनेई

भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों के साथ निकटता से जुड़ रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ब्रुनेई अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और आसियान की केंद्रीयता के अंतर्गत भारत का एक प्रमुख भागीदार है। ब्रुनेई दारुस्सलाम के साथ भारत के संबंध जोश भरा और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से मजबूत हुए। ईएएम ने सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में 74 वें यूएनजीए सत्र के मौके पर विदेश मामलों के द्वितीय मंत्री, दातो एरियन से मुलाकात की और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। ब्रुनेई सरकार की सहमति से अक्तूबर 2019 में इसरो के अपने टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलि कमांड सेंटर (टीटीसी) को ब्रुनेई में एक बड़े स्थल पर स्थानांतरित करने और केंद्र के लिए निर्माण कार्य शुरू करने के प्रस्ताव से अवगत कराया गया।

भारत और ब्रुनेई के बीच सचिव स्तर के विदेश कार्यालय परामर्श (7 वां) के दौरान नई दिल्ली में 24 जून 2019 को सचिव (पूर्व) सुश्री विजय ठाकुर सिंह और ब्रुनेई के स्थायी सचिव, विदेश मंत्रालय श्रीमती हजा दयांग सती नोरिशान के बीच पूरे द्विपक्षीय संबंध पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्रों में अधिक निकट सहयोग के लिए सहमत हुए। भारत ब्रुनेई के साथ कृषि अनुसंधान में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए सहमत हुआ।

कमांडर, रॉयल ब्रुनेई सशस्त्र बल (आरबीएएफ) ने 4-8 अगस्त 2019 को भारत का दौरा किया और सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों के साथ व्यापक चर्चा की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग पर जेडब्ल्यूजी स्थापित करने पर सहमति हुई। 30 अप्रैल से 2 मई 2019 तक पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी (डब्लूपीएनएस) में दो भारतीय नौसेना अधिकारियों की भागीदारी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ावा दिया।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें चावल के विशेषज्ञ शामिल थे, ने 14-17 अक्तूबर 2019 को कृषि और वानिकी पर 5 वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए ब्रुनेई का दौरा किया। मंत्री ने इस बैठक के मौके पर ब्रुनेई के अपने समकक्ष के साथ मुलाकात की और चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ब्रुनेई को भारतीय सहायता की पेशकश की। आसियान के स्थायी सचिव और ब्रुनेई के विदेश मंत्री महामहिम एमाले एब्द रहमान द्वारा एक दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने 13-14 दिसंबर 2019 को दिल्ली डायलॉग इलेवन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

कम्बोडिया

भारत और कंबोडिया में प्राचीन काल से करीबी सभ्यता और सांस्कृतिक संबंध हैं, जो आज भी जारी हैं। जबकि जनवरी 2018 में प्रधान मंत्री हुन सेन की भारत यात्रा और 2019 के दौरान उच्च स्तर पर अनुवर्ती यात्रा आवश्यक गति प्रदान किया, वहीं दोनों देशों ने आधिकारिक और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने और गहरा करने के लिए उत्सुकता का प्रदर्शन किया। विकास सहयोग, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण गतिविधियां द्विपक्षीय सहयोग पर केंद्रित रहीं।

8 वर्षों के अंतराल के बाद, 3 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में द्वितीय भारत-कंबोडिया विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, सचिव (पूर्व) और श्रीमती ईट सोफिया, राज्य सचिव, विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कंबोडिया ने की और हमारे द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण समीक्षा की।

कंबोडिया के साथ विकास सहयोग दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और बहुआयामी संबंधों के बढ़ते आयाम का गठन करता है। भारत ने जल संसाधन विकास, मंदिरों के संरक्षण और संरक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कंबोडिया को अपनी सहायता जारी रखी। भारत सरकार की अनुदान सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कंबोडियाई लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, डब्लूएपीसीओएस ने पहले ही कंपोंग चाम प्रांत में 1,190 अफ्रिडव हैंड पंप स्थापित किया था और बंतेई मीनची प्रांत, कंबोडिया में शेष 310 हैंड पंपों की स्थापना के लिए ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह 4 दिसंबर 2019 को आयोजित किया गया था। 2015 में इसकी स्थापना के बाद से, 15 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं (क्यूआईपी) स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण और कौशल विकास आदि के क्षेत्रों में लागू की गई हैं। लाइन मंत्रालयों द्वारा दर्शाई गई अत्यधिक रुचि को देखते हुए, क्यूआईपी परियोजनाओं की संख्या के बाद से प्रति वर्ष 5 परियोजनाओं के पहले की सीमा से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। 2019-20 के दौरान, 10 क्यूआईपी परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं।

टा प्रोहम मंदिर की जीर्णोद्धार परियोजना के पहले दो चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) वर्तमान में 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से तीसरे चरण का काम कर रहा है। भारत ने प्रिव विहार (आईसीसी) की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में प्रिव विहार, शिव मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य करने की अपनी इच्छा से अवगत कराया और यह कार्य 2019-20 में शुरू होने की आशा है।

आईटीईसी के अंतर्गत कंबोडियाई अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान सुचारू रूप से आगे बढ़ा। अब तक, 1981 में कंबोडिया में शुरू होने के बाद से 1750 से अधिक कंबोडियाई नागरिकों को आईटीईसी कार्यक्रमों से लाभ मिला। कंबोडियाई सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम ने भारत सरकार की अगुवाई में, कम्बोडिया के नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए आईटीईसी विशेषज्ञों को भेजा।

रॉयल कंबोडियाई सशस्त्र बलों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैप्सूल के संचालन के साथ रक्षा सहयोग जारी रहा। जून 2018 में आरएम की यात्रा के दौरान घोषित किए गए डिमिनिंग उपकरणों की खरीद के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के सक्रिय विचार के अंतर्गत है। कम्बोडियाई रक्षा बलों के सदस्यों ने भी आईटीईसी छात्रवृत्ति के अंतर्गत भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करना जारी रखा। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत की नौसेना की सद्भावना यात्राओं के हिस्से के रूप में दो भारतीय नौसेना जहाजों, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस किल्टान ने 5-8 सितंबर 2019 से 5-दिवसीय सद्भावना यात्रा पर सिहानोकविले पोर्ट, कंबोडिया का दौरा किया, जिसमें रॉयल कंबोडियन नेवी के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास और खेल संबंधी क्रियाकलाप शामिल थे।

पीएसआरबी विश्वविद्यालय, नोम पेन्ह में बौद्ध और संस्कृत अध्ययन में आईसीसीआर के पीठ की स्थापना के समझौता ज्ञापन के साथ इस अवधि के दौरान पनपे सांस्कृतिक संबंध को 2021-22 तक और तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाया। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ता रहा। दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत और कंबोडिया का दौरा किया। एफआईईओ बैनर तले, 27 भारतीय कंपनियों ने पहली बार नोम पेन्ह में 18 सितंबर 2019 को सीएएमबीयूआईएलडी में भाग लिया।

इंडोनेशिया

प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) का निर्माण करने के लिए वर्ष जुलाई 2019 में ओसाका में जी20 शिखर सम्मेलन और नवंबर 2019 में बैंकॉक में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान दो बार मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 5 सितंबर 2019 को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की, जिसमें विदेश मंत्री सुश्री रेटनो मार्सुडी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी शामिल है।

13 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में छठी जेसीएम हुई थी। अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के आचे प्रांत के बीच वास्तविक, आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संयुक्त कृतक बल (जेटीएफ) की स्थापना की गई और सबांग में बंदरगाह संबंधी बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए 7 दिसंबर 2019 को बांदा आचे में पहली बैठक हुई।

परिचालन स्तर पर रक्षा सहयोग के अंतर्गत तीन सेवाओं के बीच नियमित रूप से अनुबंध था। द्वितीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (नवंबर 2019), वायु सेना वार्ता के लिए तीसरा वायु सेना (अक्तूबर 2019), सेना स्टॉफ वार्ता के लिए 8 वीं सेना (अगस्त 2019) और नौसेना स्टॉफ वार्ता (अगस्त 2019) के लिए 10वीं नौसेना अभ्यास आयोजित की गईं। तीसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया (आईएआई) वरिष्ठ अधिकारियों का रणनीतिक संवाद (महानिदेशक स्तर) 19 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

वर्ष 2018-19 में इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा और इसका 21.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल व्यापार है। 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार क्षेत्र के विस्तार के लिए कई प्रयास किए गए थे, जिसमें भारत में भारतीय कृषि वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच पर विशेष ध्यान दिया गया था। जैसा कि 2018 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान घोषित किया गया था, जकार्ता में सीआईआई के प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन द्विपक्षीय निवेश की सुविधा के लिए 5 सितंबर 2019 को विदेश मंत्री द्वारा किया गया था।

विभिन्न द्विपक्षीय संवाद तंत्र के अंतर्गत वर्ष के दौरान आदान-प्रदान हुआ। प्रथम भारत-इंडोनेशिया कौंसुलर संवाद जुलाई 2019 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, जिसकी सह-अध्यक्षता श्री संजय अरोड़ा, सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने की थी। कौंसुलर, इमिग्रेशन, वीजा और आपसी हित के संबंधित मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दूसरी नीति नियोजन वार्ता 11 जुलाई 2019 को जकार्ता में हुई। दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक मुद्दों पर अभिसमय की संभावना तलाशी।

आसेह प्रांत, इंडोनेशिया के प्रतिनिधि सभा के 10 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल-एक (कानून, राजनीति और सरकार) की 14-20 जुलाई, 2019 तक भारत की यात्रा के साथ इंडोनेशिया के साथ संसदीय संबंध और मजबूत हुए। डॉ. आगस हर्मेंटो, नेशनल हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव फॉर इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट के डिप्टी स्पीकर भी 19-23 अगस्त 2019 को भारत आए। श्री अशोक मलिक, नीति सलाहकार, एमईए ने बाली में 5-6 दिसंबर 2019 को आयोजित 12 वें बाली लोकतंत्र मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

भारत और इंडोनेशिया का क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में मजबूत सहयोग है। पूरे इंडोनेशिया के ग्राम प्रधानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद में ग्रामीण विकास की पहल पर 2 सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सह प्रदर्शन दौरा में भाग लिया।

भारत और इंडोनेशिया ने दोनों देशों में साल भर चलने वाले समारोहों के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ मनाई। जैसा कि मई 2018 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सहमति बनी थी, इंडोनेशिया सरकार के डाक विभाग ने इस आयोजन पर 'रामायण' विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारतीय दूतावास, जकार्ता ने पीटी पीओएस इंडोनेशिया के साथ मिलकर महात्मा गांधी पर एक विशेष स्मारक कवर जारी किया, जिसे 5 सितंबर 2019 को विदेश मंत्री द्वारा जकार्ता की यात्रा के दौरान जारी किया गया था। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण मेदान के साड़ी मुटियारा इंडोनेशिया विश्वविद्यालय में किया गया।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुश्री रेटनो मार्सुडी की सह-अध्यक्षता में पहली द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की बैठक 13 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश और लोगों के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के क्षेत्रों सहित मौजूदा द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अपनी यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली डायलॉग XI में मुख्य भाषण भी दिया। अपने मुख्य भाषण में उन्होंने इस क्षेत्र की शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया के बीच अधिक तालमेल बनाने का आह्वान किया।

लाओ प्युपिल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक

भारत की 'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों में भारत के प्रमुख भागीदार लाओ पीडीआर के साथ संबंधों को और मजबूत किया गया। 2007 में लाओस सूचना और संस्कृति मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एएसआई की एक टीम दो चरणों (2009-17) और (2018-28) में प्राचीन खमेर शिव मंदिर वट फो में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के जीर्णोद्धार में सहायता कर रही है। परियोजना का चरण- एक 2017 में पूरा हो गया। चरण-दो 2018 में शुरू हो गया है।

भारत ने आईटीईसी, आईसीसीआर और एमजीसी कार्यक्रमों के साथ-साथ आसियान-भारत रूपरेखा के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अनुदान और ऋण साख के माध्यम से लाओ पीडीआर के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करना जारी रखा। डीजल पंपों के रूपांतरण और सिंचाई के लिए बिजली पंपों के उन्नयन के लिए एक एलओसी परियोजना अगस्त 2019 में लाओ सरकार को सौंपी गई। आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत लाओ अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए लाओ छात्रों को पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति जारी रखी गई। सेंटर फ़ॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) के एक विशेषज्ञ को भारत के वित्त पोषित लाओस में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी लाओस-इंडिया सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग (सीईएसडीटी) में आईटी कौशल में लाओ युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 6 महीने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में लाओ अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण के लिए पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए लाओस की विदेश सेवा (एफएसआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (एफएआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बाउन्कॉन्ग सिहावॉन्ग ने 02-05 दिसंबर 2019 से भारत में जीएवीआई बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए लाओ पीडीआर से

एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्री सोमचित इंथामित, उपमंत्री, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने 13-14 दिसंबर 2019 तक दिल्ली वार्ता में भाग लेने के लिए लाओ पीडीआर से एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

मलेशिया

मलेशिया जो कि आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर संबंध के आधार भारत के साथ दोस्ती के मजबूत संबंध है। मलेशिया वैश्विक रूप से भारत के लिए 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है जबकि भारत अब मलेशिया के दस सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इस मजबूत द्विपक्षीय संबंध में पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो नियमित रूप से आदान-प्रदान और राजनीतिक/आधिकारिक स्तरों पर अनुबंध शामिल है।

5 सितंबर, 2019 को रूस के व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट फोरम के मौके पर प्रधानमंत्री का अपने मलेशियाई समकक्ष तुन डॉ. महातिर बिन मोहम्मद से मुलाकात के दौरान उच्चतम स्तर पर राजनीतिक अनुबंध जारी रहा। विदेश मंत्री ने 23 अक्तूबर 2019 को अजरबैजान में गुट-निरपेक्ष आंदोलन मंत्रिस्तरीय बैठक के मौके पर मलेशियाई विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला से मुलाकात की। अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री श्री एम. कुलसेगरन की यात्रा शामिल था, जिन्होंने तमिलनाडु सहित भारत के दौरे पर तीन बार आए (16-22 मई 2019 को); बेंगलुरु (21- 24 सितंबर 2019) तथा दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई (22-27 नवंबर 2019)। प्रधानमंत्री के विभाग में मंत्री (राष्ट्रीय एकता और सामाजिक कल्याण), श्री पी. वेथा मूर्ति ने अगस्त 2019 में भारत का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने ईएएम से मुलाकात की और मई में भारत में आम चुनाव के बाद प्रधान मंत्री को उनकी जीत के लिए मलेशियाई प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्राथमिक उद्योग मंत्री सुश्री टेरेसा कोक ने मलेशियाई ताड़ के तेल और रबर को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2019 में अपनी भारत यात्रा के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। वह 25-27 सितंबर 2019 को ग्लोबिल 2019 सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई भी गईं।

सुल्तान सलेहुद्दीन इब्नी अलमरहूम सुल्तान बादलीशाह, केदाह के सुल्तान ने 13-19 नवंबर, 2019 तक भारत का दौरा किया। मुंबई की यात्रा के अलावा, उन्होंने 18-19 नवंबर, 2019 को अपने शिक्षा पायी संस्था-भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून का भी दौरा किया। रॉयल मलय रेजीमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले जुलाई 1962 से जून 1963 तक आईएमए में सुल्तान ने प्रशिक्षण लिया था। रक्षा सहयोग में भारतीय नौसेना के जहाजों का नियमित आदान-प्रदान और यात्रा शामिल थी। भारतीय तटरक्षक जहाज विजित और आईएनएस सागरध्वनि ने क्रमश: 9-13 अप्रैल 2019 और 9-13 अगस्त 2019 को पोर्ट क्लैंग में आए। आईएनएस सावित्री ने 19-21 अगस्त 2019 से पोर्ट क्लैंग में एक ऑपरेशनल टर्न अराउंड किया। भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस किल्टन ने 12-16 सितंबर 2019 तक कोटा किनबालु में संयुक्त नौसेना अभ्यास समुद्र जक्समाना 2019 के दूसरे संस्करण में भाग लिया। 18-20 सितंबर, 2019 के दौरान कुआलालंपुर में 7वीं सेना-से-सेना स्टॉफ वार्ता में मेजर जनरल रविन खोसला, एसएम, वीएसएम के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। वाइस एडमिरल दातुक खैरुल अनुर बिन याहया, रॉयल मलेशियाई नौसेना के उप प्रमुख ने 3-5 अक्तूबर 2019 गोवा समुद्री क्षेत्र कॉन्क्लेव में भाग लिया। हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स (एचडीएमसी-15) के 22 अधिकारियों ने अपने विदेशी अध्ययन दौरे के भाग के रूप में 21-25 अक्तूबर 2019

से मलेशिया का दौरा किया। एडीएमएम प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन ह्युमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए अप्रैल और जुलाई 2019 में योजना सम्मेलन के दो दौर का आयोजन किया गया। जेएस (थल सेना) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर 2019 में कुचिंग में अंतिम सम्मेलन में भाग लिया।

मलेशिया इंडिया बिजनेस काउंसिल (एमआईबीसी) और आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी) ने व्यापार और निवेश अवसरों का पता लगाने के लिए 6-10 नवंबर, 2019 तक असम और मणिपुर के उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला हेतु 30-सदस्यीय मजबूत व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 55 मलेशियाई-भारतीय छात्रों को भारतीय छात्रवृत्ति और ट्रस्ट कोष (आईएसटीएफ) के अंतर्गत दिसंबर 2019 में 2019-20 के लिए 3,00,000 आरएम की छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया।

श्री विष्णु दयाल राम, माननीय सांसद (लोकसभा) और श्रीमती संपतिया उइके की यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2019 तक अंतर-संसदीय संघ कार्यशाला के लिए मलेशिया के लिए यात्रा। मलेशिया के प्रधानमंत्री के विभाग में उप मंत्री का दौरा। श्री मोहम्मद हनिपा मैडिन का 20 से 24 दिसंबर 2019 तक भारत का दौरा। मलेशिया के पर्यटन, कला और संस्कृति उप मंत्री श्री मुहम्मद बख्तियार बिन वान चिक की यात्रा 07 से 10 जनवरी 2020 तक भारत का दौरा।

न्यूजीलैंड

वर्ष के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोस्ताना और जोश भरे संबंधों की नियमित रूप से उच्च-स्तरीय संवाद और संपर्कों के माध्यम से पुन: पुष्टि हुई। 25 सितंबर 2019 को, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मौके पर प्रधानमंत्री सुश्री जैकिंडा अर्डर्न के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसके दौरान प्रधानमंत्री अर्डर्न ने प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया कि न्यूजीलैंड ने “भारत 2022-संबंध में निवेश” नाम से एक भारत रणनीति पत्र जारी किया है ताकि आने वाले वर्षों में भारत के साथ अपने संबंधों के बारे

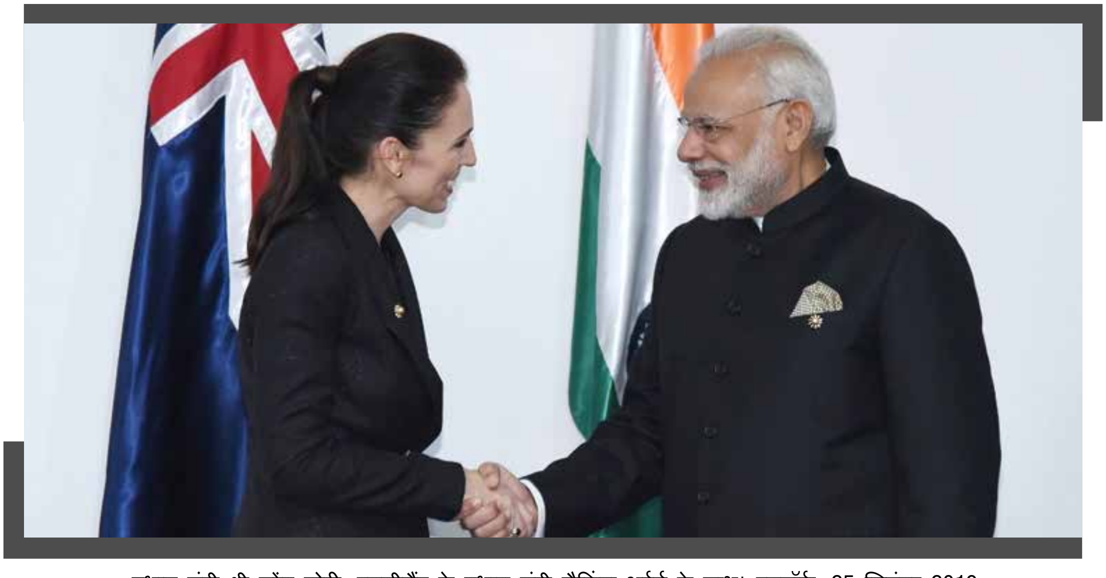

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, न्यूज़ीलैंड के प्रधान मंत्री जैकिंडा अर्डर्न के साथ। न्यूयॉर्क, 25 सितंबर 2019

में न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण के बारे में बताया जा सके। 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री एडरन छह विश्व नेताओं में से एक बने।

न्यूजीलैंड के विपक्ष के नेता साइमन ब्रिजेस ने 30 अगस्त से 5 सितंबर 2019 तक भारत का दौरा किया तथा विदेश मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जल शक्ति तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री से मुलाकात की। 1 अगस्त 2019 को, विदेश मंत्री ने आसियान से संबंधित बैठकों के मौके पर बैंकाक में उप प्रधान मंत्री (डीपीएम) और विदेश मंत्री श्री विंस्टन पीटर्स से मुलाकात की। डीपीएम विंस्टन पीटर्स, व्यापार और निर्यात विकास मंत्री डेविड पार्कर के साथ, 26-28 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा करने के लिए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। न्यूजीलैंड के व्यापार और निर्यात विकास राज्य मंत्री और कृषि मंत्री डेमियन ओ'कॉनर ने 5-7 नवंबर 2019 को भारत का दौरा किया तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कृषि और किसान कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री से मुलाकात की। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया संसदीय मैत्री समूह का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 20-26 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली और मुंबई का दौरा किया और विदेश राज्य मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन और मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की।

नौसेना स्टॉफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने 5-7 सितंबर को न्यूजीलैंड का दौरा किया। बाद में, 17 नवंबर 2019 को, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री रॉन मार्क ने बैंकाक में एडीएमएम-प्लस के मौके पर मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर व्यापक चर्चा की। विश्व मामलों के भारतीय परिषद् (आईसीडब्लूए) ने एशिया न्यूजीलैंड फाउंडेशन के साथ ट्रैक-दो संवाद के लिए 9-11 अप्रैल 2019 तक न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वरिष्ठ सिविल सेवकों के चार समूहों ने नेतृत्व, ई-गवर्नेंस और संगठनात्मक व्यवहार पर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेलिंगटन द्वारा आयोजित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किया।

द्विपक्षीय व्यापार में दो अंकों की वृद्धि देखी गई और स्टैटिस्टिक न्यूजीलैंड के आंकड़ों के अनुसार 2018 के दौरान 2.68 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर की तुलना में यह आंकड़ा 2.31 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर (जनवरी-सितंबर 2019) की राशि की रही। भारतीय आईटी दिग्गज एचसीएल ने अगस्त 2019 में हैमिल्टन में अपना वितरण केंद्र खोला। इंडिया न्यूज़ीलैंड बिजनेस काउंसिल ने 14 अक्तूबर को ऑकलैंड में 'इंडिया अनप्लग्ड: ट्रेड, कोलैबोरेट, ग्रो' विषय के साथ वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन के 6 वें संस्करण का आयोजन किया। भारत-न्यूजीलैंड आर्थिक वार्ता का 7वां दौर 28 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

न्यूजीलैंड में एक बड़े भारतीय प्रवासी के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को रेखांकित करते रहे। हाल ही में घोषित जनगणना के परिणाम के अनुसार, भारतीयों की संख्या 2,31,000 से अधिक है, जो न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या का 4.7% है। न्यूजीलैंड में हिंदी पांचवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सभी प्रमुख भारतीय त्योहारों और कार्यक्रमों को व्यापक रूप से मनाया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री, सांसद मेयर और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऑकलैंड दिवाली महोत्सव का उद्घाटन 12 अक्तूबर 2019 को प्रधानमंत्री अर्डर्न द्वारा किया गया था। सांसद श्री कंवलजीत सिंह बख्शी, सांसद डॉ. परमजीत परमार और श्री भव ढिल्लों, ऑकलैंड में भारत के माननीय कौंसल, पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित किए गए 381 लोगों में से थे जिन्हें 10 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव जी के

550वें प्रकाश उत्सव पर सम्मानित किया गया था। सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के उद्देश्य से, संस्कृति मंत्रालय ने न्यूज़ीलैंड को वर्ष 2020 के दौरान एक महोत्सव आयोजित करने के लिए शामिल किया है। श्री ग्रेग ओ'कॉनर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 20-26 नवंबर 2019 तक भारत का दौरा किया तथा 25 नवंबर 2019 को विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के सभापति श्री पीपी चौधरी और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा के साथ बातचीत की।

विदेश और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री श्री वी मुरलीधरन का 26-28 जनवरी 2019 तक ऑकलैंड और वेलिंगटन का दौरा करने का कार्यक्रम है, जिसके दौरान अन्य लोगों के अलावा उनकी उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री विंस्टन पीटर्स, व्यापार मंत्री, डेविड पार्कर, जातीय समुदाय मंत्री, सुश्री जेनी सेल्सा से भेंट करने की संभावना है।

फिलीपींस

वर्ष 2019 भारत-फिलीपींस द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा क्योंकि दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए। हमारे द्विपक्षीय संबंध की प्रमुख विशेषता रही 17-21 अक्तूबर 2019 की राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की फिलीपींस की शासकीय यात्रा तथा राष्ट्रपति दुतेर्ते के साथ रक्षा एवं समुद्री सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला, ऐतिहासिक और पूर्व-औपनिवेशिक संबंधों का संयुक्त अन्वेषण, फार्मा क्षेत्र में सहयोग तथा हवाई संपर्क जैसे विषयों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। चार समझौते: राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान व्हाइट शिपिंग सूचना को सांझा करने पर समझौता ज्ञापन, पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के कार्यक्रम (एस एंड टी) पर समझौता ज्ञापन संपन्न हुए।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, प्रतिनिधिमंडलों के परस्पर दौरे तथा नौसेना व कोस्ट गार्ड जहाजों के दौरे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का मुख्य आधार बने हुए हैं। इस संबंध में, दो भारतीय नौसैनिक जहाजों आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस किल्टन ने 23-26 अक्तूबर 2019 को फिलीपींस का दौरा किया। 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार 2.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर बना रहा। भारत का निर्यात 3% बढ़ा। वाहन, मशीनरी, फार्मा, भैंस के फ्रोज़न मांस के प्रमुख निर्यातों के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना हुआ है।

फिलीपींस में भारत द्वारा अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक कार्यक्रम भारत के राष्ट्रपति की शासकीय यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था। 19 अक्तूबर 2019 को फिलीपींस-इंडिया बिज़नेस कॉन्क्लेव और 4थे आसियान-इंडिया बिजनेस समिट ने फिक्की, सी आई आई तथा एसोचैम से 34 भारतीय कंपनियों और स्थानीय कंपनियों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। इसमें फिनटेक, स्टार्ट-अप और नवोन्मेष, फार्मा और कृषि शामिल थे। आयोजन के दौरान चार व्यावसायिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा आसियान इंडिया इनोटेक समिट एंड ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 20-22 नवंबर, 2019 को दवाओ शहर में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में सभी आसियान देशों तथा भारतीय ग्रास रूट नवप्रवर्तकों व युवा नवप्रवर्तकों के एक बड़े दल ने भाग लिया। भारत के राष्ट्रपति ने शासकीय यात्रा के दौरान मिरियम कॉलेज में सेंटर फॉर पीस एजुकेशन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रशांत द्वीपीय देश (पी आई सी)

(फिजी, कुक आइलैंड, किरिबाती, नौरू, टोंगा, वानुअतु, तुवालु, सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड, समोआ, नीयू, पलाऊ, माइक्रोनेशिया)

एकजुटता की भावना तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग से निर्देशित भारत ने लंबे समय से अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करते हुए पी आई सी के विकास प्रयासों में भागीदारी की है। जैसेकि हम 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का उदय देखते हैं, हाल ही के वर्षों में यह विशेष संबंध और प्रगाढ़ हुआ है जिससे कार्रवाई-उन्मुख इंडि-पैसिफिक आईलैंड कोऑपरेशन फोरम (एफआईपीआईसी) की स्थापना हुई है। फिपिक के दो शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में फिजी में और अगस्त 2015 में जयपुर में आयोजित किए गए, जिसके दौरान पीएम ने पी आई सी और भारत द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की समानताओं को व्यक्त किया तथा आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक अनुदान-सहायता, क्षमता, मानव संसाधन निर्माण के माध्यम से इन्हें संबोधित करने के लिए पी आई सी के साथ संबद्ध होने की भारत की इच्छा व्यक्त की। भारत द्वारा सभी पीआईसी को उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक अनुदान राशि 2015 से 125000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 200000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।

थाईलैंड में आसियान-भारत की मंत्रिस्तरीय बैठक में आसियान के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सामूहिक फोटो (01 अगस्त, 2019)

बहुपक्षीय स्तर पर, भारत 2017 में स्थापित भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के माध्यम से क्षेत्र में प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भी पीआईसी के साथ हमारे संबंधों की तारीफ करता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। जौन उसामते, माननीय इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, आपदा प्रबंधन और मौसम सेवा मंत्री (फिजी), रुआतेकि तेकाइरा, माननीय बुनियादी ढांचा और सतत ऊर्जा मंत्री (किरिबाती), रेनियर गदाबु एम.पी., माननीय जलवायु परिवर्तन, संरचनात्मक विकास और वाणिज्य, उद्योग और पर्यावरण मंत्री (नौरू), पोएसी मतैली तई, माननीय मौसम विज्ञान, ऊर्जा, सूचना, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, जलवायु

परिवर्तन और संचार मंत्री (टोंगा) और श्री अवाफोआ इराता, स्थायी सचिव, परिवहन, ऊर्जा और पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 31 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की तीसरी महासभा में शामिल हुए। फिजी, किरिबाती, नौरू, टोंगा और तुवालु से प्रतिनिधिमंडल 31 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की दूसरी महासभा में शामिल हुए। 25 सितंबर, 2019 को न्युयॉर्क में यू एन जी ए के अंतर्गत पीएसआईडीएस के नेताओं के साथ पीएम की पहली ऐतिहासिक बैठक के दौरान, हमारे प्रधानमंत्री ने पीएसआईडीएस के प्रत्येक सदस्य को उसकी पसंद के उच्च प्रभाव वाले प्रोजेक्ट के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने; सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण(एलओसी) देने और फिपिक का तीसरा शिखर सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) में 2020 की पहली छमाही में आयोजित करने की घोषणा की।

फरवरी 2018 में भूकंप से प्रभावित पीएनजी में राहत और पुनरुत्थान कार्य के लिए, भारत ने जुलाई 2019 में भारत की मानवीय सहायता के प्रति पीएनजी सरकार को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। सितंबर 2019 में जून 2019 के उलावुन ज्वालामुखी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बहाली के कार्यों के लिए एक और 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर पीएनजी को दान किए गए। भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से पीएनजी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमजी-सीईआईटी) की स्थापना की गई है।

कोमोडोर पी.के. श्रीवास्तव, निदेशक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में 4 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-27 जुलाई 2019 को प्रशांत क्षेत्र में इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कोस्टल ऐंड ओशन रिसर्च और समुद्री जीव विज्ञान अनुसंधान के नेटवर्क की स्थापना के लिए एक स्कूपिंग मिशन पर पीएनजी का दौरा किया। पीएनजी के चुनाव आयुक्त श्री पातिलास गमातो और पीएनजी के निर्वाचन आयोग के 5 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 2-5 सितंबर 2019 तक बैंगलोर में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज जनरल असेंबली में भाग लेने और नई दिल्ली में भारत के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए भारत का दौरा किया।

पीएनजी स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइज़िज़ (एसएमई) के अधिकारियों के एक दल ने भारतीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के वस्तुस्थिति अन्वेषण दौरे के लिए 3-9 नवंबर तक भारत की यात्रा की। श्री टॉमी अंगाओ, सहायक निदेशक, एशिया शाखा, विदेशी मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के साथ उप-विदेश मंत्री श्री अजीसा सेकई ने भारत के निमंत्रण पर मालदीव में 1-5 सितंबर, 2019 को आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया।

आईएसए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करके समोआ दिसंबर 2019 में आईएसए का 85वां सदस्य बन गया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ समोआ, एपिया में सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का प्रोजेक्ट 25 नवंबर 2019 से प्रचालित है। नियू में सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन आई टी स्थापित करने का काम सीडैक, पुणे के साथ समन्वय से प्रगति पर है। बाकी बची जनसंख्या के लिए 4जी नेटवर्क स्थापना के दूसरे चरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

फिजी के प्रधान मंत्री महामहिम रीयर एडमिरल (से. नि.) जोसैया वोरेक बैनीमारामा ने फरवरी 2019 में 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी)' से ससटेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड -2019 प्राप्त किया। 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 74वें सत्र के दौरान ई ए एम फीजी के विदेशी मामले, रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री इनिया बाटिकोटो सेरूईरातु से मिले और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। 2019-20 के दौरान न्यो इंडिया प्रोग्राम (केआईपी) के 54-59 शेड्यूलों में 42 प्रतिभागियों को चुना गया है। पलाऊ में, भारत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर रहा है और पलाऊ में राष्ट्रपति के कार्यालय में बिजली के लिए सौर ऊर्जा स्थापित कर रहा है। हाल ही में पलाऊ 15 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल सोलर एलाएंस

(आईएसए) में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आईएसए का 76वां सदस्य बना है।

कृषि, ग्रामीण और समुद्री विकास, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री, डॉ. महेंद्र रेड्डी ने 9-10 सितंबर 2019 को आयोजित मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 11 सितंबर 2019 को श्री गजेंद्रसिंह शेखावत, जल शक्ति, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग मंत्री के साथ सार्थक द्विपक्षीय विचार-विमर्श भी किया।

श्रीमती वीणा भटनागर, महिला, बाल एवं गरीबी उन्मूलन सहायक मंत्री और फिजी की संसद की उपाध्यक्ष ने 26 अक्टूबर 2019 को दीपोत्सव 2019 के लिए भारत (अयोध्या) का दौरा किया था। इस अवसर पर श्रीमती भटनागर को राज्य सरकार द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। श्रीमती भटनागर ने भी दिल्ली का दौरा किया और विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन से भेंट की और भारत की संसद का भी दौरा किया।

पहला क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन सुवा में 25 जनवरी 2020 को आयोजित किया जाना है। माननीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25-26 जनवरी 2020 को फिजी का दौरा करने वाले हैं। भारत, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और थाईलैंड के हिंदी विद्वानों के सम्मेलन में भाग लेने की आशा है जो विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए पर्दा उठाने वाला आयोजन होगा जो 2020 में फिजी में आयोजित होने वाला है।

महात्मा गांधी-सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र: श्री वी मुरलीधरन, विदेश राज्यमंत्री 25 जनवरी 2020 को फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी- सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं।

जनवरी 2020 में पापुआ न्यू गिनी जाने के लिए इसरो की टीम का दौरा प्रस्तावित है।

सोलोमन द्वीप समूह सरकार ने 2021-2022 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की गैर-स्थायी सीट पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की पुष्टि की।

थाईलैंड

थाईलैंड 2019 के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (आसियान) के संगठन का अध्यक्ष तथा 2018-21 तक तीन वर्ष के लिए इंडिया-आसियान डायलॉग पार्टनरशिप के लिए भारत का संयोजक देश है। 2019 में द्विपक्षीय संबंध कई उच्च स्तरीय विनिमयों सहित गहन विनियोजनों द्वारा चिह्नित हुए, जिनमें 10 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में भारत तथा थाईलैंड के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में 8वीं ज्वायंट कमीशन मीटिंग (जेसीएम); 2 दिसम्बर 2019 को नई दिल्ली में सुरक्षा सहयोग पर आयोजित 12वीं जेडब्लुजी; 23-25 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित 3सरी इंडिया-थाईलैंड आर्मी-टू-आर्मी स्टॉफ टाक्स; तथा 23-25 जुलाई 2019 को थाईलैंड में आयोजित 10वीं इंडियन एयर फोर्स-रॉयल थाई एयर फोर्स स्टॉफ टाक्स शामिल हैं।

16वीं भारत-आसियान शिखर बैठक, 14वीं ईस्ट एशिया समिट(ई ए एस) तथा तीसरी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आर सी ई पी) शिखर बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने ईएएम तथा श्री पीयूष गोयल, रेल एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के साथ 2-4 नवंबर 2019 को थाईलैंड का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल(से.नि.) प्रयुत चान-ओ-चा, वियतनाम तथा आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें तथा सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ पुल एसाइड बैठक की। प्रधानमंत्री ने 2 नवंबर 2019 को एक सामुदायिक आयोजन “सवास्दी

पी एम मोदी” को संबोधित किया जिसमें 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया तथा गुरू नानक देव जी की 550वीं जयंती पर एक विशेष यादगार सिक्का तथा तमिल साहित्य “थिरुक्कुरल” का थाई अनुवाद जारी किया।

भारत-आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक, 10वीं एमजीसी मिनिस्टीरियल मीटिंग, 9वीं ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक तथा 26वीं आसियान रीजनल फोरम (ए आर एफ) में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री ने 1-3 अगस्त 2019 को थाईलैंड का दौरा किया। इन बैठकों के बीच विदेश मंत्री ने थाईलैंड के विदेश मंत्री श्री डॉन प्रमुदविनाई तथा इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, टिमोर लेस्ते, वियतनाम के विदेश मंत्रियों तथा आसियान के महासचिव से द्विपक्षीय बैठकें की।

श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेलवे मंत्री ने 7-10 सितम्बर 2019 को बैंगकॉक में 16वीं आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स(एईएम)-इंडिया कंसल्टेशंस, 7वीं ईएएस इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग तथा 7वीं आरसीईपी मिनिस्टीरियल मीटिंग में भाग लिया। इन बैठकों के किनारे उन्होंने थाईलैंड, जापान, चीन, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्युज़ीलैंड, रशिया तथा संयुक्त राज्य अमरीका के आर्थिक मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। 9वीं आरसीईपी इंटरसेशनल मिनिस्टीरियल मीटिंग में भाग लेने के लिए उन्होंने 11-12 अक्तूबर 2019 को थाईलैंड की यात्रा भी की।

‘आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स’ मीटिंग-प्लस (एडीएमएम-प्लस) तथा डिफेंस ऐंड सिक्योरिटी 2019 प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिहं ने 16-18 नवंबर 2019 को थाईलैंड की यात्रा की। इसके पार्श्व में उन्होंने थाईलैंड, आस्ट्रेलिया तथा न्युज़ीलैंड के रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठकें की।

भारतीया नौसेना के नेवल स्टॉफ प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा ने 16-29 अप्रैल 2019 के दौरान थाईलैंड का दौरा किया। अध्यक्ष सीओएससी एवं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने चीफ ऑफ डिफेंस कॉनफ्रेंस में भाग लेने के लिए 26-29 अगस्त 2019 को थाईलैंड का दौरा किया। भारतीय नौसेना तथा रॉयल थाई नौसेना ने 5-15 सितम्बर 2019 के दौरान पोर्ट ब्लेयर तटीय सीमा से हटकर कोरपैट-28 अभ्यास किया। 16-20 सितम्बर 2019 के दौरान पोर्ट ब्लेयर में पहला भारत-थाईलैंड-सिंगापुर त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। 16-29 सितम्बर 2019 के दौरान भारतीय सेना-रॉयल थाई सेना का संयुक्त अभ्यास मैत्री 2019 मेघालय, भारत में किया गया।

अक्तूबर 2019 में जेसीएम के दौरान विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली तथा थाईलैंड के देवावोंग्से वोरापकर्न इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा 7-9 नवंबर 2019 के दौरान विशाखापटनम, भारत में आयोजित बिम्सटेक पोर्ट्स कनक्लेव के दौरान रानोंग पोर्ट तथा विशाखापटनम, चेन्नई और कोलकाता के भारतीय पत्तनों के बीच तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के सहयोग से दूतावास बैंकॉक में 21-23 फरवरी 2020 तक पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के दूसरे सत्र का आयोजन करेगा। इस महोत्सव से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और थाईलैंड और दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने की आशा है। भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस समारोह में शामिल होने की आशा है।

कोबरा गोल्ड अभ्यास 2020, अमेरिका और थाईलैंड द्वारा सह-मेजबानी 03 फरवरी - 06 मार्च 2020 से थाईलैंड में निर्धारित है। इस अभ्यास में भारत आब्जर्वर प्लस श्रेणी के रूप में भाग लेगा। भारत-थाई कॉर्पसैट अभ्यास का 29वां चक्र 12-20 फरवरी 2020 के दौरान निर्धारित किया गया है।

7वां एशिया-प्रशांत सतत विकास मंच बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र (यूएनसीसी) में 25-27 मार्च, 2020 से आयोजित किया जाएगा। एपीएफएसडी सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में विशेष आवश्यकताओं वाले देशों, विशेष रूप से समर्थन करने के लिए एक समावेशी अंतरशासी मंच और एक क्षेत्रीय मंच है। 7वें एपीएफएसडी का विषय "एशिया और प्रशांत में 2030 एजेंडा की त्वरित कार्रवाई और वितरण" है।

टिमोर-लेस्ते

टिमोर-लेस्ते के साथ भारत के संबंध और अधिक गहरे हुए। 2019 में भारत द्वारा दो प्रोजेक्ट कायान्वित किए गए। पहला था टिमोर-लेस्ते के ओय-कुस क्षेत्र में इंडिया-यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फण्ड द्वारा पोषित इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब प्रोजेक्ट जो 12 स्कूलों को शामिल करते हुए आई टी नवोन्मेष प्रयोगशालाओं तथा मोबाइल आई टी नवोन्मेष वैनों दोनों के माध्यम से स्कूलों में आई टी ज्ञान को बढ़ाने पर केंद्रित है। दूसरा प्रोजेक्ट, टिमोर-लेस्ते में आतुरो आईलैंड में स्थापित ससटेनेबल एग्रीकल्चर ऐंड पर्माकल्चर लर्निंग सेंटर आईबीएसए निधि से पोषित है जो कायम रहने वाले कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक सीखने के केंद्र के रूप में कार्य करते हुए कृषि, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाएगा।

विदेश मंत्री 2 अगस्त 2019 को बैंगकॉक में ईएएस शिखर बैठक के पार्श्व में टिमोर-लेस्ते के विदेश मंत्री महामहिम श्री डायोनीशियो दा कोस्टा बाबो सोरेस से मिले और द्विपक्षीय संबंधों के सारे पहलुओं की समीक्षा की। टिमोर-लेस्ते के कृषि एवं मत्स्य मंत्री श्री जोआकिम जोस गुसमाओ दॉस रीस मार्टिंस के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया फाउंडेशन द्वारा 3-4 सितम्बर 2019 को मालदीव्स में आयोजित चौथी अवर ओशन कॉनफ्रेंस में भाग लिया।

जलीय सीमाओं के प्रमुख वार्ताकार तथा टिमोर-लेस्ते के विशेष प्रतिनिधि श्री शनाना गुसमाओ ने 12-13 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा ग्रेटर सनराइज़ प्रोजेक्ट का विशेष संदर्भ लेते हुए टिमोर-लेस्ते के तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश की इच्छा करते हुए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ विस्तृत चर्चा की।

सिंगापुर

2019-20 में भारत-सिंगापुर कूटनीतिक सांझेदारी में विस्तृत प्रगति हुई। हमारे प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री ली ह्सेन लूंग ओसाका में जी-20 शिखर बैठक (जून 2019) तथा बैंगकॉक में आसियान/ईएएस बैठकों के पार्श्व में मिले। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने हेतु 24 सितम्बर 2019 को संयुक्त राष्ट्र, न्युयॉर्क के विशेष आयोजन में संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री ली विश्व के छह नेताओं में से एक थे।

विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिहं; तथा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मकान एवं शहरी मामले, नागरिक उड्डयन तथा राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग श्री हरदीप सिहं पुरी ने 2019 में सिंगापुर का दौरा किया। 9 सितम्बर 2019 को ईए एम ने विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन के साथ ज्वायंट मिनिस्टीरियल कमेटी (जेएमसी) की छठी बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री ने 20 नवम्बर 2019 को रक्षा मंत्री डॉ. नग

इंग हें के साथ वार्षिक डिफेंस मिनिस्टर्स' डायलॉग की सह-अध्यक्षता की। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने अगस्त 2019 में सिंगापुर का दौरा किया। सिंगापुर का दौरा करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल थे - राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार राजेंद्र खन्ना सिक्योरिटी डायलॉग के लिए तथा रक्षा सचिव श्री अजय कुमार डिफेंस पॉलिसी डायलॉग के लिए।

सिंगापुर से उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री श्री हेंग स्वी कीट अक्तूबर 2019 में उप प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आए। इस दौरे के दौरान, उप प्रधानमंत्री हेंग प्रधानमंत्री मोदी, कई कैबिनेट मंत्रियों से मिले तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्लु ई एफ) इंडिया इकोनॉमिक समिट (आई ई एस) की सह-अध्यक्षता की। इसके अलावा, अन्य उच्च-स्तरीय यात्राओं में शामिल थे, संचार एवं सूचना मंत्री तथा प्रभारी मंत्री व्यापार सम्बंध, एस. ईश्वरन जिन्होंने जून तथा अक्तूबर में यात्रा की; घरेलु मामले एवं विधि मंत्री श्री के. षणमुगम तथा शिक्षा मंत्री श्री ऑन्ग ये कुंग ने अगस्त तथा सितम्बर 2019 में भारत का दौरा किया।

इंडिया-सिंगापुर ट्रैक 1.5 स्ट्रेटेजिक डायलॉग जुलाई 2019 में दिल्ली में हुआ। वार्षिक डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग; सचिव स्तरीय डिफेंस पॉलिसी डायलॉग; एयर फोर्स, आर्मी एंड नेवी स्टॉफ टाक्स; डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी तथा डिफेंस इंडस्ट्री वर्किंग ग्रुप की बैठकों; तथा, मिलिटरी इंटेलीजेंस एजेंसियों के प्रमुखों की वार्षिक बैठक द्वारा रक्षा संबद्धता बनी रही। दोनों पक्षों ने अभ्यासों के अपने वार्षिक कार्यक्रम जारी रखे - भारत में सिंगापुर सेना के वार्षिक आर्मर एवं आर्टिलरी अभ्यास; इस वर्ष सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर-इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज़(सिम्बेक्स) का 26वां संस्करण; एयर फोर्स ज्वायंट मिलिटरी ट्रेनिंग का 10वां संस्करण जो सिंगापुर एयर फोर्स को भारत में अभ्यास करने तथा लाइव फायरिंग करने के योग्य बनाता है। इस वर्ष के संसकरण में पहली बार एक नेवल कम्पोनेंट भी शामिल किया गया। भारत ने मई 2019 में सिंगापुर में 12वीं इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्ज़ीबीशन एशिया 2019 (इम्डेक्स एशिया-2019) में भाग लिया। डीआरडीओ सहित भारतीय एजेंसियों तथा सिंगापुर की एजेंसियों के मध्य वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज सागरध्वनि ने अगस्त 2019 में सिंगापुर की यात्रा की। 16-19 सितम्बर 2019 को अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर तथा थाईलैंड के बीच आरम्भिक त्रिपक्षीय समुद्रीय अभ्यास (सिटमेक्स) किया गया। डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग के समय भारत ने सिंगापुर को चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज पर मिसाइल टेस्ट फ़ायरिंग करने की अनुमति देने की अपनी इच्छा संप्रेषित की।

वित्त वर्ष 2019-20 में (अक्तूबर 2019 तक) द्विपक्षीय व्यापार 14.8 अमेरिकी डॉलर था जिसमें सिंगापुर को निर्यात 0.4% की वृद्धि के साथ 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात 6.4% कमी के साथ 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2018-19 में भारत में प्राप्त कुल विदेशी निवेश 44.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से सिंगापुर से प्राप्त विदेशी निवेश की मात्रा 16.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। सिंगापुर को भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 66.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2000- अक्तूबर 2019) था जिसमें से वित्त वर्ष 2019-20 में अक्तूबर 2019 तक लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो सिंगापुर को भारतीय निवेशकों के लिए शीर्ष स्थानों में से एक बनाता है।

विस्तारा - सिंगापुर एयरलाइंस तथा टाटा समूह के मध्य एक संयुक्त उद्यम - अगस्त 2019 में उन्होंने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सिंगापुर से दिल्ली तथा मुम्बई की शुरूआत की, जबकि गोएयर ने बेंगलूरू तथा कोलकाता से सिंगापुर को अपनी सेवाएं अक्तूबर 2019 में प्रारम्भ कीं। प्रोद्यौगिकी, नवोन्मेष, फ़िनटेक तथा स्टार्ट अप के क्षेत्रों में सहयोग 2019 में बढ़ा है। 2019 फिनटेक महोत्सव के दौरान 13 नवम्बर को सिंगापुर में क्यु आर आधारित भुगतान भीम यूपीआई का एक पायलट डेमो किया गया। जून 2018 में शुरू किए गए रूपे इंटरनेशनल कार्ड के अलावा सिंगापुर में रूपे

डोमेस्टिक कार्ड की स्वीकार्यता के लिए भी वाणिज्यिक एवं तकनीकी प्रबंधों पर काम किया गया है। फिनटेक में जेडब्लुजी के अंतर्गत दो पक्ष इंडिया स्टैक पर आधारित एक ग्लोबल स्टैक पर प्रगति कर रहे हैं तथा एक अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिज़नेस सैंस बॉर्डर विकसित कर रहे हैं।

सरकार की दूसरी पारी में सिंगापुर में मिशन ने भारत पर क्षेत्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन "इंडिया-सिंगापुर: द नेक्स्ट फेज़" 9-10 सितम्बर 2019 को आयोजित किया। इस आयोजन ने 4500 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों को आकर्षित किया। मंत्री-स्तरीय सम्मेलनों में ईए एम, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पुरी, वरिष्ठ मंत्री टियो ची हियां तथा सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन उपस्थित थे। हमारे मिशन के स्टार्ट अप एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म "इंडिया-सिंगापुर एंटर्प्रेन्यरशिप ब्रिज (इनस्प्रेनेयर)" का तीसरा संस्करण नवोन्मेष के विषयों पर बिज़नेस एंड इनोवेशन समिट तथा भारत व सिंगापुर से 85 स्टार्ट अप की प्रदर्शनी के साथ-साथ आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर से 120 विश्वविद्यालयी छात्रों ने सितम्बर 2019 में चेन्नई में आयोजित दूसरे संयुक्त हैकाथन में भाग लिया। सिंगापुर के शिक्षा मंत्री श्री ऑन्ग ये कुंग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अध्यक्षता किए गए पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए।

केंद्रीय तथा राज्य सरकारें एवं सरकारी संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गुवाहाटी में उत्तर पूर्व कौशल केंद्र का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2019 में किया गया।

श्री तरसेम शनमुगरत्नम, वरिष्ठ मंत्री और सामाजिक नीतियों के समन्वय मंत्री ने जनवरी 2020 में, भारत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की और आरबीआई के निमंत्रण पर मुंबई में एक व्याख्यान दिया।

वायु सेनाध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय वायुसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी 2020 में सिंगापुर एयर शो में भाग लिया था। सिंगापुर सशस्त्र बलों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी 2020 में लखनऊ में डेफएक्सपो 2020 में भाग लिया था।

वित्त वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार (नवंबर 2019 तक) 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसमें सिंगापुर को निर्यात 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2019-20 में, सितंबर 2019 तक कुल प्रवाह 8.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि सिंगापुर से भारत में संचयी एफडीआई (अप्रैल 2000-सितंबर 2019) 91.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत में कुल प्रवाह का 20% है। सिंगापुर के लिए बाह्य भारतीय एफडीआई 67.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जनवरी 2008 - दिसंबर 2019) था जिसमें से वित्त वर्ष 2019-20 में नवंबर 2019 तक लगभग 1.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

वियतनाम

वियतनाम के साथ नज़दीकी तथा दोस्ताना संबंध बढ़ाने के लिए अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का पालन करते हुए भारत ने वियतनाम के साथ अपनी सम्बद्धता बढ़ाई। उच्च-स्तरीय दौरों के विनिमय, विस्तृत रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, विकास सांझेदारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के अंतर्गत इसके क्षमता निर्माण प्रयासों में वियतनाम को समर्थन देने से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए।

उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडु ने 9-12 मई 2019 को वियतनाम के हा नम प्रांत में ताम चुक पगोडा में वियतनाम बुद्धिस्ट संघ तथा इंटरनेशनल कौंसिल ऑफ यूएनडीवी द्वारा आयोजित वैसाख महोत्सव के

16वें संयुक्त राष्ट्र दिवस पर सम्मानित अतिथि के रूप में वियतनाम का दौरा किया तथा मुख्य भाषण दिया। बाकु में 18वें नाम शिखर सम्मेलन के पार्श्व में उप राष्ट्रपति 25 अक्तूबर को पुनः अपने वियतनामी समकक्ष दांग थि न्गोक थिन्ह से मिले। प्रधानमंत्री दो बार प्रधानमंत्री फुक से मिले; पहले ओसाका में 28 जून 2019 को जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान; तथा 4 नवम्बर को बैंगकॉक में आयोजित 16वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान। विदेश मंत्री 01 अगस्त 2019 को एएमएम बैठक के पार्श्व में उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री मिन्ह से मिले तथा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

पार्टी केंद्रीय समिति के सदस्य तथा फु येन प्रॉविंस' पार्टी समिति के सचिव तथा पीपल्स' कौंसिल के अध्यक्ष श्री ह्विन तान वियत मंत्रालय के विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत 15-19 अक्तूबर 2019 को भारत आए। उन्होंने वाणिज्य तथा उद्योग के राज्य मंत्री तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा में सहयोग भारत के वियतनाम के साथ सम्बंधों का मुख्य आधार है। भारत के रक्षा सचिव डॉ.अजय कुमार ने 3 अक्तूबर को वियतनाम के उप रक्षा मंत्री सी.ले.जन. गुयेन चि विन्ह के साथ हो चि मिन्ह शहर में इंडिया-वियतनाम एन्युअल सिक्योरिटी डायलॉग का 12वां चक्र आयोजित किया। वर्ष के दौरान दोनों सशस्त्र सेनाओं के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान जारी रहे। इनमें वियतनाम पीपल्स'आर्मी के स्टॉफ प्रमुख सी.ले.जन. फान वान गियांग तथा वियतनाम पीपल्स' आर्मी के उप स्टॉफ प्रमुख न्गो मिन्ह तियन के क्रमशः नवम्बर तथा दिसम्बर 2019 में दौरे शामिल थे। आर्मी टू आर्मी स्टॉफ टाक्स, नेवी टू नेवी सटाफ टाक्स तथा एयर फोर्स स्टॉफ टाक्स वियतनाम में 2019 में आयोजित की गईं। भारतीय समुद्री जहाजों ने वियतनाम के मैत्री दौरे किए। 2019 में तीन भारतीय समुद्री जहाजों सहयाद्री, कोलकाता, शक्ति ने वियतनाम के सद्भाव दौरे किए।

कनेक्टिविटी के मोर्चे पर, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त किया गया निजी एयरलाइनों- इंडिगो और वीटजेट द्वारा नई दिल्ली और कोलकाता को हनोई और हो ची मिन्ह शहर से जोड़ते हुए सीधी उड़ान के शुरू होने से। मध्य वियतनाम में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान माई सन के संरक्षण और जीर्णोद्धार का एएसआई का 5-वर्षीय प्रोजेक्ट इस साल भी जारी रहा। मई 2019 में हनोई और फु थो और विन्ह फुक प्रांतों में भागवान महावीर विकास सहयोग समिति (बीएमवीएसएस) के सहयोग से जयपुर फुट कृत्रिम अंग लगाने का शिविर आयोजित किया गया था जिसमें 500 वियतनामी नागरिकों को लाभ हुआ।

3

पूर्वी एशिया

जापान

2014 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान विकसित भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और एक बड़ी सत्ता और उद्देश्य के रूप में विकसित हुआ है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला है। आज यह द्विपक्षीय संबंध बहुआयामी है और दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों में बढ़ते अभिसरण से प्रेरित है।

2019 में द्विपक्षीय संबंध प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधान मंत्री श्री अबे शिंजो के बीच संबंधों के कारण आगे बढ़ते रहे तथा सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में प्रगति देखी गई। 2019 में जापान में आयोजित जी20 के मौके पर जापान के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने के लिए वर्ष भर कई अवसर प्राप्त हुए।

जापान के साथ भारत का निकट संबंध भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की 21-23 अक्तूबर 2019 को जापान के सम्राट महामहिम नराहितो के राज्याभिषेक के समारोह में शामिल होने के लिए जापान की यात्रा से परिलक्षित हुआ। सम्राट के राज्याभिषेक से जुड़े समारोहों और प्रधान मंत्री अबे द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने के अलावा माननीय राष्ट्रपति ने सुकिजी होंगवानजी बौद्ध मंदिर का भी दौरा किया तथा बौद्ध धर्म के आधार पर भारत और जापान के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को उद्धृत करने के लिए गया स्थित पवित्र बोधि वृक्ष से लाया गया एक पौधा लगाया।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओसाका में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27-29 जून 2019 तक जापान का दौरा किया जहां उन्होंने 27 जून

2019 को प्रधान मंत्री अबे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने व्लादिवोस्तोक में (5 सितंबर 2019) पूर्वी आर्थिक मंच और बैंकाक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (4 नवंबर 2019) के इतर द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। उन्हें बायारिट्ज (अगस्त 2019) में जी7 शिखर सम्मेलन में भी मिलने का अवसर मिला।

इस वर्ष नवंबर 2019 में भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन के लिए जापान के विदेश मंत्री श्री मोतेगी तोशिमित्सु और जापान के रक्षा मंत्री श्री कोनो तारो के दौरे के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग में भी मजबूती आयी। 2 + 2 संवाद से पहले, रक्षा मंत्री (आरएम) श्री राजनाथ सिंह ने 3 सितंबर 2019 को रक्षा मंत्री की बैठक के लिए जापान का दौरा किया। आरएम ने क्रमश: बैंकाक और नई दिल्ली में "आसियान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक+" और '2 + 2' संवाद शिखर सम्मेलन के अवसर पर नवंबर 2019 में जापानी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। 2019-2020 में विभिन्न बिंदुओं पर आयोजित तीन सेवाओं के बीच कर्मचारियों की वार्ता के साथ रक्षा बलों के तीन घटकों के बीच नियमित बातचीत हुई। पूर्व भारतीय थल सेनाध्यक्ष श्री बिपिन रावत दिसंबर 2019 में जापान गए और श्री यमाजाकी कोजी, चीफ ऑफ स्टाफ, ज्वाइंट स्टॉफ, जापान सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज, ने जनवरी 2020 में रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। अक्तूबर और अक्तूबर-नवम्बर, 2019 में क्रमश: वायु और जमीनी अभ्यासों के द्वितीय संस्करण, शिन्यु मैत्री (अक्तूबर 2019) तथा धर्म गार्डियन के आयोजन के साथ रक्षा बलों के बीच परिचालन संबंध बना रहा। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2019 को सितंबर 2019 में जापान के सागर में पश्चिमी क्यूशू में आयोजित किया गया। 19 वां भारतीय तटरक्षक-जापानी तटरक्षक संयुक्त अभ्यास जनवरी 2020 में चेन्नई में आयोजित किया गया था।"

उच्च स्तरीय संबंध के भाग के रूप में विदेश मंत्री (ईएएम) डॉ. एस. जयशंकर ने जून 2019 में जी20 ओसाका शिखर सम्मेलन के इतर 11 वें भारत-जापान विदेश मंत्रियों के रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया। नवंबर 2019 में 2+2 'संवाद के लिए जापानी विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा के दौरान 12 वां भारत-जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता भी आयोजित की गई। विदेश मंत्री ने क्रमश: अगस्त 2019 में बैंकॉक में आसियान-विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर पूर्व जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो से तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा (सितंबर 2019) के इतर न्यूयॉर्क और नागोया में और जी20 विदेश मंत्रियों (नवंबर 2019) की बैठक में पदासीन जापानी विदेश मंत्री मोटेगी से मुलाकात की।

वर्ष भर कई उच्च-स्तरीय बातचीत होती रही जिसने द्विपक्षीय संबंधों में गति को बनाए रखा। भारत से जापान की कुछ उल्लेखनीय यात्राओं में शामिल थे: डॉ. राजीव मिश्रा, उपाध्यक्ष, नीति आयोग की मार्च, 2019 में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) की 9 वीं संयुक्त समिति की बैठक (जेसीएम) के लिए यात्रा; जून, 2019 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जी20 मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए यात्रा जहां उन्होंने पूर्व एमईटीआई मंत्री हिरोशिगे सेको के साथ द्विपक्षीय बैठक की; जून 2019 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जी20 बैठक के लिए केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण की यात्रा; जून 2016 में विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (आईसी) तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राज कुमार सिंह की यात्रा; सितंबर 2019 में जी20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के लिए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार (आईसी) की यात्रा; अक्तूबर 2019 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की जी20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के लिए यात्रा; और जी20 के 6वें संसदीय स्पीकरों के शिखर सम्मेलन के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला की यात्रा।

वर्ष 2019 में जापान से भारत की उल्लेखनीय यात्राओं में शामिल थे: जुलाई 2019 में एमएएचएसआर संबंधी 10वीं जेसीएम के लिए प्रधान मंत्री के विशेष सलाहकार

डॉ. हीरोटो इज़ुमी; नवंबर 2019 में जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय (एनएसएस) के महासचिव श्री शिगेरु कितामुरा की यात्रा; जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्री श्री कजियामा हिरोशी की यात्रा जहाँ उन्होंने 10वीं भारत-जापान ऊर्जा वार्ता में भी भाग लिया।

2019 में दोनों देशों के बीच हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बातचीत में- फरवरी 2019 में टोक्यो में आयोजित भारत-जापान साइबर संवाद; मार्च 2019 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-जापान अंतरिक्ष वार्ता; 15 मई 2019 और 06 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-जापान एक्ट-ईस्ट फोरम; अक्तूबर 2019 में टोक्यो में आयोजित शहरी विकास पर 11 वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक; अक्तूबर 2019 में नई दिल्ली में अगली पीढ़ी/ शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों से संबंधित तीसरी भारत-जापान नीति वार्ता; और दिसंबर 2019 में समुद्री क्षेत्र से संबंधित मामलों पर 5वां दौर की वार्ता तथा निरस्त्रीकरण, अप्रसार, और निर्यात नियंत्रण पर 8वें दौर का परामर्श का आयोजन शामिल हैं।

जापान 2019 में भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जापानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 2.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्तमान में, जापान वर्ष 2000 से संचयी निवेश के मामले में प्रमुख निवेशकों में तीसरे स्थान पर है और अक्तूबर 2018 के अनुसार यहां 1,441 जापानी कंपनियां भारत में पंजीकृत हैं। जापान भारत के सबसे बड़े द्विपक्षीय साझेदारों में से एक है जो विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे बिजली, परिवहन, पर्यावरण और बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित परियोजनाओं में त्वरित आर्थिक विकास के प्रयासों के लिए है। 2018-19 में, जापान ने भारत में अपने आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) कार्यक्रम के तहत 416.458 बिलियन जापानी येन देने का वादा किया।

भारत और जापान दोनों ने 2019 में सांस्कृतिक, शैक्षिक, संसदीय, शैक्षणिक और ट्रैक 1.5 बातचीत के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। मार्च 2019 में राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने दौरा किया। कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन मंत्री, श्री हिरोशी मोरियमा के नेतृत्व में प्रतिनिधि सभा नेशनल डाईट आफ जापान ने अगस्त 2019 में भारत का दौरा किया तथा आवासन व शहरी मामले राज्य मंत्री (आईसी) एवं विदेश मंत्री से मुलाकात की। मेघालय, केरल और तमिलनाडु राज्यों के उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल ने वर्ष के दौरान जापान का दौरा किया। वर्तमान में, भारत के सात राज्यों और तीन शहरों/क्षेत्रों ने विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए जापान के प्रान्तों और शहरों के साथ भागीदारी की है।

मंगोलिया

भारत का मंगोलिया के साथ धर्म, लोकतंत्र और विकास साझेदारी के आधार पर जोश से भरा और सौहार्दपूर्ण संबंध है। हमारे प्रधान मंत्री की यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी जिसके बाद हमारे संबंधों में लगातार और निरंतर सुधार हुआ है। मंगोलियाई विदेश मंत्री श्री डी. सोगातबातर ने जनवरी, 2019 में नई दिल्ली में 'रायसीना संवाद' में भाग लिया और तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके बाद खनन और भारी उद्योग मंत्री श्री डी. सुमियाबाजार 'पेट्रोटेक 2019' में भाग लेने आए। उन्होंने फरवरी 2019 में हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र

प्रधान के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। इस यात्रा में मंगोलियाई रिफाइनरी और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच एक्जिम बैंक एलओसी के तहत बनायी जा रही 1.236 बिलियन डॉलर की तेल रिफाइनरी के लिए परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। संसद सदस्य और मंगोलिया के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ श्री एल. बोल्ड ने फरवरी 2019 में प्रयागराज में 'महाकुंभ' में भाग लिया।

मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री खाल्टमागिन बत्तुलगा, विदेश मंत्री डी. सोगातबातर तथा सड़क और परिवहन विकास मंत्री बंबाशुरेन एनखमगलन के साथ 19-23 सितंबर, 2019 के दौरान भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के अलावा, उन्होंने हमारे विदेश राज्य मंत्री के साथ एक शिष्टाचार भेंट भी की। इस यात्रा के दौरान चार समझौतों - सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रोटोकॉल (2019-23), आपदा प्रबंधन और जोखिम प्रशमन, शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के सहयोग और उपयोग तथा पशु स्वास्थ्य और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यापक कार्य योजना - पर हस्ताक्षर किए गए।

अक्तूबर 2019 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगोलिया के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर मंगोलिया का दौरा किया, जो शिनशंड में तेल रिफाइनरी के लिए पूर्ण किए गए अवसंरचना कार्यों के संयुक्त उद्घाटन के लिए था। डोर्नोगोवी प्रांत के 10 मंगोलियाई छात्रों के लिए सुविधाओं की जांच और आईटीईसी छात्रवृत्ति की घोषणा करने के अलावा, उन्होंने तेल रिफाइनरी के निर्माण के लिए 236 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त एलओसी पर भी हस्ताक्षर किए। 1.236 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाली यह परियोजना अब भारत के निकट पड़ोस से परे एलओसी की सबसे बड़ी परियोजना है।

कोरिया गणराज्य

राष्ट्रपति मून जे-इन (एमजेआई) की भारत यात्रा के केवल सात महीने के बाद ही उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की 21-22 फरवरी 2019 के दौरान कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्रा के साथ गत वर्ष से भारत और कोरिया गणराज्य (आरओके) के बीच अच्छे संबंध की गति बनी रही। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, आर्थिक, संस्कृति और विज्ञान सहयोग पर व्यापक चर्चा की। आधिकारिक कार्यक्रम के अलावा, पीएम मोदी ने एमजेआई के साथ मिलकर महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया, भारत-कोरिया व्यापार संगोष्ठी को संबोधित किया, गिम्हे शहर को पवित्र बोधि वृक्ष का एक पौधा उपहार दिया और सियोल शांति पुरस्कार, 2019 लिया। मीडिया, स्टार्ट-अप, सीमा पार आतंकवाद से मुकाबला करने और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, व्यापार सुविधा आदि जैसे क्षेत्रों में छह समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

पीएम मोदी ने जापान के ओसाका में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर फिर से एमजेआई से मुलाकात की और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थितियों में सुधार के तरीकों पर चर्चा की। सितंबर 2019 में एमजेआई ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम में अपनी टिप्पणी दी।

रक्षा मंत्री ने 03-05 सितंबर 2019 को कोरिया गणराज्य का दौरा किया। उन्होंने कोरिया गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री ली नाक-योन से मुलाकात की और रक्षा मंत्री श्री जियोंग क्योंग-डो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नौसेनाओं के आपसी संभार सहायता और शैक्षिक आदान-प्रदान संबंधी दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री ने भारत-कोरिया गणराज्य रक्षा सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी की।

प्रधान मंत्री 14 वें सियोल शांति पुरस्कार समारोह में सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करते हुए (22 फरवरी, 2019)

ओडिशा के राज्यपाल ने कोरिया गणराज्य का दौरा किया और चुंगचेन्गनाम प्रांत के गवर्नर के साथ द्विपक्षीय बैठक की तथा कृषि, जल कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और स्मार्ट शहरों के संबंध में सहयोग पर चर्चा की। उन्हें हान्सेओ विश्वविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।

केरल के मुख्यमंत्री ने कोरिया गणराज्य का दौरा किया, जहां कोरियाई व्यवसायी के लिए केरल में विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, पर्यटन, मत्स्यपालन और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में निवेश करने हेतु एक केरल निवेश रोड शो का आयोजन किया गया। उन्होंने बुसान बंदरगाह का भी दौरा किया और केरल के जीवंत बंदरगाह क्षेत्र और क्षमता निर्माण में सहयोग पर चर्चा की। केरल से स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और भारत योग केंद्र, बुसान के बीच एक आशय-पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किया गया।

नई दक्षिणी नीति संबंधी अध्यक्षीय समिति के आरओके अध्यक्ष ने अक्तूबर 2019 में भारत का दौरा किया और सीईओ, नीति आयोग के साथ मुलाकात की एवं भारतीय कंपनियों के साथ भी बातचीत की।

4

यूरेशिया

रूस

भारत और रूस के बीच वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की परंपरा को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने 20वें भारत-रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए 4-5 सितंबर 2019 को व्लादिवोस्तोक का दौरा किया। वे 5वें पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अतिथि भी थे। "विश्वास और साझेदारी के माध्यम से सहयोग की नई ऊँचाइयों तक पहुँचने" शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था, जिसमें भारत-रूस संबंधों की संपूर्णता को रेखांकित किया गया। इस यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा सहयोग, सड़क परिवहन तथा तेल और गैस क्षेत्रों में सहयोग के क्षेत्रों में 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में आर्थिक अवसरों में भारतीय कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रूसी सुदूर-पूर्व क्षेत्र के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण साख की घोषणा की। विदेश मंत्री (27-28 अगस्त 2019), श्री अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (21 अगस्त 2019) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान (29-30 अगस्त 2019) की रूस यात्रा ने प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तोक की द्विपक्षीय यात्रा के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। रूसी सुदूर पूर्व में व्यापार के अवसरों की खोज के लिए, एक 150-सशक्त व्यापार प्रतिनिधिमंडल श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्रियों के साथ 11-13 अगस्त, 2019 को व्लादिवोस्तोक का दौरा करने के लिए गया था और रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी ट्रूटनेव और रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के 11 राज्यपालों से भेंट की। व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने रूस और भारत के राज्यों के क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य और

सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतरसरकारी आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता के लिए 26-29 नवंबर 2019 को रूस का दौरा किया था।

रूस के उप प्रधानमंत्री श्री यूरी बोरिसोव ने विदेश मंत्री के साथ भारत-रूस अंतरसरकारी आयोग-तकनीकी और आर्थिक सहयोग की सह-अध्यक्षता में अंतर-सत्र बैठक के संचालन के लिए 22 जुलाई 2019 को भारत का दौरा किया था। रूसी परिसंघ के विदेश मंत्री श्री सर्जी लावरोव ने 15 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली की द्विपक्षीय यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री से भेंट की। विदेश मंत्री लावरोव ने रायसीना वार्ता 2020 में मुख्य भाषण दिया।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 12 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान - ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, द एपोस्टल से पुरस्कृत करने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार के विकास तथा रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में प्रधानमंत्री के विशिष्ट योगदान के लिए इस आदेश की घोषणा की गई थी। इस पुरस्कार को प्रदान करने का समारोह बाद में एक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित किया जाएगा।

उप प्रधानमंत्री और रूस के सुदूर पूर्वी संघीय जिले के राष्ट्रपति के दूत श्री यूरी ट्रुटनेव ने 17-20 जून 2019 को पूर्वी आर्थिक मंच के लिए सितंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तोक यात्रा के लिए आधार तैयार करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुदूर पूर्व में द्विपक्षीय सहयोग का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार से मुलाकात की।

श्री दिमित्री रोगोजिन, महानिदेशक, राज्य अंतरिक्ष सहयोग (आरओएससीओएसएमओएस) ने 11 जुलाई 2019 को भारत का दौरा किया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन से भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान कार्यक्रम पर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की।

प्रधान मंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, व्लादिवोस्तोक की अपनी यात्रा के दौरान ज़्वेज़्दा शिपबिल्डिंग प्लांट का दौरा करते हुए (04 सितंबर, 2019)

रूसी उप प्रधानमंत्री श्री यूरी बोरिसोव ने 22 जुलाई 2019 को नई दिल्ली का दौरा किया और भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) की अंतर-व्यावसायिक बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए विदेश मंत्री से मुलाकात की। यह आईआरआईजीसी-टीईसी की सह-अध्यक्ष के रूप में उनकी पहली बैठक थी।

युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने 28 जुलाई से 2 अगस्त, 2019 तक रूस में 32 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 11-13 अगस्त 2019 से व्लादिवोस्तोक में भारतीय कंपनियों के 140 सशक्त व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्रियों के एक उच्च-शक्ति प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस यात्रा ने प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तोक यात्रा के लिए आधार तैयार किया और रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों की योजना तैयार करने में मदद की। भारतीय राज्यों और रूसी क्षेत्रों के बीच यात्रा के दौरान पांच समझौते हुए।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 21 अगस्त 2019 को मास्को का दौरा किया और रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिव श्री निकोलाई पेत्रुसेव से मुलाकात की। उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में चल रहे सहयोग की समीक्षा करने के लिए राष्ट्र के अंतरिक्ष सहयोग (आरओएससीओएसएमओएस) के महानिदेशक श्री रोगोज़िन से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 27-28 अगस्त 2019 को मास्को का दौरा किया और विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार सामरिक साझेदारी की स्थिति और संभावनाओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्री ने आईआरआईजीसी के सह-अध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री श्री यूरी बोरिसोव से भी मुलाकात की। उन्होंने वल्दाई चर्चा क्लब में हिंद-प्रशांत पर भारत के दृष्टिकोण पर एक सत्र को भी संबोधित किया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 29 और 30 अगस्त 2019 को मास्को का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री

प्रधान मंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, व्लादिवोस्तोक की अपनी यात्रा के दौरान ज़्वेज़्दा शिपबिल्डिंग प्लांट का दौरा करते हुए (04 सितंबर, 2019)

श्री यूरी ट्रुटनेव से मुलाकात की तथा ऊर्जा और धातु क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने ऊर्जा मंत्री श्री अलेक्जेंडर नोवाक से भी मुलाकात की तथा भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व में तेल, गैस और इस्पात क्षेत्रों में अवसरों की समीक्षा करने के लिए 22-25 अक्तूबर 2019 से व्लादिवोस्तोक और सखालिन का दौरा किया।

भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग-सैन्य तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) की 19 वीं बैठक के लिए श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने 5-7 नवंबर 2019 को मास्को का दौरा किया। बैठक के दौरान रक्षा उपकरणों, उद्योग और तकनीकी सहभागिता, बिक्री समर्थ/उन्नयन और परियोजनाओं के संयुक्त निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री राजनाथ सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-रूस उच्च स्तरीय समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक में उप प्रधानमंत्री श्री यूरी बोरिसोव से भी मुलाकात की।

दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा व्यापार और आर्थिक संबंधों को सशक्त करने के लिए एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2018 में व्यापार 17.25% बढ़ा और 10.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2019 में जनवरी-सितंबर 2019 से दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 7.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों ओर से 2025 तक निर्धारित 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न पहलों के हिस्से के रूप में दूसरी भारत-रूस सामरिक वार्ता 10 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और उप आर्थिक मंत्री श्री तिमूर मैक्सिमों की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बाद में रूसी आर्थिक मंत्री श्री मैक्सिम ओर्स्किन ने 21 अगस्त 2019 को नई दिल्ली का दौरा किया। व्लादिवोस्तोक में सितंबर 2019 में 20वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी आर्थिक विकास मंत्री और भारत के वाणिज्य विभाग के बीच भारत-रूस व्यापार, आर्थिक, और निवेश सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्यनीति दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मास्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा पूरे वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाए जाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लियो टॉल्स्टॉय संग्रहालय और एस्टेट तथा इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के सहयोग से दूतावास ने 28 सितंबर 2019 को यज्ञ पोलीना में टॉल्स्टॉय एस्टेट में महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के बीच ऐतिहासिक आदान-प्रदान के लिए एक दिवसीय प्रदर्शनी और अकादमिक सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य ड्रूमा में 2 अक्तूबर, 2019 को एक गांधी-टॉलस्टॉय प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी।

बेलारूस

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और बेलारूस के विदेश मंत्री श्री व्लादिमीर मेकी की 25 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 74वें के अवसर पर भेंट हुई। दोनों ने स्मार्ट सिटीज क्षेत्र और मेक इन इंडिया सहित द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की।

गृह मंत्रालय के संयुक्त निदेशक श्री महेश दीक्षित की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3-4 सितंबर 2019 को मिन्स्क में आयोजित आतंकवाद रोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

राजदूत (सेवानिवृत्त) सुजान चिनॉय ने 7-8 अक्तूबर 2019 को मिन्स्क में आयोजित मिन्स्क संवाद मंच में महानिदेशक, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

सीआईआई के नेतृत्व में 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 17 से 20 सितंबर 2019 को मिन्स्क में आयोजित बेलारूसी औद्योगिक और निवेश फोरम में भाग लिया। सीआईआई ने निवेश और निजीकरण की राष्ट्रीय एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 16-सदस्यीय सीएपीईएक्सआईएल प्रतिनिधिमंडल ने बी2बी बैठकों के लिए 25-27 सितंबर 2019 को मिन्स्क का दौरा किया।

विभिन्न तकनीकों के प्रदर्शन के लिए हैदराबाद में बेलारूसी-भारतीय केंद्र को खोले जाने की योजना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से बेलारूस के 8-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 24-28 सितंबर 2019 को यात्रा के दौरान केंद्र को खोलने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय दूतावास द्वारा 12 नवंबर 2019 को मिन्स्क में गुरु नानक जयंती समारोह मनाया गया।

यूक्रेन

यूक्रेनी राष्ट्रपति चुनावों और यूक्रेनी संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी की जीत के बाद श्री वलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा पद संभालने के बाद 1 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने श्री जेलेंस्की को टेलीफोन पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने संक्षेप में व्यापार और अर्थव्यवस्था, लोगों से लोगों के बीच संपर्क, शिक्षा और पर्यटन सहित चल रहे द्विपक्षीय सहयोग वाले विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने की अपनी तपरता की भी पुष्टि की।

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने 25 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अवसर पर यूक्रेनी विदेश मंत्री श्री वडिम पिस्टोरिको से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा और कृषि सहयोग में संभावनाओं पर चर्चा की।

इसरो के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के निमंत्रण पर 8-13 जुलाई, 2019 को यूक्रेन का दौरा किया ताकि प्रौद्योगिकी और डेटा साझाकरण में पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के अवसरों का पता लगाया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल स्पेस फैसिलिटीज कंट्रोल एंड टेस्ट सेंटर (एनएसएफसीटीएल) के प्रमुख श्री वलोडिमिर प्रिसियाज़नी से भी मुलाकात की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तवावधान में द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग में सहयोग की खोज के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान सहयोग (बार्क) के एक प्रतिनिधि मंडल ने 9-18 सितंबर, 2019 तक यूक्रेन का दौरा किया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत-यूक्रेन कार्यकारी समूह की चौथी बैठक 2 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सीआईआई के एक प्रतिनिधि मंडल ने 'भारत मंडप' की स्थापना की और 14-17 मई 2019 तक वर्ल्ड बिल्ड कीव एक्सपो के 17 वें सत्र में भाग लिया। फिक्की के एक प्रतिनिधिमंडल ने 17-19 सितंबर 2019 तक कीव में आयोजित फार्मा टेक एक्सपो में भाग लिया।

कीव स्थित भारतीय दूतावास ने 1 मई 2019 को वार्षिक कीव साइक्लिंग मैराथन में भाग लिया जिसमें भारत के राजदूत श्री पार्थ सत्पथी और कीव के मेयर श्री विटालि क्लिट्सको ने महात्मा गांधी के संदेश को प्रसारित करने के लिए उपस्थित दर्शकों को संबोधित किया। 'ऑल यूक्रेनी डांस फेस्टिवल ऑफ इंडियन डांस-रैथम्स ऑफ जॉय' का 19वां सत्र 16-17 नवंबर, 2019 को ओडिशा में आयोजित किया गया जिसमें 250 से अधिक यूक्रेनी नर्तकियों ने भारतीय नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया। यूक्रेन में आयुर्वेद और योग पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 23-24 नवंबर, 2019 को कीव में नवगठित यूक्रेनी एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद एंड योग (यूएएवाई) द्वारा आयोजित किया गया।

आर्मेनिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री श्री निकोल पशिनयान ने 25 सितंबर 2019 को भारत-आर्मेनिया द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर मुलाकात की। श्री पशिनयान ने प्रधानमंत्री को आर्मेनिया की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी।

आर्मेनिया के स्वास्थ्य मंत्री श्री आर्सेन टोरोसियन ने 2-6 दिसंबर, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय जीएवीआई गठबंधन बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की और स्वास्थ्य क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 'हे पोस्ट' (आर्मेनिया पोस्ट) ने 23 मई 2019 को महात्मा गांधी पर एक डाक टिकट जारी किया।

अजरबैजान

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 18वें एनएएम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 24-26 अक्तूबर 2019 को बाकू गए थे। अजरबैजान की आजादी के बाद भारत की यह पहली अतिविशिष्ट यात्रा थी। एनएएम शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा उपराष्ट्रपति ने अपने स्वागत के लिए आयोजित एक भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में भाग लिया।

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने 28 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर अज़रबैजान के विदेश मंत्री श्री एल्मर ममाडिरोव से मुलाकात की। उन्होंने संयोजकता, संस्कृति, ऊर्जा और क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और अन्य क्षेत्रों में विकास करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

भारत के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने अपने अज़रबैजान समकक्षों के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ) और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के 28 सदस्यीय संयुक्त मल्टी-प्रोडक्ट बिजनेस प्रतिनिधि मंडल ने 1-2 जुलाई 2019 को बाकू का दौरा किया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 21-22 नवंबर 2019 को बाकू का दौरा किया। मार्च और सितंबर 2019 में बाकू में दो विशेष भारतीय उत्पाद प्रदर्शनी आयोजित की गईं।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर के निदेशक डॉ. वी.एन. वाघमारे को 27 अक्तूबर से 02 नवंबर, 2019 तक अजरबैजान के साथ कपास की खेती में सहयोग का पता लगाने के लिए नियुक्त किया।

महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर अज़रबैजान गणराज्य के परिवहन, संचार और उच्च प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 'अज़मर्ला' ने महात्मा गांधी पर 70 जिपिक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा अजरबैजान में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक पेंटिंग प्रदर्शनी, साइकलिंग और पौध-रोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जार्जिया

भारत और जॉर्जिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। जॉर्जिया में राष्ट्रपति चुनावों के बाद भारत के राष्ट्रपति ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की आशा व्यक्त करते हुए, सुश्री सैलोम ज़ुराबिचविली को बधाई दी।

दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने हेतु ठोस प्रयास करने के लिए भारत और जॉर्जिया ने जून 2019 में व्यापार और आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन करने पर सहमति व्यक्त की।

आर्मेनिया में भारत के राजदूत श्री के. डी. देवल, जिन्हें समवर्ती रूप से जॉर्जिया में नियुक्त किया गया, ने 6 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति सुश्री सैलोम ज़ुराबिशिली को अपना प्रत्यय पत्र दिया।

17 नवंबर 2019 को जॉर्जिया के त्सोरी के गुरुद्वारा धन गुरु नानक दरबार साहिब में सिख समुदाय के साथ भारत के दूतावास द्वारा गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती मनाई गई।

कजाकिस्तान

वर्ष के दौरान भारत और कजाकिस्तान के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग मजबूत बना रहा, जिसमें दोनों पक्षों के दौरे, रक्षा सहयोग, व्यापार मेलों में भागीदारी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल थे।

राज्य सभा के उप-सभापति श्री हरिवंश, नूर-सुल्तान में आयोजित यूरेशियन देशों के संसद के वक्ताओं की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए 23-24 सितंबर को कजाकिस्तान गए। अपने भाषण के दौरान श्री हरिवंश ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा, लैंगिक समानता और संयोजकता पर ध्यान केंद्रित किया और अपने संबंधित देशों के लोगों के लाभ के लिए इस दिशा में ठोस प्रयास करने के लिए बैठक में भाग लेने वाले सांसदों से मुलाकात की।

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर कजाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री मुख्तार तुलेबर्डी से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जिसमें लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में भारतीय सैनिकों के साथ कजाक सैनिकों की सह-तैनाती, संयोजकता में सुधार और हाइड्रोकार्बन में व्यापार की क्षमता की संभावना शामिल हैं।

क्षेत्रीय चर्चा मंच 'अस्ताना क्लब' की 5 वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन 11-12 नवंबर, 2019 को कजाकिस्तान गए। उन्होंने कजाकिस्तान की संसद के मजहिलिस के अध्यक्ष श्री नूरलान निगमातुलिन और कजाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री मुख्तार तेलेबुर्दी से भी मुलाकात की।

भारत के चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा 9 जून 2019 को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए कजाकिस्तान गए।

भारत-कजाखस्तान रक्षा सहयोग के अंतर्गत कजाकिस्तान की शांति स्थापना कंपनियां लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में भारतीय बटालियन में क्रमशः मई और नवंबर 2019 में दूसरे और तीसरे दौर के रोटेशन में शामिल हुईं। दोनों देशों के बीच उन्नत संयुक्त सैन्य अभ्यास 'केएजेडआईएनडी 2019' भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 01-16 अक्तूबर 2019 से आयोजित किया गया था। कजाख सेना की टुकड़ी ने अभ्यास में 60 कर्मियों को शामिल किया।

भारत से निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) की भागीदारी शामिल थी जिसमें काजल्ट और एक्वाथर्म 2019

एक्सपो, जिसे अल्माटी में 4-6 सितंबर 2019 तक आयोजित किया गया, में 30 भारतीय कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल; और अल्माटी में 18-20 सितंबर 2019 से आयोजित कज़कोमाक एक्सपो में 18 भारतीय कंपनियों को शामिल करने वाला एक सीएपीईएक्सआईएल प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। दोनों देशों के बीच संयोजकता में सुधार के लिए संयोजकता, परिवहन और संभार तंत्र पर भारत-कजाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 26 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

कजाखस्तान के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग, अंग्रेजी शिक्षाशास्त्र में विद्यालय शिक्षकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तथा क्रमश: हैदराबाद अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय और आईआईटी कानपुर में आयोजित साइबर सुरक्षा के साथ जारी रहा। कजाकिस्तान के 35 प्रतिभागियों ने आईआईटी चेन्नई द्वारा इंडिया-कजाकिस्तान सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 'बिग डेटा' में एक पाठ्यक्रम को पूरा किया।

वर्ष भर महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विदेश मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन की उपस्थिति में कजाकिस्तान पोस्ट द्वारा महात्मा गांधी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करना शामिल है। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती अल्माटी में कीर्तन और कथा के पाठ के साथ मनाई गई, इसके बाद 17 नवंबर 2019 को लंगर हुआ।

किर्गिज गणराज्य

प्रधानमंत्री की किर्गिज़ गणराज्य की 14 जून 2019 को द्विपक्षीय यात्रा से भारत और किर्गिज़ गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नया प्रोत्साहन मिला। यात्रा के दौरान, भारत और किर्गिज़ गणराज्य सामरिक साझेदारी स्तर तक अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की घोषणा करने के लिए सहमत हुए। राष्ट्रपति जेनेबकोव और प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से भारत-किर्गिज़ व्यापार मंच का उद्घाटन किया। यात्रा के दौरान सामरिक साझेदारी पर संयुक्त वक्तव्य, व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोड मैप, द्विपक्षीय निवेश संधि सहित 15 एमओयू/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए/अपनाए गए। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण साख की घोषणा की। बिश्केक में 13-26 जून 2019 को किर्गिज़ गणराज्य में प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ भारत-किर्गिज़ संयुक्त कपड़ा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी।

एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक और 1-3 नवंबर 2019 को द्विपक्षीय यात्रा के लिए रक्षा मंत्री की उज्बेकिस्तान यात्रा के फलस्वरूप उज्बेकिस्तान में भारतीय और उज्बेक सशस्त्र बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी की 19-23 अक्तूबर 2019 को यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम, कई समझौता ज्ञापनों के समापन और उज्बेकिस्तान और गुजरात के एंडीजॉन क्षेत्र के बीच सहयोग को और बढ़ावा मिला। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुलअजीज कामिलोव ने 14-15 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली का दौरा किया था जिसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की थी, विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और रायसीना वार्ता 2020 को संबोधित किया था। विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने अस्ताना क्लब की बैठक को संबोधित करने के लिए 11-12 नवंबर 2019 को कजाकिस्तान का दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कजाख संसद के अध्यक्ष श्री निग्मतुलली और विदेश मंत्री मुख्तार तिबरेडी से भी मुलाकात की।

पूर्व विदेश मंत्री, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने 21-22 मई 2019 को एससीओ सदस्य देशों के विदेश

मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किर्गिज़ गणराज्य का दौरा किया था। उन्होंने राष्ट्रपति जेनबकोव से मुलाकात की और किर्गिज़ के विदेश मंत्री श्री चिंगिज़ ऐदरबेकोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र के अवसर पर 27 सितंबर, 2019 को किर्गिज़ के विदेश मंत्री श्री एदारबेकोव से मुलाकात की।

पूर्व रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल, 2019 को बिश्केक में एससीओ सदस्य राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों की परिषद् की बैठक में भाग लिया। उन्होंने यात्रा के दौरान अपने किर्गिज समकक्ष मेजर जनरल रायम्बरदी दुइशेनबिएव से भी मुलाकात की।

10वां भारत-किर्गिस्तान विदेश कार्यालय परामर्श 20 अप्रैल 2019 को बिश्केक में हुआ था। किर्गिज प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप-विदेश मंत्री श्री नुरलान अब्दुर्रमानोव ने किया था और भारतीय पक्ष का नेतृत्व तकालीन सचिव (पश्चिम) श्री ए. गितेश सरमा ने किया था। सचिव (पश्चिम) ने यात्रा के दौरान किर्गिज विदेश मंत्री से मुलाकात की।

फिक्की द्वारा समन्वित 'नमस्कार यूरेशिया' नामक एक इंडिया ट्रेड एक्सपो 9-11 नवंबर 2019 तक बिश्केक में आयोजित किया गया था। इस एक्सपो में रक्षा उद्योग पर भी विशेष ध्यान दिया गया था और इसका उद्घाटन किर्गिज़ रक्षा मंत्री मेजर जनरल दुइशेनबिएव द्वारा किया गया।

ताजिकिस्तान

भारत-ताजिकिस्तान सामरिक साझेदारी चालू वर्ष के दौरान बढ़ती और मजबूत होती रही। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 14-15 जून 2019 को एशिया में सहभागिता और विश्वास बहाली उपायों के सम्मेलन (सीआईसीए) के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुशांबे का दौरा किया। शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री ने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री श्री सिरोजिद्दीन मोहरदीन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों ने 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर भी एक बैठक की।

प्रथम भारत-ताजिक कांसुलर परामर्श 6-8 जून 2019 को दुशांबे में आयोजित किया गया था। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) श्री संजीव अरोड़ा और ताजिक उप विदेश मंत्री श्री ज़ोहिर ओजोद वैदज़ोडा ने किया। 2018 में युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्षों ने सितंबर और अक्तूबर 2019 में 10-सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान किया।

26 नवंबर 2019 को दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को काफी बढ़ावा मिला जब ताजिक एयर ने दुशांबे और दिल्ली के बीच अपनी सीधी साप्ताहिक उड़ान फिर से शुरू की जबकि सोमोन एयर, एक निजी ताजिक एयरलाइन ने 1 दिसंबर 2019 से दुशांबे-दिल्ली-दुशांबे की सीधी उड़ान शुरू की।

ताजिकिस्तान ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर चार स्मारक टिकटों का एक सेट जारी किया। नवंबर 2019 में भिन्न रूप से सक्षम दो ताजिक कलाकारों ने 'संभव 2019' संगीत उत्सव में अपना प्रदर्शन दिया जिसे दिल्ली के एक एनजीओ, 'अल्पना' द्वारा आयोजित किया गया। 2019 में भारत-ताजिक मैत्री सोसायटी ने ताजिक भाषा में 9 पुस्तकें प्रकाशित कीं, जिनमें कुछ महान भारतीय कृतियों के अनुवाद भी शामिल हैं।

तुर्कमेनिस्तान

भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध है।

तुर्कमेनिस्तान ने 11 और 12 अगस्त 2019 को तटीय शहर अवाज़ा में पहले कैस्पियन आर्थिक फोरम की मेजबानी की। गेल (इंडिया) लिमिटेड के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने फोरम में भाग लिया। आधिकारिक स्तर पर भारत के राजदूत श्री अजार ए. एच. खान ने इस फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

नई दिल्ली में 9 सितंबर 2019 को आयोजित मरूस्थलीकरण से निपटने संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के दलों के 14 वें सम्मेलन में कृषि उप मंत्री श्री अल्लानुर अल्तयेव की अगुवाई में एक 3-सदस्यीय तुर्कमेन प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। तुर्कमेनिस्तान के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन के दौरान मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए देश उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

धन-शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण (ईएजी) पर यूरेशियाई समूह की 31वीं पूर्ण बैठक 25-29 नवंबर, 2019 से अश्गाबात में आयोजित की गई। इस पूर्ण बैठक में वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 73 वें सत्र में 22 अगस्त 2019 को 2021 के 'शांति और विश्वास के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया।

तुर्कमेनिस्तान ने इस क्षेत्र में पहले योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की मेजबानी की जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। भारत के दूतावास, अश्गाबत ने 25 अक्तूबर 2019 को चौथे आयुर्वेद दिवस का आयोजन अश्गाबात स्थित स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया। राजदूत ने आज की दुनिया में आयुर्वेद की प्रासंगिकता पर उपस्थित समूह को संबोधित किया और उसके बाद आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. दिनेश बरुआ द्वारा आयुर्वेद और इसके लाभों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के प्रमुख श्री गेल्दिमिरत जुमागुलियेव और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्राचार्य सुश्री नारगोज़ेल मायरात्नायज़ोवा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अश्गाबत में भारत के दूतावास ने 2 अक्तूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती बग्तियारेलिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अश्गाबट में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर मनाई और इसके बाद गांधीवादी आदर्शों के विषय पर तुर्क कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह के एक भाग के रूप में 4 अक्तूबर, 2019 को होटल 'येल्डिज़' में एक 'शाकाहारी खाद्य महोत्सव' आयोजित किया गया। श्री सपरडर्डी टॉयलियेव, तुर्कमेनिस्तान के विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष इसमें तुर्कमेन की ओर से मुख्य अतिथि थे।

श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती 12 नवंबर 2019 को चांसरी परिसर में मनाई गई थी। भारतीय समुदाय और स्थानीय तुर्कमान जनता को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान दूतावास के अधिकारियों के बच्चों ने श्री गुरु नानक देव जी पर भाषण दिए, उसके बाद एक वृत्तचित्र फिल्म दिखायी गयी।

उज्बेकिस्तान

उच्च स्तरीय नियमित यात्राओं के साथ इस साल भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों में और संवर्धन हुआ। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1-3 नवंबर, 2019 तक एससीओ प्रमुखों की बैठक में भाग लेने के लिए ताशकंद का दौरा किया और एक द्विपक्षीय यात्रा भी की जिसमें उन्होंने अपने उज़्बेक समकक्ष मेजर जनरल बखोदिर कुर्बानोव

से मुलाकात की। दोनों ने संयुक्त रूप से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया जो 4-14 नवंबर 2019 तक हुआ था।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने 19-23 अक्तूबर 2019 के दौरान उज्बेकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेश फोरम "ओपन एंडिजोन" में भाग लिया तथा राष्ट्रपति श्री शव्कत मिर्ज़ियोयेव और उप प्रधानमंत्री श्री एलोर गानिएव से मुलाकात की। यात्रा के दौरान श्री रूपानी ने एंडिजॉन में "सरदार पटेल स्ट्रीट" का उद्घाटन किया और सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी यात्रा के बाद नवंबर, 2019 के अंत में भारत में 50 सदस्यीय उज़्बेक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा हुई। कृषि मंत्रालय, उज़्बेकिस्तान और गुजरात सरकार के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर 29 नवंबर, 2019 को हस्ताक्षर किया गया।

उज्बेकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री श्री पुलट बोबोजोनोव ने गृह मंत्री श्री अमित शाह के निमंत्रण पर 20-22 नवंबर, 2019 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने द्विपक्षीय चर्चा की और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्री बोबोजोनोव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में भी श्रद्धांजलि दी।

आतंकवाद रोधी संबंधी द्विपक्षीय संयुक्त कार्यकारी समूह की 8 वीं बैठक नई दिल्ली में जुलाई 2019 में आयोजित की गई। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री पंकज सरन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय और उज्बेक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के बीच पहले ऐसे द्विपक्षीय परामर्श के लिए 23-25 सितंबर, 2019 से ताशकंद का दौरा किया।

भारत और उज्बेकिस्तान ने सितंबर 2019 में एक अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) के लिए वार्ता करने हेतु एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।

समरकंद राज्य विश्वविद्यालय ने अक्तूबर 2019 में एक 'भारतीय अध्ययन केंद्र' स्थापित किया। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर उज्बेक सरकार ने महात्मा गांधी पर एक डाक टिकट जारी किया।

शंघाई सहयोग संगठन

अप्रैल-नवंबर 2019 की अवधि के दौरान, भारत-शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सहयोग की गति भारत के पुराने सांस्कृतिक संबंधों के साथ-साथ एससीओ सदस्यों के साथ अपने जीवंत आधुनिक संबंधों के आधार पर बढ़ती रही। भारत ने किर्गिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ के विभिन्न वार्ता तंत्रों में सक्रिय और एससीओ राष्ट्र प्रमुख परिषद् के स्वरूप में उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में सक्रिय रूप से भाग लिया। तकालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने बिश्केक (किर्गिस्तान) में 22 मई 2019 को हुई एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद् की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2019 को बिश्केक (किर्गिस्तान) में किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद् की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेताओं ने बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्रों प्रमुखों के मंच के विनियमों और डिजीटलीकरण तथा सूचना-संचार के क्षेत्र में सहयोग की अवधारणा सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद (उजबेकिस्तान) में उजबेकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री अब्दुल्ला अरिपोव की अध्यक्षता में 2 नवम्बर, 2019 को आयोजित एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद् की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आपात स्थितियों के निवारण और परिसमापन से संबंधित

एससीओ की 18 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में हुई 10वीं बैठक की अध्यक्षता की।

अप्रैल-नवंबर 2019 की अवधि के दौरान, भारत ने किर्गिस्तान की अध्यक्षता और एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद् के स्वरूप में उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न एससीओ संवाद तंत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

तकालीन सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय श्री ए. जितेश सरमा ने बिश्केक (किर्गिस्तान) में 19 अप्रैल 2019 को आयोजित एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (गृह मंत्रालय) के महानिदेशक श्री अभय ने 25 अप्रैल 2019 को चोलपोन-अटा (किर्गिस्तान) में आयोजित अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए उत्तरदायी एससीओ प्रमुखों की 9वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तकालीन रक्षा मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिश्केक में 29 अप्रैल 2019 को हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री पंकज सरन ने बिश्केक में 15 मई 2019 को आयोजित एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 14वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुण गोयल ने बिश्केक में 15 मई 2019 को आयोजित एससीओ संस्कृति मंत्रियों की 16वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

तकालीन विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने बिश्केक में 22 मई 2019 को हुई एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद् की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बैठक में जून 2018 एससीओ शिखर सम्मेलन के निर्णयों के कार्यान्वयन के साथ-साथ एससीओ प्रमुखों की परिषद् की अक्तूबर 2018 को हुई बैठक में प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें जून 2019 एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई और पर्यवेक्षकों और संवाद सहयोगियों के साथ एससीओ सचिवालय के विकास की रूपरेखा को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2019 को बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद् की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेताओं ने बिश्केक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें एससीओ के विकास की संभावनाओं के साथ-साथ अंतर्राष्टीय और क्षेत्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर एससीओ सदस्य देशों की सहमत स्थितियों को रेखांकित किया गया। नेताओं ने 2019-2020 के लिए एससीओ स्वापक-रोधी रणनीति के लिए कार्य योजना, क्षेत्रों के प्रमुखों के मंच के विनियमों, डिजिटलीकरण और सूचना-संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग की अवधारणा, एससीओ अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के विकास के कार्यक्रम आदि सहित एससीओ के कई दस्तावेजों को भी मंजूरी दी गई। एससीओ के सदस्य देशों ने मास मीडिया और शारिरिक शिक्षा/खेल-कूद के क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ 2019-2021 के लिए स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक बुनियादी कार्य योजना के लिए समझौतों को अंतिम रूप दिया। एससीओ सम्मेलन में एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की कार्रवाई की भावी योजना के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन में एससीओ सचिवालय, संयुक्त राष्ट्रीय मानवीय मामले समन्वय कार्यालय और अस्ताना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत के तकालीन मुख्य न्यायाधीश, श्री रंजन गोगोई ने सोची (रूस) में 17-19 जून 2019 को आयोजित एससीओ सदस्य देशों के उच्चतम न्यायालयों के अध्यक्षों की 14वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एससीओ रक्षा सहयोग योजना 2019-20 के रूप में प्रथम दो दिवसीय सैन्य चिकित्सा सम्मेलन का उद्‌घाटन रक्षा मंत्री ने 12-13 सितंबर 2019 को भारत में आयोजित किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित कार्रवाई चिकित्सा दल टीम का प्रदर्शन किया और नई दिल्ली में सेना अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में सैन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडलों के लिए

एक निर्देशित दौरे का आयोजन किया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने नूर-सुल्तान (कजाकिस्तान) में 19 सितंबर 2019 को आयोजित एससीओ सदस्यों के रेलवे प्रशासन प्रमुखों की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में 26 सितंबर 2019 को हुई बाह्य अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार के लिए उत्तरदायी एससीओ मंत्रियों की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मास्को (रूस) में 27 सितम्बर, 2019 को आयोजित एससीओ पर्यावरण संरक्षण मंत्रीयों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अतिरिक्त महान्यायभिकर्ता, सुश्री पिंकी आनंद ने एससीओ माहभियोजक की 1 अक्तूबर, 2019 को बिश्केक में आयोजित 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद में 2 नवंबर 2019 को उज्बेकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम अब्दुल्ला अरिपोव की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ सरकार प्रमुखों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद् की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बैठक में एससीओ के भीतर व्यापार-आर्थिक और मानवीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई और वैश्विक व क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। बैठक में अनुमोदित महत्वपूर्ण दस्तावेजों में बहुपक्षीय व्यापार-आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, एससीओ सदस्यों के रेलवे प्रशासनों की बातचीत की अवधारणा, एससीओ आर्थिक विश्लेषणात्मक केंद्रों के संघ के विनियम एससीओ शहरों को पारिस्थितिक हितों का विकास शामिल था। बैठक में एससीओ के सदस्य देशों की सीमा शुल्क सेवाओं में राष्ट्रीय पारगमन प्रणालियों के पारस्परिक एकीकरण पर समझौते ज्ञापन एससीओ सचिवालय व संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 8 नवंबर 2019 को आपात स्थिति की रोकथाम और परिसमापन से संबंधित एससीओ विभागाध्यक्षों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक से पूर्व, भारत ने नई दिल्ली में 4-7 नवंबर 2019 से आपात स्थितियों की रोकथाम और परिसमापन से संबंधित विशेषज्ञों की एससीओ संयुक्त शहरी भूकंप बचाव अभ्यास और एससीओ बैठक की भी मेजबानी की।

5

खाड़ी और पश्चिम एशिया

बहरीन

भारत के बहरीन के साथ उत्कृष्ट, गहन और ऐतिहासिक संबंध हैं। बहरीन में भारतीय समुदाय बहुतायत में है और द्विपक्षीय संबंधों का आधार बना हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2017-18 में 987.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1281.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 30% से अधिक है जिसमें 742.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ और 539.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ।

बहरीन साम्राज्य के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 -25 अगस्त 2019 को बहरीन साम्राज्य की यात्रा की जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने बहरीन के सम्राट शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा से भेंट की। बहरीन के सम्राट ने बहरीन साम्राज्य के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के अपने प्रयासों को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री को 'बहरीन आर्डर-फॅस्ट क्लॉस' सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। उन्होंने बहरीन के क्राउन प्रिंस से भी भेंट की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में 200 वर्ष पुराने श्रीनाथ जी मंदिर (सबसे पुराना हिंदू मंदिर) के पुनर्विकास का शुभारंभ किया।

जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम; अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर आशय का वक्तव्य; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में बहरीन के शामिल होने पर वक्तव्य, और बहरीन में "रूपे कार्ड" का शुभारम्भ शामिल हैं। इनसे द्विपक्षीय संबंधों को अग्रसर करने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

प्रधान मंत्री को मनामा में अल गुदाईबिया पैलेस में बहरीन के शाह द्वारा किंग हमद रिनेशाँ पुरस्कार से सम्मानित किया गया (24 अगस्त, 2019)

कुवैत

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुवैत के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ और ये अधिक गहन हुए। वर्ष 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 8.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया जिसमें भारतीय निर्यात कुल 1.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 7.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारतीय समुदाय के आकार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग दस लाख है; और देश में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बना हुआ है, जो कुवैत में भारतीय समुदाय द्वारा प्राप्त घनिष्ठ विश्वास, सद्भावना और अपनेपन का घोतक है।

भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने 14-15 सितंबर 2019 को कुवैत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुवैत के उप विदेश मंत्री खालिद सुलेमान अल-जरल्लाह और आर्थिक मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती मरियम अल-अकील से भेंट की।

कुवैत इंजीनियर्स सोसायटी के अध्यक्ष इंजीनियर फैसल ड्वेह अल अटाल के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क और नवाचार उपलब्धि पर संस्थानों की अटल रैंकिंग की वार्षिक रैंकिंग स्पर्धा में भाग लिया जिसका संयोजन नई दिल्ली में अप्रैल 2019 में किया गया था। कुवैत इंस्टिट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च (केआईएसआर)

के महानिदेशक डॉ. समीरा ए.एस. उमर के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर 2019 में भारत का दौरा किया और इसरो, सीएसआईआर, आईआईएससी सहित भारत के अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ वार्ता की।

ईराक

ईराक के भारत के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत हैं और यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ईराक विगत तीन वर्षों में भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। वर्ष 2018-19 के दौरान हमारा द्विपक्षीय व्यापार 24.161 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो पिछले वर्ष के दौरान 19.07 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में 27.06% अधिक था। द्विपक्षीय वर्ता में तेल आयात सर्वाधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ष 22.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तेल आयात द्विपक्षीय व्यापार का 92% से अधिक है।

ईराक में एक अस्थिर सरकारी संरचना और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों ने दोनों पक्षों को अपने इष्टतम राजनीतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने में सुकर नहीं होने दिया। विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने 16-17 सितंबर, 2019 को ईराक का दौरा किया और ईराक के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने कुर्दिस्तान क्षेत्र में इरबिल का भी दौरा किया जहां उन्होंने कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष से भी भेंट की और शहर के एक प्रमुख स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। संसद सदस्य श्री भर्तृहरि महताब ने 03-06 सितंबर 2019 को बगदाद में एशियाई संसदीय सभा की बैठक में भाग लेने के लिए ईराक का दौरा किया था। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन से इतर 24 अक्तूबर 2019 को बाकू में ईराकी विदेश मंत्री से भेंट की। आईओसीएल के एक प्रतिनिधिमंडल ने 17-18 अप्रैल, 2019 को बगदाद का दौरा किया और तेल के क्षेत्र में संबद्धता के लिए तेल के विपणन राज्य संगठन (एसओएमओ) के साथ बैठक की थी।

भारत ने क्षमता निर्माण में ईराक की सहायता जारी रखी। वर्ष 2019-20 के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 200 स्लॉट आवंटित किए गए थे। 29 ईराकी राजनयिकों के एक बैच ने अगस्त-सितंबर, 2019 में एफएसआई में प्रशिक्षण प्राप्त किया। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 18 ईराकी अधिकारियों के एक अन्य समूह ने मार्च-अप्रैल, 2019 में हैदराबाद के अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू) में अंग्रेजी प्रवीणता के लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ईराक के लोगों के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त करने और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत एक पसंदीदा स्थल बना रहा। ईराक में लगभग 30,000-40,000 भारतीय बगदाद, कर्बला, नजफ और समरा की तीर्थयात्रा करते हैं। एयर इंडिया ने मार्च 2019 में लखनऊ-नजफ रूट पर सीधी उड़ानें शुरू कीं।

ओमान

भारत और ओमान के साझे व्यापार, सांस्कृतिक और लोगों के परस्पर संबंध सदियों पुराने हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2018 में ओमान यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को काफी बढ़ावा मिला। व्यापार, सुरक्षा और रक्षा सहयोग द्विपक्षीय सहयोग के मजबूत स्तंभ बने रहे। खनन, उच्च शिक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सकारात्मक चर्चा हुई।

ओमान ने इंडिया फाउंडेशन द्वारा मालदीव में सितंबर, 2019 में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन (आईओसी) 2019 में भाग लिया, और इसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में महासचिव सैयद बदर बिन हमद बिन हमद बिन हमद अल बुसैदी ने किया था। सम्मेलन से इतर उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी भेंट की। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलावी से भी भेंट की।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय नौसेना के प्रतिनिधिमंडलों ने वर्ष के दौरान ओमान का दौरा किया। वायुसेनाध्यक्ष,एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने भारतीय वायुसेनाध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए ओमान को चुना। वायुसेनाध्यक्ष ने ओमान के रक्षा मंत्री सैयद बदर बिन सऊद अल बुसैदी और ओमान के शाही कार्यालय के मंत्री जर्नल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से चर्चा की। वायुसेनाध्यक्ष ने ओमान की रॉयल एयरफोर्स के कमांडर एयर वाइस मार्शल मतर बिन अली अल ओबैदानी से भी भेंट की।

भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय वायुसेना-रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान एयर स्टॉफ वार्ता में भाग लेने के लिए 13-16 अप्रैल 2019 को ओमान का दौरा किया। भारतीय नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने नौसेना स्टॉफ वार्ता के लिए 02-03 सितंबर 2019 को ओमान का दौरा किया था। द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास, पूर्वी पुल वी 15-26 अक्तूबर 2019 से मसीराह में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच आयोजित किया गया था और वायुसेनाध्यक्ष इसके साक्षी बने। ओमान ने वर्ष के दौरान आगंतुक भारतीय नौसेना के पोतों और भारतीय वायु सेना के विमानों के लिए मूल्यवान प्रचालनिक परिवर्तन सहायता प्रदान करना जारी रखा।

द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध विकास पथ पर अग्रसर रहे। दोनों देशों के बीच अनेक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल दौरे हुए। वित्तीय वर्ष 2018-19 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अप्रैल-अक्तूबर 2019 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 3.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ओमान में भारतीय व्यापारियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए, फिक्की के महासचिव ने सितंबर 2019 में ओमान स्वास्थ्य प्रदर्शनी व सम्मेलन के दौरान ओमान का दौरा किया, जिसमें भारत के सबसे बड़े देश थे और, जिसमें भारत के 48 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान शामिल थे। ओमान के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 17-19 अक्तूबर 2019 से भारत का दौरा किया और वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल एक्सपो एंड समिट 2019 में भाग लिया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति की पहली बैठक 24-25 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसरो के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10-11 सितंबर 2019 को ओमान का दौरा किया और अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा की। भारत ने आईटीईसी के अंतर्गत क्षमता निर्माण और मजबूत क्षमता विकास सहयोग के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखा।

कतर

भारत और कतर के गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर संबंध हैं। कतर में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 7,50,000 है, जो देश में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है।

द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि से संबंध श्रेष्ठ होना स्पष्ट है। वर्ष 2018-19 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 12.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 25% अधिक था। वर्ष 2018-19 के दौरान कतर को भारत का निर्यात 1.61 बिलियन

अमेरिकी डॉलर था और कतर से भारत का आयात 10.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआईए) ने अक्तूबर 2019 में भारतीय एडु-टेक कंपनी बीवाईजेयू में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की।

राज्यसभा के उपसभापति श्री हरि बंश नारायण सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 06-10 अप्रैल 2019 को दोहा में 140वीं अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) असेंबली की बैठक में भाग लिया। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 30 अप्रैल-02 मई 2019 को एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए दोहा का दौरा किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र से इतर 23 सितंबर 2019 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भेंट की और द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में और बढ़ाने पर चर्चा की।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11-12 सितंबर 2019 को कतर का दौरा किया और दोहा में कतर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री श्री साद शेरीदा अल काबी से भेंट की और द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी से भी भेंट की।

वर्ष 2019 को भारत-कतर संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया गया। इस संबंध में यह निर्णय जून 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दोहा यात्रा के दौरान लिया गया था। इसके अंतर्गत लगभग 40 सांस्कृतिक कार्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सऊदी अरब

2.7 मिलियन भारतीय प्रवासियों की मेजबानी के रूप में और भारत को कच्चे तेल के दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में, सऊदी अरब भारत के विस्तारित पड़ोस में एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार है। भारत और सऊदी अरब के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को उच्चतम स्तर पर यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान से पोषित किया गया है। फरवरी 2019 के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून, 2019 को जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर उनके साथ उनसे भेंट की थी।

प्रधानमंत्री ने सऊदी किंग के निमंत्रण पर रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 28-29 अक्तूबर, 2019 को सऊदी अरब का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी परिषद् की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, सऊदी अरब ने 'विजन 2030' के अंतर्गत भारत को राज्य के सामरिक आठ साझेदार देशों में से एक के रूप में चिन्हित किया। ऊर्जा, सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, चिकित्सा उत्पादों, सामरिक पेट्रोलियम भंडार, एसएमई, रुपे कार्ड के शुभारंभ, राजनायिकों के प्रशिक्षण, स्टॉक एक्सचेंज आदि में सहयोग के क्षेत्र में बारह समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

सऊदी अरब ने भारत के चौथे सबसे बड़े व्यापार साझेदार (चीन, अमेरिका और जापान के बाद) और ऊर्जा आवश्यकताओं के एक प्रमुख स्रोत के रूप में अपनी स्थिति कायम रखी है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% इस साम्राज्य से आयात करता है। सऊदी अरब भी भारत के लिए एलपीजी आयात का एक प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2018-19 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में विगत वर्ष की तुलना

में 23.83% की वृद्धि होकर यह 34.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था जिसमें से भारत का आयात 28.47 अरब अमेरिकी डॉलर था।

प्रधानमंत्री सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन को संबोधित करते हुए, 29 अक्तूबर, 2019

सऊदी अरब के ऊर्जा, उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री खालिद अल फलिह ने पेट्रोलियम और भारत प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए 25 जुलाई को भारत का दौरा किया था और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 8 सितंबर 2019 को जेद्दा का दौरा किया था और सऊदी ऊर्जा-मन्त्री प्रिंस अद्वैत्ज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से भेंट की और ऊर्जा सहयोग के पहलुओं पर चर्चा की।

इस अवधि के दौरान अनेक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने सऊदी अरब का दौरा किया। इनमें शामिल है: इन्वेस्ट इंडिया (अप्रैल और जुलाई) हैं; टीपीसीआई (सितंबर और नवंबर); एफआईईओ (नवंबर) शामिल हैं भारत में उपलब्ध निवेश और व्यापार के अवसरों की पेशकश की गई और सऊदी अरब में व्यापार की संभावनाएं तलाशी गई। फार्मेक्सिल और एसोचैम ने क्रमशः वार्षिक एसएफडीए प्रदर्शनी (सितंबर) और फूडेक्स (नवंबर) में भाग लिया। सऊदी भारत व्यापार परिषद् के प्रतिनिधिमंडल ने सीआईआई के निमंत्रण पर सितंबर में भारत का दौरा किया था और पर्यावरण, कृषि और जल मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2019 में नई दिल्ली और मुंद्रा का दौरा किया था।

सऊदी अरब में भारतीय समुदाय की संख्या को देखते हुए सामुदायिक कल्याण के मुद्दों पर संयोजकता सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। कौंसुली और श्रम

मुद्दों पर संयुक्त कार्यकारी समूह की द्वितीय बैठक 14 अक्तूबर को रियाद में हुई थी। भारत से सर्वाधिक अधिक 200,000 भारतीय तीर्थयात्रियों ने 2019 में हज किया।

रक्षा सहयोग में, जनवरी 2019 में रियाद में हुई रक्षा सहयोग संयुक्त समिति (जेसीडीसी) की चौथी बैठक के बाद भारत के रक्षा उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल ने साम्राज्य का दौरा किया और जनरल अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्री, सऊदी अरब सैन्य उद्योग, सैन्य उद्योग निगम और रॉयल सऊदी सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथमेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा उद्योग साझेदारी पहलों में प्रगति पर चर्चा की।

संयुक्त अरब अमीरात

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी के लिए 2017 से पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 23-24 अगस्त, 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा सहित उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ हुए, इस यात्रा के दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री को ''ऑर्डर ऑफ जईद'' पदक प्रदान किया। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में रूपे कार्ड का शुभारंभ किया और प्रमुख अनिवासी भारतीय व्यापारियों से भेंट की।

वर्ष के दौरान भारत से संयुक्त अरब अमीरात की अन्य मंत्रिस्तरीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल थी - (i) वाणिज्य और उद्योग मंत्री और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 21-23 सितंबर, 2019 को निवेश पर अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स की 7वीं बैठक; (ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 9-12 सितंबर, 2019 को 8वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज और 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस और पुन: 10-12 नवंबर 2019 को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन (एडीआईपीईसी) के 35वें सत्र में भाग लेने के लिए; (iii) विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने तीन बार दौरा किया; 14 जून 2019 को, 14-17 अक्तूबर 2019 को जब उन्होंने छठी अबू धाबी वार्ता में भाग लिया और 6-8 नवंबर, 2019 को **आईओआरए मंत्रिपरिषद् की बैठक** में भाग लेने के लिए; (iv) **विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 15-17 नवंबर, 2019 को संयुक्त अरब अमीरात में सर बानी यास फोरम में भाग लिया।**

संयुक्त अरब अमीरात से भारत की उच्चस्तरीय यात्राओं में भारत में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद 7-9 जुलाई 2019 को विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद अल नाहयान की यात्रा शामिल थी। संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा और उद्योग मंत्री सोहेल बिन मोहम्मद फराज फरहा अल मजरूई ने 30-31 अक्तूबर 2019 के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी सभा में संयुक्त अरब अमीरात के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत सरकार ने 16 नवंबर, 2019 से संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को आगमन पर वीजा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की, जो जापान और दक्षिण कोरिया के बाद यह विशेष सुविधा प्राप्त करने वाला केवल तीसरा देश बन गया। संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारतीय नागरिकों को आगमन पर वीजा की सुविधा देने की घोषणा की है।

यमन

भारत और यमन के घनिष्ठ करीबी और ऐतिहासिक और लोगों के बीच परस्पर संपर्कों का लंबा इतिहास है। यमन में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति खराब होने के कारण यमन में भारतीय दूतावास को 14 अप्रैल 2015 के बाद से अस्थायी रूप से जिबूती में स्थानांतरित किया गया है। दूतावास ने यमन में भारतीय नागरिकों को अपनी सहायता देना जारी रखा है।

भारत ने 13 दिसंबर 2018को हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र के 'स्टॉकहोम समझौते' और 05 नवम्बर, 2019 को रियाद में एक शांति समझौते हस्ताक्षरित 'रियाद समझौते' का स्वागत किया। समझौते से आशा है कि यमन में शांति वापस आ जाएगी।

जॉर्डन

भारत और जॉर्डन के बीच गहन संबंध रहे है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जॉर्डन यात्रा और उसके बाद जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्‌वितीय की भारत यात्रा के बाद दोनों नेताओं की 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पुन: भेंट हुई। विदेश मंत्री ने जॉर्डन के अपने समकक्ष से भी 27 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में भेंट की। प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2019 में, 'फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव' शिखर सम्मेलन के दौरान रियाद में शाह अब्दुल्ला द्‌वितीय से भेंट की और विशेष रूप से व्यापार और निवेश में विभिन्न क्षेत्रों में द्‌विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की।

फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) की 62 सदस्यीय महिला व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्डन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमन संघ द्‌वारा आयोजित भारत-जॉर्डन व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए 12 सितंबर 2019 को जॉर्डन का दौरा किया।

21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राजधानी अम्मान में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गढ़ में किया गया। आईसीसीआर से सुश्री सस्मिता पांडा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय ओडिसी नृत्य मंडली ने अम्मान में 15वें अंतर्राष्ट्रीय शहर महोत्सव से संबंधित उत्सव में प्रदर्शन करने के लिए 26 अप्रैल से 3 मई 2019 को जॉर्डन का दौरा किया।

माननीय विदेश मंत्री ने जॉर्डन के अपने समकक्ष श्री अयमान अल सफादी के साथ 6 जनवरी 2020 को क्षेत्रीय मुद्‌दों पर टेलीफोन पर विचार-विमर्श किया।

5-8 फरवरी 2020 से आयोजित होने वाले डेफएक्सपो-2020 में भाग लेने के लिए जॉर्डन की ओर से किंग अब्दुल्ला द्‌वितीय डिजाइन और विकास ब्यूरो के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद फरहाल को नामित किया गया है।

माननीय राज्य मंत्री (वाणिज्य और उद्‌योग) की सह-अध्यक्षता में भारत-जॉर्डन संयुक्त व्यापार और आर्थिक संयुक्त समिति (आईजेजेईसी) का 11वां सत्र फरवरी/मार्च 2020 में आयोजित होने की आशा है।

भारत और जॉर्डन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार रॉक फॉस्फेट के प्रस्तावित खनन और उदारीकरण पर संयुक्त संचालन समिति की बैठक फरवरी/मार्च 2020 में जॉर्डन में होने की आशा है।

भारत-जॉर्डन आईटी के लिए उत्कृष्टता केंद्र फरवरी 2020 में अल हुसैन तकनीकी विश्वविद्‌यालय, अम्मान में स्थापित होने की आशा है।

इज़राइल

यह वर्ष भारत-इजराइल सामरिक साझेदारी और समेकन का साक्षी रहा। जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने 17-19 नवंबर 2019 के दौरान इजरायल का दौरा कर 'जल पर भारत-इज़राइल सामरिक भागीदारी' और वाटेक 2019 - नवीनतम जल प्रौद्योगिकियों पर द्विवार्षिक सम्मेलन पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। आंध्र प्रदेश कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब की राज्य सरकारों (मंत्री स्तर), और दिल्ली के प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने भी कार्यक्रमों में भाग लिया। जल शक्ति मंत्री ने अपने इजरायली समकक्ष डॉ युवल स्टीनिट्ज, ऊर्जा और जल मंत्री के साथ सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) राजेश पंत ने इजरायल में सबसे बड़ा वार्षिक साइबर सुरक्षा सम्मेलन साइबर वीक 2019 में भाग लेने के लिए 23-27 जून 2019 के दौरान इज़राइल का दौरा किया था।

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने 5-7 अगस्त 2019 के दौरान तेल अवीव में अपना वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नेटकॉन 2019 आयोजित किया, जिसमें 1,200 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो इजराइल में अब तक की सबसे बड़ा भारतीय व्यवसायियों की संख्या थी। इजराइल के निर्माण और आवास मंत्री डॉ. यिफात शाशा बिटन ने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया।

रक्षा संबंध भारत-इजरायल सामरिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच नियमित आदान-प्रदान की परंपरा जारी रही। इजरायली वायु सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीकम नॉर्किन ने 18-19 अगस्त 2019 को भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिस दौरान उन्होंने वायु सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने भारतीय समकक्ष एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ से भेंट की। पांच रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड) ने सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आईएसडीईएफ-2019 के दौरान इज़राइल में इंडिया पवेलियन की स्थापना की जून 2019 में इस कार्यक्रम में रक्षा उत्पादन विभाग के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जिसमें सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 16 रक्षा निर्माता शामिल हुए।

5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (20 जून 2019) कार्यक्रम में लगभग 500 लोगों की भागीदारी से तेल अवीव नगर पालिका और संस्कृति एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से हाटचाना में आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह में आयोजित कार्यक्रमों में 5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किबुत्स नान में पेड़ लगाना, 16 सितंबर 2019 को किरयात गेट टाउन में गांधी सर्किल का उद्घाटन, 2 अक्तूबर, 2019 को लेखक शिपर लेव के साथ चर्चा और गार्गी सेठ द्वारा क्यूरेटर और महात्मा गांधी से प्रेरित प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों पर आधारित "सत्य के साथ प्रयोग" नामक प्रदर्शनी का 11 अक्तूबर 2019 को मेनाकेम स्टार्ट हेरिटेज सेंटर में चौथे यरूशलेम बिएननेल में आयोजन शामिल है।

इजरायल की अर्किया उड़ानों ने क्रमश सितंबर और अक्तूबर से कोच्चि और पणजी के लिए सीधी उड़ानें शुरू कीं। मई 2019 में, भारतीय इतिहासकार श्री संजय सुब्रह्मण्यम को तेल अवीव में एक समारोह में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केनेट पोमेरांज के साथ "पास्ट टाईम डाइमेंशन" श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

राष्ट्रीय एकता दिवस और गुरुनानक जयंती की 550 वीं वर्षगांठ के समारोहों में भारतीय समुदायों और इजरायल की बड़ी भागीदारी देखी गई। आईसीसीआर की कथक नृत्य मंडली ने रचना यादव के नेतृत्व में जुलाई में कर्मील नृत्य महोत्सव में प्रदर्शन किया और अगस्त में राग मेले में सरोद वादक देबास्मिता भट्टाचार्य ने प्रदर्शन किया। मास्टर शेफ इंडिया सुश्री शिप्रा खन्ना को प्रदर्शित करने वाले भारत पाक महोत्सव का आयोजन जुलाई में शेरेटन होटल के साथ किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार परवीन सुल्ताना और सितार वादक शाहिद परवेज खान ने 28 नवंबर 2019 को 700 से अधिक दर्शकों को यरुशलम में हुए अंतर्राष्ट्रीय आउड समारोह में प्रदर्शन किया था।

इज़राइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन, क्नीसेट के अध्यक्ष यूली योएल एडेलस्टीन और तेल अवीव के मेयर रॉन हुल्दाई ने वीडियो संदेश जारी किए, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संविधान दिवस की 70 वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर 2019 को भारत के लोगों को ट्वीट पर बधाई दी।

मातृभूमि और आंतरिक सुरक्षा में सहयोग पर भारत और इजराइल के बीच तीसरी संयुक्त संचालन समिति की बैठक इजरायल में 14-16 जनवरी 2020 से हुई, जहां क्षमता निर्माण और पुलिस आधुनिकीकरण पर जेडब्ल्यूजी का आयोजन किया गया था।

रक्षा सचिव की अध्यक्षता में रक्षा पर जेडब्ल्यूजी फरवरी 2020 में होने की संभावना है।

लेबनान

चेन्नई स्थित एक कंपनी ऑपरेशनल एनर्जी ग्रुप (ओईजी) को लेबनान में जोक (198 मेगावाट) और जिय्या (78 मेगावाट) में दो बिजली संयंत्रों के संचालन और रखरखाव का ठेका दिया गया था। लेबनान की एक भू-तकनीकी इंजीनियरिंग, सामग्री परीक्षण और परामर्श फर्म उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकी सेवा (अधिनियमों) ने पुणे स्थित सीक्यूआरए और दुरोक्रेट इंजीनियरिंग सर्विसिंग में 51% हिस्सेदारी हासिल की है। लेबनान की कंपनी तकनीकी जानकारी के अंतरण के अलावा अगले तीन साल में लगभग 10 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी।

विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) श्री टीएस तिरुमूर्ति ने 21-22 मई, 2019 को लेबनान का दौरा किया और 22 मई 2019 को विदेश मंत्रालय के महासचिव श्री हानी चेमैटेली और लेबनान के उत्प्रवासियों और श्री नादिम मुल्ला, लेबनान के प्रधानमंत्री के सलाहकार के साथ बैठकें की।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर लेबनान के डाक विभाग ने महात्मा गांधी पर स्मारक टिकट जारी की।

जन स्वास्थ्य मंत्री के सलाहकार श्री मोहम्मद कलश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल "एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया" पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आया था। शिक्षा क्षेत्र में लेबनान के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने 15वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था।

भारत ने लेबनान (यूनिफिल) में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल की दिशा में योगदान जारी रखा। विदेश विभाग की त्वरित प्रभाव परियोजना के अंतर्गत 19 दिसंबर 2019 को लेबनान में भारतीय दूतावास और इंडबैट-XXI के माध्यम से दक्षिण लेबनान के हबाया क्षेत्र में बर्गुज़ गांव को 35 केवीए का एक जनरेटर सेट दान किया गया था।

फिलिस्तीन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 10 फरवरी 2018 को ऐतिहासिक फिलिस्तीन यात्रा के दौरान घोषित 42.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत सरकार सहायता पैकेज के अंतर्गत फिलिस्तीन में विकास परियोजनाओं पर कार्य में स्थिर गति से प्रगति हुई।

भारत ने फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क और स्कूलों सहित विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए 3.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए। भारत सरकार ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी फॉर फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए निकट पूर्व (यूआरडब्लूए) में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया और यूआरडब्लूए की सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लिया।

फिलिस्तीन ने 2 अक्तूबर 2019 को, महात्मा गांधी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो उनकी 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी "विरासत और मूल्यों" का परिचायक है।

आईटीईसी और आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 180 फिलिस्तीनी लाभान्वित हुए।

सीरिया

इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय के अवसर पर कई द्विपक्षीय आदान-प्रदान और बैठकें हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र से इतर 27 सितंबर 2019 को सीरिया के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और प्रवासियों के मंत्री श्री वालिद अल-मौलेम से भेंट की। श्रम और रोजगार मंत्री श्री एस. ए. गंगवार ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन से इतर जून 2019 में सीरिया के सामाजिक मामलों और श्रम मंत्री सुश्री रीमा कादिरी से भेंट की थी।

संयुक्त सचिव (एनएजे) डॉ. बी. बालाभास्कर के साथ सचिव (ईआर) श्री टी एस तिरुमूर्ति ने 19-21 मई 2019 को दमिश्क का दौरा किया था और प्रधानमंत्री सहित सीरियाई नेतृत्व के साथ विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की और प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों और प्रवासियों के मंत्री, योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आयोग के प्रमुख, बिजली, उद्योग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन मंत्री और विदेश मामलों और प्रवासियों के उप मंत्री के साथ चर्चा की। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) के विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम (डीवीपी) के अंतर्गत सत्तारूढ़ बाथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और उच्च शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख डॉ मोहसेन बिलाल ने 13 से 18 नवंबर 2019 तक भारत का दौरा किया। इस दौरान डॉ बिलाल ने माननीय उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और आईसीसीआर के अध्यक्ष से भेंट की। उन्होंने भारतीय परिषद् में थिंक टैंक, शिक्षाविदों, पत्रकारों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी सार्थक बातचीत की।

क्षमता निर्माण के बारे में, आईटीईसी के अंतर्गत सीरिया को 90 प्रशिक्षण स्लॉट की पेशकश की गई है; मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 'भारत में अध्ययन' कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री अध्ययन करने के लिए सीरियाई छात्रों को अन्य 600 छात्रवृत्तियां आवंटित की गई हैं; और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दौरान आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 18 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

भारत-सीरिया सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र, जिसे दिसंबर 2010 में दमिश्क में स्थापित किया गया था, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण परिचालन नहीं किया जा सका था, को अब 1 अक्तूबर को दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन करके सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए 2019 में एक नैक्स्टजेन केंद्र में अपग्रेड किया गया है।

2x200 मेगावाट की तिसरीन थर्मल पावर प्लांट एक्सटेंशन परियोजना, जिसके लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी को 2010 में सीरिया में आंशिक वित्त-पोषण (52%) के लिए बढ़ाया गया था, को भेल ने सीरिया में संकट के कारण रोक दिया था। सुरक्षा स्थिति में सुधार के साथ ही अक्तूबर 2019 से इस परियोजना पर काम फिर से शुरू हो गया है।

गांधी @150 समारोह के एक हिस्से के रूप में विदेश मंत्री द्वारा शुरू की गई 'मानवता के लिए भारत' विषय के अंतर्गत, जयपुर के भगवान महावीर सहयोग समिति (बीएमवीएसएस) के सहयोग से दमिश्क (दिसंबर 2019 - जनवरी 2020) में एक कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर का आयोजन किया गया था। सीरिया के सामाजिक मामलों और श्रम मंत्री सुश्री रीमा कादरी ने अपने उप मंत्री, सीरियाई पीपुल्स असेंबली के 6 सदस्यों, स्वास्थ्य, विदेश मामलों और प्रवासियों के वरिष्ठ अधिकारियों, रक्षा, सीरिया में भारत के राजदूत और बीएमवीएसएस के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष की उपस्थिति में शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर का उद्देश्य सीरिया में बीएमवीएसएस टीम के 6 सप्ताह के प्रवास के दौरान सीरियाई लाभार्थियों को 500 कृत्रिम अंग फिट करना था। भारत सरकार के इस मानवीय कृत्य की सीरियाई अधिकारियों ने व्यापक रूप से सराहना की है, जिसे स्थानीय मीडिया ने प्रमुखता से कवर किया गया है और सीरियाई लोगों के बीच सद्भावना पैदा करने पर काफी प्रभाव छोड़ा।

ईरान

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों में 2019-20 के दौरान सकारात्मक गति देखी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयार्क में 26 सितंबर, 2019 को हुई बैठक के इतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति डॉ हसन रूहानी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान, नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने चाबहार बंदरगाह के संचालन पर चर्चा की और इसके महत्व को एक प्रवेश द्वार के रूप में और लैंडलॉक अफगानिस्तान और मध्य एशियाई क्षेत्र के लिए नोट किया। दोनों नेताओं ने 2020 में मित्रता की द्विपक्षीय संधि की 70 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

विदेश मंत्री ने भारत-ईरान संयुक्त आयोग के 19वें सत्र के लिए 22-23 दिसंबर 2019 को ईरान की यात्रा की। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री डॉ मोहम्मद जवाद जरफ की सह-अध्यक्षता में संयुक्त आयोग ने 4 वर्ष के अंतराल के बाद तेहरान में बैठक की। उन्होंने संपर्क, व्यापार और वाणिज्य, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन किया। व्यापार और आर्थिक सहयोग को समर्थन देने के उद्देश्य से दोनों पक्ष व्यापार पर तरजीही व्यापार समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने और सीमा शुल्क मामलों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्य दल की शीघ्र बैठक आयोजित करेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने 23 दिसंबर 2019 को ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. हसन रूहानी से मुलाकात की और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव रियर एडमिरल अली शमखानी और ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री से भी भेंट की।

ईरान के विदेश मंत्री डॉ. जवाद ज़रीफ ने 14 मई 2019 को भारत का दौरा किया था और तकालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की थी और आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। विदेश मंत्री ज़रीफ का रायसिना वार्ता में भाग लेने के लिए जनवरी 2020 में भारत आने का कार्यक्रम है।

विदेश कार्यालय परामर्श

विदेश सचिव श्री विजय गोखले और ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में 16 सितंबर 2019 को तेहरान में विदेश कार्यालय परामर्श का 16वां दौर आयोजित किया गया था। संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) पर उपजे मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न दलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों पक्ष 14-18 फरवरी 2018 तक राष्ट्रपति डॉ हसन रूहानी की भारत यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप संयुक्त सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

कार्य समूह की बैठकें

भारत और ईरान के बीच बंदरगाहों और समुद्री सहयोग पर 8वीं संयुक्त समिति की बैठक तेहरान में 29-30 जुलाई 2019 को हुई। दोनों पक्षों ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में सहयोग में उनकी प्रगति की समीक्षा की और चाबहार बंदरगाह पर सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर सहमति व्यक्त की।

संयुक्त सचिव/महानिदेशक के स्तर पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय चाबहार समझौते की दूसरी अनुवर्ती समिति की बैठक 20 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में हुई। बैठक में दिसंबर 2018 में बंदरगाह संचालन शुरू करने के बाद से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी द्वारा शाहिद सैसेनी पोर्ट, चाबहार संचालन में लगातार प्रगति का स्वागत किया गया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि बंदरगाह पर 5 लाख टन से अधिक कार्गो का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है, और अफगानिस्तान ने भारत को अपने निर्यात के लिए बंदरगाह का उपयोग करना शुरू कर दिया है। चाबहार समझौते के अंतर्गत न्यू मैंगलोर और मोरमुगोवा बंदरगाहों को निर्धारित मार्ग के हिस्से के रूप में शामिल करने; बंदरगाह के माध्यम से कार्गो पारगमन को कारगर बनाने, अफगानिस्तान और भारत में अधिक व्यापार संवर्धन घटनाओं को आयोजित करने के लिए एक अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया गया।

आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक श्री टी सी ए राघवन के नेतृत्व में विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 अक्तूबर 2019 को तेहरान में राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन में भारत और ईरान के बीच संभावित सहयोग और भारत-प्रशांत क्षेत्र के सतत विकास के लिए अन्य हितधारकों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया।

द्विपक्षीय व्यापार

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार 17.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि 2017-18 में यह 13.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 23.8% की वृद्धि है। 2018-19 के दौरान, भारतीय निर्यात में 32.3% की वृद्धि हुई और 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हिस्सा था, जबकि ईरान से आयात में 21.8% की वृद्धि हुई और यह 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

कांसुलर संबंध

भारत और ईरान के बीच 11वीं संयुक्त कांसुलर समिति की बैठक 14 मई 2019 को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों पक्षों ने कांसुलर और वीजा संबंधी मुद्दों में चल रहे सहयोग की स्थिति की समीक्षा की और लोगों के परस्पर संपर्को को विस्तार करने और भारतीय और ईरान के बीच मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को बढ़ावा देने सहित पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अन्य देशों के आगंतुकों के लिए ई-वीजा सुविधा के सफल कार्यान्वयन का स्वागत किया।

संस्कृति

भारतीय दूतावास ने अपने सांस्कृतिक केंद्र (स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र) के साथ विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित तेहरान मिलाद टॉवर में वृक्षारोपण सहित महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर की गतिविधियों/कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का आयोजन किया। ईरान पोस्ट ने इस अवसर पर एक स्मारक टिकट जारी किया। दूतावास ने स्थानीय भारतीय समुदाय के साथ मिलकर गुरु नानक देवजी की 550 वीं जयंती के उपलक्ष्य में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित 10 दिन तक चलने वाली गतिविधियों का आयोजन किया।

6

अफ्रीका

अल्जीरिया

अल्जीरियाई कृषि, ग्रामीण विकास और मत्स्यिकी मंत्री महामहिम चेरिफ़ ओमारी नई दिल्ली में 7 सितंबर 2019 को आयोजित पक्षकारों (सीओपी-14) के यूएनसीसीडी सम्मेलन में भाग लेने के लिए को भारत आए। अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालयों के सम्मेलन (सीसीजेए) के स्थायी महासचिव और अल्जीरिया के पूर्व न्यायाधीश श्री मौसा लाराबा ने 6 से 12 नवम्बर 2019 तक लखनऊ में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 20 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

इस अवधि में, मैसर्स एसपीए विजय इलेक्ट्रिकल्स, जो मैसर्स सोनलगाज़ और मैसर्स इलेक्ट्रो इंडस्ट्रीज के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना है और उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त है, के 'शिलान्यास समारोह' के अवसर पर विजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 नवंबर 2019 को मैसर्स इलेक्ट्रो-इंडस्ट्रीज, अज़ाज्गा, तिज़ि ओजोऊ के परिसर की यात्रा की।

35 भारतीय कंपनियों ने विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया। इनमें शामिल हैं - 1 से 3 अक्तूबर 2019 तक अल्जीयर्स में माघरेब फार्मा, 7 से 10 अक्तूबर 2019 तक अल्जीयर्स में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड एग्रो इक्विपमेंट फेयर एसआईपीएसए-एफआईएलएएचए और 6 से 9 नवंबर 2019 तक ओरान में 8वां इंटरनेशनल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर फेयर।

जिबूती

भारत ने 21 अप्रैल 2019 को जिबूती में अपना दूतावास खोला, जो वर्तमान में यमन में भारतीय मिशन के शिविर कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है।

भारत सरकार ने मार्च 2019 में रिपब्लिक ऑफ जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

जिबूती के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री योनिस अली गुएदी ने 31 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी सभा में भाग लिया। भारत ने सरकार की वृक्षारोपण अभियान में सहायता के लिए अक्तूबर 2019 में 10 दिनों के लिए जिबूती में अपने दो विशेषज्ञों को नियुक्त किया।

मिस्र

उच्च स्तर के आदान-प्रदान ने द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करना जारी रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 28 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान ने मिस्र के प्रधानमंत्री श्री समेह हसन शौकरी से मुलाकात की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति विनीत शरन ने 19 अक्तूबर 2019 को मिस्र के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय की स्वर्ण जयंती समारोह भाग लिया। नगर विमानन, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने काहिरा में “भारतीय क्षेत्रीय कॉन्क्लेव - पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (डब्ल्यूएएनए)” में भाग लेने के लिए 5 से 7 नवंबर 2019 तक मिस्र का दौरा किया जिसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित किया गया था। कॉन्क्लेव के अवसर पर, उन्होंने 6 नवंबर 2019 को मिस्र के व्यापार और उद्योग मंत्री अमर आदेल नासर के साथ बातचीत की।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के समारोह के भाग के रूप में मिस्र पोस्ट द्वारा महात्मा गांधी पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी किया गया और अल-होर्रेया पार्क में महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया।

विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने 11 जून 2019 को अबूजा में लोकतंत्र दिवस के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार और पूर्व प्रधान मंत्री इंजी. शेरिफ इस्माइल से मुलाकात की। मिस्र के कृषि और भूमि सुधार मंत्री डॉ. एज़ एल-दीन अबू-स्टेट संयुक्त राष्ट्र कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन (सीओपी) में भाग लेने के लिए 2 से 13 सितंबर 2019 तक भारत आए थे।

भारतीय नौसेना के पोत तरकश ने 28 जून से 1 जुलाई 2019 तक मिस्र के नौसेना बेस रास अल टिन में पोर्ट कॉल किया, मिस्र के नौसेना बलों के साथ पीएएसएसईएक्स का संचालन किया। 9वीं संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की बैठक काहिरा में 5 से 7 नवंबर 2019 तक आयोजित की गई थी।

सीआईआई ने 6-7 नवंबर 2019 को काहिरा में “भारत - पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (डब्ल्यूएएनए) क्षेत्रीय कॉन्क्लेव” का आयोजन किया। कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सिंथेटिक एंड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया और फार्माएक्ससिल के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने मिस्र में व्यापार शोज़/प्रदर्शनियों में भाग लिया।

'इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी' पहल के अंतर्गत 'जयपुर फुट आर्टिफिशियल फिटमेंट कैंप' का आयोजन 2 मई से 9 जून 2019 तक मिस्र के सामाजिक एकता मंत्रालय के समन्वय में किया गया था।

मिस्र के तेरह राजनयिकों ने 10 से 22 जून 2019 तक विदेशी सेवा संस्थान, नई दिल्ली में मिस्र के राजनयिकों के लिए आयोजित पहले विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया। अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान मिस्र के 112 प्रतिभागियों ने आईटीईसी, भारत-अफ्रीका फोरम शिखर-सम्मेलन, आईआईसीआर और सीवी रमन फैलोशिप सहित कई कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण लिया।

जून 2019 में काहिरा, इस्माइलिया और अल-मिन्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 उत्साह के साथ मनाया गया। अक्तूबर-नवंबर 2019 के दौरान बारह गवर्नोरेट्स में "भारत की झलक" चित्रकला प्रतियोगिता का 25वां संस्करण आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में 1600 से अधिक स्कूलों के लगभग 16000 बच्चों ने भाग लिया। आईआईसीआर प्रायोजित कई समूहों ने मिस्र का दौरा किया। मिस्र के दूतावास द्वारा आईसीसीआर के सहयोग से 'इजिप्ट बाई दि गंगा' उत्सव का आयोजन नई दिल्ली और मुंबई में किया गया था।

एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने 24 से 27 दिसंबर 2019 को मिस्र का दौरा किया और मिस्र वायु सेना के कमांडर-इन-चीफ एयर मार्शल मोहम्मद अब्बास हेल्मी के साथ बातचीत की।

युवा मामलों के विभाग की सचिव श्रीमती उपमा चौरी ने 14-17 दिसंबर 2019 तक शर्म-अल-शेख में आयोजित विश्व युवा मंच 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

इरिट्रिया

भारत ने 26 अगस्त 2019 को अस्मारा में अपना दूतावास खोला। इरिट्रिया के साथ संबंधों को भारत के ई-विद्याभारती और ई-अरोग्यभारती (ई-वीबीएबी) नेटवर्क परियोजना के 15वें साझेदार देश बनने के साथ और भी बढ़ावा मिला। 7 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में इस संबंध में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

लीबिया

भारत ने लीबिया में भारतीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखा और इस संबंध में लीबिया के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया।

मोरक्को

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की फरवरी 2019 में सफल यात्रा के फलस्वरूप, मोरक्को साम्राज्य के साथ संबंध गहन और विविधतापूर्ण बने रहे। मोरक्को के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य सचिव (एमओएस) श्री मोहम्मद रेर्स ने मई 2019 में प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय अनुभव का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया।

पिछले तीन वर्षों में 30 से अधिक सहमति-पत्रों और समझौतों पर आधारित विस्तारित अंतर-सरकारी वार्ता

जून 2019 में जल संसाधन पर जेडब्ल्यूजी, सितंबर 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा पर जेडब्ल्यूजी और नवंबर 2019 में रेलवे में सहयोग के लिए जेडब्ल्यूजी की बैठकों के साथ जारी रही। अक्तूबर 2018 में, मोरक्को के मंत्री-प्रतिनिधि की यात्रा के साथ शुरू हुए रक्षा संबंधों को आईएनएस तरकश द्वारा टांगियर में एक पोर्ट कॉल और जुलाई 2019 में रॉयल मोरक्कन नेवी के साथ प्रथम पैसेज अभ्यास, मई 2019 में मिलिट्री मेडिसिन पर मोरक्को प्रतिनिधिमंडल के दौरे और भारतीय नौसेना संस्थानों में रॉयल मोरक्को के नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ और मजबूत किया गया था।

कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अवसरों का पता लगाने के लिए फेज़-मेकन्स के चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली का दौरा किया। मिशन ने सितंबर 2019 में मारकेश और अगाडिर में भारतीय और मोरक्कन कंपनियों के बीच दो सफल व्यापार कांफ्रेंस और बी2बी बैठकों का आयोजन किया। भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष आतिथ्य और ऑटोमोबाइल घटक क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करते हुए मोरक्को में अपने निवेश को मजबूत करना जारी रखा।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा आईटीईसी स्लॉट्स को प्रतिवर्ष दोहरा करके 75 करने की घोषणा के साथ ही प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभरा है। विदेशी सेवा संस्थान, नई दिल्ली में अप्रैल 2019 में 16 मोरक्को राजनयिकों के लिए पहले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब तक, मोरक्को सरकार के 36 प्रतिनिधियों ने आईटीईसी के तहत संचालित कार्यक्रमों में भाग लिया है। कैसाब्लांका में इंडिया-मोरक्को सेंटर फ़ॉर एक्सीलेंस इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (सीईआईटी) में बिग डेटा एनालिटिक्स पर एक ई-आईटीईसी पाठ्यक्रम शुरू किया गया। सीईआईटी ने अपनी स्थापना के बाद से दो वर्षों में 600 से अधिक मोरक्को के आईटी पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। नियमित आईसीसीआर छात्रवृत्तियों के अलावा, रबात में विश्वविद्यालय मोहम्मद V के 4 मोरक्को छात्रों, जो एक आईसीसीआर हिंदी चेयर की मेजबानी करते हैं, ने केंद्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), आगरा में हिंदी का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की।

सांस्कृतिक संबंध जीवंत बने रहे। भारत के प्रमुख चित्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला संगोष्ठी 2019 में भाग लिया, जिसमें भारत विशिष्ट अतिथि था। मोरक्को की संस्कृति का एक 9-सदस्यीय दल 'अबिदत राम' ने अंतर्राष्ट्रीय लोक संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आया। विश्वविद्यालय प्रोफेसर और नई दिल्ली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर के निदेशक श्री दिकर्रहमान को 14 मई 2019 को रबात के रॉयल पैलेस में रमजान का दूसरा धार्मिक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। 13 संपादकों और मोरक्को के वरिष्ठ पत्रकारों ने अक्तूबर 2019 में एक्सपी प्रभाग द्वारा आयोजित एक परिचय दौरे के लिए भारत का दौरा किया।

मोरक्को की संसद के पार्षदों की सभा में भारत-मोरक्को मैत्री समूह के अध्यक्ष, श्री अब्देलकरीम एल मेहदी सहित दो सांसदों ने रायसिना वार्ता 2020 में भाग लिया। उन्होंने लोकसभा में विदेश संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री पी. चौधरी से भी मुलाकात की।

सोमालिया

भारत ने सोमालिया के लिए आईएमएफ ऋण राहत पैकेज में भाग लेने का फैसला किया है। सोमालिया में 27 मिनी बसों को दान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सोमालिया के मुख्य न्यायाधीश 6-12 नवंबर, 2019 तक लखनऊ में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 20 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए।

सूडान

ऊर्जा और खनन मंत्रालय के अवर सचिव (सचिव-रैंक) डॉ. हामिद सुलेमान हामिद के नेतृत्व में दो-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 31 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी महासभा में भाग लिया और इसके दौरान द्विपक्षीय चर्चा के लिए श्री आर. के. सिंह, विद्युत् तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री से मुलाकात की। उद्योग और व्यापार मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद अली अब्दुल्ला मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 6-7 नवंबर, 2019 को काहिरा, मिस्र में सीआईआई द्वारा आयोजित प्रथम इंडिया-वाना रीजनल कॉन्क्लेव में भाग लिया और इसके दौरान श्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित गुलाबी सपेरा के नेतृत्व में 9-सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह द्वारा ओम्डुरमैन और खार्तूम शहरों के विभिन्न स्थानों पर 4-6 अक्तूबर 2019 के दौरान तीन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

खार्तूम स्थित भारतीय दूतावास द्वारा 26 नवंबर 2019 को भारत के संविधान दिवस को मनाने के लिए 'भारतीय संविधान पर चर्चा' का आयोजन, सूडान न्यायपालिका के सहयोग से किया गया था, जहां सूडान के मुख्य न्यायाधीश सुश्री नेमत अब्दुल्ला मोहम्मद खैर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर, 'भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन और संविधान सभा के कार्य पर एक फोटो प्रदर्शनी, का आयोजन भी किया गया था।

माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर सूडान की मुख्य न्यायाधीश सुश्री नेमत अब्दुल्ला खैर, 21-23 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले "न्यायपालिका और बदलती दुनिया" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में भाग लेंगीं।

आईएएफएस-2 के अंतर्गत प्रस्तावित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) की स्थापना मार्च 2020 में सूडान में स्थापित किए जाने की संभावना है।

सूडान ने 13 सितंबर, 2019 को ई-वीबाब नेटवर्क परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

फरीदाबाद में 1-16 फरवरी, 2020 तक आयोजित होने वाले 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 10 सदस्यीय सूडानी सांस्कृतिक मंडली भाग लेगी।

दक्षिण सूडान

भारतीय रक्षा कर्मियों के एक बड़े दल ने संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सूडान मिशन (यूएनएमआईएसएस) को सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा है। इसकी बटालियने जुबा, जोंगलेई और ऊपरी नील क्षेत्रों में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, यूएनएमआईएसएस से जुड़े लगभग 23 भारतीय पुलिस अधिकारियों का एक पुलिस घटक (यूएनपीओएल) भी है। शांति अभियानों के अलावा, भारतीय सैनिक सामुदायिक कल्याण गतिविधियों भी संचालित करते रहे हैं।

मंत्रालय ने मानवीय सहायता के रूप में दक्षिण-सूडान को लगभग 1 करोड़ रुपये की जीवनरक्षक दवा की आपूर्ति की है। मेसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को दक्षिण सूडान में दवाओं की खरीद और प्रेषण के लिए चुना गया है। शिपमेंट 2020 जनवरी के दूसरे सप्ताह में दक्षिण सूडान के लिए रवाना हो चुका है।

ट्यूनीशिया

भारत और ट्यूनीशिया ने सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को जारी रखा। 25-26 मई 2019 तक मणिपुर में छह ट्यूनीशियाई कला और व्यावसायिक फिल्मों की भागीदारी के साथ एक ट्यूनीशियाई फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था।

22 वरिष्ठ ट्यूनीशियाई प्रशासकों के एक समूह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली में 15 से 26 अप्रैल 2019 तक ई-गवर्नेंस और साइबर-सुरक्षा पर एक विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया।

मई 2019 में, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के समारोह के एक भाग के रूप में एक गांधी उद्यान का उद्घाटन रियाद एनसर (एरियाना गवर्नोनेट) में किया गया था।

विदेश मंत्री 22-23 जनवरी, 2020 को ट्यूनीशिया की द्विपक्षीय यात्रा करेगें।

ट्यूनीशिया के चुनाव के लिए स्वतंत्र उच्चाधिकारी (आईएसआई) के अध्यक्ष श्री नाबिल बाफनाम का 23-25 जनवरी, 2020 से भारत आने का कार्यक्रम है, जो पहले सुकुमार सेन व्याख्यान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एनवीडी समारोह में भाग लेंगे।

बोत्सवाना

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने अक्तूबर 2019 में बोत्सवाना के राष्ट्रपति डॉ. मोगवित्सी मासी के पुनः निर्वाचित होने उन्हें बधाई संदेश भेजा।

भारत और बोत्सवाना के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श 15 मई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बोत्सवाना ने अक्तूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेशी सेवा संस्थान, नई दिल्ली ने मई 2019 में बोत्सवाना के 18 राजनयिकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया।

20 भारतीय कंपनियों ने गबोरोन में 6-9 अगस्त 2019 से आयोजित बोत्सवाना के 14वें ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में भाग लिया। बोत्सवाना टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एसोसिएशन ने टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 6 अगस्त 2019 को इंडिया इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी प्रदर्शनी सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

बोत्सवाना के राष्ट्रपति डॉ. मोगवित्सी मासी 28 अप्रैल 2018 को मिशन द्वारा आयोजित भारत दिवस में शामिल हुए। सुश्री नेहा शर्मा ने 23 और 24 नवंबर 2019 को गैबोरोन में आईसीसीआर - प्रायोजित झंकार बॉलीवुड डांस ट्रूप की अगुवाई की। बोत्सवाना द्वारा वर्ष 2019-2020 में, आईटीईसी/आईएएफएस/आईसीसीआर और अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए 86 छात्रवृत्ति स्लॉटों का उपयोग किया गया है।

बुरुंडी

नई दिल्ली में 2 जुलाई 2019 को गितेगा [102.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर] और बुजुंबुरा [59 मिलियन अमेरिकी डॉलर] में दो मंत्रिस्तरीय भवनों के निर्माण के लिए बुरुंडी और एक्जिम बैंक के बीच एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे।

भारत सरकार द्वारा बुरुंडी के स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दवाइयां उपहार में दी गई थीं।

बुरुंडी के ऊर्जा और खान मंत्री श्री कम मनीराकिजा ने नई दिल्ली में 30 और 31 अक्तूबर 2019 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी महासभा में शामिल हुए।

कोमोरोस

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 10-12 अक्तूबर, 2019 को कोमोरोस के का दौरा किया। भारत से कोमोरोस के लिए इस पहली यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की। रक्षा; कला और संस्कृति; स्वास्थ्य और चिकित्सा; विदेशी कार्यालय परामर्श; राजनयिक और आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा की छूट और ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना में भागीदारी के क्षेत्र में सहयोग पर छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

यात्रा के दौरान, उच्च गति की हस्तक्षेप करने वाली नावों की खरीद के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक रियायती ऋण श्रृंखला; दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, परिवहन वाहनों के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 1000 मेट्रिक टन चावल की आपूर्ति की घोषणा की गई।

उपराष्ट्रपति कोमोरोस की यात्रा के दौरान अपना प्रेस वक्तव्य देते हुए, (11 अक्टूबर, 2019)

एस्वातिनी

भारत की अफ्रीका अधिगम्यता नीति के अनुसरण में, सुश्री राधा वेंकटरमण द्वारा उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के साथ 13 अगस्त 2019 को एस्वातिनी (पूर्व में स्वाज़ीलैंड) की राजधानी मीराबेन में भारत का एक नया निवासी मिशन खोला गया।

एस्वातिनी के कृषि मंत्री श्री जाबुलानी मबुजा ने 21 अक्तूबर 2019 को, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से 400,000 अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता के साथ आधिकारिक तौर पर लुबुएन सिंचाई योजना शुरू की।

श्री पीटर बेम्बे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, एस्वातिनी के प्राकृतिक संसाधन मंत्री 10-16 नवंबर 2019 को एक अध्ययन दौरे पर भारत आये।

इथियोपिया

अफ्रीकी संघ के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 11 और 12 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित अफ्रीका-भारत मंच शिखर सम्मेलन-III की मध्यावधि समीक्षा बैठक के लिए भारत का दौरा किया।

इथियोपिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. मुलातु तेशोम ने 5 नवंबर 2019 को इथियोपिया के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भारत का दौरा किया। डॉ. तेशोम ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भेंट की।

भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन-III के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता के भाग के रूप में परिकल्पित भारत-इथियोपिया नवाचार कार्यक्रम 23 मई 2019 को इथियोपिया के नवाचार और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. गेटाहून मर्कुरिया की उपस्थिति में शुरू किया गया।

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा अपनी राजकीय यात्रा के दौरान की गई घोषणा को पूरा करने के लिए भारत ने 13 नवंबर 2019 को इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दवाएँ उपहार में दीं। 29 नवंबर 2019 को अदीस अबाबा में मंत्रालय के 'मानवता के लिए भारत' परियोजना के अंतर्गत एक कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का उद्घाटन किया गया।

विदेश मंत्री श्री गेडु अंदाराचेव ने 4 दिसंबर 2019 को वृक्ष लगाने के लिए अदीस अबाबा में भारतीय दूतावास के नवनिर्मित परिसर का दौरा किया।

इथियोपिया एयरलाइंस ने अक्तूबर 2019 में राजधानी अदिस अबाबा और बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक नॉन-स्टॉप उड़ानों का संचालन आरंभ किया।

केन्या

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 25 अक्तूबर 2019 को बाकू में आयोजित एनएएम शिखर सम्मेलन के अवसर पर केन्या के विदेश मामलों के मुख्य प्रशासनिक सचिव (एमओएस) श्री अबाबू नामवाम्बा से भेंट की।

व्यापार, उद्योग और सहकारिता के कैबिनेट सचिव (मंत्री) श्री पीटर मुन्या ने 19-20 अगस्त, 2019 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति के नौवें सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत का दौरा किया।

भारत-केन्या संयुक्त तकनीकी समिति की दूसरी बैठक 30 मई 2019 को नैरोबी में आयोजित की गई थी।

महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सुश्री देबश्री चौधरी ने 12-14 नवंबर 2019 से नैरोबी में आयोजित जनसंख्या और विकास (आईसीपीडी25) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नैरोबी का दौरा किया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री (आई/सी) श्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 सितंबर 2019 को मॉन्ट्रियाल में अपने केन्याई समकक्ष श्री जेम्स वैंनाया मचारिया से भेंट की।

केन्या के विदेश मंत्रालय के प्रधान सचिव माखरिया कमाउ ने 3 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव श्री टीएस तिरुमूर्ति से भेंट की। 25 नवंबर से 7 दिसंबर 2019 तक विदेशी सेवा संस्थान, नई दिल्ली में केन्या के 10 राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारतीय ऋण श्रृंखला द्वारा वित्तपोषित 29.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना, रिवाटेक्स ईस्ट अफ्रीका लिमिटेड के आधुनिकीकरण का 21 जून 2019 को राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा द्वारा उद्घाटन किया गया था।

प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के चार जहाजों आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी ने 7-10 अक्तूबर 2019 को सद्भावना यात्रा पर मोम्बासा बंदरगाह का दौरा किया। केन्या की सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रारिया कोइपटन ने 27 नवंबर 2019 को भारत की आधिकारिक यात्रा की।

एयर इंडिया ने 27 नवंबर 2019 को मुंबई-नैरोबी सेक्टर पर अपना परिचालन फिर से आरंभ किया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नैरोबी में 2-4 दिसंबर 2019 से एंटरप्राइज इंडिया शो का आयोजन किया।

लिसोथो

भारत और लिसोथो के बीच सहयोग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय आयोग का चौथा दौर 30 सितंबर और 1 अक्तूबर 2019 को मासेरू में आयोजित किया गया था।

मेडागास्कर

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की 2018 में मेडागास्कर की पहली यात्रा ने भारत-मेडागास्कर संबंधों को और मजबूत किया है। विदेश राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन ने 23 अक्तूबर, 2019 को रीयूनियन आइलैंड के सेंट डेनिस में 'चूज ला रीयूनियन' व्यापारिक सम्मेलन के मौके पर मेडागास्कर के प्रधानमंत्री श्री क्रिश्चियन नेस्टे से भेंट की।

प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के चार जहाजों आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी ने 1-3 अक्तूबर 2019 से सद्भावना यात्रा पर अंटसिरनाना बंदरगाह का दौरा किया। मेडागास्कर में तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए बीईएल की एक टीम ने मेडागास्कर का दौरा किया।

भारत ने मेडागास्कर सरकार को कैंसर उपचार रेडियो थेरेपी मशीन भाभाट्रॉन-II और 100,000 एनसीईआरटी पुस्तकों का अनुदान दिया।

मलावी

मलावी के राष्ट्रपति प्रो. आर्थर पीटर मुथारिका ने भारत सरकार की 23.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के साथ 18 अक्तूबर, 2019 को, मूंजरी टू ब्लैंटायर जल परियोजना का उद्घाटन किया।

ई-विद्याभारती (टेली-शिक्षा) और ई-आरोग्यभारती (टेली-मेडिसिन) परियोजना(ई-वीबीएबी) को लागू करने के लिए नई दिल्ली में 23 अगस्त 2019 को मलावी सरकार और एम/एस दूरसंचार सलाहकार इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मोजाम्बिक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्तूबर 2019 में मोजांबिक के राष्ट्रपति श्री फ़िलिप न्यासी को उनके पुन: निर्वाचित होने पर बधाई संदेश भेजा।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 28-30 जुलाई 2019 तक मापुटो का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने मोजाम्बिक के प्रधानमंत्री से भेंट की तथा मोजाम्बिक रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और आंतरिक मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्री ने व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने पर हाइड्रोग्राफी और एमओयू के क्षेत्र में दो द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री श्री सिंह ने मोजांबिक नेवी को दो तेज गति की इंटरसेप्टर नौकाएं (एफआईबी) और मोजाम्बिक आपराधिक जांच एजेंसी के उपयोग के लिए 44 एसयूवी का उपहार दिया।

मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री श्री अटानासियो सल्वाडोर एम' टुमुके 27-30 नवंबर, 2019 को भारत आए थे। उन्होंने रक्षा मंत्री श्री सिंह से बातचीत की और मोजाम्बिक के विशेष आर्थिक क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोजांबिक के रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल से भेंट की।

मोजाम्बिक के मध्य भाग में आये चक्रवात आईडीएआई के बाद, भारत से पहले उत्तरदाता के रूप में, ऑपरेशन सहायता के अंतर्गत 18-30 मार्च 2019 को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) के लिए भारतीय नौसेना के 3 जहाजों को बीरा भेजा गया। उन्होंने 204 व्यक्तियों को बचाया और 3500 से अधिक प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। आईएनएस मगर प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 250 टन चावल और आवश्यक दवाओं (500 किलोग्राम) के साथ 13-15 अप्रैल 2019 को बीरा पहुंचा।

भारत ने, भारत सरकार द्वारा उपहार में दिये गये दो एफआईबी पर मोजाम्बिक नौसेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण और रखरखाव सहायता प्रदान करने के लिए 4-सदस्यीय भारतीय तटरक्षक दल तैनात किया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तरकश ने 26-28 सितंबर 2019 को मापुटो की सद्भावना यात्रा की।

ई-विद्याभारती (टेली-शिक्षा) और ई-आरोग्यभारती (टेली-मेडिसिन) परियोजना(ई-वीबीएबी) को लागू करने के लिए 3 अक्तूबर 2019 को मोजाम्बिक और एम/एस दूरसंचार सलाहकार इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

नामीबिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति डॉ. हेज गिंगोब ने 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के अवसर पर एक बैठक की। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2019 में राष्ट्रपति डॉ. गिंगोब के फिर से निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी।

भारत ने सितंबर 2019 में, सूखा राहत सहायता के रूप में नामीबिया को 1000 मीट्रिक टन चावल प्रदान किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में मंत्रालय की 'मानवता के लिए भारत' पहल के अंतर्गत, 17 सितंबर - 22 अक्तूबर 2019 को नामीबिया के रुंडू में एक कृत्रिम अंग शिविर "जयपुर फुट" का आयोजन किया गया था।

विदेशी सेवा संस्थान, नई दिल्ली ने 1 से 13 दिसंबर 2019 तक 20 नामीबियाई राजनयिकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। नामीबिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केनेथ मटेंगु, आईसीसीआर के शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 29 सितंबर से 5 अक्तूबर 2019 तक भारत के दौरे पर आए थे।

भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तरकस 15-18 सितंबर 2019 को एक सद्भावना यात्रा पर नामीबिया के वाल्विस बे पोर्ट पर गया था।

रवांडा

जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रवांडा की पहली राजकीय यात्रा ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक विशाल खाका तैयार किया था।

भारत ने 16 अप्रैल 2019 को, एचआईवी एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के खिलाफ लड़ने के लिए रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय को उपहार के रूप में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दवाएं सौंपीं। भारत ने 7 नवंबर 2019 को रवांडा शिक्षा बोर्ड को एनसीईआरटी की 100,000 किताबें भेंट कीं।

रवांडा के प्रधानमंत्री डॉ. एडौर्ड एनगिरेंट ने 5 अगस्त 2019 को किवली में भारत-अफ्रीका आईसीटी एक्सपो का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् (टीईपीसी) द्वारा रवांडा सरकार के साथ "अफ्रीका के डिजिटल परिवर्तन एजेंडा में तेजी लाने" के अंतर्गत किया गया था। 16 मई 2019 को किगाली में ट्रांसफ़ॉर्म अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत और जापान द्वारा अफ्रीका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कौशल में सहायक क्षमता निर्माण पर एक सत्र का आयोजन किया गया था।

रवांडा रक्षा बल कमान और स्टाफ कॉलेज का एक 39 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 30 मार्च से 06 अप्रैल 2019 तक अध्ययन दौरे के लिए भारत आया था। रवांडा के दो नागरिकों ने 01-30 अक्तूबर 2019 से राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, बैंगलोर में आयोजित भारत राष्ट्रमंडल युवा क्रिकेट कोचिंग शिविर में भाग लिया।

दक्षिण अफ्रीका

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2019 को ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के समय ब्रिक्स के नेताओं की अनौपचारिक बैठक में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामफोसा के साथ बैठक की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 और 15 नवंबर 2019 को ब्रासीलिया में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भेंट की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में 74वें यूएनजीए के समय ब्रिक्स और आईबीएसए की अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. नालदेई पंडोर से भेंट की।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दसवां विदेश कार्यालय परामर्श 3 और 4 अक्तूबर 2019 को प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था।

भारत द्वारा आयोजित उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम के अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में, ब्रिगेडियर रतन कुमार के नेतृत्व में एक 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 22 से 26 अक्तूबर 2019 तक प्रिटोरिया और कैपटाउन का दौरा किया।

दक्षिण अफ्रीका में भारत उत्सव के हिस्से के रूप में, सितंबर 2019 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी।

तंजानिया

तंजानिया ने अगस्त 2019 में एसएडीसी के राष्ट्र/सरकार के प्रमुखों की 39वीं शिखर बैठक में दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) की अध्यक्षता की।

उद्योग और व्यापार मंत्री श्री इनोसेंट बसुंगवा ने 14-15 अक्तूबर 2019 को सीआईआई-एक्जिम भारत-दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान लुसाका में विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन से भेंट की।

एयर तंजानिया ने जुलाई 2019 में दार एस सलाम से मुंबई (सप्ताह में 3 बार) तक अपनी सीधी उड़ानों का संचालन शुरू किया। तंजानिया के खनिज मंत्रालय के स्थायी सचिव नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जून 2019 में भारत का दौरा किया।

भारत-तंजानिया संयुक्त कार्य दल की बैठक 15-17 मई 2019 को दार एस सलाम में आयोजित की गई थी।

दार एस सलाम में 6 जून से 13 जुलाई 2019 तक "भारत के लिए मानवता" कार्यक्रम के अंतर्गत एक कृत्रिम अंग (जयपुर फुट) प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया था।

दो युवा नवोदित तंजानियाई क्रिकेटरों ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बैंगलोर में 1-31 अक्तूबर 2019 से बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रमंडल देशों के अंडर -16 क्रिकेटरों के लिए आयोजित पहले क्रिकेट कोचिंग में भाग लिया।

अप्रैल-नवंबर 2019 की अवधि में तंजानिया के 223 छात्रों को आईटीए छात्रवृत्ति और तंजानिया के 32 छात्रों को आईएएफएस-III के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया था।

अरुशा में 6-सदस्यीय भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (आईएमटीटी) के दिसंबर 2017 से दिसंबर 2019 तक के 2 वर्षों के कार्यकाल को, तंजानिया सरकार के अनुरोध पर जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के चार जहाजों आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी ने 14-17 अक्तूबर 2019 तक सद्भावना यात्रा पर दार एस सलाम और जंज़ीबार का दौरा किया। अप्रैल-नवंबर, 2019 से तंजानिया सरकार को 13 आईटीईसी रक्षा स्लॉट प्रदान किए गए हैं।

युगांडा

लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने कंपाला में 22-29 सितंबर 2019 तक आयोजित 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने वाले 84 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, इस प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और 25 राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य शामिल थे।

संसदीय आयुक्त, सुश्री सेसिलिया अतिम ओगवाल बारबरा के नेतृत्व में युगांडा के संसदीय आयोग के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2019 में भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने संसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एणपीएलएडीएस) के सदस्यों पर राज्यसभा संसदीय समिति से भेंट की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर युगांडा के प्रधानमंत्री डॉ. रूहकाना रगुंडा से भेंट की।

जुलाई 2018 में अपनी राजकीय यात्रा के समय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई उपहार की घोषणा को पूरा करने के लिए भारत ने युगांडा सरकार को एनसीईआरटी की 100,000 पाठ्य पुस्तकें प्रदान कीं।

युगांडा के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री साइमन डी'उजंगा ने 30-31 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी महासभा में भाग लेने वाले एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

युगांडा के राष्ट्रपति जनरल योवेरी मुसेवेनी ने 7 नवंबर 2019 को स्टेट हाउस, एंतेबे में दिवाली समारोह आयोजित किया।

युगांडा सरकार और एम/एस दूरसंचार सलाहकार इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के बीच ई-विद्याभारती (टेली-शिक्षा) और ई-आरोग्यभारती (टेली-मेडिसिन) परियोजना (ई-वीबीएबी) को लागू करने के लिए 3 अक्तूबर 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

जाम्बिया

जाम्बिया के राष्ट्रपति श्री एडगर लुंगू ने 20-22 अगस्त 2019 को भारत की राजकीय यात्रा की। रक्षा; भूविज्ञान और खनिज संसाधन; स्वास्थ्य और चिकित्सा; कला और संस्कृति; विदेशी सेवा प्रशिक्षण;चुनाव प्रबंधन और टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसिन के क्षेत्र में सात द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने एसएमई इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समर्थन की घोषणा की; जाम्बिया को 1000 मीट्रिक टन चावल और 100 टन दूध के साथ-साथ 100 सौर सिंचाई पंपों और पाँच अग्नि टेंडर दान दिए गये।

विदेश राज्य मंत्री (राज्य मंत्री) श्री वी. मुरलीधरन ने 14 और 15 अक्तूबर, 2019 को लुसाका में भारत-दक्षिणी अफ्रीका परियोजना भागीदारी कॉन्क्लेव पर सीआईआईएक्जिम बैंक क्षेत्रीय सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन राष्ट्रपति एडगर लुंगु ने किया था। यात्रा के दौरान, राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने राष्ट्रपति लुंगू, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. केनेथ कौंडा और विदेश मंत्री श्री जोसेफ मालनजी से भेंट की।

महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय में 2 अक्तूबर 2019 को सामान्य शिक्षा मंत्री श्री डेविड माबुम्बा द्वारा महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था।

मेजर जनरल सुरेश कुमार मोहंती के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) का 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 19-24 मई 2019 को एक अध्ययन दौरे पर जाम्बिया गया था।

जिम्बाब्वे

भारत ने जून 2019 में जिम्बाब्वे सरकार को 250,000 अमेरिकी डॉलर की दवाओं के उपहार की पहली खेप सौंपी। भारत-जिम प्रौद्योगिकी केंद्र की 2.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 9 सितंबर 2019 को एचएमटी मशीनें जिम्बाब्वे पहुंचाई गईं। आईटीईसी/आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रम क्षमता निर्माण के लिए जिम्बाब्वे को भारत की सहायता की एक नियमित विशेषता है। इस अवधि में, जिम्बाब्वे द्वारा 101 आईटीईसी स्लॉटों, 5 रक्षा आईटीईसी स्लॉटों और 18 आईसीसीआर छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया है।

प्रसार भारती और जिम्बाब्वे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (जेडबीसी) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन के अनुसार, जेडबीसी के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मई 2019 में आम चुनावों के अंतिम चरण को कवर करने के लिए भारत का दौरा किया।

जिम्बाब्वे की महिला मामलों, समुदाय, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री सुश्री सीतम्बिसो जी. न्योनी ने 22-25 अगस्त 2019 से एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने 14 अक्तूबर, 2019 को लुसाका में सीआईआ।-एक्जिम बैंक इंडिया-सदर्न कॉरपोरेशन कॉनक्लेव के अवसर पर जिम्बाब्वे के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री नकोबिज़िथा मंगलिसो निधलोव के साथ बैठक की।

जिम्बाब्वे के सूचना, संचार और डाक सेवा मंत्री डॉ. जेनफान मुस्वेरी नई दिल्ली में 14-16 अक्तूबर 2019 से आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भाग लेने के लिए भारत आए थे। जिम्बाब्वे के ऊर्जा और ऊर्जा विकास मंत्री श्री फार्च्यून चेस 30 और 31 अक्तूबर 2019 को द्वितीय आईएसए महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे।

जिम्बाब्वे के खान मंत्री श्री विंस्टन चिटान्डो 18-22 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में किम्बर्ली प्रक्रिया की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से भेंट की।

अंगोला

विचाराधीन वर्ष के दौरान भारत के साथ अंगोला के संबंध और अधिक सुदृढ़ हुए हैं। अंगोला के वित्त मंत्री श्री आर्चर मंगोइरा ने 2 सितम्बर 2019 को भारत की यात्रा के दौरान एलओसी/क्रेता क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित एक्जिम बैंक के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को बढ़ाए जाने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं।

भौतिक संसाधन और बुनियादी ढांचे के लिए अंगोलन सचिव जनरल अफोंसन कार्लोस नेटो के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल 05-08 फरवरी 2020 को लखनऊ में “डेफएक्सपो 2020” में भाग लेगा।

बेनिन

माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल के साथ 28-30 जुलाई 2019 के दौरान बेनिन की राजकीय यात्रा के फलस्वरूप भारत और बेनिन के बीच त्रिपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। राष्ट्र/सरकार प्रमुख के रूप में यह बेनिन की पहली यात्रा की। बेनिन द्वारा भारत को दिए गए एक विशेष सम्मान समारोह में बेनिन के राष्ट्रपति पैट्रीस टेलोन के साथ बातचीत करने के अलावा राष्ट्रपति जी ने ओटोनोवो में राष्ट्रीय सभा (संसद) को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति जी ने अपने सम्मान में दिए गए एक भोज में भारतीय समुदाय के लोगों से भी भेंट की। बेनिन की यात्रा के दौरान 4 करारों और समझौता ज्ञापनों यथा (i) राजनयिक, सरकारी, सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से संबंधित परस्पर छूट पर करार (ii) वर्ष 2019-2023 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (iii) भारत की टेली शिक्षा और टेली मेडिसिन कार्यक्रम-ई-वीबीएबी प्राप्त करने के लिए बेनिन के साथ करार और (iv) निर्यात क्रेडिट अभिकरण स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार के निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि भारत बेनिन को ई-वीजी सुविधा देगा ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सके (अक्तूबर 2019 से प्रचालित)। भारत ने राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए बेनिन को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की भी घोषणा की।

सात बेनीस राजनयिकों ने 25 नवंबर-7 दिसंबर 2019 से विदेश सेवा संस्थान, हैदराबाद में फ्रैंकोफोन मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों के राजनयिकों के लिए पहले विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया। बेनिन के विभिन्न मंत्रालयों के 20 पदाधिकारियों ने 4 नवम्बर से 13 दिसम्बर 2019 के दौरान अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू), हैदराबाद में विशेष आईटीईसी अंग्रेजी प्रवीणता पाठयक्रम किया है। भारत बेनिन के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरकर सामने आया है। वर्ष 2018-19 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार आवर्तन बढ़कर 802.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जो पहले की अपेक्षा 14.23 प्रतिशत की वृद्धि है। बेनिन में डबल रोलर गिनिंग प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने और उसका प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित मॉडल गिनिंग इकाई कॉटन टेप के पहले चरण के अंतर्गत सितंबर 2019 में प्रचालित हो गई है।

श्री होडमैन, निदेशक (नवीन और नवीकरण ऊर्जा) ने 31 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी महासभा में बेनिन के ऊर्जा मंत्री का प्रतिनिधित्व किया। बेनिन ने आईएसए के फ्रेम वर्क करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

2019-20 के दौरान भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत बेनिन में 25 सिविलियन और 61 रक्षा स्लॉटों की पेशकश की थी। इसके अलावा आईएएफएस-3 के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बेनिन के 3 नागरिक लाभान्वित हुए हैं तथा दो नागरिकों को भारत में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। 21-23 जून 2023 के दौरान कोटोनू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आइडीवाई) का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया।

बुर्किना फासो

मार्च 2019 में गाडूगो में हमारे दूतावास को दोबारा खोले जाने से बुर्किना फासो और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता आई है बुर्किना फासों के पर्यावरण मंत्री श्री वैश्यो बेसेरी ने 2-13 सितंबर 2019 के दौरान आयोजित डिसर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए यूएन कन्वेशन से संबंधित कांफ्रेंस पक्षकारों (यूएनएमसीसीडी

सीओपी 14) की चौदहवीं बैठक के संबंध में दिल्ली की यात्रा की। गाडूगों में 22 जून 2019 को बुर्किना फासो के खेलमंत्री की मौजूदगी में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। भारतीय दूतावास ने बुर्किना फासो में आबाद भारतीय समुदाय के 500 जिम्मेदार लोगों द्वारा 19 अक्तूबर 2019 को आयोजित दीवाली के समारोह में भाग लिया। 15 सितम्बर 2019 को दूतावास का नया परिसर किराए पर लेने के बाद शीघ्र ही कौंसलर सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी।

कैमरून

पश्चिम अफ्रीका के देशों में हमारी राजनयिक अभिगम्यता के एक भाग के रूप में विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरण ने 5 सितम्बर 2019 के दौरान कैमरून की यात्रा की। उन्होंने इस अवसर पर कैमरून के विदेश मंत्री श्री एम्बेला लेजोने, ओआईसी के प्रभारी राज्यमंत्री श्री अडोम गार्गोम और राष्ट्रकुल मामलों के राज्यमंत्री श्री फैलिक्स एमबायु के साथ विस्तृत परिचर्चा की। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री जोजफ डियोन एंगुटे और राष्ट्रीय सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एटोंग और राष्ट्रीय सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एटोंग हिलेरियन से भी मुलाकात की। योन्डे में आबाद भारतीय मूल के 100 से भी अधिक लोगों ने राज्य मंत्री (वीएम) के सम्मान में दिए गए भोज में भाग लिया।

12 सितम्बर 2019 को योन्डे में हमारा रेजीडेंट उच्चायोग खुलने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए है; कैमरून की ओर से राष्ट्रीय सभा की उपाध्यक्ष श्रीमति लिफाका एमीलीया मोजोंवा ने 24-29 नवम्बर 2019 के दौरान आयोजित होने वाली राष्ट्रकुल युवा संसद की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की।

श्री एन जैन गुम मूसा एम्बूटो, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक 4 सदस्ययी संसदीय शिष्टमंडल ने 2-5 दिसम्बर, 2019 के दौरान भारत की यात्रा की। 2018-19 के दौरान भारत और कैमरून के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 की तुलना में बढ़कर 523 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो कि लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि है। भारत सरकार के 93.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत नवम्बर 2019 में 225 केवी एनकोंग सांबा बाफोसाम और आबोंग एमवांग-योन्डे ट्रांसमिशन लाइन की निर्माण परियोजना शुरू हो गई है। कैमरून के 10 राजनयिकों ने नवम्बर 2019 में अफ्रीका के फ्रैंकोफोन देशों के पहले एफएसआई पाठयक्रम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

कैपवर्डे

विचाराधीन अवधि के दौरान कैपवर्डे के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। कैपवर्डे ने संयुक्त राष्ट्र संघ और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के चुनावों में भारत का समर्थन किया। डकार में हमारे मिशन ने 15 जून 2019 को प्रेया, कैपवर्डे में 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का आयोजन किया।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य

मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) में अनिश्चित राजनीतिक स्थिति और असुरक्षा की मौजूदा हालत के कारण विचाराधीन वर्ष के दौरान सीएआर सरकार के साथ भारत की बातचीत सीमित रही। मध्य अफ्रीकी गणराज्य

के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री मोहम्मद तैयब याकूब विश्व व्यापार संगठन की औपचारिक मंत्रालययी बैठक में शामिल होने के लिए 13-14 मई 2019 को दिल्ली की यात्रा पर आए। उद्योग महानिदेशक श्री शाइप्रियन किविलीवोना के नेतृत्व में मध्य अफ्रीकी गणराज्य का एक चार सदस्ययी शिष्टमंडल सीमेंट सयंत्र परियोजना (भारत सरकार एलओसी के जरिए बनाई जा रही) को शुरू करने संबंधी अनुरोध के साथ 18 नवम्बर 2019 को नई दिल्ली पहुंचा। बैंगुई में लड़ाई चलने के कारण यह कार्य रूक गया था।

चाड

चाड नई दिल्ली में अपना दूतावास खोलने जा रहा है तथा वहां के पहले रेजीडेंट राजदूत श्री सोंगोई अहमद शीघ्र ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। चाड को वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीईसी के अंतर्गत 5 सिविलियन अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की गई है। इसके अलावा अब तक (नवम्बर 2019 तक) चाड के सात नागरिकों ने आईएएफएस के अंतर्गत संचालित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिए हैं। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर अध्ययन करने वाले चाड के 8 छात्रों को छात्रवृति दी गई है। एन'डीजमेना में भारत के अवैतनिक कोंसुलेट ने 23 जून 2019 को पूरे जोश और उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आइडीवाई) 2019 का आयोजन किया।

कोटे-डी आइवोयर

विचाराधीन अवधि के दौरान भारत और कोटे-डी आइवोयर के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ रहे। पश्चिम अफ्रीका में अपनी यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री (वीएम) ने 6 सितम्बर 2019 को कोटे-डी आइवोयर की यात्रा की और वहां के उपराष्ट्रपति श्री डेनियल काबलांग के साथ व्यापक परिचर्चा की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहली बार बढ़कर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होगी। भारत की दवाई कंपनिया कोटे-डी-आइवोयर के बाजारों में विशेष ख्याति अर्जित कर रही हैं। भारत की आटोमोबाइल कंपनियां भी वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। मिशन में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठए हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के अंतर्गत ग्रांड बासम में महात्मा गांधी आईटी और जैव-टेक पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कर दिया गया है जो अब क्रियाशील है।

कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य (डीआरसी)

कांगो में अगस्त 2019 में नई सरकार आने के दौरान वहां राजनीतिक स्थिरता लौट आई है। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के साथ भारत में द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। डीआरसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के चुनावों में भारत का समर्थन किया है। भारत सरकार ने जुलाई 2019 में 140.238 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली नई लाईन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के अंतर्गत 40 एमडब्ल्यू 3 नई सौर शक्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारत विशेष रूप से भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस), आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और आईसीसीआर छात्रवृत्तियों के अंतर्गत डीआरसी को क्षमता निर्माण

सहायता उपलब्ध करा रहा है। विचाराधीन वर्ष के दौरान आईटीईसी स्लॉटों (90) का उपयोग और डीआरसी को 10 आईसीसीआर छात्रवृत्तियों की पेशकश संतोषजनक रही है। एफएसआई, विदेश मंत्रालय द्वारा फ्रैंकोफोन अफ्रीकी देशों के लिए संचालित विशेष पाठयक्रम में कांगों के 11 राजनयिकों ने भाग लिया। डीआरसी ने ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती के अवसर पर दूतावास परिसर में डीआरसी के संस्कृति मंत्री द्वारा राष्ट्रपिता की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। 5-8 नवम्बर 2019 के दौरा मिश्रधातु निगम लिमिटेड (एमआईडीएचएएनआई) के एक तीन सदस्य शिष्टमंडल ने अपने सीएमडी के नेतृत्व में किंशासा का दौरा किया ताकि डीआरसी से कोबाल्ट आयात किये जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा सके।

भूमध्य रेखीय गिनी (ईजी)

हाइड्रोकार्बन से समृद्ध भूमध्य रेखीय गिनी के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किए जाने संबंधी भारत के मौजूदा प्रयासों के अनुसार अप्रैल 2019 में वहां भारत का दूतावास खोला गया और भारत के पहले रेजीडेंट राजदूत ने सितम्बर 2019 में वहां की सरकार को अपने दस्तावेज सौंपे। भूमध्य रेखीय गिनी कई बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन करता रहा है। भूमध्य रेखीय गिनी के विदेश मंत्री श्री साई मियोन ओयोनो इसोनो आंगू ने यूएनजी के 74वें सत्र के दौरान न्यूयार्क में 24 सितम्बर 2019 को विदेश मंत्री से भेंट की तथा द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों के बीच आगामी कार्यक्रमों पर परिचर्चा की।

गेबोन

विचाराधीन वर्ष के दौरान गेबोन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और अधिक सुदृढ़ हुए हैं। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा में तैनात हमारे राजदूत को गेबोन के लिए राजदूत से संबंधित अधिकार भी प्रत्यायित किए गए। उन्होंने अक्तूबर 2019 के प्रारंभ में गेबोन सरकार को अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। विचाराधीन वर्ष के दौरान गेबोन ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) इंडियल ऑयल लिमिटेड (आईओएल) की भागीदारी में 3761 वर्ग किमी. क्षेत्र में शक्ति ब्लॉक नामक स्थान के भीतर तेल की खोज कर रहा है। ओआईएल की खोज दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है जो 2020/2023 तक जारी रहेगी। गेबोन के 13 राजनयिकों ने फ्रैंकोफोन अफ्रीकी देशों के लिए एफएसआई, विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया। गेबोन के उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री लांगु मोकाग्नी ने 15वें एफआइसीसीआई उच्चतर शिक्षा मंत्री सम्मेलन में शामिल होने के लिए 27-30 नवम्बर 2019 की अवधि हेतु एक 4 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा की।

गेम्बिया

माननीय राष्ट्रपति जी ने 30 अगस्त से 1 अगस्त 2019 के दौरान गेम्बिया की राजकीय यात्रा की। यह भारत के राष्ट्र/सरकार प्रमुख द्वारा गेम्बिया की पहली यात्रा थी। राष्ट्रपति जी ने गेम्बिया के राष्ट्र प्रमुख से बातचीत करने के अलावा वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। भारत सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट

के अंतर्गत निर्मित पश्चिम अफ्रीका के बेंजुल स्थान पर राष्ट्रीय सभा भवन परिसर विशेष परियोजनाओं में से एक है। इस यात्रा के दौरान पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गेम्बिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क करार से संबंधित दस्तावेज सौंपे गए। राष्ट्रपति जी ने कौशल विकास और लघु उद्योग परियोजनाओं के सहायतार्थ 5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाने संबंधी भारत सरकार के निर्णय की भी घोषणा की। गेम्बिया की ओर से किए गए अनुरोध और वहां की सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार न्याय, पुलिस, प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। 10-21 जून 2019 के दौरान राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र, मसूरी ने गेम्बिया की 25 वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए प्लस रियूब्रिक के अंतर्गत एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किया। गेम्बिया के सिविल सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने दिसम्बर 2019 में भारत की यात्रा की। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 25 से 31 मार्च 2020 तक 25 गैम्बियन स्थायी सचिवों/उप स्थायी सचिवों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

घाना

विचाराधीन वर्ष के दौरान दोनों देशों की ओर से उच्च स्तरीय यात्राएं किए जाने के फलस्वरूप पहले से ही पारम्परिक आधार पर मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। इस अनुक्रम में घाना के उप विदेश मंत्री श्री चार्ल्स आविरेडु ने 28 अगस्त, 2019 को आयोजित 'पहली विदेश परिचर्या' के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। 26-27 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में आयोजित-अफ्रीकी उच्चतर शिक्षा और कौशल विकास शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उप-सड़क और राज मार्ग मंत्री श्री आइजक एर्जीमेंसा ने नई दिल्ली की यात्रा की। इसके अलावा घाना के रेल विकास मंत्री श्री जोगारते ने 21-23 अक्तूबर 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी (आईआरईई 2019) में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2017-18 में 3345.83 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में 4480.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 6 मई 2019 को डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस की गई जिसके दौरान भारत के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने घाना में भारतीय व्यापारिक समुदाय के साथ बातचीत की।

भारत घाना की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के सफर में एक विश्वसनीय और स्थिर भागीदार रहा है तथा उसकी विकासगत भागीदारी घाना सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर आधारित है। 5 अप्रैल 2019 को एकरा, येन्डी नगर में पोर्टेबल जल आपूर्ति प्रणाली का उन्नयन करने के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और कृषि यंत्रीकरण के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट करारों पर हस्ताक्षर किए गए। 12 अप्रैल 2019 को एकरा में भारतीय शिक्षा मेले का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल 2019 को ऐसे ही मेले का आयोजन केपकोस्ट विश्वविद्यालय में भी किया गया। 26 अगस्त 2019 को विदेश मंत्रालय की ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए घाना गणराज्य सरकार और टेली कम्यूनिकेशनस कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईसीटी (एआईटीआई-एएसीई) में भारत-घाना कोफी अन्नान उत्कृष्टता केन्द्र ईवीबीएबी के प्रायोगिक चरण के कार्यान्वयन में भाग ले रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से एआईटीआई-केएसीई ने भी बिग डाटा एनेलाइटिक्स से संबंधित पहला ई-आईटीईसी कार्यक्रम संचालित किया। विचाराधीन अवधि अप्रैल-नवम्बर 2019 के दौरान घाना

में भारत- अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अंतर्गत 42 आईटीईसी और 32 अन्य स्लॉटों का उपयोग किया। 16 स्लोंटों में से आईसीसीआर छात्रवृत्ति के अंतर्गत 8 स्लोंटों में से आईसीसीआर छात्रवृत्ति के अंतर्गत 8 स्लोंटों की पेशकश की गई। रक्षा प्रशिक्षण स्लॉटों का पूरी तरह से उपयोग किया गया।

9 अप्रैल 2019 को आईसीसीआर दिवस मनाया गया जिसमें पर्यटन संस्कृति और रचनात्मक कला के माननीय उपमंत्री सम्मानित अतिथि थे। 22 जून 2019 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती से संबंधित दो वर्षीय समारोह के भाग के रूप में भारतीय उच्चायोग ने चेन घाना के सहयोग से 2 जून 2019 को “साइकिलिंग मार्च” का आयोजन किया; 5 जून 2019 को घाना गणराज्य के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर 150 पौधे लगाए गए; 29 सितम्बर 2019 को “शांतिकूच” का आयोजन किया गया; 37 सैनिक अस्पताल के महात्मा गांधी वार्ड को औषधीय उत्पादों और ओटीसी सामग्री का उपहार दिया गया तथा 2 अक्तूबर 2019 को एआइटीआई, केएसीई (आईसीटी में भारत-घाना कोफी अन्नान उत्कृष्टता केन्द्र) में आयोजित एक समारोह के दौरान घाना डाक विभाग द्वारा महात्मा गांधी के चित्र के साथ एक विशेष स्मृति डाक टिकट जारी किया गया। 9 नवम्बर 2019 को गुरू नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाई गई और 26 नवम्बर 2019 को संविधान दिवस का आयोजन किया गया।

घाना के उप-ऊर्जा मंत्री माननीय विलियम ओउराकु एडु ने आईसीएआर-आईएआरआई पूसा परिसर, नई दिल्ली में 9-11 जनवरी 2020 से दूसरे वैश्विक सिग्मा शिखर सम्मेलन 2020 में भाग लिया। रक्षा मंत्री डोमिनिक नितीवुल 5-8 फरवरी 2020 तक लखनऊ में डेफएक्सपो इंडिया-2020 के 11वें सत्र में भाग लेंगे। अफ्रीका के सहायक निदेशक और क्षेत्रीय एकता ब्यूरो के विदेश मामलों और क्षेत्रीय एकीकरण मंत्रालय के घाना ने 13-31 जनवरी से नई दिल्ली के एफएसआई में दूसरे वार्षिक निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के फैलोशिप कार्यक्रम 2020में भाग लिया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2020 को मनाया गया।

गिनी

जनवरी 2019 में कोनाक्री में हमारा दूतावास खुलने के साथ गिनी गणराज्य के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मोड़ आया। हमारे पहले रेजीडेंट राजदूत ने अगस्त 2019 में अपना कार्यभार ग्रहण किया। माननीय राष्ट्रपति जी ने 1-3 अगस्त 2019 के दौरान गिनी गणराज्य की पहली राजकीय यात्रा की। गिनी की राष्ट्रपति अल्फाकोंडे के साथ द्विपक्षीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत परिचर्चा करने के अलावा राष्ट्रपति ने कोनक्री में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कोनाक्री मेट्रोपोलिटन सिटी की जब आपूर्ति परियोजना (जिसे अब मंजूरी दे दी गई है और नई दिल्ली में दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किए जा रहे हैं) के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉर के नए लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान 3 निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए: (i) पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; (ii) गिनी गणराज्य की सरकार और टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंटस इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के बीच समझौता ज्ञापन ताकि ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना [पैन अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना का प्रौद्योगिकी उन्नयन] में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सके और (iii) नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन/गिनी के विदेश मंत्री श्री ममादी तोरे ने 2-5 दिसंबर 2019 के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने 5 दिसम्बर को विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय परिचर्चा में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित लाइन ऑफ क्रेडिट करारों अर्थात् (i) ग्रांड कोनाक्री की पेय जल आपूर्ति परियोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर और और (ii) दो सौर परियोजनाओं के लिए 20.22 मिलियन

अमेरिकी डॉलर: (क) सात सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के लिए बिजली और पेयजल की आपूर्ति और 200 स्वास्थ्य केंद्रों में विद्युतीकरण और प्रशीतन के लिए सौर परियोजना।

गिनी बिसाउ

विचाराधीन वर्ष के दौरान गिनी बिसाऊ के साथ परस्पर संबंधों में मजबूती आई है। भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ बूबा में निर्मित 5 एमडब्ल्यू के बिजली संयंत्र के परीक्षण का कार्य नवम्बर 2019 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। 17 सितम्बर से 31 अक्तूबर 2019 के दौरान गिनी बिसाऊ के 25 राजनयिकों के लिए एक विशेष आईटीईसी अंग्रेजी भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम संचालित किया गया।

लाइबेरिया

विचाराधीन वर्ष के दौरान लाइबेरिया के साथ संबंधों में मजबूती आई है। भारत ने मोनटोबिया में अस्पताल के निर्माण के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता अनुदान दिया है। भारत ने मोनरोबिया में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने और सरकारी अग्निशमन विभाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए 50 वाहन (45 बसें व 5 अग्निशमन ट्रक) भी उपलब्ध कराए। लाइबेरिया सरकार सभी अंतर्राष्ट्रीय/संयुक्त राष्ट्र संघ निकायों के चुनावों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करती रही है।

माली

4 नवम्बर 2019 को माली नई दिल्ली में भारत-माली विशेष कार्यालय परामर्श का पहला दौर शुरू किया गया इस परामर्श के जरिए दोनों पक्षों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने के साथ-साथ सहयोग के नए क्षेत्रों को भी तलाश करें। ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना (प्रौद्योगिकीय उन्नयन अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना (कपीएईएनपी) चरण-एक में माली की प्रतिभागिता से संबंधित समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार ने माली में बिजली क्षेत्र सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 353.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट मंजूर किया है। माली के जल और ऊर्जा मंत्री डॉ. साम्बूवागू ने 31 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी महासभा में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। आईटीईसी के अंतर्गत 2019-20 के दौरान प्रशिक्षण स्लॉटों की संख्या बढ़कर 60 से 70 हो गई है। 18 सितम्बर से 30 अक्तूबर 2019 के दौरान अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में माली के विदेश मंत्रालय के पदाधिकारियों के लिए एक विशेष अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम चलाया गया। यह आईटीईसी के अंतर्गत संचालित पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा तीसरा विशेष पाठ्यक्रम था। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए माली को आईसीसीआर अफ्रीका छात्रवृति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्तियां दी गई हैं। माली के डाक विभाग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर परएक स्मृति डाक टिकट जारी किया है।

मोरीटोनिया

मोरीटोनिया की पर्यावरण और संधारणीय विकास मंत्री सुश्री मरयम एलिजाबेथ बीके ने 2-13 सितम्बर 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित चौदहवीं कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन टू कमबैक डिसर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडीसीओपी 14) के उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। 2019-20 के दौरान मोरीटोनिया को 5 आईटीईसी स्लॉटों और 3 आईसीसीआर छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई है।

नाइजर

भारत सरकार द्वारा 35.484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के अंतर्गत नियामे में स्थापित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जनवरी/फरवरी 2020 में होने की संभावना है। नाइजीरिया के रक्षा मंत्री प्रो इससौफू काताम्बे 6 फरवरी 2020 को लखनऊ में आयोजित होने वाली डेफएक्सपो के साथ भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। नाइजर के कृषि और पशुपालन मंत्री श्री अलबाडे अबुबा 15-17 मार्च 2020 तक भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15वें सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव के साथ नई दिल्ली में 14 मार्च 2020 को भारत-अफ्रीका कृषि बैठक 2020 में भाग ले सकते हैं।

नाइजीरिया

अफ्रीका के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक और आर्थिक देश तथा अफ्रीका में हमारे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार नाइजीरिया के साथ हमारे संबंध द्विपक्षीय आधार पर और अधिक सुदृढ़ हुए हैं। भारत वैश्विक आधार पर नाइजीरिया का सबसे बड़ा भागीदार है। दोनों देशों के बीच 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार आवर्तन बढ़कर 13.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जो 18.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराता है। नाइजीरिया के साथ हमारे निर्यात की कीमत बढ़कर 3.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है जो 33.27 प्रतिशत की वृद्धि है तथा हमारा आयात बढ़कर 10.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जो 14.56 प्रतिशत वृद्धि है। 2019-20 के दौरान नाइजीरिया ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाइजीरिया हमें पैट्रोल निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। नाइजीरिया हमारी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता पूरी करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत के कच्चे तेल की वार्षिक 10 प्रतिशत आवश्यकता नाइजीरिया से पूरी होती है। विचाराधीन वर्ष के दौरान भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में आयोजित सभी बड़े व्यापारिक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया।

विदेश राज्यमंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने 12 जून 2019 को नाइजीरिया के प्रजातंत्र समारोह दिवस में शामिल होने के लिए वहां की यात्रा की और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। सितम्बर 2019 में विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव मुस्तफा एल सुलेमान के नेतृत्व में नाइजीरिया के 9 सदस्यई शिष्टमंडल ने कौंसुलर संवाद के पहले दौर में भाग लेने के लिए 9-10 सितम्बर को भारत की यात्रा की।

नाइजीरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने 31 अक्टूबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, नई दिल्ली की दूसरी सभा में भाग लिया। नाइजीरिया ने आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की और नवंबर 2019 में अनुसमर्थन के दस्तावेज प्रस्तुत किए। संचार मंत्रालय के स्थायी सचिव श्री इस्तिफानस फुक्तार ने इंडिया

मोबाइल कांग्रेस 2019 के तीसरे सत्र के लिए भारत का दौरा किया जो 14-16 अक्तूबर से नई दिल्ली के एयरोसिटी में हुआ था। संघीय उद्योग, व्यापार और निवेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नाइजीरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में 11-13 अक्तूबर 2019 से आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

मई 2019 में भारतीय नौसेना के मोबाइल प्रशिक्षण दल की तैनाती और भारत-नाइजीरिया @ 60 को मनाने के लिए सितंबर 2019 में आईएसएस ट्रैकाश की लागोस की यात्रा ने हमारे रक्षा सहयोग को और दोनों नौसेनाओं के बीच जुड़ाव भी मजबूत किया।

भारत नाइजीरिया के वरीयता वाले क्षेत्रों में रियायती ऋण की पेशकश करके उसके विकास भागीदारों के प्रमुख साथी के रूप में सामने आया है। भारत में ग्रामीण ब्रोड बैंड नेटवर्क परियोजना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर एलओसी की पेशकश की है। यह दो सौर परियोजनाओं के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण के अलावा है जिसकी घोषणा मार्च 2018 में आईएसए के संस्थापक सम्मेलन के दौरान की गई थी तथा नाइजीरिया को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर एलओसी की पेशकश पहले ही की जा चुकी है जिसमें से 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली कडोना और क्रांस रीवर परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं।

आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत नाइजीरिया के नागरिक भारत में सिविलियन और रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

सुश्री नर्मदा देवी खुमैन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय आईसीसीआर प्रायोजित मणिपुरी नृत्य मंडली, नर्मदा सांस्कृतिक संगठन ने 21-26 नवंबर 2019 तक नाइजीरिया का दौरा किया और अबुजा में अंतर्राष्ट्रीय कला और शिल्प एक्सपो के 12वें सत्र में प्रदर्शन किया। इसके अलावा श्री अनूप रंजन रंजन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से 14 सदस्यीय आइसीएसआर के बस्तर बैंड लोक नृत्य समूह ने 12-14 अप्रैल 2019 से नाइजीरिया का दौरा किया था। अबुजा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अब्दुल रशीद नाअल्लाह ने 2-11 अक्टूबर 2019 तक आईसीसीआर के अकादमिक आगंतुक कार्यक्रम (एवीपी) के अंतर्गत भारत का दौरा किया था। 15 जून 2019 को अबुजा नेशनल स्टेडियम में नाइजीरिया के संघीय युवा एवं खेल विकास मंत्रालय के सहयोग से पहली बार 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए, नाइजीरिया की संघीय सरकार के साथ साझेदारी में मिशन ने 02 अक्टूबर 2019 को एक स्मारक टिकट जारी किया। भारतीय मिशन ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल यात्रा (साइकिल रैली) का भी आयोजन किया और भारतीय उच्चायोग (ओएचसीआई) के कार्यालय लागोस ने नए पौधे, पेड़ और घास के कवर लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। हमारे मिशन ने "स्वच्छा ही सेवा" अभियान, आईटीईसी दिवस की 55वीं वर्षगांठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती, संविधान दिवस सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें भारतीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही।

कांगो गणराज्य (आरओसी)

नवम्बर 2019 में ब्राजाविले में हमारा दूतावास खुलने के साथ कांगो गणराज्य से हमारे संबंधों ने एक नया मैत्रीपूर्ण मोड़ लिया है। कांगो गणराज्य की स्वास्थ्य मंत्री डॉ. जैकलीन लीडिया मिलोगो ने 2-5 दिसम्बर 2019 के दौरान जीएवीआई (टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक वैश्विक गठबंधन) बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की।

साओ टोगे और प्रिंसीपे

भारत तथा साओ टोगे और प्रिंसीपे के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हैं। साओ टोगे ने विभिन्न बहुपक्षीय मंचो पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। भारत और साओ टोगे आर्थिक सहयोग, पारम्परिक चिकित्सा पद्धति, औषधीय पादपों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सक्रिय सहयोग करते रहें हैं। भारत ने प्रशिक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्र में साओ टोगे को अपनी सहायता जारी रखी। भारत ने साओ टोगे में सरकारी कार्यकलापों और स्कूल के आईटी संबंधी उन्नयन के लिए नवम्बर 2019 में 150 कम्प्यूटर दिए थे।

सेनेगल

सेनेगल के साथ भारत के संबंध समीक्षाधीन अवधि के दौरान और अधिक गहरे और सुदृढ़ हुए हैं। अगस्त 2019 में ब्यारिज, फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति माकीसाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुलाकात की। जुलाई 2019 में टाटाने लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत वहां 562 टाटा बसों की अंतिम खेप पहुंचाई। मई 2019 में अशोक लीलैण्ड ने 400 मिनी बसों की आपूर्ति करने के लिए सेन बस सेवा के साथ एक संवदा पर हस्ताक्षर किए जिसमें से अब तक 60 बसे पहले से ही भेजी जा चुकी हैं। मई-जून 2019 के दौरान एक लिम्ब-फिटमैंट, शिविर लगाया गया तथा विदेश मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस) द्वारा शरीर के 556 कृत्रिम अंग उपलब्ध कराये गये। एचएमटी ने नवम्बर 2019 में डकार में उद्यमी प्रशिक्षण और विकास केन्द्र (सीईडीटी) से संबंधित आधुनिकीकरण अनुदान परियोजना के पहले चरण के कार्य को पूरा करके उसे सेनेगल सरकार को सौंपा। विदेश मंत्रालय के 10 राजयनिकों ने 14-27 अप्रैल 2019 के दौरान सेनेगल राजनयिकों से संबंधित पहले विशेष पाठयक्रम में भाग लिया।

डकार में हमारा मिशन 26 जनवरी 2020 को तिरंगा 4.0, अपने सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। डांस स्मिथ से और आईसीसीआर प्रायोजन के अंतर्गत 8 सदस्यीय बॉलीवुड सांस्कृतिक मंडली 25 जनवरी-3 फरवरी 2020 से सेनेगल और क्षेत्र के देशों का दौरा करेगी। भारतीय राज्यों और सेनेगल क्षेत्रों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने के लिए 31 जनवरी 2020 को भारत-सेनेगल द्विपक्षीय संबंधों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

सिएरा लियोन

12-14 अक्तूबर 2019 के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वैंकेया नायडू द्वारा सिएरा लियोन की पहली उच्च स्तरीय ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत और सिएरा लियोन के बीच द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने फ्री टाउन में नए राजकीय भवन के निर्माण के लिएएलओसी के आवंटन हेतु भारत सरकार के निर्णय से सिएरा लियोन सरकार को अवगत किया। हमारी सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत सिएरा लियोन को 1000 एमटी चावल उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ पोर्टेबल जल परियोजना के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर पुन: आवंटित किए गए।

इस यात्रा के दौरान 6 समझौता ज्ञापनों (i) भारत के विदेश मंत्रालय तथा सिएरा लियोन के विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालयके बीच परामर्श नवाचार (ii) भारत के विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय तथा सिएरा लियोन के विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (iii) विदेश मंत्रालय की ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) और सिएरा लियोन गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन (iv) वर्ष 2019-23 के लिए भारत सरकार और सिएरा लियोन गणराज्य सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम (v) भारत सरकार और सिएरा लियोन सरकार के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और सिएरा लियोन सरकार के बीच भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता जिसमें हाइड्रोलिक्स, जल प्रबंधन प्रणाली (सिंचाई) और ट्रैक्टरों की व्यवस्था शामिल है।

अफ्रीका में 18 मिशन खोलने संबंधी भारत सरकार के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए उपराष्ट्रपति ने सिएरा लियोन में मिशन खोलने की घोषणा की है।

चुनाव आयुक्त श्री मौहम्मद एन्फाह अली कन्टेह (सीईसी) और श्री एडमंड एसएल्फाह ने 3-4 सितम्बर 2019 के दौरान बैंगलुरू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विश्व चुनाव निकाय एसोसिएशन की चौथी महासभा में भाग लिया। अप्रैल नवम्बर 2019 के दौरान सिएरा लियोन ने आईटीईसी के अंतर्गत 4 स्लॉट इस्तेमाल किए। सिएरा लियोन के सशस्त्र कार्मिकों ने 4 स्लोटो का उपयोग किया। आईसीसीआर छात्रवृत्ति के अंतर्गत आठ स्लॉटों में से 5 स्लॉट दिए गए और भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार 3 स्लॉट जारी किए गए। 22 जून 2019 को फ्री टाऊन में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

उच्च कार्यकारी अधिकारी, विदेश मंत्रालय और सिएरा लियोन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 13-31 जनवरी 2020 तक एफएसआई, नई दिल्ली में दूसरे वार्षिक निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के फैलोशिप कार्यक्रम में भाग लेंगे।

टोगो

भारत और टोगो दोनों देशों के बीच मेत्रीपूर्ण संबंध कायम है जिनमें विदेश राज्यमंत्री श्री वी. मुरलीधरन द्वारा 5-6 सितंबर 2019 के दौरान टोगो की यात्रा किए जाने से और मजबूती आई है। अपनी यात्रा के दौरान राज्यमंत्री (वीएम) ने राष्ट्रपति फोरे जी नासिगेबे से मुलाकात करने के अलावा टोगो के विदेश मंत्री, डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री, योजनामंत्री, खान और ऊर्जा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठके की। राज्यमंत्री (वीएम) ने वहां रहने वाले भारतीय अप्रवासियों से भी बातचीत की। उन्होंने लोम के राजनयिक क्लब में "भारत अफ्रीका संबंधों" विषय पर एक व्याख्यान दिया। अफ्रीका में 18 मिशन खोलने संबंधी निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए राज्यमंत्री (वीएम) ने टोगो में 2020-21 में भारतीय मिशन खोलने की घोषणा की। टोगो के खान और ऊर्जा मंत्री श्री मार्क डेडरिली एब्ली बिडामोन ने 28 अक्तूबर से 1 नवम्बर 2019 के दौरान नई दिल्ली में आईएसए की दूसरी सभा में शामिल होने के लिए एक शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से विकास भागीदारी के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ कोष के जरिए भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित फजाओ-मल्फाकासा राष्ट्रीय पार्क में (उत्तर टोगो) में जैव विविधता अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई 2019 को लोम में यूनेस्को की एक परियोजना शुरू की गई। अप्रैल-नवम्बर, 2019 की अवधि के दौरान टोगो ने आईटीईसी के अंतर्गत 5 स्लॉट, 3 रक्षा स्लॉट, भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में लिए गए

निर्णय के अनुसार 3 स्लॉट और आइसीसीआर छात्रवृत्ति के अंतर्गत उसे दिए गए 8 स्लॉटों में से 3 स्लॉटों का इस्तेमाल किया। 22 जून 2019 को लोम में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। टोगो के रक्षा और सुरक्षा मामलों के विभाग का एक अधिकारी 13-31 जनवरी 2020 तक नई दिल्ली के एफएसआई में दूसरे वार्षिक निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के फैलोशिप कार्यक्रम में भाग लेगा।

7

यूरोप और यूरोपीय संघ

बेल्जियम

भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय संबंध संवर्धित बहुपक्षीय संबंधों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए और अधिक मजबूत हुए हैं क्योंकि बेल्जियम ने वर्ष 2019-2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की गैर-स्थायी सदस्यता हासिल की है।

इस अवधि को भारत और बेल्जियम के बीच उच्च-स्तरीय आदान-प्रदानों के रूप में देखा गया है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 29-30 अगस्त, 2019 को ब्रुसेल्स का दौरा किया। इस दौरे में, उन्होंने अपने बेल्जियम समकक्षी, उपप्रधानमंत्री तथा विदेश और रक्षा मंत्री श्री डिडिएट रेयंडर्स से भेंट की और विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।

रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौडा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 14-15 अक्तूबर, 2019 को बेल्जियम का दौरा किया तथा पोर्ट ऑफ एंटवेर्प के पेट्रो रसायन क्लस्टर को भी देखने गए। शिष्टमंडल ने यूरोपीय रसायन उद्योग परिषद् (सीईएफआईसी) के सदस्यों से भी भेंट की और भारत में पेट्रोलियम रसायन, पेट्रोरसायन निवेश सेक्टरों (पीआईएसएसओआईआरएफ) के रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों में निवेश अवसरों के बारे में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने एंटवेर्प में बेल्जियम की कंपनी जेमिनी कार्पोरेशन का भी दौरा किया जो विश्व के विशालतम चक्रीय अर्थव्यवस्था बाजार निर्माताओं में से एक है।

वर्ष 1997 में स्थापित भारत-बेल्जियम लक्जमबर्ग आर्थिक संघ संयुक्त आयोग (भारत-बीएलईयू जेसीएम) द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रमुख मंच है। 16वीं भारतीय-बीएलईयू जेसीएम 17 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली

में आयोजित की गई थी जिसके दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई जैसे व्यापार वैविध्यीकरण, निवेश, आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ-प्रौद्योगिकी, जल शोधन, आईसीटी, सेवाएं, पारंपरिक औषधियां, आयुर्वेद, योग, पर्यटन, बाजार पहुंच मुद्दे, बहुपक्षीय सहयोग आदि।

भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों का केन्द्रीय स्तंभ पारंपरिक रूप से व्यापार और निवेश रहा है। भारत माल के संबंध में बेल्जियम का द्वितीय विशालतम व्यापार गंतव्य है। हीरों का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार की अगुआई करता है जो वर्ष 2018-19 में 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (15.6 यूरो) था जिसमें वर्ष 2017-18 की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत और बेल्जियम के बीच वर्ष 2018 के दौरान सेवाओं के संदर्भ में व्यापार 1110.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर (941 मिलियन यूरो) था। भारत का बेल्जियम को निर्यात 696.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (590 मिलियन यूरो) और बेल्जियम से आयात मिलियन 414.18 अमेरिकी डॉलर (351 मिलियन यूरो) था। भारत में बेल्जियम का कुल निवेश अप्रैल, 2000 से जून, 2019 तक 1.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1.70 मिलियन यूरो) था जिससे यह भारत में 22वां विशालतम निवेशक देश बन गया है।

लक्जमबर्ग

भारत ग्रैंड डच ऑफ लक्जमबर्ग के साथ कुछ और मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है।

वर्ष 1997 में स्थापित भारत-बेल्जियम लक्जमबर्ग आर्थिक संघ संयुक्त आयोग (भारत-बीएलईयू जेसीएम) द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रमुख मंच है। 16वीं भारतीय-बीएलईयू जेसीएम 17 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसके दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई जैसे व्यापार वैविध्यीकरण, निवेश, आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ-प्रौद्योगिकी, जल शोधन, आईसीटी, सेवाएं, पारंपरिक औषधियां, आयुर्वेद, योग, पर्यटन, बाजार पहुंच मुद्दे, बहुपक्षीय सहयोग आदि।

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत और लक्जमबर्ग के बीच द्विपक्षीय व्यापार 161.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर (147.18 मिलियन यूरो) की तुलना में 150 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2018 के दौरान, भारत और लम्जमबर्ग के बीच सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार 260.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर (221 मिलियन यूरो) था; भारत का लक्जमबर्ग को निर्यात 76.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (65 मिलियन यूरो) तथा लम्जमबर्ग से आयात 184.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर (156 मिलियन यूरो) था। अप्रैल, 2000 और जून, 2018 के बीच लक्जमबर्ग से भारत के लिए एफडीआई प्रवाह लगभग 2.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2.58 मिलियन यूरो) था जिससे यह भारत में 16वां विशालतम निवेशक बन गया था।

नीदरलैंड्स

वर्ष 2019 में भारत-नीदरलैंड्स संबंधों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रगति हुई जब नीदरलैंड्स के सम्राट विलियम-एलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा ने भारत की प्रथम राजकीय यात्रा की। इस राजकीय यात्रा के उपरांत भारत के विदेश मंत्री द्वारा नीदरलैंड्स का दौरा किया गया। नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श संचालित किए गए तथा भारतीय राजनयिकों के लिए दि हेग में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत के राज्यों तथा डच की प्रासंगिक सत्ताओं के बीच संबंधों को केरल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा

नीदरलैंड्स की यात्रा से और अधिक बल प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों के बीच व्यापार और अन्य क्षेत्रों के अनेक शिष्टमंडलों का भी पर्याप्त आदान-प्रदान हुआ। पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी भव्य पैमाने पर आयोजित किया गया। गांधी केन्द्र, दि हेग में बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

नीदरलैंड्स सम्राट विलियन एलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा ने 13-18 अक्तूबर, 2015 को भारत की अत्यंत सफल राजकीय यात्रा की। महामहिमगण ने एक उच्च-स्तरीय मंत्रालयी शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जिसमें शामिल थे - सुश्री सिग्रिड काग, विदेश व्यापार और व्यापार सहयोग मंत्री, श्री ब्रूनो बूइंस, चिकित्सा देखरेख और खेल मंत्री, सुश्री मोना केलीजेर, आर्थिक कार्य एवं जलवायु नीति की राज्य सचिव, तथा 250 से अधिक व्यक्तियों का व्यापार शिष्टमंडल जो विभिन्न क्षेत्रों की 140 से अधिक कंपनियों और संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसमें प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष, कृषि, जल, स्वास्थ्य-देखरेख और जलवायु भी शामिल थे। यह भारत की यात्रा पर आया अब तक सबसे विशाल डच शिष्टमंडल था। यात्रा के दौरान, महामहिमगण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। विदेश मंत्री ने सम्राट और सम्राज्ञी से भेंट की। महामहिमगण ने नई दिल्ली में 15 अक्तूबर, 2019 को आयोजित 25वें प्रौद्योगिकी शिखर-सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भी भाग लिया। नीदरलैंड्स इस शिखर-सम्मेलन का भागीदार देश था। सम्राट और सम्राज्ञी ने मुंबई और केरल राज्य की यात्रा भी की। स्मार्ट और संधारणीय पोर्ट-चालित विकास पर भारत-डच फोरम का तीसरा संस्करण 16 अक्तूबर, 2019 को मुंबई में आयोजित किया गया।

भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीदरलैंड के किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात की

डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री ने 9-11 नवम्बर, 2015 को नीदरलैंड्स का दौरा किया। विदेश मंत्री ने नीदरलैंड्स साम्राज्य के विदेश मंत्री श्री स्टेफ ब्लॉक से भेंट की तथा इस बैठक के दौरान पारस्परिक हित के अनेक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने डच हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विदेश समिति के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। डच पक्ष का नेतृत्व सुश्री पिया दिज्कस्त्रा, समिति की

सभापति द्वारा किया गया था। श्री स्वेन कूपमासं, वीवीडी (पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एवं डेमोक्रेसी) की विदेश नीति प्रवक्ता, सुश्री लिलिएने प्लोमैन, पीवीडीए (लेबर पार्टी) की विदेश नीति प्रवक्ता, श्री स्जोएर्ड स्जोएर्डस्मा, डी 66 (डेमोक्रेट्स 66) के विदेश नीति प्रवक्ता तथा श्री अचराफ बोआली डी 66 के संसद सदस्य ने भी चर्चाओं में भाग लिया।

भारत और नीदरलैंड्स के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 11 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री ए. गीतेश शर्मा, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय द्वारा तथा डच पक्ष का नेतृत्व सुश्री योका ब्रैंडट महासचिव, विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण परिधि की समीक्षा की जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग भी शामिल था। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय विषयों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग भी शामिल था।

भारतीय राजनयिकों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्लिंगेन्डील (नीदरलैंड्स इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस) एकेडमी, दि हेग में 28 अक्तूबर, से 1 नवम्बर, 2019 तक आयोजित किया गया। यूरोप में भारतीय मिशनों से छह राजनयिकों अर्थात् बेर्ने, रोम, जिनेवा, लिस्बन, बर्लिन, पेरिस तथा विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली से तीन अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

केरल के मुख्य मंत्री श्री पिनारयी विजयन ने 8-12 मई, 2019 तक नीदरलैंड्स में एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने डच अवसंरचना और जल प्रबंधन मंत्री सुश्री कोरा वैन नियूवेनहुई जेन तथा महासचिव, कृषि मंत्रालय श्री जन कीस गोयल से भेंट की। उन्होंने श्री हैंस डी बोएर, सभापति वीएनओ - एनसीडब्ल्यू (डच इम्प्लायर्स फेडेरेशन) द्वारा आयोजित बैठक में कृषि और जल क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की। उन्होंने वेजेनिंगेन यूनीवर्सिटी और पोर्ट ऑफ रोटेरडेम का दौरा भी किया। उन्होंने नीदरलैंड्स के राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया तथा केरल राज्य अभिलेखागार में प्रस्तुत डच अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर चर्चा की। उन्होंने एक व्यापार संपर्क समारोह में भाग लिया तथा नीदरलैंड्स में केरल समुदाय के साथ भी एक बैठक की।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 12-15 जून, 2019 तक नीदरलैंड्स की यात्रा पर गए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में 7-8 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाने वाली 'राइजिंग हिमाचल' वैश्विक निवेशक' प्रतिस्पर्धा का प्रचार-प्रसार करना था। इस शिष्टमंडल में राज्य उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और हिमाचल प्रदेश की कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। 14 जून, 2019 को दि हेग में एक रोड शो का आयोजन भी किया गया जिसमें हिमाचल प्रदेश में निवेश अवसरों को प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्रालय के महासचिव श्री जनकीस गोएत तथा उत्तर और दक्षिण हालैंड के प्रांतों के किंग्स कमिश्नरों से भी भेंट की।

श्री हृदय नारायण दीक्षित, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने 22-23 सितम्बर, 2019 तक नीदरलैंड्स की यात्रा की। उन्होंने दक्षिण हॉलैंड प्रांत के किंग्स कमीश्नर श्री जाप स्मिट तथा डच हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विदेश समित की सभापति सुश्री पिया दिज्कस्त्रा से भेंट की।

व्यापार और वाणिज्यिक संबंध द्विपक्षीय संबंधों का आधार बने रहे। नीदरलैंड्स, मॉरीशस और सिंगापुर के बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 3.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई अंत:प्रवाह के साथ भारत में तीसरा विशाल निवेशक था। वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल-जून) के लिए, एफडीआई इक्विटी अंत:प्रवाह 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में जर्मनी, स्विटजरलैंड, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम के बाद, नीदरलैंड्स भारत का पांचवां विशालतम व्यापार भागीदार था। कुल द्विपक्षीय व्यापार 12.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसमें

भारत से निर्यात 8.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा नीदरलैंड्स से आयात 4.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 (अप्रैल-अक्तूबर) के लिए द्विपक्षीय व्यापार 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने नीदरलैंड्स को 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया तथा नीदरलैंड्स से 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया।

भारतीय दूतावास, दि हेग ने व्यापार मिशन के उन प्रतिनिधियों के लिए 'विश्वास के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ाना' विषय पर 4 अक्तूबर, 2019 को एक ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया जो महामहिमगण के साथ राजकीय यात्रा पर साथ आए थे। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और इंवेस्ट इंडिया के प्रमुख अधिकारियों ने प्रश्नों का उत्तर देने तथा भावी निवेशकों के साथ संपर्क करने के लिए सत्र में प्रतिभागिता की। 4 नवम्बर, 2019 को प्रतिभागियों और संभावित डच निवेशकों के लिए एक प्रतिपुष्टि सत्र का आयोजन किया गया जिसमें एनडब्ल्यूओ (नीदरलैंड्स आर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च), अवसरंचना और जल प्रबंधन मंत्रालय तथा रॉयल डच शैल के वक्ताओं ने भाग लिया। धर्मशाला में 6-8 नवम्बर, 2019 तक आयोजित कार्यक्रम 'इन्वेस्ट हिमाचल' में एसोचैम ने डच कंपनियों के साथ एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। दि डच ग्रीन हाउस डेल्टा ने भी इस निवेशक कार्यक्रम के दौरान एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तथा एक उच्च प्रौद्योगिकीय ग्रीनहाउस परियोजना का विकास करने के लिए हिमाचल सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भू-स्थैतिक विश्व फोरम 2-4 अप्रैल, 2019 को एम्सटर्डम में आयोजित किया गया। सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस फोरम में भाग लिया। 3 अप्रैल, 2019 को भारतीय भू-स्थैतिक व्यापार शिखर-सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।

श्री तरुण श्रीधर, सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य-पालन) ने 8-10 अप्रैल, 2019 तक नीदरलैंड्स के दौरे पर गए शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरे के दौरान डच कृषि, प्रकृति और भोजन गुणवत्ता मंत्रालय में बैठकें आयोजित की गई तथा डच डेयरी क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय दौरे भी संचालित किए गए।

प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप कंपनियों से मिलकर बने एक भारतीय शिष्टमंडल ने एमेस्टर्डम में नेक्स्ट वेब समिट में भाग लेने के लिए 7-10 मई, 2019 तक नीदरलैंड्स का दौरा किया। शिष्टमंडल ने डच स्टार्ट-अप पारिस्थिकी को समझने के लिए अग्रणी उद्भवन केन्द्रों और संगठनों के साथ भेंट की।

अग्रणी डच स्वास्थ्य कंपनियों वाले डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी नवोन्मेषी मिशन ने 23-39 जून, 2019 तक नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का दौरा किया जिसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समझना तथा प्रमुख अस्पतालों और संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना था।

डॉ. अशोक दलवी, सीईओ, राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं सभापति, कृषक आय दोहरीकरण समिति ने 25-29 अगस्त, 2019 तक नीदरलैंड्स की यात्रा की तथा डच कृषि, प्रकृति और आहार गुणवत्ता मंत्रालय में बैठकें की तथा वेगेनिंगन विश्वविद्यालय और डच कंपनियों का दौरा किया।

श्री सिंगीरेड्डी निरंजन रेड्डी, कृषि, सहकारिता और विपणन मंत्री, तेलंगाना सरकार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने बीज क्षेत्र पर अध्ययन दौरे के लिए 2-5 नवम्बर, 2019 को नीदरलैंड्स की यात्रा की।

डिप्टी मेयर सुश्री सस्किया ब्रूइंस के नेतृत्व में दि हेग शहर के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने 17-20 नवम्बर, 2019 तक कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा किया। दि हेग शहर तथा राज्यों के बीच समझौता-ज्ञापनों को नवीकृत किया गया। शिष्टमंडल ने बेंगलुरु टेक समिट 2019 में भी भाग लिया।

श्री मार्टिन कैम्पस, महासचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय ने 23-26 जुलाई, 2019 तक भारत का दौरा किया।

उन्होंने नई दिल्ली में वैश्विक अभिनवता सूचकांक के शुभारंभ में प्रतिभागिता की तथा उसमें आधार-व्याख्यान दिया। श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा प्रो. विजय राघवन, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी इस अवसर पर उपस्थिति थे। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से भी भेंट की।

पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एमेस्टर्डम के प्रसिद्ध डैम स्क्वैयर में 16 जून, 2019 को मनाया गया। यह पहली बार था कि डैम स्क्वैयर ने भारत से संबंधित किसी सार्वजनिक समारोह की मेजबानी की थी। यह स्क्वैयर ऐमस्टर्डम का ऐतिहासिक केन्द्र है जहां रॉयल पैलेस स्थित है और जिसके समीप द्वितीय विश्व युद्ध के पीड़ितों की स्मृति में 1956 में राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया था। इस समारोह का उद्घाटन हिमालच प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया। रॉयल डच आर्मी ने पहली बार इस समारोह में भाग लिया और एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें अन्य के अलावा एक पदयात्रा भी संचालित की गई थी जिसमें विद्यालय के छात्रों और अन्य लोगों ने होबेन मैप्लेन स्थित गांधी प्रतिमा से दि हेग में शांति पैसेल तक की दूरी तय की। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन का प्रचार-प्रसार करने के लिए नीदरलैंड्स में प्रख्यात व्यक्तियों की सहभागिता के साथ संगोष्ठियां, दि हेग स्थित गांधी केन्द्र में गांधी पर फिल्मों का प्रदर्शन, गांधी केन्द्र में गांधी पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन, खादी प्रदर्शनी का आयोजन, 'एक विचार के रूप में खादी, न कि केवल एक वस्त्र के रूप में' विषय पर एक कार्यक्रम तथा दि हेग में एक साइकिल-चालन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 वृक्षों को रोपने की योजना भी बनाई गई है।

30 सितम्बर, 2019 को प्रतिष्ठित रिज्क्स्टम्यूजियम (राष्ट्रीय संग्रहालय) नीदरलैंड्स में 'भारत और नीदरलैंड्स अतीत, वर्तमान और भविष्य' नामक संगोष्ठी का संयुक्त रूप से आयोजन भारतीय दूतावास और रॉयल एशियन आर्ट सोसाइटी द्वारा किया गया जो डच रॉयल्स की अक्तूबर, 2019 में भारत की राजकीय यात्रा की पूर्व-भूमिका के रूप में आयोजित कार्यक्रम था। नीदरलैंड्स के सम्राट और साम्राज्ञी ने इस संगोष्ठी में भाग लिया जिसमें शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान मंत्री, सम्राट के उत्तरी हालैंड के कमीश्नर, एमेस्टर्डम के डिप्टी मेयर तथा 26 देशों के राजदूत भी शामिल हुए थे। इस संगोष्ठी में श्री हांस डी बोएर, अध्यक्ष, वीएनओ-एनसीडब्ल्यू, श्री मारेंस एंगेलहार्ड, निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नीदरलैंड्स श्री टाको डेबिट्स, निदेशक रजिक्स्म्यूजियम, श्री मेनो फिट्स्की, एशियन आर्ट डेवलपमेंट के प्रमुख, सुश्री मार्टिन गोसेलिंक, इतिहास विभाग की प्रमुख, दोनों रिजिस्म्यूजियम तथा श्री पीटर एरिएंश केपेर्स, सभापति, रॉयल एशियन आर्ट सोसाइटी, नीदरलैंड्स द्वारा भारत और नीदरलैंड्स के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर वार्ताएं प्रस्तुत की गई। नीदरलैंड्स में भारतीय राजदूत वेणु राजामोनी द्वारा इस विषय पर लिखी पुस्तक का विमोचन इस अवसर पर महामहिम सम्राट विलियन-एलेक्जेंडर द्वारा किया गया।

आयरलैंड

भारत और आयरलैंड के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंध निरंतर निर्बाध बने रहे। आयरलैंड ने वृहद आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में (अप्रैल, 2019) एक नया पूर्ण कांसुलेट खोला तथा पहली बार शासक फिनेगेल पार्टी से दो भारतीय मूल के काउंसलर निर्वाचित हुए जिससे

आयरलैंड की राजनीति पर भारतीय प्रवासियों का बढ़ता प्रभाव प्रतिबिंबित हुआ। आयरलैंड के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री जिम डाली ने भारत की यात्रा (मार्च, 2019) की। उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से भेंट की तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों में समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना पर विचार-विमर्श किया।

दूतावास एक नए चांसलरी परिवार में स्थानांतरित हो गया (19 अक्तूबर, 2019)। यह स्थानांतरण भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा तथा आयरलैंड में इसके संपर्क कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायक होगा।

भारत-आयरलैंड व्यापार पण्यावर्त वर्ष 2018 में 1.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस अवधि के दौरान भारत में आयरलैंड के निवेश ने 427 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर दिया। दूतावास ने सीआईआई के सहयोग से 30 सीआईआई सदस्यों के लिए 'आयरलैंड में भारतीय स्टार्ट-अप अनुसंधान मिशन' नामक एक नेटवर्किंग समारोह का आयोजन किया (10 अप्रैल, 2019) जिसे दौरान आयरलैंड के उद्योग के साथ उपयोगी संपर्क सत्रों का आयोजन किया गया। यूरोपीय संघ को छोड़ने के यूके के निर्णय ने आयरलैंड को विवश कर दिया है कि वह भारत जैसे एशिया-प्रशांत देशों के प्रति अपनी निर्यात और व्यापार रणनीतियां निर्देशित करे जो पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध कराते हैं। एक महत्वाकांक्षी एशिया-प्रशांत सम्मेलन 13 जून, 2019 को आयोजित किया गया जिसका आयोजन आयरलैंड की सरकार द्वारा किया गया था जिसमें 15 से अधिक भारतीय उद्योगपतियों ने भाग लिया जो प्रमुख कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसे लॉक्यूबेटर, पेयू, हीरो हाउसिंग फाइनेंस, हीरो फिन्कोर्प, आईसीआईसीआई बैंक, वोडाफोन, आइडिया, येस बैंक, टाटा कम्युनिकेशंस, नेटस्वीपर, टेक महिन्द्रा और टेस्ट ट्राइएंगल। प्रतिभागियों ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया, विशेष रूप से ब्रेजिट के कारण नए अवसरों के संदर्भ में विशेष रूप से स्वास्थ्य, बायो-फार्मा, कृषि-प्रौद्योगिकी और आईसीटी क्षेत्रों में।

पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयरलैंड सहित 20 देशों में 21-24 जून, 2019 तक मनाया गया जिसमें शहर की परिषदों, योग संस्थाओं और भारतीय समुदायों ने सक्रिय रूप से प्रतिभागिता की गई। डब्लिन में ही, यह समारोह व्यापारिक जिले के मध्य में आयोजित किया गया तथा इसमें लगभग 500 लोगों ने प्रतिभागिता की जिनमें राजनेता, संसद सदस्य, राजनयिक, व्यापार नेतृत्वकर्ता, खिलाड़ी, भारतीय समुदाय तथा आयरिश लोगों के अनेक वर्ग शामिल थे। आयरलैंड के राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती सबीना हिगिंस ने एक प्रभावशाली भाषण दिया जिसमें उन्होंने विद्यालय की केन्द्रीय पाठ्यचर्या में योग को शामिल करने की हिमायत की। समारोह में अन्य अतिथि थे - डब्लिन के लार्ड मेयर पॉल मैक ऑलिफे और पूर्व प्रधानमंत्री बेर्टी एहेम। समूचे आयरलैंड में लगभग 1500 लोगों ने इसमें भाग लिया।

इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कांशियसनैस (इस्कॉन) ने 27 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय डब्लिन रथयात्रा समारोह (रथ समारोह) का आयोजन किया गया। डब्लिन नगर परिषद् के प्रतिनिधियों सहित 500 से अधिक लोगों ने इस समारोह में भाग लिया। रथयात्रा के मार्ग में हजारों लोगों ने दर्शन किया। डब्लिन में फीनिक्स पार्क में 1 सितम्बर, 2019 में 5वां भारत दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया तथा भारत की सांस्कृतिक विविधता का इससे प्रदर्शन हुआ। दसवां आयरलैंड भारतीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) का आयोजन 15-17 नवम्बर, 2019 तक किया गया। प्रख्यात फिल्मी हस्ती प्रकाश झा, पावर्ती नैयर और फौकिया अख्तर उनकी फिल्म 'परीक्षा' के आयरलैंड में प्रीमियर के सिलसिले में इस वर्ष विशेष आमंत्रिती थे। समारोह के भाग के रूप में चुनिंदा बांग्ला फिल्में भी दर्शाई गईं।

डब्लिन में 19 सितम्बर, 2019 को 'देखो अपना देश' नामक पर्यटन रोड-शो आयोजित किया गया। पर्यटन और सांस्कृतिक मामले मंत्री, पंजाब सरकार श्री चरणजीत सिंह चन्नी मुख्य अतिथि थे। भारत से 20 से अधिक लोगों ने इस रोड शो में भाग लिया।

मिशन ने आयरलैंड के अनेक शहरों में महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुख्य समारोह डब्लिन, कोर्क और माओ में आयोजित किए गए। दूतावास ने गांधी पर एक पारस्परिक संपर्क चर्चा का आयोजन करने के लिए (2 अक्तूबर, 2019) यूनीवर्सिटी कॉलेज डब्लिन (यूसीडी) के साथ सहयोग किया। लाइब्रेरी हाल थिएटर, डब्लिन में 6 अक्तूबर, 2019 को 'वॉक विद गांधी' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें गांधी के जीवन और उनकी आस्था के बारे में चित्र शामिल थे। कोर्क स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में 'गांधी इन गुजरात' नामक पुस्तक का (2 अक्तूबर, 2019) विमोचन किया गया। इसमें अनेक चित्रों का एक महत्वपूर्ण संग्रह शामिल किया गया है। कोर्क के माइकल डेविट संग्रहालय के सहयोग से मायो में 'शांति वृद्धि' का रोपण किया गया (3 अक्तूबर, 2019)। यूनीवर्सिटी कॉलेज कोर्क (यूसीसी) ने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम (31 अक्तूबर, 2019) का आयोजन किया जिसके उपरांत गांधी पर वार्ता आयोजित की गई। 'लगे रहो मुन्नाभाई' फिल्म का विशेष रूप से चित्रण किया गया तथा 'गांधी@150' समारोह पूरे वर्ष भर इसी प्रकार जोर-शोर से मनाया जाता रहा।

दूतावास ने आयरलैंड में गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। लिमेरिक के मैक्स आर्थर मैक ऑलिफे के सम्मान में एक पट्टिका का अनावरण करते हुए समारोहों का शुभारंभ किया गया जिन्होंने बीसवीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब सहित पवित्र सिख पाठों का अनुवाद किया था। सेंटर फॉर इंटर-रिलीजियस डायलॉग एंड दि स्कूल ऑफ थियोलॉजी, फिलास्फी एंड म्यूजिक और डब्लिन सिटी यूनीवर्सिटी द्वारा "वर्तमान युग में गुरु नानक के जीवन और शिक्षा की प्रासंगिकता" पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया (14 अक्तूबर, 2019)। डब्लिन में क्राइस्ट चर्च में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया (11 नवम्बर, 2019) जिसे गुरुद्वारे जैसा सजाया गया था। ये समारोह वर्ष भर आयोजित किए जाएंगे।

दूतावास ने हिंदी दिवस का आयोजन किया (22 नवम्बर, 2019)। इस कार्यक्रम में हिंदी के उद्भव पर वार्ता, हिन्दी में एक नाटक, आज के विश्व में हिन्दी की प्रासंगिकता पर चर्चा तथा शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन शामिल थे। समुदाय के सदस्यों ने इस समस्त कार्यक्रमों में अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया।

दूतावास ने संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2019) के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। भारत के संविधान की उद्देशिका के सामूहिक पठन के साथ दूतावास में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके उपरांत, इक्कीसवीं शताब्दी में भारतीय संविधान की प्रासंगिकता पर एक संपर्क सत्र का आयोजन यिका गया, जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन, यूनीवर्सिटी कॉलेज डब्लिन, डब्लिन बिजनेस स्कूल और डब्लिन सिटी यूनीवर्सिटी के भारतीय छात्रों ने भाग लिया। 'इंडिया : दि स्प्रिट ऑफ फ्रीडम' का चित्रण भी किया गया। इसके उपरांत, डॉ अम्बेडकर के जीवन पर 'मूक नायक : लीडर ऑफ दि साइलेंट' नामक लघु फिल्म का चित्रण किया गया।

श्रीमती के.के. शैलजा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, केरल सरकार ने डब्लिन की यात्रा की (27-29 नवम्बर, 2019)। उन्होंने श्री जिम डाली, स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री के साथ भेंट की जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य और आयरलैंड के वृद्ध लोगों का विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। मंत्री डाली ने मार्च, 2019 में भारत की यात्रा की तथा उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा के साथ मुलाकात की। उन्होंने आयरलैंड में केरल के प्रतिष्ठित चिकित्सा परामर्शक के साथ भी बैठकें कीं। उन्होंने संट विसेंट अस्पताल की सीईओ सुश्री के कोनोली तथा अस्पताल के संकाय सदस्यों और नर्सों के साथ भी बैठक की। उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजीशियंस ऑफ आयरलैंड (आरसीपीआई) के अंतर्राष्ट्रीय मामलों

के प्रेजीडेंट और प्रमुख प्रो. मैरी होर्गन के साथ भी भेंट की। आयरलैंड में केरल समुदाय के सदस्यों ने उनके सम्मान में एक भेंट समारोह का आयोजन किया।

आयरलैंड में प्रवासी जनसंख्या लगभग 45,000 है जिनमें से 25,000 ओसीआई कार्डधारक हैं तथा लगभग 20,000 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं। अधिकांश समुदाय सदस्य स्वास्थ्य-देखरेख व्यवसाय (चिकित्सक और नर्से) आईटी, इंजीनियरी, वरिष्ठ प्रबंध पदों पर हैं तथा वे आयरिश समाज में अच्छी तरह से रच-बस गए हैं। दूतावास नियमित तौर पर डब्लिन में तथा आयरलैंड के अन्य देशों में प्रवासी भारतीय संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आयरलैंड सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है (4 अप्रैल, 2019) जिसमें उन्होंने सिख समुदाय के लोगों को पुलिस बल में कार्य करते समय पगड़ी पहनने की अनुमति दी है। ऐसे विदेशियों के लिए री-संट्री वीजा की अपेक्षा, जिनके पास निवासी कार्ड हैं, 12 अप्रैल, 2019 से समाप्त कर दी गई है। एक अन्य सकारात्मक घटनाक्रम में, आयरलैंड में महत्वपूर्ण कौशल वीजा पर कार्य करने वाले भारतीय नागरिकों के पति/पत्नी के लिए नियोजन परमिट प्राप्त करने की अपेक्षा को भी समाप्त कर दिया गया है (22 अप्रैल, 2019)। इस विषय को भारतीय नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर दूतावास के साथ उठाया गया था।

फ्रांस

भारत और फ्रांस ने अपनी रणनीतिक भागीदारी के इक्कीस वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जो 1998 में स्थापित हुए थे। घनिष्ठ होते हुए और निरंतर बढ़ते हुए रिश्ते प्राय: होने वाले उच्च-स्तर के आदान-प्रदान तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की परिधि पर विचारों की निरंतर बढ़ती हुई अभिसारिता इन संबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं,

रक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और सिविल परमाणु सहयोग के क्षेत्र हमारी रणनीतिक भागीदारी के मुख्य स्तंभ हैं। सहयोग के इन पारपंरिक क्षेत्रों के अलावा, भारत और फ्रांस सहयोग के नए क्षेत्रों में निरंतर एक-दूसरे के साथ रहे हैं जैसे अन्य के साथ-साथ हिंद महासागर में सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि सहित जलवायु परिवर्तन, और संधारणीय विकास और वृद्धि।

भारत और फ्रांस क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की परिधि पर व्यापक अभिसारिता की साझेदारी करते हैं। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखा है। फ्रांस का समर्थन एमटीसीआर, डब्ल्यूए और एजील में भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण था जबकि फ्रांस ने एनएसजी में पहुंच के लिए भारत की बोली का समर्थन करना जारी रखा है।

आर्थिक क्षेत्र में, जहां पर्याप्त संभावना व्याप्त है, फ्रांस के व्यापार और उद्यमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित किए हैं। इनके मध्य गुंजायमान द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध हैं और साथ ही लोगों-के-लोगों के साथ संपर्क में भी वृद्धि हो रही है। भारतीय प्रवासियों की भी शहरी फ्रांस में और उसके विदेशी विभागों/भू-भागों में पर्याप्त उपस्थिति है।

हाल के उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 जी-7 शिखर-सम्मेलन के लिए महामहिम राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन के विशेष आमंत्रण पर अगस्त, 2019 में फ्रांस का दौरा किया, जहां भारत 'सद्भावना' भागीदारों में से एक है। इस दौरे के दो भाग थे, द्विपक्षीय अवयव (22-23 अगस्त में शैंटिली/पेरिस) और बायरिट्ज में जी-7 संबंधी दौरा (25-26 अगस्त)। 22 अगस्त को, दोनों नेताओं ने शैंटिली (पेरिस का उत्तर) में ऐतिहासिक महलि में द्विपक्षीय बैठक के लिए मुलाकात की

जिसके उपरांत एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेस का आयोजन किया गया। दौरे के परिणामों में शामिल था - संयुक्त वक्तव्य, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर भारत-फ्रांस रोड मैप तथा 4 करार/समझौता-ज्ञापन। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी प्रधानमंत्री महामहिम श्री एडवर्ड फिलिप से मुलाकात की तथा बाद में पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बाद में 25-26 अगस्त को जी-7 शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के लिए बियारिट्ज (दक्षिण-पश्चिम फ्रांस) का दौरा किया। उन्होंने पर्यावरण तथा डिजिटल लोकतंत्र पर आयोजित सत्रों में भाग लिया।

प्रधानमंत्री तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन 24 सितम्बर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 'आतंकवाद और हिंसक उग्रवादी वर्णनों के प्रति रणनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नेताओं की वार्ता' नामक सत्र में सह-भागीदार थे। उन्होंने जून, 2019 में ओसाका में जी-20, 2019 के दौरान भी एक पारस्परिक बैठक की तथा ब्यूनस आयर्स में दिसम्बर, 2018 में जी-20, 2018 के दौरान एक द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 11-12 नवम्बर, 2019 को पेरिस की यात्रा की तथा फ्रांस की यूरोप और विदेश मंत्री श्री जीन-वाइवेस लेड्रियान के साथ वार्ता की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्री ने पेरिस शांति फोरम के द्वितीय संस्करण में भी भाग लिया, जहां उन्होंने साइबरस्पेस के बहुपक्षीय शासन पर उच्च-स्तरीय पैनल-चर्चा में भाग लिया। उन्होंने फोरम के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति से भी भेंट की। विदेश मंत्री ने बाद में इंस्टिट्यूट मोंटेग्ने (फ्रांसीसी चिंतन संस्थान) में प्रतिष्ठित व्यापारित प्रतिनिधियों और चिंतन संस्थान के सदस्यों की सभा को संबोधित किया तथा फ्रांसीसी दैनिक समाचार पत्र लेमोंडे को साक्षात्कार किया।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री सुश्री फ्लोरेंसा पार्ली के साथ द्वितीय द्विपक्षीय मंत्रालय-स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए 7-10 अक्तूबर, 2019 को पेरिस की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमैनुएल मैक्रोन से भी भेंट की तथा प्रमुख फ्रांसीसी रक्षा उद्योग उद्यमों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। रक्षा मंत्री ने सितम्बर, 2016 को हस्ताक्षरित अंतर्सरकारी संविदा के अंतर्गत फ्रांस से अर्जित किए जाने वाले प्रथम राफेल लड़ाकू विमान के हस्तांतरण समारोह में भाग लेने के लिए बोर्डियक्स की भी यात्रा की तथा उस पर उड़ान भी भरी। उन्होंने फ्रांस में चुनिंदा रक्षा उद्योग स्थलों का भी दौरा किया।

विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने फ्रांस द्वारा "भारत-प्रशांत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण" पर आयोजित शिखर-सम्मेलन बैठक में भाग लेने के लिए एक व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ रीयूनियम द्वीप समूह की यात्रा की। उन्होंने अनेक फ्रांसीसी मंत्रियों के साथ वार्ता की तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति श्री एमैनुएल मैक्रोन से भी भेंट की।

फ्रांस की ओर से, मंत्रालयी स्तर पर भारत आने वाले उच्च स्तरीय अधिकारी यूरोप और विदेश राज्य सचिव श्री जीन-बैप्टिस्टे लेमोयने (10 जून, 2019) थे तथा पारिस्थिकी और अंतर्वेशी संक्रमण राज्यमंत्री सुश्री ब्रून पोइटसन (30 अक्तूबर - 1 नवम्बर, 2019) थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के दूसरी सभा की अध्यक्षता करने के लिए पधारी थीं।

भारत और फ्रांस नियमित सांस्थानिक वार्ता तंत्रों की एक व्यापक परिधि को साझा करते हैं। भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता दोनों पक्षों के एनएसए के बीच आयोजित की जाती है। पिछली रणनीतिक वार्ता श्री अजीत डोभाल, एनएसए तथा श्री एमैनुएल बोन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार के बीच नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई थी। विदेश सचिव श्री विजय गोखले ने भी फ्रांसीसी विदेश कार्यालय के महासचिव श्री मॉरिस गॉरडॉल्ट - मोंटेग्ने के साथ नई दिल्ली में 11 जनवरी, 2019 को विचार-विमर्श किया।

समुद्री सहयोग पर चौथी द्विपक्षीय वार्ता 9 दिसम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका नेतृत्व उप एनएसए श्री पंकज शरण तथा फ्रांसीसी

सशस्त्र बल मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रणनीति महानिदेशक सुश्री एलिस गुएटिन द्वारा किया गया। वार्षिक भारत-फ्रांस आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यकारी समूह ने 15 फरवरी, 2019 को पेरिस में मुलाकात की।

रक्षा सहयोग

फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम एमैनुएल मैक्रॉन की यात्रा के दौरान (मार्च, 2018) दोनों देशों ने मंत्रालयी स्तर पर एक वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया था जिसकी दूसरी वार्ता ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार अक्तूबर, 2019 में आयोजित की गई। नियमित कार्यकारी बैठकें तथा सेवा प्रमुखों के स्तर पर दौरों का नियमित आदान-प्रदान भी होता रहा। तीनों सेनाओं ने भी नियमित रूप से रक्षा अभ्यास संचालित किए। नियमित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 'वरुण' मई, 2019 में दो चरणों में गोवा और हजिबोती में आयोजित किया गया। दोनों वायु सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 'गरुण' फ्रांस में जुलाई, 2019 में आयोजित हुआ। चल रही प्रमुख रक्षा-संबंधी परियोजनाओं में राफेल विमानों की खरीद और पी-25 स्कोर पेने परियोजना शामिल हैं।

अंतरिक्ष सहयोग

सिविल अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक संबंधों का निर्माण करते हुए भारत और फ्रांस, दोनों ने फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा (मार्च, 2018) के दौरान अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त दृष्टिकोण' जारी किया जिसे पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में क्रियान्वित किया जा रहा है। संयुक्त रूप से विकसित मेघा-ट्रोपिक्स उपग्रह, जो उष्ण कटिबंधी क्षेत्र के ऊपर बादलों और वाष्प कणों का प्रेक्षण करता है, बेहतर स्थिति में बना रहा और उसने बहुमूल्य वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराए। एक संयुक्त केए-बैंड प्रवर्धन प्रयोग भी क्रियान्वित किया जा रहा है। दूसरों और एरियनस्पेस के बीच चल रहे द्विपक्षीय सहयोग के भाग के रूप में जीएसएटी-II दिसम्बर, 2018 में कोरो (फ्रेंस गुयाना) से प्रक्षेपित किया गया था। फ्रांस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अवयवों और उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

सिविल परमाणु सहयोग

फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान (मार्च, 2018) एनपीसीआईएल तथा ईडीएफ ने औद्योगिक भावी मार्ग करार निष्पादित किया। ईडीएफ और एनपीसीआईएल के बीच परियोजना के शीघ्र पूरा होने के उद्देश्य को लेकर वार्ताएं चल रही हैं।

आर्थिक सहयोग

भारत और फ्रांस दोनों ही पारस्परिक अत्यंत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश तथा व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग से जुड़े हुए हैं। भारत में लगभग 1000 फ्रांसीसी कंपनियां विद्यमान हैं जिनका टर्नओवर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर है तथा उन्होंने लगभग 30,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। फ्रांस भारत में नौवां विशालतम विदेशी निवेशक है जिसका अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2018 तक संचयी निवेश 6.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। फ्रांस में लगभग 150 भारतीय कंपनियां विद्यमान हैं (जिनमें उप-आनुषंगियां भी हैं) जिनका अनुमानित निवेश एक बिलियन यूरो है तथा वे 7000 व्यक्तियों को रोजगार दे रही है।

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि में, भारत-फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर (+4.15 प्रतिशत) था। फ्रांस में भारत का निर्यात 5.23 बिलियन यूएसडी था जिसमें 6.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान, भारत में फ्रांस के आयात में समान अवधि के दौरान 2.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह बढ़कर 6.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तथापि, द्विपक्षीय व्यापार की समग्र मात्रा निम्न ही बनी रही, फ्रांस के साथ व्यापार भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल 1.41 प्रतिशत ही है।

सांस्कृतिक और लोगों में परस्पर सहयोग

भारतीय संस्कृति फ्रांस के लोगों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय है। विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्र नामक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र जो इस समय नवीकरण प्रक्रिया के अध्यधीन है, पेरिस में खोला जाना है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पेरिस स्थित भारतीय दूतावास द्वारा पेरिस तथा फ्रांस के अन्य शहरों में 2016 से किया गया जा रहा है जिनसे वहां से लोगों से पर्याप्त प्रशंसा बटोरी है और प्रेस में भी उनके बारे में पर्याप्त उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1987 में स्थापित और नई दिल्ली में स्थित भारत-फ्रांस प्रगत अनुसंधान संवर्धन केन्द्र (सीईएफआईपीआरए) विज्ञान में अनुसंधान तथा विद्यमान अनुसंधान परियोजनाओं के मूल्यांकन के संयुक्त प्रस्तावों का वित्त-पोषण करते हुए एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अनेक अन्य द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम भी विद्यमान हैं जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-फ्रांस मंत्रालय-स्तरीय संयुक्त समिति की शामिल है जिसकी पहली बैठक जून, 2018 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

यह अनुमान लगाया गया है कि फ्रांस में लगभग 10,000 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। फ्रांस की उच्च शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी माध्यम में संचालित पाठ्यक्रमों, विशेष रूप से व्यवसाय प्रबंध के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों से प्रोत्साहित होकर लगभग 3,000 नए भारतीय छात्र प्रतिवर्ष फ्रांस आते हैं। दोनों पक्षों का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक छात्रों की संख्या 25,000 तक पहुंच जाए। मार्च, 2018 में हस्ताक्षरित डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता का एक करार पहले से ही लागू किया गया है। अगस्त, 2019 में, दोनों देशों के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

एंडोरा

भारत और एंडोरा राज्य के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। डॉ. राजनंदिनी और उनके दल द्वारा प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम 14 मई, 2019 को एंडोरा के वार्षिक सेरमाना डीला डाइवसिटेट सांस्कृतिक महोत्सव के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 23 जून, 2019 को योग सत्रों और मंत्रोच्चारण के साथ एंडोरा ला वेरा में मनाया गया था।

स्पेन

प्रधानमंत्री द्वारा मई, 2017 में स्पेन की अधिकारिक यात्रा तथा विदेश मंत्री की फरवरी, 2019 में की गई स्पेन की अधिकारिक यात्रा से प्रदान किए गए बल के उपरांत दिसम्बर में विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन की सुनियोजित यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ बने रहे। बहुपक्षीय स्तर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क का एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल के दिसम्बर, 2019 में पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 25) में सहभागिता करने की आशा है। भारत-स्पेन संबंधों और रक्षा सहयोग की पुन: पुष्टि करते हुए, आईएनएस तरकश ने पश्चिमी बेड़ा विदेशी तैनाती के भाग के रूप में कैडिज़ में पोर्ट कॉल संचालित की।

वाणिज्यिक क्षेत्र में, वाणिज्य और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जापान में आयोजित जी 20 व्यापार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था संबंधी मंत्रालयी बैठक के दौरान त्सुबाका, जापान में 9 जून, 2019 को स्पेन सरकार

के कार्यवाहक उद्योग व्यापार और पर्यटन मंत्री से भेंट की। स्पेन सरकार की कैबिनेट ऑफ सेक्रेट्री ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म की प्रमुख श्रीमती एंतानिया एलोमर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय स्पेनी शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में 3 जुलाई, 2019 को आयोजित भारत-स्पेन पर्यटन विशेषज्ञ पैनल की दूसरी बैठक में प्रतिभागिता की। भारत के आइकानिक डेस्टिनेशनों तथा स्पेन के स्मार्ट डेस्टिनेशनों के बीच सहक्रिया पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। स्पेन सरकार की कार्यवाहक उद्योग, व्यापार और पर्यटन मंत्री सुश्री रेयेस मारोतो ने संगोविया में आयोजित होरासिस भारत-स्पेन सम्मेलन में व्याख्यान दिया जिसमें अनेक सी-स्तरीय भारतीय कार्यपालकों ने भाग लिया था। भारतीय शिष्टमंडलों ने अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी व्यापार मेला बार्सिलोन, इंटरगिफ्ट मैड्रिड तथा स्मार्ट सिटीज़ वर्ल्ड एक्स्पो कांग्रेस में भाग लिया। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् ने मैड्रिड में एक क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया तथा भारतीय पर्यटन ने अक्तूबर में बार्सिलोना, मैड्रिड और सेविला में रोड शो आयोजित किए।

पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैड्रिड 21 जून को ऐतिहासिक टेम्प्लो डी डेबोड में आयोजित कियाग या जिसके उपरांत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम 15 प्रमुख शहरों में आयोजित किए गए जैसे बार्सिलोना, टेनेरिफे, ग्रानाडा, वालाडोलिड आदि जिनमें लगभग 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आईसीसीआर अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल थे जिसके तहत और भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जो थे - स्पेन के विभिन्न शहरों में 'माई लाइफ इज़ माई मैसेज' नामक दृश्य-श्रव्य प्रदर्शनी', स्पेन के डाक-टिकट आयोग द्वारा स्मारक डाक-टिकट का विमोचन, संगीत कार्यक्रम और व्याख्यान तथा महात्मा गांधी की पांच प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि समारोह। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 'एकता यात्रा', फोटो प्रदर्शन और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। गुरु नानक देवजी की 550वीं वर्षगांठ मैड्रिड, बार्सिलोना और वेलेंसिया के गुरुद्वारों में गुरु लंगरों के साथ मनाई गई जिनमें 12000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संविधान दिवस 2019 के समारोहों में पद्मश्री डॉ. राफेल इसजुबिएटा तथा भारतीय संविधान के स्पेनी भाषा में अनुवादक प्रो. सेंटिएगो सांचेज के व्याख्यान शामिल थे। जुलाई, 2019 में एल्मैग्रो थिएटर समारोह में पहली भारत स्पेन वाटिका का मंचन किया गया। स्वतंत्र फिल्मों के फिल्म समारोह इंडिया-इंडी का द्वितीय संस्करण नवम्बर में मैड्रिड और वाला डोलिड में आयोजित किया गया।

भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क सुदृढ़ बना रहा जिसके तहत क्षेत्र और जनसांख्यिकी की भावना से ऊपर उठते हुए अनेक संपर्क कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिनमें छात्रों, वृत्तिकों, भावी पीढ़ी के उद्यमियों और खिलाड़ियों के साथ किए जाने वाले संपर्क भी शामिल हैं। संपूर्ण स्पेन में मासिक दूतावास संबंधी शिविरों का आयोजन किया गया तथा दूतावास संबंधी सेवा मुद्रण, त्वरित दस्तावेज सत्यापन और प्रक्रिया इष्टमतीकरण को जाता है।

जर्मनी

भारत और जर्मनी के बीच उच्चतम स्तर पर की जाने वाली नियमित बैठकों ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी निरंतर सुदृढ़ होती रहे। एक विशिष्ट परंपरा को जारी रखते हुए, जो दोनों देशों को जोड़ती है, 5वें अंतर्सरकारी परामर्शों की सह-अध्यक्षता 01 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा चांसलर मेर्केल द्वारा की गई जिसके उपरांत 22 करारों पर हस्ताक्षर किए गए। जलवायु परिवर्तन, शमनीकरण, डिजटलीकरण और शिक्षा कुछ प्रमुख मुद्दों में से एक थे जिन पर दोनों देशों ने गहन सहयोग किए जाने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने वर्ष के दौरान जापान में जी-20

शिखर-सम्मेलन, बियारिट्ज में जी-7 तथा न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जलवायु कार्यवाही शिखर-सम्मेलन में भी परस्पर भेंट की। दोनों देशों द्वारा नियमित आधार पर केन्द्रीय और राज्य स्तर पर अनेक द्विपक्षीय दौरों और पारस्परिक संपर्को के माध्यम से इस भागीदारी को और भी गहन बनाया गया। दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों को और विस्तारित किया गया जिससे द्विपक्षीय सहयोग का एक व्यापक आयाम प्रतिबिंबित हुआ।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की, 01 नवंबर, 2019 में

25 मई, 2019 को टेलीफोन पर हुई बातचीत में चांसलर मेर्केल ने भारत के आम चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी की विजय पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए संबंधों का भी उल्लेख किया तथा पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में सहयोग में और वृद्धि करने की अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर मेर्केल को धन्यवाद दिया तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी गहन बनाने तथा वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए उनके द्वारा निभाई गई उत्कृष्ट भूमिका का उल्लेख किया।

चांसलर मेर्केल पांचवे भारत-जर्मन अंतर्सरकारी परामर्शों की सह-अध्यक्षता करने के लिए 31 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2019 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आईं। उनके साथ जर्मनी के मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक शिष्टमंडल भी आया था जिसमें विदेश मंत्री हेको मास, कृषि मंत्री जूलिया क्लोकनेर और शिक्षा मंत्री अंजा कार्लिकजेक शामिल थे। उन्होंने भारतीय समकक्ष मंत्रियों के साथ बैठकें कीं जिनका उद्देश्य पारस्परिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना था। अपनी यात्रा के दौरान, चांसलर मेर्केल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ताएं कीं। भारत और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित करारों में कृषि, सामुद्रिक, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद, योग, व्यावसायिक रोग, विकलांग बीमित व्यक्तियों का पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भागीदारी शामिल थी। चांसलर मेर्केल ने भारत में नई हरित संचलनता परियोजनाओं में 1 बिलियन यूरो के निवेश का वायदा किया तथा भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार को क्रियान्वित करने के लिए नए प्रयास आरंभ करने का आह्वान भी किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून, 2019 को ओसाका, जापान में आयोजित जी-20 शिखर-सम्मेलन के दौरान भी चांसलर मेर्केल से भेंट की। दोनों नेताओं ने अपनी बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जैसे कृत्रिम आसूचना, ई-संचलनता, साइबर सुरक्षा, रेलवे आधुनिकीकरण और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि करना।

विदेश सचिव विजय गोखले तथा जर्मन विदेश कार्यालय में स्टेट सेकेट्री एंड्रीज माइकलिस ने 24 अप्रैल, 2019 को बर्लिन में विदेश कार्यालय चर्चाएं संचालित कीं। इस यात्रा के दौरान, सचिव गोखले ने द्विपक्षीय सहयोग के अनेक विषयों पर चर्चा करने के लिए जर्मन विदेश कार्यालय में राज्य मंत्री नील्स एनेन से भी भेंट की।

हैनोवेर मेसे के दौरान, अप्रैल, 2019 में भारतीय इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी) के सहयोग से 'भारत निवेशक कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। सचिव (भारी उद्योग विभाग) श्री ए.आर. शिहाग ने निवेशक कार्यक्रम के लिए हैनोवेर मेसे का दौरा किया।

चौथी भारत-जर्मन व्यापार वार्ता 11 सितम्बर, 2109 में भारतीय दूतावास, बर्लिन में आयोजित की गई। इस वार्ता का उद्घाटन जर्मन संसद के सदस्य श्री मार्क हॉप्टमैन तथा आर्थिक कार्य और ऊर्जा संघीय मंत्रालय में संसदीय राज्य सचिव श्री क्रिश्चन हिर्ते द्वारा किए गए स्वागत उद्बोधनों के साथ किया गया था। इसमें श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य एवं पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा श्री राल्फ ब्रिंसॉस, संसद सदस्य और जर्मन संसद में सीडीयू/सीएसयू संसदीय दल के प्रमुख द्वारा आधार व्याख्यान भी दिए गए। इस वार्ता में भारत और जर्मन के व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समारोह का आशय जर्मन और भारतीय तकनीकी जानकारी के बीच सेतु का निर्माण करना तथा जर्मनी और भारत के बीच गहन आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना था।

दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 24 बिलियन यूरो तक पहुंच गया जिसमें जर्मनी भारत का 8वां विशालतम व्यापार भागीदार बन गया। वर्ष 2018-19 में जर्मनी का कुल निवेश 886 मिलियन यूएसडी था जिसके फलस्वरूप जर्मनी भारत के लिए एक प्रमुख निवेश भागीदार बन गया है।

जर्मनी 1958 से ही भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। 1958 से कुल द्विपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहयोग 16.98 बिलियन यूरो है। ऊर्जा, संघारणीय आर्थिक विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन विकास सहयोग के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। भारत के साथ जर्मन विकास सहयोग की मुख्य विशेषता यह है कि यह स्थानीय परियोजनाओं पर कम तथा संरचनात्मक प्रभाव वाले कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान-केन्द्रित करती है। ये कार्यक्रम भारत के अपने प्रयासों तथा सुधार कार्यक्रमों पर तैयार किए गए हैं। ये आदर्श समाधान प्रदर्शित करते हैं तथा प्रतिभागिता करने वाले भागीदारों को परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से जारी रखने और उनका विस्तार करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

जर्मन-भारत व्यापार फोरम 2019 (जीआईबीएफ) का आयोजन सितम्बर, 2019 में जर्मन-भारतीय संघ (जीडीआईजैड) के सहयोग से किया गया जिसमें 'विनिर्माण उत्कृष्टता और संघारणीयता' पर ध्यान-केन्द्रित किया गया था। इस फोरम ने व्यापार, राजनीति और प्रशासन के क्षेत्रों से उच्च-स्तरीय निर्णयकर्ताओं के लिए पारस्परिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने का उपयुक्त मंच प्रदान किया।

इटली

वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री पाउलो जेंतिलोनी तथा 2018 में प्रधानमंत्री गियूसेपे की यात्राओं द्वारा सृजित की गई गतिशीलता वर्ष 2019 के दौरान भी जारी रही जिसके तहत नियमित रूप से उच्च-स्तरीय दौरों का आदान-

प्रदान किया गया तथा राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न कदम उठाए गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री कोंटे ने जून, 2019 में जापान में जी-20 बैठक तथा सितम्बर, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान परस्पर मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सितम्बर, 2019 में यूएनजीए के दौरान अपने समकक्ष विदेश मंत्री श्री लुइगी डी मेओ के साथ भेंट की।

इतालवी संसद ने 2019 में संसदीय मैत्री समूह का गठन किया जिसकी अध्यक्षता पूर्व विदेश मंत्री सीनेटर रोबर्टा पिनोटी कर रही हैं। यह समूह विभिन्न दलों के 15 सीनेटरों और डिप्टियों से मिलकर बना है।

2 अक्तूबर, 2019 को, सीनेट में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई जिसमें स्पीकर एलिसाबेटा कासेलाती, सीनेटर पिनोटी तथा अन्य सांसदों और आमंत्रितियों ने भाग लिया। रोम तथा इटली के अन्य शहरों में स्थित गांधीजी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। दूतावास ने गांधी बाइक साइकिल रैली, वृक्षारोपण, विद्यालयों और कॉलेजों में व्याख्यान फ्लोरेस में महात्मा गांधी के नाम पर पुल का समर्पण और रोम हाफ-मैराथन का आयोजन किया जिनमें दिए गए मैडलों को महात्मा गांधी के चित्र और संदेश के साथ महात्मा गांधी को समर्पित किया गया। इस वर्ष स्थानीय हाई स्कूल ने देख-रेख और अनुरक्षण के लिए रोम में पियाजा गांधी और गांधी स्मारक को अपनाया।

इटली ने महत्वपूर्ण निर्वाचनों में भारत को समर्थन प्रदान किया जिसमें यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन भी शामिल हैं। इटली ने आपदा प्रत्यास्थी अवसंरचना (सीडीआर) गठबंधन पर भारत की पहल का भी स्वागत किया है। अक्तूबर, 2019 में इटली एक वार्ता भागीदार के रूप में भारतीय महासागर रिम संघ (आईओआरए) में शामिल हुआ।

इस वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग में सत्त वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष के लिए द्विपक्षीय व्यापार के भी 10 बिलियन यूएस यूरो तक पहुंच जाने की संभावना है, जो इस संबंध में सर्वाधिक उच्च राशि है जिसमें अधिशेष भारत के पक्ष में होगा। 16 जुलाई, 2019 को दोनों देशों की सरकारों ने भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों तथा इसके विपरीत इटली में भारतीय कंपनियों और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना के करार पर हस्ताक्षर किए।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने तथा भारत में अधिक इतालवी एसएमई को आकर्षित करने के उद्देश्य से मिशन, ने डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से अक्तूबर, 2019 में एक्सेस इंडिया पहल (एआईआई) कार्यक्रम प्रारंभ किया। एआईआई के अंर्गत 30 इतालवी एसएमई की पहचान भारत में निवेश करने के लिए सहायक सेवाओं के रूप में की जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार अवसरों का अन्वेषण करने के लिए इतालवी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों ने सितम्बर, 2019 में भारत का दौरा किया तथा भारतीय कंपनियां इटली गई। सीआईआई के नेतृत्व में स्टार्ट-अप पर एक चार-सदस्यीय शिष्टमंडल ने स्टार्ट-अपों के लिए अवसरों की तलाश करने तथा उद्यमशीलता के क्षेत्र में सहयोग सृजित करने के लिए 2-6 सितम्बर, 2019 तक इटली का दौरा किया।

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग करार के ढांचे के अंतर्गत, भारत-इटली सहयोग वाला अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। वैश्विक अभिनवता और प्रौद्योगिकी गठबंधन (जीआईटीए) कार्यक्रम ने एक वित्त-पोषण तंत्र का सृजन किया है, जिसके माध्यम से भारतीय और इतालवी कंपनियां संयुक्त भारत-इटली अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं तथा नई प्रौद्योगिकियों के सृजन के लिए आशयित अन्य क्रियाकलापों के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

इस अवधि में अनेक द्विपक्षीय रक्षा क्रियाकलाप संचालित किए गए। 10 वर्ष से अधिक अंतराल के उपरांत, भारत से राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 16 सदस्यीय

शिष्टमंडल ने 25 से 31 मई, 2019 तक इटली की यात्रा की। फ्लोरेंस में 29 मई, 2019 को विश्व युद्ध-II में अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारतीय सेना के दो जवानों की अस्थियों वाले कलशों को सौंपने के लिए एक भावभीनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 10वां भारत-इटली सैन्य सहयोग ग्रुप (एमसीसी) की 5-6 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में बैठक हुई। इस अवधि के दौरान इटली से सीएनसी मशीनें, स्पेक्ट्रोमीटर, खराद मशीनें अधिप्राप्त करने के लिए डीआरडीओ और अन्य वैज्ञानिक स्थापनों की ओर से इटली के अनेक दौरे आयोजित किए गए। भारतीय सेना के मार्क्समैन दल ने इतालवी ओपन शॉटगन शूटिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने फिंशैटिएटी के लिए अपने शिष्टमंडलों के दौरों, इटालियन सेलिंग रेगाटा में सेलिंग दल की प्रतिभागिता के माध्यम से तथा इतालवी हाइड्रोग्राफिक संस्थान एवं अन्य संस्थानों के अन्य शिष्टमंडलीय दौरों के माध्यम से सहयोग को निरंतर बनाए रखा।

आतंकवाद-रोधी सहयोग पर जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक 13 जून, 2019 को भारत में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने वर्तमान आतंकवाद-विरोधी चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जिसमें कट्टरवाद, आतंकवादियों के वित्त-पोषण और आतंकवादी प्रयोजनों के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग को समाप्त करना भी शामिल था। उन्होंने पराराष्ट्रीय अपराधों तथा धन-शोधन से उत्पन्न होने वाले संकटो पर भी विचार-विमर्श किया। जेडब्ल्यूजी की आगामी बैठक दोनों पक्षों को सहमत तारीखों को इटली में आयोजित की जाएगी।

भारत ने एफएओ परिषद् के सदस्य के रूप में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) में प्रतिभागिता को जारी रखा है। भारत को एक अन्य कार्यकाल अर्थात् 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 के लिए एफएओ परिषद् के लिए निर्वाचित किया गया है। इसने विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में कार्य करना भी जारी रखा है जैसे मात्स्यिकी समिति, वानिकी समिति, एफएओ परिषद्, खाद्य सुरक्षा समिति, पण्य समस्या समिति और कृषि समिति।

वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव का 22-23 जून, 2019 को रोम में आयोजित एफएओ के 41वें सम्मेलन में अनुमोदित किया गया। भारत को वर्ष 2020 में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय विषय-निर्वाचन समिति के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) और आईएफएडी की मूल्यांकन समिति का सक्रिय सदस्य भी बना हुआ है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संबंधी पादप आनुवांशिकी संसाधन संधि (आईटीपीजीआरएफए) के शासी निकाय की 8वीं बैठक में भाग लेने के लिए 11 नवम्बर, 2019 को रोम का दौरा किया। उन्होंने अपनी इतालवी समकक्ष कृषि मंत्री सुश्री टेरेमा बोलानोवा एवं महानिदेशक, एफएओ से भी भेंट की। मंत्री द्वारा वर्ष 2021 में नई दिल्ली में आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय की बैठक आयोजित किए जाने की घोषणा की गई।

इस वर्ष दूतावास ने संस्कृति, प्रदर्शन कलाओं और योग के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। सांस्कृतिक पहलू में, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष समूचे इटली में मनाया जा रहा है जिसके तहत इटली की गुरुद्वारा प्रबंधक समितियों के सहयोग से तथा सिख प्रवासियों की जोशपूर्ण प्रतिभागिता से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाई सुखविंदर सिंह जी के आईसीसीआर प्रायोजित हजूरी रागी ग्रुप द्वारा इंडिया हाउस में एक विशेष शब्द कीर्तन का 27 अक्तूबर, 2019 को आयोजन किया गया। इस ग्रुप द्वारा 25-27 अक्तूबर तक रोम में और उसके आस-पास के गुरुद्वारों में भी कीर्तनों का आयोजन किया।

2019 में, पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया जिसमें दो सप्ताह की अवधि में दस कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष इतालवी सीनेट में इतालवी हिंदू संघ के सहयोग से दीपावली का

त्योहार भी अधिकारिक रूप से मनाया गया। यह त्योहार तथा इसके साथ कुछ अन्य कार्यक्रम जैसे एफआईएनडी फाउंडेशन के साथ ग्रीष्मकाल मेला फ्लोरेस और रोम में फिल्म समारोह अब वार्षिक कार्यक्रम बन गए हैं जहां दूतावास सक्रिय सहयोग प्रदान करता है।

वर्ष 2019 में, भारत ने 8 वर्ष के अंतराल के बाद बेनिस द्विवार्षिकी समारोह में भाग लिया जो समूचे विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित कला मेला है। संस्कृति मंत्रालय ने एनजीएमए और सीआईआई के सहयोग से 8 उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित भारतीय कलाकारों के कला कार्य का प्रदर्शन किया। 8 मई, 2019 को उद्घाटन किए गए भारतीय पेवेलियन का विषय '150वीं जयंती पर महात्मा गांधी और शांति के उनके संदेश का उत्सव मनाना' था।

इटली के मध्य और दक्षिणी भागों में निवास कर रहे भारतीय समुदाय के समुदायों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से इटली के विभिन्न प्रांतों जैसे ऐरेजो कटानिया, कग्लियरी, रेगियो कालाब्रिया, लतीना और बारी में समूचे वर्ष के दौरान दूतावास संबंधी शिविरों की श्रृंखला आयोजित की गई जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों तथा ओसीआई धारकों ने दूतावास संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भाग लिया। यह भारतीय समुदाय तक पहुंच बनाने का एक प्रभावी तरीका था तथा उनके द्वारा द्वारा इसकी पर्याप्त प्रशंसा की गइ। मिशन वीजा नियमों में हाल में हुए परिवर्तनों, जिन्हें अधिक सरल बनाया गया है, को ध्यान में रखते हुए अत्यंत तकाल तरीके से सभी श्रेणियों के वीजा जारी कर रहा है।

सैन मैरीनो

सैन मैरीनो के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं। दोनों देशों ने न केवल लाभप्रद सहयोग स्थापित किया है विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के अंतर्गत बल्कि साझे हित के मुद्दों पर भी द्विपक्षीय स्तर पर सैन मैरीनो ने यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है तथा आपदा प्रत्यास्थी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) संबंधी भारत की पहल को भी समर्थन प्रदान किया है।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 0.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसमें वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 53.38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। तथापि, सैन मैरीनो के लिए भारत के निर्यात में 9.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 0.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जबकि सैन मैरीनो से आयात में 66.82 प्रतिशत की कमी आई तथा यह 0.21 मिलियन डॉलर था।

(मूल्य यूएस मिलियन डॉलर में)

क्रम सं.		2016-17	2017-18	2018-19
1	निर्यात	0.23	0.14	0.15
2	आयात	0.39	0.64	0.21
3	कुल व्यापार	0.61	0.78	0.36

रोम में भारतीय दूतावास सैन मैरीनो की सरकार के सहयोग से सैन मैरीनो गणराज्य में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 15 जून, 2019 को बड़े पैमाने पर सैन मैरीनो में मनाया। सैन मैरीनो के संस्कृति मंत्री श्री मैक्रो पोडेश्ची ने अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया जिसके उपरांत कथक नृत्य प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक खाद्य समारोह का आयोजन भी किया गया।

बुल्गारिया

बुल्गारिया द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों मंचों पर एक मजबूत भागीदार बना रहा, जिसमें डब्ल्यूएचओ, आईसीएओ, आईएमओ, आदि के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन शामिल था। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध के प्रक्षेपवक्र ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। बुल्गेरियाई उप-प्रधानमंत्री मरियाना निकोलोवा ने 20 और 21 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित भारत यूरोप 29 बिजनेस फोरम में उच्च-स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें बुल्गेरियाई चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष, भारत बुल्गारिया बिजनेस चैंबर के अध्यक्ष, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और व्यापारी शामिल थे। बाल्कन इंडियन बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 26-28 नवंबर 2019 को बेंगलुरु में आयोजित सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी के पाँचवें संस्करण के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कई रक्षा प्रतिनिधियों ने हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के संबंध में बुल्गारिया का दौरा किया।

तकालीन विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने 16 और 17 फरवरी 2019 को बुल्गारिया की आधिकारिक यात्रा की थी।

विदेश मंत्री ने सोफिया में बुल्गारिया के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री एकातेरिना ज़हरीवा से मुलाकात की
(16 फरवरी, 2019)

उत्तरी मैसेडोनिया

उत्तरी मैसेडोनिया भारत का एक दीर्घकालिक मित्र और विश्वसनीय भागीदार बना हुआ है। इसने आईसीएओ और डब्ल्यूसीओ के लिए भारत की उम्मीदवारी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच व्यापार और निवेश संबंध बढ़ रहा है। अप्रैल से सितंबर 2019 तक द्विपक्षीय व्यापार 25.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस अवधि में भारत का निर्यात 11.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 14.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, इस अवधि में निर्यात

में 23.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। महामहिम सुश्री रेनाता डेस्कोस्का ने 6 से 12 नवंबर 2019 तक भारत का दौरा किया।

क्रोएशिया

क्रोएशिया में 02 अक्तूबर 2019 को ज़गरेब में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा की स्थापना, वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। क्रोएशिया की प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेंकोविक (क्रोएशिया की प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिमा का पहली बार अनावरण) और ज़गरेब के मेयर मिलान बैंडिक ने प्रतिमा का अनावरण किया। क्रोएशिया के इगोर स्टिमैक को 15 मई 2019 को भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया जाना भारत-क्रोएशिया के खेल सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्रोएशिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् और एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है।

भारत के आम चुनाव के मतपत्रों की गिनती के अवसर पर 23 मई 2019 को एक लाइव-स्ट्रीमिंग का आयोजन किया गया था। संसद के सदस्य, विदेश मंत्रालय के अधिकारी, राजनयिक कोर के सदस्य और मीडिया के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे वर्ष गांधी@150 का उत्सव मनाया गया था।

साइप्रस

साइप्रस भारत के जटिल और महत्वपूर्ण हित के मुद्दों पर भारत का कट्टर समर्थक रहा है। हाल के वर्षों में दोनों राष्ट्रपतियों के दौरे के बाद भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। जून 2019 तक भारत-साइप्रस व्यापार शेष 32 मिलियन यूरो था। अप्रैल 2000 से जून 2019 के दौरान 9.927 अरब अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ साइप्रस भारत में आठवां शीर्ष निवेशक है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के अवसर पर राष्ट्रपति निकोस अनास्तासीद से भेंट की।

प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन के 74 वें सत्र के अवसर पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासीदेस से भेंट की (26 सितंबर, 2019)

साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र भारत की सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता और विश्व सीमा शुल्क संगठन में भारत की उम्मीदवारी तथा आईसीएओ की परिषद् और आईएमओ की परिषद् के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। साइप्रस स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑर्गनाइजेशन (सीएसईओ) ने नई दिल्ली में 2022 में 73वें आईएसी के आयोजन के लिए इसरो के प्रस्ताव का समर्थन किया। गांधीजी की 150 वीं जयंती के अवसर पर, साइप्रस सरकार ने 10 सितंबर 2019 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

चेक गणराज्य

भारत और चेक रिपब्लिक के मध्य वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान जारी रहा - 2019 में जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए चेक प्रधानमंत्री, माननीय एंड्रेज बाबिस की भारत यात्रा और

फरवरी 2019 में चेक रक्षा मंत्री, श्री लुबोमिर मेट्नार और 20 व्यापारिक मिशनों की भारत यात्रा शामिल है। इन आदान-प्रदानों से संबंधों के उन्नयन के बाद, भारत को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चेक गणराज्य का पूर्ण समर्थन मिला। सितंबर 2019 में यूएनजीए के अवसर पर विदेश मंत्री और चेक विदेश मंत्री के बीच भेंट से रिश्ते के रणनीतिक पहलुओं को मजबूत करने में मदद मिली। चेक गणराज्य ने 2021-22 के लिए यूएनएससी की गैर-स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया, संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए समर्थन किया और यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। इस वर्ष, द्विपक्षीय आर्थिक संबंध पिछले वर्ष की तुलना में अधिक स्थिर रहे। लोगों से लोगों के संपर्क से पर्यटक प्रवाह में वृद्धि हुई और देश में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई।

अहमदाबाद में जीवंत गुजरात सम्मेलन 2019 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री, एंड्रेज बाबिस से भेंट की (18 जनवरी, 2019)

द्विपक्षीय संवाद तंत्र के अंतर्गत, भारी इंजीनियरिंग पर संयुक्त कार्यकारी समूह की छठी बैठक 8 अक्तूबर 2019 को चेक गणराज्य के ब्रनो में आयोजित की गई थी। हमारे आर्थिक संबंधों के नियमित आदान-प्रदान ने विचारों, आदान-प्रदान और भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों की खोज का अवसर दिया।

चेक गणराज्य के विदेश मंत्री टॉमा पेट्राइसक ने रायसीना वार्ता 2020 में भाग लेने के लिए एक आधिकारिक और व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ 13-15 जनवरी, 2020 तक भारत का दौरा किया; बातचीत से इतर उन्होंने विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने इस यात्रा के दौरान माननीय रक्षा मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री/रेल और नागरिक उड्डयन मंत्री से भी मुलाकात की।

रक्षा क्षेत्र में फरवरी, 2020 में लखनऊ में डेफएक्सपो के लिए चेक उप मंत्री की यात्रा से दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ बातचीत हो सकेगी और हमारे रक्षा संबंधों में वृद्धि को बनाए रखा जा सकेगा।

डेनमार्क

वर्ष के दौरान, भारत-डेनमार्क संबंधों में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र में सहयोग सहित संभावित सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गणमान्य व्यक्तियों की कई यात्राएं हुई थीं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 के लिए चार राष्ट्र प्रमुखों/ सरकार के प्रमुखो में से एक के रूप में भारत का दौरा किया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से भी भेंट की।

वाणिज्यिक संबंधों में यात्राओं का महत्वपूर्ण आदान-प्रदान हुआ। सुश्री सलोनी झावेरी, प्रमुख, निवेशक संबंध और भागीदारी, राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) ने डेनमार्क का दौरा किया; 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सतत शहरी विकास में 'नॉर्डिक मास्टर क्लास' के भाग के रूप में 15-21 जून 2019 के दौरान डेनमार्क का दौरा किया।

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) आयोजित किए गए: खाद्य प्रसंस्करण पर दूसरा संयुक्त कार्य समूह कोपेनहेगन में 19-21 जून 2019 से आयोजित किया गया था जहां संयुक्त पहल, सेमिनार आदि के लिए 2020-2023 के लिए एक सामान्य संयुक्त कार्य समूह की योजना को अंतिम रूप देने पर सहमति हुई थी और श्रम गतिशीलता पर तीसरा संयुक्त कार्य समूह नई दिल्ली में 4-5 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और डेनमार्क के बीच श्रम गतिशीलता के क्षेत्र में आगे सहयोग पर चर्चा की गई थी। डेनमार्क यूएनएससी और एनएसजी में एक स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का भी समर्थन करता है।

डेनमार्क के विदेश मंत्री जेप्पे कोफोड ने रायसेना वार्ता में भाग लेने के लिए 14-16 जनवरी 2020 के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने बातचीत से इतर विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने जलशक्ति मंत्री से भी मुलाकात की।

वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल/घटनाक्रम

डेनिश एक्सपोर्ट एसोसिएशन और डीआई फूड का एक प्रतिनिधिमंडल 8-9 जनवरी 2020 के दौरान ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नोएडा में इंडस फूड 2020 में भाग ले रहा है।

संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)

पशुपालन पर दूसरा जेडब्ल्यूजी 17 जनवरी 2020 को कोपेनहेगन में सचिव (पशुपालन एवं डेयरी) के नेतृत्व में 14-17 जनवरी 2020 तक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान आयोजित किया जाएगा।

फिनलैंड

वर्ष के दौरान, भारत-फिनलैंड राजनयिक संबंधों के 70 वर्षों को चिह्नित करने के लिए 19-20 सितंबर 2019 को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की हेलसिंकी की यात्रा से द्विपक्षीय उच्च-स्तरीय वार्ता को बढ़ावा मिला। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति श्री सौली निनिस्तो, प्रधानमंत्री, श्री एंट्टी रिने और विदेश मंत्री श्री पक्के हाविस्तो से भेंट की। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और फिनलैंड के विदेश मंत्री श्री पक्के हाविस्तो ने भारतीय सांस्कृतिक परिषद्, भारत सरकार द्वारा फिनलैंड सरकार को उपहार में दी गई महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण किया। फ़िनलैंड यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन करता है।

उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखने के लिए, फ़िनलैंड के विदेश मंत्री, श्री पक्के हाविस्तो 4 से 6 नवंबर, 2019 तक भारत के दौरे पर आये थे, उन्होंने विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री के साथ विचार विनिमय किया। उन्होंने चैन्नई में फिनलैंड की कंपनी, कोने लिफ्ट की अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का उद्घाटन भी किया।

वितीय वर्ष 2019-20 में पर्यटन में सहयोग के लिए हमारे पर्यटन मंत्रालय और फिनलैंड के आर्थिक मामलों और रोजगार मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; फिनलैंड के आर्थिक मामलों और रोजगार मंत्रालय और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटलीकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और राष्ट्रीय कौशल विकास सहयोग, भारत और ईडीयूएफआई, फिनलैंड के बीच व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 25 भारतीय स्टार्ट-अप ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समर्थन के साथ हेलसिंकी, एसएलयूएसएच में स्टार्ट-अप के वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया।

स्थायी रक्षा मंत्री श्री जक्कू जुस्ती रायसीना वार्ता 2020 में अध्यक्ष के रूप में भाग ले रहे होंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा संबंधी उपकरणों और औद्योगिक सहयोग के उत्पादन, खरीद, अनुसंधान और विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

प्रत्याशित: फिनलैंड की संसद में वित्त समिति के 10 सांसद समिति के अध्यक्ष श्री जोहानेस कोकिनेन के नेतृत्व में 23-29 फरवरी से परिचय के लिए भारत का दौरा करेंगे।

एस्टोनिया

वर्ष के दौरान, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने 20-21 अगस्त को एस्टोनिया का दौरा किया, इस दौरे में उनके साथ तीन संसद सदस्य, मीडिया और 18 कंपनियों का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी गया था। उपराष्ट्रपति और एस्टोनिया के प्रधानमंत्री, श्री जूरी रटस ने संयुक्त रूप से इंडिया एस्टोनिया बिजनेस मंच को संबोधित किया, जिसमें सीआईआई के नेतृत्व में भारत के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और एस्टोनियाई व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। यात्रा के दौरान - राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की छूट; साइबर सुरक्षा में सहयोग; और ई-गवर्नेंस और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एस्टोनिया यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है।

एस्टोनिया के विदेश मंत्री महामहिम श्री उर्मास रेनसालू भारत का दौरा कर रायसीना वार्ता 2020 में एक प्रमुख नोट वक्ता के रूप में हिस्सा लेंगे। उन्होंने विदेश मंत्री से बातचीत की और अन्य आधिकारिक व्यस्तताएं कीं।

ग्रीस

वर्ष के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के उच्च स्तरीय सेगमेंट के अवसर पर, नवनिर्वाचित ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस से भेंट की। श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (सी एवं आई) 7 सितंबर 2019 को ग्रीस के थेसालोनिकी गये थे, उन्होंने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेले (टीआईएफ 2019) का उद्‌घाटन किया। थैसालोनिकी में 7-15 सितंबर, 2019 के बीच आयोजित 84वें थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेले 2019 (टीआईएफ 2019) में भारत 'सम्मानित देश' था, यह ग्रीस का सबसे बड़ा वार्षिक वाणिज्यिक प्रदर्शन और दक्षिण-पूर्वी यूरोप और बाल्कन का सबसे बड़ा मेला है। ग्रीस यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के भारतीय दावे का समर्थन करता है।

हंगरी

वर्ष के दौरान हंगरी के साथ भारत के संबंध मजबूत होते रहे। राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई तथा विदेश मंत्री और जल मंत्री की हंगरी की यात्राओं ने द्‌विपक्षीय जुड़ाव को गहरा करने के लिए आधार बनाया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने 25-27 अगस्त 2019 को हंगरी का दौरा किया और द्‌विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्‌दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर हंगरी के विदेश मंत्री श्री पीटर सिज्जार्तो के साथ चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने 2019-22 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। हंगरी के पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की। हंगरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता, और एनएसजी की सदस्यता के लिए भारतीय के दावे का समर्थन करता है।

वर्ष के दौरान हुई अन्य यात्राओं में 14-17 अक्तूबर, 2019 को जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की

बुडापेस्ट यात्रा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 9-12 दिसंबर, 2019 को बुडापेस्ट में आयोजित पाँचवें एएसईएम परिवहन मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए बुडापेस्ट जाने की आशा है; ट्राई के अध्यक्ष और टीडीएसएटी के अध्यक्ष ने बुडापेस्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सम्मेलन 2019 में भाग लिया। हंगरी से, विदेशी आर्थिक संबंधों के उप-राज्य सचिव, श्री इस्तवान जू ने 20-22 नवंबर, 2019 को आईई29बीएफ में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया और बैठकों के अवसर पर राज्य मंत्री (वीएम) के साथ भेंट की। हंगरी ने अपनी संसद में 2018-22 की अवधि के लिए भारत हंगरी मैत्री समूह का पुनर्गठन किया।

वर्ष 2019 के पहले सात महीनों में, द्विपक्षीय व्यापार में साल-दर-साल लगभग 10% की वृद्धि हुई, निर्यात में 12% और आयात में 3% की वृद्धि हुई। दो मंत्रिस्तरीय दौरों में, शैक्षिक, पर्यटन और वैज्ञानिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के अलावा, सहयोग को मजबूत करने के लिए फिल्म निर्माण, डिजिटलीकरण, जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्रों की पहचान की गई। 22 मई 2019 को, मोटर वाहन क्षेत्र की एक भारतीय कंपनी संवर्धना मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग (एमएटीई) ने तुर्केव के अपने बेस में 15.3 मिलियन यूरो के विस्तार की घोषणा की।

हंगरी के विदेश मामलों और व्यापार मंत्री श्री पीटर सिज्जार्तो ने रायसीना वार्ता के 5वें सत्र में भाग लेने के लिए 15-17 जनवरी, 2020 तक भारत का दौरा किया था। उन्होंने बातचीत से इतर विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने सीआईएम और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री से भी मुलाकात की।

बोस्निया और हर्जेगोविना

बोस्निया और हर्ज़ेगोविना (बीआईएच) के साथ भारत के संबंध इस वर्ष में तेजी से आगे बढ़े। राजदूत कुमार तुहिन ने 18 सितंबर 2019 को बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के प्रेसीडेंसी के अध्यक्ष महामहिम श्री ज़ेल्को कोम्सिक के समक्ष अपनी पहचान प्रस्तुत की। उन्होंने 20 सितंबर 2019 को त्रिपक्षीय प्रेसिडेंसी के सर्बियाई सदस्य मिलेरोड डोडिक से भी भेंट की।

आइसलैंड

इस वर्ष भारत और आइसलैंड के बीच के संबंधों में काफी वृद्धि आई। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बढ़े। दोनों राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग करते रहे।

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव (मत्स्य), सुश्री रजनी सेखरी सिब्बल ने दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 20-22 अगस्त 2019 तक आइसलैंड का दौरा किया। यात्रा के दौरान, सचिव (मत्स्य) ने आइसलैंड के मत्स्य और नवाचार मंत्रालय के स्थायी सचिव से भेंट की और व्यापक विचार-विमर्श किया। सचिव ने आइसलैंड महासागर क्लस्टर हाउस का भी दौरा किया।

माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 9-11 सितंबर 2019 तक आइसलैंड का राजकीय दौरा किया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला। इस दौरे में उनके साथ महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती देबश्री चौधरी, संसद सदस्य डॉ. रमापति राम त्रिपाठी और श्री बसंत कुमार पांडा, एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और 35-सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी थे।

राष्ट्रपति की रिक्जेविक, आइसलैंड की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति निवास पर औपचारिक स्वागत (10 सितंबर, 2019)

राष्ट्रपति जी ने आइसलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का आयोजन किया, आइसलैंड के राष्ट्रपति ने राजकीय रात्रिभोज का आयोजन किया। दोनों राष्ट्रपतियों की उपस्थिति में तीन समझौतों/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर समझौता;

(ii) वर्ष 2019-2022 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी);

(iii) सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

राष्ट्रपति ने आइसलैंड विश्वविद्यालय में "इंडिया-आइसलैंड फॉर ए ग्रीन प्लैनेट" विषय पर एक सार्वजनिक भाषण दिया और भारत-आइसलैंड बिजनेस फोरम को संबोधित किया, जिसमें आइसलैंड के 75 से अधिक प्रमुख सीईओ ने भाग लिया।

माल्टा

वर्ष के दौरान माल्टा के साथ संबंध आगे बढ़ते रहे। माल्टा के पर्यावरण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. जोस हरेरा, 2 से 13 सितंबर 2019 तक भारत द्वारा आयोजित यूएनसीसीडी सीओपी14 बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे। माल्टा के प्रधानमंत्री, जोसेफ मस्कट ने जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 के चार राष्ट्र प्रमुखों/सरकार के प्रमुखों में से एक के रूप में भारत का दौरा किया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की।

नॉर्वे

इस वर्ष नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री एर्ना सोलबर्ग 7 और 8 जनवरी 2019 को भारत की एक राजकीय यात्रा पर आईं थीं और आपसी हित के मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने रायसीना संवाद में उद्घाटन भाषण दिया। यात्रा के दौरान भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता पर एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। नार्वे के विदेश मंत्रालय की राज्य सचिव (उप मंत्री) सुश्री मैरिएन हेगन ने 8 -12 फरवरी 2019 को भारत का दौरा किया और भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता के अंतर्गत नार्वे के विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। वे टीईआरआई द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुईं। नॉर्वे यूएनएससी और एनएसजी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन प्रदान करता है।

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग की सचिव, श्रीमती रजनी सेखरी सिब्बल ने समुद्री संसाधनों और एक्वा नोर 2019 के लिए 22-25 अगस्त 2019 को नॉर्वे के ट्रॉनहैम में आयोजित संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक में भाग लिया। नौवहन मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 18-21 नवंबर 2019 को मैरिटाइम पर सातवें संयुक्त कार्य समूह में भाग लेने के लिए ओस्लो का दौरा किया।

नॉर्वे की प्रधान मंत्री एर्ना सोलबर्ग ने नई दिल्ली में चौथे रायसीना डायलॉग में अपना उद्घाटन भाषण दिया। (08 जनवरी, 2019)

प्रत्याशित घटनाएं: (i) व्यापार और निवेश पर बातचीत की पहली बैठक (डीटीआई) नई दिल्ली में 15-16 जनवरी, 2020 को होनी है और (ii) अनुसंधान और उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री इसेलिन न्यभो 2-6 फरवरी, 2020 से भारत (दिल्ली और चेन्नई) का दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नार्वे के उच्च शिक्षा मंत्रालय के बीच उच्च शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की आशा है। संविधान दिवस के अवसर पर जनवरी, फरवरी और मार्च, 2020 में संविधान दिवस और नागरिकों के कर्तव्यों के अभियान पर वार्ता/व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे।

पोलैंड

भारत और पोलैंड के बीच मजबूत राजनीतिक साझेदारी, जीवंत आर्थिक जुड़ाव और पारंपरिक सांस्कृतिक संबंधों द्वारा चिह्नित एक दीर्घकालिक मित्रता का संबंध है। हमारे संबंधों, विशेष रूप से आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में यह सकारात्मक प्रवृत्ति, भारतीय आंकड़ों के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को दर्शाती है, जो 2015-16 के 1.59 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 2.37 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। पोलैंड में 3 अरब अमेरिकी डॉलर के भारतीय निवेश का अनुमान है जो पोलैंड के 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और भारत में अनुमानतः 673.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पोलिश निवेश हुआ है, जो पहले से काफी बढ़ गया है। पोलैंड यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के भारतीय दावे का समर्थन करता है।

विदेश मंत्री (ईएएम) डॉ. एस. जयशंकर ने 28-29 अगस्त 2019 को पोलैंड का दौरा किया। विदेश मंत्री ने पोलैंड के विदेश मंत्री जेसेक जापुतोविज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का आयोजन किया। विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के समय प्रधानमंत्री माटुस्ज़ मोरवीकी और उप-प्रधानमंत्री तथा संस्कृति और राष्ट्रीय एकता मंत्री पॉट्र ग्लिंस्की से भेंट की।

वर्ष के दौरान हुए अन्य दौरो में निम्नलिखित शामिल थे - क) कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने थोक फल, सब्जी और फूलों के बाजारों का अध्ययन करने के लिए 20-22 मई को पोलैंड का दौरा किया; ख) प्रमुख निदेशक, श्री नवीन सेठ के नेतृत्व में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल वारसॉ उपहार और डेको शो में भाग लेने के लिए 24-26 मई 2019 को वारसॉ गया; ग) भारत और नेपाल की 60 कंपनियों ने 5-15 अप्रैल 2019 को लॉड्ज़ में आयोजित मेड इन एशिया प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण में भाग लिया था।

भारतीय विश्व मामलों की परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) और पोलिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (पीआईएसएम) के बीच नई दिल्ली में 14 जनवरी, 2020 को छठा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

निम्नलिखित वाणिज्यिक घटनाओं का जनवरी-मार्च 2020 की अवधि के दौरान आयोजित किया जाना निर्धारित हैं :

जल संसाधन, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से पोलिश कंपनियों को डब्ल्यूएपीसीओएस (वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड शुरू करने के लिए फरवरी 2020 में वारसॉ में कार्यशाला।

19-20 फरवरी, 2020 के दौरान पोजनान फैशन मेले में सीएलई (काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स) के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा भागीदारी।

विदेश मंत्री ने पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस्स मोराविकी, से वारसॉ में मुलाकात की (29 अगस्त, 2019)

लिथुआनिया

भारत और लिथुआनिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों करीबी एवं सौहार्दपूर्ण हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा 17-19 अगस्त 2019 को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ लिथुआनिया के दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत की ओर से यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी), कृषि कार्य योजना और प्रत्यर्पण संधि को लागू करने के लिए प्रोटोकॉल के आदान-प्रदान के तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता, और एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन करता है।

हाल के वर्षों में भारत और लिथुआनिया के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध बढ़े हैं और 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार 339.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारतीय निवेश के (इंडोरामा समूह) 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। सितंबर 2018 में एक समर्पित भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी।

वाणिज्यिक पक्ष में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दौरे शामिल थे - श्री मोहसिन खान, उप निदेशक, सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) के नेतृत्व मे 17-19 अगस्त 2019 को व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल; फिक्की ने वूल एंड वोलेनेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (डब्ल्यू एवं डब्ल्यू ईपीसी) के साथ संयुक्त रूप से 17-19 अक्तूबर 2019 को लिथुआनियाई प्रदर्शनी और कांग्रेस केंद्र लिटएक्सपो, विनियस में बाल्टिक फैशन एंड टेक्सटाइल में "इंडिया पैवेलियन" का आयोजन किया। फिक्की ने पहली बार बाल्टिक्स के सबसे बड़े फैशन और टेक्सटाइल व्यापार मेले, 28वें बाल्टिक फैशन एंड टेक्सटाइल ट्रेड फेयर में भाग लिया और "इंडिया पैवेलियन" का आयोजन किया।

अल्बानिया

द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और आपसी विश्वास और समझदारी पर आधारित संबंध बने रहेंगे। भारत और अल्बानिया बहुपक्षीय मंचों में एक मुद्दा आधारित दृष्टिकोण पर सहयोग करते हैं। अल्बानिया यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे समर्थन करता है।

मॉल्डोवा

द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण और आपसी विश्वास और समझदारी पर आधारित हैं। भारत और मोल्दोवा बहुपक्षीय मंचों में एक मुद्दा आधारित दृष्टिकोण पर सहयोग करते हैं। मोल्दोवा के डाक विभाग ने अक्तूबर 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और डाक कार्ड जारी किए।

रोमानिया

द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण और आपसी विश्वास और समझदारी पर आधारित हैं। भारत और रोमानिया बहुपक्षीय मंचों में एक मुद्दा आधारित दृष्टिकोण पर सहयोग करते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल

जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों द्वारा रोमानिया में कार्यालय खोलने से रोमानिया में भारत की उपस्थिति बढ़ी है। रोमानिया में निर्माण क्षेत्र में मदद के लिए भारत से मानव संसाधन के आयात में लगातार वृद्धि हुई है। रोमानिया यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन करता है।

सर्बिया

इस वर्ष उच्च स्तरीय यात्राओं की श्रृंखला ने भारत और सर्बिया के द्विपक्षीय संबंधों को और गति दी। विदेश मंत्री (ईएएम), डॉ. एस. जयशंकर ने 7-9 सितंबर 2019 को सर्बिया की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान, उन्होंने सर्बिया के राष्ट्रपति श्री अलेक्जेंडर वूसिक, सर्बिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष सुश्री मेजा गोजकोविक, प्रथम उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री इविका डैसिक और सर्बिया के रक्षा मंत्री श्री अलेक्जेंडर इंसुलिन से भेंट की और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सर्बिया यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन करता है।

विदेश मंत्री ने बेलग्रेड में सर्बिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर मेजा गोजकोविक से मुलाकात की (07 नवंबर, 2019)

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग, भारत और सर्बिया के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान, और आईटी, कृषि, पर्यटन, फिल्म निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा उद्योग जैसे आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में संबंधों के आगे विकास की सहयोग के क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई। यात्रा के दौरान भारत और सर्बिया के बीच रक्षा सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

अन्य आदान-प्रदान में निम्नलिखित शामिल हैं, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने 12-18 अक्तूबर 2019 को बेलग्रेड में आयोजित अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 141वीं एसेंबली में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया; सर्बिया के कृषि, वानिकी और जल प्रबंधन मंत्रालय के राज्य सचिव श्री बोगदान इगिक ने 24-28 सितंबर 2019 को भारत में अपने मंत्रालय और निजी व्यवसायों के

अधिकारियों के 12-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारतीय दवा कंपनियों के फार्मास्यूटिकल निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधिमंडल के लिए मार्च 2020 के पहले सप्ताह में बेलग्रेड में क्रेता विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन किए जाने की संभावना है।

स्लोवाकिया

भारत - स्लोवाकिया में मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और ये किसी भी प्रमुख द्विपक्षीय विवाद से मुक्त हैं। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा सहयोग करते हैं और एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। जनवरी से अगस्त, 2019 की अवधि में स्लोवाकिया में भारत का कुल निर्यात 191.3 मिलियन यूरो और कुल आयात 61.4 मिलियन यूरो का था। स्लोवाकिया कारों का सबसे बड़ा उत्पादक है; यह उच्च गुणवत्ता की श्रम शक्ति के साथ इस क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

भारत और स्लोवाकिया के बीच संयुक्त आर्थिक समिति (जेईसी) का 10वां सत्र 13 फरवरी 2019 को, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था; इसके बाद 14 फरवरी 2019 को स्लोवाक गणराज्य के आर्थिक मंत्रालय के राज्य सचिव और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई।

ब्रातिस्लावा में इंचेबा एक्सपो सेंटर में 23-26 जनवरी, 2020 के दौरान आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन ' आईटीएफ स्लोवाकियाटूर ' के अंतर्राष्ट्रीय मेले में वाणिज्यिक प्रतिनिधि और विपणन कार्यकारी भाग लेंगे।

वाणिज्यिक खंड क्षेत्रीय वाणिज्य और उद्योग, कोसिस और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रातिस्लावा के सहयोग से फरवरी 2020 के महीने में कोसिस में एक व्यापार मंच/संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

स्लोवेनिया

माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा 15-17 सितंबर 2019 को राष्ट्र के प्रमुख के स्तर पर पहली बार की गई स्लोवेनिया की राजकीय यात्रा से भारत और स्लोवेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति मिली। उन्होंने स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बोरुत पाहोर के निमंत्रण पर महिला एवं बाल विकास के राज्यमंत्री और लोक सभा के दो सदस्यों सहित एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ स्लोवेनिया का दौरा किया। यात्रा के दौरान उनके साथ एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी गया था। राष्ट्रपति जी को स्लोवेनियाई राष्ट्रपति द्वारा राजकीय सम्मान दिया गया। उनके कार्यक्रमों में स्लोवेनियाई राष्ट्रपति के साथ बातचीत सहित, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री से भेंट शामिल थे। स्लोवेनिया यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन करता है।

राष्ट्रपति ने लोसुबजाना के राष्ट्रपति भवन में, स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बोरुत पाहोर से भेंट की (16 सितंबर, 2019)

अपनी इस यात्रा के दौरान, उन्होंने भारतीय समुदाय और स्लोवेनिया-इंडिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे :

- भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्लोवेनिया के शिक्षा, विज्ञान और खेल मंत्रालय

के बीच 2020-2022 की अवधि के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का कार्यक्रम।

- भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय और स्लोवेनिया के शिक्षा, विज्ञान और खेल मंत्रालय के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- संस्कृति, कला, शिक्षा, खेल और मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम।
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआएस) और मानकीकरण के स्लोवेनियाई संस्थान (एसआईएसटी) के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर सहयोग कार्यक्रम।
- इन्वेस्ट इंडिया और स्पिरिट स्लोवेनिया के बीच समझौता ज्ञापन।
- आईआईटी कानपुर (स्वच्छ गंगा/भारत के लिए) और वीजीबी (स्लोवेनिया) के बीच समझौता ज्ञापन।
- आईआईटी कानपुर (स्वच्छ गंगा/भारत के लिए) और स्पेस-एसआई (स्लोवेनिया) के बीच समझौता ज्ञापन।
- स्लोवेनिया के वाणिज्य और उद्योग मंडल (सीसीआईएस) और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएसएसओएएम) के बीच सहयोग समझौता।

बहुपक्षीय मंचों में दोनों देशों के बीच सहयोग और समर्थन जारी था। वर्ष के दौरान कुल द्विपक्षीय व्यापार 270.01 मिलियन यूरो से 33.79% बढ़ कर 361.25 मिलियन यूरो तक पहुँच गया। स्लोवेनिया को भारतीय निर्यात 36.57% बढ़ कर 183.52 मिलियन यूरो से 250.61 मिलियन यूरो हो गया और स्लोवेनिया से भारतीय आयात 29.15% बढ़कर 86.49 मिलियन यूरो से 110.64 मिलियन यूरो का हो गया। यह 2014-2018 की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच उच्चतम वस्तु व्यापार है।

स्वीडन

इस वर्ष राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के निमंत्रण पर स्वीडन के महामहिम राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और स्वीडन की रानी सिल्विया ने 1-6 दिसंबर 2019 तक भारत की यात्रा की। यह महामहिम की तीसरी भारत यात्रा थी, वे इससे पहले 1993 और 2005 में भारत की यात्रा पर आये थे। यात्रा के दौरान, महामहिम ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की और विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर बातचीत की। महामहिम के साथ विदेश मंत्री, सुश्री एन लिंडे, व्यापार, उद्योग और नवाचार मंत्री, श्री इब्राहिम बेलान और स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य सचिव, सुश्री मजा फज़ेस्ताद और 50 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया था। स्वीडन यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन करता है।

अन्य कुछ यात्राओं में 22 और 23 अक्तूबर 2019 को स्टॉकहोम में आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत-स्वीडिश संयुक्त आयोग के 19वें सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए वाणिज्य, उद्योग और रेलवे के लिए माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल की स्वीडन यात्रा शामिल है। माननीय वाणिज्य, उद्योग और रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 23 अक्तूबर 2019 को स्टॉकहोम में आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए इंडो-स्वीडिश जेसीएम के 19वें सत्र के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। आयुष प्रतिनिधिमंडल ने आयुष दवाओं को बढ़ावा देने और आईएसओटीसी-215 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान बैठक में भाग लेने के लिए 13-17 अप्रैल, 2019 को गोथेनबर्ग, स्वीडन का दौरा किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 1-4 मई 2019 को स्वीडन की यात्रा पर गया और स्वीडन के शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय

की राज्य सचिव, मालिन सीडरफेल्ट ओस्टबर्ग और उद्यम और नवाचार मंत्रालय की राज्य सचिव, स्टिना बिलिंग के साथ भारत-स्वीडन संयुक्त समिति की छठी संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता की। माननीय जल मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने स्वीडन में एसआईडब्ल्यूआई के विश्व जल सप्ताह 2019 में भाग लेने के लिए 28-29 अगस्त 2019 को स्वीडन गए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

स्वीडन के किंग कार्ल XVI गुस्ताफ और क्वीन सिल्विया ने अपनी भारत यात्रा के दौरान हरिद्वार में सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया (05 दिसंबर, 2019)

ई-शासन और नागरिक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 15-17 जनवरी, 2020 तक नगरीय प्रशासन विकास मंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अध्ययन यात्रा विचाराधीन है।

स्टॉकहोम में 19-20 फरवरी, 2020 तक सड़क सुरक्षा पर तीसरे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की यात्रा विचाराधीन है।

वार्षिक गोल कुर्सी सहयोग प्रतिनिधि बैठक 2020 में भाग लेने के लिए 26-27 मार्च 2020 को भारत के उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एंड्रयू वान कुपुर लैंगस्टिह के नेतृत्व में 2 सदस्यीय शिष्टमंडल का दौरा विचाराधीन है।

लातविया

इस वर्ष बढ़ती हुई राजनीतिक व्यस्तता के साथ-साथ व्यापार और वाणिज्यिक जुड़ाव के संदर्भ में उच्च स्तर की यात्रा हुई। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 19 और 20 अगस्त 2019 को लातविया का दौरा किया।

उनके साथ मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री संजय शामराव धोत्रे, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीमती रानी नाराह, राज्य सभा के संसद सदस्य, श्री मानस रंजन भूनिया, लोक सभा के सांसद, श्री रमेश बिधूड़ी, लोकसभा और एसोचैम,

सीआईआई और आईएमसी के नेतृत्व में और एक 25 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल (प्रमुख मंडल के रूप में एसोचैम के साथ) था। भारत और लातविया के बीच एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति ने लातविया के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुस्तकालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।

विदेश मंत्री, श्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में 74वें यूएनजीए के अवसर पर लातविया के विदेश मंत्री से भेंट की। लातविया यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन करता है।

लातविया एडगर्स के विदेश मंत्री रिंकावियाने ने रायसिना वार्ता के 5वें सत्र में भाग लेने के लिए 13-16 जनवरी, 2020 तक भारत का दौरा किया था। उन्होंने बातचीत से इतर विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने लोकसभा विदेश समिति के अध्यक्ष से भी मुलाकात की।

तुर्की

वर्ष के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति एर्दोगन ने जुलाई 2019 में ओसाका में जी-20 के दौरान द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और विदेश मंत्री मेवलुत कैवुसोग्लू ने सितंबर 2019 में यूएनजीए के अवसर पर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार और प्रवक्ता और तुर्की के विदेशी और सुरक्षा परिषद् के उपाध्यक्ष, डॉ. इब्राहिम कालिन, 25 अप्रैल 2019 को भारत आए थे। भारत-तुर्की विदेश कार्यालय परामर्श का 10वां दौर 8 मई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एयर वाइस मार्शल दिलीप कुमार पटनायक, वीएम के नेतृत्व में 43वें उच्च कमान पाठ्यक्रम के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14-18 अक्तूबर 2019 को तुर्की का दौरा किया।

अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार 3.75 अरब अमेरिकी डॉलर था। अगस्त 2019 में एक 18-सदस्यीय तुर्की मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। यह तुर्की मीडिया द्वारा भारत की पहली यात्रा थी।

स्विट्ज़रलैंड

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 11 से 15 सितंबर 2019 तक स्विट्जरलैंड का राजकीय दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों के पूर्ण परिदृश्य की चर्चा और समीक्षा की गई। यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भारत-स्विट्जरलैंड विज्ञान और नवाचार गठबंधन की स्थापना पर आशय का पत्र; (ii) जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन; तथा (iii) लॉज़ेन विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के आईसीसीआर चेयर की स्थापना के नवीकरण पर समझौता ज्ञापन। भारत के माननीय राष्ट्रपति और स्वीडन के राष्ट्रपति महामहिम श्री उली मौरर ने 13 सितंबर 2019 को बर्न में आयोजित भारत-स्विट्जरलैंड व्यापारिक गोल मेज में वक्तव्य दिया। माननीय राष्ट्रपति ने 14 सितंबर को विलेन्यू में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया। केरल के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पिनारायी विजयन ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 12-15 मई 2019 तक स्विट्जरलैंड का दौरा किया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-स्विस संयुक्त समिति की पाँचवीं बैठक 30 अप्रैल 2019 को बर्न में आयोजित की गई थी। भारत-स्विट्जरलैंड राजनयिक संवाद का पाँचवां दौर 11 नवंबर को बर्न में आयोजित

किया गया था। स्विट्ज़रलैंड की अंतर्राष्ट्रीय वित्त की राज्य सचिव, सुश्री डेनिएला स्टॉफेल ने 13 नवंबर 2019 को भारत का दौरा किया और कर मामलों में आगे सहायता के लिए राजस्व विभाग में बैठकें की।

अप्रैल-अक्तूबर 2019 के दौरान, स्विट्ज़रलैंड को भारत के निर्यात में अप्रैल-अक्तूबर 2018 की तुलना में 14% की वृद्धि देखी गई। स्विट्ज़रलैंड 2018-19 में 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का एक प्रमुख व्यापार भागीदार बना हुआ है।

विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक 21 से 24 जनवरी, 2020 तक दावोस में होगी और इसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी देखने को मिलेगी। जिनेवा में 24-26 मार्च 2020 से जिनेवा स्वास्थ्य मंच पर भारत देश के गेस्ट ऑफ ऑनर है। हालांकि, अभी तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना है, लेकिन मार्च 2020 में भारत-स्विट्ज़रलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग और भारत-स्विट्ज़रलैंड वित्तीय वार्ता होने की संभावना है।

लिकटेंस्टाइन की रियासत

भारत और लिकटेंस्टीन के बीच द्विपक्षीय संबंध सुचारू रूप से चलते रहे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए लिकटेंस्टीनिशे पोस्ट एजी ने 22 अक्तूबर 2019 को वडूज में महात्मा गांधी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया।

वडूज में 12 नवंबर, 2019 को राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट देने पर चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (सीपीवी) डॉ. आदर्श स्वाइका ने किया और लिकटेंस्टीन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लिकटेंस्टीन के विदेश मामलों के निदेशक, श्री डोमेनिक वांगर ने किया।

द होली सी

भारत और द होली सी के बीच द्विपक्षीय संबंध सुचारू रूप से बने रहे। विदेश राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 12 और 13 अक्तूबर, 2019 को भारत की ब्लेस्ड सिस्टर मरियम थ्रेसिया चिरमेल मनकीडियन की कैन्यनियेशन सेरेमनी में भाग लेने के लिए वेटिकन सिटी गया। प्रतिनिधिमंडल में वन और पर्यावरण, बागवानी और मृदा संरक्षण मंत्री, श्री श्याम कुमार, और महुद और शहर योजना, मणिपुर सरकार शामिल थे। राज्य मंत्री (ईए) ने पोप फ्रांसिस और आर्कबिशप पॉल गैलागर, राज्य संबंधों के सचिव [विदेश मंत्री], होली सी के साथ भेंट की। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या (01 अक्तूबर 2019) पर वेटिकन के पोंटिफिकल काउंसिल फॉर इंटर धार्मिक डायलॉग ने एक दिन के अंतर-धार्मिक कांग्रेस का आयोजन किया।

ऑस्ट्रिया

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। वर्ष के दौरान यात्राओं, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोगों से लोगों के बीच बातचीत के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया गया। यूरोप, एकीकरण और विदेश मामलों के ऑस्ट्रियाई संघीय मंत्री, डॉ. करिन कनिसल 25 और 26 फरवरी 2019 को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। यह यात्रा भारत

और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के संदर्भ में हुई।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और मंत्री करिन कनिसेल ने 25 फरवरी 2019 को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार और निवेश, शिक्षा, प्रवास, संस्कृति और पर्यटन और लोगों से लोगों के संबंधों के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकताएं तय की। विदेश मंत्री कन्सी ने एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच साझा हित पर नई दिल्ली में विभिन्न चिंतकों के साथ विस्तृत बातचीत की।

दूसरी भारत-ऑस्ट्रिया राजनयिक परामर्श 23 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के देशों की यात्रा करने के लिए अधिक पर्यटकों, व्यापारियो, पेशेवरों, अधिकारियों के लिए वीजा व्यवस्था को और अधिक उदार बनाने के लिए विभिन्न राजनयिक मुद्दों और विचारों पर चर्चा की।

मोंटेनेग्रो

समाजवादी फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया (एसएफआरई) के दिनों से ही, जिसमें मोंटेनेग्रो एक घटक गणराज्य था, मोंटेनेग्रो के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। मोंटेनेग्रो में भारत के प्रति मित्रता और सद्भावना है।

विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर 13 मार्च 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हरियाणा के कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 18 और 19 मई 2019 को मोंटेनेग्रो का दौरा किया।

यूरोपीय संघ

विगत वर्ष भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और गहनता का साक्षी रहा है। भारत की ओर से अनेक महत्वपूर्ण दौरों के साथ उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की प्रवृत्ति जारी रही जिसमें विदेश मंत्री का दौरा भी शामिल था। भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी समीक्षा बैठक भी 15वीं भारत-ईयू शिखर-सम्मेलन की तैयारी के रूप में 8 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नगोया में आयोजित जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान 23 नवम्बर, 2019 को ईयू प्रतिनिधि/उपाध्यक्ष - विदेश और सुरक्षा नीति के लिए अभिहित श्री जोसफ बोरेली के साथ बैठक की तथा भावी भारत-ईयू पर चर्चा की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 30 अगस्त, 2019 को ब्रुसेल्स की यात्रा की तथा यूरोपीय संसद के अध्यक्ष श्री डेविड मारिया सासोली, ईयू, विदेश और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि सुश्री फेडेरिका मोघेरिनी तथा ईयू मानवीय सहायता एवं संकट प्रबंध आयुक्त श्री क्रिस्टस स्टालिएनिडेस से भेंट की तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

डॉ. एस. जयशंकर और सुश्री फेडेरिका मोघेरिनी ने 1 अगस्त, 2019 को बैंकाक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर-सम्मेलन के दौरान तथा पुन: 27 सितम्बर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी परस्पर भेंट की।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने यूरोपीय आयोग द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 12 सितम्बर, 2019 को आयोजित वैश्विक टीकाकरण शिखर-सम्मेलन में प्रतिभागिता की। हस्तक्षेप के दौरान, श्री अश्विनी कुमार चौबे ने उन उपायों का वर्णन किया जिनके माध्यम

से भारत सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख को सुदृढ़ बना रही है तथा इतिहास में विशालतम टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक को कार्यान्वित कर रही है जिसमें सात टीकाकरण शामिल हैं।

भारत-ईयू रणनीतिक भागीदारी समीक्षा बैठक 5 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, सचिव (पूर्व) द्वारा तथा ईयू पक्ष का नेतृत्व श्री क्रिश्चन लेफलेर, उप महासचिव, यूरोपीय विदेश कार्यवाही सेवा द्वारा किया गया। इस बैठक में भारत-ईयू संबंध के संपूर्ण परिदृश्य को शामिल किया गया ताकि सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रों की पहचान की जा सके तथा वर्ष 2020 के प्रारंभ में आयोजित किए जाने वाले 15वें भारत-ईयू शिखर-सम्मेलन में रखे जा सकने वाले संभावित विषयों पर प्रारंभिक विचार-विमर्श किया जा सके। दोनों पक्षों ने रणनीतिक भागीदारी की प्रयोग में न लाई जा सकी संभावित क्षमता का पूर्णत: उपयोग करने की आवश्यकता को पहचना। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के क्षेत्रों सहित विद्यमान संबंधों में वृद्धि किए जाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

श्री संजीव अरोड़ा, सचिव (कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा और प्रवासी भारतीय मामले) तथा सुश्री पारसकेवी मिचोऊ, महानिदेशक, (प्रवास और गृह मामले), यूरोपीय आयोग ने नई दिल्ली में 11 जुलाई, 2019 को आयोजित भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवास और संचनलता पर पांचवी उच्च-स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम) की संयुक्त अध्यक्षता की। बैठक में हुए विचार-विमर्श में भारत-ईयू गलियारे में प्रवास और संचालनता के संदर्भ में पारस्परिक हित के मुद्दों की व्यापक परिधि को शामिल किया गया था।

भारत-ईयू व्यापार उप-आयोग की वार्षिक बैठक 4 जुलाई, 2019 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई जिसकी सह-अध्क्षता सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा श्री पीटर बेर्ज़, कार्यवाहक निदेशक, व्यापार महानिदेशालय, यूरोपीय आयोग द्वारा की गई। उप-आयोग ने उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करने वाले संयुक्त कार्यकारी समूहों की रिपोर्टों की समीक्षा की जैसे भेषजिक एसपीएस/टीबीटी (व्यापार के लिए सैनीटरी और फाइटो-सैनीटरी/तकनीकी बाधाएं), कृषि और सामुद्रिक उत्पाद आदि। इसने व्यापार संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की जैसे जीएसपी (सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली बाजार पहुंच विषय, डाटा संरक्षण, आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) इस्पात, दोनों ओर से व्यापार को प्रभावित करने वाले विनियामक उपाय आदि।

भारत-ईयू आईसीटी संयुक्त कार्यकारी समूह (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) की 12वीं वार्षिक बैठक ब्रुसेल्स में 12-13 सितम्बर, 2019 को आयोजित की गई जिसकी संयुक्त अध्यक्षता श्री राजीव कुमार, संयुक्त सचिव, मैती तथा श्री गेरार्ड डे ग्राफ, निदेशक, संचार नेटवर्क, विषय-वस्तु और प्रौद्योगिकी महानिदेशालय, यूरोपीय आयोग द्वारा की गई। इस बैठक में चर्चाएं मुख्य रूप से दूरसंचार पर केन्द्रित थी जिसमें बाजार के मुद्दे, 5जी, साइबर सुरक्षा अनुसंधान और अभिनवता, वैयक्तिक डाटा संरक्षण, एआई (कृत्रिम आसूचना), सुपरकंप्यूटिंग क्वांटम, मानकीकरण आदि भी शामिल थे। डिजीटल यूरोप तथा नैस्कॉम द्वारा 12 सितम्बर, 2019 को यूई-भारत व्यापार वार्ता भी आयोजित की गई थी।

रेल मंत्रालय तथा यूरोपीय आयोग (संचालनता और परिवहन महानिदेशालय) ने 3 सितम्बर, 2019 को रेलवे के क्षेत्र में सहयोग पर एक प्रशासनिक करार पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसरण में, दोनों पक्षों ने 19 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में एक तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें यूरोपीय आयोग के अधिकारियों तथा उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ईयू भारत का विशालतम क्षेत्रीय व्यापार भागीदार है जबकि भारत ईयू का नौवां विशालतम भागीदार है। भारत का माल के संबंध में वर्ष 2018 में ईयू के साथ द्विपक्षीय व्यापार 91.5 बिलियन यूरो (107.97 बिलियन डॉलर) था जिसमें ईयू के लिए भारत का

45.8 बिलियन यूरो (54.0 बिलियन डॉलर) तथा 45.7 बिलियन यूरो (53.9 बिलियन डॉलर) का आयोग शामिल है। ईयू के साथ जनवरी-सितम्बर 2019 की अवधि के लिए भारत का द्विपक्षीय व्यापार 68.6 बिलियन यूरो (75.46 बिलियन डॉलर) था।

ईयू के साथ वर्ष 2018 में सेवाओं के क्षेत्र में भारत का द्विपक्षीय व्यापार 36 बिलियन यूरो (42.5 बिलियन डॉलर) था जिसमें भारत का 19.3 बिलियन यूरो (22.7 बिलियन डॉलर) का निर्यात तथा 16.7 बिलियन यूरो (19.7 बिलियन डॉलर) का आयोत शामिल था।

ईयू भारत का एफडीआई का विशालतम स्रोत है। अप्रैल, 2000 जून, 2019 की अवधि के दौरान, ईयू से भारत को एफडीआई साम्या अंत:प्रवाह कुल 100.35 बिलियन डॉलर था जो कुल एफडीआई का लगभग 23 प्रतिशत है।

8

अमेरिका

संयुक्त राज्य

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध

पिछले एक वर्ष में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए) के संबंधों में व्यापक विकास होता रहा। भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री) की अमेरिका यात्रा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, डोनाल्ड जे. ट्रम्प के साथ उनकी अन्य द्विपक्षीय बैठकों ने, 2019 में संबंधों को उच्च-स्तरीय ध्यान और मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया। भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद जैसे संस्थागत संवाद तंत्र और अन्य उच्च-स्तरीय/मंत्रिस्तरीय व्यस्तताओं के कारण रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा, व्यापार और वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और लोगों के लोगों के साथ संबंध जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम मिले। भारत-अमेरिका साझेदारी ने भारत-प्रशांत के साथ-साथ विश्व स्तर पर अधिक से अधिक प्रमुखता प्राप्त की। दोनों पक्ष क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें बहुपक्षीय मंचों में उनकी भागीदारी भी शामिल है।

उच्च-स्तरीय/नेतृत्व-स्तरीय सहभागिता

प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 74वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड में भाग लेने के लिए 21-27 सितंबर 2019 को अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकी पक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं कीं। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा, 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रम्प ने, 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन में सामुदायिक शिखर सम्मेलन 'हाउडी, मोदी! साझा सपने, उज्ज्वल भविष्य'

में भाग लिया था। इस आयोजन में दोनों नेताओं ने सभा को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान ह्यूस्टन में प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत, 20 क्षेत्रों के अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं के साथ न्यूयॉर्क में एक गोलमेज चर्चा, भारतीय समुदाय के विभिन्न समूहों के साथ बातचीत, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक समारोह का आयोजन,बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का 'ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड' प्राप्त करना और ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में मुख्य भाषण देना आदि अन्य कार्यक्रम भी थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने अमेरिका के साथ व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, लोगों के लोगों से संबंधों, आतंकवाद विरोध, रक्षा आदि क्षेत्रों में भारत के संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सितंबर 2019 में अमेरिका की यात्रा पर जाने से पहले, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ-28 जून 2019 को ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर और 26 अगस्त 2019 को बियारित्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन के समय दो द्विपक्षीय बैठकें हुईं थीं। दोनों नेता जून 2019 में ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के हाशिये पर आयोजित भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय नेता-स्तरीय बैठक में भी मिले थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच हाल में दो बार (24 मई 2019 और 19 अगस्त 2019 को) टेलीफोन पर बातचीत हुई थी।

प्रधानमंत्री और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ह्यूस्टन, टेक्सास में इंडिया कम्युनिटी इवेंट में (22 सितंबर, 2019)

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय बातचीत

दूसरा भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद (2+2 संवाद) 18 दिसंबर, 2019 को वाशिंगटन, डी.सी. में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया। उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्षों- राज्य सचिव, माइकल आर पोम्पेओ और रक्षा सचिव, डॉ. मार्क एस्पर से भेंट की और रणनीतिक, सुरक्षा क्षेत्र में आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों ने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विनिमय किये।

2+2 संवाद के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं: भारत-अमेरिका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (जीएसओएमआईए) के लिए औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (आईएसए) को पूरा करना, जो अमेरिकी और भारतीय रक्षा उद्योग के बीच वर्गीकृत सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान और संरक्षण के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) के अंतर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और निष्पादन की प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए रक्षा उद्योग, रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप देना और डीटीटीआई के अंतर्गत उद्योग-से-उद्योग के ढांचे की स्थापना। दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका युवा अन्वेषक पहल स्थापित करने, संसदीय आदान-प्रदान को मजबूत करने, न्यायिक सहयोग को बढ़ाने, शांति स्थापना में सहयोग का विस्तार करने, भारत में रखरखाव मरम्मत और ओवरहाल इकाइयों की स्थापना के लिए सहयोग का पता लगाने, अमेरिका-भारत प्रशांत कमान; मध्य कमान और अफ्रीका कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बेड़ों के बीच सहयोग बढ़ाने और संबंधित सेनाओं और वायु सेनाओं के बीच समान सहयोग का विस्तार करने के लिए साथ मिलकर काम करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने सैन्य संपर्क संबंधों में विस्तार का पता लगाने का निर्णय लिया, जिसमें अमेरिकी नौसेना बलों के मध्य कमान के साथ एक भारतीय अधिकारी और भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में स्थापित सूचना संलयन केंद्र में एक अमेरिकी संपर्क अधिकारी को नियुक्त करना शामिल है। उन्होंने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता में सहयोग विकसित करने का भी निर्णय लिया।

अमेरिका ने आपदा तन्यक बुनियादी ढांचा (डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर) के गठबंधन में गठबंधन सदस्य के रूप में शामिल होने का भी निर्णय लिया।

दिसंबर 2019 में, 2+2 संवाद के लिए अमेरिका की यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 18 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ट्रम्प से मिले।

मंत्रिस्तरीय व्यस्तताएँ

वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, श्री अरुण जेटली ने अप्रैल 2019 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने यात्रा के दौरान निवेशकों के साथ गोलमेज चर्चाओं में भी भाग लिया।

अमेरिका के वाणिज्य सचिव, विलबर एल. रॉस ने मई 2019 में 'ट्रेड विंड्स इंडो-पैसिफिक फोरम एंड मिशन' नामक एक व्यापार मंच में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की और वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री सुरेश प्रभु के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

सचिव पोम्पेओ ने जून 2019 में भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की और विदेश मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) श्री अजीत डोवाल से भी मिले। उन्होंने दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत-अमेरिका संबंधों पर भाषण दिया।

विदेश मंत्री ने अगस्त 2019 में बैंकॉक में नौवें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक के हाशिये पर सचिव पोम्पेओ के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की।

अमेरिका के उप सचिव, जॉन जे. सुलिवन ने अगस्त 2019 में भारत का दौरा किया और भारत-अमेरिका मंच में भाग लिया। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ एक अलग द्विपक्षीय बैठक भी की।

रेलवे एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल (सीआईएम, श्री पीयूष गोयल), ने सितंबर 2019 में अमेरिकी का दौरा किया और यूनाइट्स स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेंटेटिव, रॉबर्ट ई. लाइटहाइज़र (यूएसटीआर लाइटहाइज़र) के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने न्यूयॉर्क में व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष इंटरैक्टिव सत्र में भी भाग लिया।

विदेश मंत्री ने 21 सितंबर से 02 अक्तूबर 2019 तक अमेरिका का दौरा किया। विदेश मंत्री के यात्रा के प्रारंभिक खंड में, ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में विभिन्न कार्यों के लिए प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल का एक हिस्सा शामिल था। इसके अलावा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और कई देशों के अपने समकक्षों और वार्ताकारों से भेंट की। इसके बाद, विदेश मंत्री ने 28 सितंबर-02 अक्तूबर 2019 को वाशिंगटन, डी.सी. का दौरा किया। उन्होंने सचिव पोम्पेओ; सचिव एस्पर; राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के अध्यक्ष, रॉबर्ट सी. ओ'ब्रायन (एनएसएओ 'ब्रियन) के सहायक और होमलैंड सिक्योरिटी के कार्यवाहक सचिव केविन मैकलेनन के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन, डी.सी. में कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, हेरिटेज फाउंडेशन, अटलांटिक काउंसिल और ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन आदि विभिन्न चिंतक संस्थाओं से बातचीत की। विदेश मंत्री ने अमेरिका-भारत सामरिक भागीदारी मंच और अमेरिका - भारत व्यापार परिषद् द्वारा आयोजित दो अलग-अलग इंटरैक्शन सत्रों में भी भाग लिया। विदेश मंत्री ने 2 अक्तूबर 2019 को, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी से भेंट की और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए भारतीय दूतावास, वाशिंगटन, डी.सी.द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया।

वित्त मंत्री (एफएम), श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अक्तूबर, 2019 में वाशिंगटन, डी.सी. में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक की वार्षिक बैठक 2019 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वार्षिक बैठकों के हाशिये पर, उन्होंने जी-20 और ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने औद्योगिक और संस्थागत निवेशकों से बातचीत की, कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाषण दियाऔर शिकागो में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बात की।

अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्टीवन टी. मनुचिन (सचिव मनुचिन) ने 01 नवंबर 2019 को दिल्ली में आयोजित सातवीं भारत-अमेरिकी आर्थिक और वित्तीय भागीदारी बैठक में भाग लेने के लिए नवंबर 2019 में भारत का दौरा किया। वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

अमेरिका के वाणिज्य सचिव, विलबर एल. रोस ने विश्व आर्थिक मंच के भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2019 में भारत का दौरा किया। इस यात्रा के समय उन्होंने वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण और सीआईएम, श्री पीयूष गोयल के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।

सीआईएम, श्री पीयूष गोयल ने नवंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने यूएसटीआर लाइटहाइज़र के साथ द्विपक्षीय बैठक की और न्यूयॉर्क में एक व्यवसायिक गोलमेज बैठक में भी भाग लिया।

वित्त मंत्री ने नवंबर 2019 में बैंकॉक में आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस के सचिव, सचिव एस्पर के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की।

वित्त मंत्री ने दिसंबर 2019 में 2+2 संवाद के साथ-साथ अन्य द्विपक्षीय कार्यक्रमों के लिए अमेरिका का दौरा किया। 2+2 संवाद में भाग लेने के अलावा, उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय से भेंट की, नॉरफ़ॉक में एक नौसेना स्टेशन का दौरा किया, और सचिव एस्पर के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

विदेश मंत्री ने दिसंबर 2019 में 2+2 संवाद के लिए अमेरिका का दौरा किया और सचिव पोम्पेओ और एनएसए ओ ब्रियन के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। विदेश मंत्री ने सीनेट की विदेश संबंध समिति के नेताओं से भी भेंट की।

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने 26 सितंबर 2019 को चतुर्भुज प्रारूप में परामर्श के लिए न्यूयॉर्क में मुलाकात की।

भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अमेरिका की यात्रा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी ने संभावित निवेशकों के साथ बैठकें करने के लिए अगस्त 2019 में अमेरिका के दौरे पर गये तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

मेघालय के मुख्यमंत्री, श्री कॉनराड के. संगमा ने सितंबर 2019 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के बर्कले इनोवेशन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका का दौरा किया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने सितंबर 2019 में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स के संभावित निवेशकों से बात करने के लिए अमेरिका का दौरा किया।

अमेरिकी राज्यों के राज्यपालों द्वारा भारत की यात्रा

न्यू जर्सी राज्य के गवर्नर फिल मर्फी ने सितंबर 2019 में भारत दौरे पर 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। भारत में उनके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक शामिल थी। उन्होंने दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद और गांधीनगर का दौरा किया।

अरकंसास राज्य के राज्यपाल आसा हचिंसन ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सितंबर-अक्तूबर 2019 में भारत का दौरा किया। अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल से भेंट की।

इंडियाना राज्य के राज्यपाल, एरिक होलकोम्ब ने सितंबर-अक्तूबर 2019 में भारत आने वाले एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान, राज्यपाल होलकोम्ब ने प्रधानमंत्री और सीआईएम, श्री पीयूष गोयल से भेंट की।

कोलोराडो राज्य के राज्यपाल, जारेड पोलिस ने नवंबर 2019 में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा किया। उन्होंने नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल आरई-इनवेस्ट एक्सपो में भाग लिया।

सांसदों के दौरे

भारतीय और अमेरिकी सांसदों के दौरे आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अधिक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सीनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज़ (सितंबर-अक्तूबर 2019), सीनेटर क्रिस वान होलेन (अक्तूबर 2019), सीनेटर मार्गरेट हसन (अक्तूबर 2019), और सीनेटर राफेल एडवर्ड क्रूज़ (अक्तूबर 2019) ने भारत की यात्रा की।

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के पांच सदस्यीय द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2019 में भारत-अमेरिका मंच में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने अन्य व्यस्तताओं के अलावा विदेश मंत्री से भी भेंट की।

अन्य प्रमुख आदान-प्रदान

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव, श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, ने विश्व बैंक द्वारा आयोजित सम्मेलन ने विश्व जल सप्ताह में भाग लेने के लिए अप्रैल 2019 में अमेरिका का दौरा किया था।

वित्त मंत्रालय के सचिव श्री सुभाष गर्ग अप्रैल 2019 में विश्व बैंक/आईएमएफ की बैठकों में भाग लेने के लिए वाशिंगटन गये थे।

शिपिंग मंत्रालय के सचिव, श्री गोपाल कृष्ण अप्रैल 2019 में सीट्रेड ग्लोबल क्रूज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गये थे।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव श्री रमेश अभिषेक ने मई 2019 में संभावित निवेशकों के साथ बात करने के लिए एक इन्वेस्ट इंडिया प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका का दौरा किया।

अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि, ज़ल्माय खलीलज़ाद मई और अगस्त 2019 में भारत आये थे, उन्होंने विदेश मंत्री से भेंट की।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा विश्व बैंक के साथ बातचीत के लिए मई 2019 में वाशिंगटन, डी.सी. गये थे।

लेखा महानियंत्रक श्री एंथनी लियानज़ुआला ने सरकारी वित्तीय प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मई 2019 में अमेरिका का दौरा किया।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) केपरमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक, डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने जून 2019 में अमेरिका के फ़र्मिलाब, इलिनोइस के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा के लिए अमेरिका जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे ने अगस्त 2019 में अटलांटा का दौरा किया।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, श्री अतनु चक्रवर्ती ने अक्तूबर 2019 में वाशिंगटन डी.सी. में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के समय, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए ट्रेजरी के अमेरिकी अवर सचिव, ब्रेंट मैकिंटोश के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, श्री वी.के. यादव ने अक्तूबर2019 में अमेरिकी पश्चिम तट के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श कर नव स्थापित राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक सहयोग का पता लगाने के लिए अमेरिका का दौरा किया।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के सचिव, श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए नवंबर 2019 में वाशिंगटन, डी.सी. गये थे।

निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव श्री टी.के. पांडे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विनिवेश के संबंध में ऊर्जा कंपनियों के साथ बैठक करने के लिए दिसंबर 2019 में अमेरिका गये थे।

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने दिसंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों/ बातचीत और गोल मेज चर्चाओं में भाग लिया।

परामर्श/संवाद तंत्र

भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न स्तरों पर कई संवाद तंत्र हैं जो कई क्षेत्रों को आवृत करते हैं। वर्ष के दौरान इन संवाद तंत्रों के अंतर्गत हुए कुछ प्रमुख द्विपक्षीय आदान-प्रदान में निम्नलिखित शामिल थे:

सुरक्षा/रणनीतिक: भारतीय वायु सेना - अमेरिकी वायु सेना के कार्यकारी संचालन समूह की 22वीं बैठक अप्रैल-मई 2019 में हवाई में हुई थी।

रक्षा खरीद और उत्पादन समूह की बैठक जुलाई - अगस्त 2019 में वाशिंगटन, डी.सी. में हुई। महानिदेशक (अधिग्रहण), रक्षा मंत्रालय, श्री अपूर्व चंद्र और निदेशक, अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी, लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स हूपर नेइसकी सह-अध्यक्षता की थी।

भारत-अमेरिका रक्षा नीति समूह की 15वीं बैठक अगस्त 2019 में वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित की गई थी। रक्षा सचिव, श्री संजय मित्रा और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव, श्री जॉन रूड ने बैठक की सह-अध्यक्षता की, इस बैठक में भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा की गई।

संयुक्त सचिव/सहायक सचिव स्तर पर दूसरी भारत-अमेरिका 2+2 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कैलिफोर्निया के मोंटेरी में अगस्त 2019 में हुई। दोनों पक्षों ने आधुनिक रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति और विकास की समीक्षा की और इन क्षेत्रों में साझा हित पर आधारित सहयोग की आगे की संभावनाओं का पता लगाया।

भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा संवाद का चौथा दौर अगस्त 2019 में, कैलिफोर्निया के मोंटेरे में आयोजित किया गया था। संवाद के दौरान, दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की और द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत-अमेरिका साइबर सुरक्षा संवाद सितंबर 2019 में दिल्ली में हुआ।

भारत-अमेरिका सूचना संचार प्रौद्योगिकी कार्य समूह की बैठक अक्तूबर 2019 में दिल्ली में हुई।

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंकाक में मई और नवंबर 2019 में बहुपक्षीय कार्यक्रमों के समय साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर परामर्श के लिए बैठक की।

पहला आतंकवाद-प्रतिरोध टेबलटॉप अभ्यास नवंबर 2019 में दिल्ली में हुआ, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे।

भारत-अमेरिका नागरिक संयुक्त कार्यदल की सातवीं बैठक नवंबर 2019 में भारत में आयोजित की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने बैठक का उद्घाटन किया।

रक्षा और मिल-टू-मिल सहयोग

रक्षा सहयोग भारत-अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है। दोनों पक्षों ने सैन्य संबंधों के साथ-साथ रक्षा व्यापार के विस्तार की दिशा में काम करना जारी रखा:

सैन्य अभ्यास

भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'युद्ध अभ्यास'का 15वां संस्करण सितंबर 2019 में अमेरिका के संयुक्त बेस लुईस-मैककॉर्ड में आयोजित किया गया था।

भारतीय, अमेरिकी और जापानी नौसेनाओं के त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास 'मालाबार' का 23वां संस्करण सितंबर, अक्तूबर 2019 में जापान के तट पर आयोजित किया गया था।

भारतीय और अमेरिकी विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' का 10वां संस्करण अक्तूबर 2019 में अमेरिका के संयुक्त बेस लुईस-मैककॉर्ड में आयोजित किया गया था।

नवंबर 2019 में भारत-अमेरिका के पहले संयुक्त त्रिकोणीय मानव-सेवा सहायता और आपदा राहत अभ्यास 'टाइगर ट्रम्फ' का आयोजन भारत के विशाखापत्तनम तट पर हुआ था। दूसरे 2+2 संवाद के समय, इस अभ्यास को सहमत प्रारूप में प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया।

अन्य आदान-प्रदान

अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ए. मिले अप्रैल 2019 में भारत आए थे।

थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने अप्रैल 2019 में अमेरिका का दौरा किया। उनके कार्यक्रमों में अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल जोसेफ एफ. डनफोर्ड और अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल मार्क ए मिले के साथ बैठकें शामिल थीं।

अमेरिकी नौसेना प्रमुख, एडमिरल जॉन रिचर्डसन ने मई 2019 में भारत आये थे।

यू.एस. पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडमिरल जॉन सी. एक्विलिनो ने अक्तूबर 2019 में भारत का दौरा किया।

वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल आर. के. एस भदौरिया ने दिसंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया और संयुक्त बेस पर्ल हार्बर-हिकाम, हवाई में आयोजित पैसिफिक एयर चीफ्स की संगोष्ठी 2019 में भाग लिया।

रक्षा प्रौद्योगिकी

भारत-अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह (जेटीजी) की 21वीं बैठक अगस्त 2019 में सैन डिएगो में आयोजित की गई थी।

अमेरिका की रक्षा अवर सचिव (एक्विजिशन एंड सस्टेनेशन), सुश्री एलेन लॉर्ड ने अक्तूबर 2019 में भारत में आयोजित नौवें इंडो-यू.एस. डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव (डीटीटीआई) के लिए भारत आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव (रक्षा उत्पादन), रक्षा मंत्रालय, श्री सुभाष चंद्रा ने किया।

ग्यारहवें भारत-अमेरिकी वरिष्ठ प्रौद्योगिकी सुरक्षा समूह (एसटीएसजी) की बैठक वाशिंगटन, डी.सी. में नवंबर 2019 में हुई थी।

व्यापार एवं वाणिज्य

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (माल और सेवाएँ संयुक्त) है। अमेरिकी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 12% से अधिक बढ़ कर 142 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। दोनों पक्ष आपसी हित के मुद्दों को सुलझाने और आर्थिक संबंधों के विस्तार में लगे हुए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का आगे बढ़ाने का कार्य जारी रहा। सितंबर 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर एक समझौते को अंतिम रूप देने से इन प्रयासों को और गति मिली। दोनों पक्षों के कई हितधारकों के बीच बातचीत के अलावा, दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित और वित्त पोषित भारत-अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम (आईयूएसएसटीएफ), इस क्षेत्र में सहयोग बनाए रखने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले एक वर्ष से इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच संयुक्त रूप से वित्त पोषित कई परियोजनाओं, विशेषज्ञों, बैठकों, सम्मेलनों आदि के बीच आदान-प्रदान होता रहा।

इसरो और नासा पृथ्वी विज्ञान, चंद्र अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष यान और अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव जून 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों की बैठक और कुछ अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अमेरिका गये थे।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, श्री एम. राजीवन ने सितंबर 2019 में सहयोगी कार्यक्रमों और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में नई वैज्ञानिक पहल पर चर्चा के लिए अमेरिका के दौरे पर गये एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

चिंतकों का आदान-प्रदान

अनंत केंद्र और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत-अमेरिका मंच अगस्त 2019 में, दिल्ली में आयोजित किया गया था। अमेरिकी प्रतिभागियों में राज्य के उप सचिव, जॉन जे. सुलिवन और अमेरिकी कांग्रेस की पांच सदस्यीय द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

समकालीन चीन के अध्ययन केंद्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया और वाशिंगटन, डी.सी. और कैलिफोर्निया में विभिन्न चिंतकों से बातचीत की।

रैंड कॉर्पोरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिसंबर 2019 में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागरिक उड्डयन मंत्रालय; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री और सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी) से भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में एशिया प्रशांत नीति के लिए रैंड सेंटर के सलाहकार बोर्ड के सदस्य शामिल थे।

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने अक्तूबर 2019 में दिल्ली में इंडिया लीडरशिप समिट का आयोजन किया। यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष जॉन चैंबर्स के नेतृत्व में यूएसआईएसपीएफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 अक्तूबर 2019 को प्रधानमंत्री से भेंट की।

लोगों के लोगों से संबंध

अनुमान है कि अमेरिका में लगभग 4 मिलियन भारतीय और भारतीय-अमेरिकी हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में बहुत रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। लोगों से लोगों के मजबूत संबंध और भारत और अमेरिका के लोगों के बीच सद्भाव भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी के विकास को एक स्थायी आधार प्रदान करते हैं।

वर्तमान में 200,000 से अधिक भारतीय छात्रों के साथ अमेरिकी संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के साथ अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए शीर्ष गंतव्य स्थल बना हुआ है। यह किसी एक देश में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की सबसे अधिक संख्या है।

दोनों पक्षों ने 2+2 संवाद के समय, एक द्विपक्षीय युवा अन्वेषक इंटर्नशिप कार्यक्रम स्थापित करने की मंशा व्यक्त की, जो उभरते युवा नेताओं के लिए वैज्ञानिक और आर्थिक प्रयासों के प्रमुख क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा।

वाशिंगटन, डी.सी. के भारतीय दूतावास और अमेरिका में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों ने भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय योगदिवस, श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती का उत्सव, बैसाखी और संविधान दिवस का उत्सव शामिल थे।

वाशिंगटन, डी.सी. के भारतीय दूतावास और अमेरिका में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों ने इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई आयोजन किए। वाशिंगटन, डी.सी. के भारतीय दूतावास ने 2 अक्तूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यू.एस. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। विदेश मंत्री और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

01 अप्रैल 2019 से हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते/ समझौता ज्ञापन

दिसंबर 2019 में दोनों पक्षों के बीच भारत-अमेरिका सामान्य सुरक्षा समझौते (जीएसओएमआईए) के लिए औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (आईएसए) पर हस्ताक्षर किए गए।

दिसंबर 2019 में जल गुणवत्ता और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के जल शक्ति मंत्रालय और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कण अनुसंधान और नवाचार पर सहयोग को मजबूत करने के लिए सितंबर 2019 में भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर एक समझौता संपन्न हुआ था।

अक्तूबर 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के बीच एयरबोर्न सिंथेटिक एपर्चर रडार एयरबोर्न अभियान की कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कनाडा

भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध हाल के वर्षों में विकसित हुए हैं, इन संबंधों को साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, समान वैश्विक दृष्टिकोण, पारस्परिक रूप से पूरक व्यापार और निवेश संबंधों और लोगों से लोगों के बीच मजबूत और बढ़ते संबंधों से ताकत मिल रही है। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिली। फरवरी 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत की यात्रा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, खेल, वाणिज्य, उच्च शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया।

कनाडा में भारतीय मूल (पीआईओ) के 1.6 मिलियन से अधिक लोग हैं, जो कनाडा की जनसंख्या के 3% से अधिक हैं। कनाडा में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 172,000 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जो कनाडा को भारतीय छात्रों के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी गंतव्य बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।

उच्च स्तरीय संपर्क

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 26 अगस्त 2019 को फ्रांस के बियारिट्ज़ में जी-7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक अनौपचारिक बैठक की। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और तत्कालीन कनाडाई विदेश मामलों के मंत्री क्रिसिलिया फ्रीलैंड ने ओसाका, जापान (जून 2019) में जी-20 शिखर सम्मेलन के समय; लंदन, ब्रिटेन (जुलाई 2019) में राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में; और बैंकाक, थाईलैंड (अगस्त 2019)में नौवें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिले।

भारत से दौरे

- नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 24 सितंबर से 4 अक्तूबर 2019 तक मॉन्ट्रियल का दौरा किया और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 40वें सत्र में भाग लिया।
- विदेश मंत्री, डॉ. एस जयशंकर ने 19-20 दिसंबर 2019 को ओटावा का दौरा किया। अपनी यात्रा मेंउन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, विदेश मामलों के मंत्री, फ्रांकोइस-फिलिप शैम्पेन और लघु व्यवसाय, निर्यात संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री, मैरी एनजी से भेंट की।

कनाडा से दौरे

- कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्टीफन हार्पर ने 18-20 नवंबर 2019 को भारत का दौरा किया।
- कनाडा के पूर्व विदेश मंत्री श्री जॉन बेयर्ड ने 11-13 नवंबर, 2019 को भारत का दौरा किया।
- व्यापार और निर्यात विकास मंत्री, सास्काचेवान के आप्रवासन और कैरियर प्रशिक्षण मंत्री, श्री जेरेमी हैरिसन 18-22 नवंबर 2019 को व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए।
- ओंटारियो के आर्थिक विकास, नौकरी सृजन और व्यापार मंत्री, श्री विक्टर फेडेली ने 16 से 23 नवंबर, 2019 के बीच भारत का दौरा किया।

संसदीय आदान-प्रदान

- कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन मिड-इयर कार्यकारी समिति की बैठक ओटावा में 11-15 अप्रैल 2019 से आयोजित की गई थी। एक 5 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया, इस प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सचिवालय के सदस्य और असम और उत्तराखंड की विधानसभाओं के सदस्य शामिल थे।
- लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, श्री हरिवंश नारायण सिंह को जनवरी 2020 के पहले सप्ताह में अध्यक्षों और राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए ओटावा भेजने का निर्णय लिया गया।
- कनाडा के सीनेट के अध्यक्ष, जॉर्ज जे फ्युरेके जनवरी 2020 के तीसरे सप्ताह में भारत आने का प्रस्ताव है।

भारत-कनाडा राजनयिक वार्ता

भारत-कनाडा की साझेदारी में लोगों से लोगों के संबंधों की गतिशील भूमिका को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान चर्चा के माध्यम से आपसी चिंता के राजनयिक मुद्दों को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की। प्रथम भारत-कनाडा राजनयिक संवाद 30 सितंबर और 01 अक्तूबर 2019 को ओटावा में आयोजित किया गया था। दोनों

पक्षों ने राजनयिक मामलों पर चर्चा की जिसमें कनाडा में भारतीय छात्रों से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, शरण, वीजा, आदि से संबंधित मामले शामिल थे।

सुरक्षा और रक्षा में सहयोग

आतंकवाद प्रतिरोध पर विशेष रूप से संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के ढांचे के माध्यम से आतंकवाद के मुकाबले के मुद्दों पर पर्याप्त संपर्क है। आतंकवाद पर 16वां जेडब्ल्यूजी ओटावा में 26-27 मार्च 2019 को आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने आतंकवाद-संबंधी अपनी-अपनी प्राथमिकताओं, रणनीतियों और विधायी रूप रेखाओं पर जानकारी दी और दुनिया भर में और अपने-अपने देशों और क्षेत्रों में सीमा पार आतंकवाद सहित उत्पन्न खतरों की समीक्षा की तथा आतंकवाद का मुकाबला करने, हिंसात्मक अतिवाद और हिंसा पर रोक लगाने के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा की।

वित्त, व्यापार और उद्योग

भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 6.36 अरब अमेरिकी डॉलर का था। इस अवधि में कनाडा को भारत का निर्यात 2.85 अरब अमेरिकी डॉलर और कनाडा से आयात 3.51 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2019-20 के पहले छह महीनों में, द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 13% की वृद्धि हुई है। कनाडाई पेंशन फंड ने भारत में अब तक लगभग सीएडी 42.5 अरब डॉलर का निवेश किया है और निवेश के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में देख रहा है। भारत में 400 से अधिक कनाडाई कंपनियों की उपस्थिति है और 1000 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं।

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र भारत-कनाडा सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। 2015 में प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के समय डीएई और कनाडाई यूरेनियम कंपनी सीएएमईसीओ द्वारा हस्ताक्षरित दीर्घकालिक यूरेनियम खरीद अनुबंध हमारे सहयोग की पराकाष्ठा का एक मूर्त उदाहरण है। नागरिक परमाणु सहयोग पर छठी भारत-कनाडा संयुक्त समिति की छठी बैठक (जेसीएम) 6-7 जून 2019 को ओटावा में आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने अनुसंधान एवं विकास और उद्योग, दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग समझौते में प्रस्तावित सहयोग पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में डीएईऔर कनाडा के प्राकृतिक संसाधन विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है और जून 2019 में ओटावा में इसकी पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सहयोग के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की गई है।

कनाडा के आर्कटिक अनुसंधान में भारतीय भागीदारी

आर्कटिक अनुसंधान सहयोग पर प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चा के अनुसार, भारत के ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के वैज्ञानिकों ने 22 से 26 सितंबर 2019 तक कैम्ब्रिज बे, नुनावुत में स्थित कनाडाई हाई आर्कटिक रिसर्च स्टेशन (सीएचएआरएस) परिसर का दौरा किया था।

भारत-कनाडा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार संवाद

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समन्वय में आईसी-इम्पैक्ट्स (कनाडा का उत्कृष्टता के केंद्रों का एक नेटवर्क ने (समुदाय में तैनाती और व्यावसायीकरण, विशेष रूप से प्रदूषित जल निकायों की सफाई और भारत में कचरे से धन पैदा करने करने में भारत-कनाडा के वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली वार्ता में 9 दिसंबर 2019 को दूसरी भारत-कनाडा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार वार्ता का आयोजन किया।

शिक्षा

शिक्षा, दोनों देशों के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। इस समय 176,000 से अधिक भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं, यह भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक बन गया है।

शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट (एसआईसीआई) कनाडा और भारतीय सरकारों के समर्थन से उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ाने में लगा हुआ है और वह अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर, एसआईसीआई ने 25-26 नवंबर, 2019 को भारत और कनाडा के लगभग 145 संस्थानों के विश्वविद्यालय अध्यक्षों और कुलपतियों के साथ दिल्ली में कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया।

सांस्कृतिक आदान - प्रदान

लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित भारत-कनाडा संबंधों को देखते हुए सांस्कृतिक अति आदान-प्रदान महत्वपूर्ण हैं। ओटावा में पाँचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। प्रतिभागियों में भारी उत्साह था।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उत्सव को चिह्नित करने के लिए अक्तूबर 2018 से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये अक्तूबर 2020 तक जारी रहेंगे। ओटावा के मेयर ने 02 अक्तूबर को गांधी दिवस घोषित किया है।

नवंबर 2019 में गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती मनाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं।

विगत 18 वर्षों से पार्लियामेंट हिल पर दिवाली मनाई जाती है। इसे भारतीय मूल के सांसद दीपक ओबराय द्वारा शुरू किया गया था। इस वर्ष ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया-कनाडा द्वारा दीपक ओबराय फाउंडेशन और कनाडा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से पहाड़ी पर 19वीं दीवाली का आयोजन किया गया था। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता श्री एंड्रयू स्कीर समारोह के मुख्य अतिथि थे।

भारत-कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद

भारत के विदेश मंत्रालय और कनाडा के वैश्विक मामलों के मंत्रालय के सहयोग से, 22 नवंबर 2019 को मुंबई में, गेटवे हाउस, मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन में नवाचार के केंद्र (सीआईजीआई), कनाडा के बीच नवाचार, विकास और समृद्धि पर भारत-कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और व्यापार जगत के नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी, टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डोमेन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

लेटिन अमेरिका और कैरेबियन

डॉमिनिकन गणराज्य

राज्यमंत्री (वीएम) की अगस्त 2019 में डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि फरवरी, 2020 में एक प्रतिनिधिमंडल डोमिनिकन गणराज्य को भेजा जाए। यह मिशन सीआईआई से प्रस्तावित दौरे पर मंत्रालय के एलएसी/ईडी प्रभागों के संपर्क में है।

विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने 25-27 अगस्त 2019 तक डोमिनिकन गणराज्य के सैंटो डोमिंगो का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री मिगुएल ओ वर्गास से मुलाकात की और ऊर्जा मंत्री एंटोनियो ईसा कोंडे, अर्थव्यवस्था, योजना और विकास मंत्री जुआन ए जिमेनेज नुनेज और उद्योग मंत्री नेल्सन टोका सिमो के साथ विचार-विमर्श किया। उनकी यात्रा के दौरान भारत गणराज्य सरकार और डोमिनिकन गणराज्य सरकार के बीच राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं में छूट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्री महोदय ने डोमिनिकन गणराज्य में गणमान्य व्यक्तियों

और भारतीय समुदाय के एक क्रॉस सेक्शन के साथ बातचीत की। राजदूत जोस ब्लैंको उप मंत्री, द्विपक्षीय विदेश नीति डोमिनिकन गणराज्य ने आईसीसीआरएस विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 10-16 नवंबर 2019 को भारत का दौरा किया।

डोमिनिकन गणराज्य के 8 राजनयिकों के एक समूह ने 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2019 तक एफएसआई नई दिल्ली में आयोजित डोमिनिकन गणराज्य के राजनयिकों के लिए पहले विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया। डोमिनिकन गणराज्य सरकार ने 27 अगस्त 2019 को विदेश संबंध मंत्रालय, सैंटो डोमिंगो में विदेश मंत्री मिगुएल ओ वर्गास की उपस्थिति में महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया।

हैती

हैती ने 2 अगस्त, 2019 को आई.एस.ए फ्रेमवर्क समझौते (एफ.ए) पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशों के कैरीकॉम समूह के 14 नेताओं के साथ भेंट की, जिसमें 25 सितंबर, 2019को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर हैती के विदेश मंत्री एडवोकेट एडमंड भी शामिल थे। 12 से 23 अगस्त, 2019 से विदेश सेवा संस्थान नई दिल्ली में आयोजित कैरिकॉम राजनयिकों के लिए हैती के तीन राजनयिकों ने द्वितीय विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया। भारत ने दो भारतीय नागरिकों को अगस्त, 2019 में हैतियन अधिकारियों के सहयोग से हैती में अगवा किए गए दो भारतीय नागरिकों की रिहाई सफलतापूर्वक करवाई।

अर्जेंटीना

राष्ट्रपति मेक्री की फरवरी, 2019 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान गतिशीलता बनी जिसके दौरान सामरिक साझेदारी में भारत-अर्जेंटीना के संबंधों में बढ़ोत्तरी हुई थी, जो वर्ष 2019-20 में अधिक सुदृढ़ हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री,श्रीवी. मुरलीधरन ने 28-29 अगस्त, 2019 को अर्जेंटीना का दौरा किया। उन्होंने श्री जोर्ज फॉरी, विदेश मंत्री और अर्जेंटीना के उप विदेश मंत्री श्री गुस्तावों ज़्लुविनन से भेंट की और फरवरी, 2019 में राजकीय यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति पर व्यापक चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों हेतु अर्जेंटीना परिषद् में गोलमेज केंद्रित भारत के विचारकों और शैक्षणिक समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने अर्जेंटीना में भारतीय प्रवासी के साथ-साथ भारत-अर्जेंटीना व्यापार समुदाय के साथ बातचीत की।

डॉ. वी. के.सारस्वत, सदस्य नीति आयोग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें खनन और खनिज क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल थे, ने खनन क्षेत्र में भागीदारी का पता लगाने के लिए 15-19 अक्तूबर, 2019 तक अर्जेंटीना का दौरा किया। उन्होंने खनन क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और कंपनियों के साथ बैठक करने के अलावा साल्टा और जुजुय के खनिज समृद्ध प्रांतों का दौरा किया।

मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोट के नेतृत्व में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अर्जेंटीना के उप-राष्ट्रपति सुश्री गैब्रिएला मिशेती के निमंत्रण पर 6-8 जून, 2019 को अर्जेंटीना का दौरा किया। डॉ. गहलोट ने द्वितीय वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सुश्री मिशेती और अर्जेंटीना नेशनल एजेंसी फॉरडिसेबिलिटी के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें कीं। बैठकों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा विशेष रूप से जनगणना की कार्यप्रणाली और विकलांगता के वर्गीकरण के साथ-

साथ सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रशिक्षण के क्षेत्र पर केंद्रित थी।

श्री लुइस मिगुएल एचेवहेरे, एग्रोइंड इंडस्ट्रीज के राज्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई, 2019 में भारत का दौरा किया और कृषि, सहयोग और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, वाणिज्य और उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्रियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक से भेंट की। दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ाने और विविधता लाने और खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।

भारत के दूतावास, विदेश मंत्रालय तथा वरशिप ऑफ अर्जेंटीना और सी.आई.आई द्वारा ब्यूनस आयर्स में1 अक्तूबर, 2019 को संयुक्त रूप से आयोजित 'भारत-अर्जेंटीना व्यापार मंच' में 17 कंपनियों के भारतीय उद्योग (सी.आई.आई.) परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। दूतावास और भारत पर्यटन कार्यालय, न्यूयॉर्क द्वारा संयुक्त रूप से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने केलिए भारतीय टूर ऑपरेटरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 9 अक्तूबर को आयोजित 'इंडिया इवनिंग' में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने 5-8 अक्तूबर तक ब्यूनस आयर्स में लैटिन अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में भाग लिया।भारत ने ब्यूनस आयर्स में 6-7 जून, 2019 को आयोजित ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म (जीआईसीएनटी) की XIवीं पूर्ण बैठक में सहभागिता की।

अर्जेंटीना गणतंत्र की उपराष्ट्रपति महामहिम सुश्री गैब्रिएला मिशेती, दूतावास में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह में मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर उनके द्वारा 'गांधी-लैटिन अमेरिकी परिप्रेक्ष्य' पर सी.ए.आर.आई. का एक विशेष प्रकाशन जारी किया गया था। इससे पहले अर्जेंटीना पोस्ट ने महात्मा गांधी पर एक डाक टिकट जारी किया था। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती 12 नवंबर को गुरुद्वारा राम दासजी में मनाई गई और24 नवंबर को शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए सिखसंगत की पारंपरिक नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई।

बोलीविया

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा 28-30 मार्च तक दोनों देशों के बीच पहली बार की गई राजकीय यात्रा के बाद भारत और बोलीविया के साथ संबंध शुरू हुए। वर्ष 2019 में, बोलीविया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य नीति आयोग के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9-12 अक्तूबर को बोलिविया का दौरा किया और लिथियम क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विचार-विमर्श किया। इसरो द्वारा 15 अक्तूबर-15 दिसंबर, 2019 को बेंगलुरू में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम यू.एन.एन.ए.टी.आई. (यूनी स्पेस नैनो सेटेलाइट असेम्बली एंड ट्रेनिंग) में बोलिवियन स्पेस एजेंसी के दो विशेषज्ञों ने सहभागिता की।

भारत तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य और बोलीविया के लिए आयात के 16वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। अगस्त, 2019 में 28 सदस्य कंपनियों में शामिल एक फार्मेक्सिल प्रतिनिधिमंडल ने भारत द्वारा बोलीविया को दस भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) स्लॉट की पेशकश की है। योग का 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह ला पाज़, सुक्रे, कोचाबम्बा और सांता क्रूज़ में आयोजित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक अनुसन्धान परिषद् (आई.सी.सी.आर.) द्वारा प्रायोजित 3-सदस्यीय सरोद मंडली ने सितंबर, 2019 में सुक्रे में अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह और सांताक्रूज में प्रस्तुतियां दीं। भारत में 4-5 नवंबर को आई.सी.सी.आर द्वारा आयोजित लैटिन अमेरिका महोत्सव में बोलीविया की एक संगीत मंडली ने प्रदर्शन

किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, भारत सरकार की सहायता से बच्चों के पार्क की सौर प्रकाश व्यवस्था का उद्‌घाटन किया गया।

ब्राज़ील

वर्ष 2019 में ब्राज़ील के साथ भारत के द्‌विपक्षीय संबंधों में बढ़ोत्तरी होती रही। ब्रासीलिया में 13-14 नवंबर, 2019 को ब्रिक्स XIवें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील का दौरा किया। प्रधानमंत्री 13-14 नवंबर, 2019 ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र, ब्रिक्स व्यापार परिषद् के नेताओं के साथ संवाद और नए विकास बैंक में शामिल हुए। शिखर सम्मेलन के अवसर पर 13 नवंबर 2019 को एक द्‌विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से भेंट की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो को गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने निमंत्रण स्वीकार किया।

प्रधान मंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अपना प्रेस वक्तव्य देते हुए (जनवरी 2020)

प्रधानमंत्री ने 29 जून, 2019 को ओसाका में जी 20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति बोल्सोनारो के साथ भेंट की थी। दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंधों में सुधार और जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के मुद्‌दों पर चर्चा की। नेताओं ने सहयोग के क्षेत्रों के रूप में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में व्यापार और निवेश, कृषि और जैव ईंधन की पहचान की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर 25 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में ब्राजील के विदेश मंत्री श्री अर्नेस्टो हेनरिकफ्रगा अरुजो और अन्य जी4 विदेश मंत्रियों के साथ भेंट की। जी4 के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया और सुरक्षा परिषद् के शीघ्र और व्यापक सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्‌धता दोहराई। उन्होंने बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार पर चर्चा करने के

लिए ब्राजील के मंत्री विदेश श्री अर्नेस्टो हेनरिकफ्रगा अरुजो के साथग्रेस नालदे मींदिसा पिंडोर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री, दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य (आईबीएसए मीट) के साथ अलग से भेंट की।

श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 9वीं बैठक (11 नवंबर, 2019) के लिए ब्रासीलिया का दौरा किया; श्री राज कुमार सिंह, ऊर्जा मंत्री (प्रभारी) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (प्रभारी) ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की चौथी बैठक (11 नवंबर, 2019) के लिए ब्रासीलिया का दौरा किया; श्री अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक (17-18 अक्तूबर, 2019) के लिए ब्रासीलिया गए; श्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति राज्य और पर्यटन मंत्री (प्रभारी) ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की चौथी बैठक (11 अक्तूबर, 2019) के लिए कूर्टिबा का दौरा किया; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक 7वीं (20 सितंबर, 2019) के लिए कैम्पिनास का दौरा किया; श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने साओ पाओलोफ़ोर से पर्यावरण ब्रिक्स मंत्रियों की 5वीं बैठक (15 अगस्त, 2019) में शामिल होने के लिए दौरा किया; और जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक (26 जुलाई, 2019) में शामिल होने के लिए रियो डी जनेरियो का दौरा किया।

ब्राजील के विभिन्न शहरों में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रासीलिया, साओ पाउलो, पोर्टोएलेग्रे, फ्लोरियानोपोलिस और कूर्टिबा शामिल हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह के एक हिस्से के रूप में ब्रासीलिया, साओ पाउलो, रियो डी जनेरियो और बेलो होरिज़ोंटे में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया था। साओ पाओलो और ब्रासीलिया में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती क्रमश: 17-22 नवंबर, 2019 को मनाई गई। ब्रासीलिया और साओ पाउलो में 26 नवंबर, 2019 को संविधान दिवस मनाया गया और नागरिकों के कर्तव्यों पर अभियान चलाया गया।

बापू@150 के साल भर के समारोहों का समापन करते हुए दूतावास ने संघीय जिले की सरकार के सहयोग से 9 जनवरी 2020 को ब्रासीलिया के प्रतिष्ठित सिटी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की। 2020 की पहली तिमाही में साल्वाडोर शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ब्राजील की राष्ट्रपति महामहिम श्री बोलसोनारो भारत के 71 वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि थी। उन्होंने 24-26 जनवरी 2020 तक भारत का दौरा किया था। उनके साथ उनके पति, विदेश मंत्री सहित अनेक कैबिनेट स्तर के मंत्री और व्यापार प्रतिनिधिमंडल का एक दल भी था।

चिली

इस वर्ष की शुरुआत माननीय राष्ट्रपति जी श्री राम नाथ कोविंद की चिली यात्रा के साथ हुई। यह यात्रा उस वर्ष में हुई जब हम भारत-चिली राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70वें वर्ष का आयोजन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति ने 1 अप्रैल, 2019 को राष्ट्रपति सेबास्टियन पीनारैने के साथ उनकी टीम के सदस्यों और चयनित व्यापारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की, जिसके दौरान भारत-चिली संबंध के विकास के लिए फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई। इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया और हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बहुआयामी विकास को नई दिशा प्रदान की। इस अवसर पर, चिली ने 6 महीने की वैधता के साथ अमेरिकी वीजा रखने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की। यात्रा के दौरान समझौतों पर हस्ताक्षर किए; जिनमें सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर एक समझौता ज्ञापन, विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए

एक संयुक्त पत्र और भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने हेतु एक संयुक्त पत्र शामिल हैं।

अप्रैल-अक्तूबर, 2019 की द्विपक्षीय व्यापार की कीमत 1204.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर (आयात: 696.32 एमएन और निर्यात: 507.79 एमएन) थी, जोकि वर्ष 2018-19 के लिए 2,227.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार आंकड़ों के समान है। दिल्ली में 30 अप्रैल, 2019 को हुई भारत-चिली पीटीए की संयुक्त प्रशासनिक समिति के बीच दूसरे दौर की चर्चाओं के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने भारत-चिली के विस्तारित पीटीए को और गहन करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद दिसंबर 2019 में दिल्ली में पीटीए के विस्तार के लिए पहले दौर की बातचीत हुई।

चिली के पूर्व राष्ट्रपति और एशिया प्रशांत में विशेष दूत श्री एडुआर्डोफ्रेई के नेतृत्व में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भेंट की। उनके साथ व्यापार मंत्री और प्रोचिली के प्रमुख भी थे।

अगस्त, 2019 में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एस.टी.सी), भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (सीईएनएबीएएसटी), चिली के बीच भारत से चिली में कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं की आपूर्ति के लिए जी2जी तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 17-19 जून, 2019 को चिली का दौरा किया, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चिली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया। नीति आयोग के नेतृत्व में एक बहु हितधारक प्रतिनिधिमंडल ने चिली का दौरा किया और लिथियम क्षेत्र में सहयोग पर एक परिणामी चर्चा की।

चिली की संसद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का आयोजन लगातार तीसरे वर्ष जारी रहा। मिशन ने 2 अक्तूबर को, सैंटियागो में प्लाजा डे ला इंडिया में स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के पास वृक्षारोपण का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 7वीं और 8वीं कक्षा के स्कूल-बच्चों के लिए महात्मा गांधी पर निबंध प्रतियोगिता, भोजन उत्सव सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

कोलंबिया

वर्ष को भारत और कोलंबिया के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया, जिसके दौरान संबंधों को सुदृढ़ किया गया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर सितंबर, 2019 में कोलंबिया के राष्ट्रपति श्री इवान डुक मार्केज़ के साथ बातचीत की। श्री वी. मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री ने बोगोटा के माध्यम से पारगमन किया और 25 अगस्त, 2019 को भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मई, 2019 में कार्टाजेना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेटवर्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलंबिया का दौरा किया। श्री सत्येन्द्र कुमार जैन, शहरी विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने जुलाई, 2019 में मेडेलिन में 'लिवेबल सस्टेनेबल सिटीज' पर एक सम्मेलन में भाग लिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने एक अक्तूबर, 2019 में 'सामूहिक भूमि और वन अधिकारों की मान्यता' विषय पर एक सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) द्वारा अक्तूबर-दिसंबर, 2019 तक आयोजित यूनिस्पेस नेनो सेटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग में कोलंबिया के दो वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और महासचिव, एनएचआरसी, के एक प्रतिनिधि मंडल ने मेडेलिन में नवंबर, 2019 में आयोजित ग्लोबल अलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की

बैठक में भाग लिया। लाइटहाउस और महानिदेशालय के दो-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने नवंबर, 2019 में कार्टाजेना में समुद्री जोखिम प्रबंधन उपकरण के उपयोग पर एक प्रशिक्षण संगोष्ठी में भाग लिया। पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मुंबई ने नवंबर, 2019 में मेडेलिन में इंटरपोल भ्रष्टाचार-निरोध और एसेट रिकवरी ग्लोबल सम्मेलन में भाग लिया।

भारत के पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर अक्तूबर, 2018 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, आयुष मंत्रालय, भारत और कोलंबिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों के बीच मई, 2019 में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था।

भारत और कोलंबिया के बीच एक आंशिक स्कोप समझौते के लिए संयुक्त संव्यवहार अध्ययन रिपोर्ट के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने और आगे की कार्य योजना का विस्तार करने वाला पहला वीडियो सम्मेलन 9 अगस्त, 2019 को आयोजित किया गया था। मिशन ने 14 मई, 2019 को बोगोटा में "फ्यूचर के लिए वाणिज्यिक और आर्थिक गठबंधन" नामक मेगा व्यापार और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कोलंबिया के वाणिज्य, उद्योग और पर्यटन मंत्री मुख्य वक्ता थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अत्याधुनिक तकनीक में प्रगति को मान्यता देते हुए, भारत को जून, 2019 में बोगोटा में आयोजित ईएमबीडीएटीए IV (बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वर्ल्ड मीट में गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें दस भारतीय विशेषज्ञों सहित 1700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ उपस्थित थे। सिंथेटिक और रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसआरटीईपीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने जून, 2019 में मेडेलिन का दौरा किया, जो कि 'सोर्स इंडिया' 2019 को बढ़ावा देता है- जिसमे रिवर्स खरीदार विक्रेता मिलते हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (एईपीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर, 2019 में कोलंबिया में भारतीय परिधान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बोगोटा और मेडेलिन का दौरा किया। आवास और शहरी विकास मंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2019 में मोबिलिटी नेटवर्क और मास ट्रांजिट सिस्टम का अध्ययन करने के लिए मेडेलिन का दौरा किया। मिशन के सहयोग से दइंडिया टूरिज्म ऑफिस, न्यूयॉर्क ने जुलाई, 2019 में कोलंबियाई टूर ऑपरेटरों के एक नेटवर्किंग सत्र का आयोजन किया। इक्वाडोर और कोलंबिया के दो पत्रकारों ने अप्रैल 2019 में भारत की पर्यटन क्षमता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत का दौरा किया।

एसआरटीईपीसी और टेक्सप्रोसिल ने कोलंबिया टेक्स-2020, मेडेलिन में 21-23 जनवरी 2020 को आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र व्यापार संवर्धन मेले में भाग लिया। भारतीय टूर ऑपरेटरों ने भारतीय पर्यटन कार्यालय, न्यूयॉर्क के तवावधान में बोगोटा में 26-28 फरवरी 2020 से आयोजित पर्यटन संवर्धन मेले विट्रीना ट्यूरिस्टिका अनाटो में भाग लिया। फिक्की ने बोगोटा में नामस्कर पैसिफिक थीम के तहत बिजनेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनियां आदि का आयोजन किया। ईपीसीएच ने बोगोटा में 19-20 मार्च 2020 तक बीएसएम का आयोजन किया। सीआईआई के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 23-25 मार्च 2020 से बोगोटा का भी दौरा किया और व्यापार सत्रों, बी2बी और बी2जी बैठकों का आयोजन किया।

फेस्टिवल ऑफ इंडिया समारोह के हिस्से के रूप में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारत के दो नृत्य समूहों ने अप्रैल और मई, 2019में इक्वाडोर और कोलंबिया में आठ शहरों में प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मई 2019 में बोगोटा में पिलोटा विश्वविद्यालय में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। कई सेमिनार, व्याख्यान, फोटोग्राफिक प्रदर्शनियां, गैस्ट्रोनॉमी उत्सव और वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग का भी आयोजन किया गया।कोलंबिया और इक्वाडोर के विभिन्न शहरों में व्यापक भागीदारी के साथ पाँचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य पैमाने पर मनाया गया। भारतीय संस्कृति के शिक्षक द्वारा योग दर्शन और अभ्यास पर सितंबर-नवंबर, 2019 से एक कोर्सपिल्टो विश्वविद्यालय में आयोजित किया

गया था। कोलंबिया के सीनेट में नवंबर 2019 में पोषण और योग पर एक वार्ता आयोजित की गई थी। मिशन ने गुरु नानक की 550वीं वर्षगांठ और हमारे संविधान को अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

इक्वाडोर

भारत और इक्वाडोर ने वर्ष 2019 में अपने राजनायिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। भारत और इक्वाडोर के बीच एक अधिमान्य व्यापार समझौते के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के समापन के लिए एक प्रोटोकॉल अक्तूबर, 2019 में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था। भारत में इक्वाडोर के कृषि उत्पादों के निर्यात की सुविधा के लिए, राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन की एक टीम ने जून, 2019 में इक्वाडोर का दौरा किया और भारत को निर्यात के लिए इक्वाडोर की फुमिगेशन एजेंसियों को प्रमाणित किया। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई), लखनऊ ने 16-18 सितंबर 2019 को 'इक्वाडोर तट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादन के लिए एक विकल्प के रूप में नई फसलों के कार्यान्वयन' पर एक तकनीकी बैठक में भाग लिया। ओ.एन.जी.सी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2019 में तेल क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए इक्वाडोर का दौरा किया। भारत ने दिसंबर, 2019 में इक्वाडोर में 'तंबाकू उत्पादों का अवैध व्यापार' पर बैठक में भाग लिया।

मई-जुलाई, 2019 के दौरान इक्वाडोर में छह शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। रवींद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का जुलाई, 2019 में कुएनका विश्वविद्यालय में अनावरण किया गया था। कपड़ा मंत्रालय द्वारा इक्वाडोर में भारत के तीन विशेषज्ञ कारीगरों को प्रतिनियुक्त किया गया था, जहां चार सौ स्थानीय कारीगरों के साथ वस्त्र, गहने और लकड़ी की वस्तुओं के डिजाइन, नवाचार और उत्पादन में अनुभव साझा किए गए थे।

मैक्सिको

इस अवधि के दौरान, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया। भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय व्यापार 7.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 22% बढ़कर 9.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान दो-तरफा व्यापार 3.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (निर्यात 1.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 2.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर)। मेक्सिको के वैश्विक व्यापार साझेदारों में, भारत की रैंक एक वर्ष में 10 से 9 तक बढ़ी। वर्ष 2018-19 में भारत से कुल निर्यात 3.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि आयात 5.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 1.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार संतुलन मेक्सिको के पक्ष में था। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान दो तरह का व्यापार 5.44 अरब अमेरिकी डॉलर (निर्यात 2.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात) था।

विदेश मंत्री ने 28 जून, 2019 को ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर अपने मैक्सिकन समकक्ष श्री मार्सेलो एबरार्ड से भेंट की। भारत और मैक्सिको के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के 5वां दौर

का आयोजन 07 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में किया गया। मैक्सिकन संसद के चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ ने 07 नवंबर, 2019 को भारत-मेक्सिको संसदीय मैत्री समूह का उद्घाटन किया। मेक्सिको के उप विदेश मंत्री, राजदूत जूलियन वेंचुरा ने नई दिल्ली में 14-16 जनवरी 2020 तक रायसीना वार्ता 2020 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। भारत और मैक्सिको के बीच 26 फरवरी-04 मार्च 2020 को कांसुलर वार्ता आयोजित की जाएगी।

वर्ष के दौरान, मिशन ने ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (निर्माण क्षेत्र की 31 कंपनियां), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गनाइजेशन (कपड़ा क्षेत्र में 30 कंपनियां), फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 37 कंपनियां), प्लास्टिक निर्यात प्रमोशन काउंसिल (15 कंपनियां), और सिंथेटिक और रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के व्यापार प्रतिनिधिमंडल को सुविधा प्रदान की। ओयो रूम्स ने भी मैक्सिको में अपनी पहुंच बना ली है।

भारत ने 30 नवंबर-8 दिसंबर 2019 को स्पैनिश भाषी क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक मेला के 33वें संस्करण, ग्वाडलाजरा इंटरनेशनल पुस्तक मेला (एफआईएल 2019) के पहले एशियाई सम्मान के रूप में भाग लिया। इस मेले का उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने किया। नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारत से साहित्य, विज्ञान, पर्यावरण, डिजाइन और वास्तुकला, कला, संस्कृति, दर्शन और इतिहास के क्षेत्रों में 50 से अधिक लेखकों और वक्ताओं के साहित्यिक और अकादमिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत के प्रतिष्ठित लेखकों, कवियों और लेखकों ने 60 से अधिक साहित्यिक और अकादमिक कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें पैनल चर्चा और पुस्तक अनावरण शामिल हैं।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्थित भारत का एक महोत्सव, 2019 में भारत की भागीदारी के साथ मेल खाता है (i) संस्कृति मंत्रालय से 5 सांस्कृतिक समूहों द्वारा 8 सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन; (ii) आई.सी.सी.आर द्वारा भेजे गए एक नाट्य समूह द्वारा प्रदर्शन; (iii) ललितकलाअकादमीऔर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा 3प्रदर्शनियों की प्रस्तुति; (iv) भारत के दूतावास द्वारा एक फिल्म समारोह; और (v) पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक गैस्ट्रोनॉमी उत्सव। 6 अन्य शहरों मेक्सिको, ओक्साका, मैक्सिको सिटी, सैन मिगुएल डी ऑलंडे, सैन लुइस पोटोसी, क्वेरेटारो और कैनकन में भी प्रदर्शन किए गए।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए, पूरे वर्ष समारोह आयोजित किए गए। महात्मा गाँधी की एक प्रतिमा को आईसीसीआर द्वारा गुआनाजुआतो के नगरपालिका को दान कर दिया गया, जो कि विश्व धरोहर शहर है, इसे 26 अप्रैल, 2019 को स्थापित किया गया था। गुरु नानकदेव जी की 550वीं जयंती मनाई गई थी। बैसाखी अप्रैल, 2019 में भी मनाई गई थी। मेक्सिको में गुरुदेव टैगोर इंडियन कल्चरल सेंटर (सीटीआईसीसी) ने मैक्सिको के कई शहरों में 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 को सक्रिय रूप से संचालित किया। मैक्सिको सिटीकेएज़ा पोटज़ल्को नगरपालिका में एक इंडिया सप्ताह का भी आयोजन किया गया था जिसमें ज़ी मुंडो के सहयोग से एक महीने का भारतीय फिल्म महोत्सव शामिल था।

पैराग्वे

मार्च, 2019 में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के पैराग्वे दौरे के बाद भारत-पराग्वे द्विपक्षीय साझेदारी में कई मोर्चों पर प्रगति हुई। पैराग्वे 4 सितंबर, 2019 को पैराग्वे आई.एस.ए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एंटोनियो रिवास पलासेओस से न्यूयॉर्क में 26 सितंबर, 2019 को 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर भेंट की और व्यापार और निवेश, आधारिक संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और वीजा सुविधा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। विश्व पर्यटन दिवस समारोह में भाग लेने के लिएपरागुआयन की पर्यटन मंत्री सुश्री सोफियो मोंटियल डी. अफारा 27 सितंबर, 2019 को भारत आईं। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति तथा पर्यटन मंत्री से भेंट की और वीजा सुविधा के लिए नए तौर-तरीकों सहित पर्यटन में द्विपक्षीय सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। पर्यटन, वाणिज्य और आतिथ्य उद्योग में हित धारकों के बीच सहयोग और सीधे संम्प्रेषण को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पेरु

भारत और पेरू के बीच लंबे समय से मित्रतापूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को वर्ष के दौरान अधिक गति मिली। माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन की लीमाकी 22-24 अगस्त, 2019 को द्विपक्षीय यात्रा और पेरू के विदेश मंत्री के साथ उनकी व्यापक भेंट ने दोनों पक्षों को प्रमुख द्विपक्षीय क्षेत्रों में प्रगति एवं अंतर्राष्ट्रीय तथा बहुपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा पेरू कांग्रेस में एक बैठक और पेरू के प्रमुख व्यक्तित्वों के साथ बातचीत, जिसमें व्यापारिक नेताओं के साथ-साथ भारतीय समुदाय ने पेरू और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को महत्व देने में मदद की।

भारत ने लीमा में 12-14 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन (आई.एस.ए) के ढांचे के अंतर्गत सौर ऊर्जा पर 3 दिवसीय आई.एस.ए-पेरू-एल.ए.सी सन वर्ल्ड 2019 में भाग लिया। बेंगलुरु में 15 अक्तूबर-15 दिसंबर, 2019 को आई.एस.आर.ओ. द्वारा संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रम यू.एन.सी.सी.ए.टी.आई. (यूनिस्पेस नेनोसेटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग), पेरू स्पेस एजेंसी (सीओएनआईडीए) के दो विशेषज्ञों ने भाग लिया।

भारत और पेरू के बीच सहयोग तथा नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौते के अनुसरण में, भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा और खान मंत्रालय की पहली संयुक्त बैठक 20 दिसंबर, 2019 ऑनलाइन आयोजित होने वाली है। सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग, नई दिल्ली के एक भारतीय विशेषज्ञ ने 7-10 अक्तूबर, 2019 से लीमा में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर के 25वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

भारत और पेरू के बीच चल रही व्यापार वार्ता ने लीमा में 11-15 मार्च, 2019 से चौथे दौर की वार्ता के बाद और 22-22 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में पांचवें दौर की वार्ता के बाद महत्वपूर्ण प्रगति की। भारत-पेरू व्यापार समझौते पर छठे दौर की बातचीत वर्ष 2020 में लीमा में होने वाली है। फिक्की की अगुवाई में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 12-14 नवंबर, 2019 तक सन वर्ल्ड 2019 में हिस्सा लिया। आई.एस.ए. के ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में, फिक्की के उप महासचिव ने इलेक्ट्रिसिटी के वाइस मिनिस्टर से भेंट की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेलिकॉम रिसर्च एंड ट्रेनिंग

(आई.एन.आई.सी.टी.ई.एल.-यू.एन.आई.) सहित पेरू के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

एक 29 सदस्यीय फार्मेक्साइल प्रतिनिधिमंडल ने 22 अगस्त को लीमा का दौरा किया। क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य अधिकारियों और इसकी एजेंसियों से भेंट की।इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 7 अक्तूबर को लीमा का दौरा किया और बीएसएम का आयोजन किया।काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स (सी.एल.ई.) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 17-18 अक्तूबर 2019 को लीमा का दौरा किया, जिसमें 13 लेदर कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष ने 21-22 अक्तूबर, 2019 को लीमा का दौरा किया।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल की एक श्रृंखला जनवरी से मार्च 2020 के दौरान लीमा का दौरा करने के लिए निर्धारित कर रहे हैं। टेक्सप्रोसिल (कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 24 से 28 जनवरी 2020 तक लीमा का दौरा करने का कार्यक्रम है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा वार्षिक भारत मेला 11-15 मार्च 2020 तक लीमा में होना है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) 25-26 मार्च 2020 को पेरू में 40 से अधिक सदस्यों के बहु-क्षेत्र प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा।

17 सितंबर को आई.टी.ई.सी. दिवस 2019 को पेरू के गणमान्य व्यक्तियों, आई.टी.ई.सी. पूर्व विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ मनाया गया, जिसमें आई.टी.ई.सी. के पूर्व विद्यार्थियों ने भारत की क्षमता निर्माण सहायता और विकास सहयोग के अन्य रूपों की प्रशंसा की। पेरू के राजनयिक भी विदेशी सेवा संस्थान द्वारा संचालित विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) में शामिल हुए हैं।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती केउपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें महात्मा गांधी के जीवन पर वृत्तचित्रों की विशेष बातचीत और स्क्रीनिंग और पेरू में प्रमुख विश्वविद्यालयों और निकायों में मेसेज, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, एक साइकिलिंग इवेंट, 150 पेड़ों का रोपण, लीमा में एक शाकाहारी भोजन उत्सव, सैन जुआन डेमिराफ्लोरेस में एक 'शांति मार्च' शामिल थे। पेरू के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय में 14-16 मई, 2019 को महात्मा गांधी पर विशेष रूप से केंद्रित तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 को लीमा, कोरिंचा, इंका साम्राज्य के सूर्य मंदिर, कुस्को और ट्रूजिलो में मनाया गया। इसके अलावा, पेरू के स्वास्थ्य, खेल, पुलिस, नागरिक संगठनों के सहयोग से कई योग कार्यशालाएं, सेमिनार और ध्यान (मेडिटेशन) सत्र आयोजित किए गए। गुरु नानकदेव जी की 550वीं जयंती मनाने की गतिविधियाँ आयोजित की गईं। आई.सी.ए ने सितंबर में पेरू का दौरे के दौरान श्री अप्रतिम मजुमदार के नेतृत्वमें 3-सदस्यीय सरोद समूह को प्रायोजित किया और विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रस्तुतियां दी और लीमा में कार्यशालाओं का आयोजन किया। लीमा में 9 अप्रैल को आई.सी.सी.आर स्थापना दिवस मनाया गया।

पेरू स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से 23-25 अक्तूबर को लीमा में "हेल्दी एजिंग थ्रू ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ़ मेडिसिन एंड आयुर्वेद" विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यशाला के लिए आयुर्वेद के एक विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति की गई थी। भारत से आयुर्वेद विशेषज्ञ की भागीदारी के साथ 6 अक्तूबर को दूतावास में एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया।

उरुग्वे

ब्रुसेल्स में जुलाई, 2019 में विश्व सीमा शुल्क संगठन परिषद् की बैठक के दौरान भारत और उरुग्वे के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 'इंडिया-लैटिन अमेरिका बिजनेस समिट' ए.एल.ए.डी.आई (लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन) सचिवालय में 3 अक्तूबर को भारत के दूतावास और सीआईआई द्वारा ए.एल.ए.डी.आई और उरुग्वे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड सर्विसेज के सहयोग से आयोजित किया गया था। उरुग्वे सरकार ने अपनी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी किया। दूतावास ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

वेनेज़ुएला

वेनेजुएला ने 18-21 जुलाई, 2019 से काराकास में 19 वीं एन.ए.एम मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने भाग लिया। बाकू में 25-26 अक्तूबर, 2019 से 18वें एन.ए.एम शिखर सम्मेलन के अवसर पर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, महामहिम श्री निकोलस मादुरो मोरोस और भारत के उपराष्ट्रपति के साथ-साथ वेनेजुएला के विदेश मंत्री, महामहिम श्री जॉर्डन अल्बर्टो अराजामोंटेसेराट और भारत के विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई। वेनेजुएला की कार्यकारी उपाध्यक्ष महामहिम सुश्री डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज़ गोमेज़ ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी विधानसभा में भाग लेने के लिए 30 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2019 तक भारत का दौरा किया। उनके साथ वेनेजुएला के अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री, महामहिम साइमन ज़र्पाडेलगाडो थे। उन्होंने इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से भेंट की।

इस वर्ष भारत को कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ता के रूप में वेनेजुएला 9वें स्थान पर है, अक्तूबर, 2019 तक कुल आयात 3,190.10 मिलियन तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच 1 अप्रैल, 2019 से 30 अक्तूबर, 2019 तक का व्यापार 3,258.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। भारतीय निर्यात मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स थे। 5-7 दिसंबर, 2019 काराकास में चाय चखने के साथ भारतीय चाय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मिशन द्वारा 20 सितंबर, 2019 को आई.टी.ई.सी. दिवस मनाया गया। इस वर्ष, वेनेजुएला के 10 उम्मीदवारों ने मिलकर आई.टी.ई.सी. के अंतर्गतएक विशेष बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में भाग लिया। एक वेनेजुएला के राजनयिक ने विदेशी सेवा संस्थान (एफ.एस.आई.) में अक्तूबर, 2019 में विदेशी राजनयिकों (पी.सी.एफ.डी.) के 68वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लिया। वेनेजुएला के विद्यार्थी भी आई.सी.सी.आर. छात्रवृत्ति कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए साइकिलिंग इवेंट और शाकाहारी भोजन उत्सव सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वेनेजुएला में पहली बार, आई.सी.सी.आर द्वारा भेजी गई एक महात्मा गांधी की प्रतिमा को यूनिवर्सिडेड मेट्रोपोलिटन में स्थापित किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21-22 जून, 2019 और चौथा आयुर्वेद दिवस 25 अक्तूबर, 2019 को मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी 31 अक्तूबर, 2019 को मनाई गई। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर 17 नवंबर, 2019 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था और स्मारक डाक टिकट 26 नवंबर, 2019 को यूनिवर्सिड कैटालिस्का आंद्रेस बेलो (यू.सी.ए.बी), काराकस में जारी किए गए थे। भारतीय पुस्तकें 21 अक्तूबर, 2019 को यू.सी.ए.बी और 26 नवंबर, 2019 को यूनिवर्सिडेट डी काराबोबो को प्रस्तुत की गई थीं।

9 जनवरी 2020 को हिंदी दिवस के साथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वेनेजुएला की मेट्रोपोलितकर यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन मार्च 2020 में किया जाएगा।

मध्य अमरीका

बेलीज़

बेलीज के साथ भारत के संबंध निरंतर महत्व प्राप्त करते रहे। इस वर्ष, बेलिजियन राजनयिक ने 68वें पी.सी. एफ.डी में भाग लिया और दो बेलिजियन राजनयिकों ने कैरिकॉम राजनयिकों के लिए द्वितीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। ऑरेंज वॉक, बेलीज में इस वर्ष महात्मा गांधी संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया था, जहां भारत सरकार द्वारा 50 कंप्यूटर दान किए गए हैं। बेलिज विश्वविद्यालय में एक भारत बेलीज सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की जा रही है। भारत ने वर्ष 2018-19 में, 16.98 मिलियन अमेरिकी डालर के माल का निर्यात किया और 0.65 मिलियन अमेरिकी डालर का माल आयात किया। वर्ष 2018-19 में कुल व्यापार 17.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष में 14.84 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 18.86% हो गया। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान दोनों तरफ का व्यापार 10.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर (निर्यात 9.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 0.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 के भाग के रूप में, बेलीज में 8 शहरों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

कोस्टा रिका

कोस्टा रिका की उप विदेश मंत्री सुश्री लोरेना अगुइलर रेवलो ने 7-9 सितंबर, 2019 को भारत का दौरा किया और यू.एन.सी.सी.डी. के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन (सीओपी14) में भाग लिया। भारत से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने प्रीकॉप 25 बैठक में भाग लेने के लिए कोस्टा रिका के 8-11 अक्तूबर, 2019 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। माननीय उपराष्ट्रपति की कोस्टा रिका की यात्रा के बाद, एम.ई.ए. ने वर्ष 2019-20 में कोस्टा रिका के आई.टी.ई.सी. स्लॉट को 40 कर दिया। अप्रैल-सितंबर 2019 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार का कारोबार 140.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर था (भारत का निर्यात 97.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 43.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर था)

अल साल्वाडोर

वर्ष 2019-20 में अल सल्वाडोर के साथ भारत के संबंधों में अधिक वृद्धि देखी गई। अल सल्वाडोर ने जून, 2018 में आई.एस.ए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और नवंबर, 2019 में आई.एस.ए की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की।

वाणिज्यिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार हुआ। भारत के पक्ष में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा वर्ष 2018-19 के दौरान 82.86 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान शेष व्यापार 39.19 अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2018-19 के दौरान ऑटोमोबाइल (दो और तीन

पहिया) का भारतीय निर्यात 17.93 अमेरिकी डॉलर था,जबकि कपड़ा और संबद्ध उत्पाद 13.32 अमेरिकी डॉलर थाऔर फार्मास्यूटिकल उत्पाद 13.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 23 जून 2019 को प्लाजा सल्वाडोर डेलमुंडो में किया गया था और इसमें अल साल्वाडोर के संस्कृति मंत्री ने भाग लिया था। आई.सी.सी.आर द्वारा प्रायोजित 4-सदस्यीय जुगलबंदी इंस्ट्रूमेंटल ग्रुप ने मई, 2019 में सांता एना के राष्ट्रीय रंगमंच और सैन सल्वाडोर के राष्ट्रीय रंगमंच पर अल सल्वाडोर के राष्ट्रीय लोकगीत बैले के सदस्यों के साथ प्रस्तुतियां दीं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वार्षिक समारोह के हिस्से के रूप में सैन साल्वाडोर के होटल क्राउन प्लाजा में एक शाकाहारी उत्सव समारोह का आयोजन किया गया था।

ग्वाटेमाला

वर्ष 2019-20 में ग्वाटेमाला के साथ भारत के संबंध और सुदृढ़ हुए। दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक मोर्चे पर व्यापार संबंधों में सुधार हुआ।वर्ष 2018-2019 के दौरान भारत के पक्ष में द्विपक्षीय व्यापार 321.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान शेष व्यापार 148.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ऑटोमोबाइल का भारतीय निर्यात वर्ष 2018-2019 के दौरान 90.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि कपास का निर्यात 52.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर और फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्यात 42.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारत के दूतावास ने केरल के फोकस के साथ स्टेट्स डे 2019 मनाया। यह आयोजन गैलीलियो विश्वविद्यालय, ग्वाटेमाला के साथ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। आयोजन का मुख्य विषय केरल और आयुर्वेद को बढ़ावा देना था। वेस्टेक्स (एसोसिएशन ऑफ अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्वाटेमाला) ने 14-16 मई, 2019 तक ग्वाटेमाला सिटी में एक परिधान सोर्सिंग शो का आयोजन किया, जहां टेक्सप्रोसिल ने भाग लिया। भारतीय मंडप 400 से अधिक आगंतुकों का साक्षी बना। रेमंड्स और वेलस्पन जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों ने शो में भाग लिया।

जून, 2019 में, दो व्यापार प्रतिनिधिमंडल; स्रोत भारत 2019 को बढ़ावा देने के लिए भारत और एसआरटीईपीसी में सेरेमिक्स एक्सपो में सेरामिक्स से एक ने ग्वाटेमाला का दौरा किया। टेक्सटाइल कंपनियों के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अर्थव्यवस्था मंत्री श्री टोनी मलौफने 21-23 अगस्त, 2019 तक मुंबई में सोर्स इंडिया 2019 शो में किया। फार्मास्यूटिकल एक्सपो आईपीएचएक्स 2019 में भाग लेने के लिए ग्वाटेमाला की दवा कंपनियों के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-12 जून, 2019 को गुजरात का दौरा किया।

भारत के दूतावास ने 2-3 नवंबर, 2019 कोकेवला, ग्वाटेमाला सिटी में'नमस्ते इंडिया: डोर टू ऑपर्चुनिटीज' एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह ग्वाटेमाला में एक भव्य पैमाने पर आयोजित किया गया पहला भारतीय त्योहार था और भारतीय व्यापार, संस्कृति और भोजन पर केंद्रित था। अर्थव्यवस्था-नामित मंत्री, श्री टोनीमलौफ ने दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें अनुमानित 6000 आगंतुकों ने दौरा किया।

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ई.ई.पी.सी) के नेतृत्व में 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने फेरेट एक्सपो 2019 के लिए 7-12 नवंबर 2019 तक ग्वाटेमाला और होंडुरास की कंपनियों को शामिल किया। एक समर्पित भारत मंडप में पावर सेक्टर से भागीदारी, चीनी उद्योग के लिए उपकरण, टूल्स, हार्डवेयर और निर्माण से संबंधित उपकरण, ऑटो कम्पोनेंट्स और निर्माण सामग्री शामिल थीं। यह पहली बार था जब इंजीनियरिंग कंपनियों के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने मध्य अमेरिका का दौरा किया। एक्सपो में भाग लेने के

अलावा, कंपनियों ने ग्वाटेमाला और व्यापार संगठनों और एसोसिएशन्स में कंपनियों के साथ बी 2 बी बातचीत की थी।

ग्वाटेमाला को वर्ष 2019-2020 के लिए 40 आईटीईसी स्लॉट की पेशकश की गई है। आई.सी.सी.आर द्वारा प्रायोजित 4-सदस्यीय जुगलबंदी वाद्य समूह ने संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में 2-9 मई, 2019 तक आयोजित कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने के लिए ग्वाटेमाला का दौरा किया। आई.सी.सी.आर मंडली ने ग्वाटेमाला में प्रस्तुति दी और प्रमुख विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संरक्षक में कार्यशालाएं आयोजित की। पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, एंटीगुआ सिटी, सेंट कैथलीना आर्क के सबसे प्रमुख स्थान और प्रतिष्ठित स्थल एंटीगुआ में मनाया गया। संस्कृति और खेल मंत्रालय द्वारा प्रबंधित सबसे प्रमुख खेल सुविधाई एल कैम्पोमार्टे में 23 जून को ग्वाटेमाला सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। समारोह में लगभग 400 व्यक्तियों ने भाग लिया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति-इलेक्ट डॉ. एलेजांद्रो जियामातेटी के साथ विदेश मंत्री नामित श्री पेड्रो बोरलों ने 2 अक्तूबर 2019 पर ग्वाटेमाला सिटी में भारत के दूतावास का दौरा किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। वर्ष के दौरान साइकलिंग, मूर्तिकला, वृक्षारोपण, विश्वविद्यालयों की यात्रा सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सुश्री रिगोबर्टा मेन्चु के साथ साझेदारी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

ग्वाटेमाला के विदेश मंत्रालय में और सैन कार्लोस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में और भारत द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों के साथ राफेल लैंडिवर विश्वविद्यालयमें एक इंडिया कॉर्नर की स्थापना कीगई थी। दूतावास ने 19-25 सितंबर, 2019 तक एक भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जिसमें स्पेनिश उप-शीर्षकों वाली 7 बॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई।

होंडुरास

वर्ष 2019-20 के दौरान होंडुरास के साथ संबंध लगातार सुदृढ़ हुए। व्यापार संबंधों में वाणिज्यिक मोर्चे पर काफी वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2018-2019 के दौरान भारत के पक्ष में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा 184.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान शेष व्यापार 102.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2018-2019 के दौरान कपड़ा और संबद्ध उत्पादों का भारतीय निर्यात 62.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि ऑटोमोबाइल (दो और तीन पहिया) 28.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और दवा उत्पाद 23.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

18 कंपनियों वाले इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ई.ई.पी.सी) के नेतृत्व में 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने क्रेता विक्रेता प्रतियोगिता के लिए 11-12 नवंबर, 2019 तक सैन पेड्रो सुला, होंडुरास का दौरा किया। होंडुरास के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री मारियोकफती सम्मानित अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक व्यापारिक बैठकें आयोजित की गईं। सांस्कृतिक मोर्चे पर, दूतावास, होंडुरास की सरकार के साथ मिलकर होंडुरास में स्थित कोपैन के प्रसिद्ध खंडहर हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर पाँचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महामहिम होंडुरास के आर्थिक विकास मंत्री श्री अर्नाल्डो कैस्टिलो; और विदेश व्यापार मंत्री, सुश्री अलेजांद्रा चांग और पर्यटन निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने भाग लिया। भारत ने वर्ष 2019-2020 के लिए होंडुरास को 35 आई.टी.ई.सी स्लॉट की पेशकश की है।

निकारागुआ

निकारागुआ के विदेश मंत्री, श्री डेनिसमोनकाडा कोलिंड्रेस ने 28 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली का दौरा किया और विदेश मंत्री से भेंट की। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत सरकार ने निकारागुआ के नई दिल्ली में निवासी मिशन को खोलने और एक रेजीडेंट राजदूत नियुक्त करने के निर्णय का स्वागत किया।

सुश्री सोनिया कास्त्रो गोंजालेज, निकारागुआ के स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली का दौरा किया और 30 जुलाई, 2019 को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से भेंट की और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की।

आवंटित आई.टी.ई.सी स्लॉट के इष्टतम उपयोग के साथ वर्ष 2019-20 में निकारागुआ के स्लॉट को 10 तक बढ़ा दिया गया है। अप्रैल-सितंबर, 2019 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार का कारोबार 34.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर था (भारत का निर्यात 32.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 2.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर था)।

पनामा

भारत को उन प्रमुख 7 देशों की सूची में शामिल किया गया है, जिनके साथ पनामा की सरकार ने राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिज़ो के नेतृत्व में अपने संबंधों को सुदृढ़ करना है। द्विपक्षीय निवेश संबंधों को बढ़ावा तब मिला जब अक्तूबर, 2019 में पनामा के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निदेशक श्री रिचर्ड किलबर्न के नेतृत्व में भारत का दौरा किया। नई दिल्ली में एक व्यावसायिक सम्मेलन आयोजित करने के अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई और पुणे का भी दौरा किया, जहां अखिल भारतीय उद्योग संघ के सहयोग से व्यापारिक समुदाय के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

कैरिबियन देश

एंटीगुआ और बारबुडा

भारत और एंटीगुआ और बारबुडा के भवय और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। दोनों देशों ने 17 सितंबर को राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता की छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एंटीगुआ और बारबुडा के फार्मास्यूटिकल नियामक अधिकारियों ने हैदराबाद में 19 और 20 सितंबर, 2019 को फार्मेक्साइल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की बैठक में भाग लिया।

भारत ने आई.टी.ई.सी कार्यक्रम के अंतर्गत 5 स्लॉट के साथ एंटीगुआ और बारबुडा को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना जारी रखा है। एंटीगुआ विदेश मंत्रालय के दो राजनयिकों ने 12-23 अगस्त, 2019 से नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान में कैरिकॉम राजनयिकों के लिए द्वितीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। भारत ने 23 जून, 2019 को एंटीगुआ और बारबुडा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया।

बहामास

भारत सरकार ने तूफान डोरियन के बाद राहत के रूप में बहामास सरकार को एक आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की। आपदा के रूप में सबसे बड़ा तूफान बहामास से टकराया था, जिसे प्रधानमंत्री डॉ. ह्यूबर्ट मिननिस द्वारा एक 'ऐतिहासिक त्रासदी' के रूप में संदर्भित किया गया था। सितंबर, 2019 में इंडिया-कैरिकॉम नेताओं की बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री मिनिस ने प्रधानमंत्री से भेंट की।

बारबाडोस

बारबाडोस और भारत करीबी और सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लेते हैं और संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल और एन.ए.एम में सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं। न्यूयॉर्क में 25 सितंबर, 2019 को पहली बार इंडिया-कैरिकॉम राष्ट्राध्यक्ष/सरकारी स्तर पर बातचीत ने द्विपक्षीय संबंधों को अधिक बढ़ावा दिया है। बारबाडोस ने एकतरफा रूप से भारत को उन देशों की सूची में रखा है जिनके नागरिकों को जून, 2019 से प्रभावी बारबाडोस जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। विकास भागीदारी में, "लोकल कंटेंट डेवलपमेंट" प्रोजेक्ट को भारत-यूएनडीपी निधि के अंतर्गत लागू किया जाना था। वर्ष 2019 में बारबाडोस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और गुरु नानकदेव जयंती का आयोजन किया गया।

क्यूबा

क्यूबा के उप स्वास्थ्य मंत्री, अल्फ्रेडो गोंजालेज ने पारंपरिक चिकित्सा के विभिन्न तरीकों के आवेदन पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया और जून, 2019 में आयुष मंत्रालय के सचिव के साथ बैठकें कीं। हवाना में 7 नवंबर, 2019 को उप राष्ट्रपति रॉबर्टो मोरालेस ओजेडा की उपस्थिति में एक आयुर्वेद केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अंग के रूप में आयुर्वेद अपनाने के बाद क्यूबा दुनिया का पहला देश है। क्यूबा में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, 4 यू.एस.डी. के इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट (एल.ओ.सी.) द्वारा वित्त पोषित सिएनफ्येगोस में एन.पी.के नाइट्रोजिनाइज्ड फर्टिलाइजर कारखानाने जुलाई, 2019 में उत्पादन शुरू किया। कारखाने में प्रतिवर्ष 300,000 टन उत्पादन करने की क्षमता है, जिसके साथ इसकी राष्ट्रीय मांग के 70 प्रतिशत को पूरा करने की आशा है।

क्यूबा कोरलोस डी क्यूबा की डाक एजेंसी ने 4 सितंबर, 2019 को 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का शुभारंभ किया। एक क्यूबा कूटनीतिज्ञ ने विदेशी सेवा संस्थान (एफ.एस.आई.) नई दिल्ली में आयोजित विदेशी राजनयिकों (पीसीएफडी), 2019 के लिए 68वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लिया। सीईसीएमईडी के प्रमुख, क्यूबा के फार्मास्युटिकल नियामक निकाय ने 19-20 सितंबर, 2019 को हैदराबाद, भारत में आयोजित फार्मेक्सिल के अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की बैठक में भाग लिया।

वर्ष 2020 भारत-क्यूबा राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का प्रतीक है। यह मिशन भारत-क्यूबा संबंधों की 60 वीं वर्षगांठ के सिलसिले में समारोह की योजना बना रहा है।

डोमिनिका

वर्ष के दौरान भारत और डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के बीच द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत डोमिनिका से 10 आईटीईसी विद्वानों को भारत भेजा गया था।

ग्रेनाडा

ग्रेनाडा के विदेश एवं श्रम मंत्री श्री पीटर डेविड ने सितंबर, 2019 में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री के साथ भेंट की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी के साथ 12 सितंबर, 2019 को एक बैठक की। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 4 आई.टी.ई.सी विद्वानों को ग्रेनाडा से भारत भेजा गया। कैरिकॉम राजनयिकों के लिए द्वितीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रेनाडा के एक प्रतिभागी ने 12-23 अगस्त, 2019 को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

गुयाना

विदेश मंत्री ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. करेन कमिंग्स से भेंट की और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. कमिंग्स के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की तर्ज पर न्यूयॉर्क में कैरिकॉम देशों के 13 अन्य नेताओं के साथ 25 सितंबर, को भेंट की।

गुयाना के वित्त मंत्री, विंस्टन जॉर्डन और बैंक ऑफ गुयाना के गवर्नर डॉ.गोबिन गंगा ने 25-29 नवंबर, 2019 को भारत का दौरा किया और भारतीय रिजर्व बैंक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। गवर्नमेंट एनालिस्ट फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट (जीए-एफडीडी) के निदेशक श्री मार्लोन कोल और फार्मेसी के निदेशक श्री वनिल एटकिन्स ने 18-19 फरवरी, 2019 को बेंगलुरु में फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। श्री मार्लोन कोल सितंबर, 2019 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की बैठक में भी शामिल हुए। गुयाना ऊर्जा एजेंसी के सीईओ डॉ. महेन्द्र शर्मा ने 31 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में द्वितीय आई.एस.ए महासभा में भाग लिया। गुयाना ने सितंबर, 2019 को आई.एस.ए के संशोधित संरचना समझौते की पुष्टि की।

गुयाना-इंडिया बिजनेस चैंबर के एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल, जिसमें खनन, बिजली उत्पादन, चीनी उद्योग, कृषि, निर्माण इत्यादि कंपनियां शामिल थीं, ने व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 3 सितंबर से 4 अक्तूबर को गुयाना का दौरा किया।ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड ने 20-22 नवंबर, 2019 तक जॉर्ज टाउन में द्वितीय वार्षिक गुयाना इंटरनेशनल पेट्रोलियम बिज़नेस समिट एंड एक्ज़िबिट (जीआईपीईएक्स-2019) में भाग लिया।

राष्ट्रपति डेविड ग्रेंजर ने5 मई, 2019 को पूर्वी बर्बिस के पालमायरा में भारतीय आगमन स्मारक (इंडियन अराइवल मोनुमेंट) की स्थापना की, जिसे भारत सरकार द्वारा उपहार में दिया गया था। भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के अंतर्गत कार्यान्वित "गुयाना में किशोर गर्भावस्था को कम करने" के लिए 7 जून, 2019 को गुयाना के जन स्वास्थ्य मंत्री, सुश्री वोल्डालॉरेंस ने परियोजना शुरू की। राष्ट्रपति ग्रेंजर ने 20 जून को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन

टेक्नोलॉजी (सीईआईटी) में उत्कृष्टता का उद्घाटन किया, जिसकी स्थापना 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से की गई है।

आई.टी.ई.सी के अंतर्गत नवंबर, 2019 तक भारत में गुयाना के 17 नागरिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारत ज्ञान कार्यक्रम(के.आई.पी) और प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना (पी.टी.डी.वाई) के अंतर्गत 35 गुयानी और हिंदी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2 ने भारत का दौरा किया। गुयाना को राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9 और सांस्कृतिक / शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत 2 स्लॉट आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली में विदेशी सेवा संस्थान (एफ.एस.आई)द्वारा12-23 अगस्त, 2019 तक आयोजित किए गए कैरिकॉम राजनयिकों के लिए द्वितीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुयाना के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ विदेश सेवा अधिकारी ने भाग लिया। गुयाना के एक राजनयिक ने 16 सितंबर-11 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री संस्थान द्वारा आयोजित किए गए 68वें विदेशी राजनयिकों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम (पी.सी.एफ.डी) में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जॉर्ज टाउन में 16 जून को गुयाना में और 23 जून, 2019 को बर्बिस में प्रतिष्ठित इंडियन अराइवल मोनुमेंट में किया गया।

नारियल उद्योग में नारियल के विभिन्न उपयोगों/ उपउत्पादों और भारत में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी और तकनीकों के बारे में गुयानीज को एक्सपोजर प्रदान करने के लिए भारतीय नारियल विकास बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने गुयाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जॉर्जटाउन में सौर ऊर्जा और ई-वाहनों पर भारत केंद्रित व्यापार संवर्धन कार्यक्रम मार्च 2020 में आयोजित किया गया था जिसमें संबंधित वाणिज्यिक संघों/संगठनों, ईपीसी, भारतीय निर्यातकों और निर्माताओं, सार्वजनिक सेवा उपक्रमों, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नियामक निकायों, राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा संबंधित क्षेत्र में भारत की भागीदारी की गई थी।

जमैका

इस अवधि के दौरान, भारत और जमैका ने विगत वर्षों में बने सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध जारी रहे। भारत ने नई दिल्ली में अपना उच्चायोग खोलने के जमैका के फैसले का भी स्वागत किया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस सितंबर, 2019 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को श्रंद्धाजलि अर्पित करने वाले पांच वैश्विक नेताओं में से एक थे। प्रधानमंत्री होल्नेस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ न्यूयॉर्क में पहली बार इंडिया-कैरिकॉम नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी भेंट की।

जमैका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए) में शामिल हो गया और 30-31 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में आई.एस.ए की द्वितीय असेम्बली में भाग लिया। वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई, जो 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। किंग्स्टन में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 20 जून, 2019 को आयोजन किया गया। मिशन ने गांधी जयंती और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई। 4 नवंबर, 2019 को आई.टी.ई.सी दिवस मनाया गया।

सैंट किट्स एंड नेविस

सेंट किट्स और नेविस 31 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में आई.एस.ए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए। 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयॉर्क में पहली भारत-कैरिकॉम नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री ने 14 कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं से भेंट की,

जिसमें सेंट किट्स और नेविस के प्रधानमंत्री, डॉ. टिमोथी हैरिस शामिल थे।

23 जून, 2019 को सेंट किट्स एंड नेविस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सेंट किट्स और नेविस को 5 आई.टी.ई.सी .स्लॉट आवंटित किए गए हैं। सेंट किट्स और नेविस के दो राजनयिकों ने 12-23 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में विदेशी सेवा संस्थान (एफ.एस.आई) द्वारा आयोजित कैरिकॉम राजनयिकों के लिए द्वितीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। सेंट किट्स और नेविस के एक राजनयिक ने सितंबर, 2019 से नई दिल्ली में विदेशी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 68वें पी.सी.एफ.डी में भाग लिया।

सेंट लूसिया

भारत के सेंट लूसिया के साथ घनिष्ठ, हार्दिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत सरकार ने सेंट लूसिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को अधिक सुदृढ़ करने के लिए उच्चतम स्तर पर सहभागिता बढ़ाने के लिए नई पहल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और कैरीकॉम के नेताओं के बीच पहली मुलाकात 25 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर अपने समकक्ष प्रधानमंत्री एलेन चेस्टरनेट से भेंट की। सेंट लूसिया के कृषि मंत्री ने सितंबर, 2019 में नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सी.सी.डी सम्मेलन में भाग लिया। सेंट लूसिया ने वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की। भारत-यूएनडीपी निधि के अंतर्गत, सेंट लूसिया की सीमांत युवा परियोजना के लिए कौशल प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य बढ़ईगीरी और जुड़ाव में युवाओं को पहचानने और प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और उन्हें 992,724 अमेरिकी डॉलर के लिए नौकरी प्रशिक्षण के साथ उनकी सहायता करना जारी है।

सैंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस

सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस (एस.वी.जी) के प्रधानमंत्री माननीय डॉ.राल्फ ई.गोंसाल्विस ने 8-12 सितंबर, 2019 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह एस.वी.जी से भारत की पहली आधिकारिक स्तर की यात्रा है। प्रधानमंत्री एस.वी.जी ने अपने भारतीय समकक्ष से भेंट की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और i) राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा की छूट, ii) आई.एस.ए फ्रेमवर्क समझौता, और iii) पारंपरिक चिकित्सा पद्धित समझौता ज्ञापनों(एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित राष्ट्राध्यक्षों/सरकार के प्रमुखों की इंडिया कैरिकॉम बैठक के दौरान दोनों नेताओं की पुन: मुलाकात हुई। त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यू.आई.पी) के कार्यान्वयन पर एक रूपरेखा समझौता ज्ञापन पर 13 नवंबर, 2019 को राजदूत और एसवीजी के प्रधानमंत्री द्वारा एसवीजी में हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत ने वर्ष 2019-20 के लिए एसवीजी को 5 आईटीईसी स्लॉट प्रदान किए हैं। कैरिकॉम राजनयिकों के लिए जून, 2019 में आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक एसवीजी विदेश सेवा अधिकारी ने पीसीएफडी और तीन विदेशी सेवा अधिकारियों ने भाग लिया। एसवीजी के दो वरिष्ठ स्तर के सीमा शुल्क अधिकारियों ने आई.टी.ई.सी के अंतर्गत 10-14 जून, 2019 को भारत में आयोजित सीमा शुल्क और कर पर भारत-कैरिकॉम विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। 1 जून, 2019 को भारतीय आगमन दिवस मनाने के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री माननीय डॉ. राल्फ ई. गोंसाल्व्स मुख्य अतिथि थे।

सूरीनाम

सूरीनाम के उपराष्ट्रपति, श्री अश्विन अधिन 25 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत-कैरिकॉम लीडर्स बैठक में शामिल हुए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। अपने सूरीनाम के समकक्ष के साथ 26 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री की बैठक और दिल्ली विश्वविद्यालय और लवली व्यावसायिक विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर सितंबर, 2019 में सूरीनाम के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बनाने में योगदान दिया।

सूरीनाम के चुनाव आयोग के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-13 मई, 2019 को भारत के चुनाव आयोग के आगंतुक चुनाव कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दौरा किया; दो अधिकारियों ने आई.टी.ई.सी के अंतर्गत जून, 2019 में आयोजित कैरिकॉम के वरिष्ठ-स्तरीय सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता की; और पांच राजनयिकों ने जून, 2019 में एफ.एस.आई द्वारा आयोजित इंडिया-कैरीकॉम विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। गुजरात के गांधीनगर में 10-12 जून, 2019 को आयोजित फार्माक्साईन प्रतियोगिता में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

विकास सहयोग साझेदारी के अंतर्गत, डेमेलकैंट्रेल, एन.वी., मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के उन्नयन और पुनर्वास के लिए 11.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन (एल.ओ.सी.) का अनुबंध 25 मई, 2019 को हस्ताक्षरित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति की जून, 2018 में ऐतिहासिक यात्रा के दौरान महिला उद्यमिता के लिए दो लघु अनुदान परियोजनाओं में से एक नामत:गार्डन ऑफ पालम्स में क्राफ्ट मार्केट, परमारिबो की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त, 2019 को इसका उद्घाटन किया गया तथा इसे पूरा किया गया। सूरीनाम के दो विद्यार्थी हिंदी सीखने के लिए वर्ष 2019 में केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा आए।आई.सी.सी.आर छात्रवृत्ति वर्ष 2019-20 के अंतर्गत, दो विद्यार्थी भारत में पढ़ रहे हैं और एक विद्यार्थी आयुष छात्रवृत्ति के अंतर्गत अध्ययनरत है। एक सूरीनामी नागरिक सुश्री प्रिसेला बिस्पम, ने आई.सी.सी.आर द्वारा प्रायोजित विदेशी श्रेणी के अंतर्गत कुंभ मेला 2019 में सहभागिता की।

ट्रिनिडाड और टोबैगो

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी) कार्यक्रम के अंतर्गत, त्रिनिदाद और टोबैगो (टी एंड टी) द्वारा 33 आईटीईसी स्कॉलर्स का लाभ उठाया गया था। भारत की संस्कृति, इतिहास को जानने के लिए भारत कार्यक्रम (के.आई.पी) के अंतर्गत टी एंड टी के प्रतिभागी भारत आए हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन के 7 प्रतिभागियों ने 22 नवंबर-8 दिसंबर 2019 तक तृतीय प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत भारत का दौरा किया, जबकि एक व्यक्ति ने वर्ष 2019-20 के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति प्राप्त की।

पांचवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 16 जून, 2019 को चगुरमास बोर्ड वॉक में आयोजित किया गया था जहां लगभग 300 लोगों ने योग अभियान में भाग लिया। 108 सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 23 जून, 2019 को आयोजित किए गए थे। 29 जून, 2019 को योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चगुरमास बोर्ड वॉक में 16 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में एक शाकाहारी खाद्य मेले का आयोजन किया गया था। त्रिनिदाद के 05 विद्यार्थी अकादमिक वर्ष अगस्त, 2019 - मई, 2020 में केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी अध्ययन कर रहे हैं। यहं पर हिंदी दिवस मनाया गया जहां महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम 'कला संध्या' का आयोजन किया गया था।

गांधी शांति पार्क में 2 अक्तूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी जिसके मुख्य अतिथि पोर्ट ऑफ स्पेन के मेयर श्री जोएल मार्टिनेज थे। गांधी की जयंती वर्ष के दौरान समारोह में ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, साइकिल रैली और पौधारोपण का आयोजन किया गया था। चगवानस में 12 अक्तूबर, 2019 को महात्मा गांधी की प्रतिमा (बस्ट) का उद्घाटन किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्बन जीरो इनिशिएटिव के सहयोग से 5 जून, 2019 कोचगवानस में एक समारोह आयोजित किया गया था।

भारत-राष्ट्रमंडल युवा क्रिकेट कोचिंग कैंप (1- 30 अक्तूबर, 2019) के अंतर्गत, तीन टी.एंड.टी (अंडर-16) युवाओं को क्रिकेट कोचिंग के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बैंगलोर भेजा गया। भारतीय उच्चायोग ने 15 नवंबर, 2019 को सैन फर्नांडो में एक 'भारत को जानो संगोष्ठी' की मेजबानी की। आई.सी.सी.आर द्वारा प्रायोजित 8 सदस्यीय मयूरभंज छऊ मंडली ने 28 नवंबर - 5 दिसंबर, 2019 तक टी.एंड.टी का दौरा किया और पूरे त्रिनिदाद में प्रस्तुतियां दी।

क्षेत्रीय संगठन

कैरीकॉम

कैरेबियन समुदाय (कैरिकॉम) के साथ भारत के सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ-साथ कैरिकॉम सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ न्यूयॉर्क के कैरिकॉम देशों के 14 नेताओं के साथ मुलाकात की। यह इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्तर की पहली चर्चा है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कैरिकॉम के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को सुदृढ़ करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और क्षमता निर्माण, विकास प्रबंधन और आपदा प्रबंधन और लचीलापन (रेजिलिएंस) में सहयोग में कैरिकॉम देशों के साथ भागीदारी पर जोर दिया। कैरिकॉम देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए) में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए, प्रधानमंत्री ने 14 कैरिकॉम देशों के लिए त्वरित प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान और सौर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मौजूदा भारत-वित्त पोषित केंद्रों को उन्नत करके जॉर्जटाउन में आईटी में एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र, और बेलिज़ में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से क्षमता निर्माण सहायता और भारत में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे की भी घोषणा की।

भारत ने वर्ष 2019 में, 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान करके गुयाना में कैरिकॉम सचिवालय और बारबाडोस और जमैका के कार्यालयों में आई.सी.टी. आधारिक संरचना और संबंधित सॉफ्टवेयर को उन्नत करने के लिए कैरिकॉम की सहायता की। कैरिकॉम देशों के क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कैरेबियन विकास निधि में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया।

सदस्य देशों को प्रदान किए गए स्लॉट से स्वतंत्र, आई.टी.ई.सी. की पांच सीटें वार्षिक कैरिकॉम सचिवालय के लिए हैं। विदेश सेवा संस्थान द्वारा कैरिकॉम राजनयिकों के लिए अगस्त, 2019 में नई दिल्ली में द्वितीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैरेबियाई पब्लिक हेल्थ एजेंसी (सीएआरपीएचए)

के फार्मास्युटिकल नियामक अधिकारियों ने हैदराबाद में 19-20 सितंबर, 2019 को फार्मेक्साइल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की बैठक में भाग लिया।

मर्कोसुर

भारत और मर्कोसुर(ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे के सीमा शुल्क संघ)ने सितंबर, 2019 में भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार के लिए विचार-विमर्श करने के लिए सहमति व्यक्त की।

पेसिफिक गठबंधन

भारत ने लीमा में 5 जुलाई, 2019 को आयोजित पेसिफिक गठबंधन (पी.ए) के 14वें शिखर सम्मेलन में ऑब्जर्वर स्टेट्स सेगमेंट में भाग लिया। भारत ने पेसिफिक गठबंधन द्वारा अपनाए गए 'प्लास्टिक के सतत प्रबंधन पर घोषणा' का समर्थन किया। भारत ने नवाचार तथा विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक पहुंच, निवेश और इन्वेस्ट इंडिया से एसएमई, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से पांच प्रस्ताव पेश किए; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जलवायु परिवर्तन, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, आईटीईसी के अंतर्गत सी-डैक से प्रकाशन क्षेत्र के विकास के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर तकनीकी सहयोग, और आईटीईसी से पी.ए सदस्य राष्ट्रों के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रबंधन (राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान से) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति पर प्रस्ताव पेश किए गए।

भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद, चिली गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री सेबेस्टियन पिनेरा के साथ 01 अप्रैल, 2019 को चिली गणराज्य में ला मोनेदा प्रेसिडेंशियल पैलेस, सैंटियागो में एकांतिक मुलाकात करते हुए

सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधान मंत्री, डॉ. राल्फ एवराई गोंसाल्विस, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में 10 सितंबर, 2019 को मुलाकात करते हुए

न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया-कैरिकॉम लीडर्स मीटिंग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। माननीय प्रधान मंत्री ने बैठक में शामिल सम्मानित विश्व राजनेताओं को धन्यवाद दिया। भारत इस ग्रह को बेहतर बनाने के लिए कैरिबियन में अपने दोस्तों के साथ काम करने के लिए उत्सुक है।

विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने अगस्त 2019 में डोमिनिकन गणराज्य की अपनी यात्रा के दौरान डोमिनिकन रिपब्लिक के विदेश मंत्री, महामहिम श्री मिगुइल वर्गास के साथ एक रचनात्मक बैठक की।

9

बिम्सटेक, सार्क और नालंदा

सार्क

विदेश मंत्री ने 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर आयोजित सार्क मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत ने अपनी "पड़ोस प्रथम नीति" के अंतर्गत पड़ोस की समृद्धि को बहुत महत्व दिया है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि सार्क की समस्याएं केवल खोए हुए अवसरों की एक कहानी नहीं थी, बल्कि इनमें जानबूझकर डाली जाने वाली बाधाएं भी शामिल हैं, आतंकवाद के उनमें से एक होने के नाते और सभी रूपों में आतंकवाद को समाप्त करना केवल फलदायी सहयोग के लिए ही एक पूर्व शर्त नहीं है बल्कि हमारे क्षेत्र के अस्तित्व के लिए भी यह आवश्यक है।

सार्क वित्त मंत्रियों की चौदहवीं अनौपचारिक बैठक 17 अक्टूबर 2019 को वाशिंगटन डीसी, यूएसए में आयोजित की गई थी। यह पहली बार था जब विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान अनौपचारिक बैठक हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा किया गया था। बैठक में, इस बात पर जोर दिया गया कि भारत क्षेत्रीय सहयोग, संपर्क और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अनुकूल माहौल में ही ऐसा करने के लिए आगे बढ़ना संभव है। यह भी रेखांकित किया गया कि भारत ने पहले ही कई सकारात्मक कदम उठाए हैं और सभी एलडीसी के लिए 99.7% टैरिफ लाइनों को साफ्टा (एसएएफटीए) के अंतर्गत सीमा शुल्क प्रभार को शून्य प्रतिशत तक घटा दिया है। सार्क के वित्त मंत्रियों की

13वीं अनौपचारिक बैठक 2 मई 2019 को नाडी, फिजी में एशियाई विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर हुई। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर सार्क-एडीबी की चौथी बैठक जून 2019 में, काठमांडू में हुई। इस बैठक में वाणिज्य मंत्रालय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें दोहराया गया कि सार्क-एडीबी की पहली बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जाना है। सार्क कृषि मंत्रियों की चौथी बैठक 24-27 जून 2019 को थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई और इसमें थिम्पू में हमारे राजदूत ने भाग लिया।

भारत तकनीकी प्रगति के परिणाम को अपने पड़ोस के समान विचार वाले देशों के साथ साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। दक्षिण एशिया के देशों के लिए अपने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का विस्तार करने की भारत की एकतरफा पहल को श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान तक विस्तारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त 2019 को भूटान तक इसके विस्तार का उद्घाटन किया। भाग लेने वाले अन्य सार्क देशों के लिए विस्तार प्रगति पर है। भारत ने 5 मई 2017 को श्रीहरिकोटा से इसका शुभारंभ किया। भारत द्वारा 2017 में लॉन्च किए गए दक्षिण एशिया उपग्रह के प्रदर्शन टर्मिनलों को भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को सौंप दिया गया है। 2019 में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान, उन्होंने भूटान के अनुरोध पर एक अतिरिक्त ट्रांसपोंडर पर अतिरिक्त बैंडविड्थ की घोषणा की। इसे भी लागू किया गया है।

पिछले वर्षों की तरह, भारत ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को अपना समर्थन जारी रखा। भारत विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और इसकी पूरी पूंजी लागत को स्वीकार किया है। नई दिल्ली में इसके स्थायी परिसर का निर्माण चल रहा है। 3 जून 2019 को आयोजित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के पुरस्कार समारोह में दी गई उपाधियों में स्नातकोत्तर (151), एमफिल (9) और पीएचडी (17) शामिल हैं।

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (अंतरिम इकाई), गांधीनगर का संचालन जारी है, यह पूरी तरह से भारत द्वारा वित्त पोषित है और क्षेत्रीय गंभीर मौसम और अचानक बाढ़ के खतरे के पूर्व चेतावनी तंत्र, राष्ट्रीय और स्थानीय डीआरआर रणनीतियों के विकास, आपदा जोखिम में कमी के लिए अंतरिक्ष और जमीन आधारित भू स्थानिक जानकारी के उपयोग और आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के क्षेत्रों में सार्क के सदस्य राष्ट्रों को संबंधित कर कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। सार्क देशों के 94 प्रतिभागियों को उपरोक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

सार्क प्रोग्रामिंग समिति का 57वां सत्र 19-20 दिसंबर 2019 को काठमांडू में आयोजित होने वाला है।

बिम्सटेक

बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल भारत की 'पड़ोस सबसे पहले' और 'एक्ट ईस्ट' की प्रमुख विदेश नीति की प्राथमिकताओं को पूरा करती है। मई 2019 में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिम्सटेक नेताओं की यात्रा क्षेत्र में बिम्सटेक की बढ़ती भूमिका और प्रासंगिकता का प्रतीक है। पिछले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अप्रैल 2019 में अपनाया गया है। सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था और व्यापार, ब्लू इकोनॉमी अर्थात् समुद्री पर्यावरण को कोई नुक़सान न पहुँचाते हुए समुद्र के संसाधनों का उपयोग, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक और युवा संपर्कों को बढ़ावा देने के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई चल रही है।

बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की तीसरी बैठक बैंकॉक में 20-22 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि जो राष्ट्र आतंकवादियों और उनके संगठनों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराते हैं, वे आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लड़ाई को कमजोर करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक से उत्पन्न निम्नलिखित कार्रवाई बिंदुओं को लागू किया गया था:

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद ने बिम्सटेक देशों के 36 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को साइबर आतंकवाद, आतंकवाद प्रतिरोध, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अपराधों पर प्रशिक्षित किया।

कट्टरपंथ और आतंकवाद विरोध पर उप समूह की पहली बैठक 11 जून 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

ट्रैक 1.5 बिम्स्टेक सुरक्षा संवाद मंच की दूसरी बैठक 30-31 जुलाई 2019 को ढाका (बांग्लादेश) में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेएस (एनएससीएस) ने किया।

पहला बिम्सटेक कॉन्क्लेव ऑफ पोर्ट्स 7-8 नवंबर 2019 को विशाखापत्तनम (भारत) में आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र में जहाजरानी (स्वतंत्र प्रभार) रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया ने भाग लिया था। रंगोंग पोर्ट (थाईलैंड के पोर्ट प्राधिकरण) और चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता के पोर्ट ट्रस्ट के बीच तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बिम्सटेक देशों के लिए तटीय सुरक्षा कार्यशाला 20-22 नवंबर 2019 को इंडियन फ्यूजन सेंटर- इंडियन ओशन रीजन (आईएफसी-आईओआर) गुरुग्राम, भारत द्वारा आयोजित की गई थी।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर दूसरी बिम्सटेक चिंतन वार्ता 27-28 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली के वीआईएफ में आयोजित की गई थी। बिम्सटेक राजदूत के महासचिव एम शहीदुल इस्लाम उद्घाटन सत्र में शामिल हुए।

हिमालय विज्ञान परिषद की पहली कार्यशाला 5-6 दिसंबर 2019 से गोवा के ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र, गोवा में आयोजित की गई थी।

अगस्त 2018 में नेपाल में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित भारत सरकार की निम्नलिखित पहलों को लागू/नियोजित किया गया है:

- दूसरे बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2019 के लिए तैयारी बैठक 14-15 नवंबर, 2019 को ओडिशा के पुरी में आयोजित की गई, जो दूसरे आपदा प्रबंधन अभ्यास की प्रणेता है, दूसरा आपदा प्रबंधन अभ्यास फरवरी 2020 में पुरी में आयोजित करने की योजना है।
- एनएएससी कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, 11-13 दिसंबर 2019 को बिम्सटेक के सदस्य राष्ट्रों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणालियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है।
- गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (जीआईडीएम) में 17-20 दिसंबर 2019 तक जोखिम सूचित शहरी नियोजन में क्षमता निर्माण पर चार दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
- नालंदा विश्वविद्यालय में बिम्सटेक देशों के लिए 24 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियो को मंजूरी दी गई। पहले चरण में 7 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

2020 के आरंभ में भारत सरकार की निम्नलिखित पहलों के कार्यान्वयन की योजना बनाई जा रही है:

- एनईएसएसी (उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र), शिलांग में अंतरिक्ष और रिमोट सेंसिंग सपोर्ट प्रोग्राम के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 24 शोधकर्ताओं/

छात्रों/पेशेवरों के लिए दो सप्ताह के अल्पावधि पाठ्यक्रम की योजना बनाई जा रही है।

- नई दिल्ली के विदेश सेवा संस्थान में बिम्स्टेक राजनयिकों के लिए 3 से 15 फरवरी 2020 तक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
- ब्लू इकोनॉमी पर बिम्सटेक देशों के युवाओं के लिए मई 2020 में, पुणे में हैकथॉन आयोजित करने की योजना है।

कृषि पर पहली बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक (पहली बीएएमएम) से पहले 11-12 जुलाई 2019 को ने पाई ताव, म्यांमार में बिम्सटेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (पहली एसओएम-ए) आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भाग लिया था। भारत ने कृषि क्षेत्र में बिम्सटेक के छात्रों के लिए 6 स्नातकोत्तर और 6 पीएचडी छात्रवृत्ति की घोषणा की। धन शोधन विरोध और आतंकवाद के वित्तपोषण पर मुकाबला करने वाले बिम्सटेक उप-समूह की ग्यारहवीं बैठक बैंकॉक, थाईलैंड में 2-5 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी। ट्रेड फैसिलिटेशन पर बिम्सटेक वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 29-30 सितंबर 2019 को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई थी। पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर राष्ट्रीय केंद्रों के बिम्सटेक नेटवर्क (बीएनएनसीसीटीएम) की चौथी बैठक 16-17 जून 2019 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी।

ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर बिम्सटेक मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा सकता है और 2020 की शुरुआत में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर बिम्सटेक कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 2020 के आरंभ में आयोजित की जाएगी।

बिम्सटेक के नेताओं के निर्देश पर चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में समन्वयकारी निकाय के रूप में काम करने के लिए बनाई गई बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति (बीपीडब्ल्यूसी) की पहली और दूसरी बैठक के आयोजन द्वारा बिम्सटेक को आगे गति प्रदान की गई, इसे बिम्सटेक के अंतर्गत वित्तीय और प्रशासनिक मामलों सहित संस्थागत प्रक्रियाओं/तंत्रों के निर्माण और संयुक्त गतिविधियों के समन्वय का काम सौंपा गया था।। जनवरी और अक्टूबर 2019 में कोलंबो में हुई बीपीडब्ल्यूसी की बैठकों ने परिणाम-उन्मुख तरीके से विविध क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को तीव्र करने के लिए भविष्य का रोड-मैप प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। बिम्सटेक संरचना की संस्थागत मजबूती के लिए, बिम्सटेक चार्टर, क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाना, बिम्सटेक केंद्रों/संस्थाओं की स्थापना के लिए टेम्पलेट एमओए, बिम्सटेक और एशियाई विकास बैंक आदि के बीच समझौता ज्ञापन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

नालंदा विश्वविद्यालय

नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2014 में शिक्षण आरंभ हुआ। अधिनियम के अनुसार, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। नालंदा ने परिसर की भौतिक संरचना के साथ-साथ शैक्षणिक कार्यक्रमों के संदर्भ में भी लगातार प्रगति की है। निर्माण परियोजना की गति मई 2017 के 0.3% से बढ़कर लगभग 60% हो गई है। स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के 12 छात्रों और अध्ययन के 2 स्कूलों के साथ आरंभ विश्वविद्यालय में आज 12 देशों के 56 छात्रों सहित अध्ययन के 5 स्कूलों और 96 छात्र है। अब लगभग 20% संकाय विदेशों से आये हैं। सितंबर 2018 में शुरू होने वाले संस्कृत, अंग्रेजी और कोरियाई जैसी भाषाओं में लघु पाठ्यक्रम 2019 में जारी रहे। ऐसे कुल 488 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। अकादमिक पाठ्यक्रमों में

नवाचार कार्यक्रम शामिल हैं जैसेकि सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जिसका उद्देश्य वर्तमान समय में पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा अकादमिक लेखापरीक्षा की प्रणालियां स्थापित की गई हैं। विश्वविद्यालय तीन वैश्विक केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया कर रहा है नामत: (i) बंगाल की खाड़ी पर अध्ययन (ii) एक समान पुरातल संसाधन केंद्र और (iii) विवाद-समाधान और शांति अध्ययन केंद्र

मंत्रालय भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक भाग के रूप में, विश्वविद्यालय को विश्व स्तर की संस्था बनाने के लिए काम कर रहा है, जिसमें इसके अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए सुविधा प्रदान करना भी शामिल हैं। नालंदा को सहयोगी गतिविधियों के उद्देश्य से जुड़ाव का नक्शा तैयार करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया है, जिससे विश्वविद्यालयों के भारत-आसियान नेटवर्क का समर्थन किया जा सके।

नेट-जीरो और हरित परिसर विकास के संबंध में, परिसर के निर्माण में सलाह और सहायता के लिए भारत सरकार के विभिन्न नियामक निकायों से नेट-जीरो कैंपस स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई है। प्रमुख स्थिरता सुविधाओं में कुल शून्य ऊर्जा, कुल शून्य पानी, कुल शून्य अपशिष्ट और कुल शून्य उत्सर्जन शामिल हैं।

10

भारत - प्रशांत

वैश्विक कार्य-प्रणाली में भारत-प्रशांत अवधारणा के निरंतर बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, विदेश मंत्रालय ने अप्रैल, 2019 में भारत-प्रशांत के लिए एक नए प्रभाग की स्थापना की। ऐसा करने का उद्देश्य द्वि-आयामी था : जून, 2018 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किए गए अवयवों के अनुरूप भारत सरकार में भारत-प्रशांत के भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाने में सहायता करना तथा उस दृष्टिकोण को नीतिगत अवयव और कार्यक्रम प्रदान करना।

भारत का दृष्टिकोण एक मुक्त खुले, अंतर्वेशी और नियम-आधारित भारत-प्रशांत पर ध्यान-केन्द्रित करता है। भारत क्षेत्र में सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और प्रादेशिक एकता, सभी राष्ट्रों के लिए समानता, विवादों के शांतिप्रिय तरीके से समाधान, धमकी के प्रयोग अथवा बल के प्रयोग को दूर करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन पर बल प्रदान करता है। भारत का उद्देश्य क्षेत्र के सभी देशों और इस विषय पर रुचि रखने वाले देशों के साथ बहु-आयाम संबंध स्थापित करना, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों को इस परिधि में शामिल करना है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) है।

इस परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2019 विभिन्न भारत-प्रशांत संगठनों के साथ भारत की सघन भागीदारी का साक्षी रहा है जिनमें अन्य के साथ-साथ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (आइएएस), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम), मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी); शामिल है। हम जुलाई, 2019 में एक विकास भागीदार के रूप में ऐयावाडी-चाओ फराया-मेमांग आर्थिक सहयोग कार्यनीति (एसीएमईसीएस) में शामिल होने के लिए भी सहमत हैं।

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव जिसका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (आसियान) इसका प्राथमिक घटक था, म्यांमार में नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी) द्वारा शासित है। एईपी के प्रमुख कारक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संबंधों के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सामरिक संबंधों में संवर्धन करना है। इस दिशा में, 2019 में, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के प्रधानमंत्रियों और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। हमारे राष्ट्रपति ने नवंबर 2019 में फिलीपींस की राजकीय यात्रा की थी, जबकि उपराष्ट्रपति ने मई 2019 में वियतनाम का दौरा किया था। विदेश मंत्री (ईएएम) डॉ एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री (राज्यमंत्री) श्री वी मुरलीधरन ने कंबोडिया और लाओस को छोड़कर आसियान के सभी विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ इस वर्ष विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) और संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) जैसी संरचित तंत्र बैठकें आयोजित की गई। प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) के साथ भारत के संबंधों को 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयॉर्क में 24 सितंबर 2019 को आयोजित ऐतिहासिक भारत-प्रशांत द्वीप विकासशील राष्ट्रों (पीएसआईडीएस) के नेताओं की बैठक हुई जिसने 23 जून, 2019 को भारत- प्रशांत अवधारणा के प्रत्युत्तर के रूप में 23 जून, 2019 को भारत-प्रशांत के प्रति आसियान ने अपने दृष्टिकोण की संरचना की। वर्ष के अंत में बैंकॉक में 2-4 नवंबर 2019 से 35 वें आसियान/14 वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) /16वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के रूप में चिह्नित किया गया, जहां प्रधानमंत्री ने आसियान नेताओं के साथ बातचीत की और ईएएस के दौरान भारत-प्रशांत समुद्र पहल (आईपीओआई) की घोषणा की।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

आसियान के साथ संबंध भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और रणनीति का एक महत्वपूर्ण अवयव रहा है और रहेगा। 'एक्टिंग ईस्ट' अब भारत के भारत-प्रशांत दृष्टिकोण में एक केन्द्रीय अवयव के रूप में शामिल है।

21वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक 12 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जहां सभी दस आसियान देशों और भारत ने आसियान-भारत सहयोग ढांचे के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की। समुद्री अर्थव्यवस्था पर तीसरी आसियान-भारत कार्यशाला, आसियान-भारत सांस्कृतिक और सभ्यात्मक संबंधों पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आसियान-भारत मंत्रालयी बैठक एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर सम्मेलन, आसियान-भारत वित्तीय वार्ता, आसियान-भारत सामुद्रिक वार्ता तथा आसियान-भारत सामुद्रिक सहयोग नेटवर्क के अवधारणा पत्रों को परिचालित किया गया।

विदेश मंत्री ने बैंकाक में 1 अगस्त, 2019 को आयोजित आसियन-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया जहां उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों के लिए कंबोडिया, लाओ पीडीआर और वियतनाम के छात्रों को उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 20 करने की घोषणा की तथा इन्हें सभी आसियान सदस्य राज्यों के लिए खोल दिया।

25 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आसियान-भारत स्मारक शिखर-सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में आसियान छात्रों के लिए 1000 एकीकृत पीएच.डी छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा के अनुसरण में, विदेश मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री ने 16 सितम्बर, 2019 को विदेश मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से अध्येतावृत्ति कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आसियान छात्रों के प्रथम बैच को जनवरी, 2020 में प्रवेश दिया जाएगा। 300 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ, अध्येतावृत्ति

कार्यक्रम आसियान के साथ इसकी भागीदारी में भारत की सर्वाधिक व्यापक क्षमता विकास पहल है।

समुद्री अर्थव्यवस्था पर तीसरी आसियान-भारत कार्यशाला 12 सितम्बर, 2019 को बैंकाक में आयोजित की गई जिसमें भारत और आसियान सदस्य राज्यों के विशेषज्ञों ने समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास, सामुद्रिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग, सामुद्रिक संयोजनता और सामुद्रिक सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया।

साइबर मुद्दों पर प्रथम आसियान-भारत ट्रैक 1.5 वार्ता प्रेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन (क्यूआरएफ) की सहभागिता के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा 14 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें आसियान सदस्य देशों और भारत के सरकारी प्रतिनिधियों तथा साइबर विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस वार्ता का आयोजन जनवरी, 2018 में नई दिल्ली में आयोजित 25वें आसियान-भारत स्मारक शिखर-सम्मेलन में भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के रूप में किया गया था। इसमें डाटा संरक्षण और निजता, मानव अधिकार और उभरती प्रौद्योगिकी, विनियमों और डिजिटल अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्रांति 4.0, 5जी की भू-राजनीति और साइबर स्पेस और साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक मानदण्डों पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 3 नवम्बर, 2019 को बैंकाक में आयोजित 16वें आसियान-भारत शिखर-सम्मेलन में भाग लिया। शिखर-सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने आसियान-भारत विश्वविद्यालय नेटवर्क परियोजनाओं के लिए 50 मिलियन रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान करने और भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान कृषि वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने 2020 में आसियान-भारत हैकाथन और स्टार्ट-अप समारोह मनाने का भी प्रस्ताव किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के साथ सहयोग करते हुए नई दिल्ली में 18-22 नवम्बर, 2019 तक 'क्षमता निर्माण और नीति, विनियम और विकास में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की साझेदारी' विषय पर आसियान सदस्य राज्यों के दूरसंचार विनियामकों के लिए एक पांच-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

दिल्ली वार्ता (डीडी XI) - भारत के उत्कृष्ट आसियान-संबंधी ट्रैक 1.5 नीति समारोह का 11वां संस्करण हिंद महासागर वार्ता के 6वें संस्करण के साथ 13 और 14 दिसम्बर, 2019 को आयोजित किया गया था। यह प्रथम अवसर था जब ये दो ट्रैक 1.5 वार्ताएं, जो क्रमश: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) और भारत-आसियान कैलेंडर्स की मुख्य अवयव है, एक साथ और समान भारत-प्रशांत विषयों पर आयोजित की गई थीं। विदेशी मामलों की भारतीय परिषद् की सहायता से आयोजित छठी हिंद महासागर वार्ता में "भारत-प्रशांत : एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिन्द महासागर की पुन: कल्पना करना विषय पर केन्द्रित थी जबकि दिल्ली वार्ता-XI का आयोजन सूचना प्रणाली (आरआईएस) की सहायता से किया गया था जिसमें 'भारत-प्रशांत में भागीदारी को आगे बढ़ाना' विषय पर ध्यान-केंद्रित किया गया था।

पूर्व एशिया शिखर-सम्मेलन (ईएएस)

विदेश मंत्री ने 2 अगस्त, 2019 को बैंकाक में आयोजित पूर्व एशिया शिखर-सम्मेलन मंत्रालय बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जिसमें उन्होंने भारत-प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का स्वागत किया।

बैंकाक में 4 नवम्बर, 2019 को आयोजित 14वें पूर्व-एशिया शिखर-सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। वैश्विक मुद्दों जैसे दक्षिण चीन सागर, कोरियाई प्राय:द्वीप, रखीन

राज्य तथा आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद पर भारत की स्थिति को रखने के अलावा प्रधानमंत्री ने भारत-प्रशांत महासागर पहल की घोषणा की जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित, संरक्षित, स्थिर, समृद्ध और संधारणीय सामुद्रिक क्षेत्र का सृजन करना है। उन्होंने यह घोषणा की कि भारत चेन्नई में 6-7 फरवरी, 2020 को सामुद्रिक सुरक्षा और सहयोग पर चौथे ईएएस सम्मेलन का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 में प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण पर एक संगोष्ठी तथा अवैध गैर-सूचित और अविनियमित (आईयूयू) से से मछली पकड़े जाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की भी घोषणा की।

मंत्रिस्तरीय मुख्य सत्र दिल्ली वार्ता (13 दिसंबर, 2019)

हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)

आईओआरए सामरिक योजना कार्यशाला 9-11 अप्रैल, 2019 तक मॉरीशस में आयोजन की गई जिसमें आईओआरए सुधारों तथा संगठन के सांस्थनिक सुदृढ़ीकरण के विभिन्न पहलुओं पर आईओआरए देशों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

भारत ने 19-20 जून, 2019 को डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 19वीं आईओआरए-द्विवार्षिक बैठक में भाग लिया। आईओरआरए के इन मध्यम-वर्षीय आकलन क्रियाकलापों से पूर्व 17-18 जून, 2019 को हिंद महासागर रिम व्यापार फोरम तथा 18 जून, 2019 को व्यापार और निवेश पर कार्यकारी ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया था।

आईओआरए आपदा जोखिम प्रबंधन सहयोग के भाग के रूप में, भारत ने 2-4 अगस्त, 2019 तक चेन्नई में भारत के चौथे वार्षिक एचएडीआर अभ्यास में आईओआरए सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की। इस अभ्यास में बांग्लादेश, केन्या, सोमालिया, शेशेल्स, श्रीलंका, नेपाल, आस्ट्रेलिया और आसियान सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारत ने श्रीलंका द्वारा 8-9 अगस्त, 2019 को कोलम्बो में सामुद्रिक सुरक्षा और संरक्षा पर आयोजित आईओआरए कार्यकारी ग्रुप की पहली बैठक में भाग लिया। इस कार्यकारी ग्रुप बैठक में सामुद्रिक सुरक्षा और संरक्षा के क्षेत्र में आईओआरए द्वारा संचालित किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए अपनाई जाने वाली दो-वर्षीय कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया।

विदेश राज्य मंत्री ने 7 नवम्बर, 2019 को आबूधाबी, यूएई में आयोजित आईओआरए मंत्री परिषद् की 19वीं बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने बैठक में आईओआरए एचएडीआर दिशा-निर्देश पुस्तिका के प्रथम अंक का विमोचन किया। आईआरेआरए विशेष निधि में भारत द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया गया।

आईओआरए की प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में, भारत ने 28-29 नवम्बर, 2019 को कोच्चि में दो-दिवसीय क्षमता निर्माण अभ्यास के लिए 17 विदेशी प्रतिभागियों की मेजबानी की। अभ्यास का नाम सोमालिया, यमन विकास कार्यक्रम था तथा इसके लिए सोमालिया और यमन के मास्तियकी विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं को आमंत्रित किया गया था ताकि शिल्पकारी मात्स्यिकी में उनके कौशलों का संवर्धन किया जा सके।

भारत ने नई दिल्ली में 13 दिसम्बर, 2019 को छठी हिंद महासागर वार्ता की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में सभी आईओआरए देशों के प्रतिनिधि उसके वार्ता भागीदारों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया था। इस समारोह से पूर्व 12 दिसम्बर, 2019 को हिंद महासागर रिम शैक्षणिक ग्रुप की 25वीं बैठक तथा आईओआरए के शैक्षणिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग की प्रथम विशेषज्ञ समूह बैठक आयोजित की गई थी।

एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम)

विदेश राज्य मंत्री ने 15-16 दिसम्बर, 2019 को मैड्रिड, स्पेन में आयोजित 14वीं एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक (एफएमएम) में भाग लेने के लिए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक से कम्बोडिया में 2020 में आयोजित होने वाले एएसईएम शिखर-सम्मेलन की तैयारी में सहायता मिली। विदेश मंत्रियों ने विभिन्न वक्तव्य दिए जिनमें एशिया और यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक और लोगों-के-लोगों के साथ संबंधों को शामिल किया गया था।

भारत ने 14-21 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में एएसईएम राजनयिकों के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पांचवीं बार आयोजन किया। 20 एएसईएस देशों के राजनयिकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी)

11वीं एमजीसी वरिष्ठ अधिकारी बैठक (11वीं एमजीसी एसओएम) का आयोजन 9 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में किया गया जिसमें भारत, कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाइलैंड और वियतनाम के वरिष्ठ अधिकारियों ने एमजीसी सहयोग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पहलों में हुई प्रगति की समीक्षा की।

विदेश मंत्री ने बैंकाक में 1 अगस्त, 2019 को हुई 10वीं एमजीसी मंत्रालयी बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। मंत्रियों ने एमजीसी कार्य-योजना (2019-2022) को अंगीकृत किया तथा वर्ष 2020 को एक समुचित तरीके से एमजीसी की 20वीं वर्षगांठ के रूप में मनाने का निर्णय लिया जिसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे जिनमें सियाम रीप, कम्बोडिया में एमजीसी एशियाई पारपंरिक वस्त्र संग्रहालय में विरासत संरक्षण तकनीकों पर एमजीसी सम्मेलन का आयोजन, एमजीसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें संगीत, दृश्य और प्रदर्शन कलाएं शामिल की जाएंगी, तथा वर्ष 2020 में एमजीसी मंत्रालयी बैठक के दौरान वियतनाम में एक त्वरित प्रभाव परियोजना (क्यूआईपी) का संयुक्त उद्घाटन किया जाएगा।

पारंपरिक और समकालीन औषधि (टीसीएम) पर मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) कार्यशाला का आयोजन आयुष

मंत्रालय के सहयोग से एमजीसी कार्ययोजना 2019-22 के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता के भाग के रूप में नई दिल्ली में 22-25 अक्तूबर, 2019 को आयोजन किया गया। मेकांग देशों के चौबीस टीसीएम वृत्तिकों और विनियामकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। दोनों पक्षों ने विनियामक और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर जानकारी का आदान-प्रदान किया तथा द्विपक्षीय सहयोग और पारंपरिक औषधि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अनेक संभावनाओं पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में 3 नवंबर 2019 को 16वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2020 में एमजीसी की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हनोई में आसियान शिखर सम्मेलनों के दौरान पहला एमजीसी स्मारक शिखर सम्मेलन प्रस्तावित किया था।

एयेयावाडी-चाओ फ्रामा-मेकांग आर्थिक सहयोग कार्यनीति (एसीएमईसीएस)

भारत आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य और अमेरिका के साथ एक विकास भागीदार के रूप में एसीएमईसीएम में शामिल हुआ। भारत आसियान क्षेत्र में संयोजनता और डिजिटल अवसंरचना के लिए नवम्बर, 2015 में कुआलालाम्पुर में आयोजित आसियान-भारत शिखर-सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित यूएसडी/बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में एसीएमईसीएम प्राथमिकता परियोजनाओं से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने का प्रयास कर रहा है।

11

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां सत्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का 74 वां सत्र 17 सितंबर 2019 को शुरू हुआ। 74 वें सत्र का विषय था "गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु कार्रवाई और समावेश के लिए बहुपक्षीय प्रयास"। इस नए सत्र की शुरुआत से ही गरीबी उन्मूलन, भुखमरी को समाप्त करने और गुणवत्ता शिक्षा पर विशेष रूप से लक्ष्य 1, 2 और 4 में एसडीजी की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न समितियों में प्रयासों को लक्षित किया गया है। विशेष रूप से अंतर्विरोध, मानव अधिकारों को बढ़ावा, महिलाओं और युवाओं के सशक्तीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संवर्धित बहु-हितधारक भागीदारी, विशेष रूप से संघर्ष की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना जारी रहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22-27 सितंबर 2019 तक संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के उच्च-स्तरीय खंड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। 23 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीन उच्च-स्तरीय बैठकों - *जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्च-स्तरीय बैठक तथा आतंकवादी और हिंसात्मक चरमपंथियों की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं*

पर नेताओं के साथ वार्ता में भाग लेते हुए यूएनजीए से जुड़े अपने कार्य की शुरुआत की।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ''*ए रेस वी कैन विन। ए रेस वी मस्ट विन*'' विषय के अंतर्गत जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरों पर राजनीतिक और कारोबारी पूंजी जुटाने हेतु संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जिससे कि कई सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में सक्षम हो। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का आह्वान किया। उन्होंने एक नए विकास दर्शन की आवश्यकता के बारे में बात की और व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक स्तर पर लोगों के आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने 450 गीगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने, पेट्रोल और डीजल के साथ जैव ईंधन के सम्मिश्रण सहित ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के उपयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने के लिए भारत के व्यावहारिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के 150 मिलियन गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराने की पहल, 50 अरब डॉलर के जल संरक्षण की पहल और एकल-उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने के निर्णय के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रतिरोध शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में स्वीडन के साथ सह-नेतृत्व किए गए उद्योग-संक्रमण ट्रैक के एक परिणाम के रूप में *आपदा प्रतिरोधक संरचना (सीडीआरआई) गठबंधन और "लीडरशिप ग्रुप"* की पहल की भी घोषणा की। नेतृत्व समूह नवाचार और कम कार्बन प्रणाली के विकास के क्षेत्र में सरकार और उद्योग के बीच अधिक से अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इस विषय पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और स्वास्थ्य सेवा के चार मुख्य स्तंभों पर काम कर रहा है: *निवारक स्वास्थ्य देखभाल, सस्ती हेल्थकेयर, आपूर्ति पक्ष में सुधार और मिशन मोड में कार्यान्वयन।* प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य पर विशेष जोर देने और 125,000 से अधिक कल्याण केंद्रों को स्थापित करने से निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने में मदद मिली है, जो जीवन शैली से जुड़े रोगों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, अवसाद आदि को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, अधिक से अधिक स्वच्छ भारत अभियान और टीकाकरण अभियानों के माध्यम से जागरूकता ने भी स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना - *आयुष्मान भारत* शुरू की, जिसके अंतर्गत 500 मिलियन गरीबों को सालाना 500,000 रुपये (7000 अमेरिकी डॉलर से अधिक) तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कई ऐतिहासिक कदमों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने माता और बच्चे के पोषण की स्थिति में सुधार लाने में *राष्ट्रीय पोषण मिशन* की भूमिका के बारे में भी बताया। उन्होंने 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले *2025 तक तपेदिक को खत्म करने* के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

भारत-पीएसआईडीएस

भारत-प्रशांत द्वीप विकासशील राष्ट्र (पीएसआईडीएस) नेताओं की बैठक 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 74 वें सत्र के इतर आयोजित की गई थी। बैठक में फिजी, किरिबाती गणराज्य, मार्शल द्वीप समूह के गणतंत्र, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, नाउरू गणराज्य, पलाऊ गणराज्य, पापुआ गिनी के स्वतंत्र राज्य, समोआ के स्वतंत्र राज्य, सोलोमन द्वीप समूह, टोंगा राष्ट्र, तुवालु और वानुआतु गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षीय प्रारूप में यूएनजीए के इतर पीएसआईडीएस के नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनकी पसंद के क्षेत्र में उच्च प्रभाव विकासात्मक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर (प्रत्येक पीएसडीएस

पर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के आवंटन की घोषणा की। इसके अलावा, 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक रियायती ऋण साख, जिसका लाभ प्रत्येक देश की आवश्यकता के आधार पर सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के उपक्रमों द्वारा लिया जा सकता है, की घोषणा की गयी।

भारत - सीएआरआईसीओएम

क्षेत्रीय प्रारूप में सीएआरआईसीओएम नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री की पहली बैठक 25 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में हुई। बैठक में एंटीगा और बारबुडा, बारबाडोस, डोमिनिका, जमैका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद और टोबैगो, बहामास, बेलीज, ग्रेनेडा, हैती और गुयाना के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षमता निर्माण, विकास सहायता और आपदा प्रबंधन और पुनरुत्थान में सहयोग के क्षेत्रों में सीएआरआईसीओएम देशों के साथ भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने सीएआरआईसीओएम देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे (सीडीआरआई) की पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सीएआरआईसीओएम में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान तथा सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन संबंधित परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण सहायता की भी घोषणा की। उन्होंने इन देशों में मौजूदा भारत पोषित केंद्रों को उन्नत करके *जॉर्जटाउन, गुयाना में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र और बेलिज में एक क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र* की स्थापना की भी घोषणा की। भारत और सीएआरआईसीओएम के बीच एक संयुक्त कार्य बल स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर शीघ्रता से नज़र रखी जा सके और आगे बढ़ने के रास्ते की पहचान की जा सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ में महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती का आयोजन

24 सितंबर 2019 को, न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 74 वें सत्र के इतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए *"नेतृत्व मामला: समकालीन दुनिया में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता"* नामक एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मून जे-इन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली ह्सिएन लूंग, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना, जमैका के पीएम श्री एंड्रयू होल्नेस और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री जैसिंडा एडरन ने भाग लिया। भाग लेने वाले गणमान्य लोगों ने गांधीवाद और आदर्शों और उनके जीवन पर इसके प्रभाव को समृद्ध श्रद्धांजलि दी। इस समारोह में 550 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों, राजनयिकों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और प्रवासी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर नेताओं ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की छत पर लगाए गए *गांधी सोलर पार्क* का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय राज्यों के प्रतीकात्मक 193 सौर पैनलों से युक्त इस परियोजना को यूएन द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से निष्पादित किया गया था। इस अवसर पर *महात्मा गांधी पर* एक *विशेष डाक टिकट* भी जारी किया गया।

आर्थिक और सामाजिक मुद्दे

जनसंख्या और विकास पर 52 वां आयोग 1 से 5 अप्रैल, 2019 को आयोजित किया गया था। काहिरा में 1994 में आयोजित जनसंख्या और विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 साल पहले की गई प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया गया। मिशन ने 3 अप्रैल, 2019 को "ऑटिज़्म: पोषण देखभाल रूपरेखा और परिवार-कैंद्रित देखभाल" पर उच्च-स्तरीय विश्व ऑटिज्म जागरूकता

दिवस कार्यक्रम को सह प्रायोजित किया और भाग लिया। ईसीओएसओसी युवा मंच 8-9 अप्रैल 2019 को आयोजित किया गया था जिसने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने के बारे में विचारों को साझा करने के लिए दुनिया भर के युवाओं के लिए एक मंच प्रदान किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ में मिशन द्वारा 12 अप्रैल, 2019 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की 128 वीं जयंती के उपलक्ष्य में "महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण: कानून और नीतियों की भूमिका" शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑन एजिंग के 10 वें सत्र का आयोजन 15 से 18 अप्रैल 2019 के दौरान किया गया। न्यायमूर्ति श्री एचएल दत्तू की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था (एनएचआरआई) के रूप में अपनी स्वतंत्र क्षमता में भाग लिया। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के तरीके, वृद्ध व्यक्तियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश और स्वस्थ उम्र बढ़ने की सुविधा के बारे में विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा हुई।

17 अप्रैल 2019 को ईसीओएसओसी फोरम ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट (एफएफडी फोरम) के इतर मिशन ने ''सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हेतु सतत वित्त पोषण'' कार्यक्रम को सह-प्रायोजित किया और उसमें भाग लिया। 10 अप्रैल से 13 जून, 2019 तक "निशक्त लोगों के अधिकार संबंधी अभिसमय (सीआरपीडी) के कार्यान्वयन के माध्यम से इस बदलती दुनिया में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने को सुनिश्चित करने" विषय पर सीआरपीडी के लिए विभिन्न राष्ट्र पक्षों का 12 वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सुश्री शकुंतला गामलिन, सचिव, निशक्त लोगों के अधिकारिता विभाग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सुश्री गामलिन ने अपने वक्तव्य में उल्लेखनीय निशक्त लोगों के अधिकार अधिनियम, जो 2017 में लागू हुआ, और अन्य नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस समझौते के कार्यान्वयन में भारत की प्रगति को उद्धृत किया।

12 वीं सीआरपीडी के अलावा मिशन द्वारा दो अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें से एक कार्यक्रम आयरलैंड के स्थायी मिशन के साथ 'इजरायल और ईएनओएसएच (इजरायली मेटल हेल्थ एसोसिएशन) के स्थायी मिशन के सहयोग से 'मनोवैज्ञानिक अक्षमताओं वाले लोगों के लिए समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना' और' एक महत्वपूर्ण मित्र: निशक्तता पर सरकार के साथ नागरिक समाज के जुड़ाव का महत्व था।

जुलाई 2019 में उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के नेतृत्व में नीति आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीजी संबंधी उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) में भाग लिया। एचएलपीएफ के इतर *"प्रतिबद्धता से उपलब्धि की ओर: सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में भारत का अनुभव"* नामक एक अलग कार्यक्रम का 16 जुलाई, 2019 को आयोजित किया गया था। यूएनडीपी के प्रशासक अचिम स्टेनर इसमें मुख्य अतिथि थे और इसी अवसर पर *"एसडीजी का स्थानीयकरण: भारत से शुरूआती सीख, 2019"* पर एक रिपोर्ट जारी की गयी। वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन (यूएन-जीजीआईएम) पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की संयुक्त समिति का 9 वां सत्र संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 7-9 अगस्त 2019 से आयोजित किया गया। श्री संजय कुमार, अध्यक्ष, यूएन-जीजीआईएम निजी क्षेत्र नेटवर्क और अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीज और डिजिटल ग्लोबल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. कुमार नवलूर जीजीआईएम के मुख्य वक्ता थे।

संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव सुश्री एमीना मोहम्मद सितंबर, 2019 में मरूस्थलीकरण से निपटने संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के 14 वें कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी 14) में भाग लेने के लिए भारत आयीं जिसका आयोजन दिल्ली में 2-13 सितंबर, 2019 के दौरान किया गया था। 25 सितंबर, 2019 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में *"लचीला बुनियादी ढाँचा: 2030 सतत विकास ढ़ांचा के 2030 एजेंडे की सफलता"* शीर्षक से अलग कार्यक्रम को आयोजित किया गया। श्री प्रकाश

जावड़ेकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सुश्री ममीज़ुटोरी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे।

24 और 25 सितंबर 2019 को राष्ट्र और सरकार प्रमुख 2030 सतत विकास एजेंडा और 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के क्रियान्वयन में प्रगति की अनुवर्ती कार्रवाई और व्यापक समीक्षा करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्रित हुए। सितंबर 2015 में 2030 एजेंडा को अपनाने के बाद से एसडीजी पर यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र का प्रथम शिखर सम्मेलन था। एसडीजी शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप राजनीतिक घोषणा, *"सतत विकास के लिए कार्रवाई और क्रियान्वयन के एक दशक की तैयारी"* को अपनाया गया। विश्व नेताओं ने 2030 तक एसडीजी को लागू करने के लिए एक दशक की कार्रवाई का आह्वान किया और घोषणा की कि वे कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। महासभा ने 15 अक्टूबर 2019 को राजनीतिक घोषणा का समर्थन किया। 100 से अधिक त्वरण कार्यों की घोषणा की गई है।

27 सितंबर 2019 को, नीदरलैंड्स के मिशन के साथ भारत के स्थायी मिशन ने एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था, *''गुड सर्वेंट, पुअर मास्टर: कैप्चरिंग द प्रॉमिस एंड रिस्क ऑफ मैनेजिंग ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड''*। भारत ने 1 जनवरी 2019 से लागू होने वाले नए रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रयोजन न्यास कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का स्वैच्छिक योगदान दिया। 19 नवंबर 2019 को भारत *विश्व शौचालय दिवस* मनाने के लिए एक अलग कार्यक्रम आयोजित करने में सिंगापुर और नाइजीरिया के साथ शामिल हुआ। *भू आबद्ध विकासशील राष्ट्रों (एलएलडीसी) के लिए वियना कार्रवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की व्यापक उच्च-स्तरीय मध्यावधि समीक्षा न्यूयॉर्क* में 5-6 दिसंबर 2019 से हुई। भारत ने सक्रिय रूप से विचार-विमर्श में भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक घोषणा हुई। भारत ने इस वर्ष की शुरुआत में मध्यावधि समीक्षा की मेजबानी के लिए एलडीसी, एलएलडीसी और एसआईडी (ओएचआरएलएलएस) के उच्च प्रतिनिधि के कार्यालय में 250,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया।

समुद्र संबंधी कानून

भारत ने 25 मार्च से 5 अप्रैल 2019 और 19 से 30 अगस्त 2019 के बीच 72/249 के प्रस्ताव के अंतर्गत बुलाई गई अंतर-सरकारी सम्मेलन (बीबीएनजे) के पहले और दूसरे सत्र में भाग लिया और उन महत्वपूर्ण चर्चाओं को संबोधित किया, जो जैसे मुद्दों का समाधान करती हैं यथा विशेष रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता का संरक्षण और स्थायी उपयोग, साथ ही और समग्र रूप में, समुद्री आनुवंशिक संसाधन, लाभ के बंटवारे संबंधी प्रश्न सहित, क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और क्षमता निर्माण जैसे उपायों और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण आदि। सम्मेलन के अध्यक्ष सम्मेलन के चौथे सत्र की तैयारियों के हिस्से के रूप में केंद्रित चर्चा और पाठ-आधारित वार्ताओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक दस्तावेज, संधि भाषा युक्त और पैकेज के चार तवों के विषय में विकल्पों को दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगें।

भारत ने 17 से 19 जून 2019 तक आयोजित समुद्र (1982) संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए पक्षकार राष्ट्रों की 29 वीं बैठक में भी भाग लिया। प्रतिनिधिमंडलों ने इस अभिसमय के अंतर्गत स्थापित संस्थानों अर्थात् महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा संबंधी आयोग, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण और समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन किया।

भारत ने किंग्स्टन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के 25 वें सत्र में भाग लिया जिसने वित्तीय भुगतान प्रणाली के लिए मॉडलों, गहरे समुद्र में खनन पर मसौदा नियम; ठेकेदारों के गैर-अनुपालन मुद्दे; उपक्रमों के

संभावित परिचालन; 2019-2023 के लिए रणनीतिक योजना; एसजी की वार्षिक रिपोर्ट; और 2019-2020 के लिए प्रस्तावित बजट पर विचार किया।

महासागरों और महासागरों से संबंधित अन्य बैठकें शामिल थीं:

- 10 से 14 जून 2019 तक "महासागर विज्ञान और सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक" संबंधी महासागरों और समुद्री कानून के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की खुली अनौपचारिक परामर्श प्रक्रिया की 20 वीं बैठक;
- 29 और 30 अगस्त 2019 से महासभा के प्रस्ताव 72/73 के पैरा 330 के अनुसरण में बुलाई गयी सामाजिक आर्थिक पहलुओं सहित समुद्री पर्यावरण की स्थिति की वैश्विक रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए नियमित प्रक्रिया पर संपूर्ण समूह के तदर्थ कार्य समूह की 12 वीं बैठक;
- 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक सीएलसीएस का 51 वां सत्र - भारत ने उप-आयोग के समक्ष यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 76 (8) के अनुपालन के लिए आंशिक रूप से प्रस्तुत करने से संबंधित एक अद्यतन प्रस्तुतीकरण दिया;
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 1-4 अक्टूबर 2019 के दौरान महासागरों और समुद्र के कानून (ओम्निबस) पर अनौपचारिक परामर्श पर विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से योगदान दिया;

भारत ने 14-19 नवंबर, 2019 तक सुभेद्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर नीचे मछली पकड़ने के प्रभाव और गहरे समुद्र में मछली के शेयरों की दीर्घकालिक धारणीयता के प्रभाव पर सतत मछली पालन प्रस्तावों के अनौपचारिक परामर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल)

न्यूयॉर्क में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 1-5 अप्रैल 2019 के दौरान यूएनसीआईटीआरएएल *कार्यकारी समूह तीन* (निवेशक-राष्ट्र विवाद निपटान सुधार), 8-12 अप्रैल 2019 तक *कार्यकारी समूह चार* (इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य), 28-31 मई 2019 तक *कार्यकारी समूह पांच* (दिवालिया कानून) और 13 से 17 मई 2019 तक *कार्यकारी समूह छह* (जहाजों की न्यायिक बिक्री) में भाग लिया।

कार्यकारी समूह छह

28 सितंबर, 2019 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की 40वीं महासभा के दौरान हुए चुनाव में 2019-2022 के लिए भारत को आईसीएओ की परिषद् के लिए फिर से चुना गया।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन

भारत को 29 नवंबर, 2019 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के 31 वें सत्र के द्विवार्षिक 2020-21 के लिए श्रेणी 'बी' के अंतर्गत आईएमओ की परिषद् के लिए फिर से चुना गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड

भारत की सुश्री जगजीत पावडिया को 2020-2025 हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) के लिए फिर से चुना गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 7 मई,2019 को हुए चुनाव में, सुश्री पावडिया ने 5 सीटों के लिए चल रहे 15 उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट (44/54) हासिल किए।

विश्व सीमा शुल्क संगठन

श्री पी.के. दास, अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), को विश्व सीमा शुल्क संगठन में 2020-25 के लिए निदेशक (अनुपालन और सुविधा) के पद के लिए चुना गया था। जून 2019 में ब्रसेल्स में ये चुनाव हुए थे।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावास

पहली संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सभा मई 2019 में नैरोबी, केन्या में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान भारत

36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया। सभा के दौरान कार्यकारी बोर्ड की पहली बैठक भी हुई।

दक्षिण केन्द्र

अप्रैल 2019 में जिनेवा में हुई दक्षिण केंद्र की प्रतिनिधि परिषद् की 20 वीं बैठक में राजदूत (सेवानिवृत्त) अजीत कुमार को 3 साल की अवधि के लिए शासी परिषद् के संयोजक के रूप में सभी सदस्य राज्यों के बीच आम सहमति से चुना गया था। राजदूत कुमार अपने चुनाव तक परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (एचआरसी)

भारत ने 2019 में अपने तीन साल के पहले वर्ष की शुरुआत मानवाधिकार परिषद् से की। इसने अपने अनुबंध और सहभागिता जारी रखी जिसमें अन्य के साथ-साथ मानवाधिकार परिषद् (एचआरसी) के सत्र, वार्षिक फोरम की बैठकें, अंतर सरकारी कार्य समूह की कार्यवाही और मानवाधिकार संधि निकाय रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल है। विभिन्न मानवाधिकारों के मुद्दों पर मानवाधिकार उच्चायुक्त सुश्री मिशेल बाचेलेट ने उच्च स्तरीय स्तर पर जुड़ी रहीं।

भारत ने एचआरसी के जून 2019 सत्र के दौरान कलंक और भेदभाव को उजागर करते हुए कुष्ठ रोग पर अलग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य प्रायोजकों में से एक भारत ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के लिए सभी के अधिकार के संदर्भ में 'दवाओं और वैक्सीन तक पहुंच' पर संकल्प को प्रस्तुत किया। भारत ने खेल में महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने', 'बाल अधिकारों संबंधी अभिसमय की तीसवीं वर्षगांठ', 'शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उच्चतम प्राप्य मानक हेतु सभी के अधिकार', 'बीजिंग घोषणा की 25 वीं वर्षगांठ और कार्रवाई के कार्यक्रम (बीजिंग +25) का अंकन', 'कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय तंत्रों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना', 'रिपोर्टिंग और अनुशंसाओं का पालन करना', 'मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन' और 'नयी और उभरती हुई डिजिटल प्रौद्योगिकियां एवं मानवाधिकार' जैसे 10 संकल्पों को सहप्रायोजित भी किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की ओर से भारत 'मानव अधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने' और 'विकास के अधिकार' पर संकल्पों का मुख्य प्रायोजक था। भारत विशेष रूप से 'उभरती प्रौद्योगिकियों' और 'मौत की सजा' के साथ-साथ एनएएम द्वारा प्रस्तावित विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर संयुक्त वक्तव्य में भी शामिल हुआ।

भारत सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा प्रक्रिया के चल रहे तीसरे चक्र में भाग लेना जारी रखा जहां 42 में से 39 सदस्य राष्ट्रों से संबंधित हस्तक्षेपों की 2019 में समीक्षा की गयी। निशक्त जनों के अधिकारों संबंधी अभिसमय के प्रावधानों के अपने कार्यान्वयन के संबंध में भारत की शुरूआती रिपोर्ट की सितम्बर, 2019 में सीआरपीडी संबंधी समिति द्वारा समीक्षा की गयी।

सचिव (पश्चिम) श्री ए. गितेश शर्मा ने 1-2 अप्रैल 2019 को जिनेवा का दौरा किया और मानवाधिकारों के उच्चायुक्त सुश्री मिशेल बाचेलेट और दक्षिण केंद्र के कार्यकारी निदेशक डॉ. कार्लोस कोरी से मुलाकात की।

सचिव (पूर्व) श्रीमती विजय ठाकुर सिंह ने सितंबर 2019 में 42वें एचआरसी सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वह मानवाधिकार उच्चायुक्त सुश्री मिशेल बाचेलेट से मिलीं।

जर्मनी के स्थायी मिशन के सहयोग से भारत के स्थायी मिशन ने 18 नवंबर 2019 को बाल अधिकारों संबंधी अभिसमय के 30वें वर्ष को मनाने के लिए 'डिजिटल युग में बच्चे-अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बच्चों से संबंधित मुद्दों की हिमायत करना' शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

स्थायी मिशन ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में 27 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डा. फ्रांसिस गुर्री, महानिदेशक, डब्ल्यूआईपीओ और डॉ. सौम्य स्वामीनाथन, मुख्य वैज्ञानिक, डब्ल्यूएचओ का सद्गुरु के साथ बातचीत कार्यक्रम का आयोजन किया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

10-21 जून, 2019 से जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 108वें शताब्दी सत्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने किया। भारत के प्रमुख कर्मचारी और श्रमिक समूह के प्रतिनिधि भी आईएलसी में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने आईएलओ उच्च-स्तरीय शताब्दी समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया जिसे बाल श्रम के बिना एक उज्जवल भविष्य के लिए एक साथ 'बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाने के लिए आयोजित किया गया।

वर्ष भर भारत ने आईएलओ की विभिन्न तकनीकी समितियों और विशेषज्ञ स्तर की बैठकों में विचार-विमर्श में भाग लिया जिसमें मानक समीक्षा तंत्र त्रिपक्षीय कार्यकारी समूह (एसआरएम-टीडब्ल्यूजी) की 5 वीं बैठक, सम्मानजनक कार्य के संवर्धन पर दिशानिर्देशों को अपनाने और परिवहन क्षेत्र में सड़क सुरक्षा तथा खेल की दुनिया में सम्मानजनक कार्य पर वैश्विक संवाद के लिए विशेषज्ञों की बैठक शामिल है।

भारत ने मार्च, जून और अक्टूबर-नवंबर 2019 में आयोजित हुए आईएलओ के क्रमशः शासी निकाय (जीबी) के 335वें, 336वें और 337वें सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत आईएलओ में चल रही सुधार प्रक्रिया में शामिल रहा, जिसमें इसकी शासन संरचनाओं से संबंधित प्रक्रिया, आईएलओ की शताब्दी (वर्ष 2019) की पहल और अंतिम परिणाम दस्तावेजों के भाग के रूप में आईएलओ पर्यवेक्षी तंत्र और मानक समीक्षा तंत्र की समीक्षा अर्थात् शताब्दी घोषणा तथा काम की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न के उन्मूलन से संबंधित अभिसमय और सिफारिश शामिल है।

एचआईवी/ एड्स संबंधी संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम (यूएनएआईडीएस)

भारत ने एचआईवी/एड्स (यूएनएआईडीएस) संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के एक नए कार्यकारी निदेशक के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड (पीसीबी) के चयन में एक सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी बैठकों में शासन सुधारों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जो कि यूएनएआईडीएस संबंधी द्विवार्षिक ईसीओएसओसी संकल्प में भी शामिल था। भारत, एशिया-प्रशांत समूह से समर्थित उम्मीदवार होने के नाते यूएनएआईडीस कार्यक्रम समन्वय बोर्ड (पीसीबी) में 2020-2022 के कार्यकाल के लिए मौखिक मतदान द्वारा चुना गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)

विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्लूएचए) के 72वां सत्र 20-28 मई 2019 तक जिनेवा में हुआ जिसमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा महत्वपूर्ण संकल्पों और निर्णयों को आकार दिया। 72वें डब्लूएचए ने 2020-23 की चार साल की अवधि के लिए डब्लूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया। 72वें डब्लूएचओ के अवसर पर स्वास्थ्य प्रतिनिधियों ने 19 मई 2019 को जिनेवा में "यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: पहुंच से बाहर लोगों तक पहुंच, सुनिश्चित करना कि कोई न छूटे" के विषय पर 31वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

'चिकित्सा उत्पादों की पहुंच-एसडीजी 2030 को प्राप्त करना' पर तीसरा विश्व सम्मेलन 19-21 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू), भारत सरकार द्वारा किया गया था। भारत ने इस मुद्दे पर नेतृत्व किया और इस वार्षिक सम्मेलन के पिछले दो संस्करणों की मेजबानी की।

प्रवासी और शरणार्थी

भारत ने अपनी कार्यकारिणी और स्थायी समितियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त (शरणार्थियों) की कई बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया, विशेष रूप से अपनी परिषद् के दूसरे विशेष और 110वें वार्षिक सत्रों में जिन्हें क्रमशः जून और नवंबर

2019 में आयोजित किया गया। यह वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए दो वैश्विक समझौतों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण था और भारत यूएनएचसीआर और आईओएम में अपने अनुबंध के माध्यम से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहा।

भारत ने क्षेत्रीय एजेंडों को आकार देने के लिए कोलंबो प्रक्रिया और प्रवास संबंधी अन्य क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रियाओं में भाग लेना जारी रखा।

भारत अपने संचालन समूह के सदस्य के रूप में वैश्विक प्रवास और विकास संबंधी मंच (जीएफएमडी) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा और वर्ष के दौरान आयोजित मंच बैठकों की संचालन समिति और मित्रों के साथ भाग लिया।

विश्व बौद्विक संपदा संगठन

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के साथ भारत का संबंध 2019 में और मजबूत हुआ। जून 2019 में भारत ने तीन और डब्ल्यूआईपीओ शासित संधियों के लिए समझौता किया नामत: (i) अंकों के पंजीकरण उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से संबंधित एक बेहतर समझौता (ii) अंकों की आलंकारिक त्तवों के एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने वाला विएना समझौता और (iii) औद्योगिक डिजाइनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करते हुए लोकार्नो समझौता। वैश्विक नमोन्वेष सूचकांक की रिपोर्ट 2019 प्रकाशित हुई, यह डब्ल्यूआईपीओ की एक प्रमुख कार्यक्रम था जो जुलाई 2019 में नई दिल्ली में हुआ। यह पहली बार रिपोर्ट शुरू होने के बाद से एक विकासशील देश में प्रकाशित होने जा रही थी। जीआईआई में भारत की वैश्विक रैंकिंग में इस साल सुधार हुआ और यह 52वें स्थान पर रहा, इसने 2015 के बाद से 29 स्थानों की छलांग लगाई।

यूएनसीटीएडी

भारत ने 2019 में यूएनसीटीएडी की सभी बैठकों में सक्रिय रूप से और रचनात्मक रूप से भाग लेना जारी रखा। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने विकास के वित्तपोषण के लिए बैठक के दौरान भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास निधि पर एक प्रस्तुति दी जिसकी सदस्य राष्ट्रों और अन्य हितधारकों द्वारा बेहतर रूप में लिया गया और इसकी सराहना की गयी। यूएनसीटीएडी इनवेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 और 2018 दोनों वर्षों में भारत शीर्ष 10 एफडीआई अंतर्वाह स्थलों में से एक था।

अंतर्संसदीय संघ

13-17 अक्टूबर 2019 से बेलग्रेड में आयोजित आईपीयू के 141वें सत्र के दौरान भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने किया। आईपीयू-141 के दौरान पहली बार आईपीयू महासभा में भारत की ओर से 'जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का समाधान' विषय पर प्रस्तावित एक आपातकालीन प्रस्ताव को सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)

सूचना सोसाइटी (डब्ल्यूएसआईएस) फोरम का विश्व शिखर सम्मेलन 8-12 अप्रैल 2019 से जेनेवा में आयोजित किया गया था। इस आयोजन का विषय "सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" था।

माननीय न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह, अध्यक्ष, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट), संचार मंत्रालय, सरकार की अगुवाई वाले एक भारतीय शिष्टमंडल ने आयोजन में भाग लिया। फोरम ने सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सूचना और ज्ञान सोसायटी में विकसित होने वाले रुझानों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) सम्मेलन का 18वां सत्र 3-14 जून, 2019 से जेनेवा में आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान डॉ. मृत्युंजय मोहपात्रा को डब्लूएमओ के कार्यकारी परिषद् में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली (यूएनडीआरआर)

चौथा विश्व पुनर्निर्माण सम्मेलन (डब्लूआरसी4) 13-14 मई, 2019 तक जिनेवा में हुआ जो "रेजिलिएंट रिकवरी के लिए समावेश" विषय पर आधारित था। यह सम्मेलन आपदा वसूली और पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए था।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी वैश्विक मंच (जीपी2019)

संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच का आयोजन (जीपी2019) 13-17 मई 2019 से जिनेवा में हुआ। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का वैश्विक मंच एक द्विवार्षिक बहु-हितधारक मंच है जो आपदा जोखिम को कम करने में प्रगति की समीक्षा करता है।

प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. पी. मिश्रा के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोजन में भाग लिया। यूएनडीआरआर के साथ "आपदा प्रतिरोध क्षमता बुनियादी ढाँचे हेतु गठबंधन (सीडीआरआई)" पर एक बैठक आयोजित की गई।

डॉ. पी.के. मिश्रा को बाढ़ और सूखे के लिए सबसे सुभेद्य समुदायों के प्रतिरोध क्षमता में सुधार लाने के लिए उनकी पहलों और सामाजिक समावेश के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए उन्हें प्रतिष्ठित "संयुक्त राष्ट्र ससाकावा अवार्ड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2019" भी प्रदान किया गया।

खाद्यन्न और कृषि संगठन

भारत खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) परिषद् के सदस्य के रूप में एफएओ में भाग लेना जारी रखा। भारत 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2023 तक एफएओ परिषद् हेतु एक और कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया है। भारत विभिन्न समितियों जैसे कि मत्स्यपालन समिति, वानिकी समिति, खाद्य सुरक्षा समिति, वस्तु समस्या संबंधी समति और कृषि संबंधी समिति, के सदस्य के रूप में भी कार्य करता रहा।

2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के लिए भारत के प्रस्ताव को 22-29 जून 2019 को रोम में आयोजित एफएओ के 41वें सम्मेलन द्वारा अनुमोदित किया गया था।

विश्व खाद्य सुरक्षा संबंधी समिति का 46 वां सत्र 14-18 अक्टूबर 2019 से एफएओ में आयोजित किया गया। भारत को एशिया से विश्व खाद्य सुरक्षा (सीएफएस) ब्यूरो की समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है।

भारत ने एफएओ के बाहरी लेखा परीक्षकों के लिए बोली जीती और नवंबर 2020 से लेखा परीक्षा शुरू करेगा।

भारत को 2020 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य की अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्य के रूप में भी चुना गया है।

भारत ने 30 साल के अंतराल के बाद 22-29 जून 2019 को रोम में आयोजित 41वें एफएओ सम्मेलन के आयोग II की अध्यक्षता की। यह आयोग II मुख्य रूप से एफएओ के बजट और वित्त से संबंधित नीति के अनुमोदन से संबंधित है।

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एफएओ रोम में 11 नवंबर, 2019 को खाद्यान्न और कृषि हेतु पौध आनुवांशिक संसाधनों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) की 8वीं शासी निकाय बैठक के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने इटली के कृषि मंत्री और एफएओ

महानिदेशक के साथ भी बातचीत की। भारत ने 2021 में नई दिल्ली में आईटीपीजीआरएफए की 9वीं शासी निकाय बैठक आयोजित करने की घोषणा की।

विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम

विश्व खाद्य कार्यक्रम में भारत 01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यभार संभालेगा। भारत विभिन्न बैठकों में डब्ल्यूएफपी का एक सक्रिय पर्यवेक्षक सदस्य था।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि

भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड में एक सक्रिय सदस्य बना हुआ है। आईएफएडी में भारत की मजबूत प्रतिबद्धता और भागीदारी आईएफएडी 11वीं पुनःपूर्ति में परिलक्षित हुई, जिसमें 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल प्रतिबद्धता थी। भारत आईएफएडी की मूल्यांकन समिति का सदस्य है। भारत जुलाई 2019 में कार्यकारी बोर्ड की कैमरून यात्रा का सदस्य भी था।

कार्यकारी बोर्ड का 206वां सत्र

कार्यकारी मंडल का 206वां सत्र 03 से 17 अप्रैल, 2019 तक पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित किया गया। कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि प्रोफेसर जे.एस. राजपूत सत्र में शामिल हुए और 9 अप्रैल, 2019 को पूर्ण सत्र में अपना भाषण दिया। भाषण का केंद्र बिंदु महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का उत्सव, यूनेस्को के रणनीतिक परिवर्तन में महानिदेशक के प्रयासों की सराहना तथा भारत की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के अपने मूल जनादेश एवं इन क्षेत्रों में भारत के सकारात्मक योगदान में यूनेस्को के कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से शामिल करने के लिए रचनात्मक प्रयास था।

विश्व विरासत समिति

विश्व विरासत समिति का 43वां सत्र 30 जून से 10 जुलाई 2019 तक बाकू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। जयपुर की चारदीवारी शहर को सत्र के दौरान भारतीय स्थलों की कुल संख्या 38 को शामिल करते हुए विश्व विरासत स्थल की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया।

यूएनईएससीएपी

यूएनईएससीएपी में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि (पीआर) सुश्री सुचित्रा दुरई ने संयुक्त राष्ट्र एशिया-प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के 75वें आयोग सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसे 27-31 मई 2019 के दौरान आयोजित किया गया। भारत ने 'भारत: एसडीजी में एक नेतृत्व की भूमिका निभाना और एक अद्वितीय निगरानी ढांचा विकसित करना' के एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया। एशिया और प्रशांत सांख्यिकीय संस्थान (यूएन-एसआईएपी) तथा आपदा सूचना प्रबंधन हेतु एशिया और प्रशांत केन्द्र (एपीडीआईएम) के शासी परिषद् के चुनाव मई 2019 में हुए और भारत को इन दोनों निकायों के लिए फिर से चुना गया था।

राजदूत ने 27-29 नवंबर 2019 तक यूएनईएससीएपी में आयोजित बीजिंग+25 समीक्षा संबंधी एशिया-प्रशांत क्षेत्र मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सम्मेलन में "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: बीजिंग+25 समीक्षा पर आगे बढ़ते हुए एशिया प्रशांत घोषणापत्र" को एक परिणामी दस्तावेज़ के रूप में अपनाया गया।

वित्त मंत्रालय के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 6-8 नवंबर 2019 से आयोजित यूएनईएससीएपी विकास की समष्टि आर्थिक नीति, गरीबी न्यूनीकरण और वित्त पोषण संबंधी समिति के दूसरे सत्र में भाग लिया।

दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र-ईएससीएपी के साथ मिलकर 4 अक्तूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र

(यूएनसीसी) में अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस का आयोजन किया।

यूएनओडीसी

मादक पदार्थो और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा आयोजित होने वाले सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों और अभिसमयों में भारत ने सक्रिय भागीदारी जारी रखी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 18 से 22 मार्च, 2019 तक विएना में आयोजित स्वापक पदार्थ आयोग (सीएनडी) के 62 वें सत्र में भाग लिया और 20-24 मई, 2019 से आयोजित अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग (सीसीपीसीजे) के 28 वें सत्र में भाग लिया। भारतीय विशेषज्ञों ने राष्ट्र पारीय संगठित अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनटीओसी) और संयुक्त राष्ट्र अपराध अभिसमय (यूएनसीएसी) के कार्यकारी समूहों की बैठकों में भी भाग लिया।

वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 के लिए यूएनपी प्रभाग की सामग्री (1 अप्रैल, 2019 से)

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां सत्र

27 सितंबर 2019 को यूएनजीए की सामान्य वाद-विवाद के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से विकास के एजेंडे को स्वच्छ-भारत, जन-धन योजना, हर-घर-जल-अभियान और जन-भागीदारी पर भारत के कार्यों पर फोकस किया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश को वैश्विक शांति, विकास और प्रगति के लिए रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की स्थापना और आपदा रोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन बनाने की पहल के बारे में भी बात की तथा देशों को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 17 प्रमुख प्रतिनिधिमंडलों (कतर, नाइजर, इटली, नामीबिया, मालदीव, अमेरिका, बेल्जियम, आर्मेनिया, न्यूज़ीलैंड, एस्टोनिया, ईरान, साइप्रस, मॉरीशस, मैक्सिको, भूटान, बांग्लादेश, कोलम्बिया) और साथ ही यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

यूएनजीए के इतर प्रधानमंत्री ने कई उच्च-स्तरीय बैठकों में भाग लिया, जिसमें यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज संबंधी उच्च-स्तरीय बैठक और आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी बयानों के प्रति रणनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नेता की वार्ता शामिल है। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर 24 सितंबर 2019 को यूएन में एक स्मरणीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति, बांग्लादेश, जमैका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और भूटान के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भाग लिया और भाषण दिए। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की इमारत की छत पर स्थापित भारत द्वारा वित्तपोषित गांधी सोलर फार्म का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री को स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से भारत में स्वच्छता लक्ष्यों को साकार करने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2019 को पैसिफिक स्माल आईलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स (पीएसआईडीएस) के नेताओं के साथ बैठक और 25 सितंबर 2019 को कैरिबियाई समुदाय (सीएआरआईसीओएम) के नेताओं के साथ बैठक करते हुए दो प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रमों की मेजबानी की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्र के इतर हुई कई मंत्रिस्तरीय बहुपक्षीय बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया नामतः, भारत-जीसीसी ट्रोइका मंत्रिस्तरीय बैठक, जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वैड मंत्रिस्तरीय बैठक, ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक, सार्क मंत्रिपरिषद अनौपचारिक मध्याह्न भोजन बैठक और 'बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन' की मंत्रिस्तरीय बैठक। इसके इतर इएएम ने 44 देशों (अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, ब्राजील, ब्रुनेई दारुस्सलाम, बुल्गारिया, चिली, चीन, कोटे-डी-वायर, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, फिजी, फ़िनलैंड, जर्मनी, ग्रेनेडा, गुयाना, ईरान, इटली, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, मालदीव, नेपाल, नीदरलैंड, पराग्वे, सिएरा लियोन, सिंगापुर, स्लोवाकिया, सीरिया, तजाकिस्तान, थाईलैंड, थाईलैंड तुर्की, यूएई, यूक्रेन, युगांडा, उज्बेकिस्तान, साथ ही साथ अफगानिस्तान और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि के लिए अमेरिकी विशेष दूत) से अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और अलग से बैठकें आयोजित की।

विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों के इतर कई मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया नामतः एशिया मंत्रिस्तरीय बैठक में सहभागिता और विश्वास-निर्माण उपायों पर सम्मेलन, एनएएम मंत्रिस्तरीय बैठक, राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक, जी-77 मंत्रिस्तरीय बैठक और एसएएमओए पाथवे बैठक। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों जैसे एससीओ, सीआईएस और सीएसटीओ के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग संबंधी वाद-विवाद में भी भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का दौरा

यूएनजीए के 74 वें सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर तिज्जानी मुहम्मद-बेंदे ने 1-4 सितंबर 2019 से नई दिल्ली का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और ईएएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार से भी मुलाकात की और आईआईटी, दिल्ली में छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज का दौरा किया और भारतीय विश्व मामलों की परिषद में एक भाषण-सह-बातचीत कार्यक्रम में भाग लिया।

भारत और शांति अभियान

8. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सबसे बड़े संचयी योगदानकर्ता के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपने बहुआयामी योगदान को जारी रखा। 31 अक्तूबर 2019 तक भारत ने 9 शांति अभियानों में 6,183 कर्मियों को तैनात किया है जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं। महिला शांति सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के तहत हमने एमओएनयूएससीओ (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन) में तेजी से तैनात किए जाने वाले बटालियन (आरडीबी) में एक वूमन इंगेजमेंट टीम (एफईटी) को तैनात किया है।

9. भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए अन्य देशों की क्षमता निर्माण हेतु भी अपना समर्थन जारी रखा। नई दिल्ली में सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग (सीयूएनपीके) ने कई अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संचालित किए जिनमें युनाइटेड नेशंस स्टाफ और लॉजिस्टिक ऑफिसर्स कोर्स (यूएनएसएलओसी), संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम (यूएनएमओसी) और संयुक्त राष्ट्र सैन्य आनुषंगिक पाठ्यक्रम (यूएनएमसीओसी) शामिल हैं। सीयूएनपीके ने संयुक्त राज्य के साथ मिलकर अफ्रीकी साझेदारों हेतु चौथे यूएन शांति पाठ्यक्रम (यूएनपीसीएपी) (10-28 जून 2019) का भी आयोजन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 6 दिसंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका, पुर्तगाल, सेनेगल, उरुग्वे और वियतनाम के साथ शांति स्थापना निष्पादन में सुधार पर संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम की सह-मेजबानी भी की।

संयुक्त राष्ट्र की आंतकवाद रोधी कार्रवाई

10. इस अवधि के दौरान भारत ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता को उद्धृत करना जारी रखा; विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को अंतिम रूप देकर। भारत ने सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित विभिन्न प्रतिबंध समितियों और संयुक्त राष्ट्र के भीतर अधिक से अधिक संस्थागत सहयोग की दिशा में काम करने के लिए मौजूदा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी संरचनाओं की अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता का भी आहवान किया।

11. प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर, 2019 को 74 वें यूएनजीए के दौरान आतंकवादी और हिंसक अतिवाद बयानों के प्रति रणनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नेताओं की वार्ता में अपने भाषण में उल्लेख किया कि आतंकवाद और चरमपंथ के विरूद्ध हमारे प्रयास और बयान तभी सफल हो सकते हैं, जब इसे जनता का समर्थन और मान्यता मिल जाए। सामान्य नागरिकों द्वारा आतंकवाद की अस्वीकृति आतंकवाद की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने इस बात को उद्धृत किया कि आतंकवाद जीवन के अधिकार जैसी मूलभूत मूलभूत अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता है।

12. भारत ने 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की प्रतिबंध समिति के साथ मिलकर काम किया और साथ ही प्रतिबंधों व्यवस्था के सदस्य राष्ट्रों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अल-कायदा और तालिबान निगरानी टीम के साथ काम किया। कई वर्षों तक लगातार प्रयासों के बाद अंत में 1 मई 2019 को, मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत सूचीबद्ध किया गया।

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी

13. वर्ष के दौरान, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली हिंदी सामग्री की मात्रा और आवृत्ति में वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र की हिंदी वेबसाइट शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में सोशल मीडिया साइट्स को भी लॉन्च किया, जिसमें फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम और हिंदी में ब्लॉग शामिल हैं। यूएन ने साउंड क्लाउड पर साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र समाचार मोबाइल ऐप का हिंदी विस्तार भी शुरू किया।

गुट निरपेक्ष आंदोलन

14. उपराष्ट्रपति (वीपी) श्री एम. वेंकैया नायडू ने 25-26 अक्तूबर, 2019 को बाकू, अजरबैजान में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के राष्ट्र प्रमुखों और सरकारों के 18वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने बताया कि एनएएम को बदलते समय के साथ तालमेल रखना चाहिए और एक उपयोगी और प्रभावशाली समूह बनने के लिए खुद को परिष्कृत करना चाहिए जो उभरती वैश्विक चुनौतियों पर अपने सदस्य देशों के हितों को बढ़ावा दे सके। शिखर सम्मेलन के इतर उपराष्ट्रपति ने वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा और वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठकें की तथा ईरान के राष्ट्रपति और बांग्लादेश एवं नेपाल के प्रधानमंत्रियों के साथ भी बैठकें की।

15. ईएएम ने 23-24 अक्तूबर 2019 को बाकू, अजरबैजान में आयोजित एनएएम मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। अपने वक्तव्य में ईएएम ने कहा कि एक लोकतांत्रिक, प्रभावी, लचीला, विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रतिनिधिमूलक बहुपक्षीय व्यवस्था - 'संशोधित बहुपक्षवाद' 21 वीं सदी की अनिवार्यता है। ईएएम ने बहरीन, कैमरून, ईरान, इराक, केन्या, कुवैत, मलेशिया, म्यांमार, मलेशिया, सर्बिया, श्रीलंका, वेनेजुएला, यमन के अपने समकक्षों और अफगानिस्तान के एनएसए के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

16. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने 21 जुलाई 2019 के दौरान वेनेजुएला के काराकस में आयोजित एनएएम मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

राष्ट्रमंडल

17. ईएएम ने 10 जुलाई 2019 को लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक (सीएफएएमएम) में भाग लिया। विदेश राज्य मंत्री ने 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र के इतर आयोजित सीएफएएमएम में भाग लिया। भारत ने उच्च स्तरीय समूह (एचएलजी) में भी सक्रिय भूमिका निभाई जिसे राष्ट्रमंडल सचिवालय की शासन व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित किया गया था।

18. कॉमनवेल्थ देशों के 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए एक क्रिकेट कोचिंग कैंप 1-30 अक्तूबर 2019 से बेंगलुरु के राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में आयोजित किया गया था। इस कैंप में 16 कॉमनवेल्थ देशों के 18 लड़के और 17 लड़कियों सहित 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अप्रैल 2018 में लंदन में सीएचओजीएम में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इस शिविर का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रमंडल देशों के लिए बढ़ाए गए समर्थन के अनुसार भारत ने तकनीकी सहयोग के लिए कोष अंशदान (सीएफटीसी), न्यू यॉर्क और जेनेवा में राष्ट्रमंडल के छोटे देशों के कार्यालयों को अतिरिक्त अंशदान दिया और साथ ही साथ भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के 'कॉमनवेल्थ सब विंडो' के माध्यम से साझेदार देशों की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया।

12

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका)

ग्यारहवां ब्रिक्स शिखर-सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “ब्रिक्स : अंतर्वेशी भविष्य के लिए आर्थिक विकास” विषय के अंतर्गत ब्रासीलिया में 13-14 नवम्बर, 2019 को आयोजित ग्यारहवें ब्रिक्स शिखर-सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। शिखर-सम्मेलन की कार्रवाईयों की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जेर.एम. बोल्सोनारो ने की। चीन के राष्ट्रपति श्री जी. जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादीमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामाफोसा ने शिखर-सम्मेलन में अपने-अपने देशों के शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया।

शिखर-सम्मेलन में, नेताओं ने वैश्विक वित्तीय और सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद का सामना, जलवायु परिवर्तन, संधारणीय विकास, बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और अंतर्राष्ट्रीय शासन की संस्थाओं के सुधार, अंतरा-ब्रिक्स सहयोग को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। इनके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, लोगों-के-लोगों के साथ संपर्क पर भी चर्चा की गई। ब्रिक्स व्यापार परिषद् तथा नवीन विकास बैंक ने भी अपने-अपने प्रतिवेदन शिखर-सम्मेलन के नेताओं को प्रस्तुत किए।

13 नवम्बर, 2019 को भारत के एक बड़े व्यापार शिष्टमंडल ने ब्रिक्स व्यापार फोरम में प्रतिभागिता के जिसमें अन्य ब्रिक्स देशों से व्यापार समुदाय ने

भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ ब्रिक्स व्यापार फोरम के समापन समारोह में भाग लिया।

वर्ष 2019 में ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता के व्यापक परिणाम थे - अभिनवता ब्रिक्स नेटवर्क (i-ब्रिक्स) और ब्रिक्स महिला व्यापार संधि (डब्ल्यूबीए) की स्थापना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभिनवता (एसटीआई) पर नई वास्तुकला का अंगीकरण, ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफार्म के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप प्रदान करना। इसके अलावा, आतंकवाद - निवारण के लिए ब्रिक्स कार्यनीतियों पर एक संगोष्ठी, मानव दुग्ध बैंकों पर एक कार्यशाला और ब्रिक्स आस्ति वसूली बैठक का भी आयोजन किया गया। ब्रिक्स व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसियों (टीआईपीए) के मध्य समझौता-ज्ञापन तथा निजी निवेश संघटन पर समझौता ज्ञापन पर भी 2019 पर हस्ताक्षर किए गए।

शिखर-सम्मेलन के परिणामों में शामिल था - ब्रासीलिया घोषणा - जिसमें ब्रिक्स नेताओं ने संप्रभुत्ता, पारस्परिक सम्मान और समानता तथा शांतिपूर्ण, स्थायी और समृद्ध विश्व के निर्माण के साझे लक्ष्य की पुन: पुष्टि की। ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद की, उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। आतंकवाद का निवारण और उसका सामना करने में राज्यों और उनके सक्षम प्राधिकारियों की प्राथमिक भूमिका को मान्यता प्रदान करते हुए, नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के तवावधान के अंतर्गत आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सत्त प्रयासों का आह्वान किया।

बहुलवाद के समक्ष वर्तमान में आ रही उल्लेखनीय चुनौतियों को पहचानते हुए, ब्रिक्स नेताओं ने बहुपक्षीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसमें सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता को दोहराया जिसमें संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है। संधारणीय विकास के महत्व को प्रदर्शित करते हुए ब्रिक्स नेताओं ने इन्हें क्रियान्वित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया : संधारणीय विकास के लिए 2030 एजेंडा, पेरिस करार, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) 15.3 को हासिल करने के उद्देश्य से 14 संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) के परिणाम, अपक्षरित भूमि और मृदा का पुन: सुधार करना तथा एक भूमि अपदरन-निष्पक्ष विश्व हासिल करने का प्रयास करना।

ब्रिक्स नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मिलने वाली सत्त चुनौतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुरूप सभी के लिए स्थायी शांति के लिए कार्य करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन और संचयन के प्रतिषेध तथा उनके विनाश (बीटीडब्ल्यूसी) पर कन्वेंशन, रासायनिक निषेध के लिए संगठन पर हथियार (ओपीसीडब्ल्यू) और रासायनिक हथियार कन्वेंशन (सीडब्ल्यूसी) के परिरक्षण के महत्व को रेखांकित किया तथा उसके प्रति अपना समर्थन प्रकट किया।

ब्राजीलिया घोषणा में अन्य अवयवों में शामिल हैं: (i) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण और उसका शांतिपूर्ण प्रयोग, (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के लिए मुक्त, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, स्थायी, अभिगम्य और गैर-भेदभावपूर्ण परिवेश, (iii) वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (एफएटीएफ) के साथ सहयोग, (iv) वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी, (v) एक मजबूत, कोटा आधारित और पर्याप्त रूप से संसाधन आईएमएफ (vi) डब्ल्यूटीओ सुधार (vii) उत्पादक क्षेत्र, ई-वाणिज्य, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई), अवसंरचना और संयोजन में निवेश।

ब्रिक्स नेताओं ने ब्राजील में नवीन विकास बैंक (एनडीटी) क्षेत्रीय कार्यालय के खोले जाने का स्वागत किया तथा अवसंरचना और संधारणीय विकास वित्त-

पोषण में एनडीबी की भूमिका की प्रशंसा की। नेताओं ने ब्रिक्स देशों में एनडीबी द्वारा 12.8 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 46 परियोजनाओं के अनुमोदन का स्वागत किया। उन्होंने ब्रिक्स स्थायी मुद्रा बांड निधि की स्थापना में हासिल की गई प्रगति को भी नोट किया तथा आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए संचालित किए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया। अपने सदस्यों के मध्य व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने में ब्रिक्स व्यापार परिषद् (बीबीसी) के प्रयासों की भी घोषणा में मान्यता प्रदान की गई।

ओसाका जी-20 शिखर-सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं की औपचारिक बैठक

ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जेर एम. बोल्सोनारो की अध्यक्षता में ब्रिक्स नेताओं की प्रथागत औपचारिक बैठक ओसाक, जापान में जी-20 शिखर-सम्मेलन के दौरान 28 जून, 2019 को आयोजित की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, रूसी प्रधानमंत्री श्री व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति श्री जी. जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामाफोसा ने बैठक में प्रतिभागिता की। नेताओं ने जी-20 शिखर-सम्मेलन के एजेंडा पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया तथा जी-20 में ब्रिक्स देशों के वैश्विक और पारस्परिक हितों के मुद्दों पर कार्यवाही करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा, बैठक के एजेंडा में वैश्विक, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वैश्विक शासन के महत्वपूर्ण और पारस्परिक हितों की एक बड़ी श्रृंखला शामिल थी। बैठक में संयुक्त मीडिया वक्तव्य भी जारी किया गया।

ब्रिक्स विदेश मंत्री बैठक, रियो डि जेनेरियो, ब्राजील

ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश/अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्रियों की बैठक 25-26 जुलाई, 2019 को रियो डि जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित की गई जिसमें ब्राजील संघीय गणराज्य, रूसी परिसंघ, भारतीय गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य ने प्रतिभागिता की। मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के मुख्य मुद्दों पर चारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने ब्रिक्स सहयोग की प्रगति की संतोष के साथ समीक्षा की जिसमें पारस्परिक सम्मान और समझ, समानता, एकजुटता, खुलापन, अंतर्वेशिता और पारस्परिक लाभ का सहयोग शामिल था। मंत्रियों ने अर्थव्यवस्था, शांति और सुरक्षा तथा लोगों-का-लोगों के साथ संपर्क के क्षेत्रों में ब्रिक्स त्रि-आयाम-चालित सहयोग को और गहन बनाने पर सहमति व्यक्त की।

यूएनजीए के दौरान ब्रिक्स मंत्रियो की बैठक

विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने न्यूयार्क में 26 सितम्बर, 2019 को आयोजित 74वें यूएनजीए के दौरान ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की पारंपरिक बैठक में भाग लिया। 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले रूस ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आने वाले ब्रिक्स शिखर-सम्मेलन के लिए ब्रिक्स सहयोग और उसकी तैयारियों पर चर्चा की गई। रूसी पक्ष ने ब्रिक्स की 2020 में अध्यक्षता से संबंधित रूस की योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की।

जी-20

चौदहवां जी-20 शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओसाका, जापान में 28-29 जून, 2019 को आयोजित चौदहवें जी-20 शिखर-सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृतव किया। जी-20 शिखर-सम्मेलन के विषय थे वैश्विक सत्त विकास सुनिश्चित करने के लिए 'वैश्विक अर्थव्यवस्था', व्यापार और निवेश', अभिनवता', 'पर्यावरण और ऊर्जा', 'नियोजन', 'महिला अधिकारिता', 'विकास' और 'स्वास्थ्य'।

ओसाका, जापान में जी 20 शिखर सम्मेलन 2019 के सदस्य देशों के प्रमुखों की सामूहिक फोटो (28 जून ,2019)

शिखर-सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'असमानताओं का निवारण, एक अंतर्वेशी और संधारणीय विश्व की परिकल्पना' विषय पर आयोजित सत्र में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का उल्लेख किया तथा यह बताया कि किस प्रकार हमारी सभी नीतियों में यही भावना निहित है। उन्होंने भारत सरकार की कुछ पहलों को रेखांकित किया जिसमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' भारत में शौचालयों का निर्माण, मुद्रा योजना शामिल हैं जिसके अंतर्गत 78 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। उन्होंने बल प्रदान किया कि भारत का व्यापक जनसांख्यिकीय आधार वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्राप्ति के लिए योगदान करेगा।

अन्य सत्रों में अपनी बात रखने के दौरान, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने, महिला अधिकारिता, पर्यटन, कृषि, अंतर्वेशी और संधारणीय विकास, अंतर्वेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य और वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, डिजिटल

अर्थव्यवस्था, सोसाइटी 5.0, मुक्त और लोचदार वित्तीय प्रणाली, भ्रष्टाचार-रोधी उपायों की आवश्यकता पर बल प्रदान किया।

जी-20 ओसाका नेताओं की घोषणा ने प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का सामना करने तथा सभी के लिए लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिजिटलीकरण और इसके अनुप्रयोग में प्रौद्योगिकीय अभिनवता की शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रमुख वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का निवारण करने और वैश्विक आर्थिक विकास को संपोषित करने के लिए मिलकर प्रयास करने पर ध्यान-केन्द्रित किया। घोषणा में इनके बारे में संदर्भ शामिल किए गए थे: (i) सुदृढ़, संधारणीय, संतुलित और अंतर्वेशी विकास, (ii) वैश्विक एकाउंट असमानताएं, (iii) जनसांख्यिकीय परिवर्तन, (iv) एक मुक्त, समुचित, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य और स्थायी व्यापार एवं निवेश परिवेश (v) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधार, (vi) डिजिटलीकरण, भरोसे के साथ डाटा फ्री फ्लो (vii) गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेश, (viii) केन्द्र में एक सुदृढ आईएमएफ के साथ वैश्विक वित्तीय सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ बनाना (ix) उचित, संधारणीय और आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कर प्रणाली (x) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष (xi) एक स्वस्थ और सक्रिय वृद्ध होते समाज को प्रोत्साहित करना (xii) लिंग-समानता और महिला अधिकारिता, (xiii) पर्यटन, (xiv) कृषि, (xv) सतत विकास एसडीजी का क्रियान्वयन, (xvi) वैश्विक स्वास्थ्य (xvii) वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दें तथा जलवायु परिवर्तन (xviii) ऊर्जा सुरक्षा, (xix) प्रवास और विस्थापन।

जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक, नागोया, जापान

विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने 22-23 नवम्बर, 2019 को नागोया में आयोजित जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में जी-20 विदेश मंत्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया अर्थात् बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन, संधारणीय विकास और अफ्रीका। विदेश मंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत के प्रयासों पर तथा अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों पर भी टिप्पणी की।

ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7)

जी-7 शिखर-सम्मेलन, बायरिट्ज, फ्रांस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25-26 अगस्त, 2019 को बायरिट्ज, फ्रांस में जी-7 शिखर-सम्मेलन के संपर्क सत्रों में सद्भावना के भागीदार - बायरिट्ज भागीदार' भारतीय प्रतिभागिता का नेतृत्व किया। शिखर-सम्मेलन का आयोजन 'असमानता से संघर्ष' के समग्र विषय के अंतर्गत किया गया था जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में महिला अधिकारिता और लिंग समानता, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपांतरण, सुरक्षा और आतंकवाद भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने दो संपर्क सत्रों में भी प्रतिभागिता की अर्थात् जलवायु, जैव-विविधता और महासागर तथा डिजिटल रूपांतरण।

प्रधानमंत्री फ्रांस के बियारिट्ज़ में जी -7 शिखर सम्मेलन के 'जैव विविधता, महासागर, जलवायु' सत्र में भाग लेते हुए (अगस्त 26, 2019)

डिजिटल रूपांतरण पर आयोजित सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री ने अधिकारिता और समावेश के माध्यम से सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने रूपांतरणकारी प्रौद्योगिकी की शक्ति, अभिनवता को प्रोत्साहन दिए जाने तथा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भारत द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का भी उल्लेख किया।

जलवायु, जैव-विविधता और महासागर विषय पर आयोजित सत्र में प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक के प्रयोग के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत में बाघों और शेरों की संख्या में वृद्धि होने का भी उल्लेख किया जो जैव-विविधता के संरक्षण के लिए सफल दृष्टिकोण का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए संवर्धित बहुपक्षवाद की आवश्यकता को भी दोहराया कि वैश्विक चुनौतियों का अर्थपूर्ण ढंग से निपटान किया जा रहा है।

आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका)

आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक

विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने 26 सितम्बर, 2019 को यूएनजीए के दौरान आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ब्राजील के विदेश मंत्री श्री एर्नेस्टो एरॉजो तथा दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री सुश्री नालेडी पेंडोर ने बैठक में भाग लिया। बैठक में मंत्रियों ने बहुपक्षीय प्रणाली के

सुधार पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)

भारत ने 'सीमित क्षेत्रक संबंध' के लिए प्रारंभ की गई अपनी नीति के अंतर्गत ओईसीडी के साथ अपने संबंधों को जारी रखा। वर्ष के दौरान ओईबीडी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दो बार भारत का दौरा किया।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)

भारत ने यूएनसीटीएटी की विभिन्न बैठकों में अपनी प्रतिभागिता जारी रखी।

13

विकास भागीदारी

पिछले कुछ वर्षों में भारत की विकास सहायता के क्षेत्र और पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। भारत के स्थायी भू-राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक हितों और भारत के सहायता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता ने विकासशील देशों के साथ विशेष रूप से विकास सहायता के मोर्चे पर अधिक से अधिक जुड़ाव पैदा किया है। इसके लिए जनवरी 2012 में विकास साझेदारी व्यवस्था (डीपीए) का सृजन किया गया ताकि अवधारण, लोकार्पण, निष्पादन और समापन के विभिन्न चरणों के माध्यम से भारत की विकास सहायता परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। डीपीए, मंत्रालय में प्रादेशिक प्रभागों के साथ गहन समन्वय के साथ कार्य करता है, जो उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने में भागीदार देशों के साथ प्रमुख वार्ताकार बने हुए हैं। डीपीए परियोजना मूल्यांकन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता उत्तरोत्तर विकसित कर रहा है।

भारत की विकास साझेदारी भागीदार देशों की जरूरतों पर आधारित है और इन देशों से तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य के रूप में प्राप्त कई अनुरोधों पर कार्य करने के लिए तैयार है। भारत की विकास सहायता के मुख्य साधनों में ऋण व्यवस्था (एलओसी), अनुदान सहायता, लघु विकास परियोजनाएं (एसडीपी), तकनीकी परामर्श, आपदा राहत और मानवीय सहायता, साथ ही साथ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के तहत नागरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल है। विकास

सहायता में भारत के पड़ोसी देश और अफ्रीका के देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, हालाँकि भारत दक्षिण पूर्व एशिया, कैरिबियाई, लैटिन अमेरिका, मंगोलिया, पैसिफिक द्वीप देशों आदि में भी अपनी विकास सहायता पहुंचा कर अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है।

ऋण सहायता

मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एलओसी उधार लेने वाले देशों को भारत से वस्तुओं और सेवाओं को आयात करने और उनकी विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार बुनियादी ढाँचे के विकास और क्षमता निर्माण के लिए परियोजनाएँ शुरू करने में सक्षम बनाता है।

एलओसी आईडीईएएस दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2015 को संशोधित और जारी किया गया था। एलओसी कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के कई क्षेत्रों को अनिवार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), परामर्शदाता और संविदाकारों के चयन हेतु पूर्व-योग्यता (पीक्यू) प्रक्रिया, एक विस्तृत निगरानी तंत्र का संस्थागतकरण और भारतीय परामर्श फर्मों और ईपीसी संविदाकारों का पैनल सहित लागू किया गया है।

नयी ऋण व्यवस्था

वर्तमान वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 2019) में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित नए एलओसी का विस्तार किया गया है:

1. सिलेंगे (मबुजी-मायी) में 15 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के लिए डी.आर. कांगो सरकार को 56.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
2. मेनोनो में 10 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए डी.आर. कांगो सरकार को 26.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी दिया गया।
3. जिमेना में 15 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए डी.आर. कांगो सरकार को 56.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
4. विदेशी नीति प्रशिक्षण संस्था के पूरे होने के लिए घाना सरकार को 2.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
5. कृषि मशीनीकरण सर्विस सेंटर को मजबूत करने के लिए घाना सरकार को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी ऑफर किया गया।
6. येंडी, घाना में पेयजल प्रणाली की पुनर्व्यवस्था और उन्नयन के लिए घाना को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
7. सौर परियोजनाओं के लिए गुएना रिपब्लिक सरकार को 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
8. ग्रैंड कोनार्की-होराइजन 2040 की पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए इस परियोजना हेतु गुएना रिपब्लिक सरकार को 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
9. बोंगोलावा, मेनाबे और अनलामंगा क्षेत्र में सिंचाई, कृषि मशीनीकरण और खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र हेतु मेडागास्कर सरकार को 80.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।

10. माली में धारणीय ग्राम की स्थापना करने और 2500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए सौर फोटो वोल्टिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए माली सरकार को 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
11. फाना, माली में 50 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के लिए माली सरकार को 60.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
12. राष्ट्रीय ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क (एनआरबीएन) की स्थापना के लिए नाईजीरिया सरकार को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
13. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से प्रशिक्षु जहाज के अधिग्रहण के लिए नाईजीरिया सरकार को 50.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
14. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से एक लैंडिंग शिप टैंक के प्रापण के लिए नाईजीरिया सरकार को 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
15. दो सौर परियोजनाओं के लिए रवांडा सरकार को 122 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
16. ह्वांगे ताप विद्युत केन्द्र को पुनर्जीवित करने के लिए जिम्बावे सरकार को 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
17. मंगोलिया की पेट्रोरसायन शोधन परियोजना के लिए मंगोलिया सरकार को 236 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
18. किास और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए श्रीलंका सरकार को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
19. अवसंरचना और अन्य विकास परियोजना के लिए रूसी संघ सरकार को 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
20. रक्षा उपकरण प्रापण के वित्तपोषण के लिए उज्बेकिस्तान सरकार को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
21. विकास परियोजनाओं के लिए बोलिविया सरकार को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
22. सूरीनाम के 50 दूरस्थ गांवों में सौर डीजी हाइब्रिड पीवी प्रणालियों के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सूरीनाम सरकार को 35.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
23. विद्युत आपूर्ति की संवर्धित गुणवत्ता के लिए मोजाम्बिक को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।
24. रक्षा आपूर्ति परियोजना के लिए सेशेल्स को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया गया।

पूर्ण एलओसी परियोजनाएं

1. 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत कोट डिलवोइर और माली के बीच विद्युत अंतर्संयोजना परियोजना।
2. मलावी को 23.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत लिखुबुला नदी में मुलांजे से ब्लांटायर तक नयी जलापूर्ति प्रणाली का निर्माण (18 अक्तूबर, 2019 को उद्घाटन)।
3. सेनेगल सरकार को 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा 500 बसों की आपूर्ति।
4. 8.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत बांग्लादेश को 500 ट्रकों की आपूर्ति।

5. 46.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत बांग्लादेश को 600 बसों की आपूर्ति।
6. लाओ पीडीआर सरकार को 30.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत वित्तपोषित 7.35 मिलियन अमेरिकी डालर वाली सवानाखेत और वियंटियन लाओ में डीजल चालित पंपों को शुरू करना (विद्युत पंपों में बदलना) और विद्युत पंपों का उन्नयन करना।
7. 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत निकारागुआ में दो विद्युत उपकेंद्रों को स्थापित करने के लिए उपकरणों की आपूर्ति।
8. 25.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत कोट डिलवोइर में महात्मा गांधी आईटी और जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन (जून, 2019 में)।
9. 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत गुएना बिसाउ में ग्रामीण विद्युतीकरण।

2019-20 में पूरी की जाने वाली अन्य एलओसी परियोजनाएं

1. केन्या सरकार को 29.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत रिफ्ट वैली टेक्सटाइल्स (आरआईवीएटीईएक्स) फैक्ट्री का उन्नयन। इसे मार्च, 2020 तक पूरे किए जाने की संभावना है।
2. सेनेगल सरकार को 27.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना।
3. तंजानिया सरकार को 256.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत तबोरा, इगुंगा और नजेगा तक लेक विक्टोरिया पाईपलाइन का विस्तार।
4. तंजानिया सरकार को 32.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत 178.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण के अंतर्गत तेगेटा से बागामोया और बेजी से लैंडिजी तक द्वितीयक और तृतीयक सिंचाई संवितरण नेटवर्क की स्थापना और आपूर्ति।
5. 0.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बांग्लादेश में पूर्णत: निर्मित आरएचडी के सर्किल प्रयोगशाला और संबद्ध सेवाओं के लिए प्रयोगशाला उपकरण का प्रापण।
6. 0.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बांग्लादेश में 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूर्जे और संबद्ध सेवाओं के साथ पूर्णत: तैयार 10 स्पॉट मिक्सिंग अस्फाल्ट प्लांट्स।
7. 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से बुर्किना फासो को बसों की आपूर्ति।
8. मारिशस सरकार को 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के तहत 7.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा डोनियर डीओ-228 एयरक्राफ्ट का उन्नयन।

अन्य एलओसी पहल

- बांग्लादेश सरकार के लिए विस्तारित भारत सरकार की 16 वीं भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय समीक्षा बैठक 25-26 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। रेलवे, बंदरगाह, सड़क, बिजली और पारेषण लाइन, शिपिंग, अस्पतालों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 46 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश में 7.862 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली एलओसी प्रदान की है। बैठक

से दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने, परियोजना के कार्यान्वयन में संभावित अड़चनों की पहचान करने और बकाया मुद्दों को हल करना में मदद मिली।

- नेपाल सरकार को प्रदान की गयी भारत सरकार की एलओसी के संबंध में 8 वीं भारत-नेपाल द्विपक्षीय समीक्षा बैठक काठमांडू में 02 दिसंबर 2019 को आयोजित की गई। भारत सरकार ने नेपाल सरकार को सड़क, बिजली और पारेषण लाइन, हेरिटेज बिल्डिंग, भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण आदि जैसे परियोजना क्षेत्रों के लिए 1.650 बिलियन अमरीकी डालर का एलओसी प्रदान किया है। चार एलओसी के तहत सभी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा की गयी। उनकी प्रगति की निगरानी करने और इन परियोजनाओं के समक्ष आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख परियोजना स्थलों की स्थल निरीक्षण भी किये गये।
- चल रही एलओसी परियोजनाओं की निगरानी के तहत, रोटेशन के आधार पर कई देशों के साथ द्विपक्षीय समीक्षा की गई। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति रिपोर्ट भारतीय मिशनों और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया से भी प्राप्त हुई थी।
- **रक्षा ऋण व्यवस्था :** इस साल सात नई रक्षा ऋण व्यवस्थाओं की भी घोषणा की गई जैसे नाइजीरिया (70 मिलियन अमेरिकी डॉलर), वियतनाम (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर), श्रीलंका (50 मिलियन अमेरिकी डॉलर), बांग्लादेश (100 मिलियन अमेरिकी डॉलर), मॉरीशस (100 मिलियन अमेरिकी डॉलर), सेशेल्स (100 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।
- **रूस :** माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 4-5 सितम्बर, 2019 को व्लादिवोस्तोक में 20वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन और 5वें पूर्वी आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के दौरान रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में 'अवसंरचना और अन्य विकास परियोजनाओं' को शुरू करने के लिए रूस को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी की घोषणा की गयी। कोयला, खनन, बिजली, पेट्रोलियम, जनशक्ति, चीनी मिट्टी की चीज़ें, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जहाज निर्माण और तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्रों की रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र में भारत के लिए संभावित हित के प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

परियोजना तैयारी सुविधा (पीपीएफ)

भारत ने अपने विकास सहयोगी देशों को ऐसी व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए परियोजना निरूपण रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार में सहायता करने के लिए प्रोजेक्ट तैयारी सुविधा (पीपीएफ) नामक एक प्रणाली स्थापित की गई है, जिस पर 2018 में लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत रियायती वित्त-पोषण के लिए विचार किया जा सकता है। पीपीपी परियोजना की कल्पना करने के लिए और एक उचित प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता की पहचान करने के लिए क्षमता के अंतर की पूर्ति करता है।

पीपीएफ अनुरोध करने वाली सरकारों को परियोजना निर्माण के लिए अनुदान आधार पर परामर्श सहायता प्रदान करेगा। यह एक मांग-प्रतिक्रिया तंत्र है और अनुरोध करने वाली सरकारों से प्राथमिकता वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए एक त्वरित पहुँच सुविधा है।

चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पीपीएफ के अंतर्गत प्रस्तुत की गईं परियोजना निरूपण रिपोर्टें इस प्रकार हैं:

- माली में 2,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए एक संधारणीय गाँव की स्थापना और

सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। यह परियोजना माली सरकार को 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत प्रारंभ की जानी है।

- फना, माली में 50 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र। यह परियोजना माली सरकार के को 60.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत प्रारंभ की जानी है।
- सूरीनाम के दूर-दराज इलाकों के 50 गांवों में हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम (सौर और डीजल आधारित) के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण। यह परियोजना सूरीनाम की सरकार द्वारा 35.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत प्रारंभ की जानी है।
- लाइबेरिया में बाली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 382.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक सड़क परियोजना।
- म्यांमार के नई पे ताव में अत्याधुनिक सामान्य अस्पताल।
- चूना पत्थर पर परियोजना का पुनर्वास जिसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत पूरा किया गया।

सौर परियोजनाएं

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सौर ऊर्जा की त्वरित और बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन की दिशा में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री की एक बड़ी पहल है। 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आईएसए का संस्थापक सम्मेलन इस दिशा में एक प्रभावी पहल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा पर सहयोग के लिए सभी देशों को एक साथ लाना है। यह स्मरणीय है कि इस संस्थापक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से 15 देशों, विशेष रूप से अफ्रीका में 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 27 परियोजनाओं को कवर करने के लिए लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) देने की भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। इनमें ईबीआईडी (निवेश और विकास के लिए ईसीओडब्ल्यूएएस बैंक) के अंतर्गत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि वाली 6 सौर परियोजनाएं शामिल हैं और शेष 21 सौर परियोजनाएं 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की हैं। इसके अंतर्गत, 200.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का लाइन ऑफ क्रेडिट को बांग्लादेश को और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विभिन्न सौर परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को विस्तारित किया गया है। इस वर्ष में, 140.33 मिलियन अमेरिकी डॉलर (3 अलग एलओसी) के नए लाइन ऑफ़ क्रेडिट, 35.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को, सूरीनाम, 122 मिलियन अमेरिकी डॉलर रवांडा के लिए, 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर गिनी के लिए, 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 60.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर माली को विस्तारित किए गए हैं। ये सौर परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

पड़ोसी देशों में अनुदान सहायता के साथ विकास परियोजनाएं

पड़ोसी देशों में भारत सरकार की अनुदान सहायता के साथ कार्यान्वित की जा रही विकास परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर जिसमें निर्माण, सड़क और पुल, जलमार्ग और ट्रांसमिशन लाइनों के

साथ-साथ बिजली उत्पादन, कृषि, क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि तक के क्षेत्रों की एक श्रृंखला को कवर करती हैं।

अनुदान सहायता के अंतर्गत श्रीलंका आवासीय परियोजना

श्रीलंका के साथ भारत की विकास साझेदारी एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के पुनर्वास के लिए 50,000 घरों के निर्माण से संबंधित आवासीय परियोजना बेहतर रूप से चल रही है :

- उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में एक स्वामी-संचालित प्रक्रिया के अंतर्गत 46,000 घरों का निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा हो गया है।
- श्रीलंकाई सरकार द्वारा 1134 घरों के लिए भूमि की पहचान की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वृक्षारोपण क्षेत्र में कार्यरत भारतीय मूल तमिलों (आईओटी) के लिए मध्य और उवा प्रांतों में 4,000 घरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। 1134 घरों के पहले लॉट का निर्माण अक्तूबर 2016 में शुरू किया गया था। 2866 घरों के दूसरे लॉट के मकानों का निर्माण भी चरणों में शुरू किया गया था। 30 नवंबर 2019 तक, 4000 में से 2243 मकान पूरे हो चुके हैं और 1550 मकान निर्माणाधीन हैं।
- भारत के प्रधानमंत्री ने मई 2017 में श्रीलंका की यात्रा के दौरान श्रीलंका के मध्य और उवा प्रांतों में भारतीय मूल के तमिलों के लिए अतिरिक्त 10,000 घरों के निर्माण के लिए घोषणा की। नवंबर 2019 में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के बाद, नई सरकार, 10,000 घरों के नए लॉट के लिए स्थान प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है और जल्द ही इसे कोलंबो में भारतीय मिशन को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

अफ्रीका में विकास परियोजनाएं

अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी सहयोग के एक मॉडल, विकास के अनुभवों को साझा करने पर आधारित है और अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को संबोधित करने पर केंद्रित है। विभिन्न विकास साझेदारी पहल के माध्यम से अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। वर्ष 2008, 2011 और 2015 में आयोजित किए गए तीन भारत-अफ्रीका फोरम शिखर-सम्मेलनों [आईएएफएस I, II और III] ने महाद्वीप के साथ विकास साझेदारी को और सुदृढ़ बनाया है।

विभिन्न क्षेत्रों जैसे सौर संयंत्र, पनबिजली, बिजली ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क, बांधों, सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, कृषि और सिंचाई, औद्योगिक इकाइयों, कौशल विकास, सिविल निर्माण आदि में अफ्रीकी देशों में 12.50 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल 204 एलओसी का विस्तार किया गया है। नए क्षेत्रों जैसे दूरसंचार को भी इस वर्ष अफ्रीका में भारत सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अफ्रीका में कुछ महत्वपूर्ण एलओसी / अनुदान परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं :

- भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के अंतर्गत सेनेगल में उद्यमी और तकनीकी विकास केंद्र (ईटीडीसी) का उन्नयन 25 जून 2019 को शुरू किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में कारीगर कौशल के लिए गांधी मंडेला विशेषज्ञता केंद्र की स्थापना पूरा होने के अग्रणी

चरण में है। सभी मशीनों का शिपमेंट सितंबर 2019 में मैसर्स एचएमटी (आई) लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया था। मैसर्स एचएमटी (आई) लिमिटेड ने दिसंबर 2019 तक निर्माण और संचालन क्रियाकलापों को पूरा करने का संकल्प लिया है।

- भारत सरकार ने 38.15 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता के अंतर्गत नियामे, नाइजर में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (एमजीआईसीसी) की स्थापना की है। एमजीआईसीसी नाइजर का निर्माण एक भारतीय कंपनी द्वारा दिसंबर 2019 में 14 महीने के रिकॉर्ड समय के भीतर पूरा किया गया है। इसका उद्घाटन 21 जनवरी 2020 को विदेश मंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

- भारत सरकार अनुदान के अंतर्गत सोमालिया को 27 मिडी बसें (30+1) सीटर, तंजानिया को 10+5 एम्बुलेंस, माली को एम्बुलेंस, लाइबेरिया को चिकित्सा उपकरण और सीटी स्कैन मशीन की आपूर्ति कर रही है।

आईएएफएस-IV

भारत-अफ्रीका फोरम शिखर-सम्मेलन-IV वर्ष 2020 में होने प्रस्तावित है। आईएएफएस-IV घोषणाएं उस क्षेत्र में हमारी बढ़ती उपस्थिति, सद्भावना और प्रभाव के अनुरूप अफ्रीका में विकास साझेदारी के लिए संवर्धित प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं।

विकास सहयोग भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। हाल के वर्षों में, विभिन्न देशों में भारत के विकास कार्यक्रमों का भौगोलिक पहुंच और क्षेत्रीय कवरेज, दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुदान सहायता, लाइन ऑफ क्रेडिट, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति और अल्पकालिक असैन्य और सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है। मेजबान सरकारों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पहचानी गईं प्रमुख विकास संबंधी परियोजनाएं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव में अवसरंचना, पन-बिजली, विद्युत पारेषण, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातात्विक संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में कार्यान्वयन के अधीन हैं। इसके आलावा, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा-पार संयोजनता के विकास और उसकी मजबूती में संतोषजनक प्रगति हो रही है। पड़ोस से परे, ऊर्जा, बिजली संयंत्र, विद्युत् पारेषण और वितरण, सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, कृषि और सिंचाई, औद्योगिक इकाइयों, सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और लघु और मध्यम उद्यम जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाएं दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में प्रारंभ की गई हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत की विकास सहायता का एक प्रमुख पहलू अन्य विकासशील देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) या रियायती शर्तों पर ऋण का विस्तार करना रहा है। इन वर्षों में, 30.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल 298 लाइन ऑफ क्रेडिट विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों को प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 12.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर अफ्रीकी देशों के लिए और 18.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर एशिया, लातिन अमेरिका, ओशिनिया और राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राज्यों (सीआईएस) को प्रदान किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान (दिसंबर 2019 तक), लगभग 3.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट विभिन्न देशों को प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 17 लाइन ऑफ़ क्रेडिट परियोजनाएं पूरा की जा चुकी हैं या उन्हें पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीइसी) कार्यक्रम के अंतर्गत 160 भागीदार देशों को लगभग 12000 नागरिक प्रशिक्षण

स्लॉट किए गए थे। इन क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रकार के विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे, जो भागीदार देशों के विशेष अनुरोधों के आधार पर थे।

आईटीईसी कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा के कारण विभिन्न नई पहल हुई हैं जिनमें ई-आईटीईसी, आईटीईसी-ऑनसाइट और आईटीईसी कार्यकारी, प्रतिभागियों की सुविधाएं बढ़ाना, आईआईटी और आईआईएम जैसे नए प्रमुख संस्थानों को शामिल करना, निजी संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाना, सोशल मीडिया आउटरीच बढ़ाना, आईटीईसी के लिए नए लोगों का शुभारंभ, आदि जैसे नए तौर-तरीकों की शुरुआत हुई है। आईटीईसी में रक्षा क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के साथ क्षमता निर्माण सहयोग भी शामिल है, जो अपने रक्षा बलों के अधिकारियों और पुरुषों के लिए 2000 से अधिक स्लॉट प्रस्तावित करते हैं। इसके अलावा, आईटीईसी कार्यक्रम ने विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति को भी कवर किया है ताकि वे भागीदार देशों द्वारा चुने गए और अनुरोध किये गये क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता और विकास के अनुभव को साझा कर सकें।

साझेदार देशों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी और कौशल बैठक के साथ ढांचागत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई, विशेष रूप से क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में उत्कृष्टता केंद्र, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र, और पुरातत्व और विरासत संरक्षण परियोजना।

भारत द्वारा डीपीआरके को खाद्य और एंटी-टीबी दवा किट दे कर मानवीय सहायता प्रदान की गई। नामीबिया, एल-सल्वाडोर और जिम्बाब्वे सहित अन्य देशों को चिकित्सा सहायता मुहैया करायी गई है।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण

नागरिक प्रशिक्षण

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम में भारत की भूमिका और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में योगदान स्पष्ट प्रतीक है, जिससे एशिया, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन के साथ-साथ प्रशांत और छोटे द्वीप देशों के 160 साझेदार देशों में हमारी सशक्त उपस्थिति के साथ क्षमता निर्माण साझेदारी निरुपित होती है। आईटीईसी भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इसने नए साझेदार संस्थानों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रिम पाठ्यक्रमों को शामिल करने के साथ-साथ दायरे और आउटरीच को मजबूत करना जारी रखा है। आईटीईसी में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, आदि जैसे तकनीकी उत्कृष्टता वाले संस्थान इसके साझेदार के रूप में शामिल हैं।

उच्च-स्तरीय व्यापक समीक्षा के बाद, पिछले दो वर्षों में आईटीईसी योजना में संपूर्ण, महत्वपूर्ण प्रणालीगत और नीतिगत स्तर के संशोधन किए गए हैं। आईटीईसी के अंतर्गत यह पेशकश और विस्तार किया गया है जो एक आर्थिक और तकनीकी रूप से उभरते हुए उन्नत भारत को वास्तव में प्रतिबिंबित करने के लिए किया गया है, साथ ही यह हमारे विश्व प्रसिद्ध प्राचीन ज्ञान जैसे योग, ध्यान और आयुर्वेद का प्रचार भी कर रहा है। साझेदार देशों की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम भी आगे बढ़ाए जाते हैं।

व्यापक समीक्षा में तकनीकी उत्कृष्टता के लगभग 27 नए साझेदार संस्थानों को शामिल किया गया है। 7 अन्य नए निजी क्षेत्र के संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को

एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आईटीईसी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चुना गया था।

प्रतिभागियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने, प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार, आउटरीच और पूर्व छात्रों की व्यस्तता बढ़ाने के लिए आईटीईसी मानदंडों और दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। तदनुसार, ऑनलाइन आईटीईसी पोर्टल में कई बदलाव भी किए गए हैं, जो विदेश मंत्रालय के मिशनों, आईटीईसी संस्थानों और कार्यक्रम के आवेदकों/ लाभार्थियों के लिए इंटरैक्टिव डिजिटल इंटरफेस है।

चूँकि दक्षिण-दक्षिण सहयोग मांग से प्रेरित है, अतः विशेष पाठ्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जो कि भागीदार देशों की सरकारों के अनुरोध पर प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हैं। वर्ष 2019 में, 38 विशेष पाठ्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं जबकि अन्य 18 विशेष पाठ्यक्रम दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान आयोजित किए जाने हैं। इन पाठ्यक्रमों में सिविल सेवकों के लिए प्रशासन के क्षेत्र में मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम और साइबर सुरक्षा, योग और संग्रहालय जैसे क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, पूरे भारत में फैले संस्थानों में विभिन्न अल्पकालिक और मध्यम-अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए 160 साझेदार देशों को आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत 11400 नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट की पेशकश की गई थी। नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा 89 प्रमुख संस्थानों में पूरी तरह से प्रायोजित है, जिसमें कृषि, खाद्य और उर्वरक, बैंकिंग, बीमा, वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी, एआई और इमर्जेंट प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, गवर्नमेंट फंक्शन, स्वास्थ्य और योगा, मानव संसाधन विकास और योजना, सिंचाई और जल संसाधन, आईटी और दूरसंचार, प्रबंधन और नेतृत्व, मीडिया और पत्रकारिता, समुद्र विज्ञान, पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन, बिजली, नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा, परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, एसएमई और उद्यमिता, सतत विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग, कपड़ा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, शहरी योजना, महिला सशक्तिकरण, आदि जैसे कौशल और विषयों की एक विस्तृत और विविध श्रेणी में 334 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। पाठ्यक्रमों, संस्थानों और साझेदार आईटीईसी देशों की अद्यतन सूची आईटीईसी पोर्टल (www.itecgoi.in) पर उपलब्ध है।

पिछले वर्षों की तरह, इस कार्यक्रम ने नागरिकों और रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को शामिल किया। आईटीईसी पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रियाओं ने आईटीईसी प्रतिभागियों, मिशनों / पोस्टों और प्रतिभागी संस्थानों की आवश्यकताओं को सुगम बना दिया, ताकि संस्थानों और स्वीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित विवरणों तक पहुंच आसान हो सके। आईटीईसी पोर्टल और अन्य सामाजिक नेटवर्किंग उपकरण के माध्यम से और विदेशों में मिशनों में आयोजित वार्षिक 'आईटीईसी दिवस' और भारत में आईटीईसी पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के माध्यम से पूर्व छात्रों के नेटवर्क के साथ जुड़ाव लगातार मजबूत होता रहा है। आईटीईसी ने महाद्वीपों में पूर्व छात्रों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है, जो अपने-अपने देशों में आईटीईसी के मशाल वाहक बन गए हैं और इस प्रक्रिया में, भारत और संबंधित देश के बीच एक शक्तिशाली सांस्कृतिक पुल विकसित किया है। आईटीईसी ने विकास साझेदारी के क्षेत्र में एक मजबूत ब्रांड नाम हासिल कर लिया है।

आईटीईसी की आउटरीच का विस्तार करने के लिए, 7 अक्टूबर 2019 को आयोजित 55 वें आईटीईसी दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री ने आईटीईसी, ई-आईटीईसी, आईटीईसी कार्यकारी और आईटीईसी ऑनसाइट का नया डेरिवेटिव लॉन्च किया। आईटीईसी कार्यक्रम की विकसित प्रकृति का एक नया लोगो प्रतिबिंबित किया गया।

ई-आईटीईसी

ई-आईटीईसी आईटीईसी कार्यक्रम का एक प्रकार है जिसमें भारतीय संस्थानों द्वारा वास्तविक समय में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। पहला ई-आईटीईसी पाठ्यक्रम पायथन में अपाचे स्पार्क के साथ बिग डेटा एनालिटिक्स, चार साथी देशों (म्यांमार, लाओसपीडीआर, मोरक्को और वियतनाम) के प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित किया गया था। इस पाठ्यक्रम का संचालन आईआईटी मद्रास ने ई-आईटीईसी पहल के अंतर्गत किया था।

आईटीईसी ऑनसाइट

आईटीईसी ऑन-साइट के अंतर्गत स्वनिर्धारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम हमारे प्रशिक्षक देशों को अल्प अवधि के लिए हमारे प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करके अपने देश में प्रशिक्षण स्थानांतरित करके प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पहचाने जाने वाले कई सशक्त क्षेत्रों में उर्वरक प्रौद्योगिकी; मत्स्य प्रौद्योगिकी; कृषि और संबद्ध क्षेत्र; शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान; खुले शिक्षा संसाधन; प्रतिभूति बाजार; वायु ऊर्जा; ग्रामीण विद्युतीकरण; दक्षिण-दक्षिण सहयोग आदि शामिल है। इसके अलावा, भारतीय मिशन को भागीदार देशों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं की तलाश जारी रखने की सलाह दी गई है।

आईटीईसी कार्यपालक

आईटीईसी कार्यपालक, नीति निर्माताओं, वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और साझेदार देशों के पेशेवरों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है जो भारत में सर्वोत्तम प्रथाओं/ प्रणालियों की समझ प्रदान करने के उद्देश्य से सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अध्ययन/ एक्सपोज़र विज़िट को कवर करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और नीति क्षेत्रों के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उच्च स्तर पर अभिग्रहण करना है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) और स्व-नियोजित महिला संघ (एस ई डब्ल्यू ए) के साथ बातचीत करने और प्रधानमंत्री कर्सल विकास योजना, महिला ग्राम उद्योग और इसी तरह की अन्य परियोजनाओं के अनावरण करने के लिए 2018-19 के दौरान, युगांडा के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी तरह की तर्ज पर, पूर्वी अफ्रीकी सामुदायिक मामलों के विदेश मंत्रालय के तीन प्रतिनिधिमंडल भारत में चाय, कॉफी और कपास के खेतों का दौरा करने के लिए और अपने अनुभव, विशेषज्ञता और चाय, कॉफी और कपास के खेत की खेती, प्रसंस्करण और विपणन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आये थे। लाओ पीडीआर, दक्षिण सूडान की कई अन्य यात्राओं को हमारी सर्वोत्तम वित्तीय प्रथाओं और आरबीआई द्वारा स्थापित संस्थानों के लिए आने वाले महीनों में आयोजित किया जाना है। जबकि कंबोडिया, ट्यूनीशिया, मंगोलिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व, ई-गवर्नेंस और स्थानीय प्रशासन के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, “डिजिटल अफ्रीका: सशक्त नागरिक” विषय के साथ ई-गवर्नेंस पर नीति निर्माताओं का एक पैन-अफ्रीका सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

रक्षा प्रशिक्षण

भागीदार देशों को वर्ष 2019-20 के दौरान, 2342 रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए थे। दोनों पाठ्यक्रम सामान्य और विशेष प्रकृति के थे, जिसमें सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन, रक्षाप्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, समुद्री जल सर्वेक्षण, प्रतिवाद और जंगलयुद्ध, तट रक्षक मुख्यालय द्वारा समुद्री कानून और तीनों सेवाओं में युवा अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम भी शामिल थे। नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन जैसे प्रमुख संस्थानों में पाठ्यक्रम काफी लोकप्रिय रहे और स्व-वित्त पोषण के आधार पर विकसित देशों के अधिकारियों को भी आकर्षित किया।

आईटीईसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

भागीदार देशों के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति ने विकासशील देशों के साथ

भारतीय विशेषज्ञता को साझा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डोमेन विशेषज्ञों के एक आसानी से उपलब्ध पूल के निर्माण के लिए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से एक एसओपी तैयार करने और विभिन्न देशों/क्षेत्रों के साथ अपनी विशेषज्ञता को मैप करने और एमईए के साथ साझा करने के लिए परामर्श दिया गया है, ताकि हमारे मिशन को उचित रूप से सूचित किया जा सके।

नवंबर 2019 तक, विभिन्न क्षेत्रों के 47 विशेषज्ञ, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रतिक्रिया, पुरातत्व, आयुर्वेद, कानूनी विशेषज्ञों, अंग्रेजी शिक्षकों और आयुर्वेद के क्षेत्रों में भागीदार देशों की प्रतिनियुक्ति पर हैं। युगांडा, तंजानिया, वियतनाम, म्यांमार, सेशेल्स, नामीबिया, लाओपीडीआर में कई रक्षा प्रशिक्षण टीमों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है।

अन्य विकासशील देशों में अनुदान परियोजनाएँ

अन्य विकास परियोजनाओं में, भारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का विस्तार कर रहा है, जिसने कंबोडिया में ता-प्रोम और प्रीहिवीयर, वियतनाम में माइ सन और लाओ पीडीआर में वाट-पोह आदि दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सांस्कृतिक धरोहरों की पुनर्स्थापना और संरक्षण के लिए और मंदिरों का निर्माण किया है। मंदिर के जीर्णोद्धार की परियोजनाओं के विस्तार के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु कार्य की बहाली के लिए एक विस्तृत पूल से सहायता लेने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के विभिन्न केंद्रों की स्थापना के माध्यम से और मोरक्को, गुयाना, नामीबिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, सीरिया, अर्जेंटीना और प्रशांत देशों अर्थात फिजी, पापुआन्यूगिनी, समोआ, नाउरू, कुकआइलैंड्स, नीयू और वानुअतु सहित भागीदार देशों को प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की ताकत साझा की जा रही है। मलावी में एक व्यापार ऊष्मा नियंत्रक केंद्र स्थापित किया गया है और बेलीज में एक इंडो-बेलीज सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग और जंजीबार में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) स्थापित किया जा रहा है।

मानवीय सहायता और आपदा राहत

भारत द्वारा आपदा से प्रभावित देशों में मानवीय आधार पर और मानवीय मोर्चे पर सहयोग बढ़ाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के माध्यम से एंटी-टीबी दवा किट में से प्रत्येक में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू एफ पी) के माध्यम से गेहूं की सहायता की आपूर्ति डीपीआर कोरिया को प्रदान की जा रही है। देशों को चिकित्सा सहायता के प्रावधान पर प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के प्रयास में मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है, जिसने नामीबिया, एल-सल्वाडोर और जिम्बाब्वे सहित विदेश मंत्रालय के संबंधित प्रभागों के माध्यम से विभिन्न देशों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सुचारू रूप से आपूर्ति में मदद की है।

भारत की विकास भागीदारी

भारत की बाह्य भागीदारी में विकास की भागीदारी विशेष रूप से सरकार की 'पड़ोस प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के अंतर्गत हमारे निकट पड़ोस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत के विकास सहयोग की पहल का एक लंबा और स्थायी इतिहास है, हाल के वर्षों में इस तरह की विकास सहायता की प्रकृति और प्रसार ने भौगोलिक और क्षेत्रीय दोनों क्षेत्रों में विस्तार किया है। भारत का विकास सहयोग सहयोगी भागीदार देशों की विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है।

विदेश मंत्रालय के विकास भागीदारी प्रशासन (डी.पी.ए) विंग के गठन के आठ वर्ष बाद, परियोजना वितरण

और कार्यान्वयन सहित विदेशी देशों के साथ सरकार के विकास की पहल के लिए, अधिक संस्थागत सहयोग और ध्यान केंद्रित किया गया है। मेजबान देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को प्रधानता देने वाले भारत के विकास सहायता मॉडल ने, भारत को अपनी विकास वृद्धि यात्राओं में एक मूल्यवान भागीदार बनाया है। भारत के विकासात्मक सहायता का ध्यान भारतीय अनुभव को साझा करने, क्षमताओं का निर्माण करने, लोगों में निवेश करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा बनाने और हमारे विस्तारित पड़ोस के साथ जुड़ाव बढ़ाने पर है। भारतीय अनुदान सहायता में बुनियादी ढांचा निर्माण शामिल है जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे लिंक, सड़कों और पुलों, जलमार्ग, सीमा-संबंधी बुनियादी ढांचे, पारेषण लाइनों, बिजली उत्पादन, जल विद्युत इत्यादि का विस्तार करता है। क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामुदायिक विकास कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां भारत पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।

अफ़गानिस्तान

अफगानिस्तान के लिए भारत की विकासात्मक सहायता उस देश के साथ घनिष्ठ सामरिक साझेदारी का एक प्रमुख आधार है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास पर केंद्रित विकास सहायता लगातार प्रदान करने के लिए सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है। काबुल में नए संसद भवन का उद्घाटन 25 दिसंबर, 2015 को हुआ, और अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम (जिसे पहले सलमा डैम के नाम से जाना जाता था) का उद्घाटन जून, 2016 को किया गया था, जो एक अखंड, लोकतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख प्रतीक है। दोनों देशों द्वारा सितंबर, 2017 में 'न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप' के अंतर्गत, भारत अफगानिस्तान में व्यापक विकास सहायता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपदाओं के समय भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करके त्वरित कार्रवाई की है। वर्ष 2018 में 1.7 लाख टन गेहूं और 2000 टन दालों की आपूर्ति के रूप में की गई सहायता के बाद भारत वर्ष 2020 में मानवीय सहायता के रूप में अधिक गेहूं की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है। 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परिव्यय के साथ तीन चरणों के अंतर्गत 140 से अधिक उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एचआईसीडीपी) के अंतर्गत, अफगानिस्तान में कृषि, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सक्रिय कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन समुदाय आधारित छोटी परियोजनाओं को स्थानीय भागीदारी के साथ भारत द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है जो जमीनी स्तर पर प्रभावपूर्ण त्वरित विकास में मदद करता है। अफगानिस्तान दौरे के दौरान दिसंबर, 2015 की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुसार, दोनों देश इस कार्यक्रम के चौथे चरण में 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर (एच.आई.सी.डी.पी. का चरण IV) के पारगमन की तैयारी भी कर रहे हैं।

शिक्षा और क्षमता निर्माण सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों में निवेश करना, भारत की अफगानिस्तान के साथ विकास साझेदारी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है। अफगानिस्तान केंद्रित विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रत्येक वर्ष 1000 अफगान लाभार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा, एक और 500 छात्रवृत्ति स्लॉट अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के शहीदों के बच्चों / आश्रितों के लिए और कृषि अध्ययन के लिए 614 छात्रवृत्ति स्लॉट, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से प्रशासित, अफगान नागरिकों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। कंधार में भारत अपनी तरह के पहले अफगानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएएसटीयू) की स्थापना में भी अफगानिस्तान का समर्थन कर रहा है।

म्यांमार

म्यांमार में प्रमुख संयोजकता परियोजनाएं जैसे भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग कलादान मल्टी मॉडल मार्गस्थ परिवहन परियोजना

का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क (संयोजकता) को बढ़ाना है। एक बार चालू होने वाली कलादान परियोजना, भारत के पूर्वी समुद्री बोर्ड और म्यांमार के सिटवे पोर्ट बंदरगाहों के बीच पर और इसके बाद मिज़ोरम में भारत-म्यांमार सीमा के बीच संयोजकता प्रदान करेगी। त्रिपक्षीय राजमार्ग पहल के हिस्से के रूप में भारत, म्यांमार में तामू-कायगोन-कालेवा रोड सेक्शन में उनहत्तर पुलों के निर्माण के लिए और कालेवा-यारगी सेक्शन में 120 किलोमीटर सड़क के उन्नयन के लिए दो परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

भारत संयोजकता परियोजनाओं के अलावा, म्यांमार के लिए मांडले में म्यांमार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईआईटी) की स्थापना और नायपियडॉ के निकट कृषि अनुसन्धान और शिक्षा उन्नत केंद्र (एसीएआरई) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण मे सहायता प्रदान करता है। ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों को प्रमुख क्षेत्रों में क्षमताओं में सुधार करने और उनकी आजीविका के अवसरों का विस्तार करने में मदद कर रही हैं।

नेपाल

भारत ने वर्ष 2019 में नेपाल में प्रमुख संरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और पूरा करने में प्रगति की है। बीरगंज में अप्रैल, 2018 में एकीकृत चेक पोस्ट के पूरा होने और उद्घाटन के बाद, बिराटनगर में भारतीय सहायता के अंतर्गत दूसरा आईसीपी भी वर्ष 2019 के अंत में पूरा हो गया है। ये आई.सी.पी. भारत और नेपाल के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेंगे। चरण I के अंतर्गत आईसीपी की सफलता के बाद, चरण II में अगले वर्ष (2020) काम शुरू होगा। नेपालगंज में आईसीपी का कार्यान्वयन वर्ष 2020 में शुरू हो जाएगा। नेपाल में सीमा पार(क्रॉस बॉर्डर) रेल लिंक बिहार के जयनगर को नेपाल में बर्दीबास और बिहार में जोगबनी को नेपाल के विराटनगर से जोड़ रहा है। इस वर्ष नेपाल-भारत मैत्री पॉलिटेक्निक परियोजना का निर्माण भी शुरू हुआ है। भारत नेपाल पुलिस अकादमी का निर्माण करने के लिए नेपाल की सहायता भी करेगा, जिसके लिए वर्तमान में परियोजना का विकास कार्य चल रहा है।

श्रीलंका

जाफना में एक अत्याधुनिक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, जिसमें दो-मंजिला संग्रहालय, बारह-मंजिला लर्निंग टॉवर, एक ऑडिटोरियम ब्लॉक, एक सार्वजनिक वर्ग और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए एक अस्थायी मंच जनवरी, 2020 तक पूरा होना निर्धारित है। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के चरणI की सफलता के बाद, जुलाई 2018 से जुलाई, 2019 तक शुरू होने वाले चरणों में श्रीलंका के शेष सात प्रांतों में कुल 209 एम्बुलेंस के साथ द्वीप विस्तृत आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जो नवंबर, 2019 के अंत तक 1.5 मिलियन कॉल का निस्तारण कर चुकी हैं।

मालदीव

मालदीव में पिछले वर्ष के अंत से, विकास परियोजनाओं को गति मिली है और अनुदान और एल.ओ.सी सहायता दोनों के अंतर्गत पर्याप्त नई प्रतिबद्धताएं भी प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में, भारत, अन्य बातों के साथ, मालदीव में माफिलाफुशी द्वीप में समग्र प्रशिक्षण केंद्र में अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। मुख्य प्रशिक्षण केंद्र को अगस्त, 2015 में पूरा किया गया था और मालदीव सरकार के अनुरोध पर जुलाई, 2019 में भारतीय अनुदान सहायता के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण शुरू किया गया था। भारत मालदीव के लिए नए रक्षा मंत्रालय भवन के निर्माण में भी मदद करेगा जो अगले वर्ष शुरू होने वाला है। सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अध्ययन संस्थान (आईएसएलईएस) का निर्माण तेज गति से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2020 में पूरा होने की आशा है।

मॉरीशस

भारत ने विकास सहायता के अंतर्गत मॉरीशस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करने हेतु हाथ

मिलाया है। मेट्रो रेल ट्रांजिट आधारिक संरचना, नया उच्चतम न्यायालय भवन, ग्रेड 3 तक के लिए प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा-टैबलेट, गरीबों के लिए विशेष आवास और न्यू ई.एन.टी चिकित्सालय जैसी परियोजनाओं को भारतीय सहायता के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। राजधानी, पोर्ट लुइस, रोज हिल से और आर्ट पेपरलेस ई.एन.टी चिकित्सालय को जोड़ने वाली मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के चरण I को पूरा किया गया और इस वर्ष अक्टूबर में संयुक्त रूप से दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वीडियो-उद्घाटन किया गया। इस वर्ष की शुरुआत में पूरे किए गए 'अर्ली डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम' के अंतर्गत मॉरीशस के सभी 278 प्राइमरी विद्यालयों में कक्षा 3 तक के प्राथमिक विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों को दो चरणों में कॅस्टमाइज्ड स्मार्ट टैबलेट प्रदान किए गए थे।

14

आर्थिक कूटनीति और राज्य

आर्थिक कूटनीति और राज्य प्रभाग ने देश की विदेश नीति के आर्थिक कूटनीति आयाम को केंद्रित दिशा देने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में 2019-20 के दौरान अनेक पहल की। प्रभाग के प्रयास भारत के निर्यात को बढ़ाने, विदेशों में भारतीय उद्यमों के लिए नए व्यापार के अवसर खोलने, अधिक निवेश आकर्षित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत में एफडीआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, के संगत मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, व्यापार और उद्योग मंडलों और मिशनों/पोस्टों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करना था।

भारतीय मिशनों/पोस्टों को अपने **"बाजार विस्तार गतिविधियों"** बजट के अंतर्गत उनकी मान्यता, आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग के देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में सक्षम करने के लिए ***10 करोड़*** रुपये की फंडिंग बढ़ा दी गई है। इस वित्तपोषण का उपयोग कैटलॉग शो और क्रेता-विक्रेता बैठकों के माध्यम से भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करने, बाजार अध्ययन तैयार करने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापार सेमिनार आयोजित करने और विदेशों में व्यापार के अवसरों की मांग करने वाले भारतीय उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने के लिए हिमाकत का काम शुरू करने के लिए किया गया है।

इस प्रभाग ने विदेशों में मिशनों और पदों के नेटवर्क और भारत में शाखा सचिवालयों और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के माध्यम से राज्यों के बाह्य आर्थिक जुड़ाव को सुगम बनाया। मिशन और पोस्टों ने राष्ट्र सुविधा विदेश निधि के माध्यम से राज्य सुविधा गतिविधियों का संचालन किया। राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से आईएफएस अधिकारियों को राज्यों के आवंटन की पहल पर अपने रेजिडेंट कमिश्नरों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से राज्य और संघ

शासित सरकारों के साथ संपर्क जारी रखा गया और प्रगति हुई। प्रभाग ने राज्य सरकारों और शहरों के बीच अपने विदेशी समकक्षों के साथ समझौता ज्ञापन की सुविधा सिस्टर-स्टेट और शहर साझेदारी स्थापित करने के लिए भी सहयोग प्रदान किया।

1. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत सीओपी21 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से की थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की तेजी से और व्यापक तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना है। आईएसए वन प्लैनेट समिट की 12 प्रतिबद्धताओं में भी योगदान देता है। आईएसए का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता के मामले में सौर ऊर्जा की भारी तैनाती के लिए मुख्य आम बाधाओं के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए देशों को एक साथ लाना है। इसका उद्देश्य 2030 तक 1 टीडब्ल्यू सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक ट्रिलियन डॉलर जुटाना है। एक कार्यकरण उन्मुख संगठन के रूप में आज तक आईएसए ने कार्रवाई के पांच प्रमुख कार्यक्रम स्थापित किए हैं :

- कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोगों को स्केलिंग
- पैमाने पर किफायती वित्त
- सौर मिनी ग्रिड स्केलिंग
- सौर छत की स्केलिंग
- सौर ई-गतिशीलता और भंडारण की स्केलिंग।

आज तक 85 देशों ने आईएसए के संरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इनमें से 64 देशों ने संरचना समझौते की पुष्टि भी की है। आईएसए की 3 अक्तूबर 2018 को हुई पहली आम सभा के दौरान आईएसए की विधानसभा ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को आईएसए सदस्यता खोलने के लिए संरचना समझौते में संशोधन के लिए भारत द्वारा किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अपनाया। संशोधित संरचना समझौता अपने सदस्य देशों के दो तिहाई (30) द्वारा अनुसमर्थन पर लागू होगा। आज की तारीख में 20 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संशोधित संरचना समझौते को स्वीकार/अनुसमर्थन किया है।

नवीन और नवीकरण ऊर्जा के नोडल मंत्रालय (एमएनआरई) के समन्वय से प्रभाग ने नई दिल्ली में 31 अक्तूबर 2019 को आयोजित आईएसए की दूसरी आम सभा के आयोजन में सहायता की। दूसरी आम सभा में आईएसए देशों के लगभग 23 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। दूसरी आम सभा में गठबंधन के कार्य और प्रगति और पांच कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। विधानसभा ने आईएसए का छठा कार्यक्रम भी अपनाया जिसमें आईएसए सदस्य देशों के समूहों में सोलर पार्क अवधारणा के अंतर्गत विकसित की जाने वाली बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

2. सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए)

मुख्यत: पर परिभाषित सामाजिक सुरक्षा समझौते भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते हैं जो सीमा पार कामगारों के हितों की रक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, अर्थात विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के साथ-साथ उन करार करने वाले देशों के नागरिक भी हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 'नो कवरेज' या 'डबल कवरेज' से बचने और दोनों देशों के कामगारों को समान व्यवहार प्रदान करना है।

द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते भारतीय पेशेवरों, कुशल कामगारों के हितों की रक्षा करते हैं जो विदेशों में कार्यरत कामगरों को तीन लाभ प्रदान करते है: दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान देने से बचना; लाभों का आसान प्रेषण (निर्यात क्षमता); और लाभों के नुकसान (टोटलाइजेशन) को रोकने के लिए योगदान अवधि (दो देशों में) का समेकन करना। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, एसएसए पर बातचीत करने के लिए "सक्षम प्राधिकारी" है। ईपीएफओ के अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने और कवरेज प्रमाणपत्र (सीओसी) जारी करने के लिए संपर्क एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आज तक भारत ने कुल अठारह देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है।

चल रही बातचीत

i. 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में गोवा घोषणापत्र की भावना और जिनेवा में 9 जून 2016 को हुई ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठकों के परिणामों और नई दिल्ली में 27-28 सितंबर 2016 को भारत और ब्राजील ने 13-16 मार्च तक एसएसए पर चर्चा की। ब्रासीलिया में सीएच 2017 और सामाजिक सुरक्षा समझौते के अंतिम पाठ का शुभांरभ किया। प्रशासनिक व्यवस्था पर बातचीत का दूसरा दौर 13-16 नवंबर 2017, नई दिल्ली से आयोजित किया गया था और प्रशासनिक व्यवस्था के मसौदे पाठ को अंतिम रूप दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है, जिस पर जनवरी 2020 में हस्ताक्षर होने वाले हैं।

ii. भारत-चीन सर्व स्वास्थ्य विभाग पर पहली तकनीकी बैठक 28-29 मई 2018 को चीन के बीजिंग में हुई थी, जबकि दोनों पक्षों के बीच पहले दौर की टेक्स्ट बेस्ड वार्ता 13-15 नवंबर 2019 से नई दिल्ली में हुई थी। विदेश मंत्रालय भारत और फिलीपींस के बीच सामाजिक सुरक्षा पर समझौते पर औपचारिक वार्ता में भी शामिल है और दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, थाईलैंड, मैक्सिको, पेरू, पोलैंड, साइप्रस आदि कई अन्य देशों के साथ एसएसए में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। सर्व धर्म अभियान/टोटलाइजेशन पर अनौपचारिक विचार-विमर्श भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रहा है।

3. नागरिक उड्डयन

आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग ने द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ताओं पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया। विदेश पक्ष इन मुद्दों पर और पर्यटन, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उड़ान संचालन या कोड शेयर की आवश्यकता पर भी जानकारी प्रदान करता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने आईसीएओ के सदस्य देशों के समकक्ष मंत्रियों को पत्र लिखकर अक्तूबर, 2019 में हुए इकाना चुनावों के दौरान परिषद सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा था। प्रभाग ने हमारे मिशनों की सहायता से सभी आईसीएओ सदस्यों के साथ उनका समर्थन मांगा था। प्रभाग ने ब्रिटेन, इजरायल, बांग्लादेश, जापान, यूएई, सऊदी अरब के साथ हुई बातचीत में भी हिस्सा लिया।

4. द्विपक्षीय निवेश संधियां (बीटीएस)

आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर आर्थिक मामलों के विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस प्रभाग ने दिसंबर 2015 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारत के नए मॉडल पाठ के आधार पर द्विपक्षीय निवेश संधि पर विभिन्न दौरों की बातचीत में भाग लिया। चालू वर्ष में आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग ने मैक्सिको, सऊदी अरब, कंबोडिया और रूस के साथ इन वार्ताओं में हिस्सा लिया है। इस प्रभाग द्वारा सूचनाओं और वार्ताओं को सुगम बनाने और अनुवर्ती कार्रवाई के संदर्भ में पर्याप्त योगदान दिया गया था। **आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग निवेशक राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) में सुधारों पर यूएनसीआरएल वर्किंग ग्रुप-3 का भी हिस्सा है। यह प्रभाग एल एंड टी प्रभाग के साथ प्रभाग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है और बीटीएस से संबंधित मध्यस्थता मामलों पर सभी अंतर-मंत्रालयी बैठकों में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है।**

5. निवेश संवर्धन और प्रचार और उद्योग अभिगम्यता

i. प्रभाग ने ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) द्वारा 14-15 जनवरी 2019 के बीच आयोजित इंडसफूड 2019 के दूसरे सत्र के लिए वित्तीय सहायता और लोगो सहायता प्रदान की। टीपीसीआई ने 14-15 जनवरी, 2019 को इंडसफूड के दूसरे संस्करण की तर्ज पर B2B संवादों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य 20 देशों अर्थात् अमेरिका, रूस, बेलारूस, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, कनाडा, कतर, यूएई, मलेशिया, इजराइल, वियतनाम, न्यूजीलैंड, मिस्र, आर्मेनिया, कोलंबिया, घाना, केन्या और सिंगापुर में एफएंडबी सेक्टर में भारत का निर्यात बढ़ाना था। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य विदेशी खरीदारों और भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता के मामलों को दूर करने और नियामक तंत्र, एनटीबी (गैर-यातायात बाधाओं) और टीबीटी (ट्रेड बैरियर टैरिफ) आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से अनौपचारिक बातचीत करना है।

ii. प्रभाग ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा प्रगतिमैदान में 3 से 5 फरवरी, 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के 23वें सत्र को आईईटीएफ 2019 के संगठन की सुविधा प्रदान की।

iii. प्रभाग ने ग्वाटेमाला सिटी में 14-16 मई, 2019 से आयोजित किए जा रहे परिधान सोर्सिंग शो में भाग लेने के लिए भारतीय दूतावास, ग्वाटेमाला सिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की।

iv. मनीला में 19 अक्तूबर, 2019 को आयोजित चौथे आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन के लिए माननीय राष्ट्रपति जी, भारतीय दूतावास, मनीला की राजकीय यात्रा के साथ-साथ वित्तीय सहायता और सहायता भी प्रदान की गई थी।

v. प्रभाग ने 13 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय सहयोग "पड़ोस" पर गोलमेज चर्चा आयोजित करने में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सीआईआई के साथ समन्वय किया। यह प्रभाग आयोजन समिति की बैठकों का भी हिस्सा था और आयोजन की सफलता के लिए विदेश मंत्री दल से आवश्यक सहायता प्रदान की गई थी।

vi. प्रभाग ने नई दिल्ली में 24-26 सितंबर 2019 के बीच यूएसएड द्वारा आयोजित "भारत-अफगानिस्तान व्यापार और निवेश शो" सम्मेलन का समर्थन किया। इसने मुंबई में 06-08 मार्च, 2019 तक 'ग्लोबल इकोनॉमिक समिट' के 8वें

संस्करण के आयोजन के लिए ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज की भी सहायता की। प्रभाग ने नई दिल्ली में 3-5 अक्तूबर 2019 से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो 2019 के लिए भी सहायता प्रदान की।

vii. प्रभाग ने 11-13 अक्तूबर 2019 के बीच नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स ट्रेड फेयर (आईआईसीटीएफ) के संगठन का समन्वय और समर्थन किया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने किया था। यह भारत और विदेशों में सहकारी-से-सहकारी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति मेला था जिससे ग्रामीण और कृषि समृद्धि में वृद्धि हुई।

viii. प्रभाग ने लुसाका में 14-15 अक्तूबर, 2019 तक आयोजित भारत-दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए हमारे मिशनों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसी तरह, प्रभाग ने मिस्र के काहिरा में 6-7 नवंबर, 2019 तक पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीका (वाना) पर क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए पांच देशों के गणमान्य व्यक्तियों को आतिथ्य प्रदान किया।

ix. प्रभाग ने 11-12 नवंबर 2019 तक मुंबई में आयोजित "ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया" के लिए 23 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में रेजिडेंट मिशनों के लिए एक ब्रीफिंग का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन फिक्की के समर्थन से डी/ओ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने किया था। इस प्रभाग ने इस आयोजन के लिए विदेशी प्रचार के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ-साथ वीजा सुविधा के लिए भी समन्वय किया।

x. प्रभाग ने 1-4 नवंबर 2019 के बीच नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया, 2019 का आयोजन किया। इस संबंध में प्रभाग ने खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 35 देशों के विदेशी निवासी मिशनों के लिए ब्रीफिंग का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में संबंधित देशों से भागीदारी की मांग की।

xi. प्रभाग ने 19 नवंबर, 2019 को दिल्ली में आयोजित आईसीबीसी वार्षिक अधिवेशन के लिए इंडो-कैनेडियन बिजनेस चैंबर को वित्तीय सहायता प्रदान की।

xii. विदेश मंत्रियों के सीआईआई और मध्य यूरोप प्रभाग के सहयोग से प्रभाग ने नई दिल्ली में 20-21 नवंबर 2019 तक 5वें इंडिया यूरोप 29 बिजनेस फोरम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग एवं रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। इसमें 29 यूरोपीय देशों के कुछ 400 प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। फोरम के इस संस्करण के लिए फोकस क्षेत्र स्मार्ट सिटी, आईटी और आईटीईएस, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) थे।

xiii. प्रभाग ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से 11 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में "ग्लोबल हेल्थ में आयुर्वेद के दायरे" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आयुष की अन्य प्रणालियों की क्षमता और प्रभावकारिता के बारे में दर्शकों में जागरूकता पैदा करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में आयुर्वेद को नियंत्रित करने वाले मजबूत बुनियादी ढांचे और नियामक प्रावधानों के साथ दर्शकों को परिचित कराने में मदद करना था, साथ ही क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास में अवसरों के बारे में जागरूक करना भी था। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली में देशों के रेजिडेंट मिशनों के राजनयिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष के लिए विदेश मंत्री और राज्यमंत्री ने की।

xiv. प्रभाग ने 28 से 30 दिसंबर, 2019 तक चेन्नई ग्लोबल इकोनॉमिक समिट 2019 के आयोजन के लिए मद्रास डेवलपमेंट सोसाइटी (एमडीएस) को वित्तीय सहायता प्रदान की।

xv. यह प्रभाग नई दिल्ली में 2-8 मार्च, 2020 से आयोजित होने वाले "अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020" के आयोजन की प्रक्रिया में शामिल है। यह आयोजन आईजीसी के वैज्ञानिक प्रायोजक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस के तवावधान में किया जाएगा। यह प्रभाग खान मंत्रालय के समन्वय से भारत में विभिन्न बैठकों, क्षेत्र भ्रमणों और मुख्य आयोजन के लिए विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी से संबंधित वीजा/अनुमति/अनुमोदन आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है और इस के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान करने की नोडल एजेंसी है। यह प्रभाग मजबूत प्रचार और वीजा सुविधा के लिए विदेशों में निवासी विदेशी मिशनों और भारतीय मिशनों तक भी पहुंच रहा है।

7. वीवीआईपी दौरों के दौरान व्यापार प्रतिनिधिमंडल

आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग, व्यापार मंडलों के सहयोग से, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का गठन करता है और आने वाले और निवर्तमान वीवीआईपी यात्राओं के लिए व्यावसायिक मंचों का आयोजन करता है। 2019 में, प्रभाग ने निम्नलिखित यात्राओं के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और मंचों का आयोजन किया :

i. प्रभाग ने मार्च 2019 में,भारत के माननीय राष्ट्रपति की यात्रा के सिलसिले में चिली और बोलीविया के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आयोजन किया। प्रभाग ने मार्च 2019 में भारत के माननीय उप राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कोस्टा रिका और पराग्वे में प्रतिनिधिमंडलों और व्यापार मंचों का भी आयोजन किया।

ii. प्रभाग ने अगस्त 2019 में माननीय उप राष्ट्रपति के साथ लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आयोजन किया। वीवीआईपी यात्रा के सिलसिले में इन देशों में बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया।

iii. प्रभाग ने सितंबर 2019 में भारत के माननीय राष्ट्रपति की आइसलैंड, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड की यात्रा के दौरान व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और मंचों को व्यवस्थित करने में भी मदद की।

iv. शीर्ष व्यापार मंडलों के साथ समन्वय में विभाजन आने वाले वीवीआईपी यात्राओं के दौरान व्यापार मंचों का आयोजन; उनमें से कुछ निम्नलिखित रूप में कर रहे हैं :

- अगस्त, 2019 में जाम्बिया गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा के दौरान भारत-जाम्बिया व्यापार मंच का आयोजन किया गया।
- सितंबर, 2019 में मंगोलिया के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा के दौरान भारत-मंगोलिया व्यापार मंच का आयोजन किया गया।
- 4 अक्तूबर 2019 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत-बांग्लादेश व्यापार मंच

9. अध्ययन/बाजार सर्वेक्षण और आकलन करना

i. प्रभाग ने ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था कार्यनीति रिपोर्ट का नेतृत्व करने के लिए सीआईआई को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस रिपोर्ट के मसौदे पर प्रभाग ने संबंधित लाइन मंत्रालयों के साथ अंतर मंत्रालयी चर्चा के लिए कार्रवाई की थी। इस रिपोर्ट पर एक और बैठक डीपीआईआईटी द्वारा 17 दिसंबर

2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें आर्थिक कूटनीति प्रभाग ने हिस्सा लिया था। मसौदा रिपोर्ट में प्रस्तावित सिफारिशों की सूचना सीआईआई को दे दी गई। फिलहाल इस रिपोर्ट की विदेश मंत्रालय और डीपीआईआईटी द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

ii. इस प्रभाग ने म्यांमार के बाजार की संभावनाओं और औद्योगिक परिदृश्य और भारतीय के लिए इसकी निवेश क्षमता का आकलन करने के लिए अध्ययन करने के लिए सेंटर फॉर स्टडीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डेवलपमेंट (सीएसआईएफडी), कोलकाता को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस मसौदा रिपोर्ट को मंडल ने जनवरी 2020 में आयोजित होने वाली अंतर-मंत्रालयी बैठक के माध्यम से चर्चा के लिए लिया है।

10. वेबसाइट और संसाधनों की वैश्विक मैपिंग

आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग अपनी वेबसाइट “indbiz.gov.in” के नवीकरण की प्रक्रिया में है। आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग की वेबसाइट का उद्देश्य विदेशी उद्यमों के लिए भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार के माहौल के बारे में सभी जानकारी साथ ही विदेशों और भारतीय मिशनों और पोस्टों के लिए भारतीय व्यवसायों के लिए भी एक-स्टॉप स्रोत होना है। यह भारत के फायदों, भारत के एक सामान्य, आर्थिक, राजनीतिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी, क्षेत्रीय अवसर और सफलता की गाथाओं, प्रमुख राज्य लाभ, राज्य निवेश संवर्धन एजेंसियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपडेट, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत और राज्यों की रैंकिंग पर भी अवलोकन करेगा।

वेबसाइट का एक वर्ग संसाधन मंच को समर्पित है जो तीन क्षेत्रों में विश्व संसाधन बंदोबस्ती और अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा :

i. खनिज संसाधन: यह मंच भारत के लिए सामरिक खनिजों के वैश्विक भंडारों का पता लगाने के लिए एक वैश्विक एटलस के रूप में काम करेगा।

ii. कृषि निर्यात के अवसर: यह मंच दुनिया भर के देशों में अपनी मांग के केंद्रों के साथ भारतीय कृषि उत्पादों का नक्शा तैयार करेगा, इस प्रकार निर्यातकों को कृषि निर्यात के लिए संभावित अवसरों की पहचान करने में मदद करेगा।

iii. हमारे नागरिकों के लिए विदेशी रोजगार के अवसर भारत के बढ़ते जनसांख्यिकीय लाभांश को ध्यान में रखते हुए, यह मंच विदेशों के देशों में कुशल/अर्ध-कुशल श्रम के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की पहचान करने में मदद करेगा।

वेबसाइट 2020 की पहली तिमाही में लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी

11. विभिन्न बोर्डों/समितियों को इनपुट

आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग के प्रमुख कई बोर्डों/समितियों का हिस्सा हैं, जैसेकि निर्यात संवर्धन परिषद फॉर ईओयू एंड एसईजेड (ईपीसीईएस) (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीपीसी), भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), इन्वेस्ट इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी), डब्ल्यूओपीसीओएस जैसे सदस्य हैं। आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग के अन्य अधिकारी मत्स्य पालन सब्सिडी, कोल तैयारी सोसायटी

ऑफ इंडिया (सीपीएसआई), दालों के गुटबंदी/जमाखोरी पर गठित समूह, बाजार पहुंच पहल (एमएआई) जैसी समितियों पर विदेश मंत्री का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बोर्डों/समितियों, ईडी और राज्यों के भाग के रूप में, विदेश मंत्री दल के आवश्यक आदान और मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं।

12. ऊर्जा

आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ भारत के संबंधों का समन्वय करता है। आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग ने भारत और आईईए के बीच विकसित द्विवार्षिक कार्य कार्यक्रमों में योगदान दिया है, जिसमें संयुक्त वक्तव्य और 2015-17 के लिए संयुक्त कार्रवाई (जेएस एंड एसजेए) की अनुसूची, नीति आयोग और आईईए के बीच आशय का विवरण (एसओआई) के साथ-साथ आईईए के साथ-साथ आईईए और भारत सरकार के बीच संयुक्त कार्यकरण कार्यक्रम 2018-2021। आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग आईईए के साथ भारतीय लाइन मंत्रालयों के संबंधों को सुगम बनाने वाली प्राथमिक समन्वय एजेंसी भी है। बहुपक्षीय मंच पर भारत की ऊर्जा व्यस्तताओं को सुगम बनाने के अलावा, आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा संवादों को आगे बढ़ाने में शामिल संबंधित मंत्रालयों के समूह का भी एक हिस्सा है।

13. बाजार विस्तार गतिविधियां

भारतीय उद्योग और व्यापार की बढ़ती मांगों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए विदेशों में हमारे मिशनों/पोस्टों को सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय के में एक बजट प्रमुख है जिसका शीर्षक है "बाजार विस्तार गतिविधियां" जो शुरू में 2010 में शुरू हुई थी। उनके द्वारा संभाले गए द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा (तेल आयात में छूट) के आधार पर विदेशों में हमारे मिशनों/पोस्टों के लिए बजट प्रमुख के अंतर्गत धन आवंटित किया जाता है। यह बजट हमारे वाणिज्यिक शाखाओं को न केवल नियमित व्यापार और निवेश पूछताछ से निपटने, उनकी मान्यता के देशों में आर्थिक और व्यावसायिक माहौल के बारे में जानकारी प्रदान करने, बल्कि बाजार सर्वेक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं, वाणिज्य मंडलों, उद्योग संघों आदि को लक्षित करने वाली अभिगम्यता गतिविधियों जैसे प्रचार गतिविधियों को शुरू करके नए व्यापार अवसरों की पहचान करने में प्रभावी ढंग से और भारतीय निजी क्षेत्र की अपेक्षाओं के लिए समयबद्ध तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। प्रधान के अधीन मिशन/पोस्टों द्वारा व्यय बाजार विस्तार बजट के लिए व्यय दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है।

इस वर्ष आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग ने विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों/पोस्टों के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राज्य अभिगम्यता

इस प्रभाग ने विदेशों में मिशनों और पोस्टों के नेटवर्क और भारत में शाखा सचिवालयों और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के माध्यम से राज्यों के बाह्य आर्थिक जुड़ाव को सुगम बनाया। मिशनों और पोस्टों ने 09-10 सितंबर 2019 तक भारतीय उच्चायोग, सिंगापुर द्वारा आयोजित अगले चरण-सिंगापुर जैसे राज्य सुविधा

विदेश निधि के माध्यम से राज्य सुविधा गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें आंध्र प्रदेश के राज्य प्रतिनिधिमंडलों ने इसमें पंजाब, उत्तराखंड और ओडिशा ने भाग लिया।

प्रभाग ने आंध्र प्रदेश में आर्थिक और निवेश के अवसरों पर केंद्रित राजनयिक अभिगम्यता इवेंट (विजयवाड़ा में 09 अगस्त, 2019 को आयोजित) और डेक्कन वार्ता के दूसरे संस्करण (हैदराबाद में 31 अगस्त, 2019 को आयोजित) जैसी घटनाओं का आयोजन किया ताकि सुविधा प्रदान की जा सके। राज्यों की कूटनीतिक पहुंच और राज्य सुविधा और ज्ञान सहायता कोष का उपयोग करते हुए राज्य स्तर पर आर्थिक कूटनीति वार्ता को बढ़ावा देना। इस प्रभाग ने 06-08 नवंबर, 2019 तक धर्मशाला में राइजिंग हिमाचल-ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन के संगठन में हिमाचल सरकार के साथ भागीदारी की। साथ ही, प्रभाग ने 10 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन के उद्घाटन का आयोजन किया।

राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से आईएफएस अधिकारियों को राज्यों के आवंटन की पहल पर अपने रेजिडेंट कमिश्नरों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से राज्य और संघ शासित सरकारों के साथ संपर्क जारी रहा और प्रगति हुई। प्रभाग ने राज्य सरकारों और शहरों के बीच अपने विदेशी समकक्षों के साथ समझौता ज्ञापन की सुविधा सिस्टर-स्टेट और शहर साझेदारी स्थापित की।

I) राज्यों द्वारा राजनयिक पहुंच की सुविधा

i. आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग शाखा सचिवालय के माध्यम से, हैदराबाद ने 9 अगस्त, 2019 को **आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राजनयिक अभिगम्यता कार्यक्रम** का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई मिशनों के प्रमुखों सहित दिल्ली और अन्य भारतीय शहरों के 40 से अधिक राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां राज्य में आर्थिक और निवेश के अवसरों पर आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीजगन मोहन रेड्डी ने उन्हें संबोधित किया। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय ने प्रस्तुति दिया और मौजूद राजनयिक समुदाय और प्रतिभागी कारोबारी नेताओं से बातचीत की। माननीय मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लगभग 20 राजदूतों के साथ अलग से बैठकें भी कीं।

ii. **डेक्कन वार्ता -II "व्यवधानों के युग में आर्थिक कूटनीति" :** आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग ने शाखा कार्यालय, हैदराबाद के माध्यम से 31 अगस्त, 2019 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सहयोग से डीक्कन संवाद-II "व्यवधानों के युग में आर्थिक कूटनीति" का आयोजन किया। माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकैया नायडू ने डेक्कन वार्ता-2 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य मंत्री, राजनयिक समुदाय, व्यापार जगत के नेता और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। हैदराबाद में हुए इस कार्यक्रम को 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेने के साथ काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त की।

iii. आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग ने 7-8 नवंबर, 2019 को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सरकार का एक प्रमुख व्यावसायिक आयोजन **राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019** की सुविधा प्रदान की। इस कार्यक्रम में राज्य में विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आठ फोकस क्षेत्रों में नीति और नियामक वातावरण, निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में यूएई, नीदरलैंड, पीआईओसीसीआई, रूस, वियतनाम, जर्मनी आदि के 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 1700 से अधिक व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 10 देशों के राजदूतों ने भाग लिया। निवेशक सम्मेलन के लिए एक रन अप के रूप में, आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिसमें रेजिडेंट एंबेसडर्स ने भाग

लिया था और इसकी अध्यक्षता राज्यमंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने की थी।

II) मिशन/पोस्टों द्वारा राज्य सुविधा गतिविधियां

विदेशों में मिशनों और पोस्टों ने राज्यों और केंद्र प्रदेशों को अपने देश से निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विदेशों में राज्य सुविधा गतिविधियों का आयोजन किया। इन गतिविधियों के लिए बजट प्रमुख 'राज्य सुविधा विदेश' के अंतर्गत प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग किया गया था।

इस प्रभाग ने 11-13 अगस्त, 2019 तक रूसी सुदूर पूर्व में भारत-रूस सहयोग के लिए व्लादिवोस्तोक, रूस के व्लादिवोस्तोक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडलों की पूर्वी आर्थिक मंच के लिए रन-अप भागीदारी की सुविधा प्रदान की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और लगभग 140 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए भारत के पांच राज्यों और रूसी सुदूर पूर्व के क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

III) राज्य और संघ शासित सरकारों के साथ संपर्क करना

विदेश मंत्रालय को राज्यों और संघ शासित सरकारों से जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करते हुए, प्रभाग ने उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के समन्वित आने-जाने वाले दौरों के संबंध में विदेश मंत्रालय की ओर से अंतर-मंत्रालयी परामर्श में भाग लिया। पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दे और शासन के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने विदेशी समकक्षों के साथ राज्य और शहर के प्राधिकारियों द्वारा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में सुविधा प्रदान की गई। आर्थिक कूटनीति और राष्ट्र प्रभाग ने 01 नवंबर 2019 को मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश सेवा संस्थान में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यों और केंद्र प्रदेशों के निवासी आयुक्तों की बैठक आयोजित की। इस प्रभाग ने राज्यों में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए 13 नवंबर, 2019 को उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा आयोजित राज्यों के निवासी आयुक्तों की बैठक में भाग लिया और योगदान दिया।

IV) विदेशी शहरों/राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन की सुविधा

वर्ष 2019-20 के दौरान, आर्थिक कूटनीति और राज्य प्रभाग ने विभिन्न विदेशी संस्थाओं, शहरों और राज्य सरकारों के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में सुविधा प्रदान की :

i) सिस्टर-स्टेट पार्टनरशिप

i. जेओलालनम-डू-प्रांत, कोरिया गणराज्य और पश्चिम बंगाल राज्य, भारत गणराज्य के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के सहयोग और विकास पर समझौता।

ii. ग्योंगनम-डू-प्रांत, कोरिया गणराज्य और पश्चिम बंगाल राज्य, भारत गणराज्य के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के सहयोग और विकास पर समझौता।

iii. रूसी संघ के सखालिन ओब्लास्ट की सरकार और व्यापार सहयोग पर भारत गणराज्य के हरियाणा राज्य के बीच समझौता ज्ञापन।

iv. रूसी परिसंघ के सखा गणराज्य (याकुतिया) और व्यापार सहयोग पर भारत गणराज्य के गुजरात राज्य के बीच समझौता ज्ञापन।

v. रूसी संघ के बुरियातिया गणराज्य और व्यापार सहयोग पर भारत गणराज्य के महाराष्ट्र राज्य के बीच समझौता ज्ञापन।

vi. रूसी संघ के ज़बैकलस्की क्राई और व्यापार सहयोग पर भारत गणराज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के बीच समझौता ज्ञापन।

vii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और फुकुओका प्रीफेक्चुरल सरकार (एफपीजी), जापान के बीच ट्विनिंग समझौते का विस्तार।

viii. गुजरात राज्य, भारत गणराज्य और न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सिस्टर-स्टेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट।

ix. तेलंगाना राज्य, भारत गणराज्य और न्यू जर्सी राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सिस्टर स्टेट पार्टनरशिप समझौते की स्थापना।

x. रूसी परिसंघ के कमचटका क्राय और व्यापार सहयोग पर भारत गणराज्य के गोवा राज्य के बीच समझौता ज्ञापन।

ii) सिस्टर-सिटी पार्टनरशिप

i. नगर निगम, चंडीगढ़ और नॉटिंघम सिटी काउंसिल के बीच सिस्टर सिटी करार।

iii) अन्य समझौते

i. केरल में ई-बस के निर्माण और ई-बस के निर्माण के लिए स्विस ई-बस निर्माता फर्म एचईएसएस और परिवहन, मत्स्य पालन और राजस्व विभाग, केरल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।

ii. नगरीय प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग, तमिलनाडु सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच सहयोग ज्ञापन।

iii. मेघालय राज्य में स्मार्ट गांवों को लागू करने के लिए एक पुरस्कार के लिए मेघालय सरकार और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन।

15

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलें

वैश्विक शांति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे पर टिकी हुई है। भारत निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और भारत ने विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर अपने अनुभवों और व्यस्तताओं के आधार पर मजबूत और विश्वसनीय सोच विकसित की है। निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर भारत का रुख अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की परंपरा के कारण पथप्रदर्शक था, जो विकसित हो रहे भू-स्थानिक वातावरण में वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देता है।

वर्ष 2019 में, भारत ने सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के साथ-साथ सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति

भारत ने 7 अक्टूबर से 8 नवंबर 2019 के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति के 74वें सत्र में वैश्विक, गैर-भेदभावपूर्ण और सत्यापनीय परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

'आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार उपलब्ध करने से रोकने के उपाय', का भारत का संकल्प जिसे वर्ष 2002 में प्रथम बार पेश किया गया था, इस वर्ष फिर से आम सहमति से अपनाया गया है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का सहायता देने के उद्देश्य से उपाय करने का आह्वान किया गया है।

"परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध" पर भारत का संकल्प ने सम्मेलन का आयोजन संभव बनाया इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के उपयोग अथवा खतरे को रोकने के लिए हथियारों के निरस्त्रीकरण विषय पर चर्चा हुई।

'परमाणु खतरे को कम करने' पर भारत के संकल्प ने परमाणु हथियारों के जानबूझकर या आकस्मिक उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा और तकाल उठाये जाने वाले कदम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें उनकी डी-अलर्टिंग और डी-टारगेटिंग शामिल हैं।

'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर भारत के संकल्प को आम सहमति से अपनाया गया था। पिछले साल रिजॉल्यूशन द्वारा अनिवार्य यूएनएसजी की रिपोर्ट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मौजूदा विकास और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण प्रयासों पर उनके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला। प्रस्ताव राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य राज्यों को सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुपक्षीय संवाद के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मौजूदा विकास पर संबंधित हितधारकों के बीच बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण प्रयासों पर उनके संभावित प्रभाव को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कतर के साथ मिलकर 19 अगस्त, 2019 को यूएनआईडीआईआर द्वारा पहले वार्षिक 'इनोवेशन डायलॉग' के संगठन का समर्थन किया। सेमिनार का आयोजन भारत के साथ जुड़े महासभा के प्रस्ताव 73/32 में लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। इनोवेशन डायलॉग का विषय 'डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी' था।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यूएनडीसी)

वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग को औपचारिक सत्र बुलाने की सर्वसम्मति न बन पाने के कारण 16 अप्रैल से 29 अप्रैल 2019 तक केवल अनौपचारिक अवस्था में आयोजित किया गया था। भारत ने वर्तमान तीन वर्षीय चक्र के लिए अपनाए गए दो एजेंडा आइटम (परमाणु हथियार और बाहरी स्थान) पर अनौपचारिक चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया।

निरस्त्रीकरण (सीडी) पर सम्मेलन

निरस्त्रीकरण सम्मेलन सत्र 21 जनवरी से 29 मार्च, 13 मई से 28 जून और 29 जुलाई से 13 सितंबर 2019 तक हुआ। 2019 सत्र के दौरान, सम्मेलन के बाद के अध्यक्षों ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन के कार्यक्रम के कार्य पर आम सहमति बनाने के लिए गहन विचार-विमर्श किया, जो अंत तक टालमटोल वाला रहा। भारत ने सीडी एजेंडा पर चार प्रमुख मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया, जिसमें परमाणु निरस्त्रीकरण, फिशाइल

मैटेरियल कट-ऑफ ट्रीटी (एफएमसीटी), प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस (पीएआरओएस) और नेगेटिव सिक्योरिटी अश्यूरंश (एनएसए) शामिल हैं। भारत ने सीडी द्वारा कार्य का कार्यक्रम अपनाने का आह्वान किया, ताकि बातचीत फिर से शुरू की जा सके। भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक गैर-भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय रूप से सत्यापित एफएफसीटी के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत शुरू करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी)

भारत यूएनएससी संकल्प 1540 (2004) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समिति के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है जो राज्यों, अंतर-देशों को किसी भी तरह से गैर-राज्यों के विकास, अधिग्रहण, निर्माण, रखने, परिवहन, स्थानांतरण या परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों और उनके वितरण प्रणाली का उपयोग करने से रोकने के लिए बाध्य करता है। वर्ष 2004 से भारत यूएनएससीआर 1540 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है। भारत ने जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र में अपनी नवीनतम राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की, जून 2017 की अंतिम राष्ट्रीय रिपोर्ट के बाद से निर्यात नियंत्रण और यूएनएससीआर 1540 के कार्यान्वयन के क्षेत्र में की गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया।

जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन (बीटीडब्ल्यूसी)

भारत ने जेनेवा में 29 जुलाई - 8 अगस्त 2019 तक आयोजित विशेषज्ञों (एमएक्सपी) की पांच बैठकों के साथ ही 03-06 दिसंबर, 2019 तक राष्ट्रों की पार्टियों की वार्षिक बैठक (एमएसपी) में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने, विशेषज्ञों की बैठक के अवसर पर "विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए परिदृश्य : जैव-खतरे का पता लगाने और न्यूनीकरण में नई सीमाएं और चुनौतियां" पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

भारत ने दो कार्यपत्रक प्रस्तुत किए हैं - (i) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ''बीडब्ल्यूसी के अनुच्छेद-III के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना'' और (ii) फ्रांस के साथ 'बीडब्ल्यूसी के अनुच्छेद-VII के ढांचे में सहायता के लिए एक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव'।

रासायनिक शस्त्र सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी)

रासायनिक शस्त्रों के निषेध (ओपीसीडब्ल्यू) के लिए संगठन की कार्यकारी परिषद् (ईसी) के सदस्य के रूप में, भारत ने रासायनिक शस्त्र विनाश, उद्योग निरीक्षण, राष्ट्रीय कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता जैसे मुद्दों में अहम योगदान दिया। पिछले वर्षों की तरह, भारत ने पूरे वर्ष ईसी के विभिन्न सत्रों के दौरान राष्ट्र समुदाय पक्षकारों के साथ जुड़कर और 25-29 नवंबर, 2019 के दौरान आयोजित होने वाले राष्ट्र दलों के सम्मेलन (सीएसपी) के वार्षिक सत्र में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा।

ओपीसीडब्ल्यू नेशनल अथॉरिटी मेंटरशिप/पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, भारत ने अफगान अधिकारियों को उनके ज्ञान, कौशल और अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम का पहला दौर नई दिल्ली में दिनांक 29 अप्रैल से 03 मई, 2019 तक आयोजित किया गया था।

कुछ पारंपरिक हथियारों पर सम्मेलन (सीसीडब्ल्यू)

भारत ने संशोधित प्रोटोकॉल-II के विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया; विशेषज्ञों का समूह (22 अगस्त 2019); प्रोटोकॉल V, विशेषज्ञों की बैठक (23 अगस्त 2019) और एलएडब्ल्यूएस पर सरकारी विशेषज्ञों का समूह (25-29 मार्च और 20-21 अगस्त 2019)। भारत ने 13 से 15 नवंबर, 2019 तक सीसीडब्ल्यू के साथ-साथ 12 नवंबर और 11 नवंबर, 2019 को संशोधित प्रोटोकॉल-II और प्रोटोकॉल- V के वार्षिक सम्मेलनों में उच्च अनुबंध वाले दलों की वार्षिक बैठक के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया।

एन्टी-पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन (एसपीएमबीसी)

भारत ने 25-29 नवंबर, 2019 को ओस्लो में आयोजित एसपीएमबीसी के चतुर्थ समीक्षा सम्मेलन में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। भले ही भारत सम्मेलन के लिए एक पार्टी न हो, परंतु सीसीडब्ल्यू अतिरिक्त प्रोटोकाल-II के अनुसार भारत, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

छोटे और हल्के शस्त्र

जुलाई 2001 में अपनाए गए सभी पहलुओं (यूएनपीए) में छोटे शस्त्र और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार को रोकने, उसका मुकाबला करने और उसके उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक उपायों का एक व्यापक स्वरूप है। भारत ने यूएनपीए और अंतर्राष्ट्रीय अनुरेखण साधन के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति करना जारी रखा है। भारत ने 18-29 जून 2018 से न्यूयॉर्क मे एसएएलडब्ल्यू पर तीसरे समीक्षा सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

सरकारी विशेषज्ञों के समूह में भागीदारी (जीजीई)

भारत ने आउटर स्पेस (पीएआरओएस) में शस्त्र दौड़ की रोकथाम के लिए सरकारी विशेषज्ञों के समूह में सक्रिय रूप से भाग लिया, सत्र का समापन मार्च 2019 में हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर ऑफ कन्वेंशनल एम्स (यूएनआरओसीए) में जीजीई के तीन सत्रों मार्च, अप्रैल और जून 2019 में भी भाग लिया।

परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन (सीईआरएन)

भारत 2017 में सीईआरएन का सहयोगी सदस्य बना। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने सीईआरएन परिषद्, वित्त समिति एवं वैज्ञानिक नीति समिति के सत्रों में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

वियना में दिनांक 16-20 सितंबर 2019 के दौरान आयोजित आईएईए आम सम्मेलन के 63वें सत्र में भारत ने भाग लिया। भारत ने आईएईए के 63वें आम सम्मेलन के मौके पर वियना में एनएसजी विश्वम कैंसर केयर कनेक्शन 17 सितंबर 2019 को लॉन्च किया। इसी के आधार पर, टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) द्वारा स्थापित और प्रबंधित राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (एनएसजी) जिसमें भारत से 183 भाग लेने वाले हितधारक हैं, उसे विदेशों के कैंसर अस्पतालों और अन्य संबंधित संस्थानों के लिए खोला गया है। पिछले वर्षों की तरह, भारत ने मार्च, जून, सितंबर और नवंबर, 2019 में आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकों के दौरान राष्ट्र पक्षकारों के साथ जुड़कर एक सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है।

समुद्री मामले

भारत ने 2019 में वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार, फ्रांस, जापान, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्षिक समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित किया। संवादों में आपसी हित के मुद्दों को शामिल किया गया, जिसमें भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा स्थिति के विकास के साथ-साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएं शामिल हैं। समुद्री क्षेत्र के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए भारत ने कई देशों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी संख्या अब 17 हो गई है। इसके अलावा, भारत ने ट्रांस रिजनल मैरीटाइम नेटवर्क (टी-आरएमएन) पर एक आरोहण समझौते पर भी हस्ताक्षर किया, जो 30 देशों की एक बहुपक्षीय रचना है।

मलक्का और सिंगापुर की समुद्र-संधि (एसओएमएस)

वर्ष 2007 में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) 'प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल शिपिंग लेन' पहल के अंतर्गत मलक्का और सिंगापुर (एसओएमएस) के सहकारी तंत्रों में सक्रिय सदस्य रहा है। पूर्व के योगदान के आधार पर, भारत ने अप्रैल और सितंबर 2019 में मलेशिया में आयोजित नेविगेशन फंड (एएनएफ) समिति की 22 वीं और 23 वीं बैठक में भाग लिया। भारत ने एएनएफ के लिए 30 लाख रुपये का योगदान दिया, जो सहकारी यांत्रिकी के लिए कोषाध्यक्ष की तरह से कार्य करता है और नेविगेशन की जरूरी सहायता के नियोजित रखरखाव के लिए एक बजट उपलब्ध कराता है।

सोमालिया के तट पर पायरेसी पर संपर्क समूह (सीजीपीसीएस)

भारत ने 20 जून 2019 को मॉरीशस में आयोजित सोमालिया (सीजीपीसीएस) के तट पर पायरेसी पर संपर्क समूह के 22वें पूर्ण सत्र में भाग लिया। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और सेशेल्स के साथ, 'सागर में संचालन' पर समूह की सह-अध्यक्षता की।

एशिया में परस्पर सहयोग और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए)

भारत ने वर्षभर सीआईसीए कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

विदेश मंत्री, डॉ. एस. जयशंकर, 14-15 जून 2019 को ताजिकिस्तान के दुशान्बे में एशिया (सीआईसीए) शिखर सम्मेलन में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर आयोजित 5वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन का विषय "सुरक्षित और अधिक समृद्ध सीआईसीए क्षेत्र के लिए सांझी दृष्टि" था।

विदेश राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन ने 74वें यूएनजीए के अवसर पर सीआईसीए के एक अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) और एडीएमएम प्लस

भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के अनुरूप, भारत ने एआरएफ के तवावधान में आयोजित अंतर-व्यावसायिक बैठकों (आईएसएम) और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में सक्रिय रूप से भाग लिया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने दिनांक 02 अगस्त 2019 को सिंगापुर में 26 वीं एआरएफ मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया।

रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने 18 नवंबर 2019 को बैंकॉक में आयोजित वार्षिक एडीएमएम प्लस संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत म्यांमार के साथ मिलिट्री मेडिसिन पर एडीएमएम प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप का सह-अध्यक्ष हैं और उन्होंने इंटर सैशनल मीटिंग (आईएसएम) में अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति पूरा किया है इसके साथ ही उन्होंने एक साथ एडीएमएम प्लस के तवावधान में आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में भाग लिया है।

परमाणु सुरक्षा संपर्क समूह (एनएससीजी)

एनएससीजी परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का परिणाम है और भारत ने 2019 में समूह की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने 23 मई 2019 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित एनएससीजी पूर्ण बैठक में भाग लिया।

निर्यात नियंत्रण

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, जो स्वैच्छिक आधार पर, समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ लाती हैं, ने निर्यात नियंत्रण और विशिष्ट वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों की सूची जारी करने के लिए गैर-प्रसार के लक्ष्यों में योगदान दिया है जिनके निर्यात को विनियमित किया जाना चाहिए। भारत जून 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर), दिसंबर 2017 में वासेनार अरेंजमेंट (डब्ल्यूए) और जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) का सदस्य बना। एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का आवेदन विचाराधीन है।

भारत के बहु-एजेंसी प्रतिनिधिमंडलों ने तीन बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की विभिन्न बैठकों जैसे;

दिसंबर 2019 में डब्ल्यूए, जून 2019 में एजी और अक्टूबर 2019 में एमटीसीआर की बैठकों सहित डब्ल्यूए, एजी, एमटीसीआर में भाग लिया।

वर्ष के दौरान, विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (एससीओएमईटी) की भारत की निर्यात नियंत्रण सूची 2018 के दिशा-निर्देशों और चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की नियंत्रण सूचियों के तालमेल के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2019 को नवीकृत (24 जुलाई 2019 से प्रभावी) की गई है।

विदेश मंत्रालय ने निर्यात नियंत्रण लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया, जैसेकि; इंट्रा कंपनी ट्रांसफर (जीएआईसीटी) के लिए वैश्विक प्राधिकरण और ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) आदि।

एमईए, डीजीएफटी और उद्योग भागीदारों सहित अपने सरकारी भागीदारों के साथ, निर्यात नियंत्रण प्रणाली के कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग के रूप में आउटरीच गतिविधियों में शामिल रहा है। इनमें बैंगलोर में 23 फरवरी 2019 को एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के संदर्भ में भारत के निर्यात नियंत्रण ढांचे पर कार्यक्रम, बैंगलोर में 5 मार्च 2019 को अमूर्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (आईटीटी) पर चर्चा करने के लिए उद्योग सहभागिता, रासायनिक उद्योग के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा 25 मार्च 2019 को सूरत में रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) और एससीओएमईटी शामिल हैं। इसके अलावा, निर्यात नियंत्रण पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 17 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 'उत्पाद सुरक्षा तथा वाणिज्यिक ग्रेड विस्फोटकों (सीजीई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा' विषय पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 19 अगस्त, 2019 को नागपुर में आयोजित की गई थी।

हेग आचार संहिता

भारत जून 2016 में हेग आचार संहिता (एचसीओसी) में शामिल/सदस्यता ले चुका है। पारदर्शिता और विश्वास निर्माण उपायों के लिए प्रतिबद्धताओं के अनुपालन में, भारत ने नियमित रूप से भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के पूर्व प्रक्षेपण सूचनाओं के एचसीओसी को अधिसूचित किया।

भारत ने एचसीओसी की 18वीं नियमित बैठक में भाग लिया, जो 3-4 जून 2019 तक वियना में आयोजित की गई थी। भारत ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी वार्षिक घोषणा भी प्रस्तुत कर दी है।

आउटर स्पेस

भारत ने वियना में संयुक्त राष्ट्र समिति की आउटर स्पेस का शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी उपसमितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा। 24 दिसंबर 2017 को सरकारी विशेषज्ञों के एक समूह (जीजीई) द्वारा 25 सदस्यीय राज्यों की सदस्यता के साथ "आउटर स्पेस में हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए आगे के व्यावहारिक उपायों" के हकदार यूएनजीए संकल्प 72/250 अपनाने के परिणामस्वरूप, और आउटर स्पेस में हथियारों की स्थापना की रोकथाम पर आउटर स्पेस में हथियार दौड़ की रोकथाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के पर्याप्त तत्वों पर विचार करने और सिफारिश करने के साथ काम किया। भारत ने अगस्त 2018 और मार्च 2019 में आयोजित जीजीई के दोनों सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारत- जापान अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन 07 मार्च 2019 को नई दिल्ली में किया गया। भारत-अमेरिका अंतरिक्ष वार्ता का तीसरा चरण 12 मार्च 2019 को वाशिंगटन में आयोजित किया गया था।

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर फैलोशिप कार्यक्रम

निरस्त्रीकरण, अप्रसार और हथियारों पर नियंत्रण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, और युवा राजनयिकों को आवश्यक ज्ञान और कौशलयुक्त बनाने के लिए, विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों (डी एण्ड आईएसए) प्रभाग के सहयोग से विदेश मंत्रालय प्रभाग दिनांक 13 से 31 अक्टूबर, 2020 तक विदेशी राजनयिकों के लिए द्वितीय निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की फैलोशिप का आयोजन कर रहा है।

भारत की पहल यूएनजीए संकल्प 71/57 'निरस्त्रीकरण और अप्रसार शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र का अध्ययन' के जनादेश को पूरा करती है और यूएनएसजी के निरस्त्रीकरण' एजेंडा 'विश्व और हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने' पर केन्द्रित है।

16

विधिक और संधि प्रभाग

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विधि

संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (विधिक)

संयुक्त राष्ट्र की छठी समिति, महासभा की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को विधिक प्रश्नों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। पिछले वर्षों की तरह, विधिक और संधि प्रभाग ने छठी समिति के कार्यों का अनुसरण किया और इसके विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया।

महासभा के 74वें सत्र के दौरान छठी समिति की बैठक 07 से 14अक्तूबर और 20 नवंबर 2019 को हुई। महासभा ने सत्र के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति को आवंटित मदों पर निम्नलिखित प्रस्तावों और निर्णयों को अपनाया :

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कृत्यों के लिए राष्ट्रों की जिम्मेदारी
- मिशन पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और विशेषज्ञों की आपराधिक जवाबदेही
- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग की बावनवें सत्र पर कार्यों की रिपोर्ट
- शिक्षण, अध्ययन, प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्यापक सराहना में सहायता के संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम
- इसके इकहत्तरवें सत्र के काम पर अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट
- राजनयिक संरक्षण
- खतरनाक गतिविधियों से सीमापार नुकसान की रोकथाम और इस प्रकार के नुकसान के मामले में नुकसान के निर्धारण पर विचार
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर विशेष समिति की रिपोर्ट और संगठन की भूमिका को सुदृढ़ करना

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि का शासन
- सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के सिद्धांत का दायरा और अनुप्रयोग
- सीमापार जलभृतों का विधि
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय
- महासभा के कार्य का पुनर्निधारण
- कार्यक्रम आयोजन
- संयुक्त राष्ट्र में न्याय की अनुपालना
- मेजबान देश के साथ संबंधों पर समिति की रिपोर्ट
- महासभा में तुर्कभाषी राष्ट्रों की सहयोग परिषद के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा
- महासभा में यूरेशियन आर्थिक यूनियन के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा
- महासभा में कम्यूनिटी ऑफ डेपोंक्रेटिक्स के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा
- महासभा में वेटलैंड्स सचिवालय पर रामसर अधिवेशन के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा
- महासभा में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा
- महासभा में ग्रुप ऑफ सैवन प्लस के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा
- महासभा में नियोक्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा
- महासभा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा
- महासभा में एशिया के बोओ फोरम के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा

भारत ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और कुछ विषयों पर वक्तव्य दिया।

अंतर्राष्ट्रीय विधि सप्ताह

संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधि सप्ताह निर्धारित है। इस अवधि के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (विधिक समिति) अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के कार्य की समीक्षा करती है और पिछले एक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट पर चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 28 अक्तूबर से 1 नवंबर 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय विधि सप्ताह मनाया गया। विदेश मंत्रालय की अवर सचिव और विधि सलाहकार सुश्री उमा शेखर ने अंतर्राष्ट्रीय विधि सप्ताह के दौरान कार्यक्रमों में भाग लिया और समकालीन प्रासंगिकता के अंतर्राष्ट्रीय विधि मुद्दों पर चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय विधि सप्ताह के दौरान छठी समिति ने श्री पावेल स्टर्मा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रभागों के 71वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के कार्यों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। समीक्षाधीन अवधि (71 वें सत्र) के दौरान, आयोग ने अपने कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि (जूस कॉजन) के मौलिक मानदंडों का संहिताकरण, मानवता के विरूद्ध अपराध, विदेशी आपराधिक क्षेत्राधिकार से राष्ट्र के अधिकारियों की प्रतिरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और समुद्र स्तर में वृद्धि आदि शामिल है।

भारत ने अपने हस्तक्षेपों में आयोग (आईएलसी) द्वारा तैयार किए गए अनुच्छेदों के मसौदे पर महत्वपूर्ण विश्लेषण की पेशकश की जिसमें इन मुद्दों पर महासभा द्वारा संभावित कन्वेंशन के विस्तार के लिए महासभा में आयोग की सिफारिशें शामिल हैं, विशेष रूप से, आयोग का मानवता के विरूद्ध अपराधों को समन्वित करने/परिभाषित करने का प्रयास (हत्या, यातना, व्यक्तियों का जबरन गायब होना, संहार, जबरन गर्भावस्था आदि) अपने मसौदा लेखों में एक संभावित कन्वेंशन के लिए अपने मसौदा लेखों में, जो

एक संभावित कन्वेंशन के लिए अनुच्छेदों का संहार, जो अनुभववादी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का विश्लेषण, लेकिन काफी हद तक सादृश्य या अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों से कटौती द्वारा किए गए हैं और सार्वभौमिकता प्राप्त नहीं की गई है।

इस अवधि में छठी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर बहस की। भारत ने इस बहस में भाग लिया, आईएलसी द्वारा विचार किए गए अंतर्राष्ट्रीय विधि विषयों की जांच की और जूस कॉजेन्स पर भारत की स्थिति, राज्य के अधिकारियों की प्रतिरक्षा, 'समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके निहितार्थ आदि विषयों पर टिप्पणी की।

छठी समिति के विचार-विमर्श के अवसर पर विधिक सलाहकारों की अनौपचारिक बैठक भी हुई। यह एक ऐसी पहल है जो 1989 में कनाडा, भारत, मैक्सिको, पोलैंड और स्वीडन के विदेश मामलों के मंत्रालयों के विधिक सलाहकारों द्वारा की गई थी ताकि सदस्यों के लिए समकालीन प्रासंगिकता/हित के अंतर्राष्ट्रीय विधि मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विदेश मामलों के मंत्रालयों के विधिक विभागों के प्रमुखों को एक साथ लाया जा सके। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान, मेक्सिको अनौपचारिक चर्चाओं का समन्वय करता है। माननीय सदस्यों ने गैर-राष्ट्र भागीदारों के विरुद्ध बल प्रयोग पर रोक, चुनौतियों, सीमाओं के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की भूमिका और युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों आदि के मामलों में वीटो का उपयोग करने जैसे मुद्दों पर चिंतन किया।

अंतर्राष्ट्रीय विधि सप्ताह के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विधिक सलाहकार भी अनौपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक करते हैं और ब्रिक्स सदस्य देशों में विशेष रुचि रखते हैं। ब्राजील ने इस वर्ष की अनौपचारिक ब्रिक्स विधिक सलाहकारों की बैठक का अध्यक्ष होने के नाते पहल की। प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के समक्ष साइबर सुरक्षा, विधि का शासन, बहुपक्षीयता के साथ-साथ यूएनसीआईटीआरएएल द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं जैसे निवेशक राष्ट्र विवाद निपटान तंत्र में संभावित सुधारों जैसे विषयों पर अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान किया।

महासागरों और समुद्र के विधि

विधिक और संधि प्रभाग के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे, जिन्होंने 14-18 अक्तूबर, 2019 के न्यूयॉर्क में आयोजित कॉन्टिनेंटल शेल्फ (सीएलसीएस) की सीमाओं पर आयोग के उप-आयोग के साथ बैठक में भाग लिया। उप आयोग की स्थापना अरब सागर में भारत के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के संबंध में भारत द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं की जांच करने के लिए की गई है। उप-आयोग ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (यूएनसीएलओएस) के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत प्रस्तुत भारतीय दावे प्रस्तुत करने की जांच की।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीईट्रल)

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की मुख्य विधिक संस्था है। 50 से अधिक वर्षों के लिए दुनिया भर में वाणिज्यिक विधि सुधार में विशेषज्ञता सार्वभौमिक सदस्यता के साथ एक विधिक निकाय, यूएनसीईट्रल

प्रगतिशील सामंजस्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विधि के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है, विशेष रूप से, संहिताबद्ध और सामंजस्य वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि के वर्तमान और विकसित मुद्दे पर। भारत इसकी स्थापना के बाद से यूएनसीआईटीआरएल का सदस्य है, जो इसके सत्रों में भाग ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि के विकास में योगदान दे रहा है। भारत ने वर्ष 2019-20 के दौरान चुनिंदा कार्य समूहों की बैठकों में हिस्सा लिया है। यूएनसीआईटीआरएएल के अंतर्गत विभिन्न कार्य समूह हैं:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों पर कार्य दल
- मध्यस्थता और सुलह/विवाद निपटान पर कार्य दल द्वितीय
- निवेशक-राष्ट्र विवाद निपटान सुधार पर कार्य दल III
- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर कार्य दल IV
- दिवाला विधि पर कार्य दल वी सुरक्षा हितों पर कार्य दल VI

भारत कार्यदल III (निवेशक-राष्ट्र विवाद निपटान सुधार के लिए निवेशक राज्य विवाद निपटान तंत्र में सुधार के लिए अनिवार्य) के लिए मसौदा समिति में शामिल हो गया है। भारत ने अपने राष्ट्रीय संवाददाताओं को भी उन्सीट्राल सीएलयू के लिए नामित किया।

उन्सीट्राल का 52 वां वार्षिक अधिवेशन (वियना में 8-19 जुलाई 2019 से आयोजित) ने अपने कार्य समूहों के माध्यम से यूएनसीआईटीआरएल में अब तक की गई प्रगति पर अपडेट प्रदान करने का आकलन किया। भारत ने ऊपर उल्लिखित विभिन्न कार्य समूहों में भाग लिया और विचारों का आदान-प्रदान किया।

एशियाई-अफ्रीकी विधिक सलाहकार संगठन (एएलसीओ)

विधिक और संधि प्रभाग ने 21-25 अक्तूबर 2019 को तंजानिया के दार-ए-सलाम में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी विधिक सलाहकार संगठन (एएलसीओ) के 58 वें वार्षिक अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सत्र में एएलसीओ के पच्चीस सदस्य देशों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की विधिक और संधि प्रभाग की अपर सचिव और विधिक सलाहकार सुश्री उमा शेखर ने किया। तंजानिया के उपराष्ट्रपति महामहिम सामिया सुलुहू हसन, जो मुख्य अतिथि थे, ने सत्र का उद्घाटन किया।

सत्र में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई: अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की कार्यसूची के विषय; समुद्र का विधि; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश विधि; साइबर स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय विधि; विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा; राष्ट्रीय विधानों का अतिरिक्त प्रादेशिक अनुप्रयोग; और फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन। इसके अतिरिक्त संगठन के संगठनात्मक और वित्तीय मामलों पर भी चर्चा हुई।

सामान्य वक्तव्य के अलावा, भारतीय शिष्टमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की कार्यसूची में विषयों; समुद्र का विधि; साइबर स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय विधि; विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा; और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश विधि पर वक्तव्य दिए।

विधिक और संधि प्रभाग ने 15 नवंबर 2019 को दिल्ली में आयोजित 63 वें संविधान दिवस समारोह में भी भाग लिया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय की अपर सचिव और विधिक सलाहकार सुश्री उमा शेखर ने भी विशेष संबोधन दिया।

भारत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद न्यायनिर्णयन

1. **एनरिका लेक्सी मामला (इटली और भारत) :** इटली ने जून 2015 में भारत पर "अनुच्छेद 287 और अनुलग्नक सातवीं, यूएनसीएलओएस के अंतर्गत अधिसूचना" की सेवा करके मध्यस्थता कार्यवाही की स्थापना की थी। अंतिम मौखिक सुनवाई 8-20 जुलाई, 2019 से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आयोजित की गई थी, जिसे पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, हेग, नीदरलैंड द्वारा सुगम बनाया गया था। सुनवाई के दौरान भारत और इटली ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ इटली के दावों और भारत के जवाबी दावों की खूबियों को संबोधित करते हुए अपनी दलीलें पेश कीं।

2. **कुलभूषण जाधव मामला (भारत बनाम पाकिस्तान)** : जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के समक्ष योग्यता पर अंतिम मौखिक सुनवाई नीदरलैंड के हेग में 18 से 21 फरवरी, 2019 तक हुई थी। अदालत ने 17 जुलाई, 2019 को अपना निर्णय सुनाया। अपने आदेश में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस (वीसीसीआर) के कथित उल्लंघनों के आधार पर भारत के दावों का संज्ञान लेने करने का क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा, न्यायालय ने भारत के इस दावे को बरकरार रखा कि पाकिस्तान ने श्री जाधव की नजरबंदी के अविलंब भारत को सूचित करने में विफल रहने से वीसीसीआर के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत अपने दायित्वों का उल्लंघन करने का काम किया है।

3. **हैदराबाद निजाम निधि मामला (पाकिस्तान बनाम भारत और अन्य) :** लंदन, यूनाइटेड किंगडम में उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य सुनवाई भारत, पाकिस्तान और उत्तराधिकारियों के बीच हैदराबाद के सातवें निजाम शीर्षक विभाजन विवाद का निर्धारण करने की याचिका पर 10-19 जून, 2019 को मुख्य सुनवाई हुई। यह पाया गया कि 7वां निजाम लाभकारी रूप से निजाम निधि का हकदार था। ब्रिटेन उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए 2 अक्तूबर, 2019 के अपने निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला कि 7वें निजाम - भारत, प्रिंस मुफखाम जाह और प्रिंस के अधिकार में दावा करने वाले लोग मुकरराम जाह- निधि के हकदार थे।

4. **निवेश से संबंधित मध्यस्थता मामले :** स्थायी पंचाट न्यायालय (पीसीए) द्वारा प्रशासित विभिन्न निवेश संधियों के अंतर्गत भारत गणराज्य के विरूद्ध शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में चालू वर्ष (2019-20) के दौरान हुई घटनाएं।

- **रूसी परिसंघ सरकार और रूसी संघ सरकार के बीच समझौते के अंतर्गत टेनोक होल्डिंग्स लिमिटेड (साइप्रस), श्री मैक्सिम नौचेंको (रूसी परिसंघ) और श्री एंड्री पोलुएक्टोव (रूसी परिसंघ) [दावेदार] और भारत गणराज्य [प्रतिवादी],** निवेश को बढ़ावा देने और पारस्परिक संरक्षण के लिए भारत गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य और साइप्रस गणराज्य के बीच समझौता पारस्परिक संवर्धन और निवेश के संरक्षण के पक्ष में प्रतिवादी, भारत गणराज्य, ट्रिब्यूनल ने निवेशकों के सभी दावों को खारिज करते हुए भारत के पक्ष में निर्णय सुनाया।

- भारत-जापान सीईपीए के अंतर्गत निसान मोटर कंपनी लिमिटेड; ट्रिब्यूनल ने दावेदार **(अर्थात् निसान मोटर)** के पक्ष में क्षेत्राधिकार पर प्रारंभिक आपत्तियों पर निर्णय सुनाया, जिसमें कर मामलों के सीईपीए के दायरे में आने के प्रश्न को छोड़कर सभी मामलों पर भारत की क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। यह प्रश्न फरवरी, 2020 में सुनवाई के अगले दौर में है।

- **वेदांता रिसोर्सेज,** भारत-ब्रिटेन बिपा के अंतर्गत वेदांता द्वारा इस मामले में अंतिम सुनवाई मई, 2019 में संपन्न हुई और 2020 में मध्यस्थ पंचाट प्राप्त होने की आशा है।

प्रत्यर्पण

वर्ष 2019 के दौरान, विधिक और संधि प्रभाग ने भारत और विदेशों के 60 प्रत्यर्पण अनुरोधों की जांच की, जिनमें भगोड़ों से जुड़े कुछ अति संवेदनशील मामले शामिल हैं।

प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि पर हेग सम्मेलन (एचसीएचएच)

प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि (एचसीएचएच) पर हेग सम्मेलन के पेरेंटेज/सरोगेसी परियोजना पर विशेषज्ञों के समूह की छठी बैठक 29 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2019 को हेग, नीदरलैंड में हुई, जिसमें विधिक पितृत्व पर विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों को स्वीकार करने की संभावना पर चर्चा की गई; विदेशों में स्थापित विधिक पितृत्व को पहचानने की संभावना जहां कोई न्यायिक निर्णय नहीं है; इस बात पर चर्चा करते हुए कि क्या विधिक पितृत्व पर एक समान लागू विधि नियमों पर समझौते तक पहुंचना संभव है, विधि के संचालन, विधिक पितृत्व से संबंधित विदेशी न्यायिक निर्णयों के द्वारा सीमापार मान्यता के संबंध में परिष्कृत प्रावधान जिसमें यह भी शामिल है कि ऐसे कोई नियम सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। भारत ने इस सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया और परियोजना में योगदान दिया।

अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि

श्रीलंका के कोलंबो में 11-13 नवंबर, 2019 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि पर 9वां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति (आईसीआरसी) द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय था, "आईएचएल होम: रोकथाम और संरक्षण की गाथा"। प्रतिनिधियों ने 33 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्तावित विषयगत संकल्पों जैसे आईएचएल होम को लाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया; जलवायु-स्मार्ट आपदा विधि और नीतियां; परिवार के लिंक बहाल; और मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को संबोधित करते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जिनेवा कन्वेंशन के 70 वर्षों पर भाषण दिया।

संधि वार्ता

विधिक और संधि प्रभाग ने राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व के विभिन्न विषयों से संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनमें से सबसे उल्लेखनीय बहुपक्षीय वार्ताएं हैं,

- नैरोबी में आयोजित "पर्यावरण विधि के लिए वैश्विक समझौता" के प्रति तदर्थ मुक्त कार्य समूह का तृतीय सत्र;
- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में साइबर स्पेस में उत्तरदायी राष्ट्र व्यवहार को आगे बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों का समूह (जीजीई)। ओईडब्ल्यूजी का पहला सत्र सितंबर में आयोजित किया गया था और जीजीई का पहला सत्र दिसंबर में आयोजित किया गया था।
- वियना में 1-12 अप्रैल, 2019 से आयोजित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर संयुक्त राष्ट्र समिति पर विधिक उप-समिति का 58 वां सत्र।
- वियना में 27-29 मार्च, 2019 से आयोजित साइबर अपराध पर व्यापक अध्ययन करने के लिए

5वीं यूएनओडीसी अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की बैठक। कार्य योजना के अनुसार, विशेषज्ञ समूह ने विधि और प्रवर्तन और जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और आपराधिक न्याय के विषयों पर भी चर्चा की।

- भारत और दस अन्य देशों (जैसे इजरायल, रूस, सऊदी अरब, कंबोडिया, मैक्सिको, यूएई आदि) के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि वार्ता।
- जकार्ता में 28-31 अक्तूबर 2019 तक आयोजित (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते) आरसीईपी की विधिक स्क्रबिंग के लिए तैयारी बैठक। बैठक में आरसीईपी समझौते के विभिन्न अध्यायों की विधिक स्क्रबिंग पर दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं तय की गईं (भारत ने बाद में इसे बाहर करने का विकल्प चुना)।
- उपर्युक्त के अलावा, विधिक और संधि प्रभाग ने व्यापार, नागरिक और आपराधिक कानूनों, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी मामलों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

ऑनलाइन संधि डाटाबेस

भारत सरकार की ओर से अपने विदेशी समकक्षों के साथ संपन्न किए गए समझौतों/संधियों को भारतीय संधि डाटाबेस में अनुक्रमित और अपलोड किया जाता है जिसे विधिक और संधि प्रभाग द्वारा बनाए और लगातार अद्यतन किया जाता है। संधि डाटाबेस (वेब लिंक: https://www.mea.gov.in/TreatyList.htm?1) में 1950 से 2019 तक की अवधि को कवर करने वाली संधियां शामिल हैं। वर्तमान में डाटाबेस में 3,200 से अधिक ऐसी संधियां हैं जिन्हें आम जनता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

विधिक दस्तावेजों की जांच/पुनरीक्षण

विधिक और संधि प्रभाग ने समझौता ज्ञापन, संधियों/समझौतों के साथ-साथ कैबिनेट नोट्स सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय विधि साधनों की जांच की है और विधिक राय प्रदान की है। प्रभाग, अंतर आलिया ने रक्षा सहयोग, कृषि, रेलवे, सार्क, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, बाहरी अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह) और बहु-क्षेत्रीय तकनीकी के लिए बंगाल की खाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में संधियों, समझौतों, समझौता ज्ञापनों और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी/मादक पदार्थ; गोपनीयता पर भी समझौते; हाइड्रोलॉजिकल डेटा का बंटवारा; गैस और ऊर्जा; सांस्कृतिक सहयोग, ऑडियो विजुअल सहयोग, सड़क परिवहन, व्यापार और निवेश, विदेशों में लागू की जाने वाली परियोजनाओं, शिक्षा, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर द्विपक्षीय समझौते; जल संसाधन; जैव विविधता; सौर गठबंधन; ओजोन घटते पदार्थ; हाइड्रोग्राफी, ट्विनिंग/सिस्टर सिटी एग्रीमेंट और सीमा शुल्क सहयोग समझौते आदि पर अपने मत व्यक्त किए।

विधिक राय और विधिक शोध

विधिक और संधि प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय विधि और घरेलू विधिक मामलों जैसे संयुक्त राष्ट्र मामलों, आईसीजे मामलों, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार मुद्दों, स्थानीय कर्मचारियों के मामलों, मानवाधिकारों के मुद्दों, मानवीय

विधि से जुड़े विभिन्न विषय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक विधि और विधिक सहायता मामले, अंतरिक्ष और वायु विधि के मुद्दे, अदालती मामले, निविदा दस्तावेज आदि मामलों पर विधिक राय दी।

संधियों की सूची

भारत ने वर्ष 2019 के दौरान विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनेक बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियों/समझौतों पर हस्ताक्षर/पुष्टि की है। ऐसे समझौतों/संधियों की एक व्यापक सूची **अनुलग्नक-I** पर है। वर्ष 2019 के दौरान जारी अनुसमर्थन/परिग्रहण के साधनों की सूची **अनुलग्नक-II** पर है; और वर्ष 2019 के दौरान जारी पूर्ण शक्तियों के साधन की सूची **अनुलग्नक-III** पर है। यह देखा जा सकता है कि भारत ने 2019 के दौरान 200 से अधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर किए है।

राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड के विलेन्यूवे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए (14 सितंबर, 2019)

प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में गांधी @ 150 कार्यक्रम के अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए (24 सितंबर, 2019)

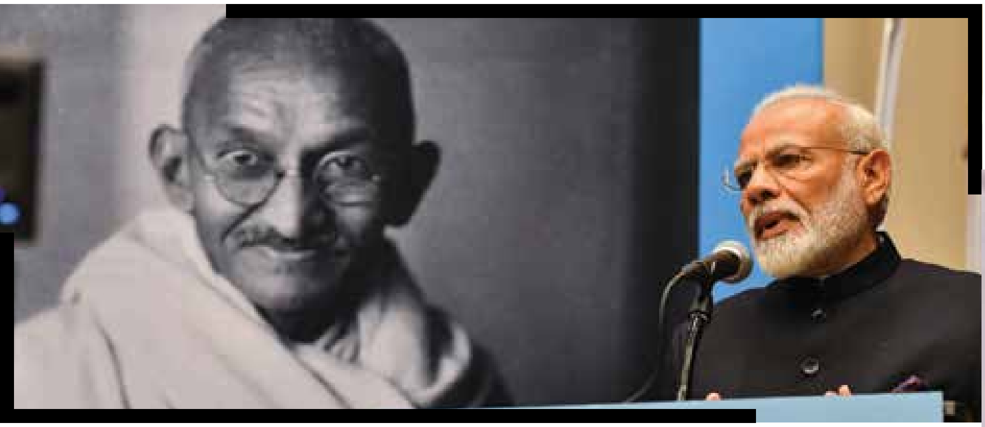

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा नई दिल्ली में पहली आईबीएसए गांधी-मंडेला मेमोरियल फ्रीडम व्याख्यान देते हुए (25 जनवरी, 2019)

स्पेन की अपनी यात्रा के दौरान कैनरी द्वीप पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण करते विदेश राज्य मंत्री (17 दिसंबर, 2019)

प्रधानमंत्री और मून जे-इन, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति सोल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए (21 फरवरी, 2019)

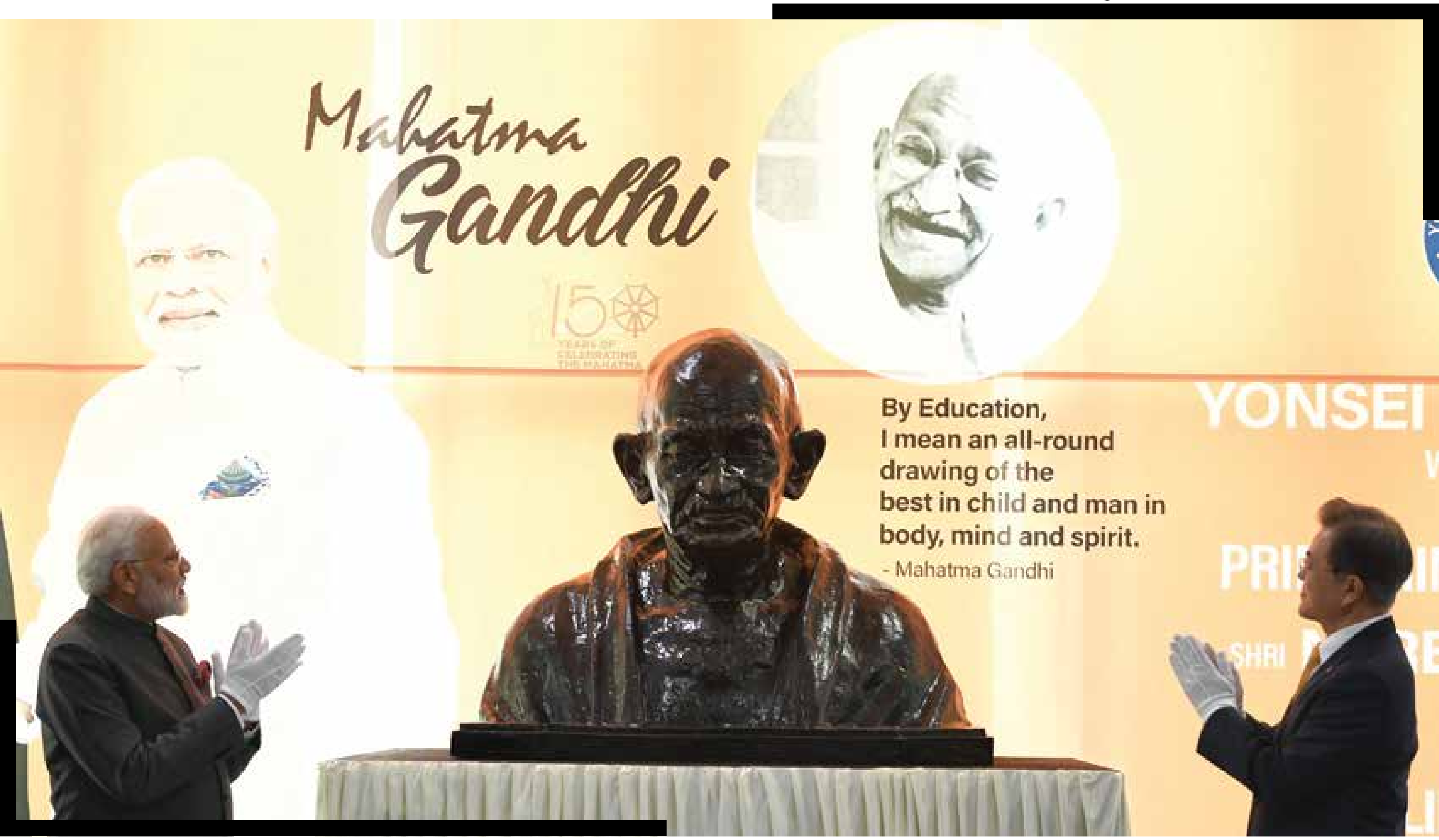

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा नई दिल्ली में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती की स्मृति में राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक में भाग लेते हुए (दिसंबर 19, 2019)

विदेश मंत्री ने सोफिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की (17 फरवरी, 2019)

17

नीति आयोजना और अनुसंधान
(सीमा प्रकोष्ठ और पुस्तकालय सहित)

नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग, मंत्रालय का केंद्रीय प्रभाग है, जो प्रमुख सम्मेलन पहलों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय और भारत-आधारित सामरिक समुदाय के साथ चर्चा और नियमित आधार पर मंत्रालय के लिए आंतरिक नीति विश्लेषण करता है। प्रभाग विशेष रूप से भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के समन्वय के साथ-साथ अत्याधुनिक पहलों में मंत्रालय के प्रयासों का नेतृत्व करता है। यह प्रभाग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले दो स्वायत्त निकायों आईसीडब्ल्यूए और आरआईएस से संबंधित मामलों का प्रशासी प्रभाग भी है। नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग, विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय और सीमा प्रकोष्ठ का प्रशासनिक प्रभारी भी है।

नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग, अपने अधिदेश के अनुरूप, भारत और विदेशों में, दोनों स्थानों पर प्रमुख चिंतक और शैक्षणिक संस्थानों की साझेदारी से प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन करता है। ये सम्मेलन उदीयमान प्रौद्योगिकियों से संबंधित भू-राजनीति, भू-अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के विषयों पर केंद्रित और एक बहु-हितधारक, पार-क्षेत्रीय बैठक के रूप में संरचित होते हैं, जो मंत्रियों और सरकार के उच्च-स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ नीति पेशेवरों; व्यवसाय और उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों और सामरिक समुदाय, मीडिया के सदस्यों और शिक्षाविदों को निर्णयकर्ताओं के रूप में संलिप्त करते हैं। नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग द्वारा जिन प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, उन विषयों की पूरी सूची संदर्भ के लिए संलग्न है।

रायसीना वार्ता का पांचवां सत्र 14-16 जनवरी, 2020 को “21 @ 20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी” विषय पर आयोजित किया गया था। यह अत्यंत सफल रहा,

प्रधान मंत्री नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2020 के उद्घाटन समारोह (14 जनवरी, 2010) में भाग लेते हुए

2019 के 93 से अधिक देशों के 600 वक्ताओं और प्रतिनिधियों की तुलना में 2020 की पुनरावृति में इसने 103 देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों को आकर्षित किया।

विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग 2020 में बातचीत करते हुए (15 जनवरी, 2020)

प्रभाग द्वारा 2019 में आयोजित अन्य प्रमुख सम्मेलनों में नई दिल्ली में, भारत-अमेरिका मंच (16-17 अगस्त 2019) का तीसरा सफल सत्र; हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित रखने के विषय पर मालदीव में हिंद महासागर सम्मेलन (3-4 सितंबर 2019) का चौथा सत्र: पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियां; और "द फ्यूचर ऑफ डाटा" (05-06 दिसंबर, 2019) विषय पर बेंगलुरु में आयोजित वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का तीसरा सत्र शामिल थे। एशिया और उदीयमान व्यापार प्रणाली विषय पर एक भू-आर्थिक सम्मेलन" वर्ष का अंतिम प्रमुख सम्मेलन है, जो फरवरी/मार्च 2020 के माह में पुणे में आयोजित किया जाने वाला है।

प्रभाग ने इन प्रमुख सम्मेलन पहलों के अलावा, ट्रैक 1.5 संवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में विदेश नीति के मुद्दों पर अकादमिक संगोष्ठी जैसे कई विशेष विषयगत सम्मेलन आयोजित किए। इन कार्यक्रमों की एक पूरी सूची संलग्न है। प्रभाग ने भारत के पड़ोस पर चिंतकों द्वारा की गई विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की।

नीति नियोजन संवाद

प्रभाग में अन्य देशों के विदेश मंत्रालयों में समकक्ष नीति नियोजन इकाइयों के साथ संलग्न होने की प्रणाली है। वर्ष 2019 में, नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग ने पेरिस शांति मंच के अवसर पर फ्रांस के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नीति नियोजन मंच में भाग लेने के अलावा रूस (नई दिल्ली), जर्मनी (बर्लिन) और इंडोनेशिया (जकार्ता) के साथ व्यापक नीति नियोजन संवाद आयोजित किया। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में, नई दिल्ली में अमेरिका के साथ एक नीति नियोजन संवाद आयोजित किया गया था और एक नीति नियोजन संवाद चीन के साथ बीजिंग में आयोजित किया जाएगा।

उभरती अंतर-मंत्रालयीय पहलें : सीडीआरआई

आपदा प्रतिरोधक बुनियादी संरचना गठबंधन, आपदा प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ज्ञान और क्षमता के साझाकरण के लिए एक वैश्विक मंच विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सरकारों और बहुपक्षीय बैंकों, क्षेत्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र जैसे अन्य हितधारकों की वैश्विक साझेदारी स्थापित करने के लिए भारत सरकार की एक अभिनव पहल है। सितंबर 2019 में, न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा के बाद से, हमारे अनुरोध पर गठबंधन के चार्टर के समर्थन के लिए पर्याप्त संख्या में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई हैं।

विदेश मंत्रालय में, नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग को आपदा प्रतिरोधक बुनियादी संरचना के लिए गठबंधन से संबंधित मामलों के लिए प्रमुख प्रभाग नामित किया गया है। वर्ष 2019 में, सीडीआरआई का चार्टर तैयार करने में नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग की प्रमुख भूमिका थी और इसे विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया, जिससे अंततः गठबंधन की स्थापना हुई। वर्ष 2020 में, सीडीआरआई की पहली प्रशासकीय परिषद् की बैठक के माध्यम से सीडीआरआई को औपचारिक रूप से अस्तित्व में लाया जाएगा, बैठक की संभावित तारीख 18 मार्च 2020 निर्धारित की गई है। नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग, नई दिल्ली (मार्च 2020) में डीआरआई पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन और फिजी (मई 2020 में) और बारबाडोस (जुलाई 2020) में सीडीआरआई पर आउटरीच सम्मेलन आयोजित करने में एनडीएमए की सहायता कर रहा है। नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग अन्य देशों के साथ बुनियादी संरचना संबंधी पहलों में शामिल होने के साथ-साथ ब्रिक्स और जी-20 जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के नीति एजेंडे को पेश करने के संदर्भ में एनआरडीएमए/सीडीआरआई को नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है।

गठबंधन 2020 में, अपनी शासी परिषद् की पहली बैठक के माध्यम से औपचारिक रूप से अस्तित्व में आएगा। इस बीच, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार (एनडीएमए) अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की पहल कर चुका है, जो डीआरआई पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और प्रशांत द्वीप राज्यों और छोटे कैरिबियन द्वीप राज्यों पर केंद्रित तकनीकी कार्यशालाएं और क्षेत्र-विशिष्ट कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से सीडीआरआई के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य के शुभारंभ की देखरेख करेगा।

प्रभाग के अन्य प्रशासनिक कार्य

आईसीडब्ल्यूए : प्रभाग आईसीडब्ल्यूए के लिए सहायता अनुदान के साथ-साथ आईसीडब्ल्यूए के शासन से संबंधित प्रशासनिक मामलों के प्रसत्र के लिए प्रशासनिक प्रभाग है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, आईसीडब्ल्यूए के लिए 15 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। संसद में आईसीडब्ल्यूए की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भी प्रभाग का ही है।

आरआईएस : प्रभाग आरआईएस के लिए सहायता अनुदान के साथ-साथ आरआईएस के प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक मामलों की देख-रेख करता है। आसियान इंडिया सेंटर के कामकाज को मजबूत करना, कार्यान्वयन के लिए लंबित मामलों में से एक है, जो प्रशासनिक रूप से आरआईएस के भीतर स्थित है। आरआईएस के अध्यक्ष को आरआईएस के उपनियमों में संशोधन करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआईसी के पास मौजूदा महानिदेशक के समकक्ष शक्तियों सहित एक स्वतंत्र महानिदेशक है और एआईसी के लिए आरआईएस बजट से अलग वित्तपोषण तंत्र स्थापित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, आरआईएस को 12 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। प्रभाग संसद में आरआईएस की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है।

पुस्तकालय एवं सीमा प्रकोष्ठ : विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय को प्रशासनिक रूप से एएस (नीति नियोजन और अनुसंधान) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय, दुर्लभ पुस्तकों, वर्तमान पुस्तकों और पत्रिकाओं की देखरेख के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और डेटा बेस की सदस्यता प्रदान करने का प्रभारी है।

सीमा प्रकोष्ठ को प्रशासनिक रूप से नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सीमा प्रकोष्ठ के कार्यों में भारतीय सर्वेक्षण और अन्य एजेंसियों द्वारा प्राप्त मानचित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पुनरीक्षण करना; अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संरेखण की जांच करना और क्षेत्रीय प्रभाग की अनापत्ति/टिप्पणियों के लिए उन्हें क्षेत्रीय प्रभाग को भेजना; सीमा-संबंधी मामलों पर क्षेत्रीय प्रभागों के साथ बातचीत करना; भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ सीमा से संबंधित कार्यों के लिए धन से संबंधित अनुरोधों को संकलित और संसाधित करना और उसके लिए अनुमोदन जारी करना; मानचित्रों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गलत चित्रण से संबंधित शिकायतों को संभालना शामिल है। वर्ष 2019 में, सीमा प्रकोष्ठ ने भारत-नेपाल, भारत-भूटान, भारत-म्यांमार और भारत-बांग्लादेश सीमाओं से संबंधित सीमा मामलों पर अनेक द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया।

18

आतंकवाद का मुकाबला

समूचे विश्व में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर आतंकवाद के मुद्दे का, वर्ष के दौरान हर स्तर पर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में प्रमुखता से उल्लेख हुआ। इस प्रकार की सभी चर्चा के दौरान, भारत ने विश्व स्तर पर आतंकवाद के खतरे का प्रतिकार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। आतंक के किसी भी कृत्य के लिए, किसी भी औचित्य को अस्वीकार करने, आतंक को धर्म से जोड़ने, आतंकवाद को कतई सहिष्णुता और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में सभी देशों को एकजुट होने की आवश्यकता के भारत के आह्वान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकार किया और यह द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों और विभिन्न देशों के साथ अन्य बैठकों के बाद और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय में जारी किए गए अनेक परिणाम दस्तावेजों से परिलक्षित होता है।

वर्ष के दौरान, भारत ने विभिन्न साझेदार देशों के साथ आतंकवाद से निपटने वाले संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी-सीटी) के माध्यम से संरचित परामर्श जारी रखा। भारत, वर्तमान में जेडब्ल्यूजी-सीटी के तंत्र के माध्यम से 24 राष्ट्रों और 3 बहुपक्षीय समूहों के वरिष्ठ वार्ताकारों के साथ कार्यरत है। वर्ष 2019 के दौरान, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और उजबेकिस्तान के साथ जेडब्ल्यूजी-सीटी के माध्यम से आतंकवाद प्रतिकार पर द्विपक्षीय परामर्श किया। भारत ने ब्रिक्स आतंकवाद निरोधक कार्यकारी समूह की बैठक में भी भाग लिया। जेडब्ल्यूजी-सीटी बैठकें, आतंकवाद विरोधी सहयोग जिनमें सीमा पार आतंकवाद, सूचनाओं के सहभाजन, सीमा-पार आंतकवाद सहित वैश्विक आंतकवाद, के बारे में अनुभव और आकलन, संगत प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रासंगिक निर्माण,

आतंकवाद और आतंक वित्तपोषण के विरूद्ध लड़ाई में बहुपक्षीय प्रयासों को सुदृढ़ करना, पारस्परिक विधिक सहायता मांग पर त्वरित कार्रवाई करना, एजेंसी से एजेंसी को सहयोग सुकर करना और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक समेकित अधिवेशन (सीसीआईटी) को शीघ्र अपनाने की महत्ता पर जोर देने का प्रावधान है।

भारत वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अग्रणी रहा है और उसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रमुख वैश्विक पहलों में भाग लिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर आतंकवादियों और चरमपंथी आख्यान के लिए सामरिक प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए नेताओं की वार्ता में भाग लिया। गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 7-8 नवंबर 2019 को आयोजित दूसरे 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने आतंकवाद, घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने और संजोने वाली सामग्री से साइबर स्पेस को हटाने के लिए क्राइस्ट चर्च के कार्रवाई करने के आहवान का समर्थन किया।

ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (जीसीटीएफ) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत नियमित रूप से इसकी बैठकों में भाग लेता है। भारत ने जीसीटीएफ समन्वय समिति की 16वीं बैठक में एक वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर भाग लिया और 23-25 सितंबर 2019 तक न्यूयॉर्क में आयोजित जीसीटीएफ मंत्रिस्तरीय की पूर्ण 10वीं बैठक में भाग लिया। भारत 2010 से वितीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का सदस्य भारत ने है। 2019-20 के दौरान, ऑरलैंडो और पेरिस में आयोजित एफएटीएफ पूर्ण बैठकों में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कैनबरा में आयोजित मनी लॉन्ड्रिंग (एपीजी) पर एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) की पूर्ण बैठकों और मॉस्को में आयोजित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवित्त पर यूरेशियन ग्रुप (ईएजी) की पूर्ण बैठकों में भी भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधियों ने शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (एससीओ-आरएटीएस) की बैठकों में भी नियमित रूप से भाग लिया। भारत ने 3-4 सितंबर 2019 को मिंस्क में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओटी) द्वारा आयोजित 'आतंकवाद का मुकाबला करने और नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग' पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। मास्को में 5-6 सितंबर 2019 को अवैध हथियारों की तस्करी का प्रतिकार करने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि ने न्यूयॉर्क में 20-21 नवंबर 2019 को आतंकवाद का प्रतिकार करने और हिंसक उग्रवाद को रोकने में दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने पर संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक केंद्र (यूएनसीसीटी) के विशेषज्ञों की बैठक में भी भाग लिया।

भारत ने नई दिल्ली में 11 जून 2019 को उग्रवाद का प्रतिकार करने पर बिम्सटेक उप-समूह की नई दिल्ली में हुई पहली बैठक और 21-22 नवंबर 2019 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की भागीदारी के साथ आतंकवाद निरोधक टेबल टॉप अभ्यास की मेजबानी की। इंटरनेट के आतंकी प्रयोग को रोकने के लिए ब्रिटेन के साथ एक गोलमेज बैठक का आयोजन 9 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में किया गया। "आईएसआईएस नेटवर्क की जांच" पर भारत-यूरोपीय संघ की आतंकवाद निरोधक कार्यशाला का 3-4 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजन किया गया था।

वर्ष के दौरान, भारत के प्रमुख आतंकवाद निरोधक बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, उज्बेकिस्तान आदि सहित अनेक देशों के विशेष बलों के साथ आंतकवाद प्रतिकार पर संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास किया। एनएसजी ने पड़ोसी देशों के अधिकारियों के लिए आंतकवाद के प्रतिकार के लिए क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए। अमेरिका की आतंकवाद निरोधक एजेंसियों के सहयोग से भारतीय एजेंसियों के लिए केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी - भोपाल, एनएसजी मानेसर और केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सीडीटीएस), हैदराबाद में क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

19

वैश्विक साइबर मुद्दे, ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी

ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग

ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, डिजिटल इंडिया के हितार्थ सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलों को अनुकूलित करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस अवधि के दौरान प्रभाग ने मंत्रालय में आईटी परिसंपत्तियों के आनुपातिक विकास की दिशा में काम किया।

ईजीएंडआईटी प्रभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारत सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समन्वय से ई-शासन अनुप्रयोगों के प्रणाली अध्ययन, विकास, परीक्षण और रखरखाव का कार्य किया। ईजीएंडआईटी प्रभाग ने मंत्रालय में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को विदेशों में सभी मिशनों/पोस्टों पर लागू करने के लिए कदम उठाए। *ई-क्रांति (डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का चौथा स्तंभ) की चार मिशन मोड परियोजनाएं अर्थात् ई-कार्यलय, ई-प्रापण, आप्रवासन, वीजा, विदेशियों पंजीकरण और*

ट्रैकिंग प्रणाली (आईवीएफआरटी) और पासपोर्ट सेवा परियोजनाएं (पीएसपी) विदेश मंत्रालय और मिशनों/पोसटों में चालू की गई थी।

प्रभाग ने डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों के अनुरूप कई ई-शासन उन्नयन परियोजनाओं की शुरुआत की जिसमें, *ई-राजनैतिक मंजूरी प्रणाली, एकीकृत मिशन लेखांकन प्रणाली (आईएमएएस), छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल, प्रवासी बच्चों के लिए कार्यक्रम, पूर्व-छात्र (ए2ए) आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रम में प्रवेश, भारत जानों कार्यक्रम, कैलाश मानसरोवर यात्रा, विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) पूर्व छात्र पोर्टल, प्रदर्शन मूल्यांकन निगरानी प्रणाली, राजनयिक पहचान पत्र पंजीकरण और जारी करने की प्रणाली, ई-सनाद शामिल हैं। आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन वेबसाइट, प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) वेबसाइट, विदेश ऐप (स्थिर, सम्मेलन कक्ष बुकिंग, फाइल प्रबंधन प्रणाली)*। ई-शासन परियोजनाओं के विकास के अलावा, ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग ने नवीनतम प्रौद्योगिकियों के आधार पर अनुप्रयोगों की निगरानी, प्रबंधन और समय-समय पर सुधार करने और साइबर की बढ़ती चुनौतियों को कम करने के लिए एक केंद्रित सुरक्षा दृष्टिकोण को लगातार आगे बढ़ाया है।

विदेश मंत्रालय डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट

इसके अलावा, ईजीएंडआईटी प्रभाग ने कई परियोजनाएं बनाई हैं जो मंत्रालय के आंतरिक कामकाज में सुधार करने में मदद करती हैं। ये परियोजनाएं संरचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर, कार्मिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर आदि की प्रकृति की हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं स्थापना प्रभाग के लिए ऑनलाइन माल-सूची प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा ब्यूरो के लिए कार्मिक प्रबंधन प्रणाली, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, सतर्कता दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, संपत्ति प्रबंधन वेबसाइट या प्रवासी हैं भारतीय केंद्र, वैश्विक संपदा प्रबंधन पोर्टल आदि।

विदेश मंत्री ने 14 अगस्त 2019 को *"विदेश मंत्रालय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड"* का शुभारंभ किया जिसे ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग की देखरेख में बनाया गया था। यह डैशबोर्ड तीन लक्षित क्षेत्रों पर बनाया गया है, जिसमें मंत्रालय के सभी प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों को कैप्चर किया गया है, जिसमें अनेक प्रमुख संकेतक है और पांच समूहों (प्रवासी कार्यक्रम, विकास साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, व्यापार और वाणिज्य और नागरिक सेवाएं) में है।

मंत्रालय में सुरक्षा ढांचे की समीक्षा की गई है और साइबर सुरक्षा की लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए नई पीढ़ी के नेटवर्किंग और खतरे प्रबंधन उपकरणों के साथ मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया गया है।

प्रभाग ने 2016 के बाद से, मंत्रालय के अधिकारियों के लिए *साइबर सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों* पर प्रतिवर्ष चार (4) ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है ताकि साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें साइबर खतरों का प्रबंधन और शमन करने में सक्षम बनाया जा सके।

ई-शासन सेवा परियोजनाओं को लागू करने के अलावा, ईजीएंडआईटी प्रभाग ने विदेशी राजनयिकों और अधिकारी प्रशिक्षुओं को साइबर सुरक्षा, सुरक्षित कंप्यूटिंग और विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) में अन्य संबंधित विषयों पर कई व्याख्यान और प्रशिक्षण भी दिए हैं।

ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग निम्नलिखित विकास कार्य का संचालन कर रहा है:

- विदेशों में भारतवंशियों को शामिल करना: एक पोर्टल और ऐप बनाया जा रहा है जिसमें विभिन्न हितों के प्रवासी भारतीय समुदाय (एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ) के साथ जुड़ने और विभिन्न नई और मौजूदा सरकारी योजनाओं से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। यह पोर्टल और ऐप किसी भी संकट प्रबंधन के दौरान सहायता भी करेगा और भारतवंशियों को मदद का हाथ भी बढ़ाएगा।
- विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के साथ संलग्नता : एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी होगी।
- एमजीसी सदस्य देशों की सुविधा के लिए भारत की पहल के आधार पर ईजीएंडआईटी प्रभाग द्वारा एक वेबसाइट बनाई जा रही है जो मेकांग गंगा सहयोग का अवलोकन प्रदान करेगी और विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में उपयोगी जानकारी देगी। इस वेबसाइट में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी शामिल करने और सदस्य देशों से संपर्क के एमजीसी बिंदुओं के लिंक भी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

वैश्विक साइबर मुद्दे

प्रभाग के कार्य

(i) विश्लेषणात्मक टिप्पणी और भारत के समग्र संबंध

भारत, वैश्विक साइबर नीति निर्धारण और अपनी साइबर सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए साइबर संवादों/ सेमिनारों और सम्मेलनों में अपने मत को व्यक्त करने के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत में, शासन के बहु-हितधारक मॉडल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, साइबर नीति को आकार देने और रणनीति बनाने के लिए निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के साथ कार्यरत है। इसके अलावा, इंटरनेट शासन में भारत की बड़ी भूमिका को मान्यता देते हुए, इसने हैदराबाद में नवंबर 2016 में आईसीएएनएन 57 के ऐतिहासिक पोस्ट-आईएनए ट्रांजिशन सेशन की मेजबानी की।

भारत संयुक्त राष्ट्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने पर कार्यकारी समूह के 25 सदस्यों में से एक के रूप में 2014-18 से कार्य कर रहा है जहां सूचना सोसायटी के लिए ट्युनिस एजेंडा के खंड 69-71 के अंतर्गत जनादेश को लागू करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ii) व्यक्तिगत देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध

साइबर कूटनीति प्रभाग ने, अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका), यूरोपीय संघ (ईयू), रूस, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम (यूके), कोरिया गणराज्य, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड और मिस्र सहित पंद्रह से अधिक देशों के साथ साइबर संवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने, 2016 में आईसीटी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-अमेरिका साइबर संबंध संरचना पर हस्ताक्षर किए और रूस के साथ आईसीटी के प्रयोग में सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2019 में भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साइबर संवाद किए।

(iii) साइबर मुद्दों में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

भारत ने, वर्ष 2015 में सूचना सोसायटी (डब्ल्यूआईएस) पर विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा में योगदान दिया। इस योगदान का उल्लेख यूएनजीए रिपोर्ट में किया गया है।

साइबर मुद्दों पर वैश्विक समुदाय के साथ व्यापक बातचीत करने के अपने प्रयासों में 2015 में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 16-17 अप्रैल 2015 को हेग में आयोजित वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन (जीसीसीएस) 2015 में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसके अलावा, भारत ने फरवरी 2016 में हेग में दूसरे टैलिन मैनुअल 2.0 पर परामर्श में भाग लिया।

भारत ने वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन के सह-अध्यक्षता की और नवंबर 2017 में वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन की मेजबानी और सूचना समाज के लिए वैश्विक सम्मेलन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए अगले कार्य समूह के सदस्य के रूप में भी काम किया।

विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2016-17 में आयोजित 5वें संयुक्त राष्ट्र सरकारी विशेषज्ञों समूह (यूएनजीजीई) चर्चा में चयनित पच्चीस देशों में से एक के रूप में भाग लिया। यूएनजीजीई को साइबर स्पेस, क्षमता निर्माण, विश्वास निर्माण उपायों, अंतर्राष्ट्रीय कानून, मौजूदा और उभरते खतरों आदि में राष्ट्रों के उत्तरदायी व्यवहार के मानदंडों पर चर्चा करने का जनादेश है। भारत, मौजूदा छठे यूएनजीईई में चयनित पच्चीस देशों में से एक है जो 2019-2021 की अवधि में साइबर स्पेस के विवादास्पद मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। छठें यूएनजीजीई का पहला सत्र न्यूयॉर्क में 9-13 दिसंबर, 2019 को आयोजित किया गया था।

भारत, साइबर मुद्दों पर आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस प्रकार की अंतिम बैठक जून, 2019 में सिंगापुर में हुई थी। भारत, ब्रिक्स, एससीओ आदि की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

भारत, ओपन एंडिड वर्किंग ग्रुप (ओईडब्ल्यूजी) की बैठकों में भी भाग ले रहा है जो 2019-20 की अवधि के दौरान साइबर से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। ओईडब्ल्यूजी की अंतिम महत्वपूर्ण बैठक 09-13 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी।

भारत, वैश्विक साइबर विशेषज्ञता मंच (जीएफसीई) का संस्थापक सदस्य बन गया जिसका शुभारंभ जीसीसीएस के दौरान किया गया था और यह जीएफसीई की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जीएफएसई की अदीस अबाबा, इथियोपिया में अक्तूबर, 2019 को हुई अंतिम बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि में भाग लिया था।

साइबर कूटनीति प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय साइबर मुद्दों से निपटने के अपने उद्देश्य के अनुरूप, वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय स्तरों के साथ-साथ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तर पर देशों के साथ जुड़ा रहा है। भारत, वैश्विक साइबर नीति निर्धारण और अपनी साइबर सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए साइबर संवादों/सम्मेलनों और सम्मेलनों

में अपने मत को व्यक्त करने के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत शासन के बहु-हितधारक मॉडल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, साइबर नीति को आकार देने और रणनीति बनाने के लिए निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के साथ कार्यरत है।

2. भारत ने वर्ष 2019 में अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साइबर संवाद किए। श्री उपेंदर सिंह रावत, संयुक्त सचिव (ईजीएंडआईटी एंड सीडी) विदेश मंत्रालय ने 20 जून 2019 को पेरिस में तृतीय इंडो-फ्रेंच साइबर वार्ता और 04 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में तृतीय भारत-ऑस्ट्रेलिया साइबर नीति वार्ता का नेतृत्व किया। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री राजिंदर खन्ना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका साइबर वार्ता में भाग लिया था।

3. विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2019-2021 की अवधि में आविरत छठे संयुक्त राष्ट्र सरकारी विशेषज्ञ समूह (यूएनजीजीई) में चयनित पच्चीस देशों में से एक के रूप में भाग लिया। छठे यूएनजीजीई का पहला सत्र न्यूयॉर्क में 9-13 दिसंबर, 2019 को आयोजित किया गया था। भारतीय विशेषज्ञ, ओपन एंडिड वर्किंग ग्रुप (ओईडब्ल्यूजी) की बैठकों में भी भाग ले रहा है जो 2019-20 की अवधि के दौरान साइबर से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। ओईडब्ल्यूजी की अंतिम महत्वपूर्ण बैठक 09-13 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी।

4. भारत ने साइबर मुद्दों पर आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठकों में भाग लिया है। इस प्रकार की पिछली बैठक सिंगापुर में 25-26 जून 2019 को हुई थी। आईसीटी के प्रयोग में सुरक्षा पर ब्रिक्स कार्यकारी समूह की पांचवीं बैठक ब्राजील के ब्रासीलिया में 21-22 अगस्त 2019 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर एससीओ विशेषज्ञों समूह की बैठक 12 नवंबर 2019 को मास्को में हुई थी। विदेश मंत्रालय ने साइबर नियम, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा पर 20-22 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में समर्थन प्रदान किया और भाग लिया।

5. भारत, वैश्विक साइबर विशेषज्ञता मंच (जीएफसीई) का संस्थापक सदस्य बन गया जिसका शुभारंभ जीसीसीएस के दौरान किया गया था और यह जीएफसीई की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जीएफएसई की अंतिम वार्षिक बैठक अदीस अबाबा, इथियोपिया में 8-10 अक्तूबर, 2019 को हुई। इसमें साइबर क्षमता निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु संरचना सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।

6. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पोंस टीम, (सीईआरटी-इन), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा 2019 में निम्नलिखित दो समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए :

सीईआरटी-आईएन और एस्टोनिया गणराज्य की इन्फार्मेशन सिस्टम अथार्टी के बीच एस्टोनिया में 21 अगस्त 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सीईआरटी-आईएन और दक्षिण कोरिया गणराज्य की कोरियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पोंस टीम एंड कोर्डिनेशन सेंटर (केआरसीईआरटी/सीसी) के बीच 28 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

20

कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

मंत्रालय का पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) प्रभाग, भारत और विदेशों में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है। पासपोर्ट जारी करना मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सबसे उल्लेखनीय सांविधिक और नागरिक केंद्रित सेवा के रूप में उभरी है। मंत्रालय, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन कर रहा है, ताकि प्रशिक्षित और प्रेरित कार्यबल द्वारा सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और प्रतिबद्धता के माध्यम से नागरिकों को समय पर पारदर्शी, अधिक सुलभ, विश्वसनीय और सुखद परिवेश में पासपोर्ट प्रदान किए जा सकें।

भारतीय पासपोर्ट (अन्य यात्रा दस्तावेजों जैसे राष्ट्रविहीन व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र, भारत लौटने वालों को आपातकालीन प्रमाणपत्र, पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र, आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में नियंत्रण रेखा यात्रा परमिट) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और इसके अखिल भारतीय नेटवर्क, सीपीवी प्रभाग (केवल राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट) और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इस नेटवर्क का सार्वजानिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) स्वरूप में 93 परपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और इन 36 पासपोर्ट कार्यालयों के विस्तारित शाखा के रूप में 424 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) (डाक विभाग के सहयोग से) को जोड़कर काफी विस्तार किया गया है। देश में पीएसके और पीओपीके सहित 31 दिसंबर, 2019 तक कार्यरत पासपोर्ट सेवा केंद्रों की कुल संख्या 517 थी। विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए 192 भारतीय मिशनों/पोस्ट पासपोर्ट और आपातकालीन प्रमाणपत्र प्रदान कर रहे हैं।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी)

मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ सार्वजानिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) स्वरूप में सेवा प्रदाता के रूप में लागू किए जा रहे पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी), एक मिशन मोड परियोजना ने 12 जून, 2012 को "लाइव" होने के बाद से अपने सफल संचालन के साढ़े सात वर्ष पूरे कर लिए हैं।

भारत और विदेशों में मिशन/पोस्ट में पासपोर्ट सेवाएं

मंत्रालय ने जनवरी से दिसंबर 2019 के दौरान, भारत में लगभग 1.18 करोड़ पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई की, जबकि 2018 के दौरान इसी अवधि में यह संख्या 1.12 करोड़ थी। 36 पासपोर्ट कार्यालयों, मुख्यालयों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के कार्यालय को पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने सहित 1,18,54,498 पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,17,04,641 पासपोर्ट और संबंधित दस्तावेज जारी किए गए। वर्ष 2019 में 1,11,15,315 पासपोर्ट और 5,89,326 पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेज जैसे पीसीसी आदि जारी किए गए थे।

विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों में 12,00,706 पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए और 11,38,363 लाख पासपोर्ट, आपातकालीन प्रमाणपत्र (ईसी) और पासपोर्ट से संबंधित अन्य विविध दस्तावेज जारी किए। इस प्रकार भारत सरकार ने 2019 के दौरान 1.28 करोड़ से अधिक पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेज जारी किए।

अर्जित राजस्व

भारत सरकार को वर्ष 2011-2012 में पासपोर्ट शुल्क से रुपये 1030.58 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। सभी पासपोर्ट सेवाओं से दिसम्बर 2019 तक कुल राजस्व अर्जन रुपये 1885.59 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2018 में इसी अवधि में यह धनराशि रुपये 1957.64 करोड़ थी।

पासपोर्ट सेवा वितरण में सुधार

पीएसपी के क्रियान्वयन और मंत्रालय द्वारा किए जा रहे सत्त प्रयासों के फलस्वरूप देश में पासपोर्ट सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सार्वजानिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) स्वरूप में समूचे देश में बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) द्वारा लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जा रही है। इस प्रणाली में आवेदकों को अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) नेट बैंकिंग/एसबीआई चालान के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होता है, मुलाकात के समय का निर्धारण करना होता है और फिर नामित पीएसके/पीओपीएसके पर जाना होता है। एक उपयोक्ता अनुकूल पोर्टल उपलब्ध है। जब कोई आवेदक पीएसके/पीओपीएसके में जाता है, तो आवेदकों की आवाजाही की निगरानी के लिए, सभी पीएसके/पीओपीएसके में प्रथम आए, प्रथम जाए के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पंक्ति प्रबंधन प्रणाली (ईक्यूएमएस) कार्यरत है। आवेदक स्वयं, पोर्टल और एसएमएस सेवा के माध्यम से अपने आवेदनों की स्थिति देख सकते

हैं। पासपोर्ट जारी करने की वर्तमान प्रणाली में, किसी भी स्तर पर, कोई मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होता और पूरी प्रक्रिया एकबारगी आगमन से ही पुनः नियत प्रक्रिया के अंतर्गत डिजिटल रूप में संचालित होती है।

एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप

एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, जिनमें पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, भुगतान करने और मुलाकात का समय-निर्धारण करने की अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष 2019 में एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप का उपयोग करके 3.94 लाख आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होगी। एमपासपोर्ट सेवा ऐप में अब निम्नलिखित अतिरिक्त पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध होंगी :

i. नया उपयोगकर्ता पंजीकरण

ii. पंजीकृत उपयोगकर्ता खाते में साइन इन

iii. पासपोर्ट और पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र का आवेदन करने के लिए आवेदन प्रपत्र फाइल करना

iv. पासपोर्ट सेवाओं के लिए भुगतान करना

v. मुलाकात का समय-निर्धारण करना

vi. आवेदन उपलब्धता की स्थिति

vii. दस्तावेज़ सलाहकार

vi। शुल्क कैलकुलेटर

भारत में कहीं से भी आवेदन करना

कोई भी आवेदक अब भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। यह पहल आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत वांछित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)/डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके), जहाँ वे आवेदन करना चाहते हैं, चाहे आवेदन पत्र में निर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में हो या नहीं, के चयन की सुविधा प्रदान करती है। पुलिस सत्यापन उस पुलिस स्टेशन द्वारा किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रपत्र में उल्लिखित पता है और पासपोर्ट का मुद्रण किया जाएगा और चयनित पासपोर्ट कार्यालय, आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लिखित पते पर पासपोर्ट भेजेगा। कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 9 लाख आवेदन प्रस्तुत किए गए थे।

मुलाकात का समय-निर्धारण

मंत्रालय प्रतिदिन लगभग 78,000 लोगों के लिए समय-निर्धारण करके उन्हें सूचित करता है, जिसमें 424 पीओपीएसके में लगभग 19,500 समय-निर्धारण शामिल हैं। पीएसके में पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन समय-निर्धारण प्राप्त करना सरल बनाया गया है। पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए, वर्तमान प्रावधान में, आवेदकों को समय-निर्धारण/पुनर्निर्धारण के लिए शीघ्रातिशीघ्र पांच उपलब्ध तिथियों (कार्य दिवसों) में से किसी भी दिन का चयन करने की सुविधा दी जाती है। इस प्रावधान से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सुगम और त्वरित हो गई है।

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, 355 पासपोर्ट केंद्रों में अगले कार्य दिवस में, 104 पासपोर्ट केंद्रों पर 2 से 7 कार्य दिवसों के बीच और 58 पासपोर्ट केंद्रों में 7 कार्य दिवसों के बाद मुलाकात का समय-निर्धारण उपलब्ध था।

आवेदनों की संख्या

प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के मामले में शीर्ष पांच राज्य महाराष्ट्र (13,56,903), केरल (12,89,709), तमिलनाडु (11,15,725), उत्तर प्रदेश (10,65,996) और पंजाब (10,35,439) थे, जो 31 दिसम्बर, 2019 तक पूरे देश से प्राप्त कुल आवेदनों (1,18,54,498) का लगभग आधा था।

वर्ष 2019 में प्राप्त आवेदनों की संख्या के मामले में 30 नवंबर, 2019 तक शीर्ष पांच पासपोर्ट कार्यालय थे, मुंबई (8,37,846), बेंगलुरु (7,95,980), चंडीगढ़ (7,15,153), अहमदाबाद (6,91,794) और दिल्ली (6,64,215)।

पासपोर्ट सेवा शिविर और मेले

पीएसके/पीओपीएसके से दूर स्थित लोगों की पासपोर्ट की मांग की पूर्ति करने और उन तक पहुंचने के लिए ऐसे स्थानों पर पासपोर्ट सेवा शिविरों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019 में ऐसे सात शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, नरोवाल, पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों को पासपोर्ट आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी। ऐसे शिविरों के दौरान 1655 पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

पासपोर्ट कार्यालयों ने मुलाकात के समय-निर्धारण में नागरिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए सप्ताहांत पासपोर्ट मेलों का भी आयोजन किया। दिसम्बर 2019 तक 159 पासपोर्ट मेलों का आयोजन किया गया जिनमे कुल 61,123 पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

छात्रों से जुड़ाव की पहल

“छात्रों से जुड़ाव” पहल का उद्देश्य अधिक छात्रों को समय पर अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है, और साथ ही, उन्हें ई-शासन पहलों के बारे में जागरूक करना है। इस पहल के हिस्से के रूप में, विदेश मंत्रालय और सेवा प्रदाता की टीमों ने संयुक्त रूप से भारत भर में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ प्रस्तुतियों और प्रश्नोंत्तर सत्रों के माध्यम से जागरूकता प्रसारित करना जारी रखा है। अनेक शिक्षण संस्थानों ने, युवा पीढ़ी को सुगम और सुविधाजनक तरीके से पासपोर्ट प्राप्त करने की इस पहल के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए स्वागत और प्रशंसा की है।

पुरस्कार और मान्यता

पासपोर्ट सेवा परियोजना की, मामला अध्ययन स्तर पर, सरकार में उच्चतम स्तर पर प्रशंसा हुई है, और इसने वर्ष 2019 में प्रदत्त निम्नलिखित सहित अनेक पुरस्कार जीते हैं:

(i) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 21 जून, 2019 को विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना को ट्रिपल आईएसओ प्रमाणन सहित प्रमाणित :

- आईएसओ 9001-2015- पीएसके संचालन- नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए
- आईएसओ/आईईसी- 20000-1:2011 - सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन प्रणाली
- आईएसओ/आईईसी - 27001: 2013 - सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

(ii) मंत्रालय को गर्वेनेंसनाउ से 6 नवंबर 2019 को "विशेष उपलब्धि - जी2सी सेवा पुरस्कार" श्रेणी में पासपोर्ट सेवा परियोजना के लिए "डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, 2019" प्राप्त हुआ।

पासपोर्ट सेवाओं की अभिगम्यता

1 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)

मंत्रालय ने आम जनता द्वारा पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें पासपोर्ट नियमों का सरलीकरण और पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं की सुपुर्दगी में लोगों तक अभिगम्यता शामिल है। सरकार का उद्देश्य पासपोर्ट की मांग को पूरा करना और पासपोर्ट कार्यालयों से दूर स्थित लोगों तक पहुंचना रहा है। इस दिशा में, मंत्रालय ने मई 2014 से 16 पीएसके खोले हैं जिसमें भारत के पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं। 31 दिसंबर, 2019 तक देश में 93 पीएसके कार्यरत हैं। इन 36 पासपोर्ट कार्यालयों की सूची अनुलग्नक -I में और 93 पीएसके की सूची अनुलग्नक -II में है।

2. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)

मंत्रालय ने डाक विभाग (डीओपी) के सहयोग से 24 जनवरी, 2017 को 'डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र' (पीओपीएसके) नामक देश में प्रधान डाकघरों (एचपीओ)/ डाकघर (पीओ) में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए एक अभिनव पहल की घोषणा की। मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2019 तक 424 पीओपीएसके चालू किए जिनकी सूची अनुलग्नक -III में है।

पीओपीएसके अन्य मौजूदा पीएसके की तरह काम कर रहे हैं। पीओपीएसके खुलने के बाद पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक, अपनी मुलाकात का समय-निर्धारण कर सकते हैं और फिर पीएसके के सामान, पासपोर्ट जारी करने से पहले औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए नामित पीओपीएसके में जा सकते हैं। फोटो, बॉयोमेट्रिक्स और सहायक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीओपीएसके में कैप्चर कर लिया जाएगा और आवेदक को पासपोर्ट जारी करने से पहले वहां पुनः जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इन पीओपीएसके में, 2019 तक, 21.82 लाख से ज्यादा पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

3. विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों का पीएसपी में एकीकरण

विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों को पीएसपी में एकीकृत करने की प्रक्रिया अक्तूबर 2018 में शुरू हुई थी और यह आज भी जारी है। इसका प्रयोजन विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के आवेदन प्राप्त करना और पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने और केंद्रीकृत पासपोर्ट जारी करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मंत्रालय ने 25 देशों जैसेकि ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कनाडा, चीन, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको, म्यांमार, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रूसी संघ, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, युगांडा, यूएई, ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम में 50 मिशनों और पोस्टों में पासपोर्ट जारी करने की प्रणालियों को पीएसपी में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। एकीकृत मिशनों/ पोस्टों की सूची अनुलग्नक -IV में है। ये मिशन/पोस्ट विदेशों में कुल पासपोर्ट के 90% से अधिक पासपोर्ट जारी करते हैं। मंत्रालय विदेशों में सभी भारतीय मिशनों/पोस्टों के एकीकरण को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने कि दिशा में काम कर रहा है।

पुलिस सत्यापन

पासपोर्ट समय पर जारी करने में पुलिस सत्यापन की अहम भूमिका होती है। मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन में तेजी लाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्र) में पुलिस विभागों के साथ मिलकर काम किया। पुलिस सत्यापन पूरा करने के लिए लगने वाले दिनों की संख्या के लिए अखिल भारतीय औसत अभी 16 दिन है और लगभग 87 प्रतिशत पुलिस सत्यापन 21 दिन की अपेक्षित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाता है।

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने लगातार पुलिस सत्यापन करने में लगने वाले समय को बनाए रखा है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश औसतन तीन दिन में और तेलंगाना और हरियाणा औसतन चार दिन में पुलिस सत्यापन पूरा करता है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु (पांच दिन), गुजरात (दस दिन) और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश (ग्यारह दिन) में पुलिस सत्यापन पूरा करते है। मंत्रालय के निरंतर और ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, वरीय जिला पुलिस मुख्यालय (डीपी मुख्यालय) सत्यापन मॉडल में परिवर्तित करने वाले जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब तक 764 पुलिस जिलों में से 741 ने नई व्यवस्था अपनाई है और जिला मॉडल पर काम कर रहे हैं।

मंत्रालय ने प्रारम्भ से अंत तक कागज रहित डिजिटल फ्लो के लिए एंड्रॉयड आधारित ***एमपासपोर्ट पुलिस*** ऐप लॉन्च किया है। ऐप में पासपोर्ट आवेदक के व्यक्तिगत विवरण और फोटोग्राफ को कैप्चर करने और संबंधित हितधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की क्षमता है। यह ऐप पुलिस द्वारा फील्ड सत्यापन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हुए आवेदक के निवास स्थान के स्थान को भी कैप्चर करेगा। 196 डीपीएचक्यू **एमपासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन** का उपयोग कर रहे हैं। पुलिस एप की स्थापना के बाद से 31 दिसंबर 2019 तक मोबाइल एप के माध्यम से कुल 63,37,649 आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

कार्यकरण के संवर्धन/न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन अधिप्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण

(1) वैश्विक पासपोर्ट सेवा परियोजना (जीपीएसपी) पर काम कर रहे विदेशों में पासपोर्ट पर भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा 'स्याही से हस्ताक्षर' को 'मुहर लगे हस्ताक्षर' से बदल दिया गया है। इससे पासपोर्ट पर मैन्युअल रूप से हस्ताक्षर करने में लगी जनशक्ति कम हो जाएगी।

(2) पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी, गैर-ईसीआर (इमीग्रेशन चेक आवश्यक नहीं) पासपोर्ट जारी करने के लिए मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संगठनों जैसेकि अंतर्राष्ट्रीय बेक्कालॉरेट प्रमाण पत्र या मिडल ईयर कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बेक्कालॉरेट डिप्लोमा, आईजीसीएसई/जीसीएसई प्रमाण पत्र, कैंब्रिज इंटरनेशनल सिस्टम्स (ओ एंड ए लेवल) के शैक्षिक प्रमाण पत्र स्वीकार करेंगे।

(3) आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने और ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने से संबंधित प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की गई है।

(4) पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र में संशोधन किया गया है, ताकि जिस विशिष्ट उद्देश्य और देश के लिए उसे पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता है, उसका उल्लेख आवेदन-पत्र में किया जा सके।

(5) तकाल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने के लिए नियमों/अपेक्षाओं में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :

i. आधार कार्ड, जो पहले तकाल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज था, अब वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है।
ii. पासपोर्ट जारी करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण के रूप में आधार पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
iii. तकाल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए अंतिम पासपोर्ट (केवल पुन जारी करने के लिए) और पैन कार्ड भी निर्धारित किया गया है।
iv. तकाल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए संलग्नक 'ड़' जमा करने समाप्त कर दिया गया है।
v. बिना किसी अतिरिक्त तकाल शुल्क का भुगतान किए, सामान्य योजना के अंतर्गत नए पासपोर्ट का आउट ऑफ टर्न जारी करना बंद कर दिया गया है।

पासपोर्ट सेवा दिवस और पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन 2019

मंत्रालय ने 24-25 जून 2019 को जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली में 7वे पासपोर्ट सेवा दिवस और वार्षिक पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया। यह 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधिनियमन की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विदेश मंत्री, डॉ. एस जयशंकर ने 24 जून, 2019 को इन उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता की। विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन की पूर्व संध्या पर पासपोर्ट अधिकारियों से बातचीत की।

विदेश मंत्री ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पासपोर्ट सेवाओं के विगत पांच वर्षों में "पासपोर्ट क्रांति" आयी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का जनादेश सुशासन और पारदर्शी, कुशल, समय पर, प्रभावी, विश्वसनीय, आश्वासित और उत्तरदायी जन सेवा सुपुर्दगी तंत्र सुनिश्चित करना था। वर्ष 2017 के बाद से अनेक डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने में विदेश मंत्रालय को सक्षम बनाने के लिए माननीय संचार मंत्री और डाक विभाग का धन्यवाद करते हुए, विदेश मंत्री ने कहा कि डाक विभाग के साथ साझेदारी वास्तव में नागरिक केंद्रित शासन में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अद्भुत उदाहरण थी।

विदेश मंत्री ने हमारे नागरिकों के हित के लिए पारदर्शी और कुशल पासपोर्ट सुपुर्दगी प्रणाली सुनिश्चित करने में प्रयासरत होने के लिए भारत और विदेशों में सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों को सम्मानित किया। विदेश मंत्री ने, नागरिकों को प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देते हुए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पासपोर्ट कार्यालयों, डाक विभाग के अधिकारियों और सेवा प्रदाता के कर्मियों को पासपोर्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किया। आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के पुलिस विभागों को भी त्वरित पुलिस अनापत्ति प्रदान करने के उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए पुरस्कार दिए गए।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

पासपोर्ट सेवा परियोजना के अंतर्गत, विदेश मंत्रालय ने एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली लागू की है जिसके अंतर्गत एक बहुभाषी राष्ट्रीय कॉल सेंटर जिसमें टोल फ्री नंबर (1800-258-1800), 17 भाषाओं में काम करना और 24X7 आधार पर, शिकायतों और नागरिक प्रतिक्रिया से निपटने सहित पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में एक केंद्रीय प्रणाली मंच पर काम करता है, जिसने वर्ष 2019 में प्रतिदिन लगभग 15,000 कॉलों को संभाला (जिनमें से 55% हिंदी में थे, 25% में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में 24%)। पासपोर्ट पोर्टल में एक ईमेल आधारित हेल्पडेस्क भी है, जहां सुझाव और शिकायतें लॉग इन की जा सकती हैं। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट आवेदन/शिकायत की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी भी कर सकते हैं।

संयुक्त सचिव (पीएसपी) और सीपीओ जिन्हे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मानिटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के लिए मंत्रालय के लोक शिकायत निदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, की देखरेख में एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) की स्थापना की गई है। यह आम जनता से टेलीफोन, ई-मेल और डाक और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से भी संदर्भ के रूप में प्राप्त शिकायतों का संव्यवहार करता है। इसके अलावा, सभी पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (https://pgportal.gov.in) सीपीजीआरएम वेबसाइट और पासपोर्ट शिकायतें अर्थात पासपोर्ट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) के माध्यम से जनता की शिकायतों का संव्यवहार करते हैं। आवेदकों की सहायता करने और शिकायतों तथा इन पर शीघ्र कार्रवाई करने के प्रयोजन से पीओ और पीएसके में सामरिक स्थानों पर सूचना एवं सुविधा काउंटर, लोक शिकायत प्रकोष्ठ, शिकायत/सुझाव बॉक्स और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। लोक शिकायत अधिकारी का नाम, पता और फोन नंबर पीओ/पीएसके में और पीओ की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। नागरिकों की किसी भी शिकायत की समयबद्ध सीमा में जांच और निराकरण करने के लिए सभी पीओ में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है।

सीपीग्राम के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2019 (2018 के लंबित 633 को शामिल करना) की अवधि के

दौरान 13,034 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 12,617 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इस अवधि के दौरान, 58,580 लोक शिकायत याचिकाएं (जिसमें ईमेल, पोस्ट, फैक्स, शिकायतों/जांच और सीपीग्राम से संबंधित 44,479 शामिल हैं, शिकायतों/जांच और सीपीग्राम से संबंधित हैं जिनमें से 58,101 शिकायतों का निपटारा किया गया है। उनके आवेदन पर नवीनतम स्थिति, आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशों के साथ, वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है, जो जनता द्वारा पहुँचा जा सकता है।

पासपोर्ट अदालतें

पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट आवेदकों की शिकायतों के निवारण के लिए नियमित रूप से पासपोर्ट अदालतें आयोजित करते हैं। ये अदालतें 2017 में आवेदकों के साथ सीधी बातचीत के माध्यम से कुछ 7000 पुराने और जटिल मामलों के निपटान में बहुत उपयोगी रही हैं।

हज यात्री

भारत की हज समिति (संसद के 2002 के अधिनियम संख्या 35 के अंतर्गत गठित) द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, केवल वैध पासपोर्ट धारक ही हज के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले वर्षों की तरह, सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे संभावित हज यात्रियों के पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई करने में उच्च प्राथमिकता दें और एक नोडल अधिकारी मनोनीत करने, सुविधा काउंटर खोल करके, ऐसे आवेदकों के लिए मुलाकात का समय-निर्धारण स्लॉट आरक्षित करने और ऐसे नागरिकों से प्राप्त अनुरोध/शिकायत याचिकाओं पर कार्रवाई करके अपेक्षित दस्तावेज, पुलिस सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं पूरा करने पर त्वरित पासपोर्ट जारी करना सुनिश्चित करें।

पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

विभिन्न राज्यों में पासपोर्ट कार्यालयों के साथ-साथ पीएसके और पीओपीएसके का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि उनकी प्रक्रियात्मक और परिचालन दक्षता में सुधार हो और उनकी नागरिक केंद्रित सेवाएं संतोषजनक तरीके से प्रदान करने की क्षमता हो। इस वर्ष में 5 पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है। पूरे भारत में चल रहे पासपोर्ट सेवा केंद्रों का भी नियमित आधार पर गैर तकनीकी सेवित स्तरीय समझौतों (एसएलए) के अंतर्गत निरीक्षण किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को जानकारी देने के लिए प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति की गई है। पीएसपी प्रभाग में भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सीपीओ) केवल मंत्रालय में पीएसपी प्रभाग से जुड़े मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

17 जून, 2014 से सभी पासपोर्ट कार्यालयों में एक सीपीआईओ ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। वर्ष 2019 के दौरान कुल 8,000 ऑनलाइन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,542 का निस्तारण किया गया।

अपील (पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत)

पीआईए के निर्णयों के विरूद्ध अपील, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रभावित व्यक्तियों को प्रदत्त सांविधिक अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी इन मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी हैं। दिसम्बर 2019 तक 14 अपील सत्र हुए, जिनमें 98 अपीलकर्ताओं की सुनवाई हुई।

यात्रा दस्तावेजों का विनिर्माण और निजीकरण

सभी भारतीय यात्रा दस्तावेजों का निर्माण भारत सुरक्षा प्रेस, नासिक द्वारा किया जाता है, जो भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के अंतर्गत एक इकाई है। भारतीय पासपोर्ट की समग्र गुणवत्ता, कार्यक्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। पासपोर्ट कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से नए डिजाइन और लेआउट में पासपोर्ट पुस्तिकाएं लागू की गई हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों, मुख्यालयों और विदेशों में चुनिंदा मिशनों/पोस्टों पर मशीन पठनीय पासपोर्ट प्रिंटर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मशीन-पठनीय पासपोर्ट जारी करते हैं।

विदेशों में 163 दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों और सहायक सचिव (पासपोर्ट) अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कार्यालय पोर्ट ब्लेयर के लिए, सुरक्षा सुविधा के साथ मशीन पठनीय पासपोर्ट (एमआरपी), पीएसपी प्रमाण, नई दिल्ली के केंद्रीय भारतीय पासपोर्ट मुद्रण प्रणाली (सीआईपीपीएस) में मुद्रित किए जाते हैं। सीआईपीपीएस ने दिसम्बर 2019 तक 1,50,094 पासपोर्ट मुद्रित किए (587 राजनयिक पासपोर्ट और 423 आधिकारिक पासपोर्ट सहित हैं)। वर्ष के दौरान, सीआईपीएस/ओसीआई सेल और विदेशों में मिशनों में 3,29,369 ओसीआई कार्ड भी व्यक्तिगत बनाए गए थे।

ई-पासपोर्ट

मशीन पठनीय यात्रा दस्तावेजों में बायोमेट्रिक डेटा को शामिल करने के लिए आईसीएओ की सिफारिशों के अनुसार, भारत ने अपने वर्तमान पासपोर्ट का उन्नयन करने और नागरिकों को उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर मुद्रण और बेहतर कागज वाले चिप सक्षम ई-पासपोर्ट जारी करने का भी निर्णय लिया है। सरकार ने भारत सुरक्षा प्रेस (आईएसपी) नासिक को ई-पासपोर्ट के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक संपर्क रहित इनले की खरीद के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) - अनुपालन इलेक्ट्रॉनिक संपर्क रहित इनले के साथ-साथ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो ई-पासपोर्ट के निर्माण के लिए आवश्यक है, की खरीद के लिए वैश्विक तीन चरण निविदा जारी

करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक द्वारा निविदा और क्रय प्रक्रिया के सफल समापन पर उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर मुद्रण और कागज की गुणवत्ता के साथ ई-पासपोर्ट का निर्माण प्रारंभ होगा।

आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएगें और चिप में संग्रहीत किए जाएगें। यदि कोई भी चिप के साथ छेड़छाड़ करता है, तो सिस्टम इसकी पहचान करने में सक्षम होगा जिसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट का प्रमाणीकरण स्वतः विफल हो जाएगा। जानकारी की अभिगम्यता इस प्रकार से सुरक्षित है कि पासपोर्ट के भौतिक रूप से प्राप्त किए बिना चिप को नहीं पढ़ा जा सकता। इस प्रकार ई-पासपोर्ट धोखाधड़ी और छेड़छाड़ के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के मशीन पठनीय यात्रा दस्तावेजों (एमआरटीडी) पर तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में कार्य किया और एमआरटीडी पर आईसीएओ दिशानिर्देशों को लागू कर रहा है। आईसीएओ ने केंद्रीय संदर्भ के रूप में दस्तावेज 9303 के संदर्भ में नागर विमानन सुरक्षा में सुधार करने के लिए आईसीएओं के सामरिक प्रयोजनों को समर्थित करने हेतु इलेक्ट्रोनिक यात्रा दस्तावेजों के लिए वैश्विक अंतर-प्रचालनीय ई-पासपोर्ट प्रमाणिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ईसीएओ पब्लिक की डायरेक्ट्री (पीकेडी) की स्थापना की गई। पीकेडी बोर्ड के सदस्य पीकेडी प्रतिभागी देशों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और आईसीएओ परिषद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत फरवरी 2009 में आईसीएओ पीकेडी का सदस्य बना।

भारत ने 29-30 अक्तूबर, 2019 को आइसलैंड के रेकजाविक में आयोजित आईसीएओ पब्लिक की डायरेक्ट्री (पीकेडी) बोर्ड की 26वीं बैठक में भाग लिया।

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) का गठन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1959 में हुआ था और इसके पक्ष में संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी हैं, जो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी और वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन नियम 1978 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष भी हैं।

1 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार सीपीओ में पदों की स्वीकृत संख्या 2741 और कार्यकारी कर्मचारी 1838 थे। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा परियोजना की 15 तकनीकी और 6 सहायक कर्मचारी पासपोर्ट सेवा परियोजना यूनिट की परियोजना प्रबंधन ईकाई का संचालन करते हैं। वर्तमान समूह 'क' स्तर पर 53 रिक्तियां, समूह 'ख' राजपत्रित स्तर पर 273 और समूह 'ख' और अराजपत्रित समूह ग' स्तर पर 577 रिक्तियां हैं। कुल रिक्तियां 903 हैं। समूह क स्तर पर रिक्तियां अन्य सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लेकर भरी जाती हैं। मंत्रालय ने स्वीकृत संख्या और कामकाज के बीच की खाई को पाटने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पासपोर्ट कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए खाली अराजपत्रित पदों के प्रति 370 डाटा एंट्री ऑपरेटरों और 60 कार्यालय सहायकों (एमटीएस) को भी तैनात किया है। कर्मचारी चयन आयोग को 31 कनिष्ठ अनुवादकों, 6 आशुलिपिकों (ग्रेड घ' और 24 कार्यालय सहायकों (एमटीएस) के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए कहा गया है।

मंत्रालय ने सीपीओ संवर्ग की पुनर्संरचना और विस्तार करके, सीपीओ कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि उपलब्ध रिक्त पदों को भर्ती नियमों की पात्रता अनुसार आवश्यक संशोधनों कर पदों को साथ तेजी से भरा जा सके। उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) आर्थिक रूप से पूर्व निर्धारित मानकों के प्रति व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए यह अनूठी योजना है। सीपीओ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता प्रदान करने और इस प्रकार देश के शासन में सुधार लाने में योगदान देने के उद्देश्य से पासपोर्ट सेवा पुरस्कारों की स्थापना की गई है। प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों के चयनित कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान सीपीओ में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की नियमित बैठकें हुई हैं। 1 जनवरी 2020 तक 17 सहायक पासपोर्ट अधिकारियों को उप पासपोर्ट अधिकारियों, वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक को सहायक अधीक्षक और 7 कनिष्ठ पासपोर्ट सहायकों को वरिष्ठ पासपोर्ट सहायकों के पद पर पदोन्नत करने के लिए मंजूरी दी गई है। अधीक्षक से वरिष्ठ अधीक्षक और कार्यालय सहायकों से कनिष्ठ पासपोर्ट सहायकों की विभागीय पदोन्नति स्थिति होने वाली है। उप पासपोर्ट अधिकारी से पासपोर्ट अधिकारी और वरिष्ठ अधीक्षक से सहायक पासपोर्ट अधिकारी की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नती प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किया गया है। सीपीओ के 31 कार्मिकों को विभिनन ग्रेड में एमएसीपी देने के लिए विचार किया गया। 31 में से 1 सहायक अधीक्षक, 1 आशुलिपिक, 5 वरिष्ठ पासपोर्ट सहायकों, 4 कनिष्ठ पासपोर्ट सहायकों और 4 कार्यालय सहायकों को एमएसीपी दिया गया है।

कैंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) द्वारा 2010 से 2019 तक 36 पासपोर्ट कार्यालयों, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 424 पीओपीएसके के नेटवर्क के माध्यम से संसाधित पासपोर्ट आवेदनों में शत प्रतिशत वृद्धि को देखते हुए कैडर के पुनर्गठन और समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई है। व्यय विभाग की कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू) द्वारा सीपीओ के प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं स्टाफिंग अध्ययन का प्रस्ताव नवंबर 2019 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।

सार्वजनिक अभिगम्यता

पीएसपी प्रभाग अपनी अभिगम्यता के विस्तार के हिस्से के रूप में, सेवा प्रदाता के सहयोग से पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी युक्त एक अर्द्ध वार्षिक बुलेटिन “पासपोर्ट पत्रिका” का प्रकाशन कर रहा है। अनेक पासपोर्ट कार्यालयों ने स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत भी की, जिसमें मीडिया को पासपोर्ट सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार के बारे में जानकारी दी गई।

विदेश मंत्री 7वें पासपोर्ट सेवा दिवस के समारोह पर जेएनबी, नई दिल्ली में 24 जून, 2019 को दीप प्रज्जवलित करते हुए

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, नर्मदा जिला, गुजरात में 14.09.2019 को राजपीपला मुख्य डाकघर में 'डाकघर पासपोर्ट सेवा' कैंद्र का उद्घाटन करते हुए।

विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, नेनमारा, पलक्कड़ जिला, केरल में 05.10.2019 को पीओपीओएसके का उद्घाटन करते हुए।

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (प्रभारी) श्री संतोष कुमार गंगवार, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और हरदोई जिलों में 11.10.2019 को पीओपीओएसके का उद्घाटन करते हुए।

विदेश मंत्री, जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली, में 24 जून, 2019 को 7 वें पासपोर्ट सेवा दिवस के उपलक्ष्य में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

विदेश मंत्री, डॉ. एस. जयशंकर 14.09.2019 को नर्मदा जिले, गुजरात में राजपीपला प्रधान डाकघर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए।

विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन 5.10.2019 को केरल के पलक्कड़ जिले के नेनमारा में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए।

वीज़ा

विदेश में मिशन/पोस्टों द्वारा वीजा जारी करना

विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टो ने 1 अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर, 2019 के दौरान, 20,91,282 नियमित वीजा जारी किए। नियमित वीजा के अलावा, उपरोक्त अवधि के दौरान 18,36,910 इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) जारी किए गए थे।

सीपीवी प्रभाग द्वारा वीजा जारी करना- सीपीवी प्रभाग को राजनयिकों और विदेशी मिशनों के अधिकारी को वीजा जारी करने/विस्तारित करने के साथ-साथ अन्य कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सीपीवी प्रभाग ने अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान विदेशी राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को 4018 वीजा जारी किए/उनकी अवधि बढ़ाई है।

इसी अवधि के दौरान, सीपीवी प्रभाग द्वारा भारत सरकार के अधिकारियों को हस्तांतरण और आधिकारिक व्यस्तताओं पर विदेश जा रहे 6120 वीजा नोट जारी किए गए हैं।

वीजा-आगमन पर

दक्षिण कोरिया के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा (वीओए) को मार्च 2016 में और अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित किया गया था। आगमन पर वीजा सुविधा 6 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से प्रवेश के लिए व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए अधिकतम 60 दिनों से अधिक नहीं अवधि के लिए उपरोक्त नागरिकों को दोहरा प्रवेश वीजा प्रदान करती है। नवंबर 2019 में, आगमन पर वीजा सुविधा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों को दी गई थी, जिन्होंने पहले कम से कम एक बार, भारत की यात्रा के लिए ई-वीजा/नियमित वीजा प्राप्त किया है।

ई-पर्यटक वीजा (ई-टीवी)

भारत सरकार ने 27 नवंबर 2014 को ई-वीजा योजना शुरू की थी। प्रारंभ में यह योजना 43 देशों के लिए ई-पर्यटक वीजा के लिए खुली थी और पांच नामित हवाई अड्डों के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी गई थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना को धीरे-धीरे उदार बनाया गया है और इसे दूसरे देशों में लागू किया गया है। वर्तमान में यह योजना 169 देशों पर लागू है। 28 भारतीय हवाई अड्डों और 5 भारतीय समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश/निकास की अनुमति है। इस योजना को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में लागू किया जा रहा है। मार्च 2019 में, ई-वीजा को व्यापार, चिकित्सा, सम्मेलन और चिकित्सा सहायक सहित अन्य वीजा श्रेणियों में बढ़ा दिया गया था। अगस्त 2019 में ई-वीजा व्यवस्था में और उदारीकरण किया गया है। ई-पर्यटक वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है और कम शुल्क पर तीन महीने की अवधि (30 दिनों के रहने के साथ) के ई-पर्यटक वीजा की नई श्रेणियां शुरू की गई हैं। ऑफ सीजन माह (अप्रैल-जून) में 3 महीने के ई-पर्यटक वीजा का शुल्क कर दिया है। सामान्य पेपर वीजा के संबंध में ई-वीजा की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है और 2019 में यह लगभग 46% है।

वीजा- छूट समझौते

भारत ने 114 देशों के साथ राजनयिक और/या सरकारी पासपोर्ट धारकों के संबंध में वीजा छूट समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 101 वर्तमान में चालू हैं जबकि शेष अनुसमर्थन के विभिन्न चरणों में हैं। इस अवधि के दौरान 7 देशों बेनिन, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, आइसलैंड, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, एंटीगुआ और बारबुडा और कोमोरोस के साथ वीजा छूट समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अगले 3 महीनों में लिकटेंस्टीन, ग्रेनाडा, सिएरा लियोन और अंगोला के साथ वीजा छूट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रत्यर्पण

विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) आतंकवाद, वित्तीय धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा

उपलब्ध कराने के लिए द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों के लिए विभिन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। सरकार की यह नीति है कि वह यथासंभव अधिक से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां करे ताकि भगोड़े अपराधी न्याय से न बच सकें।

विदेश मंत्रालय आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर समझौते के लिए बातचीत की भी सुविधा प्रदान करता है। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने आज की तारीख में 50 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था की गई है। भारत ने 28 अगस्त, 2019 से आर्मेनिया के साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था की थी। अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान, भारत को 15 प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त हुए, और संबंधित विदेशों को 24 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे हैं। वर्ष 2019 में छह भगोड़े अपराधियों को विदेशों ने भारत प्रत्यर्पित किया था और भारत ने तीन भगोड़े अपराधियों को विभिन्न विदेशों में प्रत्यर्पित किया था।

कांसुलर संवाद

विभिन्न देशों के साथ कांसुलर मामलों की व्यापक समीक्षा के लिए स्थापित तंत्र के हिस्से के रूप में, 2019 में ईरान, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, नाइजीरिया और रूस, कनाडा, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड के साथ कांसुलर संवाद आयोजित किए गए थे। इनमें से इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, नाइजीरिया और कनाडा के साथ पहली बार कॉन्सुलर वार्ता की गई। फिलहाल भारत के पास 24 देशों के साथ कॉन्सुलर वार्ता तंत्र है। *वाशिंगटन डीसी में 9 जनवरी, 2020 को अमेरिका के साथ कांसुलर वार्ता हुई थी। फरवरी 2020 में फ्रांस और इटली के साथ भी कॉन्स्लर वार्ता आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।*

कांसुलर मुद्दे

विदेशों में भारतीय मिशन/पद भारतीय नागरिकों को विभिन्न दस्तावेजों के साथ विभिन्न कांसुलर सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसेकि भारतीय नागरिकों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को भारत वापस भेजना, भारतीय नागरिकों के विवाह का पंजीकरण/सत्यनिष्ठा, विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों के लिए कांसुलर पहुंच, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को भारतीय अदालतों के सम्मन की तामील करना आदि। कांसुलर सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिकायतों और कांसुलर शिविरों में भाग लेने के लिए अनेक मिशनों/पोस्टों द्वारा खुले मंचों का भी आयोजन किया जाता है। खाड़ी देशों में जहां बड़ी संख्या में भारतीय कामगार हैं, हमारे मिशनों और पोस्टों पर विशेष सामुदायिक कल्याण विंग और श्रम विग हैं।

एपोस्टिल/साक्ष्यांकन

मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग में साक्ष्यांकन सेल विदेशों के देशों में व्यक्तिगत और वाणिज्यिक उपयोग के लिए व्यक्तियों के शैक्षिक, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए साक्ष्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्यात के साथ-साथ विदेशों में अन्य व्यावसायिक उद्यमों के लिए विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) द्वारा सत्यापित वाणिज्यिक दस्तावेजों की भी आवश्यकता है। प्रमाणीकरण दो प्रकार का है: सामान्य साक्ष्यांकन और एपोस्टिल प्रमाणन। एपोस्टिल प्रमाणन तब किया जाता है जब उन देशों में दस्तावेजों का उपयोग किया जाना है जो हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के सदस्य हैं। 2017 में लॉन्च होने के बाद से ई-सनाद पर 2,75,000 से अधिक दस्तावेजों पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई है- विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई एपोस्टिल/ साक्ष्यांकन के लिए ऑनलाइन पेपर रहित और संपर्क रहित सेवाएं। अप्रैल से नवंबर 2019 तक

एपोस्टिल/साक्ष्यांकित दस्तावेजों का ब्यौरा इस तरह है- (i) एपोस्टिल- 480552 (ii) साक्ष्यांकन - 410483 (iii) दस्तावेज ई-सनद - 156162 के माध्यम से एपोस्टिल/साक्ष्यांकित।

मदद-कांसुलर सेवा प्रबंधन प्रणाली :

विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) ने सरकार की 'सुशासन' और 'डिजिटल इंडिया' पहल के अनुपालन में, विदेशों में भारतीयों को मदद का हाथ बढ़ाने के लिए फरवरी 2015 में मदद नाम से एक वेब पोर्टल (ऑनलाइन कांसुलर सेवा प्रबंधन प्रणाली) शुरू की थी। विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और पोस्टों के साथ-साथ चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता में विदेश विदेश मंत्रालय की शाखा सचिवालय कांसुलर शिकायत पंजीकरण और समाधान के लिए इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। कई राज्यों ने एमएएडी नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं और अपने राज्य में लोगों को इस प्रकार के शिकायत निवारण मंच की उपलब्धता के बारे में जागरूक कर रहे हैं।

मदद ऑनलाइन पोर्टल के संचालन और कांसुली शिकायतों के समाधान ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से, अग्रेषित, ट्रैकिंग और उनके अंतिम समाधान तक में गुणात्मक में सुधार हुआ है। यह जनता द्वारा शिकायतों का प्रत्यक्ष पंजीकरण और उसके बाद पूरी शिकायत संचालन प्रक्रिया की प्रभावी ट्रैकिंग को सुकर करता है। मदद पोर्टल पर नवंबर 2019 तक 55,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 48000 शिकायतों का समाधान हो चुका है।

भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड योजना

भारत सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए अगस्त 2005 में ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड योजना शुरू की थी। ओसीआई कार्ड भारत आने के लिए आजीवन वीजा है। वर्ष 1999 में शुरू हुई तत्कालीन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) कार्ड योजना का 2015 में ओसीआई स्कीम में विलय हो गया था। अब तक 34 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अप्रैल से नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान जारी किए गए ओसीआई कार्डों की कुल संख्या 225522 है।

21

प्रवासी भारतीय मामलें

भारतीय कामगारों का कल्याण और संरक्षण

प्रभाग ने आवश्यक जागरूकता पैदा करने और प्रवासी कामगारों को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में संवेदनशील बनाने की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई की :

(i) प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास कार्यक्रम - जनवरी 2018 से शुरू हुए विदेश गमन पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) कार्यक्रम का उद्देश्य, प्रवासियों को जागरूक करने के लिए हमारे प्रवासी कामगारों के कौशल में गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपरा और स्थानीय नियमों और विनियमों के अनुरूप संवर्धन करना और सुरक्षित और विधिक प्रवास साधनों और उनके कल्याण और संरक्षण के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना है।

इस वर्ष में, विदेश जाने वाले प्रवासी कामगारों के अधिक पीडीओ प्रशिक्षण करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में, 13.1.2020 तक 21 केंद्रों में 79,500 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को पीओ प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन 21 केंद्रों में से वर्ष 2019 में भारत के विभिन्न राज्यों में 15 नए पीडोओ केंद्र खोले गए हैं। पीडीओटी केंद्रों की सूची इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	पीडीओटी केंद्र	एजेंसी	खोलने का वर्ष
1.	मुंबई (विदेश भवन)	एनएसडीसी सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदार बनाया	2018
2.	मुंबई (अंधेरी)		2018
3.	दिल्ली (मंदिर मार्ग)		2018
4.	दिल्ली (ओखला)		2018
5.	कोची		2018
6.	लखनऊ		2018
7.	गोरखपुर		2019
8.	चंडीगढ़		2019
9.	चेन्नई		2019
10.	जयपुर	आरएसएलडीसी (राजस्थान)	2019
11.	सीकर		2019
12.	नागौर		2019
13.	हैदराबाद	टीओएमसीओएम (तेलंगाना)	2019
14.	करीमनगर		2019
15.	निजामाबाद		2019
16.	दरभंगा	श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार	2019
17.	गया		2019
18.	मुजफ्फरपुर		2019
19.	पटना		2019
20.	विजयवाड़ा	ओएमसीएपी (आंध्र प्रदेश)	2019
21.	कडप्पा		2019

(ii) पीडीओ के लिए ई-मैनुअल और ई-हैंडबुक बनाना : इस वर्ष, मास्टर प्रशिक्षकों के लिए पीडीओ मैनुअल और एक मानकीकृत सामग्री सहित उत्प्रवासी श्रमिकों के लिए भारतीय उत्प्रवासन केंद्र (आईसीएम) के तवाधान में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मलयालम, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में ई-पुस्तकें तैयार की गई हैं। इन ई-पुस्तकों को व्यापक जन-प्रसार के लिए ई-माइग्रेट वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(iii) पीडीओटी और सुरक्षित और विधिक प्रवासन पर राज्यों के साथ अधिक सहयोग करना : राज्यों के साथ मंत्रालय के सहयोग के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया। इस संदर्भ में, मंत्रालय ने भारतीय

उत्प्रवासन केंद्र (आईसीएम) और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इनका उद्देश्य जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ ही प्रतिभागियों को प्रवासी कामगारों के लिए मंत्रालय के सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास और कल्याण और संरक्षण उपायों के लाभों के बारे में जागरूक करना है। टीओटी कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्यों की क्षमता निर्माण करना है ताकि वे उन प्रमुख जिलों में जमीनी स्तर पर पीडीओ कार्यक्रम आयोजित कर सकें जहां से अधिकांश कामगार विदेश जाते हैं।

राज्य सरकार के संबंधित विभागों के समन्वय से, मार्च 2017 से अब तक नौ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की बीस कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, अब तक इस प्रकार की कुल 5 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं :

क्रम संख्या	राज्य	शहर	भागीदार	सहभागी
1.	तमिलनाडु	चैन्नई	21-22 फ़रवरी 2019	आईसीएम, एनआरटी कमिश्नरेट
2.	केरल	तिरुवनंतपुरम	29-30 अगस्त 2019	नोरका विभाग
3.	तमिलनाडु	चैन्नई	25 सितम्बर 2019	एनआरटी कमिश्नरेट
4.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	4 अक्तूबर 2019	एनआरआई विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार
5.	दिल्ली	नई दिल्ली	24-25 अक्तूबर 2019	आईसीएम, एनएसडीसी

प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी

प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी हमारे जनसांख्यिकीय हित का उपयोग करने और हमारे छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों, व्यवसायों आदि के लिए गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 10 मार्च, 2018 को भारत गणराज्य सरकार और फ्रांसीसी गणराज्य सरकार के बीच प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस वर्ष, भारत-जर्मन प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते के प्रमुख कारकों पर आशय वक्तव्य को अंतिम रूप दिया गया है। इसका संदर्भ नई दिल्ली में 1 नवंबर, 2019 को आयोजित 5वें भारत-जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श (आईजीसी) के संयुक्त वक्तव्य के पैरा 57 में भी किया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि "नेता इस बात पर सहमत थे कि दोनों पक्ष आशय वक्तव्य के आधार पर समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से, दोनों सरकारों के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर चर्चा यथाशीघ्र पूरी की जाए''।

प्रवासन और गतिशीलता पर साझी कार्यसूची (सीएएमएम) और प्रवासन एवं गतिशीलता पर उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम) पर भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त घोषणा

भारत और यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के बीच, प्रवासन और गतिशीलता पर साझी कार्यसूची (सीएएमएम) पर संयुक्त घोषणापत्र पर 29 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। सीएएमएम काफी हद तक दोनों पक्षों के लिए प्रवासन और गतिशीलता के मुद्दे पर एक व्यापक और सशक्त दृष्टिकोण वाला दस्तावेज है। प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम) में कार्यान्वयन के लिए एक समग्र संचालन तंत्र का प्रावधान है। सीएएमएम पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद, अप्रैल 2017 में ब्रसेल्स में, एचएलडीएमएम की बैठक हुई थी, जिसने तकनीकी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया था। तदनुसार, प्रवासन और गतिशीलता के मुद्दे पर, पारस्परिक रूप से सहमत गतिविधियां शुरू करने के लिए एक तकनीकी सहायता परियोजना का शुभारंभ किया गया। सीएएमएम और एचएलडीएमएम प्रवासन और गतिशीलता से संबंधित मामलों पर भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय साझेदारी की महत्वपूर्ण विशेषता है।

प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम) की नई दिल्ली में 11 जुलाई, 2019 को हुई पांचवीं बैठक में दोनों पक्षों ने एचएलडीएमएम और प्रवासन और गतिशीलता पर साझी कार्यसूची (केएमएम) पर संयुक्त घोषणा के महत्व की पुष्टि की, जो दोनों पक्षों के लिए प्रवासन और गतिशीलता पर सहयोग के लिए संरचना और चल रही सहायता परियोजना के अंतर्गत ठोस उपायों के साथ सीएएमएम के प्रत्येक पहलू को चालू करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेगा।

इस वर्ष, परियोजना के अंतर्गत किए गए मुख्य कार्यकलापों में महाराष्ट्र के पुणे में प्रतिभा गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ संगोष्ठी (14-15 जून, 2019) शामिल है : भारत-यूरोपीय संघ के गलियारे में पेशेवरों, व्यवसायों और उद्यमियों के संबंध में तीन क्षेत्रों (आईटी उद्योग, ऑटोमोटिव उद्योग और स्टार्ट-अप) की गतिशीलता; प्रवासन शासन पर अच्छी प्रथाओं के सहभाजन पर नई दिल्ली में संगोष्ठी (10 जुलाई, 2019); इटली में भारतीयों के लिए एकीकरण पुस्तिका (अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी) और छात्र जांच सूची (यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए) भी जारी की गई।

श्रम और जनशक्ति से जुड़े मुद्दों पर सहयोग

भारत और डेनमार्क के बीच 2009 में श्रम गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और पहला जेडब्ल्यूजी 2010 में आयोजित किया गया था। संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक 4-5 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा कौशल योग्यता और प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता के माध्यम से समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए संभावनाएं तलाशने; डेनिश नियोक्ताओं और भारत सरकार के बीच बी 2 बी सहयोग भर्ती एजेंसियों और प्रशिक्षण भागीदारों को मान्यता प्रदान की गई; भारतीय व्यापार मंडलों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और डेनिश उद्योग और श्रम बाजार भागीदारों और संघों आदि के बीच सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई थी।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) और जॉर्डन के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग समझौते ज्ञापन/समझौते लागू हैं। इसके अलावा, जीसीसी देशों में घरेलू कामगारों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए मंत्रालय ने, सऊदी अरब के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती, कुवैत के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। भारत ने, क्षेत्रीय परामर्शदात्री प्रक्रियाओं में विशेष रूप से अबू धाबी वार्ता और कोलंबो प्रक्रिया में, भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

अबू धाबी वार्ता (एडीडी)

एडीडी की स्थापना 2008 में श्रम मूल और गंतव्य के एशियाई देशों के बीच बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी ताकि संविदात्मक श्रम गतिशीलता पर क्षेत्रीय सहयोग को सुगम बनाया जा सके, सर्वोत्तम अनुभवों को साझा किया जा सके और एक-दूसरे के अनुभव से सीखा जा सके। भारत, 2008 से एडीडी का सदस्य है।

राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने 16-17 अक्तूबर, 2019 को दुबई में आयोजित पांचवें मंत्रिस्तरीय परामर्श में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस मंत्रिस्तरीय परामर्श के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात के मानव संसाधन और उत्प्रवासन मंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के साथ राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने संयुक्त अरब अमीरात (एनबीटीसी समूह) के विदेशी नियोक्ता और रोजगार के लिए यूएई की यात्रा करने वाले 5 भारतीय कामगारों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया। उनके कौशल को दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों नामत: भारत में एनएसडीसी और यूएई में एडीक्यूसीसी ने भारत और यूएई के बीच कौशल योग्यता, मूल्यांकन के चल रहे सहयोग का प्रमाणन किया जो एडीडी के विषय क्षेत्रों के अंतर्गत एक पॉयलट परियोजना है।

एडीडी के पांचवें मंत्रिस्तरीय परामर्श के दौरान, राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने, संयुक्त अरब अमीरात के एमओएचआरई, यूएई की ऑनलाइन श्रम भर्ती प्रणाली के साथ भारत की ई-माइग्रेट प्रणाली के बीच चल रहे एकीकरण के बारे में एडीडी सदस्य देशों को भी अवगत कराया जिससे वास्तविक समय के आधार पर सूचना सहभाजन करना सुकर होगा और भर्ती प्रक्रियाओं में संयुक्त सरकार के निरीक्षण को सुदृढ़ करने में वृद्धि होगी। यह भी एडीडी के विषयगत क्षेत्रों में से एक पॉयलट परियोजना है।

भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ)

वर्ष 2009 में स्थापित आईसीडब्ल्यूएफ का उद्देश्य सर्वाधिक योग्य मामलों में संकट और आपातकाल के समय में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना है। आईसीडब्ल्यूएफ का विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और पोस्टों में विस्तार किया गया है। 1 सितंबर, 2017 के आईसीडब्ल्यूएफ दिशानिर्देशों में संशोधन से विदेशों में भारतीय नागरिकों के सहायता के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने में विदेशों में भारतीय मिशनों और केंद्रों को अधिक लचीला बनाया गया है।

इस वर्ष के दौरान, आईसीडब्ल्यूएफ का प्रभावी ढंग से उपयोग विदेशों में संकट की स्थिति में भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने में किया गया था जिसमें आपातकालीन चिकित्सा सहायता, फंसे हुए भारतीयों को हवाई मार्ग की सुविधा, कानूनी सहायता,

भोजन और आवास, वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रही भारतीय महिलाओं को सहायता और पार्थिव शरीर को भारत लाने में सहायता करना शामिल है। इसकी स्थापना के बाद से, आईसीडब्ल्यूएफ के 145,000 से अधिक लाभार्थी हैं। वर्ष 2014 से अब तक, लगभग 100,000 भारतीय नागरिक आईसीडब्ल्यूएफ से लाभान्वित हुए हैं।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) ईसीआर देशों में उत्प्रवासन जाँच अनिवार्य (ईसीआर) श्रेणी के अंतर्गत विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए अनिवार्य बीमा योजना है जिसमें क्रमश: दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए रुपए 275 और रुपये 375 क्रमश: के बीमा प्रीमियम पर, दुर्घटना मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये का कवर बीमा मिलता है। इस योजना को संबंधित हितधारकों के परामर्श से 1 अगस्त, 2017 को व्यापक रूप से नया रूप दिया गया और इसे प्रवासी कामगारों के लिए सरल और अधिक लाभप्रद बनाया गया था और इसका उद्देश्य दावों का शीघ्र निपटान करना है।

ईसीआर श्रेणी के श्रमिकों को जनवरी से दिसम्बर 2019 के दौरान 3,68,000 से अधिक पीबीबीवाई नीतियां जारी की गई थीं।

भारतीय उत्प्रवासन केंद्र (आईसीएम)

भारतीय उत्प्रवासन केंद्र (आईसीएम) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से जुड़े सभी मामलों पर मंत्रालय का शोध विचारक मंच है। आईसीएम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, राज्य सरकारों के सहयोग से सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया। आईसीएम ने सभी पीडीओ कार्यक्रमों पर स्वयं को एक संसाधन केंद्र के रूप में तैयार किया है और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विदेश गमन-पूर्व अभिविन्यास पर प्रवासी कामगारों और हैंडबुक मैनुअल बनाए गए है।

इस वर्ष, भारत-यूरोपीय संघ सीएएमएम परियोजना के अंतर्गत आईसीएम ने आईएलओ के सहयोग से प्रतिभा, गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ संगोष्ठी (पुणे, महाराष्ट्र में 14-15 जून, 2019) का आयोजन किया, भारत-यूरोपीय संघ के गलियारे में पेशेवरों, व्यवसायियों और उद्यमियों के संबंध में तीन क्षेत्रों (आईटी उद्योग; ऑटोमोटिव उद्योग और स्टार्ट-अप) की गतिशीलता पर केंद्रीत थी और प्रवासन शासन पर अच्छी प्रथाओं के सहभाजन पर नई दिल्ली में संगोष्ठी (10 जुलाई, 2019) के साथ सीएएमएम के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। आईसीएम ने 14-15 नवंबर, 2019 को आईएलओ और आईसीएमपीडी के साथ समन्वय में नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में यूरोपीय उच्च शिक्षा आभासी मेले (ईएचईवीएफ-2019) का श्रवण सत्र भी आयोजित किया। आईसीएम ने प्रवासी कामगारों के लिए प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास पर व्यापक मैनुअल की ई-पुस्तकें और विदेश गमन-पूर्व अभिविन्यास पर हैंडबुक भी तैयार की है। ई-पुस्तकें, ई-माइग्रेट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं।

भारत से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग विदेशी रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाते हैं। विगत कुछ वर्षों में, भारत से उत्प्रवासी कामगारों का प्रमुख बहिर्गमन खाड़ी देशों में हुआ है। खाड़ी देशों सहित मध्य पूर्व में जाने वाले अधिकांश प्रवासी अर्ध-कुशल और अकुशल कामगार हैं और उनमें से अधिकांश अस्थायी प्रवासी हैं जो अपने संविदात्मक रोजगार की अवधि समाप्त होने के बाद भारत लौटते हैं। उत्प्रवासन जांच अनिवार्य

(ईसीआर) पासपोर्ट धारकों को 18 नामित ईसीआर देशों में रोजगार के लिए विदेश जाते समय उत्प्रवासन अनुमति की आवश्यकता होती है।

तीन नए पीओई कार्यालय खोलना - मंत्रालय के सौ दिनों/एक वर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत बंगलुरू, गुवाहाटी और पटना में तीन उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) कार्यालय खोलने की योजना थी। पटना और बेंगलुरु में उत्प्रवासी संरक्षक के पद के लिए दो अधिकारी चयनित किए गए और उन्होंने कार्यालयों में अपना कार्यभार संभाल लिया हैं।

उत्प्रवासन का रुझान

वर्ष 2019 (30.11.2019) के दौरान, 3.34 लाख कामगार उत्प्रवासन मंज़ूरी प्राप्त करने के बाद भारत से गए थे। चालू वर्ष के दौरान, प्रमुख ईसीआर देशों में उत्प्रवासन के लिए दी गई उत्प्रवास मंज़ूरियों की, देशवार संख्या नीचे तालिका में दी गई है :-

ई-माइग्रेट करने वाले कामगार (लाखों में)

क्रम सं.	देशों का नाम	वर्ष-2019 (30.11.2019)
1	सऊदी अरब	1.43
2	यूएई	0.72
3	कुवैत	0.42
4	कतर	0.28
5	ओमान	0.26
6	बहरीन	0.09
7	मलेशिया	0.10
8	अन्य	0.04
	कुल	**3.34**

उत्प्रवास करने वाले कामगारों के राज्यों क्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना राज्य प्रमुख राज्य थे। वर्ष 2019 (30-11-2019) के दौरान, इन राज्यों से उत्प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे पाई चार्ट में दर्शाई गई है :

प्रवासी भारतीय दिवस 2020

प्रवासी भारतीय दिवस 2020 का आयोजन 9 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में किया गया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रहमण्यम जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने समारोह में भाग लिया। विदेश मंत्री ने अपने मुख्य भाषण के बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पर्थ, सिंगापुर, कुआलालंपुर, दोहा, पोर्ट लुई, लंदन, पैरामारिबो और न्यूयॉर्क में भारतवंशियों के साथ बातचीत की।

12वां गोवा जानों कार्यक्रम

12वां गोवा जानों कार्यक्रम का आयोजन 4-18 जनवरी 2020 को किया गया। गोआ सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और ब्रिटेन के सात गोआ प्रवासी युवाओं ने भाग लिया।

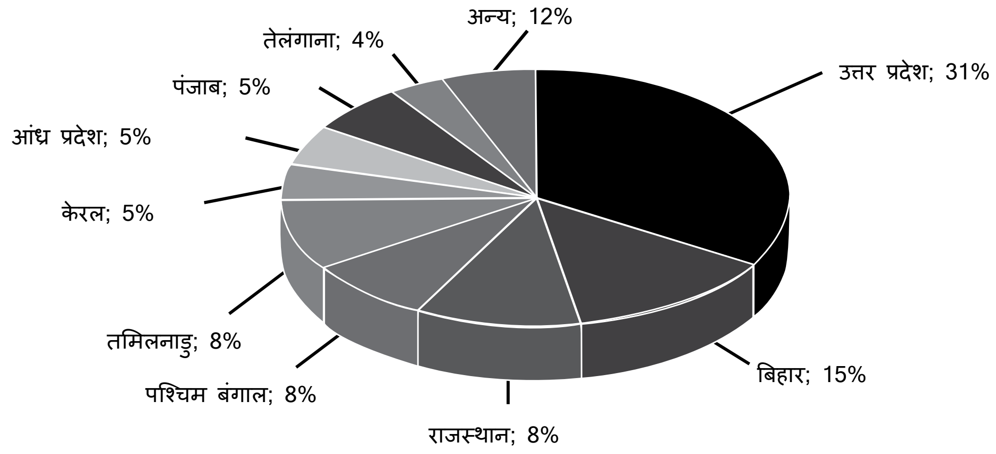
अन्य; 12%
तेलंगाना; 4%
उत्तर प्रदेश; 31%
पंजाब; 5%
आंध्र प्रदेश; 5%
केरल; 5%
तमिलनाडु; 8%
पश्चिम बंगाल; 8%
बिहार; 15%
राजस्थान; 8%

22

प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल प्रभाग में सात अनुभाग हैं अर्थात् प्रोटोकॉल-1, प्रोटोकॉल-2, प्रोटोकॉल-3, प्रोटोकॉल (हैदराबाद हाउस), प्रोटोकॉल स्पेशल, प्रोटोकॉल (आतिथ्य और लेखा) और सरकारी आतिथ्य संगठन (जीएचओ) हैं।

प्रोटोकॉल-1 अनुभाग - उप प्रमुख प्रोटोकॉल (शिष्टाचार) के अधीन यह अनुभाग राष्ट्राध्यक्षों/सरकारों के अध्यक्षों/ उप-राष्ट्रपतियों और विदेश मंत्रियों की आवक यात्राओं, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जावक यात्राओं, सत्कार (विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक मध्याहन भोज, रात्रिभोज और स्वागत) और शिष्टाचार कार्यों, विमानपत्तन के पास, शिष्टाचार और आरक्षित लाउंज तक पहुंचने आदि कार्यों की देखरेख करता है।

प्रोटोकॉल-II और **प्रोटोकॉल विशेष** अनुभाग दोनों- उपप्रमुख प्रोटोकॉल (विशेषाधिकार) के अधीन ये अनुभाग, भारत के बाहर स्थित राजनयिक मिशनों के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का संव्यवहार करते हैं, जैसेकि दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में विदेशी प्रतिनिधियों के संबंध में राजनयिक/आधिकारिक पहचान पत्र जारी करना; लाभप्रद नियोजन के लिए करार को अंतिम रूप देना और तपश्चात्, भारत में राजनयिक मिशनों और भारत में कांसुली पोस्टों के सदस्यों के परिवार सदस्यों के लिए लाभप्रद नियोजन की मंजूरी के आवेदनों पर कार्रवाई करना; भारतीय विश्वविद्यालयों में पंजीकरण के लिए विदेशी राजनयिकों को अनुमति प्रदान करना; भारत में विदेशी प्रतिनिधियों और उनके निवास-स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था करना; संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करना, पारस्परिकता के सिद्धांत पर कर छूट से संबंधित मुद्दों, भारत में राजनयिकों/अधिकारियों और राजनयिक मिशनों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी न्यायालय सम्मन को अग्रेषित करना और मोटर वाहनों के क्रय /पंजीकरण/विक्रय और सीमा शुल्क मुक्त आयात के

आवेदनों पर कार्रवाई करने आदि कार्यों की देखरेख करते हैं।

प्रोटोकॉल-III - इस अनुभाग के कार्य क्षेत्र में मिशनों के प्रमुखों को उनके प्रथम आगमन और अंतिम प्रस्थान तक प्रोटोकॉल सुविधाएं प्रदान करना; राष्ट्रपति भवन में प्रत्यय (क्रेडेंशियल) समारोह की व्यवस्था करना, जहां आगंतुक मिशनों के प्रमुख राष्ट्रपति जी को अपने प्रत्यय प्रलेख सुपुर्द करते हैं; गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, संसद के संयुक्त सत्र, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह, योग दिवस आदि के दौरान मिशनों और राजनयिकों के प्रमुखों (जहां भी लागू हो) को सुविधा प्रदान करना; भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/पोस्टों के संबंध में प्रतिवर्ष पारस्परिकता के अधीन विमानपत्तन में स्थाई प्रवेश पास प्रदान करने संबंधी कार्रवाई करना; जिसका निर्धारण विदेशों में हमारे सभी मिशनों/पोस्टों से जानकारी प्राप्त करने और छानबीन करने के बाद किया जाता है; नए महावाणिज्य दूतावास, उप उच्चायोगों, व्यापार कार्यालयों, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करने संबंधी कार्रवाई करना; विदेशों के मानद कांसुल, महावाणिज्यदूत, उप उच्चायोगों (राष्ट्रमंडल देशों के लिए पोस्टों के प्रमुख) की नियुक्ति करना और उसके बाद मान्यता-पत्र/राजपत्रित अधिसूचना तैयार करना; विदेशी मिशन परिसरों में पृथ्वी उपग्रह स्टेशनों की स्थापना के अनुरोध संबंधी कार्रवाई करना; विदेशों द्वारा भारतीय अधिकारियों को दिए गए पुरस्कारों के बारे में अनुमोदन संबंधी कार्रवाई करना; विदेशी राजनयिक मिशनों में रक्षा अताशे और रक्षा कर्मियों की नियुक्ति; विदेशी राजनयिक मिशनों में नए राजनयिक या आधिकारिक पदों के सृजन के अनुमोदन संबंधी कार्रवाई करना; भारत में विदेशी मिशनों द्वारा मनाए जाने वाले विदेशों के राष्ट्रीय दिवसों के लिए मुख्य अतिथि की व्यवस्था करना और कार्यक्रम स्थल पर प्रोटोकॉल दिशानिर्देश बनाए रखना व सुनिश्चित करना; वीवीआईपी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री) के संदेश राष्ट्राध्यक्षों और विदेशों की सरकारों के प्रमुखों को भेजना; विदेशी सरकारों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों के संदेश, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और भारत सरकार के अधिकारियों को अग्रेषित करना; विदेशी राजनयिक मिशनों और भारतीय स्थानीय कर्मचारियों के बीच भुगतान विवादों से संबंधित अदालती मामलों पर कार्रवाई करना और एचओएम/एचओपी द्वारा शिष्टाचार अनुरोधों पर कार्रवाई करना शामिल है।

प्रोटोकॉल आवास अनुभाग, सीपीडब्ल्यूडी के बागवानी, सिविल और विद्युत विंग के सहयोग से हैदराबाद हाउस के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसमें विद्युत/सिविल/बागवानी के मरम्मत और अनुरक्षण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, यह अनुभाग, प्रशासनिक, प्रबंधन और परिचालन व्यय के लिए आईटीडीसी को भुगतान संबंधी कार्रवाई करता है; दिल्ली में सभी राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में भूमि की खरीद/बिक्री/आवंटन, निर्मित संपत्ति, पट्टे आदि से संबंधित मामले जिनमें भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकारों के साथ संचार करना, पट्टा विलेख आदि पर हस्ताक्षर करना; दिल्ली और अन्य राज्यों में भू-स्वामियों और राजनयिक मिशनों के बीच विवाद/अदालती मामलों; एयरफोर्स स्टेशन, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाओं (एमईएस) और सीपीडब्ल्यूडी की सहायता से पालम में वीवीआईपी स्वागतकक्ष का प्रचालन और राजनयिक मिशनों की एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, एमटीएनएल आदि सेवाओं के संबंध में सहायता करना शामिल है। इसके अलावा, विगत कुछ वर्षों से, यह अनुभाग द्वारका नई दिल्ली में बनने वाले द्वितीय राजनयिक एन्क्लेव की परियोजना पर विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय भी कर रहा है।

वर्ष 2019 में, प्रोटोकॉल-1 अनुभाग ने राष्ट्राध्यक्षों, उप राष्ट्रपति, सरकार के प्रमुख और विदेश मंत्री के स्तर पर 100 आवक-जावक यात्राओं का संचालन किया (18 दिसंबर, 2019 तक)।

प्रोटोकॉल-1 अनुभाग ने जनवरी 2019 में रायसीना वार्ता में 6 विदेश मंत्रियों की भागीदारी, मई 2019 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 8 एचएएस/

एचओजी की भागीदारी और दिसंबर 2019 में ग्यारहवीं दिल्ली वार्ता में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी का समन्वय किया।

इसके अलावा, प्रोटोकॉल-1 अनुभाग ने 320 सत्कार समारोहों (31 दिसंबर, 2019 तक) को संभाला और विमानपत्तन के पास, लाउंज (सत्कार और आरक्षित) और तलाशी से छूट के लिए प्रति सप्ताह औसतन 180 अनुरोध सुकर किए।

प्रोटोकॉल-1 अनुभाग

वर्गीकरण और यात्राओं की संख्या

यात्रा शीर्ष	संख्या
राष्ट्राध्यक्षों/सरकारों के प्रमुखों की राजकीय यात्राएं	10
राष्ट्राध्यक्षों/सरकारों के प्रमुखों/उप-राष्ट्रपति और समकक्ष की राजकीय कार्यकारी यात्राएं	16
राष्ट्राध्यक्षों/सरकारों के प्रमुखों/उप-राष्ट्रपति और समकक्ष की निजी/मार्गस्थ यात्राएं	4
विदेश मंत्री और समकक्ष की आधिकारिक यात्राएं	26
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं	20
विदेश मंत्री की विदेश यात्राएं	26
कुल	**102**

यात्राओं का कैलेंडर

राष्ट्राध्यक्षों/सरकारों के प्रमुखों की राजकीय यात्राएं

क्रम संख्या	देश	दिनांक
1.	नॉर्वे के प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा	07-09 जनवरी, 2019
2.	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	25-26 जनवरी, 2019
3.	अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	17-19 फरवरी, 2019
4.	सऊदी अरब साम्राज्य के क्राउन प्रिंस की राजकीय यात्रा	19-20 फरवरी, 2019
5.	जाम्बिया के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	20-22 अगस्त, 2019
6.	मंगोलिया के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	19-23 सितम्बर, 2019
7.	नीदरलैंड साम्राज्य के महामहिम राजा विलियम-अलेक्जेंडर और महामहिम रानी मैक्सिमा की राजकीय यात्रा	13-18 अक्तूबर, 2019

क्रम संख्या	देश	दिनांक
8.	जर्मन चांसलर की राजकीय यात्रा	31 अक्तूबर - 02 नवम्बर, 2019
9.	श्रीलंका के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	28-30 नवम्बर, 2019
10.	स्वीडन के राजा और रानी की राजकीय यात्रा	01-06 दिसम्बर, 2019

सरकार के प्रमुख/महत्वपूर्ण/उप राष्ट्रपति और समकक्ष द्वारा आधिकारिक यात्राएं

क्रम संख्या	देश	दिनांक
1.	मॉरीशस गणराज्य के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा	20-28 जनवरी, 2019
2.	मोनाको के एचएसएच की आधिकारिक यात्रा	04-10 फरवरी, 2019
3.	घाना के उपराष्ट्रपति (सीआईआई - एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव) की आधिकारिक यात्रा	16-20 मार्च, 2019
4.	गिनी के प्रधानमंत्री (सीआईआई- एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव)	16-27 मार्च, 2019
5-12.	**प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह** बांग्लादेश के राष्ट्रपति किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति म्यांमार के राष्ट्रपति मॉरीशस के प्रधानमंत्री भूटान के प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री थाईलैंड के विशेष दूत	29 मई - 1 जून, 2019
13.	सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा	08-11 सितम्बर, 2019
14.	बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा	03-06 अक्तूबर, 2019
15.	बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कोलकाता की आधिकारिक यात्रा	22 नवम्बर, 2019
16.	पुर्तगाल के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा	19-20 दिसम्बर, 2019

राष्ट्राध्यक्षों/सरकार के प्रमुखों/उप राष्ट्रपति और समकक्ष की निजी यात्राएं

क्रम संख्या	देश	दिनांक
1.	जिम्बाब्वे के उप राष्ट्रपति की निजी यात्रा	19 मई - 09 जून, 2019
2.	युगांडा के राष्ट्रपति की मार्गस्थ यात्रा	23-24 जून, 2019
3.	श्रीलंका के प्रधानमंत्री की निजी यात्रा	26-27 जुलाई, 2019
4.	भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री की मार्गस्थ यात्रा	26-28 जुलाई, 2019

स्वागतकक्ष

राष्ट्राध्यक्षों/सरकार के प्रमुखों/उप राष्ट्रपति और समकक्ष की निजी यात्राएं

क्रम संख्या	देश	दिनांक
1-6.	रायसीना संवाद ईरान इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जापान के विदेश मंत्री स्पेन के विदेश मंत्री नेपाल के विदेश मंत्री	07-09 जनवरी, 2019
7.	किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री	27-31 जनवरी, 2019
8.	अल्जीरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य के विदेश मंत्री	30 जनवरी - 01 फरवरी, 2019
9.	ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री	25-27 फरवरी, 2019
10.	केन्या के विदेश मंत्री	04-06 मार्च, 2019
11.	गाम्बिया के विदेश मंत्री	07-12 मार्च, 2019
12.	ईरान के विदेश मंत्री	13-15 मई, 2019
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव	25-27 जून, 2019
14.	संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री की यात्रा	08-09 जुलाई, 2019
15.	संयुक्त राष्ट्र पीआर की यात्रा	18-24 अगस्त, 2019
16.	संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष की यात्रा	01-05 सितम्बर, 2019
17.	थाईलैंड के विदेश मंत्री की यात्रा	09-11 अक्तूबर, 2019

क्रम संख्या	देश	दिनांक
18.	निकारागुआ के विदेश मंत्री की यात्रा	27-29 अक्तूबर, 2019
19.	फिनलैंड के विदेश मंत्री की यात्रा	04-07 नवम्बर, 2019
20.	भूटान के विदेश मंत्री की यात्रा	17-23 नवम्बर, 2019
21.	बुल्गारिया के आर्थिक और जनसांख्यिकीय नीति उप प्रधानमंत्री की यात्रा	19-22 नवम्बर, 2019
22.	जापान के विदेश मंत्री की यात्रा	30 नवम्बर, 2019
23.	गिनी गणराज्य के विदेश मंत्री की यात्रा	02-05 दिसम्बर, 2019
24.	मालदीव के विदेश मंत्री	10-14 दिसम्बर, 2019
25.	**XIवीं दिल्ली वार्ता और आईओआरए VI** इंडोनेशिया के विदेश मंत्री	December 12-13, 2019

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं

क्रम संख्या	देश	दिनांक
राष्ट्रपति		
1.	क्रोएशिया, बोलीविया और चिली	25 मार्च -04 अप्रैल, 2019
2.	बेनिन, गाम्बिया, गिनी	28 जुलाई - अगस्त 03, 2019
3.	आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया	09-18 सितम्बर, 2019
4.	फिलीपींस और जापान	17-23 अक्तूबर, 2019
उपराष्ट्रपति		
5.	पैराग्वे और कोस्टा रिका	04-11 मार्च, 2019
6.	वियतनाम	09-12 मई, 2019
7.	लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया	17-22 अगस्त, 2019
8.	कोमोरोस और सिएरा लियोन	10-14 अक्तूबर, 2019
9.	अज़रबैजान	24-26 अक्तूबर, 2019

क्रम संख्या	देश	दिनांक
प्रधानमंत्री		
10.	कोरिया गणराज्य	21-22 फरवरी, 2019
11.	मालदीव और श्रीलंका	08-09 जून, 2019
12.	बिम्स्टेक (किर्गिज गणराज्य)	13-14 जून, 2019
13.	ओसाका (जापान)	27-29 जून, 2019
14.	भूटान	17-18 अगस्त, 2019
15.	फ्रांस, बहरीन और यूएई	22-27 अगस्त, 2019
16.	व्लादिवोस्तोक, रूस	04-05 सितम्बर, 2019
17.	संयुक्त राज्य अमरीका	21-28 सितम्बर, 2019
18.	सऊदी अरब	28-29 अक्तूबर, 2019
19.	थाईलैंड	02-04 नवम्बर, 2019
20.	ब्राजील	12-15 नवम्बर, 2019

विदेश मंत्री की विदेश यात्राएं

क्रम संख्या	देश	दिनांक
1.	समरकंद, उज्बेकिस्तान	12-13 जनवरी, 2019
2.	बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन	16-19 फरवरी, 2019
3.	वुज़ेन, चीन	27 फरवरी, 2019
4.	अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात	28 फरवरी -मार्च 01, 2019
5.	मालदीव	17-18 मार्च, 2019
6.	किर्गिस्तान	21-22 मई, 2019
7.	थिम्पू, भूटान	07-08 जून, 2019
8.	दुशांबे, ताजिकिस्तान	14-16 जून, 2019
9.	ओसाका, जापान	27-29 जून, 2019
10.	लंदन, इंग्लैंड	09-11 जुलाई, 2019

क्रम संख्या	देश	दिनांक
11.	बैंकॉक, थाईलैंड	31 जुलाई - अगस्त 03, 2019
12.	बीजिंग, चीन	11-13 अगस्त, 2019
13.	ढाका, बांग्लादेश	20 अगस्त, 2019
14.	काठमांडू, नेपाल	21-22 अगस्त, 2019
15.	बुडापेस्ट (हंगरी), मॉस्को (रूस), वारसॉ (पोलैंड), ब्रसेल्स (बेल्जियम)	25-31 अगस्त, 2019
16.	माले (मालदीव), जकार्ता (इंडोनेशिया), सिंगापुर	03-10 सितम्बर, 2019
17.	हेलसिंकी (फिनलैंड), ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन (अमेरिका)	19 सितम्बर 04 अक्तूबर, 2019
18.	बाकू, अजरबेजान	23-26 अक्तूबर, 2019
19.	बैंकॉक, थाईलैंड	02-04 नवम्बर, 2019
20.	बेलग्रेड (सर्बिया), एम्स्टर्डम (नीदरलैंड) और पेरिस (फ्रांस)	07-12 नवम्बर, 2019
21.	अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात	15-17 नवम्बर, 2019
22.	कोलंबो, श्रीलंका	19-20 नवम्बर, 2019
23.	नागॉया, जापान	22-24 नवम्बर, 2019
24.	रोम, इटली	06-08 दिसम्बर, 2019
25.	संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ईरान, ओमान	17-25 दिसम्बर, 2019
26	टोक्यो, जापान	28 दिसम्बर, 2019 -04 जनवरी, 2020

प्रोटोकॉल आवास अनुभाग

द्वारका राजनयिक एन्क्लेव- प्रस्तावित द्वितीय डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, द्वारका में कुछ जमीन के लिए चल रहे मामले का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निपटान कर दिया है और जिसका निर्णय 9 दिसंबर 2019 को दिया जाएगा। प्रस्तावित द्वितीय राजनयिक एन्क्लेव में आवंटन के लिए कुल 85 एकड़ जमीन उपलब्ध है। नई दिल्ली में भूमि चाहने वाले विदेशी मिशनों को अपनी यथार्थवादी आवश्यकता और संभावित भूमि उपयोग भेजने के लिए एक नोट वर्बल जारी किया गया है।

एयरफोर्स स्टेशन, पालम- नए और पुनर्निर्मित वीवीआईपी स्वागतालय दोनों पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। वायु सेना इन दोनों स्वागतालयों का रखरखाव

और आंतरिक देखभाल कर रही है और इसके खर्चे विदेश मंत्री वहन करता है। वीवीआईपी स्वागतालय में इंटरनेट सेवाओं के लिए ओएफसी केबल बिछाने का काम एमटीएनएल कर रहा है।

हैदराबाद हाउस- हैदराबाद हाउस के क्लोजर अवधि-2019 के दौरान किए जाने वाले कार्यों को सीपीडब्ल्यूडी के सिविल, विद्युत और बागवानी विंग द्वारा मरम्मत और रखरखाव कार्य पूरे कर लिए गए है।

दूतावासों के मुद्दे- मिशनों के सिविक मामलों को स्थानीय एजेंसियों जैसेकि एनडीएमसी, डीडीए, एमसीडी, जल बोर्ड, एमटीएनएल, बिजली बोर्ड आदि के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाया गया था और अधिकांश मुद्दों का समाधान हो गया है। जिम्बाब्वे, गैबन, स्पेन, कोटे डी आइवर और अन्य मिशनों के उनके किराए के परिसर के मालिकों के साथ मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है।

प्रोटोकॉल II अनुभाग

जीएसटी लागू करने से राजनयिक समुदाय का प्रभाव- भारत विदेशी दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सबसे बड़े मेजबानों में से एक है। भारत जैसे विशाल देश में वैट, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, विलासिता कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत करना एक दुष्कर कार्य था। प्रोटोकॉल प्रभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बदलाव से भारत में स्थित राजनयिक मिशन न्यूनतम प्रभावित हों। अन्य विक्रेताओं के विपरीत, पूरे भारत में किए गए लेनदेन के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत मिशन को एक एकल यूआईन जारी किया और राजनयिक मिशनों के लिए नई कर प्रणाली के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए अनेक कार्यशालाएं भी आयोजित की गई।

ऑनलाइन पहचान-पत्र आवेदन प्रणाली का शुभारंभ - संवर्धित सुरक्षा विशेषताओं वाले राजनयिक/सरकारी पहचान-पत्र के मुद्रण के लिए नया ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल हाल ही में 01 अप्रैल, 2019 को शुरू किया गया था। नए ऐप की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(i) नई दिल्ली स्थित राजनयिक मिशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राजनयिक/आधिकारिक पहचान-पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(ii) उन्हें अपने आवेदन की स्थिति के बारे में वास्तविक जानकारी मिलेगी।

(iii) प्लास्टिक पहचान-पत्र संवर्धित सुरक्षा विशेषताओं सहित हाई-एंड प्रिंटर पर मुद्रित किए जाएगें।

प्रोटोकॉल-III अनुभाग

विदेशी मिशनों प्रमुखों द्वारा 1 जनवरी, 2019 से प्रस्तुत प्रत्यय प्रलेख

क्रम संख्या	देश	राजदूत/उच्चायुक्त का नाम	प्रत्यय प्रलेख प्रस्तुत करने की तिथि
1	इजराइल	महामहिम डॉ रॉन मालका	10.01.2019
2	माली	महामहिम श्री सेकोउ कासे	10.01.2019
3	बेलारूस	महामहिम श्री आंद्रेई रझेस्स्की	10.01.2019

क्रम संख्या	देश	राजदूत/उच्चायुक्त का नाम	प्रत्यय प्रलेख प्रस्तुत करने की तिथि
4	लाओ-पीडीआर	महामहिम बाउंनेम चौंगहोम	10.01.2019
5	नाइजर	महामहिम श्री एडो लेको	10.01.2019
6	नामीबिया	महामहिम श्री गेब्रियल पैंदुरनी सिनिम्बो	08.02.2019
7	मालदीव	महामहिम सुश्री आइसथ मोहम्मद दीदी	08.02.2019
8	तुर्कमेनिस्तान	महामहिम श्री शालर गेल्डियानारोव	08.02.2019
9	चिली	महामहिम श्री जुआन रोलान्डो एंगुलो मोनसल्वे	13.03.2019
10	बुल्गारिया	महामहिम श्रीमती एलिनोरा दिमित्रोव	13.03.2019
11	किर्गिज गणराज्य	महामहिम श्री असिन इसाव	13.03.2019
12	नेपाल	महामहिम श्री निलोम्बर आचार्य	13.03.2019
13	सेशेल्स	महामहिम श्री थॉमस सेल्बी पिल्लै	13.03.2019
14	मोंटेनेग्रो	महामहिम श्री जोरान जानकोविक	13.03.2019
15	वेनेजुएला	महामहिम श्रीमती कोरोमोटो गोडोय काल्डेरॉन	20.05.2019
16	पापुआ न्यू गिनी	महामहिम श्री पाउलियस कोर्नी, ओबे	20.05.2019
17	जर्मनी	महामहिम श्री वाल्टर जोहान्स लिंडनर	21.05.2019
18	कोलंबिया	महामहिम श्री अलवारो सैंडओवल बर्नल	21.05.2019
19	पेरू	महामहिम श्री कार्लोस राफेल पोलो कास्टानेडा	21.05.2019
20	इथियोपिया	महामहिम डॉ (श्रीमती) तिज्मिता मुलुगेटा यीमम	25.06.2019
21	ताजिकिस्तान	महामहिम श्री रहीमजोदा सुल्टन	25.06.2019
22	फिलीपींस	महामहिम श्री रेमन एस बागट्सिंग, जूनियर फिलीपीन	25.06.2019
23	निकारागुआ	महामहिम श्री रोनाल्डो कोरोनेल किंलोच	25.06.2019
24	दक्षिण अफ्रीका	महामहिम श्री जोएल सिबुसिसो नडेबेले	28.08.2019
25	चीन	महामहिम श्री सन वेडोंग	28.08.2019

क्रम संख्या	देश	राजदूत/उच्चायुक्त का नाम	प्रत्यय प्रलेख प्रस्तुत करने की तिथि
26	सोमालिया	महामहिम श्रीमती फडूमा अब्दुल्ला मोहमुद	28.08.2019
27	ग्रीस	महामहिम श्री डायोनिसियोस कीवेटोस	28.08.2019
28	एस्टोनिया	महामहिम सुश्री कातिन किवी	25.09.2019
29	कोस्टा रिका	महामहिम श्री क्लाउडियो एंसोरेना मोंटेरो	25.09.2019
30	जिम्बाब्वे	महामहिम श्री गॉडफ्रे चिपरे	25.09.2019
31	आयरलैंड	महामहिम श्री ब्रेंडर वार्ड	25.09.2019
32	नॉर्वे	महामहिम श्री हंस जैकब फ्रीडेनलुंड	25.09.2019
33	डेनमार्क	महामहिम श्री फ्रेडी स्वेण	03.10.2019
34	फ्रांस	महामहिम श्री एमन्यूएल लीनाइन	03.10.2019
35	यूरोपीय संघ	महामहिम श्री उगो अस्तुतो	03.10.2019
36	मेक्सिको	महामहिम श्री फेडरिको साल्वे लोफे	03.10.2019
37	कजाकिस्तान	महामहिम श्री येरलान अलीम्बयेव	03.10.2019
38	जापान	महामहिम श्री सातोशी सुजुकी	27.11.2019
39	स्लोवेनिया	महामहिम डॉ मार्जन एनसेन	27.11.2019

1 जनवरी, 2019 से विदेशी मिशनों के प्रमुखों की प्रथम आगमन की स्थिति

क्रम संख्या	मिशन प्रमुख का नाम	देश	आगमन की तारीख
1	उच्चायुक्त श्री गेब्रियल पेंदुरनी सिनीम्बो	नामीबिया गणराज्य	17.01.2019
2	राजदूत सुश्री आइशाथ मोहम्मद दीदी	मालदीव गणराज्य	18.01.2019
3	राजदूत श्री शालर गेलडिनाजारोव	तुर्कमेनिस्तान	27.01.2019
4	राजदूत श्री जुआन एंगुलो	चिली	31.01.2019
5	राजदूत श्री अहमद युसिफ मोहम्मद एल्सिडिग	सूडान गणराज्य	29.01.2019
6	राजदूत महामहिम श्रीमती एलिनोरा दिमित्रोवा	बुल्गारिया गणराज्य	13.02.2019
7	राजदूत महामहिम श्री असिन इसाव	किर्गिज गणराज्य	18.02.2019

क्रम संख्या	मिशन प्रमुख का नाम	देश	आगमन की तारीख
8	राजदूत महामहिम श्री निलांबर आचार्य	नेपाल	18.02.2019
9	उच्चायुक्त महामहिम थॉमस सेल्बी पिल्लै	सेशेल्स गणराज्य	28.02.2019
10	राजदूत महामहिम श्रीमती कोरोमोटो गोडोय काल्डेरॉन	वेनेजुएला बोलीवेरियन गणराज्य	05.03.2019
11	राजदूत महामहिम श्री जोरान जानकोविक	मोंटेनेग्रो	11.03.2019
12	उच्चायुक्त महामहिम श्री पाउलियस कोर्नी, ओबीई	पापुआ न्यू गिनी	14.03.2019
13	राजदूत महामहिम श्री मुहमद तलहा हाजी हाजी	पनामा गणराज्य	20.03.2019
14	राजदूत महामहिम श्री वाल्टर जोहानेस लिंडनर	जर्मनी का संघीय गणतंत्र	31.03.2019
15	राजदूत महामहिम श्री चोई हुई चोल	लोकतांत्रिक गणराज्य कोरिया	30.03.2019
16	राजदूत महामहिम श्री अलवारो सैंडओवल बर्नल	कोलंबिया	29.04.2019
17	राजदूत महामहिम श्री कार्लोस राफेल पोलो कास्टानेडा	पेरू	01.05.2019
18	राजदूत महामहिम डॉ (श्रीमती) तिज्ता मुलुगेटा यीमम	इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य	15.05.2019
19	राजदूत महामहिम रेमन एस बैगटसिंग, जूनियर फिलीपीन	फिलीपींस गणराज्य	01.06.2019
20	राजदूत महामहिम रहीमजोदा सुल्टन	ताजिकिस्तान गणराज्य	28.05.2019
21	राजदूत महामहिम रोड्रिगो कोरोनेल किंलोच	निकारागुआ गणराज्य	23.06.2019
22	उच्चायुक्त महामहिम श्री जोएल सिबुसिसो नडेबेले	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य	11.07.2019
23	राजदूत महामहिम श्री सन वेडोंग	चीन लोकतांत्रिक गणराज्य	21.07.2019
24	राजदूत महामहिम सुश्री कातिन किवी	एस्टोनिया	01.08.2019
25	राजदूत महामहिम श्रीमती फडूमा अब्दुल्ला मोहमूद	सोमालिया	15.08.2019

क्रम संख्या	मिशन प्रमुख का नाम	देश	आगमन की तारीख
26	राजदूत महामहिम श्री डायोनिसियोस काइवटोस	यूनान	15.08.2019
27	राजदूत महामहिम श्री क्लाउडियो एंसोरेना मोंटेरो	कोस्टा रिका गणराज्य	18.08.2019
28	राजदूत महामहिम डॉ गॉडफ्रे चिपरे	जिम्बाब्वे गणराज्य	22.08.2019
29	राजदूत महामहिम श्री हंस जैकब फ्रीडेनलुंड	नॉर्वे	01.09.2019
30	राजदूत महामहिम श्री फ्रेडी स्वेने	डेनमार्क	01.09.2019
31	राजदूत महामहिम श्री ब्रेंडन वार्ड	आयरलैंड	28.08.2019
32	राजदूत महामहिम इमैनुएल लेनिन	फ़्रांस	14.09.2019
33	राजदूत महामहिम श्री उगो अस्तुतो	यूरोपीय संघ	16.09.2019
34	राजदूत महामहिम श्री फेडरिको साल्वे लोफे	मेक्सिको	17.09.2019
35	राजदूत महामहिम श्री येरलान अलीबायेव	कजाखस्तान गणराज्य	23.09.2019
36	राजदूत महामहिम श्री सातोशी सुज़ुकी	जापान	01.11.2019
37	राजदूत महामहिम डॉ मार्जन सेंसेन	स्लोवेनिया गणराज्य	18.11.2019
38	राजदूत महामहिम सुश्री रित्वा कूक्कू-रोडे	फ़िनलैंड	02.12.2019
39	राजदूत महामहिम श्री विनसेन्ज़ो डी लुका	इटली	04.12.2019

1 जनवरी, 2019 से विदेशी मिशनों के प्रमुखों के अंतिम प्रस्थान की स्थिति

क्रम संख्या	मिशन प्रमुख का नाम	देश	प्रस्थान तिथि
1	राजदूत श्री परखत एच दुरयेव	तुर्कमेनिस्तान	09.01.2019
2	राजदूत श्री असफाव डिंगामो	इथियोपिया	10.03.2019
3	राजदूत डॉ मार्टिन नेनी	जर्मनी संघीय गणतंत्र	30.03.2019
4	उच्चायुक्त श्री सोहेल महमूद	पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र	14.04.2019
5	राजदूत एमए टेरेसीता सी दाज़ा	फिलीपींस गणराज्य	25.04.2019

क्रम संख्या	मिशन प्रमुख का नाम	देश	प्रस्थान तिथि
6	राजदूत श्री लुओ झाओहुई	चीन लोकतांत्रिक गणराज्य	28.05.2019
7	राजदूत सुश्री मेलबा प्रिया	मेक्सिको	04.06.2019
8	राजदूत सुश्री नीना वकुल्लाट्टी	फ़िनलैंड	18.06.2019
9	राजदूत सुश्री एयन महामेड सलाह	सोमालिया संघीय गणराज्य	31.07.2019
10	राजदूत श्री मैक्सवेल रंगा	जिम्बाब्वे गणराज्य	29.07.2019
11	राजदूत श्री पैनोस कालोगरोपोलोस	यूनान	10.08.2019
12	राजदूत श्री पीटर तकसो-जेनसेन	डेनमार्क	29.08.2019
13	राजदूत श्री निल्स रागनार काम्सवेग	नॉर्वे	31.08.2019
14	राजदूत श्री एलेक्जेंडर जिगलर	फ़्रांस	30.08.2019
15	राजदूत श्री एरियल जारेड एंड्रेड गैलंडो	अल साल्वाडोर गणराज्य	06.09.2019
16	राजदूत श्री बुलट सरसेनबायेव	कजाखस्तान गणराज्य	21.09.2019
17	राजदूत श्री जोज़ेफ ड्रोफेनिक	स्लोवेनिया गणराज्य	25.09.2019
18	राजदूत श्री केंजी हिरमात्सु	जापान	22.10.2019
19	राजदूत श्री अहमद यूसुफ मोहम्मद एल्सिडिग	सूडान गणराज्य	30.11.2019
20	राजदूत श्री एंज़ो एंजेलोनी	इटली	01.12.2019
21	उच्चायुक्त श्री बोबटा त्सिकोआन	लेसोथो साम्राज्य	11.12.2019

1 जनवरी, 2019 से अनुमोदित निवासी मिशन/व्यापार कार्यालय/महावाणिज्य दूतावास /उप उच्चायोग/मानद कौंसुल की सूची

क्रम संख्या	विवरण	देश
1.	**रेजिडेंट मिशन**	जमैका
2.		नौरू
3.		निकारागुआ

क्रम संख्या	विवरण	देश	स्थान
1.	महावाणिज्य दूत/उप उच्चायोग	सऊदी अरब	बेंगलुरू
2.		बांग्लादेश	चेन्नई

क्रम संख्या	विवरण	देश	स्थान
1.	मानद वाणिज्य दूतावास	बेल्जियम	हैदराबाद
2.		माल्टा	मुंबई
3.		माली	बेंगलुरू
4.		कोरिया - गणराज्य	अहमदाबाद
5.		मालदीव	बेंगलुरू
6.		पलाउ	नई दिल्ली
7.		ट्यूनीशिया	बेंगलुरू
8.		सेशल्स	बेंगलुरू
9.		फ़िनलैंड	कोलकाता
10.		कज़ाकस्तान	मुंबई
11.		नीदरलैंड	चेन्नई
12.		ज़िम्बाब्वे	मुंबई
13.		कज़ाकिस्तान	चेन्नई

1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों में नवनिर्मित पोस्टों की माहवार सूची

1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक सृजित नई पोस्टों के सृजन की वार्षिक रिपोर्ट	
जनवरी	01
फरवरी	05
मार्च	04
अप्रैल	16
मई	12
जून	06

1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक सृजित नई पोस्टों के सृजन की वार्षिक रिपोर्ट	
जुलाई	20
अगस्त	11
सितम्बर	15
अक्तूबर	11
नवम्बर	10
कुल	**111**

23

बाह्य प्रचार और लोक राजनयिकता प्रभाग

बाह्य प्रचार और लोक राजनयिकता प्रभाग ने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रोफाइल को अत्यंत तेजी से अनुकूल कर लिया है और यह घरेलू एवं वैश्विक लोगों तक उत्तरदायी और ध्यान-केन्द्रित पहुंच के माध्यम से त्वरित गति से संप्रेषण परिवेश विकसित कर रहा है। ऐसा मीडिया के साथ व्यापक संबंधों के माध्यम से तथा घर और बाहर, दोनों के स्थानों पर भारत के सार्वजनिक राजनयिक कदमों को विस्तारित करते हुए और परिणाम को अधिकतम बनाते हुए सामाजिक मीडिया एवं आधुनिक उपकरणों को प्रयोग करते हुए हासिल किया गया है।

प्रभाग ने लोक राजनयिकता का तीन विशेष पहलों को प्रोत्साहित किया है - विद्यालय एवं एमईए संबंध कार्यक्रम (एसएएमईईपी) - भारतीय विदेश सेवा से संबंधित उस विद्यालय के पूर्व-छात्रों तक संपर्क 'विदेश आया परदेश के द्वार', जो समूचे भारत के विभिन्न शहरों में प्रादेशिक मीडिया के साथ ध्यान-केन्द्रित संबंध तथा 'भारत एक परिचय - विदेश स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के पुस्तकालयों में भारत पर लिखी गई पुस्तकों के लिए स्थान। प्रेस संबंधों के मामले में, प्रभाग ने 'इंडिया बियांड हैडलाइंस' नामक नई पहल आरंभ की है, जो भारत में रहने वाले विदेशी पत्रकारों के लिए एक परिचय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विभिन्न विषयों पर भारत की समझ उत्पन्न करने का मौका देना है।

एक्सपीडी प्रभाग महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों के लिए नोडल बिंदु है। प्रभाग ने इस अवसर का उत्सव मनाने के लिए विदेश स्थित हमारे मिशनों और पोस्टों द्वारा

आयोजित किए गए अनेक क्रियाकलापों को सहायता प्रदान की है। इस अवसर पर 'व्हाट गांधी मीन्स टु मी' पर एक संग्रह निकाला गया जिसमें समूचे विश्व के उत्कृष्ट व्यक्तित्वों के योगदानों को शामिल किया गया है। प्रभाग ने गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती के समारोहों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक नवीन पहल में, गुरु नानक की शिक्षा पर एक एलईडी फिल्म भी प्राप्त की गई तथा उसे विश्व के विभिन्न भागों में दिखाया गया।

इन प्रयासों ने विश्व में भारत की स्थिति को मजबूत बनाते हुए प्रयास करते हुए भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

मीडिया के साथ संबंध

प्रेस कवरेज

एक्सपीडी प्रभाग संभार-तंत्र संबंधी व्यवस्थाएं करता है जिसमें पूर्णत: सज्जित मीडिया सेंटरों की स्थापना और उनका प्रचालन तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आवक और जावक दौरों के लिए मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करना भी शामिल है। ये व्यवस्थाएं देश के भीतर और साथ ही विदेश में लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी का त्वरित संप्रेशण सुनिश्चित करती है।

शिखर-सम्मेलन/सम्मेलन और संपर्क क्रियाकलाप

प्रभाग ने प्रधानमंत्री की मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, यूएई, बहरीन और सउदी अरब की छह द्विपक्षीय यात्राओं के लिए संबंधित व्यवस्थाएं की हैं। इसके अतिरिक्त, सात बहुपक्षीय -13-14 जून को बिश्केक, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन, 27-29 जून को जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन, 26-27 अगस्त को बियारिट्ज, फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन, व्लादिवोस्तोक, 04-06 सितंबर को रूस में पूर्वी आर्थिक मंच, 22-27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में महासभा सत्र, 02-04 नवंबर को आसियान और बैंकॉक, थाईलैंड में संबंधित शिखर सम्मेलन और ब्राजीलिया, ब्राजील में 13-14 नवंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की व्यवस्था की। एक्सपीडी प्रभाग ने भारत के राष्ट्रपति की ग्यारह देशों की द्विपक्षीय यात्राओं, उपराष्ट्रपति की छह देशों की द्विपक्षीय यात्राओं तथा गुट-निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन के लिए अजरबैजान के एक बहुपक्षीय दौरे और विदेश मंत्री की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों की भी मीडिया ने व्यवस्था की।

प्रभाग भारत आने वाले उच्च-स्तरीय के लिए मीडिया कवरेज सुनिश्चित करता है। प्रभाग ने अगस्त में जांबिया गणराज्य के राष्ट्रपति, सितम्बर में मंगोलिया के राष्ट्रपति, अक्तूबर में नीदरलैंड्स के सम्राट और सम्राज्ञी, सितम्बर में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, अक्तूबर में चेन्नई में द्वितीय औपचारिक शिखर-सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति, अक्तूबर में जर्मनी के चांसलर, नवम्बर में प्रिंस ऑफ वेल्स तथा नवम्बर में श्रीलंका के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा के लिए मीडिया व्यवस्थाओं को सुकर बनाया। प्रभाग ने मई, 2019 में नव-निर्वाचित सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह के लिए विदेश गणराज्य अतिथियों के साथ आए मीडिया शिष्टमंडलों के लिए संभार-तंत्र व्यवस्थाएं की और उन्हें यथासंभव सुविधाएं मुहैया कराई जिसमें छह बिमस्टेक राष्ट्रों किर्गिज गणराज्य और मॉरीशस गणराज्य के राज्याध्यक्षों/ सरकार प्रमुखों ने भाग लिया था। इस अवधि के दौरान विदेश मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आवक दौरों के लिए मीडिया व्यवस्थाएं की गईं।

भारतीय मीडिया के लिए शिष्टमंडल ने भी 12-16 अगस्त, 2019 तक तीसरे भारत-चीन उच्च स्तरीय मीडिया फोरम में भाग लेने के लिए बीजिंग और शंघाई की यात्रा भी की।

सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर ईएएम प्रेस कांफ्रेस

प्रभाग ने सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर, 2019 को ईएम प्रेस कांफ्रेस आयोजित की।

एफएसआई में भारतीय मीडिया (राजनयिक पत्रकार) के लिए विशेष पाठ्यक्रम

भारतीय मीडिया के लिए विदेश नीति पर एक विशेष पाठ्यक्रम 16-22 अक्तूबर, 2019 को विदेश सेवा संस्थान के सहयोग से एक्सपीडी प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से विदेश मंत्रालय के आयोजनों को कवर करने वाले सैंतीस भारतीय पत्रकारों ने उक्त पाठ्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम भारतीय विदेश नीति तथा राजनयिक पत्रकारों के लिए मंत्रालय के कार्यकरण की समीक्षा करने में लाभप्रद साबित हुआ।

विदेश मीडिया के साथ संबंध

इंडिया बियांड हैडलाइंस

एक्सपीडी प्रभाग ने 'इंडिया बियांड हैडलाइंस' नामक एक पहल आरंभ की है जो भारत में रहने वाले विदेश पत्रकारों के लिए परिचय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उन्हें अनेक विषयों पर भारत के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पहल के अंतर्गत पहला दौरा 26-28 जुलाई, 2019 को कश्मीर जाने वाली विदेशी पत्रकारों के समूह के लिए आयोजित किया गया था।

विदेश पत्रकारों के लिए परिचायक दौरे

मित्र देशों के बीच भारत के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मीडिया आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए, एक्सपीडी प्रभाग विदेशी पत्रकारों के लिए भारत की परिचित यात्राओं का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 21 देशों [कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, भूटान, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, रोमानिया और रूस] के 169 पत्रकार भारत का दौरा कर चुके हैं। ब्रिटेन, आईओआर देशों और अफ्रीकी देशों के पत्रकारों का इस वित्तीय वर्ष में दौरा करने का कार्यक्रम है।

विदेश राजनयिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

एक्सपीडी प्रभाग ने अप्रैल-नवम्बर, 2019 की अवधि के दौरान लगभग 90 देशों से 194 विदेशी राजनयिकों के लिए कुल 9 बैचों में मीडिया और लोक राजनयिकता पर एक-दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया। इस मॉड्यूल के भाग के रूप में, प्रत्येक बैच के लिए दो प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) का दौरा भी आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को 23-24 अप्रैल, 2019 को 2018 बैच के 39 आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए भी आयोजित किया गया था जिसमें एक मॉक प्रेस कांफ्रेस भी शामिल थी।

डिजिटल पहुंच

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट भारत की विदेश नीति के प्रतिपादन को मूर्त रूप प्रदान करती है तथा यह भारत के द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अनेक पक्षीय संबंधों से

जुड़ी समस्त जानकारी का संग्रहण भी है। यह वेबसाइट द्विभाषी, प्रयोक्ता-हितैषी, प्रयोग में लचीली, सतत तथा मानक विनिर्देशनों का अनुपालन करती है। जानकारी के प्रचार-प्रसार के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वेबसाइट को मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों के लिए समान रूप से डिजाइन किया गया है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट दृष्टि और श्रव्य बाधित व्यक्तियों के लिए भी सुलभ है। इसके सितम्बर, 2012 में औपचारिक शुभारंभ के बाद से, वेब पोर्टल ने 5 करोड़ से भी अधिक हिट्स प्राप्त किए हैं जिनमें 1 करोड़ से अधिक हिट्स केवल जनवरी, 2019 के बाद से ही किए गए हैं तथा इसने मंत्रालय की डिजिटल छवि को पूरी तरह से बदल दिया है।

विशेष मीडिया प्लेटफार्म

विदेश मंत्रालय व्यापक सोशल मीडिया व्यक्तित्व और डिजिटल पहचान हासिल करने वाला देश का अग्रणी मंत्रालय रहा है जिसे फॉलोअर्स की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

1. मंत्रालय के ट्विटर पर 3.4 मिलियन फॉलोअर्स है जिसमें @MEAIndia पर 2.02 मिलियन फॉलोअर्स हैं और @IndiaDiplomacy पर 1.4 फॉलोअर्स हैं। मिशनों और पोस्टों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का सक्रिय रूप से प्रयोग करते हुए मेजबान देश में प्रवासी भारतीयों और वहां की जनसंख्या के साथ संपर्कों में वृद्धि को भी जारी रखा है। आज, लगभग 179 भारतीय मिशन/पोस्ट ट्विटर और फेसबुक पर हैं तथा लगभग 51 मिशनों ने इन्स्टाग्राम पर उपस्थित दर्ज कराई है। जैसे-जैसे संपूर्ण विश्व में सोशल मीडिया के बारे में रुचि में परिवर्तन होता जा रहा है, नए प्लेटफार्म उभरकर सामने आए हैं। मिशन/पोस्टों के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में मानकीकरण का अनुपालन किया गया है, जिसके तहत सभी एकाउंटों का मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्लेटफार्म में सत्यापन किया जाता है। मंत्रालय की इस चहुंमुखी डिजिटल पहुंच ने मंत्रालय और मिशनों/पोस्टों के क्रियाकलापों के बारे में लोगों को न केवल भारत में बल्कि समूचे विश्व में जानकारी के त्वरित, प्रत्यक्ष और सटीक संप्रेषण को समर्थ बनाया है।

2. मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के तकाल प्रसार के लिए ट्विटर एक प्रभावी माध्यम है। मंत्रालय के अधिकारिक प्रवक्ता के हैंडल (@MEAIndia) तथा लोक राजनयिकता हैंडल (@IndiaDiplomacy) ने पिछले वर्ष लगभग 1,50,000 और 10,00,000 फॉलोअर्स की वृद्धि हुई है। @MEAIndia आज समूचे विश्व में सभी विदेश मंत्रालयों में से सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला तीसरा हैंडल बन गया है। इस प्लेटफार्म का प्रयोग भारत के विदेश संबंधी पर ट्वीट अद्यतन बनाने के लिए किया जाता है। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अनेक पक्षीय संबंधों के दौरान, ट्विटर को रीयल टाइम आधार पर अद्यतन बनाया जाता है। दोनों ट्विटर हैंडलों के सक्रिय रूप से ट्विटर के वीडियो फार्मेटों का प्रयोग किया है विशेष रूप से विदेशी यात्राओं के दौरान लघु वीडियो तथा प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की समाप्ति के पश्चात् वीडियो रिकैप ने ट्विटर पर सर्वाधिक प्रशंसा और प्रभाव अर्जित किया है।

3. विदेश मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनल में नवम्बर, 2019 तक कुल 7,093 सब्सक्राइबर हैं जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा कुल 5.7 मिलियन व्यू हुए हैं। भारतीय राजनयिकता के यू-ट्यूब चैनल के नवम्बर, 2019 तक 83,861 सब्सक्राइबर है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और

कुल 15.2 मिलियन व्यू हुए हैं।

4. विदेश मंत्रालय ने इंस्ट्राग्राम पर अपनी फॉलोअरशिप में भारी वृद्धि की है जो चित्रों से परिपूर्ण प्लेटफार्म है। पिछले वर्ष की तुलना में 158 % की वृद्धि के साथ, विदेश मंत्रालय के पास 399,000 फॉलोअर्स की फॉलोअरशिप है। इंस्टाग्राम युवा पीढ़ी को अधिक आकर्षित करता है तथा इसकी विषय-वस्तु विशेषतः युवाओं के लिए तैयार की जाती है।

5. विदेश मंत्रालय का फ्लिकट एकाउंट (विदेश मंत्रालय फोटो गैलरी) भारत और विदेश में विदेश मंत्रालय के सभी प्रमुख समारोहों के सभी फोटोग्राफ की संग्रहशाला है जिसमें नवम्बर, 2019 तक 41,142 एचडी फोटो का फोटो बैंक था।

6. विदेश मंत्रालय का साउंड क्लाउड एकाउंट (विदेश मंत्रालय भारत) समस्त मीडिया ब्रीफिंग की श्रव्य क्लिपों तक पहुंच बनाने के लिए एक उपयोगी डाटाबेस है। सभी मीडिया ब्रीफिंग की वीडियो क्लिप्स भी यू-ट्यूब पर अपलोड की जाती है।

7. विदेश मंत्रालय ने लिंक्डइन पर पिछले वर्ष की तुलना में 620 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 11,850 फॉलोअर्स के साथ फॉलोअर्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

8. मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने के लिए भी अतिसक्रिय रहा है जैसे महात्मा गांधी के 150 वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, गुरु नानक देवीजी की 550वीं जयंती, संविधान दिवस आदि।

डिजिटल आउटरीच के विस्तार और स्वयं को 'डिजिटल रूप से अग्रिम' के रूप में ब्रांडिंग करने में विदेश मंत्रालय के प्रयासों की लोकप्रियता और सफलता सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में अपने अनुयायियों के निरंतर विकास से प्रदर्शित होती है।

दृश्य पहुंच-फिल्में और वृत्त चित्र

विदेश में भारत की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने के लिए विदेश मंत्रालय वर्ष 1981 से ही विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र तैयार करा रहा है जिसमें भारतीय संस्कृति, राजनीति, आर्थिक और अन्य सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय फिल्मों द्वारा विदेश में हासिल की जाने वाली सराहना में और वृद्धि करने के लिए उपयुक्त भारतीय फिल्मों को गैर-व्यावसायिक अधिकारों के साथ खरीदा भी जाता है।

चार विषयों अर्थात् डा. बी.आर. अम्बेडकर (मूकनायक), भारत सरकार द्वारा संचालित बचाव अभियान कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा विकास सहयोगी पहलों पर चार वृत्तचित्र पूर्ण किए गए तथा उन्हें विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित किया गया। भारतीय निर्वाचन (इंडिया इंक), महात्मा गांधी और गुरु नानक देवजी पर तीन विशेष लघु फिल्में भी विनिर्दिष्ट प्रयोग के लिए खरीदी गई हैं।

जनता तक पहुंच

विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला

इस जनसंपर्क पहल के अंतर्गत सेवारत वरिष्ठ और सेवानिवृत्त राजनयिकों, भारत के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं में विदेश नीति पर व्याख्यान देते हैं। इस पहल की शिक्षा समुदाय द्वारा पर्याप्त सराहना की गई है तथा इसे 2010 में इसकी स्थापना के बाद से धीरे-धीरे विस्तारित किया गया है। व्याख्यान माला ने अब अपने क्षेत्राधिकार के अंगत 253 शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल कर लिया है जिसमें 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी,

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में तीन सेनाएं भी शामिल हैं जैसे भारतीय सेना अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और रक्षा स्टाफ सेवा आयोग। व्याख्यानों में विदेश नीति से संबंधित विभिन्न विषय होते हैं जिन्हें पूरे देश में आयोजित किया जाता है। 2019 में 44 व्याख्यान आयोजित किए गए हैं तथा इस पहल के प्रारंभ होने से अब तक 297 व्याख्यान दिए गए हैं।

समीप-छात्र और विदेश मंत्रालय संपर्क कार्यक्रम

समीप प्रभाग की एक संपर्क पहल है जिसका उद्देश्य छात्र समुदाय से भारत के विभिन्न शहरों और कस्बो में संपर्क स्थापित करना है और उन्हें विदेश मंत्रालय की भूमिका और कार्यों, भारत की विदेश नीति के मुख्य अवयवों, विदेश नीति के संबंध में सफलता गाथाओं तथा और उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारी अपनी छुट्टियों के दौरान अपने गृह नगर/राज्य में स्थित विद्यालयों और कॉलेजों का दौरा करते हैं तथा छात्रों के साथ संपर्क करते हुए उनसे विदेश मंत्रालय में कार्य करने के दौरान उन्हें प्राप्त अनुभवों को साझा करते हैं। वर्ष 2018 में इस पहल के प्रारंभ होने से लेकर अब तक 44 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

व्हाट गांधी मींस टु मी - एक जीवनी

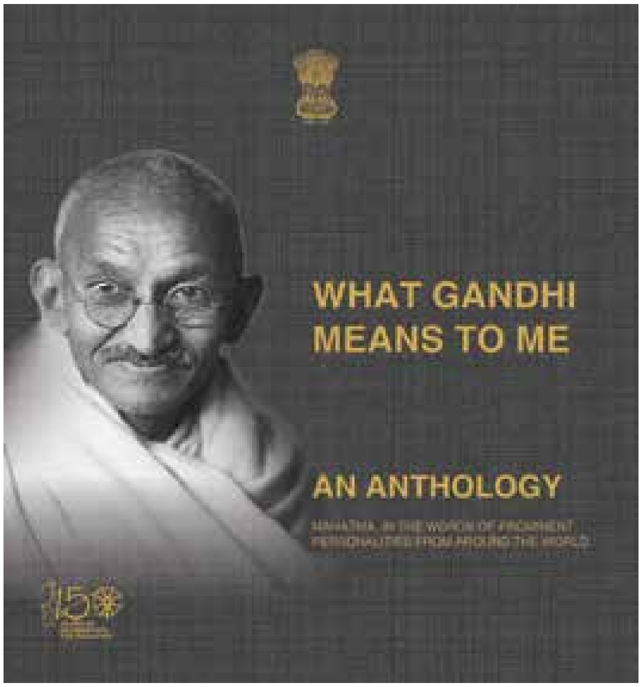

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोहों के भाग के रूप में 'व्हाट गांधी मींस टु मी' नामक लेख-संग्रह प्रकाशित किया गया है जिसमें विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्वों ने लेखों का योगदान दिया है। इस लेख-संग्रह ने इस बात को उजागर किया है कि किस प्रकार समूचे विश्व के लोग महात्मा गांधी की शिक्षा और दर्शन से लाभान्वित हुए हैं।

पुस्तकें और पत्रिकाएं

पुस्तक समिति

पुस्तक समिति की स्थापना एक लोक राजनयिक उपकरण के रूप में 2003 में की गई थी जिसका उद्देश्य मिशनों के पुस्तकालय तथा प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन के लिए पुस्तकों का चयन करना था। पुस्तक समिति की 41वीं बैठक में विभिन्न श्रेणियों की 343 पुस्तकों का चयन किया गया है जैसे भारतीय शास्त्रीय-कलाएं, विदेश नीति और कार्य, प्रौद्योगिकी एवं लोकप्रिय विज्ञान हिन्दी एवं संस्कृत, कला एवं संस्कृति। मिशनों से प्राप्त अनुरोधों के निर्बाध प्रक्रमण के लिए इस वर्ष एक ऑनलाइन पोर्टल भी सृजित किया गया है।

भारतीय संदर्भ

मंत्रालय की प्रमुख पत्रिका अब 16 भाषाओं में एक डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है। पत्रिका का वेब संस्करण मिशनों और पोस्ट द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने के विकल्प के अनुकूलन की सुविधा प्रदान करता है। इसे www.indiaperspectives.gov.in और www.mea.gov.in पर ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है।

24

प्रशासन, स्थापना और आरटीआई मामलें

प्रशासन प्रभाग

प्रशासन प्रभाग का प्रयास मुख्यालय और विदेशों में 193 भारतीय मिशनों/केंद्रों दोनों में, मंत्रालय की मानव पूंजी के प्रबंधन और कुशलतापूर्वक तैनाती करके जनशक्ति उपयोग का अनुकूलन करना है। यह दिशा प्रभाग, संवर्ग प्रबंधन की देखरेख करता है जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती/स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और आजीविका प्रगति नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रभाग ने भारतीय मिशनों और केंद्रों में सेवारत भारतीय कार्मिकों और स्थानीय कर्मचारियों सहित संबंधित भारत सरकार के नियमों और विनियमों के गठन, संशोधन और कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी कार्मिक नीतियों को भी अद्यतन किया। मंत्रालय और उसके कार्यालयों की बदलती अपेक्षाओं और अपेक्षित सुपुर्दगी की पूर्ति के लिए संगठन संरचना और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं।

मंत्रालय में वर्तमान पदों की स्वीकृत संख्या 4261 (परिशिष्ट IX) है जिसमें से लगभग 53% पद विदेशों में मिशन और केंद्रों में हैं। मंत्रालय के कुल पद विभिन्न संवर्गों जैसे भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), आईएफएस सामान्य संवर्ग शाखा बी, आशुलिपिक संवर्ग, दुभाषिए संवर्ग, विधिक और संधि संवर्ग आदि में विभाजित है। मंत्रालय ने कैडर प्रबंधन के हिस्से के रूप में वर्ष 2018-19 में सीधी भर्ती (डीआर) और विभागीय प्रोन्नति (डीपी) के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कर्मियों की भर्ती करके अपनी जनशक्ति में वृद्धि की। मंत्रालय

ने भारत-प्रशांत प्रभाग के सृजन, भारत महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय आवंटनों को पुनर्व्यवस्थित करने आदि जैसे नए कार्यों और कार्यात्मक प्राथमिकताओं के लिए अपने प्रभागों और उनके उत्तरदायित्वों का पुनर्गठन किया है।

मंत्रिमंडल की मार्च, 2018 में अफ्रीका में 2018-21 के दौरान 18 नए मिशन खोलने की मंजूरी के अनुपालन में, प्रथम चरण में छह मिशन - रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, बुर्किना फासो और गिनी और द्वितीय चरण में तीन मिशन एवतिनी, इरिट्रिया और कैमरून खोलने का कार्य पूर्ण हो गया है। लाइबेरिया, सिएरा लियोन और साओ टोम और प्रिंसिप में नए मिशन स्थापित करने के लिए प्रारंभिक प्रशासनिक और स्थापना से संबंधित उपाय शुरू किए गए है।

मंत्रालय ने आर्थिक कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, साइबर सुरक्षा, लैंगिक बजटिंग, लेखांकन, कांसुलर और पासपोर्ट सेवाओं, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग आदि पर विशेष मॉड्यूल सहित अपने सभी संवर्गों के प्रशिक्षण पर उचित ध्यान केंद्रित किया। निर्वचन सहित अधिकारियों के विदेशी भाषाई कौशल के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप सेवा में गुणवत्ता पूर्ण विदेशी भाषा कौशल वाले अधिकारियों का एक बड़ा पूल बन गया (परिशिष्ट X)।

विचारों के आदान-प्रदान, डिजिटल की गई प्रक्रियाओं, सूचना संग्रहण और मिशनों/पोस्टों के कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रभावी मॉनीटरन के लिए मुख्यालय और मिशनों/पोस्टों के बीच एक ऑनलाईन इंटरफेस ई-समीक्षा पोर्टल जैसे प्रौद्योगिकी साधनों का प्रभावी उपयोग किया।

ग्लोबल एस्टेट मैनेजमेंट डिवीजन

विदेशों और भारत में संपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/पुनर्विकास/नवीकरण सहित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नैरोबी में एक भूखंड और टोक्यो में दो आवासीय अपार्टमेंट का अधिग्रहण पूरा हो गया है। ताशकंद और मालदीव में भूमि के बहुत बड़े भूखंडों के आवंटन पर संबंधित मिशनों के लिए चांसरी-सह-आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए सफल वार्ता की गई। विदेश मंत्रालय के एक अन्य कार्यालय के लिए नई दिल्ली में लगभग 2.5 एकड़ जमीन का एक भूखंड निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। व्लादिवोस्तोक (चांसरी), तेल अवीव (चांसरी), म्यूनिख (चांसरी), बर्न (चांसरी), रोम (चांसरी), मिलान (चांसरी एंड सीजी निवास), मनीला (चांसरी) और बिश्केक (चांसरी) में संपत्तियों की अधिग्रहण पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की गई। भारतीय राज्यों के राजधानी शहरों में विदेश भवनों की स्थापना के लिए भूमि के उपयुक्त भूखंडों को आवंटन के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय उपलब्धियों में पोर्ट लुई (चांसरी और निवास), अदीस अबाबा (चांसरी और निवास) और निकोसिया (निवास) में निर्माण परियोजनाओं का पूरा होना था। इस्लामाबाद (निवास), काठमांडू (चांसरी-सह-आवासीय परिसर), पोर्ट ऑफ स्पेन (सांस्कृतिक केंद्र) और वेलिंगटन (चांसरी और निवास) में निर्माण परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई। बैंकॉक (निवास), काबुल (निवास और बैरक) और फुएंत्शोलिंग (चांसरी और निवास) में नई निर्माण परियोजनाएं शुरू हुईं। पालम में वीवीआईपी रिसेप्टरियम, सियोल में राजदूत निवास और डबलिन में चांसरी सहित प्रमुख नवीकरण परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। पेरिस (सांस्कृतिक केंद्र), हेलसिंकी (निवास), डार-ए-सलाम (राजदूत निवास) और यंगन (सांस्कृतिक केंद्र) में चल रही नवीकरण परियोजनाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है। भुवनेश्वर और लखनऊ स्थित विदेश भवन परिसर के जीर्णोद्धार में भी प्रगति हुई।

आईसीसीआर मुख्यालय के पुनर्विकास के लिए डिजाइन, आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली और केजी मार्ग, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के आवासीय परिसर, अम्मान में निवास और दूतावास निवास, जेद्दा में चांसरी और निवास, रबत में सांस्कृतिक विंग और निवास सिंगापुर में चांसरी और निवास, कैनबरा में चांसरी एनेक्सी, मास्को में निवास, शंघाई में चांसरी और निवास और चेन्नई में विदेश भवन के लिए निर्णय लिया गया।

सतर्कता इकाई सीएनवी डिवीजन

सीएनवी प्रभाग की सतर्कता इकाई से संबंधित कार्य का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

- 31.03.2019 को लंबित मामलों की संख्या: 88
- 01.04.2019 से 13.12.2019 की अवधि के दौरान परीक्षा के लिए प्राप्त मामलों की संख्या: 32
- 01.04.2019 से 13.12.2019 की अवधि के दौरान औपचारिक दंड लगाने के साथ बंद किए गए मामलों की संख्या- 9
- 01.04.2019 से 13.12.2019 की अवधि के दौरान मृत्यु, वीआरएस, अन्य कारणों से बिना दंड के बंद किए गए मामलों की संख्या: 19
- 13.12.2019 को मामलों की कुल संख्या: 92
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28.10.2019 से 02.11.2019 तक मनाया गया। मंत्रालय, भारत में इसके संलग्न कार्यलयों और विदेशों में सभी भारतीय मिशन/पोस्टों के कार्मिको को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई गई।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में प्रयास जारी रखा। स्वतः प्रकटीकरण पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आरटीआई आवेदनों/अपीलों/प्रतिक्रियाओं को अपलोड करना और सार्वजनिक डोमेन पर मासिक आरटीआई के आंकड़े अपलोड किए गए हैं। आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति और निस्तारण की व्यवस्था विदेशों में 192 मिशनों/पोस्टों पर आरटीआई वेब पोर्टल के साथ तालमेल बनाकर लागू की गई है।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाले कुल 2008 आरटीआई आवेदन और 140 प्रथम अपील प्राप्त हुई हैं और उनका संतोषजनक निस्तारण कर दिया गया है। सामान्य तौर पर आवेदनों में विदेशी संबंधों, प्रशासनिक मुद्दों, द्विपक्षीय यात्राओं और उन पर किए गए खर्च जैसे विषय थे।

केंद्रीय सूचना आयोग की सभी सुनवाई में संबंधित सीपीआईओ और आरटीआई सेल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सीआईसी की अपेक्षानुसार, तिमाही विवरणियां, निर्धारित समय पर दायर की गई हैं।

विदेश सेवा संस्थान के सहयोग से, सीआईसी के निर्देशानुसार मंत्रालय के सभी सीपीआईओ द्वारा ऑनलाइन स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण (ट्रांसपेरेंसी ऑडिट) को समयबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया गया है।

25

विदेशों में राजभाषा नीति और हिंदी का प्रचार-प्रसार

भारत सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन मंत्रालय की प्राथमिकता बनी हुई है। विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों के माध्यम से हिंदी भाषा के संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए एक व्यापक योजना लागू की गई है। हिंदी प्रचार कार्यकलापों के आयोजन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को विदेशों में मिशनों और पोस्टों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हिंदी शिक्षण और हिंदी संवर्धन में कार्यरत संगठनों को प्रस्तुति देने के लिए विदेशों में मिशनों और पोस्टों पर हिंदी शिक्षण सामग्री की आपूर्ति की जाती है। हिंदी के अलावा मंत्रालय संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा दे रहा है।

मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा विदेशों में हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में शामिल स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान लिस्बन में क्षेत्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा, हमारे सभी मिशनों और पोस्टों के साथ-साथ मुख्यालय में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया जाता है। मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी पढ़ने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति देने से संबंधित कार्यों का समन्वय करता

है। इस वर्ष 98 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। सचिवालय के कामकाज का समन्वय विदेश मंत्रालय और मॉरीशस सरकार में उसके मॉरीशस समकक्ष द्वारा किया जाता है।

हिंदी दिवस 2019 के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के साथ-साथ विदेशों में हमारे मिशनों ने इस अवसर पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन कार्यकलापों के आयोजन के लिए विदेशों में मिशनों और पोस्टों को विशेष अनुदान स्वीकृत किए गए थे। मंत्रालय में पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण और आलेखन, हिंदी टंकण और राजभाषा सामान्य ज्ञान लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में 08 नवंबर, 2019 को आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, मुख्य अतिथि थे और उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। मंत्रालय के अंतर्गत रांची, कोलकाता, भोपाल और जालंधर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) को इस वर्ष राजभाषा नियम 1976 के उप नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। इस प्रकार इस नियम के अंतर्गत कुल 18 आरपीओ अधिसूचित किए गए हैं।

मंत्रालय ने अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी और स्पेनिश भाषाओं में भाषांतर के लिए विशेष दुभाषियों का एक पूल बनाने के उद्देश्य से भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए अटल भाषांतर योजना (एबीवाई) की स्थापना की है। अरबी, चीनी और रूसी भाषाओं में 3 उम्मीदवारों का पहला बैच, प्रत्येक में एक-एक, संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भाषांतर और अनुवाद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं।

फिजी के सुवा में एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन 25 जनवरी 2020 को आयोजित किया जाना है। विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन इस सम्मेलन में भाग लेंगे जो वर्ष 2021 में फिजी के सुवा में आयोजित होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए पर्दा उठाने का काम करेगा।

विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन मार्च के अंत तक होने की संभावना है।

26

वित्त और बजट

विदेश मंत्रालय को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित कुल बजट अनुमान रुपए 17,884.75 करोड़ है।

2. प्रमुख आवंटनों के लिए बजट का क्षेत्रीय वितरण नीचे दिया गया है :

क्षेत्र		**आबंटन** (करोड़ रुपये में)
विदेशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी)	अनुदान	7333.79
	ऋण	842.00
	कुल टीईसी	**8175.79**
विदेशों में भारतीय मिशन और पोस्ट		2748.05
विशेष राजनयिक व्यय		2663.01
पासपोर्ट और उत्प्रवास		1620.95
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		986.19
लोक निर्माण और आवास पर पूंजी परिव्यय		531.55
विदेश मंत्रालय सचिवालय		459.93
संस्थानों को अनुदान सहायता		281.22
अन्य		418.06
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल बजट अनुमान		**17,884.75**

3. मंत्रालय के बजट में सबसे बड़ा आबंटन अनुदान और ऋण के रूप में सहायता के माध्यम से विदेशों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) के लिए है। वित्त वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 17,884.75 करोड़ के बजट में से टीईसी का परिव्यय 45.71% अथवा रुपये 8175.79 करोड़ है, जिसमें से रुपये 7333.79 करोड़ (41%) अनुदान कार्यक्रमों के लिए है और 842 करोड़ रुपये (4.7%) ऋण के लिए है। वित्त वर्ष 2019-20 में टीईसी परिव्यय का शीर्ष-वार वितरण नीचे दिया गया है :

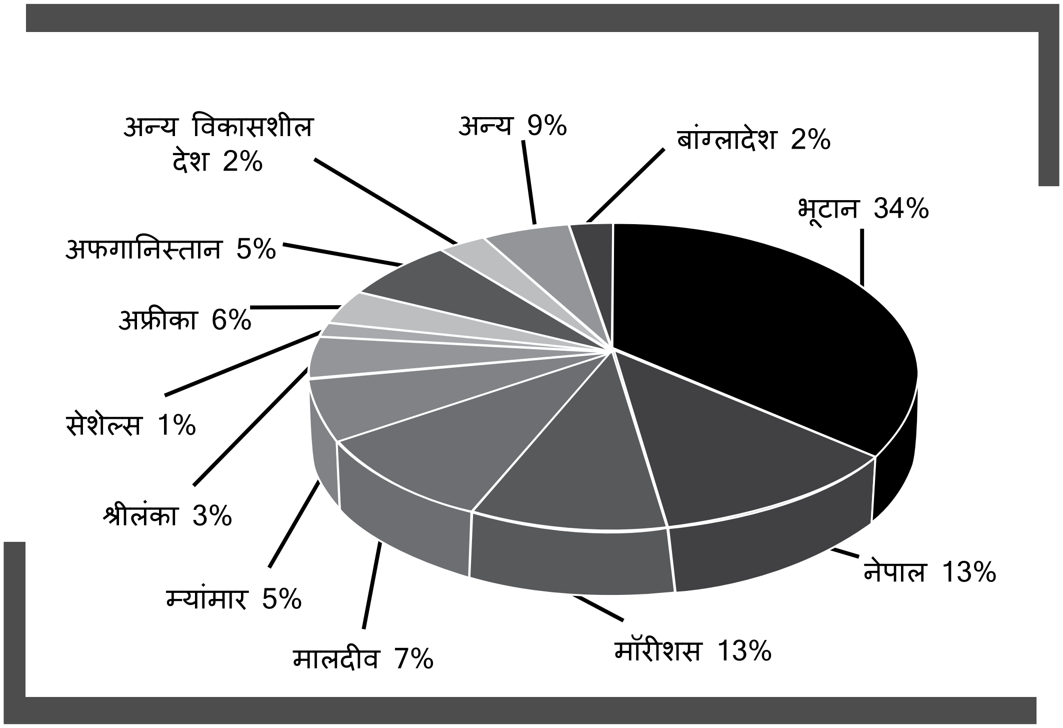

तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) शीर्ष		आबंटन (करोड़ रुपये में)	कुल टीईसी आबंटन का %
बांग्लादेश को सहायता		175	2.14%
भूटान	अनुदान	2135.79	34.26%
	ऋण	666.00	
	कुल, भूटान	**2801.79**	
नेपाल को सहायता		1050.00	12.84%
मॉरीशस को सहायता		1100.00	13.45%
अफगानिस्तान को सहायता		400.00	4.89%
सेशेल्स को सहायता		100.00	1.22%
म्यांमार को सहायता		400.00	4.89%

तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) शीर्ष		आबंटन (करोड़ रुपये में)	कुल टीईसी आबंटन का %
आईटीईसी कार्यक्रम		220.00	2.69%
अफ्रीकी देशों को सहायता		450.00	5.50%
श्रीलंका को सहायता		250.00	3.05%
चाबहार बंदरगाह, ईरान		45.00	0.55%
मालदीव को सहायता	अनुदान	400.00	7.04%
	ऋण	176	
	कुल, मालदीव	**576**	
अन्य विकासशील को सहायता		150.00	1.83%
निवेश प्रचार और संवर्धन कार्यक्रम		300.00	3.66%
भारत-प्रशांत सहयोग		45.00	0.55%
यूरेशियन देशों को सहायता		45.00	0.55%
बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम		20.00	0.24%
लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता		15.00	0.18%
आपदा राहत के लिए सहायता		20.00	0.24%
सार्क कार्यक्रम		8.00	0.09%
मंगोलिया को सहायता		5.00	0.06%
कुल		**8175.79**	

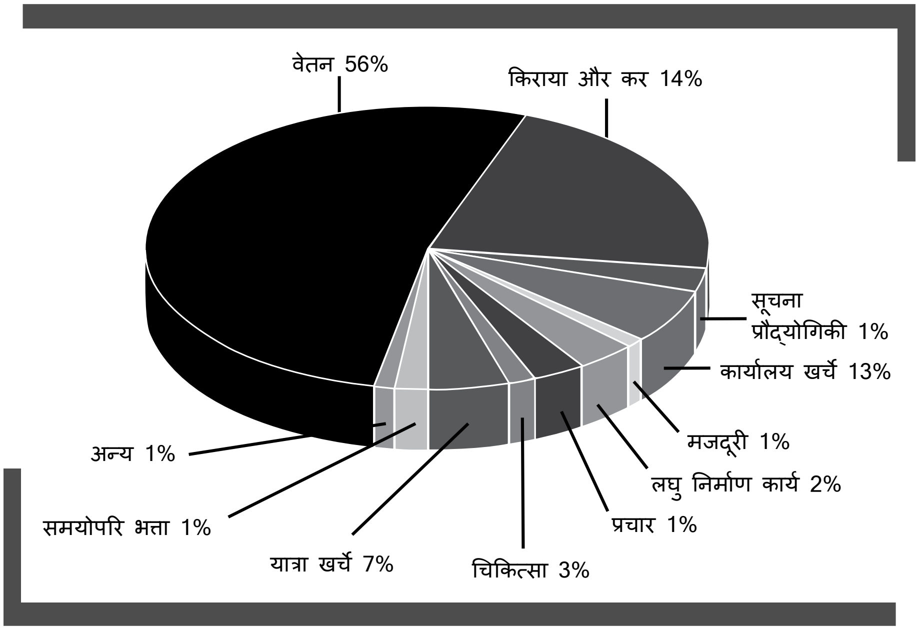

4. मंत्रालय के बजट में दूसरा सबसे बड़ा आबंटन विदेशों में 190 से अधिक भारतीय राजनयिक मिशनों और पोस्टों के रखरखाव के लिए है। वित्त वर्ष 2019-20 में, सभी मिशनों और पोस्टों के लिए आबंटित बजट, मंत्रालय के कुल बजट का 15.63% अथवा रुपए 2748.05 करोड़ है, जिसमें से शीर्ष-वार वितरण (प्रतिशत वार) नीचे दिया गया है :

5. वित्त वर्ष 2019-20 के 17884.75 करोड़ रुपये के कुल बजट में से स्थापना शीर्षों और गैर-स्थापना शीर्षों के बीच आबंटन का विभाजन क्रमशः 27 प्रतिशत (4852 करोड़ रुपये) और 73 प्रतिशत (13,032 करोड़ रुपये) है। मंत्रालय ने अपने कुल बजट के 30% के तक ही स्थापना शीर्षों पर अपने व्यय को लगातार बनाए रखा है।

6. मंत्रालय वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों (आरई) के स्तर पर इसे आवंटित निधियों का बेहतर उपयोग कर रहा है, जैसाकि विगत दस वर्षों के लिए नीचे दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान होना	संशोधित आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट अनुदान के प्रतिशत के रूप में उपयोगिता	संशोधित अनुमान के प्रतिशत के रूप में उपयोगिता
	करोड़ रुपये में; पूर्णांकित				
2009-10	**6293**	**6333**	**6291**	**100 %**	**99 %**
2010-11	**6375**	**7120**	**7154**	**112 %**	**100 %**
2011-12	**7106**	**7836**	**7873**	**111 %**	**100 %**
2012-13	**9662**	**10062**	**10121**	**105 %**	**100 %**
2013-14	**11719**	**11794**	**11807**	**101 %**	**100 %**
2014-15	**14730**	**12620**	**12149**	**82 %**	**96 %**
2015-16	**14967**	**14967**	**14541**	**97 %**	**97 %**
2016-17	**14663**	**13426**	**12772**	**87 %**	**95 %**
2017-18	**14798**	**13690**	**13750**	**93 %**	**100 %**
2018-19	**15011**	**15582**	**15,526**	**103%**	**99%**

7. मंत्रालय को वित्त वर्ष 2019-2019 में 31 अक्टूबर 2019 तक रुपये 3039.72 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पासपोर्ट सेवाओं से (रुपये 1487.46 करोड़), वीजा शुल्क से (रुपये 1078.51 करोड़) और अन्य पावतियों से (रुपये 473.75 करोड़)। विगत पांच वर्षों, में वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार हैं :

वर्ष	विभाग	राशि	प्रतिशत
2015-16	पासपोर्ट	2240.42	47%
	वीजा	1890.82	39%
	अन्य	684.34	14%
	कुल	4815.58	

वर्ष	विभाग	राशि	प्रतिशत
2016-17	पासपोर्ट	2285.85	45%
	वीजा	2018.04	40%
	अन्य	717.07	14%
	कुल	5020.96	
2017-18	पासपोर्ट	2479.08	47%
	वीजा	2152.15	41%
	अन्य	668.38	12%
	कुल	5299.61	
2018-19	पासपोर्ट	2679.75	44%
	वीजा	2688.9	44%
	अन्य	680.06	11%
	कुल	6048.71	
2019-20 (* आंकड़े 31 अक्तूबर 2019 तक)	पासपोर्ट	1487.46	49%
	वीजा	1078.51	35%
	अन्य	473.75	16%
	कुल	3039.72*	

8. जनवरी 2018 में मंत्रालय में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की 2017 की रिपोर्ट संख्या 12 से केवल एक पैरा लंबित था। वर्ष 2018 की सीएंडएजी की रिपोर्ट संख्या 4 में 5 और पैरे थें। इन पांचों पैरा के लिए कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत करने की स्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष	सीएंडएजी रिपोर्ट	पैरों की कुल संख्या	अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत	कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रक्रियाधीन
2017	2017 की रिपोर्ट संख्या 12	4	3	1
2018	2018 की रिपोर्ट संख्या 4	5	5	शून्य
कुल		9	8	1

इन सीएंडएजी पैरा का विवरण और स्थिति निम्नानुसार है:

सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या	पैरा नं.	विषय	स्थिति
2017 का 12	**9.3**	ईओआई टोक्यो में सरकारी लेखे के इतर प्राप्तियां और व्यय	इस पैरा के लिए पीएसी प्रक्रिया, सीएंडएजी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही शुरू हो गई थी। पीएसी के माननीय सदस्यों ने 13 अक्तूबर, 2017 को हुई सुनवाई में मंत्रालय को इस पैरा के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया था यह कार्य किया गया और उसके बाद सीएंडएजी प्रक्रिया की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रथम एटीएन 03 दिसंबर 2019 को सीएंडएजी को प्रस्तुत किया गया। एटीएन पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षित टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
2018 के 4	**7.1**	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के लिए कैम्पस का निर्माण	लेखापरीक्षा ने प्रस्तुत की गई अंतिम एटीएन स्वीकार्य की-**पैरा का निपटान हो गया है**
	7.2	मिशन और पोस्टों में कांसुली सेवाओं में राजस्व की हानि	लेखापरीक्षा ने प्रस्तुत की गई अंतिम एटीएन स्वीकार्य की-**पैरा का निपटान हो गया है**
	7.3	संपत्ति प्रबंधन में लागत वृद्धि और परिहार्य खर्च	लेखापरीक्षा ने प्रस्तुत की गई अंतिम एटीएन स्वीकार्य की-**पैरा का निपटान हो गया है**
	7.4	संयुक्त राज्य अमेरिका में आउटसोर्स सेवा प्रदाता द्वारा कूरियर शुल्क अधिक प्रभारित करना	लेखापरीक्षा ने प्रस्तुत की गई अंतिम एटीएन स्वीकार्य की-**पैरा का निपटान हो गया है**
	7.5	सीजीआई के वैंकूवर, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को में आकस्मिक स्टॉफ भर्ती	लेखापरीक्षा ने प्रस्तुत की गई अंतिम एटीएन स्वीकार्य की-**पैरा का निपटान हो गया है**

पीएसी पैरा

वर्ष	पीएसी रिपोर्ट संख्या	पैरों की कुल संख्या	प्रस्तुत किए गए एएनएस	देय एएनएस	टिप्पणियां
2018	**पीएसी रिपोर्ट संख्या 112**	7	7	-	पैरा 3 पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षित टिप्पणियों की प्रतिक्षा है

बकाया पीएसी पैरा के विवरण और स्थिति निम्नानुसार है :

लोकसभा संख्या	रिपोर्ट संख्या	पैरा संख्या	विषय	स्थिति
16	112	1	सीएंडजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 11 के पैरा 7.1 ("ओटावा और उसके वाणिज्य दूतावासों में विनिमय दर को गलत आकलन करना") और पैरा 7.2 ("एचसीआई लंदन में सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ") के संबंध में मंत्रालय के कार्यकरण में कुछ कमियों पर समिति की टिप्पणियां	मसौदा एटीएन दिसम्बर 2019 में प्रस्तुत लेखापरीक्षक की पुनरीक्षित टिप्पणियों की प्रतीक्षा है
		2	निर्धारित प्रक्रियाओं/नियमों का पालन करने में ढिलाई	मसौदा एटीएन नवंबर 2019 में प्रस्तुत लेखापरीक्षक की पुनरीक्षित टिप्पणियों की प्रतीक्षा है
		3	आंतरिक लेखा परीक्षा	मसौदा एटीएन नवंबर 2019 में प्रस्तुत लेखापरीक्षक की पुनरीक्षित टिप्पणियों की प्रतीक्षा है
		4	तकाल आधार पर अल्पवधि में वीजा	लेखा परीक्षा ने प्रस्तुत अंतिम एटीएन स्वीकार की - **पैरा का निपटान हो गया है**
		5	मिशनों पर प्रशासनिक नियंत्रण	लेखा परीक्षा ने प्रस्तुत अंतिम एटीएन स्वीकार की - **पैरा का निपटान हो गया है**
		6	अनुबंधों को अंतिम रूप देने से पहले संविदाओं को अंतिम रूप देने से पूर्व सम्यक तपरता	लेखा परीक्षा ने प्रस्तुत अंतिम एटीएन स्वीकार की - **पैरा का निपटान हो गया है**
		7	कंप्यूटरीकरण	मसौदा एटीएन नवंबर 2019 में प्रस्तुत लेखापरीक्षक की पुनरीक्षित टिप्पणियों की प्रतीक्षा है

27

संसद और समन्वय प्रभाग

संसद और समन्वय प्रभाग में निम्नलिखित प्रभाग है :

(1) संसद प्रभाग
(2) समन्वय प्रभाग
(3) शिक्षा अनुभाग
(4) निगरानी प्रकोष्ठ

संसद प्रभाग

संसद प्रभाग संसद के साथ मंत्रालय का इंटरफेस है और इस मंत्रालय के संसद से संबंधित सभी कार्यों के लिए केंद्र बिंदु है। प्रभाग ने विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन किया और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति और अन्य संसदीय समितियों के साथ मंत्रालय की बातचीत से संबंधित कार्यों का समन्वय किया।

अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान, मंत्रालय की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के साथ तीन बैठकें आयोजित की गई - (i) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच, (ii) पंजीकरण की परीक्षा अनिवासी भारतीयों के विवाह के पंजीकरण विधेयक की जांच, 2019 और (iii) भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति: संभावनाएं और सीमाएं:

जनवरी-मार्च 2020 के दौरान प्रत्याशित परामर्शदात्री समिति की बैठक और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक है।

समन्वय प्रभाग

समन्वय प्रभाग ने मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और गैर-सरकारी संगठनों सहित स्वायत्त निकायों और निजी संस्थानों के बीच संवाद का समन्वय किया। प्रभाग ने मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों की विदेश में आधिकारिक/निजी यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी का संव्यवहार किया। इसमें विदेशी भागीदारी, भारत में खेल टूर्नामेंटों जिनमें विदेशी प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया, और विदेशों में खेल टूर्नामेंट जिनमें भारतीय प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था, विदेशी सैन्य उड़ानों की लैंडिंग/ओवरफ्लाइट मंजूरी, विदेशी नौसैनिक जहाजों की आवाजाही, भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों और भारत के विभिन्न संस्थानों में दौरे/प्रशिक्षण/निरीक्षण आदि के प्रयोजन से आने वाले विदेशी विद्यवानों के छात्र वीजा को शोध वीजा में परिवर्तित करने से संबंधित मंजूरियों का संव्यवहार किया।

प्रभाग ने मंत्रीमंडल सचिवालय के ई-समीक्षा पोर्टल और शिकायत निवारण पर प्रधानमंत्री के प्रगति वीडियो कांफ्रेंसिंग में मंत्रालय की भागीदारी और कार्याक्रमों व परियोजनाओं की समीक्षा का समन्वय किया। इस प्रभाग ने पद्म पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भाषाओं के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्र पुरस्कार आदि सहित विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित समन्वित कार्य भी किया। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन, विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों के प्रभागों से प्राप्त किए जाते हैं और मंत्रालय की सिफारिशों को नोडल मंत्रालयों को भेजा जाता है। प्रभाग ने मिशनों/पोस्टों द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस, सद्भावना दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस सहित महत्वपूर्ण आयोजनों का भी समन्वय किया। आईसीसीआर का प्रशासनिक नियंत्रण समन्वय प्रभाग करता है।

अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान, समन्वय प्रभाग ने विदेश यात्राओं के लिए 2403 राजनीतिक मंजूरी, भारत में सम्मेलनों के लिए 1718 राजनीतिक मंजूरी, विदेशी गैर-अनुसूचित सैन्य उड़ानों के लिए 423 मंजूरी, विदेशी नौसैनिक जहाजों के दौरे के लिए 47 मंजूरी, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी और विदेशी खिलाड़ियों/टीमों की भारत यात्रा के लिए 176 मंजूरी प्रदान कीं।

शिक्षा अनुभाग

मंत्रालय के शिक्षा अनुभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को आवंटित सीटों के लिए स्व-वित्त पोषण योजना के अंतर्गत, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस, बी आर्क, बीई, बी फार्मेसी के लिए 57 मित्र पड़ोसी और विकासशील देशों के विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश संबंधित कार्रवाई की। भारत में स्थित बांग्लादेश और पाकिस्तान के सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासियों को भी इस योजना के अंतर्गत सीटें प्रस्तावित की जाती हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के दौरान, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 59 सीटें आवंटित की गई थीं और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 49 सीटें आवंटित की गई थीं। अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान, शिक्षा अनुभाग ने विदेशी छात्रों के संबंध में ऐच्छिक प्रशिक्षण, प्रेक्षक,

लघु/दीर्घकालिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परियोजनाओं के लिए राजनीतिक मंजूरी के 360 मामलों, विभिन्न पीजी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले विदेशी छात्रों के लिए राजनीतिक मंजूरी के 1037 मामले और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में प्रवेश के लिए विदेशी छात्रों के लिए 102 मामलों पर कार्रवाई की।

मॉनीटरन प्रकोष्ठ

मॉनीटरन प्रकोष्ठ को विदेशों द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/करारों की सत्त प्रासंगिकता और स्थिति के दृष्टिकोण से समीक्षा के समन्वय का काम सौंपा गया है। ई-समीक्षा पोर्टल पर 3126 समझौता ज्ञापनों/करारों को अपलोड किया गया। अब तक, 2995 समझौता ज्ञापनों/करारों की समीक्षा की गई है और 477 समझौता ज्ञापनों/करारों को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित किया गया है।

28

सम्मेलन प्रभाग

सम्मेलन प्रभाग भारत और विदेशों में विदेश मंत्रियों/प्रतिनिधियों की अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय भागीदारी सहित बैठकों/आयोजन/संगोष्ठी/सम्मेलनों के आयोजन में विदेश मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को सभी प्रकार की व्यवस्था प्रदान करता है। प्रोटोकॉल, प्रतिनिधियों की सुरक्षा और सटीकता की उच्चतम स्थिति से जुड़े आयोजनों की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए, सम्मेलन प्रभाग ने 08 इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों का पैनल बनाया है। आयोजन के लिए ईएमसी का चयन मंत्रालय के संबंधित प्रभाग की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। 01 अप्रैल, 2019 से 15 दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान, **सम्मेलन प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित 12 सम्मेलनों/कार्यक्रमों/बैठकों के लिए सभी व्यवस्थाओं में सहायता प्रदान की है:**

क्रम सं.	सम्मेलन/शिखर सम्मेलन/बैठक	स्थल शहर	दिनांक	कार्यक्रम का स्तर
1	21वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक (एआईएसओएम)	दिल्ली	11-12 अप्रैल 2019	सचिव
2	भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) शेरपा की बैठक	कोच्चि	3-5 मई 2019	सचिव
3	कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 के लिए ड्रा	दिल्ली	15 मई 2019	विदेश सचिव

क्रम सं.	सम्मेलन/शिखर सम्मेलन/बैठक	स्थल शहर	दिनांक	कार्यक्रम का स्तर
4	योग दिवस का प्रशिक्षण सत्र	दिल्ली	15-20 जून 2019	रेजिडेंट एचओएम
5	05 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन	दिल्ली	21 जून 2019	विदेश मंत्री
6	11वीं मेकांग गंगा सहयोग वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम)	दिल्ली	09 जुलाई 2019	सचिव
7	विदेश मंत्रालय निष्पादन स्मार्ट बोर्ड का शुभारंभ	दिल्ली	14 अगस्त 2019	विदेश मंत्री
8	आसियान देशों के लिए विभिन्न आईआईटी छात्रों के लिए फैलोशिप खोलने के लिए पोर्टल का शुभारंभ	दिल्ली	16 सितम्बर 2019	विदेश मंत्री
9	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) दिवस समारोह	दिल्ली	07 अक्तूबर 2019	विदेश मंत्री
10	रन ऑफ यूनिटी	दिल्ली	31 अक्तूबर 2019	एचएम
11	संविधान दिवस का आयोजन	दिल्ली	26 नवम्बर 2019	विदेश मंत्री
12	हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) अकादमिक समूह बैठक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आईओआरए विशेषज्ञ समूह की बैठक (ईजीएमएएसटी), हिंद महासागर संवाद-06 और दिल्ली संवाद-XI	दिल्ली	12-14 दिसम्बर, 2019	विदेश मंत्री

2. इसके अलावा, सम्मेलन प्रभाग, प्रवासी भारतीय केंद्र (पीबीके) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने 02 अक्तूबर, 2016 को किया था। प्रवासी भारतीय केंद्र अब विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित आधिकारिक आयोजनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के लिए एक प्रमुख प्रतिष्ठित सम्मेलन केंद्र बन गया है। पीबीके के उद्घाटन के बाद से राष्ट्रपति ने 3 कार्यक्रमों में भाग लिया है, उपराष्ट्रपति ने 09 कार्यक्रमों में भाग लिया है और प्रधानमंत्री ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में 15 कार्यक्रमों में भाग लिया है।

पीबीके में आयोजित कार्यक्रमों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है :-

क्रम सं.	अवधि	कार्यक्रमों की संख्या
1	अक्तूबर, 2016 से मार्च, 2017	45
2	अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018	144

क्रम सं.	अवधि	कार्यक्रमों की संख्या
3	अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019	210
4	अप्रैल, 2019 से 15 दिसंबर, 2019	50
	कुल	**449**

पीबीके में आयोजित कार्यक्रमों की संगठन-वार कुल संख्या इस प्रकार है :

क्रम सं.	कार्यक्रम आयोजक	अक्तूबर, 2016 से मार्च, 2017	अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018	अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019	अप्रैल, 2019 से 15 दिसंबर, 2019	कुल
1	विदेश मंत्रालय	23	69	89	15	196
2	अन्य मंत्रालय/विभाग	16	59	95	27	197
3	अन्य सरकारी संगठन	0	10	3	6	19
4	अन्य संगठन	6	6	23	2	37
	कुल	**45**	**144**	**210**	**50**	**449**

कार्यक्रमों की कुल संख्या केवल कार्यक्रमों को दर्शाती है, न कि प्रयुक्त सुविधाओं के दिनों की संख्या, जो बहुत अधिक है क्योंकि अनेक कार्यक्रम दो या अधिक दिनों तक चले हैं।

29

अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन

विदेश मंत्रालय का अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन प्रभाग, अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता है। अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आरईएम) के अद्‌यतन, वर्तमान सॉफ्टवेयर का प्रतिस्थापन और अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंकड़ों की अभिगम्यता के लिए वर्तमान में प्रयुक्त किए जा रहे सर्वर का नए सर्वर से प्रतिस्थापन करने के साथ-साथ पुराने डेस्कटॉपों का प्रतिस्थापन नियमित अंतराल पर किया जाता है।

रिपोर्ट की अवधि में, मंत्रालय के संबंधित विभागाध्यक्षों से उचित अनुमोदन प्राप्त करके विभिन्न प्रभागों/अनुभागों के 2315 पुराने अभिलेखों/फाइलों को नष्ट किया गया। 703 पुरानी फाइलों को नष्ट करने से पहले उनकी सूचियां विभिन्न विभागाध्यक्षों को उनके अनुमोदन के लिए भेजी गई। विभागध्यक्षों से अनुमोदन प्राप्त होने पर इन फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। लगभग 685 पुरानी वर्गीकृत फाइलों की सूचियां भी विवर्गीकरण अनुमोदन के लिए विभिन्न विभागध्यक्षों को भेजी गई हैं। 25 वर्ष से अधिक पुराने 1000 गैर-वर्तमान सार्वजनिक अभिलेखों/फाइलों को अलग करके उनके आकलन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखाकार के आकलनकर्ता को सुपर्द की गई। राष्ट्रीय अभिलेखाकार के आकलनकर्ता की मंजूरी मिलने पर स्थायी प्रकृति के अभिलेखों (1000) को संरक्षण और स्थायी अभिरक्षा के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर दिया गया है। सेवानिवृत्त राजदूतों, शोधार्थियों और विदेशों से आने वाले शिक्षाविदों जब कभी, अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन प्रभाग, से फाइलों का अवलोकन करने के लिए संपर्क करते हैं तो संबंधित विभागध्यक्षों से

अनुमोदन प्राप्त करके उन्हें इसके लिए सुकर किया गया।

11 सितंबर 2019 से 2 अक्तूबर 2019 तक 'स्वच्छता ही सेवा 2019' का आयोजन किया गया। छह कॉम्पैक्टर, जिनमें 282 रैक हैं और कुल लगभग 1,50,000 फाइलें हैं, की अभिलेख छँटाईकार ने सफाई की। इसके अतिरिक्त, संपोषणीय विकल्पों को प्रोत्साहित करके प्लास्टिक के एकबारगी प्रयोग को समाप्त करने और प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित निपटान को बढ़ावा देने के बारे में स्टाफ सदस्यों को जागरूक किया गया।

इस प्रभाग को शीघ्र ही वर्तमान स्थान से सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक नए आधुनिक स्थान पर, चल रहे नवीकरण कार्य के पूरा होने पर, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सभी संग्रहीत/पुरालेख फाइलों (संख्या में लगभग 1,50,000) को भी इस नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

30

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई)

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापकता और संख्या में वृद्धि 2019 में जारी रही। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अधिकारियों के लिए नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए। भारतीय पत्रकारों को विदेश नीति के मुद्दों पर प्रकटन देने के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी और उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों के लिए पदोन्नति से संबंधित गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और आशुलिपि प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए। इस वर्ष विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 750 की रिकॉर्ड संख्या में विदेशी राजनयिकों को प्रशिक्षित किया गया। एफएसआई की नई पहलों में त्रैमासिक समाचार पत्र *विदेश सेवा* शामिल थी।

भारत सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

I. भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के लिए कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम :

i. प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम :

मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में सिविल सेवा आधारभूत पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 2018 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षु (ओटीएस) छह माह के लंबे प्रवेशन प्रशिक्षण के लिए 10 दिसंबर 2018 को एफएसआई में शामिल हुए, जिसका समापन जो 31 मई 2019 को हुआ।

एफएसआई में अधिकारी प्रशिक्षु के प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्मुख मॉड्यूल, चरण-1 और चरण-2 शामिल थे। उन्मुख मॉड्यूल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत की विदेश नीति, प्रशासन, वित्त, लेखों और स्थापना पर मॉड्यूल शामिल थे। प्रथम चरण में द्विपक्षीय और

बहुपक्षीय संबंध, रक्षा और सुरक्षा, कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा मामलों को शामिल किया गया। द्वितीय चरण में व्यापार और आर्थिक कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजभाषा नीति, प्रोटोकॉल और आतिथ्य, रिपोर्टिंग और संचार कौशल, सांस्कृतिक कूटनीति, मीडिया प्रबंधन और सार्वजनिक कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को पड़ोसी विदेशों में भारतीय मिशनों के कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करने के लिए पड़ोसी भारतीय मिशनों में एक सप्ताह तक मिशन उन्मुख प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए एक सप्ताह तक चलने वाली भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया ताकि उन्हें देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, विरासत और पर्यटन क्षमता से बेहतर तरीके से परिचित कराया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों में राज्य प्रशिक्षण भी शामिल था जहां अधिकारी प्रशिक्षुओं को राज्य के बारे में जानने और बाहरी दुनिया के साथ राज्य के संबंधों को सुगम बनाने के बारे में समझने का अवसर मिला। अधिकारी प्रशिक्षुओं ने सीमा प्रबंधन और क्षेत्र में सेना के अधिकारियों के साथ संपर्कों को बेहतर परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए भारतीय सेना के साथ एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

अधिकारी प्रशिक्षुओं के 2018 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और कुंभ मेला (1 सप्ताह) में विशेष प्रोटोकॉल संयोजन में तैनात किया गया था। उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में रायसीना वार्ता (2 दिन) में भाग लिया।

प्रशिक्षण अंत: संवादी व्याख्यान, पैनल चर्चा, अनुकरण अभ्यास, भूमिका निभाने, मामला अध्ययन, सफलता की गाथाओं, कार्यशालाओं के माध्यम से प्रदान किया गया था।

पूर्व विदेश मंत्री की अध्यक्षता में 16 मई 2019 को एक समापन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर 2018 बैच के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु को विदेश मंत्री स्वर्ण पदक, दल भावना के लिए राज्यमंत्री रजत पदक, सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध के लिए राजदूत विमल सान्याल स्मारक पदक, सर्वश्रेष्ठ समिति के लिए ट्रॉफी और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की गई।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं का 2019 बैच वर्तमान में मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। 30 भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं ने 09 दिसंबर 2019 को एफएसआई में अपना प्रशिक्षण प्रारंभ किया।

ii. आजीविका-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-1:

32 उप सचिव (डीएस) /अवर सचिव (यूएस) स्तर के अधिकारियों के लिए आजीविका-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-1 निम्नलिखित सारणी के अनुसार 16 सितंबर-4 अक्तूबर 2019 को आयोजित किया गया था :

क्र. सं.	अवधि	मॉड्यूल	संस्थान का नाम
1	16-20 सितम्बर 2019	विदेश नीति	विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली
2	23-24 सितम्बर 2019	घरेलू नीति	विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली
3	26-27 सितम्बर 2019	राज्य की यात्रा	आवंटित राज्य में
4	30 सितम्बर - 04 अक्तूबर 2019	प्रबंधन	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद

iii. आजीविका-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-II:

आजीविका-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-II निम्नलिखित सारणी के अनुसार 9 सितंबर-4 अक्तूबर 2019 से 2004 और 2005 बैच के 22 आईएफएस अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था:

क्र.सं.	अवधि	मॉड्यूल	संस्थान का नाम
1.	9-13 सितम्बर 2019	कूटनीति	फ्लेचर स्कूल, टफ्स यूनिवर्सिटी, अमेरिका
2.	16-20 सितम्बर 2019	प्रबंधन	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद
3.	23-24 सितम्बर 2019	साइबर सुरक्षा	गुजरात न्याय विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर
4.	26-28 सितम्बर 2019	राजकीय यात्रा	आबंटित राज्यों में
5.	30 सितम्बर -4 अक्तूबर 2019	विदेश नीति	विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली

iv. आजीविका-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-III:

1992-1995 बैच के 22 भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों के लिए निम्नलिखित सारणी के अनुसार 29 अक्तूबर-12 नवबंर, 2019 को जीविका-मध्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया:

क्र.सं.	अवधि	मॉड्यूल	संस्थान का नाम
1.	29 अक्तूबर -01 नवम्बर 2019	विदेश नीति	विदेश सेवा संस्थान
2.	4-8 नवम्बर 2019	प्रबंधन	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद
3.	11-12 नवम्बर 2019	राज्य की यात्रा	आवंटित राज्य में

II कार्यात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

v. वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

अफ्रीका और अमेरिका क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रतिनिधियों (सीआरएस) के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम 08-12 अप्रैल 2019 आयोजित किया गया था। विदेश सेवा संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में 19 वाणिज्यिकी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

vi. ऑनलाइन आरटीआई पर कार्यशाला :

जवाहरलाल नेहरू भवन और विदेश सेवा संस्थान में क्रमश: 09 जुलाई 2019 और 21 अगस्त 2019 को मंत्रालय के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन आरटीआई पर दो विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

III विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम:

vii. रक्षा अताशे के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

15 रक्षा अताशे के लिए 10-14 जून 2019 को संलग्नों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

viii. विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

विदेश सेवा संस्थान में 1-2 मई 2019 को विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के 34 निदेशकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

ix. भारतीय मीडिया के लिए विदेश नीति पर विशेष पाठ्यक्रम :

विदेश सेवा संस्थान में 16-22 अक्तूबर 2019 को भारतीय मीडिया के लिए विदेश नीति पर एक विशेष परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मीडिया से 36 लोगों ने भाग लिया।

x. विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के कला प्रदर्शन शिक्षकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान में 18-22 नवंबर 2019 को आईसीसीआर के 29 कला प्रदर्शन शिक्षकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

IV गैर-प्रतिनिधित्व श्रेणी (एनआरजी) प्रशिक्षण कार्यक्रम:

एनआरजी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

- एसएसए, जेएसए और स्टेनोग्राफर के लिए पदोन्नति संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम 8-12 अप्रैल 2019 को आयोजित किया गया जिसमें 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- वैयक्तिक सचिवों के लिए पदोन्नति संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 से 31 मई 2019 को आयोजित किया गया जिसमें 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- अनुभाग अधिकारियों के लिए पदोन्नति संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 मई से 10 जून तक आयोजित किया गया जिसमें 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- जेम कार्यशाला का आयोजन 4 जून, 2019 को किया गया जिसमें 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 14-17 जून 2019 को किया गया जिसमें 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- एमटीएस और स्टाफ कार ड्राइवरों के लिए पदोन्नति संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 17 से 21 जून 2019 को किया गया जिसमें में 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 73वां आईएमएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 18 जून-15 जुलाई 2019 को किया गया जिसमें 99 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 23 जुलाई 2019 को आयोजित 73वें आईएमएएस पुन: परीक्षा में 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- आईवीएफआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 29 जुलाई-2 अगस्त 2019 को किया गया जिसमें 106 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- एओओ के लिए 16 अगस्त 2019 को आयोजित त्रैमासिक टाइपिंग परीक्षा में 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 19 से 20 अगस्त 2019 का आयोजित लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 74वां आईएमए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 21-27 अगस्त 2019 को किया गया जिसमें 59 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 23 सितंबर 2019 को आयोजित 74वें आईएमए पुन: परीक्षा में 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- आईवीएफआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 5-8 नवंबर 2019 को किया गया जिसमें 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 21 नवंबर 2019 को पीएएस और स्टेनोग्राफर के लिए आयोजित अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा में 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान ने 2019 में विदेशी राजनयिकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजित किए :-

- विदेशी राजनयिकों के लिए 13 मार्च-12 अप्रैल 2019 को 67वां व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें 48 राजनयिकों ने भाग लिया।
- मोरक्को के राजनयिकों के लिए 15-27 अप्रैल 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 16 राजनयिकों ने भाग लिया।
- सेनेगल के राजनयिकों के लिए 15-27 अप्रैल 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 10 राजनयिकों ने भाग लिया।
- अंगोलन राजनयिकों के लिए 6-18 मई 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 6 राजनयिकों ने भाग लिया।
- बोत्सवाना से राजनयिकों के लिए 6-18 मई 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 18 राजनयिकों ने भाग लिया।
- इक्वेटोरियल गिनी के राजनयिकों के लिए 6-18 मई 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 4 राजनयिकों ने भाग लिया।
- लाइबेरिया राजनयिकों के लिए 6-18 मई 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 20 राजनयिकों ने भाग लिया।
- साओ टोम और प्रिंसिप राजनयिकों के लिए 6-18 मई 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 4 राजनयिकों ने भाग लिया।
- मिस्र के राजनयिकों के लिए 10-22 जून 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 13 राजनयिकों ने भाग लिया।
- मध्य एशियाई देशों के राजनयिकों के लिए 24 जून-6 जुलाई 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 29 राजनयिकों ने भाग लिया।
- मालदीव के राजनयिकों के लिए 24 जून-6 जुलाई 2019 को द्वितीय विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 8 राजनयिकों ने भाग लिया।
- अरब देशों की लीग के लिए 22-29 जुलाई 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 16 राजनयिकों ने भाग लिया।
- कैरिकॉम के लिए 12-23 अगस्त 2019 को द्वितीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 23 राजनयिकों ने भाग लिया।
- रेजिडेंट हेड्स ऑफ मिशन (एचओएम) के लिए 19-23 अगस्त 2019 को तृतीय परिचय कार्यक्रम जिसमें 17 एचओएम ने भाग लिया।
- इराकी राजनयिकों के लिए 26 अगस्त-7 सितंबर 2019 को तृतीय विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 29 राजनयिकों ने भाग लिया।
- फिलिस्तीनी राजनयिकों के लिए 2-14 सितंबर 2019 को द्वितीय विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 15 राजनयिकों ने भाग लिया।
- लीबिया के राजनयिकों के लिए 6-21 सितंबर 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 15 राजनयिकों ने भाग लिया।
- विदेशी राजनयिकों के लिए 16 सितंबर-11 अक्तूबर 2019 को 68वां व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें 55 राजनयिकों ने भाग लिया।
- एएसईएम राजनयिकों के लिए 14-21 अक्तूबर 2019 को 5वां विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 20 राजनयिकों ने भाग लिया।
- आसियान राजनयिकों के लिए 14-26 अक्तूबर 2019 को 13वां विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 12 राजनयिकों ने भाग लिया।
- मंगोलिया से राजनयिकों के लिए प्रथम विशेष पाठ्यक्रम 28 अक्तूबर-9 नवंबर 2019 को जिसमें 25 राजनयिकों ने भाग लिया।

- मालदीव के राजनयिकों के लिए तृतीय विशेष पाठ्यक्रम 28 अक्तूबर-9 नवंबर 2019, जिसमें 5 राजनयिकों ने भाग लिया।
- डोमिनिकन गणराज्य के राजनयिकों के लिए 28 अक्तूबर-9 नवंबर 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 8 राजनयिकों ने भाग लिया।
- अफगान राजनयिकों के लिए द्वितीय भारत-चीन संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम 11-23 नवंबर 2019, जिसमें 10 राजनयिकों ने भाग लिया।
- बेनीस राजनयिकों के लिए 25 नवंबर-7 दिसंबर 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 7 राजनयिकों ने भाग लिया।
- गैबोनीज राजनयिकों के लिए 25 नवंबर-7 दिसंबर 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 13 राजनयिकों ने भाग लिया।
- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राजनयिकों के लिए 25 नवंबर-7 दिसंबर 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 11 राजनयिकों ने भाग लिया।
- कोटे डी आइवर से राजनयिकों के लिए 25 नवंबर-7 दिसंबर 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 10 राजनयिकों ने भाग लिया।
- कैमरून के राजनयिकों के लिए प्रथम विशेष पाठ्यक्रम 25 नवंबर-7 दिसंबर 2019 को जिसमें 10 राजनयिकों ने भाग लिया।
- केन्याई राजनयिकों के लिए 25 नवंबर-7 दिसंबर 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 10 राजनयिकों ने भाग लिया।
- नामीबिया राजनयिकों के लिए 30 नवंबर-13 दिसंबर 2019 को प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 20 राजनयिकों ने भाग लिया।
- बांग्लादेशी राजनयिकों के लिए 9-22 दिसंबर 2019 को चतुर्थ विशेष पाठ्यक्रम जिसमें 24 राजनयिकों ने भाग लिया।

समझौता ज्ञापन

विदेश सेवा संस्थान ने विदेशों में निम्नलिखित समकक्ष संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए :

- 21 अगस्त 2019 को जाम्बिया इंस्टिट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल स्टडीज, विदेश मंत्रालय, जाम्बिया गणराज्य.
- 6 सितंबर 2019 को इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स, विदेश मामलों के मंत्रालय, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
- 10 अक्तूबर 2019 को देववोंग से वरोपाकर्ण इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, थाईलैंड साम्राज्य
- 29 अक्तूबर 2019 को सऊदी अरब सम्राज्य में विदेश मंत्रालय के प्रिंस अल फैसल इंस्टिट्यूट ऑफ डिप्लोमेटिक स्टडीज।
- 13 अक्तूबर 2019 को सिएरा लियोन गणराज्य का विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय।

भारत को जानिए कार्यक्रम (के.आई.पी) और अन्य कार्यक्रम/यात्राएं

विदेश सेवा संस्थान ने भारतीय अधिकारियों/कार्मिकों और विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, भारत को जानिए कार्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया :

- 2 अगस्त 2019 को 54वें भारत को जानिए कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया; 24 सितंबर 2019 को 55वें भारत को जानिए कार्यक्रम में 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया।; 17 अक्तूबर

2019 को 56वें भारत को जानिए कार्यक्रम में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया; 6 नवंबर 2019 को 57वें भारत को जानिए कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया; 2 दिसंबर 2019 को 58वें भारत को जानिए कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- पांच मध्य एशियाई देशों (कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान) के 20 पत्रकारों/संपादकों ने 24 अप्रैल 2019 को एक अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए विदेश सेवा संस्थान का दौरा किया।
- अफगानिस्तान के 20 पत्रकारों/संपादकों ने 21 जून 2019 को एक अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए विदेश सेवा संस्थान का दौरा किया।
- मलेशिया के इंस्टिट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशंस (आईडीएफआर) से डिप्लोमेसी में डिप्लोमा के लिए अध्ययन कर रहे 7 मलेशियाई राजनयिकों ने 29 जुलाई 2019 को विदेश सेवा संस्थान का दौरा किया।
- चेक गणराज्य के विदेश मंत्रालय की राजनयिक अकादमी के निदेशक ने 01 अगस्त 2019 को विदेश सेवा संस्थानका दौरा किया
- विदेश मंत्रालय और मलावी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 20 अगस्त 2019 को विदेश सेवा संस्थान का दौरा किया था।
- दक्षिण केंद्र, जिनेवा के कार्यकारी निदेशक ने 22 अगस्त 2019 को विदेश सेवा संस्थान का दौरा किया।
- चाईना फॉरन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने 11 नवंबर 2019 को विदेश सेवा संस्थान का दौरा किया था। उनके साथ सीएफएयू के विदेश मामलों के कार्यालय के निदेशक और नई दिल्ली में चीन के दूतावास के राजनयिक भी थे। सीएफएयू के अध्यक्ष ने अफगानिस्तान से राजनयिकों के लिए द्वितीय भारत-चीन संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अफगान राजनयिकों को संबोधित किया।

भारतीय विदेश सेवा के 2018 बैच के अधिकारी प्रशिक्षु प्रधान मंत्री श्री मोदी से मुलाकात करते हुए।

31

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

प्रशासन:

परिषद् ने अपनी स्थापना के 69वें वर्ष में पहली बार आईसीसीआर मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों कुछ मिशनों/ पोस्टों में और 09 अप्रैल, 2019 को आईसीसीआर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जिसमें अपने संस्थापक राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आजाद की 131 वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। आईसीसीआर की नई वेबसाइट 24 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई है।

परिषद्, 22 फरवरी 2020 को अपने संस्थापक राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आजाद की 62वीं पुण्यतिथि मौलाना अबुल कलाम आजाद (जामा मस्जिद से सटी दिल्ली) की मजार पर मनाएगी।

छात्रवृत्ति:

आईसीसीआर ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दौरान, विदेशी नागरिकों को भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक-पूर्व /स्नातकोत्तर/एम.फिल/पीएच.डी स्तर के पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3940 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रस्तावित किए। आईसीसीआर ने, भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन करने की मंशा रखने वाले विदेशी नागरिकों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त करने और प्रक्रिया

करने के लिए एडमिशन टू एलुमनी (ए2ए) पोर्टल प्रारम्भ किया। छात्रवृत्ति के 3861 स्लॉट के लिए, 2632 अनंतिम प्रवेश पुष्टिओं को भारतीय मिशनों को भेजा गया है। छात्रवृत्ति मॉड्यूल के डिजिटलीकरण से तत्परता आयी, कार्मिकों को विभिन्न विकल्प प्राप्त हुए और पारदर्शिता बनाए रखी गई।

आईसीसीआर ने अपने कल्याणकारी कार्यकलाप के भाग के रूप में, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नए भर्ती विदेशी छात्रों के लिए 13 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद में भी अक्तूबर, नवंबर, 2019 में उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

आईसीसीआर स्थापना दिवस का आयोजन 09 अप्रैल 2019 को दिल्ली में मुख्यालय में और 84 विदेशी मिशनों में किया गया, जिसका केंद्र बिंदु आईसीसीआर के पूर्व छात्र थे। आईसीसीआर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पढ़ने वाले आइसीएसआर के विदेशी छात्रों को अनूठी लद्दाखी संस्कृति से परिचित कराने के लिए लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसायटी के साथ सहयोग से दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में 18 जनवरी, 2020 को लोसार महोत्सव का आयोजन करेगी।

कुलपति सम्मेलन पर वार्षिक सम्मेलन 28-30 जनवरी, 2020 को पुणे में आयोजित किया जाना है।

शिक्षण पीठ:

आईसीसीआर ने परस्पर सहमत समझौता ज्ञापनों (परिषद् और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच) के आधार पर विश्व भर में 65 शिक्षण पीठ स्थापित की हैं। शिक्षण पीठ की स्थापना के लिए 04 समझौता ज्ञापनों के नवीनीकरण और 01 नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईसीसीआर पारस्परिक रूप से सहमत समझौता ज्ञापन (परिषद् और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच) के आधार पर विश्व भर में 65 चेयर का संचालन कर रहा है। दिसंबर, 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आईसीसीआर चेयर से संबंधित एक नए समझौता ज्ञापन और 03 समझौता ज्ञापन (नवीनीकरण) पर हस्ताक्षर होने का अनुमान है।

सम्मेलन और संगोष्ठी :

03 अध्येताओं को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए क्रमशः मई और जून के माह में स्टॉकहोम, टोक्यो और अंकारा की यात्रा करने के लिए यात्रा अनुदान प्रदान किया गया। 03 अध्येताओं ने उर्दू भाषी संघ द्वारा नवंबर, 2019 में मिर्जा गलिब की 150 वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मॉरीशस का दौरा किया।

सम्मेलन और संगोष्ठी:

आईसीसीआर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हैं : (i) भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आरसी लाहोटी द्वारा द्वितीय पं. दीन दयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय स्मारक व्याख्यान का 21 मई 2019 को नई दिल्ली में आयोजन (ii) आयुष मंत्रालय और ज्ञान साझेदार - एसवीवाईएएसए के सहयोग से, लंदन, यू.के.में 22 जून 2019 को आयोजित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन (iii) पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र का भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में 16 अगस्त 2019 को अनावरण (iv) प्रवासी भारतीय केंद्र ने “श्री गुरु नानक

देव जी के उपदेश और विश्व के कल्याण में सिख धर्म का योगदान" पर अंतर्राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी का 6 नवंबर 2019 को आयोजन किया जिसके बाद पटना, अमृतसर और नांदेड़ में तीन तख्तों का 7-10 नवंबर 2019 को दौरा किया गया (v) भारत को शिक्षा केंद्र बनाने के लिए 16-17 जनवरी, 2020 को 'डेस्टिनेशन इंडिया कॉन्फ्रेंस' और मार्च, 2020 में चौथी 'इंडोलॉजी कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया गया।

(i) जम्मू-कश्मीर विचार मंच ने "गाष्टारुख VII - द केपी आइडल (फाइनल्स) का जून 2019 में नई दिल्ली में आयोजन किया

(ii) आईसीसीआर के अध्यक्ष ने "संवाद III : मतभेद परिहार पर वैश्विक हिंदी-बौद्ध पहल और पर्यावरण बोध" में भाग लेने के लिए सितंबर 2019 में मंगोलिया का दौरा किया

(iii) महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में व्याख्यान देने के लिए 03 अध्येताओं को अक्तूबर 2019 में स्पेन, थाईलैंड और जर्मनी भेजा गया (iv) श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में व्याख्यान देने के लिए 02 अध्येताओं को नवंबर 2019 में मलेशिया और थाईलैंड भेजा गया।

संसदीय आश्वासन के अनुपालन में रोमा केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद् (एआरएसपी) और आईसीसीआर के बीच जुलाई 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईसीसीआर, सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (स्थान साझेदार) और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (ज्ञान साझेदार) के सहयोग से पुणे में 28-29 जनवरी 2020 को **"डेस्टिनेशन इंडिया-मेकिंग द प्रिफर्ड हब ऑफ एजूकेशन"** का आयोजन कर रहा है।

चौथा इंडोलॉजी सम्मेलन "री-एग्जामिनिंग इंडोलॉजी: रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट" का आयोजन भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) शिमला के सहयोग से आईआईसीएस, शिमला में 13-15 मार्च, 2020 को आईसीसीआर द्वारा किया जाएगा।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक विद्वान की 18-21 जनवरी, 2020 को जिबूती की यात्रा को प्रायोजित करना।

विदेशी प्रतिभागियों पर किए गए खर्च के संबंध में 2.00 लाख रुपये का अनुमोदन करके हैदराबाद में 8 से 15 दिसंबर 2019 तक **5वीं फिल्म संरक्षण एवं बहाली कार्यशाला इंडिया 2019** का समर्थन किया।

विदेशी प्रतिभागी को एक यात्रा अनुदान प्रदान करके **वैदिक-गणित 2019 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** का समर्थन किया। (22-24 दिसंबर 2019)।

हंस राज कॉलेज द्वारा (10-11 जनवरी, 2020) को आयोजित किए जाने वाले **अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन** में विदेशी प्रतिभागियों को तीन यात्रा अनुदान दिया जाएगा।

इंडिया थिंक काउंसिल द्वारा विदेशी प्रतिभागियों को दो यात्रा अनुदान प्रदान करके **"श्री राम: ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल"** पर अयोध्या में 21 जनवरी, 2020 को एक दिवसीय सम्मेलन का समर्थन किया गया।

जबलपुर में विदेशी प्रतिभागियों को छह यात्रा अनुदान प्रदान करके **दूसरे रामायण सम्मेलन** का समर्थन (26-28 जनवरी 2020)

पुरस्कार :

भारत-जर्मन मैत्री को मजबूत करने की दिशा में अद्वितीय योगदान के लिए आईसीसीआर के अध्यक्ष द्वारा 9 दिसंबर, 2019 को सुश्री एंटेजे स्टिबिट्ज़ और प्रो डॉ हीके ओबर्लिन को क्रमशः **वर्ष 2018 और 2019 के लिए गिसेला बॉन पुरस्का**र प्रदान किए गए।

आईसीसीआर विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार 2019 28 जनवरी 2020 का आयोजन सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (मानद विश्वविद्यालय) कैंपस, लावले, पुणे, महाराष्ट्र में किया जाना है।

आईसीसीआर विश्व संस्कृत पुरस्कार 2019 और विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2018 और 2019 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाना है। दोनों पुरस्कार समारोहों के आयोजन के लिए तिथियों का निर्धारण नहीं हुआ है।

हिंदी :

आईसीसीआर मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा (16-30 सितंबर 2019) का आयोजन किया गया जिसमें एमटीएस कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं - निबंध, हिंदी टाइपिंग, सामान्य हिंदी, हिंदी कमेंट्री, पत्र लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी और डिक्टेशन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 26 सितंबर 2019 को आजाद भवन में हिंदी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। दिल्ली में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों और परिषद् के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी में काव्य पाठ किया। परिषद् ने 30 सितंबर 2019 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया।

भारतीय उच्चायोग, लंदन द्वारा लंदन (यूके) में 19 सितंबर 2019 से 05 अक्तूबर 2019 तक आयोजित विराट हिंदी कवि सम्मेलन में परिषद् ने 07 कवियों की हवाई यात्रा प्रायोजित की। परिषद् ने परिषद् की हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और दिसंबर 2019 में आजाद भवन में हिंदी टिप्पण और पत्र लेखन विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। परिषद् ने 9-11 जनवरी 2020 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन प्रवासी विद्वानों को प्रायोजित किया है।

हिंदी द्विमासिक पत्रिका 'गगनांचल' वर्ष 42 अंक 5-6 (सितंबर-दिसंबर) 2019 और 43 अंक 01 (जनवरी-फरवरी) 2020 फरवरी-मार्च, 2020 के दौरान मुद्रित किया जाएगा। मार्च 2020 में एक हिंदी कार्यशाला और परिषद् की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है।

भारतीय सांस्कृतिक केंद्र :

परिषद् का मुख्य उद्देश्य भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति की जागरूकता और सराहना को प्रेरित करने के प्रयोजन से भारत और अन्य देशों के बीच परस्पर तालमेल बनाना और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना, पुनर्जीवित करना और सशक्त करना है।

परिषद् विश्व के विभिन्न भागों में 37 पूर्ण भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों (आईसीसीएस) का संचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आईसीसीआर, वलाडोलिड, स्पेन और बुसान, दक्षिण कोरिया में 'पीपीपी' मॉडल (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) पर स्थानीय समर्थन से स्थापित दो देशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों को सहायता प्रदान कर रही है। विश्व स्तर पर योग, वेद और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए परिषद् ने विभिन्न मिशनों/केंद्रों/भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों में भारतीय संस्कृति के शिक्षकों और युनान मिंज़ू विश्वविद्यालय, कुनमिंग, चीन में योग के दो सहायक प्रोफेसरों को तैनात किया है। परिषद् ने भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, हिन्दुस्तानी/कर्णाटक गायन, तबला और हिंदी भाषा आदि के भारतीय शिक्षकों की अपने भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों में तैनाती की है। इसके अलावा, परिषद् ने जहां आईसीसीआर के सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, वहां भी योग और भारतीय नृत्य के शिक्षकों को स्त्रोत कर्मियों के रूप में तैनात किया है। परिषद् ने विदेशों में 172 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2019 के आयोजन की सुविधा प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 समारोह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रुपये 7.78 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

अभ्यागत कार्यक्रम :

परिषद् ने निम्नलिखित को आमंत्रित किया :

- 04 विशिष्ट अभ्यागत कार्यक्रमों के अंतर्गत ओमान, अजरबेजान, डोमिनिकन गणराज्य और सीरिया से राजनीति, कला और संस्कृति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 04 सुप्रसिद्ध हस्तियों को आमंत्रित किया गया।
- अकादमिक अभ्यागत कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, नामीबिया, नाइजीरिया,

उजबेकिस्तान, स्पेन और पुर्तगाल के 07 प्रख्यात शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया।

- इस अभ्यागत कार्यक्रम के अंतर्गत डीपीआर कोरिया से हिंदी शिक्षण के 09 छात्रों को आमंत्रित किया गया।
- दशो कुंजांग वांगदी, सदस्य, रॉयल रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल, महामहिम के सचिवालय, भूटान को 24 दिसंबर 2019 से 2 जनवरी 2020 तक **विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम** के अंतर्गत भारत की यात्रा करेगें।

जनवरी से मार्च 2020 तक विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया है :-

- सीनेटर पीटर बोह्म, सीनेटर, ओंटारियो, कनाडा से भारत के लिए 20-29 फरवरी 2020 अथवा 28 फरवरी- 08 मार्च 2020.
- मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति श्री एन एनखबायर 07 से 16 मार्च 2020 तक।
- सुश्री कॉय कोल्स जेंस, हेरिटेज फाउंडेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष, मार्च, 2020 में।
- मार्च 2020 के दौरान न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री हेलेन क्लार्क।

प्रो कियू योंग हुई, सिचुआन विश्वविद्यालय, चेंग्दू में विशिष्ट समकालीन धर्म विशेषत: भारतीय धर्म के विद्वान 16 से 25 दिसंबर 2019 तक अकादमिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दौरा करेगें।

जनवरी-मार्च 2020 के दौरान अकादमिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रख्यात शिक्षाविदों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया है :-

- सुश्री मारिसोल शुल्ज मनौत, महानिदेशक, ग्वाडलहारा, मेक्सिको का पुस्तक मेला 21 से 30 जनवरी, 2020 तक।
- प्रो क्लाऊस लारेस, रिचर्ड एम क्रास्नो, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय, चैपल हिल, अमेरीका 03 - 12 फरवरी, 2020।
- प्रो एलेजैंड्रो गारे, ग्वाटेमाल शिक्षाविद का मायान संस्कृति और मान्यताओं, को बढ़ावा देने के लिए मायान देवी के बारे में व्याख्यान, ग्वाटेमाल, 10-18 फरवरी, 2020।
- प्रो फाम क्वांग मिंह, रेक्टर, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विश्वविद्यालय, वियतनाम 17-25 फरवरी, 2020।
- प्रो ओ न्यामदाववा, निदेशक, भारतीय अध्ययन केंद्र और मंगोलिया के पूर्व राजदूत, 06 से 16 मार्च, 2020
- डॉ जस्टिन वैलेंटिन, कुलपति, सेशेल्स विश्वविद्यालय 20 से 30 मार्च, 2020।
- प्रो सेल्विन कुडजो, अकादमिक, विद्वान, प्रोफेसर, अफ्रीकी अध्ययन, वेलेस्ले कॉलेज मार्च/अप्रैल 2020 के दौरान।

निवर्तमान सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल :

कला की विभिन्न शैलियों के कुल 69 समूहों को प्रायोजित किया गया जिनमें 17 लोक संगीत और नृत्य; 19 शास्त्रीय नृत्य; 2 समकालीन नृत्य; 3 कव्वाली संगीत; 09 वाद्य संगीत; 04 बॉलीवुड; 04 फ्यूजन; 01 जैज; 02 कर्णाटक और हिंदुस्तानी गायन के प्रत्येक के 02; 06 भक्ति गायन संगीत के समूह शामिल थे। भारत के 20 अलग-अलग राज्यों के इन कलाकारों ने विदेशों में भारत की संस्कृति प्रदर्शित करने के लिए 62 देशों का दौरा किया। कुल 05 समूहों को प्रायोजित किया गया था जिसमें 02 लोक संगीत और नृत्य समूहों के साथ कला रूपों की विभिन्न शैलियों को शामिल किया गया था; 01 वाद्य समूह; 01 पर्कशन समूह; 01 रागी (भक्ति) समूह। उन्हें दिसंबर 2019 के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन देने के लिए भारत के 04 राज्यों से 08 देशों में भेजा गया था।

09 राज्यों के 16 समूहों को 04 लोक संगीत और नृत्य समूहों के साथ कला रूपों की विभिन्न शैलियों को शामिल करते हुए 23 देशों में सांस्कृतिक प्रदर्शन देने का कार्यक्रम है; 04 वाद्य समूह; 02 कव्वाली समूह;

01 कठपुतली समूह; 01 कथक समूह; 01 भांगड़ा समूह; 01 बॉलीवुड समूह; 01 भोजपुरी ग्रुप; और 01 जनवरी मार्च 2020 से भक्ति समूह।

आगंतुक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल :

परिषद् ने 15 विदेशी समूहों द्वारा 30 प्रदर्शन और भारतीय कलाकारों द्वारा 8 प्रदर्शन का आयोजन किया। अपने नियमित रामायण और लैटिन अमेरिका त्योहारों के अलावा, आईसीसीआर ने 13-21 नवंबर, 2019 को "इजिप्ट बाई द गंगा" महोत्सव की भी मेजबानी की। परिषद् ने नई दिल्ली के कामनी ऑडिटोरियम में 2-4 दिसंबर, 2019 से छठा अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य एवं संगीत समारोह आयोजित किया। दिल्ली के अलावा 11 देशों के प्रतिभागी समूहों ने भी 11 अन्य भारतीय शहरों में प्रदर्शन किया। परिषद् ने जनवरी, 2020 में दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में लियोन, स्पेन ईथ डॉ एल सुब्रमण्यम के सिम्फनी आर्केस्ट्रा द्वारा एक संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया।

परिषद् ने मंजूरी दे दी है। विश्व शांति संगीत समारोह "सुर जहां" के आयोजन में सहयोगी उद्यम फरवरी, 2020 में कोलकाता, गोवा और जयपुर में आयोजित किया जाएगा। आईसीसीआर ने 11 फरवरी, 2020 को बांसुरी कंसर्ट आयोजित करने के लिए पुर्तगाल के दूतावास के साथ सहयोग करने को भी मंजूरी दे दी है।

प्रदर्शनी :

परिषद् ने विभिन्न प्रारूपों जैसेकि पैंटिंग, फोटोग्राफ और वस्त्रों पर विदेशों में 7 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। परिषद् ने विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 19 कलाकारों को यात्रा अनुदान प्रदान किया। इसके अलावा, परिषद् ने 22-26 मई, 2019 के दौरान पेरिस के ग्रैंड पालिस में आयोजित रेवेलेशन्स - इंटरनेशनल फाइन क्राफ्ट एंड क्रिएशन बिएननेल में भाग लेने के लिए दिल्ली-पेरिस-दिल्ली के रास्ते कला कार्यों के परिवहन के लिए सुश्री गुंजन गुप्ता को सहायता प्रदान की। कोलंबो, श्रीलंका से जनवरी, 2020 में श्री बेनॉय के बहल द्वारा बौद्ध स्थलों/विरासत की प्रदर्शनी के लिए प्राप्त प्रस्ताव।

मिंस्क, बेलारूस से दो प्रदर्शनियों के लिए प्राप्त एक प्रस्ताव अर्थात् "भारतीय वस्त्रों की वस्त्रराम-अश्वम दुनिया" और "मंदिर, किले और महल: भारतीय वास्तुकला के 2000 साल" इंटैच द्वारा फरवरी, 2020 में।

फरवरी-मार्च, 2020 के दौरान मालदीव के माले में एक एक्टर वर्कशॉप का आयोजन किया जाना है। कार्यशाला में एनएसडी से तीन विशेषज्ञ भाग लेंगे।

जनवरी-फरवरी, 2020 के दौरान सुवा से विलिंगटन के लिए एक प्रदर्शनी "जैसलमेर येलो" भेजी जानी है।

अर्ध-प्रतिमा और मूर्ति :

आईसीसीआर ने गांधी@150 के उपलक्ष्य में 40 देशों में स्थापना के लिए महात्मा गांधी की 29 कांस्य की अर्ध-प्रतिमाएं और 17 मूर्तियां प्रदान कीं। परिषद् ने इक्वाडोर, कोलंबिया में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की एक शैलीबद्ध प्रतिमा और अमेरिका के ग्लूसेस्टर, बोस्टन में स्थापना के लिए स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया। परिषद् ने दिसंबर, 2019 में न्यूयॉर्क के अम्हेस्ट में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा भेजी थी। विचाराधीन में अन्य प्रस्ताव हैं :

- जनवरी, 2020 में कजाकिस्तान के अस्ताना के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव (पुष्टि का इंतजार)।
- जॉर्जिया के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव (ईओआई, येरेवन, आर्मेनिया) की पुष्टि फरवरी, 2020 में प्रतीक्षा की जा रही है।
- मुंडुक (बाली, इंडोनेशिया) के लिए महात्मा गांधी का प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव की फरवरी, 2020 में पुष्टि की प्रतीक्षा है।
- मार्च, 2020 में न्यूयॉर्क के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनुभाग

क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने और सुदृढ़ करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह देने/मार्गदर्शन करने के प्रयोजन से आईसीसीआर के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 4 अप्रैल, 2019 को आईसीसीआर, आजाद भवन में 14 क्षेत्रीय कार्यालयों की आईसीसीआर क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के सदस्यों के लिए एक अभिविन्यास/कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य आरओ के कामकाज में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए अपने आरओ को सलाह देना और मार्गदर्शन करना था। क्षेत्रीय निदेशकों की वार्षिक बैठक 28-30 जनवरी 2020 की अवधि के दौरान पुणे में आयोजित की जानी है।

उपर्युक्त के अलावा संयुक्त सहयोग के लिए परिषद और केरल सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा रहा है।

महानिदेशक, आईसीसीआर की अध्यक्षता में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के रेजिडेंट कमिश्नरों की एक बैठक 11 अक्तूबर, 2019 को आईसीसीआर, आजाद भवन में हुई। इस बैठक का उद्देश्य यह पता लगाना और इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था कि राज्य सरकारें/केंद्र सरकार किस प्रकार परिषद् की गतिविधियों में सहयोग कर सकती हैं।

डॉ. हेइक ओबेरलिन को डॉ. विनय सहस्रबुद्धे (अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद) द्वारा वर्ष 2019 के लिए भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद गिसेला बॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री अखिलेश मिश्रा (महानिदेशक, भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद), डॉ. एल. सुब्रमण्यम, सुश्री कविता कृष्णमूर्ति और कैस्टिले और लियोन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के निदेशक द्वारा संगीत कार्यक्रम का उद्घाटन

32

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

आईसीडब्ल्यूए ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और व्यापक वैश्विक भू-सामरिक परिवेश में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा विकास में शोध और अध्ययन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है। इनके निष्कर्ष का प्रचार-प्रसार सप्रू हाउस पेपर्स, इश्यू ब्रीफ, पॉलिसी ब्रीफ और व्यू पॉइंट्स, डिस्कशन पेपर्स, शोध लेख (एआइसीटी) के रूप में किया गया जिनका आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर प्रकाशन किया गया है। इसके अतिरिक्त आईसीडब्ल्यूए ने अपने अकादमिक आउटफिट्स को हिंदी में अनुवाद करने की प्रक्रिया जारी रखी जिन्हें नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है। इसके अलावा, अप्रैल 2019 के बाद से पुस्तकों और सप्रू हाउस पेपर का प्रकाशन किया गया है। परिषद् की वेबसाइट को और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए इसे दुरुस्त करने के प्रयास चल रहे हैं। यह अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। आईसीडब्ल्यूए ने आम जनता के लिए अपना पुस्तकालय भी खोला है और सदस्यता नियमों में ढील दी गई है।

अपने जनादेश के अनुरूप आईसीडब्ल्यूए ने बड़ी संख्या में व्याख्यान, चर्चाएं, सम्मेलन, थिंक टैंक संवाद और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया।

विस्तृत जानकारी इस प्रकार हैं :

अनुसंधान

अनुसंधान संकाय की वर्तमान ताकत इस प्रकार है:

1.	निदेशक (अनुसंधान)	1
2.	अध्येता	23
3.	रिसर्च इंटर्न (आरआई)	3

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद् के अनुसंधान संकाय 4 पुस्तकें, 03 नीति संक्षेप, 30 अंक संक्षेप, 26 दृष्टिकोण, और मीडिया और अन्य अकादमिक पत्रिकाओं में विभिंन लेख का उत्पादन किया। चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा पर परिषद् में देश विशिष्ट नीति अध्ययन किए गए, मेक्सिको, अमेरिका और रूस। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडो-पैसिफिक और आर्कटिक पर क्षेत्र विशिष्ट अध्ययन किए गए। इसके अलावा नाटो, जी-20 और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय और क्षेत्रीय समूहों पर अध्ययन किए गए। परिषद् ने विज्ञान और कूटनीति, गिलगित 1947-48, भारतीय उपमहाद्वीप इतिहास में भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय कारकों, भारत की विदेशी सहायता, अफ्रीका को विकास सहायता, मध्य एशिया और म्यांमार और मध्य एशिया पर भारत की बौद्ध मूर्तिकला का प्रभाव की समीक्षा की।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् की पुस्तक परियोजना अनुदान योजना के अंतर्गत 11 नए पुस्तक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 14 पुस्तक परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। परिषद् ने अपने अनुसंधान और पुस्तक परियोजनाओं के क्षेत्र में विविधता लाने की भी कोशिश की है।

आईसीडब्ल्यूए रिसर्च फैकल्टी को हिंदी में लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया और 4 ऐसे शोध लेख (हिंदी में 1 विशेष रिपोर्ट) शामिल हैं और इसे परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए आईसीडब्ल्यूए ने हिंदी में अपने अकादमिक लेखों के अनुवादित संस्करणों को प्रकाशित करना जारी रखा। इस उद्देश्य की खोज में 02 पुस्तकें, 03 अंक संक्षेप, 13 दृष्टिकोणों का हिंदी में अनुवाद कर परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आईसीडब्ल्यूए ने विश्वविद्यालयों/अकादमिक संस्थानों के सहयोग से विदेश नीति जागरूकता कार्यक्रम (हिंदी में) और प्रायोजित सेमिनारों की स्थापना की, जहां इसका प्रतिनिधित्व एक या एक से अधिक आरएफ द्वारा किया गया था।

अपनी आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में और युवाओं के बीच विदेश नीति के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, आईसीडब्ल्यूए ने स्कूल जाने वाले छात्रों (10-12 मानक) और स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के बीच दो राष्ट्रीय स्तर की निबंध लेखन प्रतियोगिताएं (अंग्रेजी और हिंदी में) की।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन

आईसीडब्ल्यूए ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक सचेत प्रयास किया है। परिषद् ने विदेश नीति संस्थानों के साथ तीन नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, नामत उज्बेकिस्तान गणराज्य (सीआईआर), उज्बेकिस्तान गणराज्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए केंद्र; उज्बेकिस्तान गणराज्य (आईएसआरएस), ताशकंद, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के अंतर्गत सामरिक और क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान; एशिया न्यूजीलैंड फाउंडेशन (फाउंडेशन), वेलिंगटन। राष्ट्रीय स्तर पर परिषद् ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू (सीयूजे), चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज (सी3एस)

जैसे संस्थानों के साथ इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; एशिया सेंटर, बैंगलोर; दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत अध्ययन के लिए केंद्र; विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर वुमन, तमिलनाडु; कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई; यूजीसी सेंटर फॉर मैरीटाइम स्टडीज पांडिचेरी यूनिवर्सिटी। वर्तमान में परिषद् के पास ऐसी 71 व्यवस्थाएं हैं। (कुल समझौता ज्ञापन: इंटरनेशनल-53, नेशनल-18)।

प्रकाशन

आईसीडब्ल्यूए के प्रमुख जर्नल 'इंडिया त्रैमासिक' को 2019-20 की अवधि के दौरान नियमित रूप से लाया गया था। इसके अलावा, आईसीडब्ल्यूए निम्नलिखित प्रकाशनों को सामने लाया गया है :

क्रम सं.	शीर्षक	संपादक/लेखक	प्रकाशन का वर्ष
I पुस्तकें/पुस्तिकाएं			
1.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत के संबंध (परिप्रेक्ष्य में 25 वर्ष 1991-2016)	लेखक वी. श्रीनिवास द्वारा वाई वी. रेड्डी द्वारा अग्रेषित	2019
2.	भारत और यूरोपीय संघ : एक अंतरंग दृष्टिकोण	भास्वती मुखर्जी	2019
3.	शक्ति की मान्यता : सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्	दिलीप सिन्हा	2019
4.	पाकिस्तान बलूचिस्तान पहेली	तिलक देवाशेर	2019
इंडिया क्वार्टरली			
1.	अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष अंक के एक जर्नल विशेष अंक - यूरेशिया	खंड-75 संख्या-1	2019
2.	अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जर्नल विशेष अंक-चीन	खंड-75 संख्या -2	2019
3.	अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक जर्नल	खंड-75 संख्या -3	2019

प्रक्रियाधीन पुस्तक परियोजनाओं की सूची

1. सप्रू हाउस पेपर (चेंजिंग ट्रांसेटलांटिक पार्टनरशिप : ए केस ऑफ नाटो" सह-लेखक डॉ. स्तूति बनर्जी और डॉ. अंकिता दत्ता)
2. पुनर्मुद्रण (कश्मीर ए स्टडी इन इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस, लेखक शिशिर गुप्ता। (प्रथम संस्करण -1966; पुनर्मुद्रण-1998)।
3. साउथ काकेसस ट्रांजिशन फ्रॉम सबजुगेशन टू इंडिपेंडेंस-लेखक अचल मल्होत्रा।
4. हिन्दी "भारत-चीन सीमा मुद्दे: विवाद निपटान की तलाश- लेखक रंजीत सिंह काल्हा"।
5. हिन्दी "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ भारत के संबंध के परिप्रेक्ष्य में 25 वर्ष 1991-2016- लेखक वी. श्रीनिवास"।

आईसीडब्ल्यूए सम्मेलन/संगोष्टी/और अन्य कार्यकलाप

आईसीडब्ल्यूए के आउटरीच कार्यक्रमों में देश भर में परिषद् के समझौता ज्ञापन भागीदारों सहित अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों और थिंक टैंक के साथ संयुक्त सम्मेलन और संगोष्ठि शामिल थे। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अनेक देशों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्याख्यानों में भागीदारी थी।

आईसीडब्ल्यूए ने 1 अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर 2019 तक, निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया :-

व्याख्यान	-	09
संगोष्ठी/सम्मेलन	-	18
द्विपक्षीय सामरिक वार्ता	-	09
पैनल चर्चा/पृष्ठभूमि ब्रीफिंग/अंत:संवाद	-	16
पुस्तक विमोचन/विज्ञप्ति/चर्चा समारोह	-	06
कुल	-	58

व्याख्यान

9 अप्रैल 2019	*"राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान: उभरती चुनौतियों से निपटना"* पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष राजदूत पी.एस. राघवन का व्याख्यान स्थान : सप्रू हाउस
7 मई 2019	*"इजराइल चुनाव और इसराइल-फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया के भविष्य"* पर प्रोफेसर डेविड न्यूमैन द्वारा वार्ता अध्यक्षता : राजदूत तलमिज अहमद स्थान : सप्रू हाउस
14 मई 2019	*"एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक- एशिया से अवसंरचना वित्त-पोषण की बदलती रूपरेखा"* पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अवर सचिव श्री वी. श्रीनिवास का व्याख्यान और उसके बाद एक पैनल चर्चा अध्यक्षता : लेफ्टिनेंट जनरल एस एल नरसिम्हन, पीवीएसएम, एवीएसएम*, वीएसएम, पीएचडी (सेवानिवृत्त), महानिदेशक, *सेंटर फॉर कंटेम्परेरी चाइना स्टडीज, नई दिल्ली* स्थान : सप्रू हाउस

17 मई 2019	*'अफगान शांति प्रक्रिया में वर्तमान घटनाक्रम'* पर अफगान उच्च शांति परिषद् के मुख्य कार्यकारी श्री मोहम्मद उमेर दजई द्वारा वार्ता अध्यक्षता : राजदूत विवेक काटजू, अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत स्थान : सप्रू हाउस
10 जुलाई 2019	प्रोफेसर वी. कामकोटी, प्रोफेसर, विज्ञान और इंजीनियरी, आईआईटी, चैन्नई; एसोसिएट डीन, आईआईटी चेन्नई, और सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा *"भारतीय परिप्रेक्ष्य में 5जी प्रौद्योगिकी"* पर व्याख्यान अध्यक्षता : डॉ. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए स्थान : सप्रू हाउस
30 जुलाई 2019	प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर, पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (मानद विश्वविद्यालय) चंडीगढ़ के पूर्व कुलपति द्वारा *''द्वितीय विश्व युद्ध और भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास''* पर व्याख्यान अध्यक्षता : डॉ. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए स्थान : सप्रू हाउस
23 अगस्त 2019	डॉ. विनीत ठाकुर, विश्वविद्यालय व्याख्याता इतिहास संस्थान, लीडेन विश्वविद्यालय, नीदरलैंड द्वारा *"अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सांप्रदायिक मामलें आईआर के औपनिवेशिक भारत में आगमन"* पर व्याख्यान अध्यक्षता : डॉ. जोरावर दौलेत सिंह, फेलो, नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली स्थान : सप्रू हाउस
27 अगस्त 2019	*''ओमान, खाड़ी क्षेत्र और भारत: ओमान के राष्ट्रीय संग्रहालय -सल्तनत ऑफ ओमान के म्यूजियोग्राफिकल संदर्भ से समुद्री-संबंधित गतिविधि पर दृष्टिकोण"* पर डॉ. जमाल अल-मूसावी, महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, ओमान की सल्तनत द्वारा वार्ता अध्यक्षता : प्रोफेसर हिमांशु प्रभा रे, अध्येता, ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, म्यूनिख स्थान : सप्रू हाउस

2 सितम्बर 2019	महामहिम अध्यक्ष प्रोफेसर तिज्जानी मुहम्मद-बांदे संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 74 वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा *''संयुक्त राष्ट्र की 74वीं महासभा के लिए प्राथमिकताओं''* पर वार्ता अध्यक्षता : राजदूत असोक मुखर्जी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि स्थान : सप्रू हाउस

संगोष्ठियां/सम्मेलन

10 और 11 अप्रैल 2019	*"दक्षिण एशियाई देशों में भारत की सुरक्षा चुनौतियां"* पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : वीपीओ- बहल-127028, हरियाणा
17 और 18 अप्रैल 2019	14वीं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) फोरम की बैठक स्थान : बीजिंग, चीन
18 और 19 अप्रैल 2019	*"एशिया के राजनयिक इतिहास: बदलते रूपरेखा"* पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : वाराणसी
3 मई 2019	*"चीनी अर्थव्यवस्था: वर्तमान स्थिति और संभावनाएं"* पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : चेन्नई
15 मई 2019	*"भारत-म्यांमार संबंधों में संवर्धन : आगे की राह"* पर राष्ट्रीय संगोष्ठी स्थान : सप्रू हाउस
26 जून 2019	*'परिवर्तित विश्व व्यवस्था में यूरोपीय संघ पर सम्मेलन: भारत-यूरोप साझेदारी के लिए संभावनाएं'* पर सम्मेलन स्थान : सप्रू हाउस
12 और 13 जुलाई 2019	*"भारत और हिंद महासागर क्षेत्र: भूराजनीति, सुरक्षा और वैश्विक कॉमन्स की गतिशीलता"* पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : चेन्नई
12 और 13 जुलाई 2019	*"स्टार्टअप इंडिया: द विंग्स ऑफ फॉरेन ट्रेड"* पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : तिरुचेंगोड, तमिलनाडु

8 और 9 अगस्त 2019	*"भारत-लैटिन अमेरिका और कैरेबियन संबंधों का जायजा लेना"* पर राष्ट्रीय संगोष्ठी मुख्य अतिथि द्वारा विशेष संबोधन : श्री वी. मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार स्थान : सप्रू हाउस
19 अगस्त 2019	संयुक्त आईसीएस-आईसीडब्ल्यूए कार्यक्रम *'सप्रू हाउस लॉन से श्री राम मार्ग तक: चीनी अध्ययन संस्थान के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में'* स्थान : सप्रू हाउस
29 और 30 अगस्त 2019	*"वर्तमान संदर्भ में भारत-श्रीलंका संबंध? क्या यह नीति के पुनर्स्थापन का समय है?"* पर राष्ट्रीय संगोष्ठी स्थान : सप्रू हाउस
3 और 4 सितम्बर 2019	*'परिवर्तित वैश्विक व्यवस्था में भारत-अफ्रीका साझेदारी: प्राथमिकताएं, संभावनाएं और चुनौतियां'* पर राष्ट्रीय सम्मेलन समापन भाषण (4 सितंबर 2019 को 1600 बजे) माननीय श्री एम वेंकैया नायडू, भारत के उप राष्ट्रपति और अध्यक्ष, आईसीडब्ल्यूए स्थान : सप्रू हाउस
19 और 20 सितम्बर 2019	*"एशियाई क्षेत्र की बदलती राजनीतिक-रणनीतिक गतिशीलता और यह भारत, क्षेत्र अध्ययन को कैसे प्रभावित करता है (यूनाइटेड स्टेट स्टडीज)"* इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : अध्ययन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थान : नई दिल्ली
20 और 21 सितम्बर 2019	*"एशिया के साथ संलिप्तता: 21 वीं सदी में भारत की विदेश नीति"* पर सम्मेलन आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : कोलकाता
23 और 24 सितम्बर 2019	*"भारत-नेपाल संबंध: 21वीं सदी में द्विपक्षीय संबंधों का कायाकल्प"* पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : आईसीसीआर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

10 और 11 अक्तूबर 2019	*'पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा के बाहरी आयाम'* पर आईसीडब्ल्यूए-एस्कॉन राष्ट्रीय सम्मेलन स्थान : सप्रू हाउस
29-31 अक्तूबर 2019	*"हिंद-प्रशांत के विचार को नेविगेट करना: भारतीय और दक्षिणपूर्व एशियाई परिप्रेक्ष्य"* पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : मदुरई
15 और 16 नवम्बर 2019	*"कश्मीर के पुनर्गठन"* पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आईसीडब्ल्यूए द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम : स्थान : मथुरा

द्विपक्षीय और सामरिक वार्ता

3 और 4 अप्रैल 2019	वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी (वीएएसएस) के साथ दूसरा संवाद आईसीडब्ल्यूए और एनआईएस, बैंगलोर के लिए प्रतिनिधिमंडल की यात्रा (आईसीडब्ल्यूए के समझौता ज्ञापन साझेदार) स्थान : सप्रू हाउस
10 और 11 अप्रैल 2019	भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे दौरे की वार्ता [विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (आईसीडब्ल्यूए), एशिया न्यूजीलैंड फाउंडेशन (एएनजेडएफ) और न्यूजीलैंड इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजेडआईआरआई)] आईसीडब्ल्यूए प्रतिनिधिमंडल का न्यूजीलैंड का दौरा स्थान : वेलिंगटन, न्यूजीलैंड
15 अप्रैल 2019	आईसीडब्ल्यूए और अमीरात सामरिक अध्ययन और अनुसंधान (ईसीएसएसआर) के बीच पहली वार्ता दो सत्रों की वार्ता स्थान : सप्रू हाउस
10 और 11 सितम्बर 2019	चौथी आईसीडब्ल्यूए-मिस्र विदेश मामलें परिषद् (ईसीएफए) वार्ता (आईसीडब्ल्यूए के समझौता ज्ञापन साझेदार) स्थान : काहिरा, मिस्र

13 अक्तूबर 2019	आईसीडब्ल्यूए-राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (आईपीआईएस) संवाद आईपीआईएस, तेहरान के लिए आईसीडब्ल्यूए के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा (आईसीडब्ल्यूए के समझौता ज्ञापन साझेदार) स्थान : तेहरान
01 नवम्बर 2019	प्रथम भारत-जर्मनी सामरिक वार्ता स्थान : सप्रू हाउस
7 नवम्बर 2019	चीनी पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (सीपीआईएफए) के साथ छठी आईसीडब्ल्यूए वार्ता (आईसीडब्ल्यूए के समझौता ज्ञापन साझेदार) स्थान : सप्रू हाउस
19 और 20 नवम्बर 2019	रूस के विदेश मंत्रालय की रूस अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद् (आरआईएसी) के साथ तृतीय रूस-भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "रूस की सामरिक दृष्टि - भारत संबंध और विश्व व्यवस्था में परिवर्तन" स्थान : रूस
26 नवम्बर 2019- 02 दिसम्बर 2019	चौथा भारत-चीन थिंक टैंक फोरम (चौथा आईसीटीएफ) और संबंधित बैठकें (भारत-चीन थिंक टैंक फोरम की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर विदेश मंत्रालय और चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी (सीएएसएस), बीजिंग द्वारा हस्ताक्षर किए गए) स्थान : बीजिंग, हैंग झोउ और शंघाई, चीन

पैनल चर्चा/पृष्ठभूमि ब्रीफिंग/अंत:संवाद

4 अप्रैल 2019	डॉ. मरीना कनेटी, सहायक प्रोफेसर, एनयूएस, सिंगापुर के साथ बातचीत अध्यक्षता : सुश्री नूतन कपूर महावर, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए स्थान : सप्रू हाउस
23 अप्रैल 2019	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएस), बैंगलोर के साथ *'विज्ञान और राजनयिक'* पर बातचीत अध्यक्षता : डॉ. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए स्थान : सप्रू हाउस

24 अप्रैल 2019	एशिया और प्रशांत प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक अध्यक्षता : सुश्री नूतन कपूर महावर, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए स्थान : सप्रू हाउस
30 अप्रैल 2019	*''आईसीडब्ल्यूए के इतिहास पर रैंडम प्रतिबिंब''* पर गोलमेज चर्चा अध्यक्षता : प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती, आईसीएस स्थान : सप्रू हाउस
9 मई 2019	2018 वार्षिक भारत-रूस संयुक्त वक्तव्य के आधार पर *"परिवर्तित विश्व व्यवस्था में भारत-रूस सामरिक साझेदारी"* पर मध्यावधि समीक्षा के लिए बंद दरवाजा मंथन अध्यक्षता : श्री पी. एस. राघवन, रूस में पूर्व राजदूत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष स्थान : सप्रू हाउस
28 जून 2019	*"5जी, हुआवेई और भूराजनीति-भारतीय रोडमैप"* और *"क्रा नहर (थाईलैंड में एक बीआरआई परियोजना):* भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?" पर विचार मंथन सत्र के बाद आइडियाशाला (पैनल चर्चा) [तक्षशिला संस्था, बैंगलोर के सहयोग से] स्थान : सप्रू हाउस
16 जुलाई 2019	*"अमेरिका-ईरान गतिरोध: निहितार्थ का आकलन"* पर पैनल चर्चा अध्यक्षता : राजदूत अनिल के त्रिगुनौत, जॉर्डन, लीबिया और माल्टा में पूर्व राजदूत, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में प्रतिष्ठित फेलो स्थान : सप्रू हाउस
14 अगस्त 2019	*''कुलभूषण जाधव मामले पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय : भावी राह''* पर गोल मेज चर्चा अध्यक्षता : राजदूत विवेक काटजू, अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत स्थान : सप्रू हाउस
26 अगस्त 2019	तुर्की से मीडिया प्रतिनिधिमंडल और आईसीडब्ल्यूए के शोध संकाय के बीच बातचीत स्थान : सप्रू हाउस

13 सितम्बर 2019	हिंदी पखवाड़े के अवसर पर परिषद् द्वारा *"हिंदी में विदेश नीति विमर्श को प्रोत्साहन"* विषय पर परिचर्चा का आयोजन अध्यक्ष राजदूत श्री अनिल त्रिगुणायत *विशिष्ट अध्येता, विवेकानंद इंटरनेश्नल फाउंडेशन* स्थान : सप्रू हाउस
24 सितम्बर 2019	*"क्या भारत अपना अगली पीढ़ी का नेटवर्क बना सकता है"* पर प्रस्तुतियां अध्यक्षता : प्रोफेसर वी. कामकोटी, वरिष्ठ प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास और सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड स्थान : सप्रू हाउस
30 सितम्बर 2019	क्यूबा के विदेश मंत्रालय (वरिष्ठ जेएस के समकक्ष रैंक) के नीति नियोजन महानिदेशालय (डीजीपीपी) के उप महानिदेशक श्री एर्नेको एंटोनियो डेविस के साथ बातचीत स्थान : सप्रू हाउस
21 अक्तूबर 2019	*''चीनी प्रौद्योगियों में प्रौन्नतियां''* पर प्रोफेसर आरोग्यस्वामी जे. और और एमआईएमओ (अनेक इनपुट अनेक आउटपुट) वायरलेस प्रौद्योगिकी के एक अग्रणी आविष्कारक द्वारा चर्चा अध्यक्षता : राजदूत भास्कर बालाकृष्णन, ग्रीस और क्यूबा में भारत के पूर्व राजदूत स्थान : सप्रू हाउस
14 नवम्बर 2019	कर्नल ले विएट क्यूंग, निदेशक, सैन्य रणनीति संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, समाजवादी वियतनाम गणराज्य, सामरिक अध्ययन प्रभाग के के नेतृत्व में तीन सदस्यीय वियतनाम प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत, स्थान : सप्रू हाउस
15 नवम्बर 2019	*"भारत और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता"* पर सत्तारूढ़ बीएएटीएच पार्टी, सीरिया के उच्च शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख डॉ. मोहसेन बिलाल के साथ इंटरएक्टिव सत्र अध्यक्षता : राजदूत गौतम मुखोपाध्याय, पूर्व राजनयिक स्थान : सप्रू हाउस

28 नवम्बर 2019	राजदूत गैलमा एम बोरू, निदेशक, विदेश विज्ञान अकादमी, विदेश मंत्रालय, केन्या के साथ बातचीत <u>अध्यक्षता :</u> सुश्री नूतन कपूर महावर, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए स्थान : सप्रू हाउस

पुस्तक विमोचन/विज्ञप्ति/चर्चा कार्यक्रम

2 अप्रैल 2019	*"भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति: एक वैश्वीकृत दुनिया में बहुलवाद का आयोजन"* पुस्तक का विमोचन और चर्चा लेखक : राजदूत परमजीत सहाय द्वारा [आईसीडब्ल्यूए का प्रकाशन] <u>अध्यक्षता :</u> राजदूत ललित मानसिंह, भारत के पूर्व विदेश सचिव अध्यक्ष, कलिंग इंटरनेशनल फाउंडेशन स्थान : सप्रू हाउस
29 अप्रैल 2019	प्रोफेसर एस.डी. मुनि और डॉ. राहुल मिश्रा द्वारा *"इंडिया ईस्टवार्ड एन्गेजमेन्ट : फ्रॉम एंटिक्विटी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी"* पर पुस्तक प्रक्षेपण और चर्चा अध्यक्षता : राजदूत प्रीति सरन, पूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्री स्थान : सप्रू हाउस
26 जुलाई 2019	श्री वी श्रीनिवास, अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, भारत सरकार और कार्यकारी निदेशक (भारत) आईएमएफ के पूर्व सलाहकार द्वारा *"अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत के संबंध: परिप्रेक्ष्य में 25 वर्ष 1991-2016"* [आईसीडब्ल्यूए प्रकाशन] पुस्तक का विमोचन <u>मुख्य अतिथि</u> श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक स्थान : सप्रू हाउस सभागार
22 अगस्त 2019	श्री तिलक देवशर (पुस्तक के लेखक) द्वारा *"पाकिस्तान: बलूचिस्तान एक पहेली"* [एक आईसीडब्ल्यूए और हार्पर कोलिन्स भारत का प्रकाशन] पुस्तक का विमोचन और चर्चा, <u>मॉडरेटर :</u> श्री मारूफ रजा, परामर्श संपादक, टाइम्स नाउ स्थान : सप्रू हाउस

26 सितम्बर 2019	श्री राघवेंद्र सिंह, भारत सरकार के पूर्व सचिव, द्वारा लिखित पुस्तक *'इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर: द स्टोरी ऑफ नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान'* पर चर्चा अध्यक्षता : डॉ. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए स्थान : सप्रू हाउस
17 अक्तूबर 2019	गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती आयोजित करने के लिए 'नेपाल की सिख विरासत' पर प्रस्तुति और पुस्तक विमोचन [बी.पी. कोइराला इंडिया-नेपाल फाउंडेशन के सहयोग से] स्थान : सप्रू हाउस

एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग परिषद् (सीएससीएपी)

आईसीडब्ल्यूए 2001 से एशिया प्रशांत सुरक्षा सहयोग परिषद् (सीएससीएपी) - भारत समिति के सचिवालय की मेजबानी कर रहा है।

परिषद् ने 1 अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लिया:

1. 6 और 7 अप्रैल 2019 को इंडोनेशिया के बाली में अप्रसार और निरस्त्रीकरण पर सीएससीएपी अध्ययन समूह की बैठक आयोजित की गई।
2. मलेशिया के कुआलालंपुर में 24-26 जून 2019 को 33वीं एशिया प्रशांत राउंड टेबल मीटिंग आयोजित की गई।
3. मलेशिया के कुआलालंपुर में 27 जून 2019 को 51 वीं संचालन समिति की बैठक हुई।
4. चीन के बीजिंग में 02-10 सितंबर 2019 को एशिया पैसिफिक यंग स्कॉलर्स के लिए 5वीं कार्यशाला का आयोजन किया गया।
5. सियोल, दक्षिण कोरिया में 4-13 नवंबर 2019 को भविष्य एशिया प्रशांत नेताओं के लिए दूसरी वैश्विक कोरिया कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आईसीडब्ल्यूए पुस्तकालय

सप्रू हाउस पुस्तकालय, 1955 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय और विदेशी विद्वानों के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में उभरा है। इसमें वर्तमान में 1,52,407 पुस्तकें, पत्रिकाएं, नक्शे और संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के दस्तावेज हैं। आशा है कि 31 मार्च 2020 तक पुस्तकालय संग्रह में लगभग 600 और पुस्तकें जुड़ जाएंगी। पूरा संग्रह डिजिटाइज्ड इंडेक्स के माध्यम से सुलभ है और इसे ऑन-लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के माध्यम से खोजा जा सकता है। सप्रू हाउस पुस्तकालय का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल प्रारूप में शोध विद्वानों के लिए सुलभ है, जैसाकि आईसीडब्ल्यूए जर्नल- क्वार्टरली इंडिया का पूरा संग्रह है। आधुनिक साइबर पुस्तकालय से संपन्न, सप्रू हाउस पुस्तकालय का अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ संबंध है जो आईसीडब्ल्यूए विद्वानों को पहुंच प्रदान करते हैं।

पुस्तकालय का उद्देश्य दक्षिण एशिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय विदेश नीति के मुख्य क्षेत्रों में शोध

सामग्रियों और दस्तावेजों का व्यापक भंडार बनना है। यह हमारी शोध परियोजनाओं के क्षितिज के विस्तार और अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है।

प्रचार प्रसार

आईसीडब्ल्यूए ने अपने आउटपुट कार्यकलापों को अधिकांश संभावित वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने और राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में भारतीय चिंताओं और आकांक्षाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रसार की नीति बनाई है। आईसीडब्ल्यूए के जनादेश की अधिप्राप्ति में प्रकाशन अलर्ट प्रसार के साथ-साथ वेबसाइट www.icwa.in को दुरुस्त करने की एक प्रणाली और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की वैश्विक वेबकास्टिंग सहायक रही है।

33

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस)

बीएपीए+40 के उपरांत नए अवसर और नई भागीदारियां

दक्षिण-दक्षिण और त्रिपक्षीय सहयोग पर दिल्ली प्रक्रिया पांचवा सम्मेलन

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय (यूएनओएसएससी), दक्षिणी थिंक-टैंक नेटवर्क (एनईएसटी) तथा भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) के साथ साझेदारी करते हुए आरआईएस ने 'ब्यूनोस एयरेस' कार्ययोजना (बीएपीए)+40 के उपरांत नए अवसरों और नई भागीदारियों की तालाश' के लिए दक्षिण-दक्षिण और त्रिपक्षीय सहयोग पर दिल्ली प्रक्रिया पांचवें सम्मेलन का आयोजन किया।

श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल मंत्री तथा वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने 'नवीकृत बहुपक्षवाद' पर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए वित्तीय शासन के संदर्भ में दक्षिण द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और विद्यमान अवसरों का उल्लेख करते हुए आधार व्याख्यान दिया।

महामहिम डॉ. नोमवुयो नोकवे, महासचिव, हिंद महासागर एसोसिएशन, मॉरीशस ने उद्घाटन भाषण दिया। राजदूत मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री जोर्गे चेडिएक, निदेशक, यूएनओएसएससी; प्रोफेसर अनुराधा शिनाय, अध्यक्ष, एफआईडीसी; ओर प्रोफेसर ली जियाओयुन, अध्यक्ष, एनईएसटी ने भागीदार संस्थाओं की ओर से प्रस्तुतीकरण पेश किए तथा टी.एस.त्रिमूर्ति, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी विशेष टिप्पणियों से सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और 53 से अधिक देशों से आए प्रतिभागियों, जिसमें 16 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और प्रमुख एसएससी हितधारक शामिल थे, का स्वागत किया।

विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे जिनमें शामिल थे - उद्योग 4.0 के संदर्भ में एसएससी का उन्नयन; एक ऐसा प्रभाव आकलन ढांचा तैयार करना जो एसएससी की प्रमुख विशेषताओं को समादित कर सके; कर्ताओं की विविधता तथा दक्षिण की आकांक्षाओं की पूर्ति में संस्थाओं की भूमिका; वैश्विक वित्तीय शासन के लिए एसएससी की भूमिका तथा त्रिपक्षीय सहयोग (टीआरसी) की क्षमता के अन्वेषण के लिए उसकी साथ-साथ संलिप्तता। चर्चा में सुदृढ़ सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी की साझेदारी तथा दूसरे सह-सृजन की आवश्यकता का अन्वेषण किया गया तथा हमने वैश्विक दक्षिण की उभरती हुई एजेंसियों के लिए एसएससी के सांस्थानीकरण हेतु अनुभव ज्ञान और तंत्रों को साझा करने के एक साथ आने के प्रयोजनार्थ स्थान उपलब्ध कराया।

सम्मेलन में एक ओर गैर-वार्तालाप सिद्धातों के प्रति एसएससी के आकलन पर एक व्यापार सर्वसम्मति भी बनाई गई जबकि दूसरी ओर प्रचालन में दूसरी विविधताओं की रूपात्मकताएं प्रस्तुत कीं गई। अंतर्आश्रित रूपात्मकताओं के अनुपूरक सेट के रूप में 'विकास सघनता' की प्रतिभागियों द्वारा पर्याप्त सराहना की गई। इसके अलावा, सम्मेलन ने उस समय सत्त वार्तालाप के लिए मार्गों को भी खोला जब हम दक्षिणी सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा एजेंडा 2030 की प्राप्ति के लिए त्रिपक्षीय भागीदारियां प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

दिल्ली प्रक्रिया पांचवें सम्मेलन ने एक चिंतक-विश्वविद्यालय संपर्क ओर एक युवा विद्वतजन फोरम को प्रांरभ करने के लिए ज्ञान संबंधों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अत्यावश्यक कदम भी उठाए गए। चिंतक-विश्वविद्यालय संपर्क ने ज्ञान सृजनकर्ताओं के लिए सामूहिक मंच का सृजन किया जिसका उद्घाटन प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा, सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद् (आईसीएसएसआर) और डॉ. भूषण पटवर्धन-उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया। इस नई पहल का उद्देश्य उच्चतर शिक्षण के विभिन्न संस्थानों में शिक्षण ओर अनुसंधान पर ओर अधिक बल प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, विकास अध्ययनों के विषयक्षेत्र शामिल करना तथा एक सामूहिक मंच में सार्वजनिक नीति तैयार करने के प्रक्रिया के साथ उन्हे सहयोजित करना है।

आरआईएस ने कोच्चि में छठे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (आईवीएसए) शैक्षिणिक फोरम की सह-मेजबानी की

आरआईएस को कोच्चि, केरल में 3-4 मई 2019 को आईबीएसए शेरपा बैठक के साथ-साथ छठी आईबीएसए शैक्षिणिक फोरम का आयोजन करने का कार्य सौंपा गया था। फोरम ने आईबीएसए प्रक्रिया को अपेक्षित गति प्रदान की और वैश्विक शासन और विकास सहयोग के लिए इस विशिष्ट त्रिपक्षीय भागीदारी की सत्त प्रासंगिकता को पुन: प्रवर्तित किया। आरआईएस अपनी शुरूआत से ही आईबीएसए के साथ सहयोजित रहते हुए अत्यन्त गौरवान्वित महसूस करती है।

छठे आईबीएसए शैक्षिणिक फोरम का प्रथम दिवस प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस दवारा स्वागत भाषण और संदर्भ परिचय के साथ प्रांरभ हुआ। राजदूत सुनील लाल, ब्राजील में भारत के पूर्व राजदूत ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। श्री टी.एस. त्रिमूर्ति, सचिव, (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया। जिसके उपरांत समकालीन वैश्विक शासन-व्यवस्था और आईबीएसए की भूमिका पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता राजदूत राजीव कुमार भाटिया, पूर्व महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (आईसीडब्ल्यूए), भारत ने की।

आईबीएसए के अध्यक्ष ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग एसएससी पर पूर्ण सत्र-I की अध्यक्षता, श्री जोस रोमेरों पेररिया जूनियर समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यक्रम, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रासिलिया, (यूसीबी), एवं शोधकर्ता, ब्राजीलियन इंस्टिट्यूट फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च (आईपीईए), ब्राजील ने की। इसके उपरांत आईबीएसए देशो में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के मध्य सहयोगी शैक्षिणिक नेटवर्क के और अवसर और सभांवित लाभ पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

दूसरे दिन की शुरूआत 'व्यापार सहयोग: प्रतिस्पर्धात्मकता और समकालीनता' पर पूर्ण सत्र-II के साथ हुई। श्री शेशाद्री चारी, सदस्य, शासी परिषद्, आईआरएस ने समापन सत्र 'आईबीएसए 2030- भावी मार्ग' की अध्यक्ष्ता की। डॉ. सब्यासाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस और संकाय समन्वयक, आईबीएसए फैलोशिप कार्यक्रम ने संवक्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की प्रतिनिधि संस्थाओं ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए। आईबीएसए शेरपा के साथ विशेष वार्ता भी आयेजित की गई। इस अवसर पर, आरआईएस प्रशासन 'डायनैमिक्स ऑफ आईबीएसए डेवलपमेंट कोओपरेशन' का विमोचन भी किया गया। इस प्रकाशन में पिछले वर्ष के आईबीएसए फेलों के योगदान को शामिल किया गया है।

आईबीएसए शैक्षिणिक फोरम से उत्पन्न होने वाली अंतिम उदघोषणा में उत्पन्न आईबीएसए शिखर-सम्मेलन को शीघ्र आयोजित किए जाने का आह्वान किया गया तथा बहुपक्षावाद, संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रीकरण, विश्व शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने में भूमिका तथा संपोषणीय विकास को मुख्यधारा में लाने में भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। फोरम ने यह दोहराया कि आईबीएसए भागीदारी का आधार दक्षिण-दक्षिण सहयोग के सुदृढ़ स्तंभों पर आधारित है जिसके दृष्टिकोणों की बहुलवादिता और रूपात्मकताओं अभिसारिता विद्यमान है तथा इसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आईबीएसए उदघोषणा के महत्व को प्रदर्शित किया। शैक्षिणिक फोरम ने मानकों, निदेश और वित्तीय क्षेत्र के गहन व्यापार एकीकरण और सहयोग का आह्वान किया। अंत में, शैक्षिणिक फोरम ने विकास वार्तालाप में दक्षिणी संदर्शों को सुदृढ़ बनाने के लिए आईबीएसए में मजबूत शैक्षिणिक और अनुसंधान संबंधों का निर्माण करने; तथा उभरते हुए क्षेत्रों जैसे मानव सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियां, समुद्री अर्थव्यवस्था और महासागर शासन को मजबूत बनाने की अनुशंसा की जिनमें आईबीएसए के लिए पर्याप्त महत्व निहित है।

जी20 ओसाका शिखर-सम्मेलन पर परिचायक सत्र

ओसाका, जापान में जी20 नेताओं का शिखर-सम्मेलन 28-29 जून को आयोजित किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिखर-सम्मेलन में भाग लिया तथा जी20 प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान दिया। माननीय श्री सुरेश प्रभु, पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री, शिखर-सम्मेलन जी20 के भारत के

शेरपा थे। यह शिखर-सम्मेलन वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में जी20 के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सदस्य देशों के लिए एक बहु-प्रतिक्षित आयोजन था। पिछले शिखर-सम्मेलनों की ही भांति, भारत ने ओसाका शिखर-सम्मेलन में सक्रियता के साथ भाग लिया तथा सदस्य राष्ट्रों के मध्य सांझी रूचि के वैश्विक मुद्दों को दृढ़ता के साथ उठाने में अपना योगदान दिया।

चूंकि भारत 2022 में जी20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि ओसाका शिखर-सम्मेलन से प्राप्त भावी मार्ग पर सामूहिक चर्चा कर ली जाए। चिंतकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, व्यपारियों और अन्य हितधारकों के मध्य संसूचित वाद-विवाद सृजित करने के उद्देश्य से, आरआईएस ने जी20 ओसाका शिखर-सम्मेलन पर परिचय सत्र का आयोजन किया। माननीय सुरेश प्रभु, जी20 शेरपा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने एक विशेष व्याखान दिया। डॉ. मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की। सोउ शेरपा श्री सुरेश रेड्डी, संयुक्त सचिव, बहुपक्षीय आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय ने भी विचार-विमर्शों में भाग लिया। श्री मॉगे स्टीन पीटन, विजिटिंग फेलो, आरआईएफ ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।

इस समय व्यापार का मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक व्यापार, उच्च आर्थिक विकास के प्रति योगदान कर सकता है। परंतु वैश्विक व्यापार में तब तक वृद्धि नहीं हो सकती है, जब तक डब्ल्यूटीओ कार्यात्मक नहीं हो जाता है। भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहलें की है कि डब्ल्यूटीओ वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए निश्चितता के रूप में बन सके। वर्ष 2017 में अर्जेंटिना मंत्रालायी बैठक के निराशाजनक परिणाम के उपरांत भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए 19 मार्च 2018 को एक लघु-मंत्रालयी बैठक आयोजित की कि डब्ल्यूटीओ अधिक प्रभावी बन सके। इसमें 57 देशों की प्रतिभागिता ने हर समारोह की सफलता को प्रतिबिंबित किया गया जिससे यह पता चला कि सदस्य राष्ट्र डब्ल्यूटीओ के कार्यकरण में संशोधन का पक्ष ले रहे हैं। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना एक उत्प्रेरक हो सकती है।

अनेक देश, विभिन्न भागों में विकसित हो रही अवसंरचना में निवेश करते हुए लाभान्वित हो रहे हैं। अवसंरचना से समूचे विश्व में आर्थिक क्रियाकलापों में सक्रियता लाने की क्षमता विद्यमान है। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संबंध में अनेक पहलें की है, जो वस्तुत: बदलते हुए वैश्विक ऊर्जा सम्मिश्रण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देंगी। भारत महासागर अर्थव्यवस्था पर तथा आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए महासागरों की भूमिका पर जी20 के पक्ष का समर्थन करता है। माध्यस्थम अवसरों को हासिल करने तथा कर-वचन आश्रयगाहों का पता लगाने के लिए आधार क्षरण और लाभ साझेदारी (बीईपीएस) ढ़ांचे को मजबूत बनाया जाना चाहिए। जी20 को ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए जो सभी देशों विशेषत: इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और मेक्सिकों जैसे उभरते हुए बाजारों को आपस में जोड़ सके जो प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर समन्वित कार्यवाहियों का समर्थन देने तथा वैश्विक सार्वजनिक माल को प्रोत्साहित करने में वैश्विक शासन में नए देश हैं। इस चर्चा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बाह्य क्षेत्र कौशल और नियोजन पर परिबोधन सत्र

भारत सरकार उपयुक्त कौशलों के विकास के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लक्ष्य बना रही है। इस संदर्भ में, इस मुद्दें पर तथा इससे संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए 17 जून 2019 को चुनिंदा विशेषज्ञों के समूह के साथ आरआईएस में एक परिबोधन सत्र का आयोजन किया गया।

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवासन और शहरी मामले मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नागर विमानन मंत्रालय तथा राज्य मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सत्र की अध्यक्षता की। चर्चा भाग लेने वाले अन्य सदस्य थे: श्री शेशाद्री चारी, सदस्य आरआईएस शासी परिषद्; डॉ. दिलीप शेनॉय, महासचिव, एफआईसीसीआई; डॉ. नागेश कुमार, यूएन-ईएससीएपी नई दिल्ली; डॉ. सुनील शुक्ला, निदेशक, ईडीआई, गांधीनगर, गुजरात; प्रोफेसर मुक्ति कांत मिश्रा, अध्यक्ष सेंचुरियन विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर; श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन सेंटर फॉर डेवलेपमेंट सपोर्ट, भुवेनश्वर; प्रोफेसर पुलक घोष, चेयर ऑफ एक्सेलेंस एवं प्रोफेसर, डिसीजन सांइसेस, आईआईएम बंगलूरू; सुश्री श्रुति गोजाल्वेस, प्रबंध निदेशक, सेवा गृह रिन लिमिटेड, नई दिल्ली; डॉ. गायत्री वासुदेवन और श्री राजेश, सीईओ, लेबरनेट बंगलूरू; प्रोफेसर अनूप कुमार सत्पथी; वी वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा, श्री रंजीत भट्टाचार्य और श्री अनंत मणि प्रथम एजुकेशन फांउडेशन नई दिल्ली तथा श्री हर्ष सिंह, वरिष्ठ समन्वयक, यूएनडीपी।

आरआईएस की ओर से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर अमिताभ कुंडु, विशिष्ट फेलो; डॉ. प्रियदर्शनी दास, सहायक प्रोफेसर, डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर; श्री गौरव शर्मा, परियोजना प्रबंधक, जीडीआई; डॉ. दुरैराज कुमार सामी, परामर्शक और श्री शुभोमय भट्टाचार्य ने भाग लिया।

आरआईएस बीएपीए+40 में रॉल प्रेबिश और विकास रणनीति पर आरआईएस वॉल्यूम का विशेश ध्यान केन्द्रण

संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रत्याशित भागीदार संगठन के रूप में आरआईएस ने 20-22 मार्च 2019 तक ब्यूनस आयर्स में आयोजित दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर वित्तीय उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (बीएपीए)+40 में भाग लिया। इस अवसर पर, आरआईएस ने नेटवर्क ऑफ साउथर्न थिंक टैंक्स (एनईएसटी) के तवाधान में चार कार्यक्रमों की मेजबानी भी की। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित विद्वानों, विशेषज्ञों, वृत्तियों और नीति-निर्माताओं की पैनल चर्चा के रूप में आयोजित किए गए जिनका उद्देश्य विकास सहयोग के प्रति एशियाई दृष्टिकोण के आयामों को सामने लाना; दक्षिण-दक्षिण सहयोग (एसएससी), की बहुलता का प्रदर्शन करना; स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के प्रति बेहतर पहुंच की आवश्यकता को रेखांकित और आकलन करना, निगरानी एवं मूल्याकंन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था।

आरआईएस ने 20 मार्च, 2019 को एनईएसटी के साथ भागीदारी करते हुए विदेशी मामलें और अर्चना मंत्रालय, पैलिसियों सैन मार्टिन, ब्यूनर्स आयर्स में 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग की तुलना में प्रभाव आकलन और निगरानी एंड मूल्यांकन वाद-विवाद की स्थिति' विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की। मोनोग्राफ में 'उत्तर-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण संबंधों में नए संदर्भ, पर आयोजित संगोष्ठी की कार्यवाहियां अंतनिहित है। इसमें रॉल प्रेबिश द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योगदान भी शामिल है। इन चर्चाओं में प्रभाग आकलन और निगारनी के बीच अवधारणात्मक और राजनीतिक मतभेदों तथा विकासशील क्षेत्रों जैसे भारत, परागुए और ब्राजील द्वारा मांग-चालित आकलन और मूल्यांकन क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए प्रयासों को मान्यता प्रदान की गई थी।

आरआईएस, एनईएसटी और चाइना इंस्टिट्यूट फॉर साउथ-साउथ कोओपरेशन इन एग्रीकल्चर (सीआईएसएससीए) ने 19 मार्च, 2019 को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनर्स आयर्स में 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर एशियाई रिवायत अन्वेक्षण' पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। आरआईएस और एनईएसटी ने 21 मार्च, 2019 को 'स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग' विषय पर इंस्टिट्यूटो नैशिनल सैन मार्टिनीएनों, ब्यूनर्स आयर्स में एक पैनल चर्चा का आयोजन किया जिसमें द्वीतीय स्तर पर सहयोग को प्राथमिकता दी गई। इस कार्यक्रम की शुरूआत अर्जेंटीना में भारत के राजदूत श्री संजीव रंजन द्वारा टुगेदर टुवडर्स ए हैल्थी फ्यूचर इंडियाज पार्टनरशिप्स इन हैल्थकेयर' नामक विशेष आरआईएस प्रकाशन का विमोचन करते हुए की गई। एनईएसटी ने ब्राजील, मेक्सिको, चीन, आर्जेंटीना और अफ्रीका कंट्री चैप्टरों के साथ तथा आरआईएस और ब्रिक्स पॉलिसी सेंटर, ब्राजील की भागीदारी से 22 मार्च को एसोसिएशन डी एमिगोस डेल म्युसियो नेसिओनल डी बेल्लास आर्टेस, ब्यूनर्स आयर्स में 'दक्षिण-दक्षिण सहयोगकी बहुलवादिता' पर भी एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम, 2019

आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र एसडीजी विचार-विमर्श, उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) तथा संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय के साथ अपने घनिष्ठ सहयोग को जारी रखते हुए, महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने 13-19 जुलाई 2019 को न्यूयार्क में एचएलपीएफ 2019 में भाग लेने के लिए दो सदस्यीय आरआईएस शिष्टमंडल का संयुक्त राष्ट्र में नेतृत्व किया जिसमें डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर भी शामिल थे। पूर्व वर्षों की ही भांति, आरआईएस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों और एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से एसडीजी, विशेष रूप से एसडीजी-17 पर चर्चा करने, उसे समझने और उसका विश्लेषण करने में योगदान देने के लिए न्यूयार्क में एचएलपीएफ 2019 के दौरान दो नीति-विषयक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।

महानिदेशक को 13 जुलाई 2019 को प्रभावी विकास सहयोग की वैश्विक भागीदारी (जीपीईडीसी) की वरिष्ठ स्तरीय बैठक (एसएलएम) में 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग में प्रभावकारिता' पर आयोजित सत्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉ. साहा को एसएलएम में प्रतिभागिता करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन में, प्रोफेसर चतुर्वेदी ने दक्षता और अभिसारिता के संबंध में दक्षिण-दक्षिण सहयोग में प्रभावकारिता पर विशिष्ट संदर्शों का उललेख किया।

इस कार्यक्रम में विशेष अभिभाषण, डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार ने दिया तथा इस सत्र के संवक्ता प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, नई दिल्ली थे। विशिष्ट पैनलविदों में शामिल थे- सुश्री रेनाटा लोक-डेसालिएन, भारत में यूएन रेजीडेंट कार्डिनेटर; श्री जार्ज चेडिएक, निदेशक एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग महासचिव के राजदूत, दक्षिण-दक्षिण सहयोग संयुक्त राष्ट कार्यालय; डॉ. देवप्रिय भट्टाचार्य, चेयर एंड डिस्टिंग्विश्ड फेलो, साउथर्न वॉयस ऑन पोस्ट-एमडीजी इंटरनेशनल डेवलमेंट गोल्स, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग, बांग्लादेश; डॉ. जॉन डब्ल्यू मैकआर्थर, सीनियर फेलो, ग्लोबल इकोनॉमी एंड डेवलमेंट प्रोग्राम, ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूशन, वाशिंगटन, डीसी तथा डॉ. मैनुअल एफ. मौंटेस, वरिष्ठ सलाहकार, वित्त एवं विकास, दक्षिण केन्द्र, जिनेवा। अपने विशेष व्याख्यान में डॉ. राजीव कुमार ने संसाधनों के अभिनव प्रयोग, प्रौद्योगिकी के सन्निहित अनुप्रयोग तथा विकासशील देशों के लिए स्वदेशी विकास मॉडलों पर बल प्रदान किया।

दूसरा कार्यक्रम एनईएसटी, यूएनओएससी, ओईसीडी और ब्रिक्स नीति केंद्र के साथ दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से एसडीजी 17 को सुदृढ़ बनाना; बहुलवादिता और बीएपीए + 40 से भावी मार्ग" विषय पर 18 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया था। इस सत्र के संवक्ता श्री जॉर्ज चेडिएक, निदेशक दक्षिण-दक्षिण सहयोग के महासचिव के राजदूत, दक्षिण-दक्षिण सहयोग संयुक्त राष्ट्र कार्यालय थे। इसमें भाग लेने वाले विशिष्ट पैनलिस्टों में शामिल थे - राजदूत नागराज नायडू, राजदूत और उप स्थायी प्रतिनिधि, भारत के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन; सुश्री एना सियुती, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेश और अर्चना मंत्रालय, श्री रॉबिन ओगिलवी, ओईसीडी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू दि यूएन, डॉ. पाउलो एस्टेवेस, निदेशक ब्रिक्स नीति केंद्र, ब्राजील, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस तथा सुश्री जियाओजुन ग्रेस वांग, उप निदेशक, कार्यक्रम और आयोजन।

आरआईएस ने डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग एवं एचएलपीएफ में भारतीय शिष्टमंडल के अध्यक्ष के सम्मान में 16 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एक रात्रिभोज का भी आयोजन किया। इस बैठक में उक्तसंदर्भित विषय पर विचार-विमर्श किया गया और इसमें अमेरिका में स्थित प्रतिष्ठित लोकहितैषी प्रतिष्ठानों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सामाजिक उद्यमियों और भारत के सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महामहिम सुश्री रेगिनाह माकगैबो महौले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की उप मंत्री, दक्षिण अफ्रीका के साथ एक संपर्क सत्र

आरआईएस ने दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उप मंत्री महामहिम सुश्री रेगिनाह माकगैबो महौले के साथ 9 जनवरी 2019 को एक संपर्क सत्र का आयोजन किया। डॉ. मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की और स्वागत संबोधन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस द्वारा दिया गया। 'भारत-दक्षिण अफ्रीका साझेदारी और नई वैश्विक व्यवस्था' पर आयोजित पैनल चर्चा के दौरान निम्नलिखित विशेषज्ञों द्वारा भागीदारी की गई: राजदूत वीरेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद; राजदूत राजीव भाटिया, पूर्व महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए; डॉ. फिलानी म्थेम्बु, कार्यकारी निदेशक, इंस्टिट्यूट फॉर ग्लोबल डायलॉग, दक्षिण अफ्रीका; और सुश्री रुचिता बेरी, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट, आईडीएसए। पैनल ने सरकार से परे सहयोग पहलें और नीतिगत वार्तालाप संचालित करने की दिशा में ट्रैक 1.5 राजनयिकता में कर्ताओं के महत्व को प्रस्तुत किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के चिंतकों के बीच संबंधित सहयोग ने प्रासंगिक, समयबद्ध और अनुप्रयुक्ता अनुसंधान की गुंजाइश में वृद्धि की जिसने धरातल पर परिवर्तन किया। ऐसा कोई प्रयास सरकार-से-सरकार और लोगों-से-लोगों के साथ सहयोग के सत्त ट्रेको को बल प्रदान करेगा।

पैनल चर्चा के पश्चात्, महामहिम सुश्री रेगिनाह माकगैबो महौले अंतर्राष्ट्रीय संबंध उप मंत्री, दक्षिण अफ्रीका ने "दक्षिण अफ्रीका में स्वाधीनता के 25 वर्ष" शीर्षक पर एक व्याखान दिया। महामहिम सुश्री महौले ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास, भारत के साथ अपनी साझेदारी को महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के काल से जोड़ा तथा उन्होंने अंतर्वेशी दक्षिणी विकास सुनिश्चित करने में दोनों देशों की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग के विद्यमान बहुपक्षीय मंचों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा आरआईएस तथा दूसरे दक्षिण अफ्रीकी सहयोगियों एसएआईआईए और आईजीडी के बीच

समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने से सहयोग के गहन होने की गुंजाइश का उल्लेख किया। श्री बी.जे. जोबर्ट, चार्ज डी अफेयर्स, भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

एएजीसी के माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप तक पहुंचना

एशिया अफ्रीका विकास गलियारा (एएजीसी) एशिया और अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत और जापान द्वारा प्रारंभ की गई एक बहु-देशीय विकास पहल है। एएजीसी के लिए भारतीय चिंतक आरआईएस ने दृष्टिपत्र दस्तावेज की संकल्पना करने और उसे तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। इस पहल के साथ भारतीय फिल्मों और व्यवसायों को जोड़ने तथा पहल के बारे में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से आरआईएस और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से 17 मई, 2019 को मुंबई में "एएजीसी के माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप के समीप आना" विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यपारों के लिए व्यापार के अवसरों, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, निवेश संभावनाएं और चुनौतियों, वित्त-पोषण तंत्र, सांस्थानिक सुविधा और नीतिगत हस्तक्षेप से संबंधित विषयों पर रूचिकर विचार-विमर्श किया।

व्यापार और उद्योग जगत से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया, जिनमें शामिल थे-केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड; लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड; महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड; टाटा कंसल्टेंसी; टाटा मोटर्स लिमिटेड; टाटा स्टील लिमिटेड; इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड; और किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। श्री केशव चंद्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा श्री प्रसन्नवी वी. सालियन, उप सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने परामर्श बैठक में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। एक्जिम बैंक का प्रतिनिधित्व श्री डेविड रसक्विनहा, ईडी; श्री सैमुअल जोसेफ; सीजीएम; श्री डेविड सिनेट, सीजीएम और श्री प्रहलाथन एस अय्यर, सीजीएम ने किया था। आरआईएस की ओर से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; श्री शेशाद्रि चारी, सदस्य, आरआईएस, शासी परिषद् और महासभा; श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो; राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो; और श्री सुभमोय भट्टाचार्य, परामर्शक ने परामर्श बैठक में भाग लिया।

वैश्विक विकास पर पहल की शुरूआत

आरआईएस ने डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त रूप से 9 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में 'वैश्विक विकास पर पहल' के शुभारंभ का आयोजन किया। यह पहल विकास के अनुभवों, ज्ञान और तकनीकी जानकारी की साझेदारी की ओर यात्रा प्रारंभ करती है, जिसके माध्यम से एक अंतर्वेशी और समान भागीदारी के लिए नई दिशा प्रशस्त की जा सके। यह भागीदारी एक विविध विकास सहयोग संरचना को मान्यता देने और विकासशील देशों के मध्य दृष्टिकोणों की बहुलता की विद्यमानता की संभावना को पूर्वानुमानित करती है। यह पहल भारत के विकास के अनुभवों को एशिया और अफ्रीका के साथी देशों के साथ साझा करने के लिए एक मंच का निर्माण भी करती है।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता राजदूत मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस द्वारा की गई। स्वागत भाषण राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस द्वारा दिया गया। विशेष उल्लेख श्री मनोज भारती, अपर सचिव, (आर्थिक राजनयिकता और राज्य प्रभाग), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; श्री पीट वाउलेस,

निदेशक, एशिया, कैरेबियन एंड ओवरसीज टेरेटोरीज़ डिवीजन, डीएफआईडी; तथा श्री गेविन मैकगिलिवरे, प्रमुख, डीएफआईडी इंडिया द्वारा दिए गए। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने 'वैश्विक विकास पर पहल' विषय पर प्रस्तुति दी।

पहल के उद्घाटन के उपरांत 'वैश्विक विकास पर पहल के प्रभाव' विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो आरआईएस ने की। इसमें पैनलिस्ट थे - श्री फिलिप परहाम, यूके के राष्ट्रमंडल में राजदूत; प्रोफेसर अनुराधा चेनोय, अध्यक्ष, एफआईडीसी; और डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष, एशिया प्रतिभागिता अनुसंधान (पीआरआईए)। चर्चा में उभरकर सामने आने वाले कुछ मुख्य संदर्भों ने विकासशील देशों में सभी हितधारकों के मध्य वार्तालापों के सह-संचालन के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसका लक्ष्य ज्ञान के संग्रहण और व्यवस्थीकरण की ओर था जिसमें विश्व स्थानीय मुद्दों को अपना सके। चर्चा के उपरांत प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया।

सुधार बहुपक्षीय विकास वर्तमान वैश्विक सत्यता को प्रतिबिंबित करें: राजदूत अनिल सूकलाल

दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), ब्रेटन वुड्स संस्थानों (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, आईएमएफ और विश्व बैंक) और डब्ल्यूटीओ के भीतर सुधारों का आह्वान किया है ताकि इन संस्थानों द्वारा विश्व समुदाय की वर्तमान सत्यताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। इसने यह भी मांग की है कि अग्रणी उभरता हुआ आर्थिक संगठन ब्रिक्स (जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं) बहुपक्षीय प्रणाली में विद्यमान 'अर्ध-अव्यवस्था' को निराकरण करने के लिए विभिन्न उपायों पर ध्यान केंद्रित करें।

इन बहुपक्षीय संस्थानों के भीतर सुधार किए जाने की हिमाकत करते हुए राजदूत अनिल सूकलाल, दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग के उप महानिदेशक और ब्रिक्स, आईबीएमए तथा जी-20 देशों में दक्षिण अफ्रीका के शेरपा (अथवा राजदूत) और वरिष्ठ सहयोजित फेलो, आरआईएस ने कहा: "आज हमारी एक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है जो धराशायी है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। और आज हमारे पास पी 2 और P3 के बीच एक स्थाई विभाजन भी है"। उन्होंने आगे कहा: "यह असमर्थता ही है जो (संपूर्ण) बहुपक्षीय प्रणाली में व्यापत है। हमें इन त्रुटियों का निरंतर समाधान करने के लिए ब्रिक्स जैसे मंचों का प्रयोग करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम किस प्रकार उसे निरंतर अपनी निगरानी में रख सकते है, जब तक कि हम इन दृष्टिकोणों (सुधार पर) को जीवंत रखने के लिए सर्वसम्मति बनाने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त गति का निर्माण न कर लें"। वरिष्ठ राजनयिक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस) तिरुवनंतपुरम के शिक्षाविदों और छात्रों को संबोधित कर रहे थे।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ जल्द ही मनाई जाएगी (वर्ष 2020 में), राजदूत ने कहा: "हमारे पास अभी भी P5 है, परंतु यह P5 कितना प्रभावी है? एक समय भी आएगा जब यह अप्रासंगिक हो जाएगा। आपके पास अन्य प्रमुख वैश्विक संगठन होंगे जो वैश्विक परिदृश्य को लेकर अपनी ताकत प्रदर्शित करेंगे और एक ऐसा प्रभाव जमाएंगे कि आपको संरचना (संयुक्त राष्ट्र की) को बदलना ही होगा। समय और बदलता वैश्विक परिवेश इस स्थिति का ध्यान रखेगा। वे 30 जनवरी, 2019 को सीडीएस में 'उभरती अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक शासन के मध्य सहयोग: ब्रिक्स अनुभव से सबक' विषय पर व्याख्यान देने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। इस समारोह का आयोजन आरआईएस के

सहयोग से किया गया था। अपने व्याख्यान में राजदूत सूकलाल ने विभिन्न मुद्दों को भी लिया जैसे वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग को सुदृढ बनाए जाने की आवश्यकता तथा जी-20 ब्रिक्स और आईबीएसए सहित वैश्विक और प्रादेशिक मंचों पर की जाने वाली बैठकों से अधिक मूल्यवान सुझाव प्राप्त करने के महत्व। इसके अलावा, उन्होंने ब्रिक्स देशों में लोगों का लोगों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने और ब्रिक्स देशों में चिंतकों के बीच साझेदारी में सुधार लाने पर भी जोर दिया। राजदूत ने ब्रिक्स संपर्क कार्यक्रमों का विस्तार किए जाने का भी सुझाव दिया जिसमें जी-20 शिखर सम्मेलन की वार्ताओं में विकासशील विश्व के हित के अधिक बिंदु शामिल हैं।

अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय के यूनेस्को मदनजीत सिंह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संस्थान (यूएमआइएसएआरसी) दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र में भी व्याख्यान दिया। उन्होंने 121वीं शताब्दी में 'गांधी की प्रासंगिकता' पर व्याख्यान दिया जिसका आयोजन आरआईएस के सहयोग से किया गया था। राजदूत सूकलाल ने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के जीवन की समानताओं का उल्लेख किया तथा यह बताया कि अहिंसा, सत्य और सतत विकास के सिद्धांत और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने गांधी और मंडेला द्वारा पालन के गए सिद्धांतों तथा वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) और उबुंतु ('मैं इसलिए हूं कि हम सभी हैं' या साझेदारी के सार्वभौमिक बंधन मान्यता जो सपूर्ण मानव जाति को जोड़ती है') के आधार पर नई विश्व व्यवस्था के सृजन पर भी बल दिया। उन्होंने 2 फरवरी 2019 को अहमदाबाद में 'गांधी मंडेला विरासत' विषय पर व्याख्यान भी दिया, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान और गुजरात विद्यापीठ ने किया था तथा 28 जनवरी 2019 को स्कूल ऑफ द इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली द्वारा आयोजित व्याखान-माला में "अफ्रीका में भारत और दक्षिण अफ्रीका", विषय पर भी व्याख्यान दिया।

सुश्री आर्मिडा साल्सिया अलिसजाहबाना, कार्यकारी सचिव, यूएन-ईएससीएपी के साथ संपर्क सत्र

सुश्री आर्मिडा साल्सिया अलिसजाहबाना, कार्यकारी सचिव, यूएन-ईएससीएपी ने एक संपर्क सत्र के लिए 22 जनवरी 2019 को आरआईएस का दौरा किया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया जिसके बाद संकाय सदस्यों द्वारा आरआईएस कार्य पर प्रस्तुतिकरण पेश किया गया। डॉ. नागेश कुमार, निदेशक, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया कार्यालय, यूएनईएससीएपी; डॉ. राजन सुदेश रत्ना, आर्थिक कार्य अधिकारी, यूएनईएससीएपी; श्री के. एल. थापर, अध्यक्ष, एशियाई परिवहन विकास संस्थान; और श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति ने भी संपर्क सत्र में भाग लिया।

युवा राजनयिकों कॉन्क्लेव 2.0- भारत-आसियान संबंधों में स्फूर्ति लाना

आरआईएस ने विजन इंडिया फाउंडेशन (वीआईएफ) के साथ संयुक्त रूप से 17 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में युवा राजनयिकों के कॉन्कलेव 2.0- भारत-आसियान संबंधों में स्फूर्ति लाना' का आयोजन किया। राजदूत ए.के. बनर्जी, आईएफएस (सेवानिवृत्त), और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने प्रारंभिक टिप्पणियां की। 'भारत-प्रशांत क्षेत्र में प्रादेशिक वास्तुकला को अर्थपूर्ण रूप से तैयार करने में भारत-आसियान

संबंध की भूमिका' विषय पर प्रथम सत्र की अध्यक्षता राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस द्वारा की गई। इस सत्र में श्री संजय पुलीपाका विशिष्ट फेलो, आरआईएस, एनएमएमएल ने 'भारत-प्रशांत के डायनेमिक्स में अभियान की केन्द्रीयता' विषय पर और प्रोफेसर हर्ष वी. पंत, किंग्स कॉलेज लंदन ने एक सामरिक अवधारणा के रूप में 'क्वाड' के उद्‌भव पर व्याख्यान दिया। 'भारत-आसियान: भिन्न संबंधित संस्कृतियों' विषय पर सत्र की अध्यक्षता सुश्री अरुणिमा गुप्ता, वीआईएफ ने की। महामहिम श्री सिद्‌धार्तो रेजा सूर्यादिपूरों, राजदूत इंडोनेशिया के दूतावास ने पारस्परिक लाभप्रद संबंध का निर्माण करने के लिए अतीत के भारत-इंडोनेशिया संबंधों को सुदृढ़ बनाना' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. गौतम कुमार झा जेएनयू ने भारत-आसियान सभ्यात्मक आंतरिक संबंधों को समझना' विषय पर मत व्यक्त किया। श्री राजीव खेर, विशिष्ट फेलो आरआईएस के ने आरसीईपी और क्षेत्रीय आर्थिक वास्तुकला-अवसर, चुनौतियां और भावी मार्ग विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। भारतीय उद्‌योग परिसंघ (सीआईआई) ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र (आसियान) के साथ सीमा पार व्यापार को संवर्धित करना' विषय पर संबोधन दिया। समापन भाषण श्री शोभित माथुर, कार्यकारी निदेशक, वीआईएफ ने दिया।

'वित्तीय स्थायित्व को संवर्धित करने के लिए बृहत-मितव्ययी नीति' पर संगोष्ठी

आरआईएस ने जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी के साथ संयुक्त रूप से 14 मार्च 2019 को आरआईएस में 'बृहत-मितव्ययी नीति' पर संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। प्रोफेसर आर सुदर्शन, डीन, स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रारंभिक उद्‌बोधन दिया। श्री मारेक लिकाक, निदेशक, 'बृहत-मितव्ययी नीति' डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल बैंक, स्लोवाकिया ने मुख्य प्रस्तुतिकरण पेश किया जिसके उपरांत पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसके पैनलिस्ट थे: डॉ. आलोक शील, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, आईसीआरआईईआर; श्री लुदोविक ओडोर, वाइस गवर्नर, नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया; और श्री बंदुला जयशेकरा, विजिटिंग फेलो, आरआईएस। महामहिम श्री इवान लैंकैरिक, राजदूत सुश्री कैटरीना तोमकोवा, डिप्टी चीफ, स्लोवाक गणराज्य दूतावास, नई दिल्ली तथा प्रोफेसर बिस्वजीत बनर्जी, मुख्य अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री, स्लोवाक गणराज्य एवं अर्थशास्त्र प्रोफेसर, अशोका विश्वविद्‌यालय इस अवसर पर प्रतिभागियों के साथ शामिल थे।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली का संवर्धन : चुनौतियां और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं पर क्षेत्रीय परामर्श

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम (एफआईटीएम) ने 20 मार्च 2019 को बेंगलुरु में "भारतीय चिकित्सा प्रणाली का संवर्धन : चुनौतियां और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं" विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया। वैद्‌य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय ने उद्‌घाटन भाषण दिया। उद्‌घाटन सत्र में उपस्थित प्रतिष्ठित वक्ताओं में शामिल थे - श्री राजीव खेर, पूर्व वाणिज्य सचिव और प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; डॉ. बी आर रामकृष्ण, कुलपति एस-व्यासा विश्वविद्‌यालय, बेंगलुरु; और श्री अरविंद वर्चस्वी, प्रबंध निदेशक, श्री श्री त्तव, बेंगलुरु।

परामर्श के दौरान चार सत्रों का आयोजन किया गया जैसे 'उत्पाद मानक और गुणवत्ता आश्वासन: सफलता और

चुनौतियां', 'गुणवत्ता सेवाएं: मानकीकरण तंत्र', 'भारतीय चिकित्सा प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण: घरेलू तैयारी के लिए कार्यनीतियों की साझेदारी'; और औषधीय पादप शासन: संरक्षण और पैदावार। प्रतिष्ठित पैनलविदों में अन्य के साथ-साथ शामिल थे- श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय; डॉ. सुधांशु पांडेय, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डॉ. बालकृष्ण पशुपति, अध्यक्ष और न्यासी, विधि, पर्यावरण, विकास एवं शासन फोरम (फलेज), बेंगलुरू तथा श्रीमती मीनाक्षी नेगी, आयुक्त, आयुष विभाग, कर्नाटक। सरकारी अधिकारियों और शिक्षाविदों के अलावा उद्योग के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में बैठक में भाग लिया। विचार-विमर्श में उन चुनौतियों को प्रदर्शित किया गया जिनका सामना आयुष क्षेत्र कर रहा है तथा अनेक कदमों का सुझाव भी दिया जो सरकार और उद्योग के इस क्षेत्र के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉ. नम्रता पाठक, अनुसंधान एसोसिएट, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

'क्या आर्थिक बहुपक्षवाद कायम रह सकता है' विषय पर चर्चा के लिए बैठक

ब्रुसेल्स में स्थापित ब्रुएगेल थिंक टैंक के पूर्व संस्थापक और प्रमुख फ्रांसीसी सरकार के पूर्व नीतिगत आयोजना आयुक्त तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री जीन पिसानी-फेरी के साथ एक चर्चा बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 8 जनवरी 2019 को आयोजित की गई। श्री जीन पिसानी-फेरी ने 'क्या आर्थिक बहुपक्षवाद कायम रह सकता है' विषय पर अपनी बात रखी। डॉ. मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो ने मुख्य अतिथि और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रतिभागीयों में शामिल थे : डॉ. सुधांशु पांडेय, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डॉ. सुमन बेरी, पूर्व महानिदेशक एनसीएईआर; डॉ. रामगोपाल अग्रवाल, प्रतिष्ठित फेलो, नीति आयोग; और डॉ. मुकेश भटनागर, सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज।

औषधियों तक संवर्धित पहुंच और स्वास्थ्य में साक्ष्य आधारित नीति

आरआईएस ने रोगी स्वास्थ्य अनुपालन और निगरानी पर एक अध्ययन का समन्वय किया, जिसमें स्वास्थ्य -कर्मी (आशा) और आंकड़ा प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप का प्रयोग करना भी शामिल था। यह अध्ययन एर्नाकुलम, केरल के पांच तालुका में संचालित किया गया था, जिसके अंतर्गत एक लाख जनसंख्या को कवर किया गया था। इससे फलस्व्रूप कार्डियो-वैस्कुलर रोग (सीवीडी) से पीड़ित रोगियों की पहचान की गई और उनके स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संप्रेषणों की प्रतिक्रिया की निगरानी की गई और उसे निरंतर देखा जाता रहा। पूर्व अध्ययन के निष्कर्षों, जिसने इस अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया था, को सहयोगी समीश्रित जर्नलों में प्रकाशित किया गया है जिनमें बीएमजे ओपन, इंडियन हार्ट जर्नल और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी भी शामिल हैं। यह अध्ययन रिवार्ड परियोजना के अंतर्गत किया गया था (जिसमें स्वास्थ्य में स्वास्थ्य आधारित नीति निर्माण पर ध्यान-केंद्रित किया जाता है, और औषधि-अनुसंधान एवं विकास में अभिनवता को प्रोत्साहित किया जाता है) जिसका वित्त-पोषण यूरोपीय अनुसंधान परिषद (ईआरसी) ने भागीदार संस्थानों के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर, और आरआईएस के साथ किया था। चूंकि यह अध्ययन केरल सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों की प्रतिभागिता के साथ किया गया था, इसके निष्कर्षों को केरल में और वस्तुत: अन्य राज्यों में भी लोक स्वास्थ्य नीति के निर्माण में प्रासंगिक समझा गया। इस संबंध में आरआईआईएस ने 26 जून 2019 को तिरुवनंतपुरम में प्रचार-प्रसार कार्यशाला और 28 जून 2019 को नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक का आयोजन किया।

विज्ञान राजनयिकता पर आरआईएस-डीएसटी-एनआईएएस संगोष्ठी

आरआईएस ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से एनआईएएम, बेंगलुरु के साथ संयुक्त रूप से 'विज्ञान राजनयिकता कार्यक्रम' प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में क्षमता निर्माण, नेटवर्क विकास और सामरिक चिंतन के माध्यम से विज्ञान राजनयिकता की संभावना का पता लगाया गया।

इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, आरआईएस-एनआईएएम ने नई दिल्ली में 22 अप्रैल 2019 को विज्ञान राजनयिकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया जिसका उद्देश्य विज्ञान राजनयिकता के सिद्धांत और व्यवहार पर भारत के उभरने वाली व्याख्याओं पर चर्चा करना और विज्ञान राजनयिकता का प्रयोग करते हुए अंतरिक्ष, परमाणु और एयरोस्पेस के क्षेत्र में भारत के सफल प्रयासों को प्रस्तुत करना था। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण से कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके उपरांत प्रोफेसर वी.एस. रामामूर्ति, पूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अतिथि प्रोफेसर, एनआईएएस द्वारा विशेष व्याख्यान दिया गया। डॉ. साधना रेलिया, प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने आधार-व्याख्यान दिया; जिसके उपरांत डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान राजनयिकता फेलो, आरआईएस और पूर्व भारतीय राजदूत तथा प्रोफेसर डी. सुबा चंद्रन, डीन, स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, एनआईएएम और समन्वयक एनआइएएम विज्ञान राजनयिकता पहल ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए।

संगोष्ठी के दौरान प्रतिष्ठित वक्ताओं ने वर्तमान युग में विज्ञान की भूमिका का उल्लेख किया तथा उभरते हुए मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। जो मुख्य बातें उभरकर सामने आई वे थी : एक औपचारिक राजनयिक उपकरण के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग बीसवीं शताब्दी का एक अत्यंत उल्लेखनीय घटनाक्रम है। तथापि, यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसे सहयोग केवल वैज्ञानिक समुदाय तक सीमित रहे हैं तथा इसमें राज्य की अत्यंत सीमित भूमिका है। अत: राष्ट्रीय विकास और राष्ट्र की अथव्यवस्था में वृद्धि में प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक राजनयिकता की क्षमता को उन्नत बनाने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) स्थापित करने में भारत की अग्रणी भूमिका को हाल के दिनों में सफल विज्ञान राजनयिक प्रयास की उल्लेखनीय घटना के रूप में देखा जाता है। विचार-विमर्श के दौरान यह उल्लेख किया गया कि भारत को पड़ोस के अन्य विकासशील देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भागीदारी और बढ़ाने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयासों में भारत की सिद्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए, एशियाई क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के चुनिंदा देशों में राजनयिक लाभ के लिए इसका उपयोग किए जाने की संभावना का और अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे विचारों को विज्ञान राजनयिकता में भारत के प्रयासों में संवृद्धि करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे पड़ोसी क्षेत्र में सभी विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 'मुक्त विश्वविद्यालय' की स्थापना तथा स्वास्थ्य देखरेख को समूचे क्षेत्र में व्यापक जनसंख्या तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए 'टेलीमेडिसिन' को प्रोत्साहित करना। संगोष्ठी के दौरान भारत के विज्ञान राजनयिकता प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक मूल्यवान परिणाम उभरकार सामने आए। एक उच्च प्रौद्योगिकी वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों को प्रदर्शित करने, उनकी समीक्षा करने और उन्हें अंगीकृत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्भवन (इंटरफेस) केंद्र की स्थापना, कर भविष्य में और अधिक अन्वेषण किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत विवरण आरआईएस वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-वाणिज्य और डब्ल्यूटीओ पर संगोष्ठी

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने वैश्विक व्यापार वार्तालाप में केंद्रीय स्थान हासिल कर लिया है। इसे अनेक तरीकों से प्रतिपादित किया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर स्थायी मोराटोरियम का प्रस्ताव तथा ब्यूनस आयर्स में डब्ल्यूटीओ मंत्रालयी बैठक में ई-वाणिज्य पर एक बहुपक्षीय समूह का गठन। हाल ही में, भारत ने भी तेजी से विकसित होने क्षेत्र में एक विनियामक और विकास प्रोफाइल सृजित करने के लिए एक ई-वाणिज्य नीति का मसौदा तैयार किया है। भारत ने डब्ल्यूटीओ में ई-वाणिज्य पर बहुलवादी चर्चा में भाग न लेने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, ऐसे अनेक मुद्दें डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यमान हैं, जिन पर समूचे विश्व में नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों द्वारा पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आरआईएस ने 5 जून 2019 को "ई-वाणिज्य" पर एक परामर्श का आयोजन किया। राजदूत मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने परिचायक टिप्पणियां की। इसके उपरांत श्री सुधांशु पांडेय, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग ने प्रारंभिक उद्बोधन दिया। श्री राजीव खेर, विशिष्ट फेलो आरआईएस ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर मोराटोरियम तथा डब्ल्यूटीओ में ई-वाणिज्य चर्चाओं पर प्रथम कार्यकारी सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें सुश्री रश्मि बंगा, वरिष्ठ आर्थिक कार्य अधिकारी, यूएनसीटीएडी प्रमुख वक्ता थीं। राजदूत जयंत दासगुप्ता, डब्ल्यूटीओ के पूर्व भारतीय राजदूत तथा श्री ए.के. गर्ग, निदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य हस्तक्षेपकर्ता थे।

'डाटा संरक्षण, भागीदारी और प्रकमण का महत्व : भारत के लिए चुनौतियां और अवसर' विषय पर आगामी सत्र में मुख्य वक्ता श्री किरण कार्निक, पूर्व अध्यक्ष, नैसकॉम थे। श्री आनंद कृष्णन, भारत के डाटा सुरक्षा परिषद तथा श्री अरविंद गुप्ता, प्रमुख, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन हस्तक्षेपकर्ता थे। समापन सत्र मसौदा राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति पर था जिसमें श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग मुख्य वक्ता थे तथा श्री अभिजीत दास, प्रमुख, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र हस्तक्षेपकर्ता थे।

कृषि में भारत-अफ्रीका भागीदारी

भारत और अफ्रीका का मैत्री और सहयोग का अतीत इतिहास रहा है। जबकि उनके बीच विकास सहयोग वृद्धि हो रही है, दोनों क्षेत्रों कतिपय साझी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं विशेष रूप से खाद्य और पोषक सुरक्षा और उत्पादकता के क्षेत्रों में। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में भारत-अफ्रीका सहयोग को मजबूत बनाने के लिए अनेक पहलों को प्रोत्साहित किया है। चूंकि आगामी भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक मुद्दे और अवसर सामने आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, आरआईएस कृषि क्षेत्र में भारत-अफ्रीका सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाओं को सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान कर रहा है। इस प्रयास के अनुक्रम में, आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थाओं (आईआरआरआई) के सहयोग से 7 जून 2019 को "कृषि में भारत-अफ्रीका भागीदारी पर गोलमेज" का आयोजन किया। महामहिम श्री बेन जूबर्ट, कार्यवाहक उच्चायुक्त, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की।

कृषि में भारत-अफ्रीका सहयोग : संभावनाओं और चुनौतियों पर सत्र-1 की अध्यक्षता डॉ. सुरेश पाल, निदेशक, आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था और नीति अनुसंधान संस्थान ने की। डॉ. अलका भार्गव,

अपर सचिव, (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग भारत-अफ्रीका कृषि अनुसंधान एंड विकास और प्रौद्योगिकीयां विषय पर आयोजित सत्र-2 की अध्यक्ष थीं। समापन सत्र की अध्यक्षता डॉ. अरबिंद मित्रा, वैज्ञानिक सचिव, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा की गई। डॉ. नीना मल्होत्रा, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय ने विशेष उद्बोधन किया। डॉ. नफीस मीह, दक्षिण एशिया प्रतिनिधि आईआरआई ने चर्चा के मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए।

विचार-विमर्श के दौरान अनेक नए विचार उभर कर सामने आये जो एशिया और अफ्रीका के साथ जुड़े आरआईएस के व्यापक कार्यक्रम में पर्याप्त सहयोग प्रदान करेंगे, जहां क्षेत्रीय विशिष्टताओं की संभावनाओं की तलाश की जा रही है, क्योंकि भारत अगले वर्ष भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) की तैयारियां कर रहा है। पहली बिंदु, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है, अफ्रीका को आगे बढ़ाने में सहायता के लिए एसडीजी की उल्लेखनीय भूमिका को रेखांकित करना है तथा इस बात पर ध्यान देना है कि किस प्रकार एसटीआई विद्यमान मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा मुद्दा भारत का स्वयं विकास अनुभव, भारत की स्वयं नीतिगत ताने-बाने, से जुड़ा है तथा यह कृषि, समुद्री अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन और पशुधन सहित विभिन्न क्षेत्रों के भारत-अफ्रीका के बीच भागीदारी को आगे बढ़ाने के संदर्भ में है। तीसरी मुख्य बिंदु अफ्रीकी देशों में भारतीय भागीदारों द्वारा अब तक किए गए सफल हस्तक्षेपों का उननयन किए जाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) द्वारा सफलतापूर्वक संचालित कॉटन-4 परियोजना का अनुभव एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अंतिम बिंदु संस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में है। भारतीय संस्थाएं अफ्रीका के साथ संबंध स्थापित कर रही हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और भारतीय संस्थाएं सहायता तंत्रों के रूप में एक-दूसरे की निकट आ रही है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह वही बात है, जिस पर भारत अफ्रीका के साथ संबंधों के संदर्भ में बल प्रदान कर रहा है। सांस्थानीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत द्वारा विभिन्न अफ्रीकी देशों में तेरह अफ्रीकी उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का सफल उदाहरण साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कृत्रिम आसूचना पर विशेष सत्र

आरआईएस कृत्रिम आसूचना (एआई) प्रौद्योगिकी और शासन में उभरते हुई वैश्विक प्रवृत्तियों और नीति निर्माताओं और विनियामकों, विशेष रूप से सामान्यत: भारत और विकासशील देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर निकटता के साथ नज़र बनाए हुए है। इसे ध्यान में रखते हुए, आरआईएस ने कृत्रिम आसूचना और समाज पर अनुसंधान का मापन करने और व्यापक विषयों और चिंताओं की पहचान करने के उद्देश्य से 23 अप्रैल 2019 को एक संक्षिप्त जागरूकता सत्र का आयोजन किया और उसके उपरांत कृत्रिम आसूचना और दूसरे शासन को जातिय, सामाजिक और कानूनी विवक्षाओं पर आगे अनुसंधान करने के लिए भावी मार्ग तैयार किया।

इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के उद्घाटन उद्बोधन के साथ हुई। राजदूत एस. टी. देवरे, अध्यक्ष अनुसंधान परामर्श परिषद् (आरएसी), आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रतिष्ठित वक्ता थे- श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; प्रोफेसर वी. कमकोटी,

कंप्यूटर विज्ञान एंड इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास; सुश्री सिंधुश्री खुल्लर, सदस्य, आरएसी, आरआईएस; डॉ. वी. सिद्धार्थ, भारत के प्रधानमंत्री की विज्ञान परामर्श परिषद के पूर्व सचिव; डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान राजनयिकता फेलो, आरआईएस और पूर्व भारतीय राजदूत; डॉ. साधना रेलिया, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; डॉ. एस. आर. राव, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग; सुश्री कविता भाटिया, निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; श्री मयंक, वैज्ञानिक डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

आरआईएस की ओर से डॉ. रवि श्रीनिवास, परामर्शक; श्री सुभमोय भट्टाचार्य, परामर्शक; डॉ. साब्यची साहा, सहायक प्रोफेसर; डॉ. अमित कुमार, अनुसंधान एसोसिएट और सुश्री गीतिका खंडूजा, अनुसंधान सहायक ने भी सत्र में भागीदारी की।

त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर इसका प्रभाव : तामु सीमा प्राधिकरण के साथ संपर्क

आरआईएस 'त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर इसका प्रभाव' विषय पर एक नया अध्ययन संचालित कर रहा है। इस अध्ययन के संबंध में, डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, आसियान-भारत केंद्र (एआईसी) आरआईएस के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय अध्ययन दल ने तामु का दौरा किया और तामु, म्यांमार में 9 अप्रैल 2019 को तामु सीमा व्यापार अधिकारियों के साथ भेंट की। इस बैठक में भारतीय महावाणिज्य दूत श्री नंदन सिंह भैसोरा भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रोफेसर प्रियरंजन सिंह, मणिपुर विश्वविद्यालय, भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिला कलेक्टर, तामु; व्यापार, सीमा शुल्क विभाग; मोरेह और तामु के व्यापार चैम्बर्स तथा भारत और म्यांमार के अन्य हितधारकों और व्यापार समुदाय ने भाग लिया। सीमा व्यापार, प्रक्रियाओं, संयुक्त सीमा व्यापार समिति गठित करने, रुपया व्यापार, संयोजक परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, ई-वीजा, सीमा पास, वायु और बस संयोजकता, मोटर वाहन करार और विभिन्न अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

एक्ट ईस्ट पर संगोष्ठी: पूर्वोत्तर सीमा में भारत का व्यापार

आरआईएस ने 3 जून 2019, नई दिल्ली को "एक्ट ईस्ट: पूर्वोत्तर सीमा पर भारत का व्यापार" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत गौतम मुखोपाध्याय ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की तथा प्रारंभिक उद्बोधन दिया। डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, आसियान-भारत केंद्र (एआईसी), आरआईएस ने "एक्ट ईस्ट: पूर्वोत्तर भारत में व्यापार" पर प्रस्तुतिकरण पेश किया। उनके प्रस्तुतिकरण में एक्ट ईस्ट नीति (एईपी) के अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में चुनौतियों और अवसरों को व्यापक रूप से शामिल किया गया था। विशेष रूप से, डॉ. डे ने पूर्वोत्तर भारत की पहले किए गए और हालिया क्षेत्रीय दौरों के बारे में बात की तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की संभावनओं को तलाशने के लिए अनेक निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें प्रदान की तथा विभिन्न सीमा संयोजकता परियोजनाओं और पहलों का उल्लेख किया। श्री वनलालरुआता फनाई, सहायक महाप्रबंधक, अनुसंधान एवं विश्लेषण समूह, एक्जिम बैंक इसमें चर्चा में शामिल थे। संगोष्ठी में अन्य लोगों के साथ-साथ अनुसंधान विद्वानों, सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों ने भाग लिया।

भारत-मध्य एशिया: पारंपरिक संबंध और विकास भागीदारी

भारत ने सदैव ही मध्य एशियाई देशों के साथ विकास सहयोग को सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता प्रदान की है। इस आवश्यकता को समझते हुए, आरआईएस ने 4 अप्रैल 2019 को 'भारत-मध्य एशिया: पारंपरिक संबंध और विकास भागीदारी' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस द्वारा स्वागत भाषण से हुआ। राजदूत आलोक डिमरी, किर्गिस्तान में भारत के राजदूत, मुख्य वक्ता थे। उनके भाषण के बाद महामहिम श्री असेन असिएव, एम्बैस्डर एक्ट्राआर्डिनरी एंड प्लेनीपोटेंशियरी, किर्गिज गणराज्य दूतावास; महामहिम श्री शालर गोल्डी नाजारोव, राजदूत, तुर्कमेनिस्तान दूतावास; महामहिम एजामजॉन मंसूरोव, प्रथम सचिव, डिप्टी डैड ऑफ मिशन, भारत में उज्बेकिस्तान दूतावास; तथा डॉ. राम उपेंद्र दास, प्रमुख और प्रोफेसर, प्रादेशिक व्यापार केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्था के बीच वार्ता आयोजित की।

एफटीए और भारतीय अर्थव्यवस्था

मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक चर्चा बैठक का आयोजन 9 मई 2019 को आरआईएस में किया गया था। चर्चा में शामिल प्रतिष्ठित व्यक्ति थे- श्री सुधांशु पांडेय, अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच; श्री दामु रवि, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; डॉ. रतिन रॉय, निदेशक, एनआईपीएफपी; डॉ. अभिजीत दास, प्रमुख, सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज, आईआईएफटी; श्री अनिलेश महाजन; और डॉ. राम उपेंद्र दास, प्रमुख, प्रादेशिक व्यापार केंद्र। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, प्रोफेसर एस के मोहंती; राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो; और श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस से विचार-विमर्श में प्रतिभागिता की।

"दक्षिण एशिया में सत्त विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावना का प्रयोग करना" पर प्रादेशिक नीतिगत वार्ता

आरआईएस ने यूएन-ईएससीएपी के साथ संयुक्त रूप से "दक्षिण एशिया में सत्त विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावना का प्रयोग करना" विषय पर एक क्षेत्रीय नीतिगत वार्ता का आयोजन 20 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में किया। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और भारत के चिंतन संस्थानों के प्रतिष्ठित प्रमुखों को एक मंच पर एकत्र किया ताकि दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के लिए उपक्षेत्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए विद्यमान अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की जा सके। कार्यक्रम का शुभांरभ डॉ. नागेश कुमार, प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र ईएससीएपी दक्षिण एंड दक्षिण-पश्चिम एशिया कार्यालय (यूएनईएससीएपी-एसएसडब्ल्यूए) तथा डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, (आरआईएस) ने किया। प्रतिष्ठित वक्ताओं में शामिल थे: श्री नजीर कबीरी, कार्यकारी निदेशक, बिरुनी संस्थान, अफगानिस्तान; डॉ. सेलिम रैहान, कार्यकारी निदेशक, एसएएनईएम, बांग्लादेश; श्री सोनम ताशी, प्रमुख, नीति एवं आयोजना प्रभाग, आर्थिक कार्य मंत्रालय, भूटान; डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), भारत; श्री दिलीप चेनॉय, महासचिव, फिक्की; डॉ. पॉश राज पांडे, अध्यक्ष, साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड इकोनॉमिक्स एंड एंवायर्नमेंट (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल; और डॉ. दुश्नी वेराकून, कार्यकारी निदेशक, इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज (आईपीएस) श्रीलंका। इससे पूर्व, प्रतिनिधियों ने आरआईएस संकाय के साथ संपर्क सत्र में भाग लेने के लिए आरआईएस का भी दौरा किया।

वैश्वीकृत विश्व में गैर पारंपरिक आर्थिक और सुरक्षा जोखिम

आरआईएस ने इंस्टिट्यूट फॉर पॉलिसी, एडवोकेसी और गवर्नेंस (आईपीएजी) एशिया पैसिफिक के साथ भागीदारी करते हुए गुरुवार, 28 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में 'वैश्वीकृत विश्व में गैर-पारंपरिक आर्थिक और सुरक्षा जोखिम' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में गैर-पारंपरिक सुरक्षा और आर्थिक परिदृश्य के विषय विशेषज्ञों को वैश्विक समुदाय से समक्ष आ रहे आर्थिक और सुरक्षा संबंधी जोखिमों की मात्रा पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ एकत्र हुए तथा उन्होंने नीतिगत रणनीतियों और विकल्पों की तलाश की। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित सत्र शामिल थे: पर्यावरणीय और ऊर्जा सुरक्षा; प्रवास; व्यापार सत्र; परा-राष्ट्रीय अपराध का परिणाम तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, मानव और आर्थिक सुरक्षा में साइबर विश्व का उदय।

भारत-अफ्रीका आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना

आरआईएस ने अफ्रीका के साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और वित्त संबंधी सहयोग पर एक प्रमुख मौलिक अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस पर विचार करते हुए, मुख्य प्राथमिकताओं, मुख्य चुनौतियों और संभव संस्थानिक सहयोगों और प्रतिक्रियाओं की पहचान करने में आगे के मार्ग को तलाशने के लिए 27 जून 2019 को एक परामर्श आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने चर्चा में भाग लिया: राजदूत सतीश मेहता; राजदूत अजीत कुमार; राजदूत दिव्यभ मनचंदा; राजदूत आजमपुर रंगियाह घनश्याम; राजदूत राधिका लोकेश; श्री जी. वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय; श्री मोहित यादव, निदेशक (सीएंडडब्ल्यूए), विदेश मंत्रालय; श्री ई. बी. राजेश, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय निदेशक-अफ्रीका, सीआईआई; डॉ. मिलन शर्मा, प्रमुख-वैश्विक पहुंच, आईएलएंडएफएस क्लस्टर्स विकास पहल लिमिटेड, श्री नदीम पंजेतन, मुख्य महाप्रबंधक, एक्जिम बैंक; प्रोफेसर अजय कुमार दुबे, जेएनयू; डॉ. शाहिद अहमद, पूर्व में प्रोफेसर और प्रमुख, जामिया मिलिया इस्लामिया; प्रोफेसर सुरेश कुमार, पूर्व में, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय; और डॉ. रुचिता बेरी, आईडीएसए। आरआईएस से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ. एस.के. मोहंती; राजदूत अमर सिन्हा; राजदूत भास्कर बालाकृष्णन; डॉ. पी.के. आनंद; श्री कृष्ण कुमार; डॉ. रवि श्रीनिवास; डॉ. बीना पांडे; श्री अरुण एस नायर; डॉ. साब्यची साहा; डॉ. प्रियदर्शिनी दास; डॉ. अमित कुमार; डॉ. सुशील कुमार; सुश्री निमिता पांडी; डॉ. आभा जायसवाल; श्री सी.एम. अरोड़ा; और डॉ. नम्रता पाठक ने चर्चा में भाग लिया।

एशियाई आर्थिक एकीकरण की शुरूआत

आरआईएस में आसियान-भारत केंद्र (एआईसी) ने आसियान अध्ययन केंद्र (एएससी) और इंडिया स्टडीज सेंटर के साथ संयुक्त रूप से 6 जून 2019 को चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय, बैंकॉक, में जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का विमोचन किया। प्रोफेसर सुथीफंद चिराथिवत, कार्यकारी निदेशक आसियान अध्ययन केंद्र (एएससी) ने प्रारंभिक उद्बोधन दिया। डॉ. मिया मिकिक, निदेशक, व्यापार, निवेश और अभिनवता, यूएनईएससीएपी, बैंकॉक ने विशेष व्याख्यान दिया। दि जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन (जेएईपी) जिसका आरआईएस में आसियान-भारत सेंटर (एआईसी) तथा चुलांग्कोर्न विश्वविद्यालय

के आसियान अध्ययन केंद्र (एएससी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशन किया जाता है, एशिया के संबंधित अर्थशास्त्र में अनेक विषयों पर व्यापक कवरेज उपलब्ध कराती है जिसमें मौजूदा अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं और देश अध्ययनों का अन्वेषण भी शामिल है। "एशियन एकीकरण : उभरती प्रवृत्तियां और चुनौतियां" विषय पर एक पैनल चर्चा का डॉ. पिटी, निदेशक, शैशणिक मामलें, आसियान अध्ययन केंद्र, चुलालोंगकोर्न यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। पैनलिस्ट थे: डॉ. मिया मिमिक, डॉ. चैरिट तिगंसादादह, एसोसिएट प्रोफेसर और पूर्व निदेशक, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय; डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक आसियान-भारत केन्द्र (एआईसी) आरआईएस, नई दिल्ली और डॉ. विताड़ा ऑन्कूनवाटाका, आर्थिक कार्य अधिकारी, यूएनईएससीएपी। अंत में डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

'औषधीय पादप क्षेत्र का निर्यात संवर्धन : चुनिंदा औषधीय पादपों के लिए कार्यनीति' पर अध्ययन पर परामर्श

आगामी कदम उठाने से पूर्व विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, 15 अप्रैल 2019 को आरआईआईएस में 'औषधीय पादप क्षेत्र का निर्यात संवर्धन : चुनिंदा औषधीय पादपों के लिए कार्यनीति' पर अध्ययन पर एक परामर्श चर्चा का आयोजन किया गया।

यह बैठक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ प्रारंभ हुई। श्री राजीव खेर, पूर्व वाणिज्य सचिव और प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने विशेष व्याख्यान दिया और डॉ सलाहुद्दीन अयूब, रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस ने अध्ययन की वर्तमान स्थिति पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। इसके बाद विभिन्न प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए जैसे : श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय; श्री श्यामल मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय; श्री अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण; सुश्री अमरजीत आहूजा (आईएएस सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, औषधीय पादप विशेषज्ञ समिति; राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण; श्री अश्विन के. नायक, अध्यक्ष, एसएचईएफईएक्सआईएल; प्रोफेसर तनूजा मनोज नेसारी, सीईओ, एनएमएमपीबी; श्री प्रहलादन अय्यर, मुख्य महाप्रबंधक, एक्जिम बैंक; और डॉ. देवांजनि रॉय, कार्यकारी निदेशक, एसएचईएफईएक्सआईएल। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

आसियान भारत-प्रशांत दृष्टिकोण और भारत

'भारत-प्रशांत' निर्माण ने हाल ही के वर्षों में काफी महत्व हासिल कर लिया है। भारत और आसियान, दोनों ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखते हैं। भारत एक ऐसे भारत-प्रशांत में विश्वास करता है जो मुक्त, खुला और अंतर्वेशी हो तथा एक हो, जो सहयोगी और सहायक नियम-आधारित व्यवस्था पर निर्मित किया गया हो। इसके लिए समर्थन न केवल क्षेत्र से अपितु, समूचे विश्व की ओर से प्राप्त हुआ है। भारत-प्रशांत एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनेक एशियाई शक्तियां विशेष रूप से भू-आर्थिक संदर्भ में पुन: विकास कर रही हैं। जबकि आसियान की केंद्रीयता को स्वीकार किया गया है, आसियान और भारत भारत-प्रशांत के निर्माण में साथ मिलकर काम कर सकते हैं। समुद्रिक पड़ोसियों के रूप में, साझे सामुदायिक क्षेत्र, महासागरों और सागरों पर साझी निर्भरता तथा महासागर संसाधनों के सत्त दोहन के महत्व पर साझी समझ रखते हुए, आसियान

और भारत भारत हिंद-प्रशांत भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श भागीदार हो सकते हैं।

आसियान देशों ने अपने संबंधित भारत-प्रशांत वर्जनों को प्रस्तुत किया। इंडोनेशिया ने 20 मार्च 2019 को जकार्ता में एक उच्चस्तरीय भारत-प्रशांत वार्ता का आयोजन किया। थाईलैंड आसियान का अध्यक्ष होने के नाते भारत-प्रशांत एजेंडा को तैयार करने पर सक्रियता से कार्य कर रहा है तथा थाईलैंड की भारत-प्रशांत कार्यनीति को समझना महत्वपूर्ण है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में इन मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए, डॉ. सुरिया चिंदावोंगसे, महानिदेशक, आसियान मामलें विभाग, विदेश मंत्रालय, थाईलैंड ने 10 अप्रैल 2019 को आरआईएस में "आसियान भारत-प्रशांत दृष्टिकोण और भारत" विषय पर आरआईएस जलपान वार्ता प्रस्तुत की। महामहिम श्री चुटिन्टॉर्न गोंगसाक्दी, भारत में थाईलैंड के राजदूत ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया। संगोष्ठी की अध्यक्षता राजदूत अनिल वाधवा, पूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने की। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने खुली चर्चा में भाग लिया।

अमेरिका-भारत व्यापार संबंध

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बढ़ती हुई अभिसारिता के हितों के आधार पर "वैश्विक सामरिक साझेदारी" के रूप में निरंतर विकसित हो रहें हैं। अमेरिका और भारत व्यापार में एक लंबे समय से भागीदार रहे हैं। आरआईएस अमेरिका-भारत आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान संचालित करने के लिए कार्य करता रहा है। इस कार्य के भाग के रूप में, आरआईएस ने 25 जुलाई 2019 को आरआईएस में अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। डॉ. सुरूपा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों, यूनीवर्सिटी ऑफ मैरी वाशिंगटन फ्रेडरिकिक्सबर्ग, अमेरिका मुख्य वक्ता थीं।

अपने प्रस्तुतिकरण में, वक्ता ने यह उल्लेख किया कि ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका के अनेक द्विपक्षीय संबंधों ने नाटकीय व्यवधानो का सामना किया है। इस पृष्ठभूमि में, भारत के साथ सामरिक संबंध लगभग समान गति से जारी रहे हैं। तथापि, दो लोकतंत्रों के बीच व्यापार संबंधों में वर्तमान अमेरिकी पहलों के फलस्वरूप उतार-चढ़ाव आया है, जिनमें स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफों का अधिरोपण, भारत के लिए अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम को समाप्त करना और सेवा क्षेत्र व्यापार में भारत को चुनौती देना भी शामिल है। यह भी तर्क दिया गया कि व्यापार में ठहराव भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर वैश्विक मानदंडों पर दीर्घकालिक, सामान्य संघर्ष का एक भाग है। इसके साथ, जबकि व्यापार विवाद पर इसके प्रभाव के अत्यंत अल्प ही रहने की संभावना है। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इस चर्चा में भाग लिया।

बिम्सटेक का भावी अभिविन्यास

आरआईएस अपनी स्थापना से ही बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के कार्यक्रमों के साथ सक्रिय रूप से सहयोजित रहा है। हाल ही में, बिम्सटेक के सदस्य देशों के साथ हमारे संबंधों का सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में, आरआईएस ने 24 जुलाई 2019 को आरआईएस में 'बिम्सटेक का भावी अभिविन्यास' विषय पर माननीय श्री एम. शाहिदुल इस्लाम, महासचिव, बिम्सटेक के साथ एक वार्ता का आयोजन किया। राजदूत डॉ. मोहन कुमार, अध्यक्ष,

आरआईएस, ने इसकी अध्यक्षता की। महामहिम श्री चुटिन्टॉर्न गोंगसाक्दी, राजदूत, थाईलैंड दूतावास, नई दिल्ली तथा श्री शेशाद्री चारी, सदस्य, आरआईएस, शासी परिषद् विशिष्ट वार्ताकार थे। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने खुली चर्चा में भाग लिया।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग में विज्ञान राजनयिकता और क्षमता निर्माण

आरआईएस ने अपने भारतीय राजनयिकता फोरम (एफआईएसडी) के अंतर्गत 18 सितंबर 2019 को एक मासिक व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ की जिसमें डॉ. ए सेंथिल कुमार, निदेशक, एशिया-प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा केंद्र (सीएसएसटीईपी) (यूएस केंद्र) देहरादून ने "अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में विज्ञान राजनयिकता और क्षमता निर्माण" पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने प्रारंभिक उद्बोधन दिया जिसमें उन्होंने विभिन्न सामाजिक चुनौतियों तथा एसडीजी का निवारण करने में एसटीआई की निर्णायक भूमिका का उल्लेख किया। आमंत्रित वक्ता डॉ. सेंथिल कुमार ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुप्रयोगों के विभिन्न आयामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने ऐसे नौ सामाजिक क्षेत्रों का उल्लेख किया जो अंतरिक्ष आंकड़ों से लाभान्वित होते हैं। ये हैं : आपदाएं, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, जलवायु, जल, मौसम, पारिस्थितिकी और जैव विविधता। इसके अलावा, अंतरिक्ष आंकड़े नगर आयोजन, परिवहन और संचार नेटवर्क के लिए बहुत उपयोगी हैं।

सीएसएसटीएपी की भूमिका पर 1995 में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए अमेरिकी कार्यालय (यूएन-ओएसएसए) द्वारा एक विशिष्ट केन्द्र स्थापित किया गया था, डॉ. सेंथिल कुमार ने उन विभिन्न क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों (जिनमें विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रमों भी शामिल हैं) पर प्रकाश डाला जो यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही वृत्तिकों के लिए संचालित करता है, जो विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के लिए आयोजित किए जाते हैं। अब तक, 36 एशिया-प्रशांत देशों के 2217 प्रतिभागी इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से लाभान्वित हो चुके है। भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और नेपाल के साथ अपने स्व-शिक्षण शिक्षा डैशबोर्ड "स्वामी" (सिस्टम फॉर वेदर एंड आपदा मैनेजमेंट इंफार्मेशन) को भी साझा करता है। डॉ. सेंथिल कुमार ने भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के छह आयामों के बारे में भी बात की, अर्थात् अंतरिक्ष अवसंरचना, अनुप्रयोग, संस्थायीकरण, भू-खंड, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतरिक्ष के क्षेत्र में 34 देशों के साथ सहयोग व्यवस्था भी बनाए रखता हैं। व्याख्यान के दौरान विज्ञान के आंकड़ा राजनयिकता की आवश्यकता भी वर्जित की गई, ताकि प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए देशों के मध्य आपदाओं सें संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जा सकें।

समुद्री अर्थव्यवस्था पर तीसरी आसियान-भारत कार्यशाला

थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश मंत्रालय, आसियान और पूर्वी एशिया आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता, राष्ट्रीय सामुद्रिक (एनएमएफ), नई दिल्ली तथा विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 12 सितंबर 2019 को बैंकॉक में समुद्री अर्थव्यवस्था पर तीसरी आसियान-भारत कार्याशाला का आयोजन किया। डॉ. सुरिया चिंडावोंगसे, महानिदेशक, आसियान मामलें विभाग, थाईलैंड विदेश मंत्रालय ने प्रारंभिक भाषण दिया। आधार-व्याख्यान महामहिम

सुश्री सुचित्रा दुरै, थाईलैंड में भारतीय राजदूत द्वारा दिया गया। इस कार्यशाला में आसियान सदस्य राज्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और आसियान और भारत के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला को चार सत्रों में विभाजित किया गया था ताकि समुद्री अर्थव्यवस्था पर गहनता से चर्चा की जा सके और ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां आसियान और भारत साथ मिलकर सहयोग दे सकते हैं। और कार्य कर सकते हैं। ये चार सत्र थे (1) समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास; (2) समुद्रिक संसाधनों का सत्त उपयोग; (3) समुद्री संयोजकता और (4) समुद्री सुरक्षा और राजनयिकता। समुद्री अर्थव्यवस्था पर तीसरी आसियान-भारत कार्यशाला ने समुद्री अर्थव्यवस्था पर गहन विचार-विमर्श किया, जिसे निरंतर अंतर्वेशी और संपोषणीय विकास और वृद्धि के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है।

आसियान और भारत में, समुद्री अर्थव्यवस्था की पहचान तटीय क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलाप के एक नए स्तंभ के रूप में की गई है तथा यह महासागरीय संसाधनों के सत्त दोहन के माध्यम से अनेक सुदूर प्रदेशों को जोड़ती है। समुद्री अर्थव्यवस्था ज्ञान गहन है जिसके अनेक स्रोतो से विशेषज्ञता की अपेक्षा होती है, अत: विशेषशता की पूलिंग के संदर्भ में भारत और आसियान के बीच सहयोग की आवश्यकता विद्यमान है। चूंकि समुद्रिक पड़ोसी साझे समुद्रिक प्रदेश को साझा करते हैं, महासागरों और समुद्रों की साझी निर्भरता तथा महासागरीय संसाधनों के सत्त उपयोग के महत्व पर साझी समझ को महसूस करते हुए आसियान और भारत समुद्री अर्थव्यवस्था के एजेंडा को आगे ले जाने के लिए आदर्श भागीदारी हैं। क्षेत्र में समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने और समुद्री अर्थव्यवस्था में आसियान-भारत सहयोग में वृद्धि करने के लिए प्रतिभागियों ने अनेक नीतिगत सिफारिशों का सुझाव दिया। अंतत: श्री असी मामनी, उप महानिदेशक, आसियान मामलें विभाग, थाईलैंड विदेश मंत्रालय ने समापन भाषण दिया। श्री निखिलेश गिरि, संयुक्त सचिव, भारत-प्रशांत प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत ने समापन भाषण दिया। प्रोफेसर यासुहिरो यामादा, ईआरआईए के अध्यक्ष के विशेष सहायक ने विशेष संबोधन दिया। डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

राज्य का विधि और विधि का राज्य

आरआईएस ने नानी पलकीवाला जन्म शताब्दी उत्सव संचालन समिति और भारत इंटरनेशनल सेंटर के साथ 15 नवंबर 2019 को डॉ. बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 'राज्य की विधि और विधि का राज्य' विषय पर पलकीवाला स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत (डॉ.) मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस और मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त) मानद सचिव नानी पलकीवाला जन्म शताब्दी समारोह संचालन समिति के उद्गारों के साथ हुई। श्री एन. एन. वोहरा, अध्यक्ष, आईआईसी ने इसकी अध्यक्षता की।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

'विज्ञान राजनयिकता' पर आईटीईसी कार्यक्रम

'विज्ञान राजनयिकता' पर आईटीईसी-आरआईएस क्षमता निर्माण कार्यक्रम 7-18 जनवरी 2019 तक आरआईएस में आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में 25 देशों के 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल किए गए: विज्ञान राजनयिकता का परिचय: अवधारणाएं और आयाम;

विज्ञान राजनयिकता में अनुभव साझेदारी; जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता; जलवायु परिवर्तन; सांस्कृतिक दौरे; डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों; प्रौद्योगिकी, व्यापार और विज्ञान राजनयिकता; और एसडीजी और दक्षिण-दक्षिण सहयोग। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण से हुआ। प्रोफेसर विजय राघवन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान राजनयिकता फेलो, आरआईएस और पूर्व भारतीय राजनयिक और डॉ. पूर्णिमा रूपाल, निदेशक, सीईएफआईपीआरए ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। समापन सत्र 18 जनवरी 2019 को आयोजित किया, जिसमें श्री दिनकर अस्थाना, अपर सचिव, (डीपीएआईआई), विदेश मंत्रालय ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इसके उपरांत प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

आईटीईसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दें और विकास नीति पर कार्यक्रम

"अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईआईडीपी) पर आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम 11 फरवरी से 8 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया। 20 देशों से मध्यम स्तर के सरकारी कर्मचारियों/राजनयिकों, नीति वृत्तिकों और स्कॉलरों सहित तीस प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल किए गए: व्यापार और वित्त पर वैश्विक सांस्थानिक अवसंरचना, क्षेत्रीय गतिशीलता, आर्थिक एकीकरण और विकास सहयोग; अवसंरचना वित्तपोषण: विकासशील देशों और अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्यताए; तथा समाज, भागीदारी और संस्कृति: भारतीय संदर्भ। प्रतिष्ठित माननीय भारतीय विशेषज्ञों ने इन मुद्दों के विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से अपने उद्गार व्यक्त किए।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण से हुई। श्री जे.एस. मुकुल, डीन, विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) ने उद्घाटन भाषण दिया। समापन सत्र की अध्यक्षता डॉ. मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस ने की। समापन भाषण सुश्री नगमा एम. मलिक, संयुक्त सचिव, (पीपीएंडआर), विदेश मंत्रालय ने दिया। आईटीईसी प्रतिभागियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण दिए गए समूह 1 - एसडीजी और सार्वजनिक नीति पर सुश्री करीना मारियाला जारा तामायो (इक्वाडोर); समूह 2 - अवसंरचना/संयोजकता/नवीकरणीय ऊर्जा, श्रीमती मिनाक्षी दाबी हौश्री (मॉरीशस); समूह 3- व्यापार (व्यापार संतुलन और पूंजी प्रवाह पर एफटीए का प्रभाव): श्री मोसेस लुफुके (तंजानिया); समूह 4 - जी20/ब्रिक्स श्री हेल्डर पाउलो मचादो सिल्वा (ब्राजील); समूह 5 - व्यापार (व्यापार में विकासशील देशों की मोलतोल की शक्ति): श्री टेस्फाये एयालेव मेकोनेन (इथियोपिया); और समूह 6 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना, विकास वित्त और वैश्विक कर मुद्दों पर डॉ. हेबतल्लाह हनाफी महमूद आदम (मिस्र)।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रक्रिया पर चौथा आरआईएस-एक्सिम बैंक ग्रीष्मकालीन विद्यालय

आरआईएस ने एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से 10-19 जून 2019 को 'आरआईएस-एक्जिम बैंक ग्रीष्मकालीन विद्यालय - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रक्रिया' के चौथे संस्करण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विद्वानों का क्षमता निर्माण करना था। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया था - व्यापार सिद्धांत में हालिया घटनाक्रम; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डेटाबेस और सूचना तथा व्यापार विश्लेषण में उपकरण और तकनीक; एफटीए और क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक को समझना; प्रौद्योगिकी के व्यापार के मुद्दे; तथा व्यापार और विकास: आईपीआर और नए मुद्दे। इसमें 49 विद्वानों ने भाग लिया जिनमें दो बिम्सटेक सचिवालय से तथा एक-एक तीन बिम्सटेक देशों (बांग्लादेश, नेपाल और थाईलैंड) में थे।

कार्यक्रम का प्रारंभ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण से हुआ, जिसके उपरांत प्रोफेसर एस. के. मोहंती, आरआईएस द्वारा उद्बोधन दिया गया। श्री देबाशीष मल्लिक, डीएमडी, एक्पोर्ट-इंपोर्ट बैंक ने अपने उद्गार व्यक्त किए तथा उद्घाटन भाषण श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस द्वारा दिया गया। प्रोफेसर दीपक नैय्यर, प्रोफेसर एमेरिटस, जेएनयू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और विशेष व्याख्यान दिया।

कार्यक्रम ने छात्रों को प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की सहायता से व्यापार सिद्धांत के विभिन्न आयामों पर अपने ज्ञान के आधार को सुदृढ़ बनाते हुए उनके परिमाणत्मक कौशलों के गहरे ज्ञान को और भी व्यापक बनाया जिनमें समूचे देश के उच्च रैंकिंग वाले ज्ञान प्रदाता शामिल थे। इसमें न केवल सुस्थापित अनुमान और व्यापार, निवेश और सेवा डाटा तकनीकों का निर्वचन शामिल था, बल्कि इसने प्रतिभागियों को विकसित होती व्यापार और वित्त वैश्विक अवसंरचना की बेहतर समझ हासिल करने में भी समर्थ बनाया। दो दिवसीय व्यावहारिक अनुप्रयोग कार्यशाला का आयोजन भी उन्हें अनुभव जन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था, ताकि वे पढ़ाए गए सैद्धांतिक ढांचों के व्यावहारिक आयाम के लिए मेगा डेटा सेटों का निपटान कर सकें। ये प्रतिभागी निम्नलिखित विषयों पर समूहिक कार्यों पर लगाए गए थे: भारत का व्यापार निष्पादन; निवेश, वित्त और विनिमय दर; प्रौद्योगिकी, जीवीसी, प्रतिस्पर्धात्मकता; बहुपक्षवादिता और धर्मवाद; और व्यापार एवं नियोजन। उनके द्वारा तैयार किए लघु अनुसंधान लेखों को प्रकाशन “अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रक्रिया : समकालीन मुद्दें” में प्रकाशित किया गया था।

सतत विकास लक्ष्य

जानकारी और जागरूकता सृजित करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी क्रियान्वयन कार्यनीतियों का अन्वेषण करने के लिए, आरआईएस ने नई दिल्ली में 5-16 अगस्त 2019 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत एसडीजी पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरे संस्करण का संचालन संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में 24 देशों के 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस समूह ने शैक्षणिक और नीति-निर्माता के क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ संपर्क और उनके भाषणों की विषय वस्तु का लाभ उठाया। प्रतिभागियों को एसडीजी पर राष्ट्रीय और वैश्विक प्रगति पर प्रकाश डालने वाले विश्लेषणात्मक स्थिति पत्र तैयार करने के लिए समूहिक चर्चाओं में भी शामिल किया गया। ये पत्र “लोकलाइजिंग एसडीजी पर्सपेक्टिवस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़” नामक रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए।

विषय-संबंधी सत्रों के अलावा प्रतिभागियों के लिए अध्ययन दौरे भी आयोजित किए गए जिसके अंतर्गत उन्हें भारतीय संसद और अन्य संबद्ध मंत्रालयों में ले जाया गया। विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उनकी भेंट करवाई गई जिनमें शामिल थे : नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री हरदीप सिंह पुरी (जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार; और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं) तथा श्री प्रवीण श्रीवास्तव, सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री।

व्यापार और संधारणीयता

आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और विद्वानों के मध्य क्षमता बढ़ाने के लिए जुलाई 2018 में विशेष रूप से तैयार किया गया “आईटीईसी प्रोग्राम ऑन ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी” का शुभारंभ किया। पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण 8 से 19 जुलाई 2019 तक 16 देशों के 29 उम्मीदवारों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था जो दक्षिण एशिया, उप-सहारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका और कैरेबियन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कार्यक्रम में चार व्यापक स्तंभ थे: जैव-विविधता और जैव-सुरक्षा के मुद्दे जिनमें

जैविक विविधता कन्वेंशन, नागोया प्रोटोकॉल, आदि, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, गैर-टैरिफ उपाय, आदि, हरित वित्त, जलवायु वित्त, विनियम, व्यावसायिक नवाचार, आदि सहित वित्त-पोषण, और एफटीए और आरटीए में पर्यावरणीय प्रावधान भी शामिल थे। प्रतिभागियों को व्याख्यान में भाग लेने, और इन विषयों पर समूह कार्यों में संलग्न होने का लाभ प्राप्त हुआ - विकासशील देशों में जैविक संसाधनों के सतत दोहन : अधिक समृधि के लिए आनुवंशिक संसाधन; पर्यावरण वस्तुएं और सेवाएं: विकासशील देशों के लिए चुनौतियां और अवसर; विकासशील देशों में हरित वित्त-पोषण : मंगोलिया, केन्या और नाइजीरिया के अनुभव; और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में पर्यावरणीय प्रावधान। इन्हें *"व्यापार और संधारणीयता पर उभरते मुद्दे"* शीर्षक की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग को समझने पर आईटीईसी कार्यक्रम

आरआईएस ने नई दिल्ली में 11 से 22 नवंबर, 2019 तक 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग को समझने' पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) आयोजित किया। कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों के मध्यम स्तर के सरकारी अधिकारियों/ राजनयिकों, चिकित्सकों और विद्वानों सहित 30 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को प्रतिभागियों को दक्षिण-दक्षिण सहयोग (एसएससी) की एक एकीकृत और बहुआयामी समझ की ओर उन्मुख करने के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें इसकी विविधता और बहुलता से अवगत कराएगा। कार्यक्रम सैद्धांतिक ढांचे, वैश्विक वास्तुकला पर ध्यान केंद्रित करेगा और समावेशी विकास में प्रवेश के लिए सामने आ रही दबावकारी चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेगा। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय सहयोग और एसएससी के लिए एक मूल्यांकन ढांचे की दिशा में प्रयासों और चुनौतियों को भी कवर करेगा। इन-हाउस संकाय के अलावा, आरआईएस ने प्रतिभागियों के लाभ के लिए इन मुद्दों पर एक व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।

आरआईएस में आने वाले प्रतिनिधि

- इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट (आईटीडी) और चुलालांगकोर्न विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन केंद्र से प्रतिनिधिमंडल का दौरा।
- आईएसडी और थाईलैंड के चुलालांगकोर्न विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन केंद्र के प्रतिनिधिमंडल के लगभग 12 सदस्यों ने 15 जुलाई 2019 को आरआईएस में एआईसी का दौरा किया। डॉ. सूरत होरचेकुल, निदेशक, भारतीय अध्ययन केंद्र, राजनीति विज्ञान के संकाय, चुलालांगकोर्न विश्वविद्यालय थाईलैंड से आए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने बिम्सटेक और भारत के साथ बंगाल के सहयोग के दृष्टिकोण पर बातचीत की। डॉ. प्रबीर डे ने "बिम्सटेक: वर्तमान स्थिति और अवसरों" पर एक प्रस्तुतिकरण पेश किया, जिसके बाद बिम्सटेक और अन्य वैश्विक मुद्दों पर थाईलैंड के दृष्टिकोण पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बातचीत हुई। श्री महेश अरोड़ा, निदेशक (वित्त और प्रशासन), आरआईएस ने भी चर्चा में भाग लिया।
- युन्नान विश्वविद्यालय से चीन के तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9 अगस्त 2019 को आरआईएस में एआईसी का दौरा किया। आगंतुकों ने आपसी हितों के कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय विषयों पर चर्चा की, जिनमें विशेष रूप से बिम्सटेक, आसियान-भारत सहयोग और भारत-चीन सहयोग शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व युन्नान विश्वविद्यालय

के प्रोफेसर और उपाध्यक्ष डॉ. ली चेनयांग ने किया और इसके अन्य सदस्य थे, डॉ. लू गुआंगशेंग, प्रोफेसर, सेंटर फॉर चाइनाज़ नेबर डिप्लोमेसी स्टडीज, युन्नान विश्वविद्यालय; डॉ. लियू पैंग, एसोसिएट प्रोफेसर, म्यांमार अध्ययन संस्थान, युन्नान विश्वविद्यालय, युन्नान प्रांत, चीन; और श्री झांग लियांग, काउंसलर, पॉलिसी प्लानिंग सेक्शन के प्रमुख, भारत, नई दिल्ली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दूतावास। आरआईएस में आसियान-भारत केंद्र (एआईसी) के समन्वयक प्रोफेसर प्रबीर डे ने भारतीय विदेश नीति पर एक प्रस्तुतिकरण पेश किया और भारत और चीन के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

- मोरक्को के एक मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने 14 अक्टूबर 2019 को पारस्परिक-संपर्क सत्र के लिए आरआईएस का दौरा किया।
- भूटान के एक मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने 19 नवंबर 2019 को पारस्परिक-संपर्क सत्र के लिए आरआईएस का दौरा किया।

एसटीआईपी व्याख्यान माला

एसटीआईपी व्याख्यान माला के भाग के रूप में, निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- 10 जनवरी 2019 को भारत में विज्ञान कार्यक्रमों पर पैनल चर्चा। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने इसकी अध्यक्षता की। पैनलविद थे - प्रोफेसर वी. एन. राजशेखरन पिल्लई, स्वदेशी विज्ञान आंदोलन; डॉ. डी. रघुनंदन, ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क; प्रोफेसर दिनेश अबरोल, दिल्ली विज्ञान मंच और श्री जयंत सहस्रबुद्धे, विभा।
- "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज : पहुँच बनाने की चुनौती" पर सत्रहवां एसटीपी व्याख्यान प्रोफेसर एम. साईं बाबा, टी. वी. रमन पई, चेयर प्रोफेसर, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, बेंगलुरु द्वारा 15 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में दिया गया। इसकी अध्यक्षता श्री गौहर राजा, अग्रणी विज्ञान संचारक और पूर्व वैज्ञानिक, सीएसआईआर ने की।
- "भारत में सौर ऊर्जा का विकास" पर अठारहवें एसटीआईपी व्याख्यान 12 मार्च 2019 को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के महानिदेशक डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा दिया गया। डॉ. अश्विनी कुमार, वरिष्ठ निदेशक, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) ने इसकी अध्यक्षता की।
- "शहरीकरण और वैश्विक तापन के संदर्भ में उभरते संक्रामक रोगों पर प्रतिक्रिया : विज्ञान कहाँ है?" विषय पर उन्नीसवां एसटीपी फोरम व्याख्यान डॉ. ओलिवर टेल्ले, सीएनआरएस के शोधकर्ता, फ्रांस डी साइंसेज ह्यूमेनेस, फ्रांस के दूतावास द्वारा भारत में 22 अप्रैल 2019 को दिया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. दिनकर एम. सलून्के, निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली ने की।
- "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ज्ञान उत्पादन की पद्धतियों के बीच संबंध" पर बीसवां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान प्रोफ़ेसर रवि बी. ग्रोवर, एमेरिटस प्रोफेसर और पूर्व वीसी, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान एवं सदस्य, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 7 जून 2019 को दिया गया। प्रोफेसर राममूर्ति राजारामन, थेरेटिकल फिजिक्स के एमरिटस प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, जेएनयू ने अध्यक्षता की।
- "भारत को अपनी गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की क्यों आवश्यकता है?" विषय पर इक्कीसवाँ एसटीआईपी व्याख्यान श्री गौहर राजा, अग्रणी विज्ञान संचारक और पूर्व वैज्ञानिक, सीएसआईआर द्वारा 12 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में दिया गया।

- "फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एंड क्लीन-टेक" पर बाईसवां एसटीआईपी व्याख्यान श्री मनीष चौरसिया, प्रबंध निदेशक, टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड द्वारा 12 अगस्त 2019 को दिया गया और इसकी अध्यक्षता श्री आर.आर. रश्मि, प्रतिष्ठित फेलो और कार्यक्रम निदेशक, टेरी द्वारा की गई।
- "समाज के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार" पर तेईसवां एसटीआईपी व्याख्यान डॉ. शेखर सी. मांडे, सचिव, डीएसआईआर एवं महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा 19 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में दिया गया। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रोफेसर और पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एवं अध्यक्ष-निर्वाचित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के प्रोफेसर डॉ. चंद्रिमा शाह ने की।
- 'ऊर्जा क्रांति में अभिनवता और नीति : यूरोप से कतिपय उल्लेख' पर चौबीसवाँ एसटीआईपी फ़ोरम लेक्चर 3 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में प्रोफेसर माइकल ग्रब, रिसर्च निदेशक एवं प्रोफेसर, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन द्वारा दिया गया।
- 'आईटी स्किल ट्रेनिंग फॉर स्पोकन ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन एंड इम्प्लॉयमेंट' पर पच्चीसवां एसटीपी फोरम व्याख्यान 18 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में प्रोफेसर कन्नन एम. मौदगल्य, एराच और मेहेरू मेहता एडवांस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी चेयर प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई द्वारा दिया गया। डॉ. देवयानी खोब्रागड़े, संयुक्त सचिव, डीपीए II, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने इसकी अध्यक्षता की।

अनुबंध - I

आरआईएस प्रकाशन

पुस्तकें/रिपोर्टें

आईटीईसी एलएसएससी रिपोर्ट 2019

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

मुख्य क्रियाकलाप : बीएपीए + 40 दिल्ली प्रक्रिया का समारोह - IV दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग: सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और अनुभवजन्य वास्तविकताएं

प्रकाशन वर्ष : 2019

वैश्विक दक्षिण में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला की शक्ति

आईटीसी और आरआईएस, जिनेवा, 2019

रौफ प्रेबिस्च और विकास रणनीति

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

स्वस्थ भविष्य की ओर मिलकर बढ़ना : स्वास्थ्य देखरेख में भारत की भागीदारी

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

एक्ट ईस्ट : आसियान-भारत साझी सांस्कृतिक विरासत

आरआईएस, एआईसी, नई दिल्ली, 2019

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर दक्षिण संदर्श

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

विकास के लिए व्यापार और वित्त : दक्षिण संदर्श

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

व्यापार और निवेश के लिए एलएसी कार्यनीति के साथ भारत के आर्थिक संबंध

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

आईबीएसए विकास सहयोग गतिशीलता

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

गैर-टैरिफ उपाय (एनटीएस): आसियान-भारत व्यापार से साक्ष्य

एआईसी और आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

सेलिंग टू सुवमभूमि : सांस्कृतिक मार्ग और सामुद्रिक परिदृश्य

हिमांशु प्रभा रे और सुसन मिश्र, एआईसी और आरआईएस, 2019

भारत-मध्य एशिया भागीदारी : क्षेत्रीय विकास और संयोजनता के लिए कार्रवाई

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रक्रिया : समकालीन मुद्दे

आरआईएस-एक्सिम बैंक, नई दिल्ली, 2019

दक्षिण-दक्षिण सहयोग में वैश्विक मुद्दे और स्थानीय

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

प्रमुख क्रियाकलाप : दक्षिण-दक्षिण और त्रिपक्षीय सहयोग पर दिल्ली प्रक्रिया पांचवां सम्मलेन

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

व्यापार और संधारणीयता

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

आरआईएस चर्चा पत्र

#242 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आय अभिसरण अनुभव: एक अनुभवजन्य जांच सुनीता घटक और प्रबीर डे द्वारा

#241 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाएँ मनमोहन अग्रवाल और अद्रिता बनर्जी द्वारा

#240 सतत कृषि और पोषण सुरक्षा: उत्पादन विकल्पों के साथ उभरती नीति विकल्प पी. के. आनंद, कृष्ण कुमार और श्रुति खन्ना द्वारा

#239 मुद्रास्फीति और वृद्धि पर मौद्रिक नीति प्रभाव मनमोहन अग्रवाल और इरफान अहमद शाह द्वारा

#238 ओवर पॉलिसी मिज पर काबू पाने के लिए देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के लिए मार्ग कृष्णा कुमार और पी. के. आनंद द्वारा

#237 स्थानीय मुद्रा में व्यापार: भारत के नेपाल, ईरान और रूस के साथ भारतीय रुपए के व्यापार का चित्रण प्रियदर्शी दास, मोनिका शर्मा और गुलफ्शन निजामी द्वारा

#236 सरकार की नीतियां और भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग का विकास 1947-2018: एक समीक्षा प्रशांत कुमार घोष द्वारा

#241 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाएँ मनमोहन अग्रवाल और अद्रिता बनर्जी द्वारा

#240 सतत कृषि और पोषण सुरक्षा: उत्पादन विकल्पों के साथ उभरती नीति विकल्प पी. के. आनंद, कृष्ण कुमार और श्रुति खन्ना द्वारा

#239 मुद्रास्फीति और वृद्धि पर मौद्रिक नीति प्रभाव मनमोहन अग्रवाल और इरफान अहमद शाह द्वारा

#240 सतत कृषि और पोषण सुरक्षा: उत्पादन विकल्पों के साथ उभरती नीति विकल्प पी. के. आनंद, कृष्ण कुमार और श्रुति खन्ना द्वारा

#241 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाएँ मनमोहन अग्रवाल और अद्रिता बनर्जी द्वारा

#242 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आय अभिसरण अनुभव: एक अनुभवजन्य जांच सुनीता घटक और प्रबीर डे द्वारा

जर्नल ऑफ एशियन इकॉनोमिक इंटीग्रेशन

खंड 1, सं.1, अप्रैल 2019, सेज

साउथ एशिया इकॉनोमिक जर्नल

खंड 20, सं.1, मार्च 2019, सेज

स्मारक अंक (2000-2020), आरआईएस एंड आईपीएस

विकास सहयोग समीक्षा

खंड 1 सं. 10-12, जनवरी-मार्च 2019

खंड 2 सं. 1 अप्रैल 2019

खंड 2 सं. 2 एवं 3 मई-जून 2019

खंड 2 सं. 1 अप्रैल 2019

एफआईटीएम नीति सार

#3 गरीबी निवारण के लिए औषधीय पौधे की खेती: संभावनाएं और चुनौतियाँ प्रोफेसर टी.सी. जेम्स और डॉ नम्रता पाठक द्वारा।

#4 कल्याण पर्यटन के लिए विशेष कल्याण क्षेत्र: समर्पित आईएसएम हब बनाने की संभावनाओं की खोज प्रोफेसर टी. सी. जेम्स और अपूर्वा भटनागर द्वारा।

विज्ञान राजनयिकता न्यूज़ अलर्ट

अंक 22: 16-30 सितम्बर 2019

अंक 21: 01-15 सितम्बर 2019

अंक 20: 16-31 अगस्त 2019

अंक 19: 01-15 अगस्त 2019

अंक 18: 16-31 जुलाई 2019

अंक 17: 01-15 जुलाई 2019

अंक 16: 16-30 जून 2019;

अंक 15: 01-15 जून 2019

अंक 14: 16-31 मई 2019;

अंक 13: 01-15 मई 2019

अंक 12: 16-30 अप्रैल 2019;

अंक 11: 01-15 अप्रैल 2019

अंक 8: 16-28 फरवरी 2019;

अंक 7: 01-15 फरवरी 2019;

अंक 6: 16-31 जनवरी 2019;

अंक 5: 01-15 जनवरी 2019

आरआईएस नीति सार

 # 87 ऊर्जा क्षेत्र और वित्तीय बाज़ार : भारत के लिए अवसर सुभोमोय भट्टाचार्जी द्वारा

#88 चीन में वस्त्र क्षेत्र का रोबोटीकरण : प्रभाव और अनिवार्यताएं अमित कुमार द्वारा

साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू
खंड 1 सं. 2, जनवरी 2019

आरआईएस डायरी
खंड 15 सं. 2, अप्रैल 2019
खंड 15 सं. 1, जनवरी 2019
खंड 15 सं. 3, जुलाई 2019

अनुबंध - II

श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार पूर्ण सत्र I में आधार व्याख्यान देते हुए।

प्रतिभागियों को संबोधित करते पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु

अनुलग्नक सूची

अनुलग्नक - I	2019 के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों/संधियों की सूची**
अनुलग्नक - II	2019 के दौरान भारत द्वारा अनुमोदित/अनुसमर्थित समझौतों/संधियों की सूची
अनुलग्नक - III	भारत द्वारा 2019 के दौरान जारी पूर्ण शक्तियों के दस्तावेज़
अनुलग्नक - IV	पीपीएंडआर डिवीजन द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित सेमिनार, सम्मेलन, आदि:
अनुलग्नक - V	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय - राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार
अनुलग्नक - VI	पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सूची
अनुलग्नक - VII	डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार सूची
अनुलग्नक - VIII	पासपोर्ट सेवा परियोजना के साथ एकीकृत विदेशों में मिशन/पोस्ट
अनुलग्नक - IX	मुख्यालय और विदेशों में मिशनों में 2019-20 के दौरान कैडर की संख्या (वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बजट किए गए पदों, गैर-संवर्ग के पदों और एमओआईए और पीओई से संवर्ग के पदों सहित है)
अनुलग्नक - X	विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त आईएफएस अधिकारियों की संख्या: (02.12.2019 की स्थिति के अनुसार)
अनुलग्नक - XI	एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया

अनुलग्नक I

2019 के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों/संधियों की सूची**

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
1	भारत-फ्रांस प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता	2019	**फ्रांस**	विदेश मंत्रालय
2	अवैध उपभोग और मादक पदार्थों और रसायनिक अवयवों और संबंधित अपराधों के अवैध व्यापार के दमन पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता	2019	**फ्रांस**	गृह मंत्रालय
3	कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के आशय की संयुक्त घोषणा	2019	**जर्मनी**	कौशल विकास मंत्रालय
4	कृषि बाजार विकास के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग परियोजना की स्थापना पर संयुक्त घोषणा	2019	**जर्मनी**	उपलब्ध नहीं
5	सतत् विकास के लिए कौशल के आशय की संयुक्त घोषणा	2019	**जर्मनी**	सीमेंस लिमिटेड, भारत और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
6	इसरो और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर के बीच कार्मिकों के आवाजाही की व्यवस्था को लागू करना	2019	**जर्मनी**	अंतरिक्ष विभाग
7	भारत-जर्मन प्रवास और गतिशीलता भागीदारी समझौते के प्रमुख कारकों के आशय पर वक्तव्य	2019	**जर्मनी**	विदेश मंत्रालय
8	सर्बिया गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच वायु सेवा करार	2019	**सर्बिया**	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
9	सिएरा लियोन गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच वर्ष 2019-2023 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	2019	**सिएरा लियोन**	संस्कृति मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
10	सिएरा लियोन गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच एक संयुक्त आयोग की स्थापना पर करार	2019	**सिएरा लियोन**	विदेश मंत्रालय
11	विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, सिएरा लियोन गणराज्य और विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य के बीच परामर्श के लिए प्रोटोकॉल	कोई जानकारी नहीं	**सिएरा लियोन**	विदेश मंत्रालय
12	सिएरा लियोन गणराज्य और भारतीय निर्यात-आयात बैंक के बीच सिएरा में सिंचाई विकास परियोजना के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का करार	कोई जानकारी नहीं	**सिएरा लियोन**	एग्जिम बैंक
13	भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;	2019	**ज़ाम्बिया**	खान मंत्रालय
14	स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;	2019	**ज़ाम्बिया**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
15	भारत के विदेश सेवा संस्थान और जाम्बियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल स्टडीज के बीच समझौता ज्ञापन	2019	**ज़ाम्बिया**	विदेश मंत्रालय
16	भारत के चुनाव आयोग और जाम्बिया के चुनाव आयोग के बीच समझौता ज्ञापन	2019	**ज़ाम्बिया**	भारत निर्वाचन आयोग
17	भारत गणराज्य और अफगानिस्तान की इस्लामी गणराज्य सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि	14.09.2016	**अफ़गानिस्तान**	विदेश मंत्रालय
18	राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं से छूट पर समझौता ज्ञापन	01.11.2018	**बोत्सवाना**	विदेश मंत्रालय
19	भारत - नॉर्वे महासागर वार्ता पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय, नॉर्वे सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	07.01.2019	**नॉर्वे**	विदेश मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
20	बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन	10.01.2019	**फिनलैंड**	अंतरिक्ष विभाग
21	साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन	10.01.2019	**फिनलैंड**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
22	पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय, भारत और चुलांग्कोर्न विश्वविद्यालय, थाईलैंड के बीच समझौता ज्ञापन	10.01.2019	**थाईलैंड**	विदेश मंत्रालय
23	भारत और नाइजीरिया के बीच हवाई सेवा समझौता (एएसए)	14.01.2019	**नाइजीरिया**	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
24	लाओ पीडीआर के साथ वर्ष 2019 के दौरान हवाई सेवा समझौते (एएसएएस)	16.01.2019	**लाओ पीडीआर**	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
25	भारत के नौवहन मंत्रालय और डेनमार्क के उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन	18.01.2019	**डेनमार्क**	पोत परिवहन मंत्रालय
26	भारत और चीन के बीच भारत से चीन को तंबाकू के पत्तों के निर्यात हेतु पादप स्वास्थ्य अपेक्षा संबंधी प्रोटोकॉल	21.01.2019	**चीन**	कृषि मंत्रालय
27	व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में सहयोग के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, भारत और ईडीयूएफआई के बीच समझौता ज्ञापन	23.01.2019	**फिनलैंड**	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
28	मौसम और जलवायु विज्ञान में सहयोग पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मौसम कार्यालय, यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता ज्ञापन	28.01.2019	**युनाइटेड किंगडम**	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
29	राजनयिक और सरकारी/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर भारत गणराज्य और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया की सरकार के बीच समझौता	31.01.2019	**अल्जीरिया**	विदेश मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
30	भारत गणराज्य सरकार और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	31.01.2019	**अल्जीरिया**	संस्कृति मंत्रालय
31	राष्ट्रीय औषधीय संयंत्र बोर्ड (एनएमएमपीबी), आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बांग्लादेश के बीच औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	08.02.19	**बांग्लादेश**	आयुष मंत्रालय
32	राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, मसूरी और लोक प्रशासन मंत्रालय, बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के सिविल कार्मिकों के लिए, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर समझौता	08.02.2019	**बांग्लादेश**	प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग
33	भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो और बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच समझौता ज्ञापन	08.02.2019	**बांग्लादेश**	03-130 गृह मंत्रालय
34	चंद्रयान मिशन-2 पर सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यवस्था लागू करना	11.02.2019	**संयुक्त राज्य अमेरिका**	अंतरिक्ष विभाग
35	भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अर्जेंटीना गणराज्य के आधुनिकीकरण के सरकारी सचिवालय के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग की मंशा पर संयुक्त घोषणा	18.02.2019	**अर्जेंटीना**	संचार मंत्रालय
36	अर्जेंटीना गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्रालय और भारत गणराज्य के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच अंटार्कटिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन	18.02.2019	**अर्जेंटीना**	03-131 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
37	चिकित्सा उत्पाद नियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता ज्ञापन	18.02.2019	**अर्जेंटीना**	स्वास्थ्य मंत्रालय
38	सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए भारत-अर्जेंटीना उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के संबंध में समझौता	18.02.2019	**अर्जेंटीना**	03-131 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
39	पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	18.02.2019	**अर्जेंटीना**	03-131 पर्यटन मंत्रालय
40	भारत के वैश्विक परमाणु ऊर्जा सहभागिता केन्द्र (जीसीएनईपी) और अर्जेंटीना के ऊर्जा सचिवालय सीएनईए के बीच समझौता-ज्ञापन	18.02.2019	**अर्जेंटीना**	03-131 परमाणु ऊर्जा विभाग
41	भारत के प्रसार भारती और अर्जेंटीना के मीडिया एवं जनसामग्री की संघीय प्रणाली के बीच सहयोग पर समझौता-ज्ञापन	18.02.2019	**अर्जेंटीना**	03-131 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
42	आवासन और शहरी मामलें मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और राष्ट्रीय योजना, शहरी नियोजन, आवास और शहर नीति मंत्रालय, राज्य सरकार के बीच मोरक्को आवास और मानव निपटान के क्षेत्र में सूचना और तकनीकी सहयोग के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन	18.02.2019	**मोरक्को**	03-134 आवास और शहरी मामले मंत्रालय
43	आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य दल के गठन पर भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन	18.02.2019	**मोरक्को**	03-134 गृह मंत्रालय
44	युवा मामलों में सहयोग पर भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन	18.02.2019	**मोरक्को**	03-134 युवा मामलों और खेल मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
45	राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और विदेश विभाग, पापुआ न्यू गिनी के बीच समझौता ज्ञापन	19.02.2019	**पापुआ न्यू गिनी**	विदेश मंत्रालय
46	भारतीय गणराज्य सरकार और सऊदी अरब साम्राज्य सरकार के बीच राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश पर समझौता ज्ञापन	20.02.2019	**सऊदी अरब**	03-135 वित्त मंत्रालय
47	प्रसार भारती, नई दिल्ली, भारत और सऊदी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (SBC), सऊदी अरब के बीच ऑडियो विजुअल कार्यक्रम के आदान-प्रदान के लिए प्रसारण पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	20.02.2019	**सऊदी अरब**	03-135 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
48	भारत गणराज्य के इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब साम्राज्य के सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच द्विपक्षीय निवेश संबंधों को बढ़ाने पर संरचना सहयोग कार्यक्रम	20.02.2019	**सऊदी अरब**	03-135 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
49	भारतीय गणराज्य सरकार और सऊदी अरब साम्राज्य सरकार के बीच राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश पर समझौता ज्ञापन	20.02.2019	**सऊदी अरब**	03-135 वित्त मंत्रालय
50	भारत गणराज्य और सऊदी अरब सरकार के बीच आवास के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	20.02.2019	**सऊदी अरब**	03-135 आवास और शहरी विकास मंत्रालय
51	भारत गणराज्य के पर्यटन मंत्रालय और सऊदी अरब साम्राज्य के सऊदी पर्यटन और राष्ट्रीय विरासत आयोग के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	20.02.2019	**सऊदी अरब**	03-135 पर्यटन मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
52	भारत में कोरियाई कंपनियों के निवेश का समर्थन करने के लिए कोरिया प्लस के विस्तार पर इन्वेस्ट इंडिया और व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	22.02.2019	**कोरिया**	03-137 वाणिज्य मंत्रालय
53	भारत और कोरिया के बीच स्टार्ट-अप सहयोग पर समझौता ज्ञापन	22.02.2019	**कोरिया**	03-137 वाणिज्य मंत्रालय
54	भारत गणराज्य-कोरिया गणराज्य की संयुक्त डाक टिकट जारी करने के लिए भारत और कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन	22.02.2019	**कोरिया**	संचार मंत्रालय
55	कोरियाई राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और गृह मंत्रालय के बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध का प्रतिकार करने और पुलिस सहयोग विकसित करने पर समझौता ज्ञापन	22.02.2019	**कोरिया**	03-137 गृह मंत्रालय
56	कोरियाई ब्राडकास्टिंग सिस्टम और प्रसार भारती के बीच ब्राडकास्टिंग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	22.02.2019	**कोरिया**	03-137 सूचना और प्रसारण मंत्रालय
57	भारत और दक्षिण सूडान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श पर समझौता ज्ञापन	22.02.2019	**दक्षिण सूडान**	विदेश मंत्रालय
58	राजनयिक और कांसुलर अकादमी कार्लोस एंटोनियो लोपेज, पराग्वे गणराज्य के विदेश मंत्रालय और विदेश सेवा संस्थान, भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	06.03.2019	**पैराग्वे**	विदेश मंत्रालय
59	सहयोग पर भारत और पैराग्वे के बीच समझौता ज्ञापन	06.03.2019	**पैराग्वे**	विदेश मंत्रालय
60	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और विदेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गाम्बिया प्रवासी मंत्रालय, के बीच समझौता ज्ञापन	07.03.2019	**गाम्बिया**	03-140 विदेश मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
61	राजनयिक अधिकारी और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत और कोस्टा रिका के बीच समझौता	08.03.2019	**कोस्टा रिका**	विदेश मंत्रालय
62	भारत और कोस्टा रिका के बीच जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर आशय पत्र	08.03.2019	**कोस्टा रिका**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
63	मानव संसाधन विकास में सहयोग पर भारत गणराज्य और अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन (स्वयं)।	15.03.2019	**अफ़गानिस्तान**	मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय
64	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर समझौता;	17.03.2019	**मालदीव**	विदेश मंत्रालय
65	ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर मालदीव गणराज्य और ईईएसएल की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	17.03.2019	**मालदीव**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
66	स्थानीय निकायों के माध्यम से उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में भारत गणराज्य और मालदीव गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	17.03.2019	**मालदीव**	विदेश मंत्रालय
67	पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और क्रोएशिया गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	26.03.2019	**क्रोएशिया**	पर्यटन मंत्रालय
68	ज़गरेब के काइन्सियोलॉजी विश्वविद्यालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के संकाय के बीच समझौता ज्ञापन	26.03.2019	**क्रोएशिया**	खेल मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
69	संस्कृत भाषा के लिए आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर आईसीसीआर और ज़गरेब विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन	26.03.2019	**क्रोएशिया**	विदेश मंत्रालय
70	आईसीसीआर और ज़गरेब विश्वविद्यालय के बीच हिंदी की आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	26.03.2019	**क्रोएशिया**	विदेश मंत्रालय
71	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली और राजनयिक अकादमी, विदेश मंत्रालय, बोलीविया के बीच समझौता ज्ञापन	29.03.2019	**बोलीविया**	विदेश मंत्रालय
72	भारत और चिली के बीच वर्ष 2019-2022 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	01.04.2019	**चिली**	संस्कृति मंत्रालय
73	भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन के लिए संयुक्त नवीकरण पत्र	01.04.2019	**चिली**	खान मंत्रालय
74	विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच आशय पत्र	01.04.2019	**चिली**	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
75	करों के संबंध में एकत्रन में सूचना और सहायता के आदान-प्रदान के लिए भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच समझौता	08.04.2019	**ब्रुनेई**	वित्त मंत्रालय
76	निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच भारतीय मिर्च के आयात पर स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी विनियमों का प्रोटोकॉल	09.05.19	**चीन**	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
77	भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और किर्गिज गणराज्य की सुरक्षा परिषद के कार्यालय के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	15.5.2019	**किर्गिज गणराज्य**	03-150 गृह मंत्रालय
78	भारत गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और किर्गिज गणराज्य की सुरक्षा परिषद के कार्यालय के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	15.05.2019	**किर्गिज गणराज्य**	एनएससीएस
79	भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	08.06.2019	**मालदीव**	स्वास्थ्य मंत्रालय
80	भारतीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड और मालदीव सीमा शुल्क सेवाएं के बीच सीमा शुल्क निर्माण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	08.06.2019	**मालदीव**	वित्त मंत्रालय
81	भारत सरकार और परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मालदीव सरकार के बीच समुद्र के द्वारा यात्री और कार्गो सेवाओं की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	08.06.2019	**मालदीव**	पोत परिवहन मंत्रालय
82	भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जलराशि विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	08.06.2019	**मालदीव**	पोत परिवहन मंत्रालय
83	राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और मालदीव सेवा आयोग के बीच मालदीव के सिविल अधिकारीयों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन	08.06.2019	**मालदीव**	प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग
84	भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और किर्गिज गणतंत्र के सशस्त्र बलों के राष्ट्रीय गार्ड के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन।	14.6.2019	**किर्गिज गणराज्य**	गृह मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
85	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में सहयोग पर भारत और किर्गिज गणतंत्र के बीच समझौता ज्ञापन।	14.6.2019	**किर्गिज गणराज्य**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
86	विधिक माप - विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के उपभोक्ता मामले मंत्रालय और किर्गिज गणतंत्र के आर्थिक मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	14.6.2019	**किर्गिज गणराज्य**	उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
87	स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	14.6.2019	**किर्गिज गणराज्य**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
88	भारत-किर्गिस्तान दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) के अनुच्छेद 26 में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल।	14.6.2019	**किर्गिज गणराज्य**	वित्त मंत्रालय
89	भारत और किर्गिज गणतंत्र के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि	14.6.2019	**किर्गिज गणराज्य**	वित्त मंत्रालय
90	भारत और किर्गिज गणतंत्र के बीच पांच वर्ष की अवधि (2019-2024) के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी रूपरेखा	14.06.2019	**किर्गिज गणराज्य**	वाणिज्य मंत्रालय
91	सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	14.06.2019	**किर्गिज गणराज्य**	संचार मंत्रालय
92	दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी रोकने के लिए किर्गिज गणराज्य और भारत गणराज्य गणराज्य की सरकार के बीच में 13 अप्रैल, 1999 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल	14.06.2019	**किर्गिज गणराज्य**	वित्त मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
93	भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और किर्गिज गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	14.06.2019	**किर्गिज गणराज्य**	स्वास्थ्य मंत्रालय
94	किर्गिज गणराज्य के सशस्त्र बलों के राष्ट्रीय गार्डों और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	14.06.2019	**किर्गिज गणराज्य**	गृह मंत्रालय
95	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) तथा किर्गिज गणतंत्र की राष्ट्रीय सामारिक अध्ययन संस्थान (एनआईएसएस) के बीच समझौता ज्ञापन	14.06.2019	**किर्गिज गणराज्य**	विदेश मंत्रालय
96	मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौता	14.06.2019	**एससीओ**	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
97	शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर एससीओ सदस्य देशों के सक्षम अधिकारियों के बीच समझौता	14.06.2019	**एससीओ**	खेल मंत्रालय
98	किर्गिज गणराज्य की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की राज्य समिति और सूचना के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच संचार और प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन	16.06.2019	**किर्गिज गणराज्य**	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
99	भारत गणराज्य सरकार और ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे सरकार के बीच सीमा-शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के संबंध में समझौता	28.06.2019	**उरुग्वे**	वित्त मंत्रालय
100	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और क्रिलोव राष्ट्र अनुसंधान केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन	26.07.2019	**रूस**	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
101	राजनयिक, सरकारी/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से सहमत छूट पर भारत गणराज्य और बेनिन गणराज्य की सरकार के बीच समझौता	29.7.2019	**बेनिन**	विदेश मंत्रालय
102	चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	02.08.2019	**गिनी**	आयुष मंत्रालय
103	नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	02.08.2019	**गिनी**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
104	भारत और चीन के बीच खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	12.08.2019	**चीन**	03-158 खेल मंत्रालय
105	नवयुग कंटेनर टर्मिनल, कृष्णापट्टनम पोर्ट, भारत और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड (रानोंग पोर्ट) के बीच समझौता ज्ञापन	15.08.2019	**थाईलैंड**	पोत परिवहन मंत्रालय
106	भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और लिथुआनिया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	17.08.2019	**लिथुआनिया**	संस्कृति मंत्रालय
107	भारत गणराज्य और लिथुआनिया गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण पर संधि के अनुसमर्थन के साधनों के आदान-प्रदान से संबंधित प्रक्रिया	17.08.2019	**लिथुआनिया**	विदेश मंत्रालय
108	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी के बीच सहयोग पर मंशा की अभिव्यक्ति	19.08.2019	**बहरीन**	अंतरिक्ष विभाग
109	केन्या-भारत संयुक्त व्यापार समिति के 19-20 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में आयोजित नौवें सत्र के मिनट कार्यवृत्त	20.08.2019	**केन्या**	वाणिज्य मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
110	भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और लातविया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच वर्ष 2019 - 2021 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	20.08.2019	**लाटविया**	संस्कृति मंत्रालय
111	ई-शासन और उदीयमान डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	21.08.2019	**एस्टोनिया**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
112	साइबर सुरक्षा अगस्त 2019 में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	21.08.2019	**एस्टोनिया**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
113	राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत और एस्टोनिया के बीच समझौता	21.08.2019	**एस्टोनिया**	विदेश मंत्रालय
114	खाद्य सुरक्षा पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन	21.08.2019	**नेपाल**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
115	विदेश सेवा संस्थान, भारत गणराज्य और जाम्बिया इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल स्टडीज, विदेश मंत्रालय, जाम्बिया गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	21.08.2019	**ज़ाम्बिया**	विदेश मंत्रालय
116	कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जाम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन	21.08.2019	**ज़ाम्बिया**	संस्कृति मंत्रालय
117	भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जाम्बिया के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	21.08.2019	**ज़ाम्बिया**	नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
118	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्रालय, फ्रेंच गणतंत्र सरकार के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग	22.08.2019	**फ्रांस**	कौशल विकास और उद्यमियों के मंत्रालय
119	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और फ्रेंच वैकल्पिक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आयोग (सीईए) के बीच समझौता ज्ञापन	22.08.2019	**फ्रांस**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार
120	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी 'उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केंद्र' और एटीओएस के बीच सहयोग पर करार	22.08.2019	**फ्रांस**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
121	संयुक्त समुद्री परिक्षेत्र जागरूकता के लिए इसरो और सीएनईएस फ्रांस के बीच व्यवस्था का कार्यान्वयन	22.08.2019	**फ्रांस**	अंतरिक्ष विभाग
122	साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भारत-फ्रांसीसी रोडमैप पर समझौता ज्ञापन	22.08.2019	**फ्रांस**	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
123	बहरीन में "रुपे कार्ड" लॉन्च करने के लिए बेनिफिट्स और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के बीच समझौता ज्ञापन	24.08.2019	**बहरीन**	वित्त मंत्रालय
124	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच समझौता	26.08.2019	**डॉमिनिकन गणराज्य**	विदेश मंत्रालय
125	भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और हंगरी के मानव क्षमता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2022 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	26.08.2019	**हंगरी**	संस्कृति मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
126	रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	29.08.2019	**रूस**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
127	भारत गणराज्य की सरकार और मालदीव गणराज्य की सरकार के बीच आपराधिक मामले में पारस्परिक विधिक सहायता संबंधी करार	03.09.2019	**मालदीव**	गृह मंत्रालय
128	भारत गणराज्य और मालदीव गणराज्य के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संबंधी करार	03.09.2019	**मालदीव**	गृह मंत्रालय
129	भारत गणराज्य सरकार और रूसी संघ सरकार के बीच ऑडीओ-विज़ुअल सह-प्रोडक्शन में सहयोग पर करार	04.09.2019	**रूस**	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
130	भारत गणराज्य के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ सरकार के परिवहन मंत्रालय के बीच सड़क परिवहन और सड़क उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन	04.09.2019	**रूस**	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
131	भारत गणराज्य के पोत परिवहन मंत्रालय और रूसी संघ सरकार के परिवहन मंत्रालय के बीच चेन्नई बंदरगाह तथा व्लादिवोस्तक बंदरगाह के बीच समुद्री संचार के विकास के बारे में समझौता ज्ञापन	04.09.2019	**रूस**	पोत परिवहन मंत्रालय
132	भारत के वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड तथा फेडरल कस्टम्स सर्विस (रूसी संघ) के बीच 2019-22 में सीमा शुल्क उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए सहयोग की योजना	04.09.2019	**रूस**	वित्त मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
133	रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग के बारे में समझौता ज्ञापन	04.09.2019	**रूस**	03-169 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
134	भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में योजना तैयार करना	04.09.2019	**रूस**	03-169 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
135	नीति आयोग और रूस के बीच 2020-25 के लिए व्यापार सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारतीय-रूसी सहयोग के कार्यक्रम की तैयारी के लिए सुदूर पूर्व और आर्कटिक के लिए समझौता ज्ञापन	04.09.2019	**रूस**	वाणिज्य मंत्रालय
136	विदेश मामलें संस्थान, विदेश मंत्रालय, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	06.09.2019	**लाओ पीडीआर**	विदेश मंत्रालय
137	मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और आइसलैंड के इंडीट्रीज एंड इनोवेशन मंत्रालय, मत्स्य पालन और जलकृषि विभाग के बीच समझौता ज्ञापन सतत मत्स्य पालन विकास के क्षेत्र में सहयोग	10.09.2019	**आइसलैंड**	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
138	भारत गणराज्य और आइसलैंड सरकार के बीच वर्ष 2019-2022 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	10.09.2019	**आइसलैंड**	संस्कृति मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
139	मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और आइसलैंड के उद्योग और नवाचार मंत्रालय, मत्स्य पालन और जलकृषि विभाग के बीच सतत मत्स्य पालन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10.09.2019	**आइसलैंड**	कृषि मंत्रालय
140	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत गणराज्य और आइसलैंड सरकार के बीच समझौता	10.09.2019	**आइसलैंड**	विदेश मंत्रालय
141	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के बीच समझौता	10.09.2019	**सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस**	विदेश मंत्रालय
142	भारत और स्विस फेडरल काउंसिल के बीच भारत स्विट्जरलैंड विज्ञान और नवाचार गठबंधन के रूप में भविष्य के लिए भारत-स्विट्जरलैंड संबंधों को और मजबूत करने के लिए आशय पत्र	13.09.2019	**स्विट्ज़रलैंड**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
143	भारत गणराज्य सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और स्विट्जरलैंड सरकार के तकनीकी सहयोग पर संघीय विदेश मामलें विभाग के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	13.09.2019	**स्विट्ज़रलैंड**	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
144	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लॉज़ेन विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन की आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	13.09.2019	**स्विट्ज़रलैंड**	विदेश मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
145	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत और एंटीगुआ और बारबुडा के बीच समझौता	17.09.2019	**एंटीगुआ और बारबुडा**	विदेश मंत्रालय
146	भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्लोवेनिया के शिक्षा, विज्ञान और खेल मंत्रालय के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए 2020-2022 की अवधि का कार्यक्रम	17.09.2019	**स्लोवेनिया**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
147	भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय और स्लोवेनिया के शिक्षा, विज्ञान और खेल मंत्रालय के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17.09.2019	**स्लोवेनिया**	भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय
148	संस्कृति, कला, शिक्षा, खेल और जन संचार के क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम	17.09.2019	**स्लोवेनिया**	संस्कृति मंत्रालय
149	मानकीकरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारतीय मानक ब्यूरो और स्लोवेनियाई मानकीकरण संस्थान के बीच सहयोग का कार्यक्रम	17.09.2019	**स्लोवेनिया**	भारतीय मानक ब्यूरो
150	भारत गणराज्य सरकार और मंगोलिया सरकार के बीच शांतिपूर्ण और नागरिक प्रयोजनों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर समझौता	20.09.2019	**मंगोलिया**	अंतरिक्ष विभाग
151	भारत गणराज्य के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और मंगोलिया के खाद्य, कृषि और प्रकाश उद्योग मंत्रालय के बीच पशु स्वास्थ्य और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यापक कार्य योजना	20.09.2019	**मंगोलिया**	कृषि मंत्रालय
152	भारत गणराज्य सरकार और मंगोलिया सरकार के बीच वर्ष 2019-2023 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	20.09.2019	**मंगोलिया**	03-175 संस्कृति मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
153	भारत गणराज्य और मंगोलिया सरकार के बीच राजनयिक मिशन या कांसुलर पोस्ट के सदस्यों के आश्रितों को लाभप्रद रोजगार में शामिल होने के लिए अधिकृत करने के लिए समझौता	20.09.2019	**मंगोलिया**	विदेश मंत्रालय
154	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (भारत) और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (मंगोलिया) के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।	20.09.2019	**मंगोलिया**	03-175 गृह मंत्रालय
155	भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की 21-22 अगस्त, 2019 को काठमांडू में हुई पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त	23.09.2019	**नेपाल**	विदेश मंत्रालय
156	भारत और अमरीका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता	23.09.2019	**संयुक्त राज्य अमेरिका**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
157	सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए भारत-सीरिया नेक्स्ट जेनरेशन सेंटर के उन्नयन के लिए समझौता ज्ञापन (नेक्स्टजेन-आईएससीसीईआईटी)	01.10.2019	**सीरिया**	विदेश मंत्रालय
158	एयरबोर्न सिंथेटिक अपर्चर रडार एयरबोर्न कैम्पेन पर सहयोग के लिए	01.10.2019	**संयुक्त राज्य अमेरिका**	अंतरिक्ष विभाग
159	भारत गणराज्य और बांग्लादेश लोकतांत्रिक सरकार के बीच वर्ष 2020-2022 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	05.10.2019	**बांग्लादेश**	संस्कृति मंत्रालय
160	बांग्लादेश को दी गई भारत सरकार की लाइन ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) के कार्यान्वयन से संबंधित करार	05.10.2019	**बांग्लादेश**	विदेश मंत्रालय
161	जल शक्ति मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश जन लोकतांत्रिक सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	05.10.2019	**बांग्लादेश**	जल शक्ति मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
162	भारत गणराज्य सरकार के युवा मामलें और खेल मंत्रालय और बांग्लादेश जन लोकतांत्रिक सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के बीच युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	05.10.2019	**बांग्लादेश**	03-178 युवा मामलों और खेल मंत्रालय
163	ई-वीबाब नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए मोजाम्बिक और टीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन	07.10.2019	**मोजाम्बिक**	विदेश मंत्रालय
164	भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के विदेश मामलों के संस्थान देववॉन्से वरोपकरण के बीच समझौता ज्ञापन	10.10.2019	**थाईलैंड**	विदेश मंत्रालय
165	भारत-थाईलैंड संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की आठवीं 10 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में हुई बैठक के सहमत कार्यवृत्त	10.10.2019	**थाईलैंड**	विदेश मंत्रालय
166	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारक के लिए वीजा की छूट पर समझौता ज्ञापन	11.10.2019	**कोमोरोस**	विदेश मंत्रालय
167	कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	11.10.2019	**कोमोरोस**	कला और संस्कृति मंत्रालय
168	स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	11.10.2019	**कोमोरोस**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
169	भारत और कोमोरोस के बीच परामर्श के लिए प्रोटोकॉल	11.10.2019	**कोमोरोस**	विदेश मंत्रालय
170	ई-वीबाब नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए समझौता ज्ञापन	11.10.2019	**कोमोरोस**	विदेश मंत्रालय
171	विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, सिएरा लियोन गणराज्य और विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य के बीच परामर्श के लिए प्रोटोकॉल	13.10.2019	**सिएरा लियोन**	विदेश मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
172	भारतीय दूतावास और पीहू येन प्रांत रेग भारतीय अनुदान सहायता की पीपुल्स कमेटी के बीच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन	14.10.2019	**वियतनाम**	विदेश मंत्रालय
173	भारतीय दूतावास और क्वांग निन्ह प्रांत की पीपुल्स कमेटी, वियतनाम रेग भारतीय अनुदान सहायता के बीच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (QIP) के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन	15.10.2019	**वियतनाम**	विदेश मंत्रालय
174	भारतीय दूतावास और पीहू थो प्रांत रेग भारतीय अनुदान सहायता की पीपुल्स कमेटी के बीच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन	18.10.2019	**वियतनाम**	विदेश मंत्रालय
175	भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, पाकिस्तान जाने के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए समझौता	24.10.2019	**पाकिस्तान**	गृह मंत्रालय
176	भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद पर करार	29.10.2019	**सऊदी अरब**	विदेश मंत्रालय
177	नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	29.10.2019	**सऊदी अरब**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
178	सुरक्षा सहयोग पर समझौता	29.10.2019	**सऊदी अरब**	गृह मंत्रालय
179	मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और मादक पदार्थों और रासायनिक पदार्थों की तस्करी से निपटने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	29.10.2019	**सऊदी अरब**	गृह मंत्रालय
180	नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	29.10.2019	**सऊदी अरब**	नागरिक उड्डयन मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
181	चिकित्सा उत्पाद विनियमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	29.10.2019	**सऊदी अरब**	स्वास्थ्य मंत्रालय
182	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (आईएसपीआरएल) और सऊदी अरामको के बीच पडूर कैवर्न में सामरिक पैट्रोलियम रिजर्व क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	29.10.2019	**सऊदी अरब**	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
183	स्टॉक एक्सचेंजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	29.10.2019	**सऊदी अरब**	वित्त मंत्रालय
184	सऊदी अरब में रुपे कार्ड लॉन्च करने पर समझौता ज्ञापन	29.10.2019	**सऊदी अरब**	वित्त मंत्रालय
185	राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण और अकादमिक पाठ्यक्रमों के लिए सहयोग कार्यक्रम	29.10.2019	**सऊदी अरब**	विदेश मंत्रालय
186	नवाचार प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए आशय पत्र	29.10.2019	**सऊदी अरब**	नीति आयोग
187	कृषि तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, मैनेज और नीनबर्ग शहर में जर्मन कृषि अकादमी देऊला के बीच समझौता ज्ञापन	30.10.2019	**जर्मनी**	कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण
188	वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने, स्थापित करने और विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन	31.10.2019	**जर्मनी**	प्रौद्योगिकी विज्ञान मंत्रालय
189	आयुर्वेद, योग और ध्यान में अकादमिक सहयोग की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	31.10.2019	**जर्मनी**	आयुष मंत्रालय
190	सामरिक परियोजनाओं पर सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा	01.11.2019	**जर्मनी**	रेल मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
191	व्यावसायिक रोगों, पुनर्वास और विकलांग बीमाकृत व्यक्तियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	01.11.2019	**जर्मनी**	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
192	स्टार्ट-अप के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए आशय की घोषणा	01.11.2019	**जर्मनी**	वाणिज्य मंत्रालय
193	2020-2024 की अवधि के लिए परामर्श के आशय की संयुक्त घोषणा	01.11.2019	**जर्मनी**	विदेश मंत्रालय
194	व्यावसायिक रोगों, पुनर्वास और विकलांग बीमाकृत व्यक्तियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	01.11.2019	**जर्मनी**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
195	ग्रीन शहरी गतिशीलता के लिए भारत-जर्मन भागीदारी पर आशय की संयुक्त घोषणा	01.11.2019	**जर्मनी**	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
196	समुद्री कचरे की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा	01.11.2019	**जर्मनी**	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
197	अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट शहर नेटवर्क में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा	01.11.2019	**जर्मनी**	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
198	कृत्रिम आसूचना पर अनुसंधान और विकास में संयुक्त सहयोग के लिए आशय की संयुक्त घोषणा	01.11.2019	**जर्मनी**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
199	भारत-रूस व्यापार और निवेश संवर्धन के लिए संयुक्त कार्य-योजना	01.11.2019	**रूस**	वाणिज्य मंत्रालय
200	एससीओ सदस्य देशों की सीमा शुल्क सेवाओं के बीच राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली के पारस्परिक एकीकरण पर समझौता ज्ञापन	02.11.2019	**एससीओ**	वित्त मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
201	भारतीय दूतावास और येन बाई प्रांत की पीपुल्स कमेटी ऑफ येन बाई प्रोविंस, वियतनाम के बीच, वियतनाम "टान एन वार्ड नहिआ लो टाउन, येन बाई प्रोविंस में इनफील्ड नहर के निर्माण'' परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन	04.11.2019	**वियतनाम**	विदेश मंत्रालय
202	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और थाईलैंड के पोर्ट अथॉरिटी के बीच समझौता ज्ञापन	07.11.2019	**थाईलैंड**	पोत परिवहन मंत्रालय
203	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, भारत और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड (रानोंग पोर्ट) के बीच समझौता ज्ञापन	07.11.2019	**थाईलैंड**	पोत परिवहन मंत्रालय
204	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, भारत और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड (रानोंग पोर्ट) के बीच समझौता ज्ञापन	07.11.2019	**थाईलैंड**	पोत परिवहन मंत्रालय
205	पर्यटन मंत्रालय, भारत और आर्थिक मामलों और रोजगार मंत्रालय, फिनलैंड के बीच पर्यटन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	21.11.2019	**फिनलैंड**	पर्यटन मंत्रालय
206	डिजिटलीकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत और आर्थिक मामलों और रोजगार मंत्रालय, फिनलैंड के बीच आशय की संयुक्त घोषणा	22.11.2019	**फिनलैंड**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
207	आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर तजाकिस्तान गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	29.11.2019	**ताजिकिस्तान**	गृह मंत्रालय
208	भारत और स्वीडन के बीच प्रशिक्षण, प्रमाणन और नाविकों की निगरानी 1978 के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय संमेलन के विनियमन 1/10 के अनुसार प्रमाण पत्र की मान्यता पर समझौता	02.12.2019	**स्वीडन**	पोत परिवहन मंत्रालय

क्रम सं.	शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	देश/संगठन	मंत्रालय/विभाग
209	विदेश सेवा अकादमी, केन्या गणराज्य के विदेश मंत्रालय और विदेश सेवा संस्थान, भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	03.12.2019	**केन्या**	विदेश मंत्रालय
210	भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और वित्तीय खुफिया इकाई मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन	13.12.2019	**मालदीव**	वित्त मंत्रालय
211	भारत और मालदीव के चुनाव आयोगों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	13.12.2019	**मालदीव**	भारत निर्वाचन आयोग

* एलएंडटी डिवीजन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूची 25-12-2019 तक

** संवेदनशील समझौतों को सूची से बाहर रखा गया है।

अनुलग्नक - II

2019 के दौरान भारत द्वारा अनुमोदित/अनुसमर्थित समझौतों/संधियों की सूची

क्रम सं.	समझौते/संधि का शीर्षक	देश/संगठन	अनुसमर्थन/ परिग्रहण की तिथि	मंत्रालय/विभाग
1	भारत और अफगानिस्तान के बीच समन, न्यायिक दस्तावेजों, आयोग, निर्णयों के निष्पादन और मध्यस्थ पुरस्कारों की तामील के लिए न्यायिक और नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर समझौता	अफ़गानिस्तान	15.04.2019	विधि और न्याय मंत्रालय
2	अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और अल्जीरिया के बीच समझौता	अल्जीरिया	30.01.2019	अंतरिक्ष विभाग
3	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत और एंटीगुआ और बारबुडा के बीच समझौता	एंटीगुआ और बारबुडा	18.11.2019	विदेश मंत्रालय
4	युवा मामलों में सहयोग पर भारत और आर्मेनिया के बीच समझौता	आर्मीनिया	28.08.2019	युवा मामलें मंत्रालय
5	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट के लिए वीजा की आवश्यकता को माफ करने पर भारत और बहामा के बीच समझौता	बहामा	15.04.2019	विदेश मंत्रालय
6	निवेश पर बेलारूस और भारत के बीच संधि	बेलारूस	25.02.2019	वित्त मंत्रालय
7	राजनयिक, सरकारी/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से पारस्परिक छूट पर भारत गणराज्य और बेनिन गणराज्य सरकार के बीच समझौता	बेनिन	15.10.2019	विदेश मंत्रालय
8	करों के संग्रहण में सूचना और सहायता के आदान-प्रदान के लिए भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच समझौता	ब्रुनेई	08.04.2019	वित्त मंत्रालय

क्रम सं.	समझौते/संधि का शीर्षक	देश/संगठन	अनुसमर्थन/परिग्रहण की तिथि	मंत्रालय/विभाग
9	चीन और भारत गणराज्य सरकार के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए 18 जुलाई 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार को संशोधित करने का प्रोटोकॉल	चीन	01.01.2019	वित्त मंत्रालय
10	राजनयिक अधिकारी और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत और कोस्टा रिका के बीच समझौता	कोस्टा रिका	08.04.2019	विदेश मंत्रालय
11	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच समझौता	डॉमिनिकन गणराज्य	18.11.2019	विदेश मंत्रालय
12	राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत और एस्टोनिया के बीच समझौता	एस्टोनिया	08.11.2019	विदेश मंत्रालय
13	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत और आइसलैंड के बीच समझौता	आइसलैंड	18.11.2019	विदेश मंत्रालय
14	जहाजों की सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि रीसाइक्लिंग के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2009	आईएमओ	25.11.2019	पोत परिवहन मंत्रालय
15	शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच फ्रेमवर्क समझौता	इंडोनेशिया	06.05.2019	अंतरिक्ष विभाग
16	भारत गणराज्य की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय के बीच समझौता	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन	29.10.2019	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क्रम सं.	समझौते/संधि का शीर्षक	देश/संगठन	अनुसमर्थन/ परिग्रहण की तिथि	मंत्रालय/विभाग
17	किर्गिज गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच और दोहरे कराधान से बचने के लिए और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए 13 अप्रैल 1999 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल	किर्गिज गणराज्य	14.10.2019	वित्त मंत्रालय
18	भारत गणराज्य की सरकार और मालदीव गणराज्य सरकार के बीच वीजा व्यवस्थाओं की सुविधा पर समझौता	मालदीव	07.02.2019	विदेश मंत्रालय
19	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत और मालदीव के बीच समझौता	मालदीव	26.06.2019	विदेश मंत्रालय
20	आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत गणराज्य और मालदीव गणराज्य के बीच संधि	मालदीव	29.10.2019	गृह मंत्रालय
21	भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण समझौता	मोरक्को	18.01.2019	गृह मंत्रालय
22	भारत और मोरक्को के बीच समन, न्यायिक दस्तावेजों, अनुरोध पत्र और निर्णय डिक्री और मध्यस्थ पंचाटों के निष्पादन की तामील के लिए विधिक और न्यायिक और नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर समझौता	मोरक्को	25.04.2019	विधि और न्याय मंत्रालय
23	आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण को रोकने के लिए कर संधि उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन	ओईसीडी	11.06.2019	वित्त मंत्रालय
24	सीआईवीएल और वाणिज्यिक मामलों में विधिक और न्यायिक सहयोग पर भारत और ओमान के बीच समझौता	ओमान	15.04.2019	विधि और न्याय मंत्रालय
25	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और पेरू के बीच समझौता	पेरू	18.01.2019	वित्त मंत्रालय

क्रम सं.	समझौते/संधि का शीर्षक	देश/संगठन	अनुसमर्थन/परिग्रहण की तिथि	मंत्रालय/विभाग
26	सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारतीय-रूसी अंतरसरकारी आयोग की स्थापना के लिए भारत और रूस के बीच समझौता	रूस	25.02.2019	रक्षा मंत्रालय
27	हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान के लिए कार्यक्रम पर भारत गणराज्य और रूसी संघ सरकार के बीच समझौता	रूस	14.10.2019	रक्षा मंत्रालय
28	भारत और रूस के बीच रूसी/ सोवियत मूल हथियारों और रक्षा उपकरणों से संबंधित कलपुर्जों, घटकों, समुच्चर और अन्य सामग्री के संयुक्त विनिर्माण में पारस्परिक सहयोग पर समझौता	रूस	09.12.2019	रक्षा मंत्रालय
29	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के बीच समझौता	सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस	18.11.2019	विदेश मंत्रालय
30	शंघाई सहयोग संगठन बजट समझौता	एससीओ	27.07.2019	विदेश मंत्रालय
31	राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता में छूट पर भारत और कोमोरोस के बीच समझौता	कोमोरोस संघ	18.11.2019	विदेश मंत्रालय
32	यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए 8वां अतिरिक्त प्रोटोकॉल	यूपीयू	08.11.2019	डाक विभाग
33	यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए 9वां अतिरिक्त प्रोटोकॉल	यूपीयू	08.11.2019	डाक विभाग
34	राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता	उज़्बेकिस्तान	07.02.2019	विदेश मंत्रालय
35	अंकों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से संबंधित अच्छा समझौता	डब्ल्यूआईपीओ	29.04.2019	वाणिज्य मंत्रालय

क्रम सं.	समझौते/संधि का शीर्षक	देश/संगठन	अनुसमर्थन/ परिग्रहण की तिथि	मंत्रालय/विभाग
36	अंकों के आलंकारिक कारकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने संबंधी वियना समझौता	डब्ल्यूआईपीओ	29.04.2019	वाणिज्य मंत्रालय
37	औद्योगिक डिजाइनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की स्थापना करने संबंधी लोकार्नो समझौता	डब्ल्यूआईपीओ	29.04.2019	वाणिज्य मंत्रालय
38	दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए जाम्बिया और भारत के बीच समझौता	ज़ाम्बिया	30.01.2019	वित्त मंत्रालय

* सूची, एलएंडटी प्रभाग के पास 27-12-2019 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार

अनुलग्नक - III

भारत द्वारा 2019 के दौरान जारी पूर्ण शक्तियों के दस्तावेज़

क्रम सं.	जारी करने की तिथि	समझौते का शीर्षक	देश
1	19.12.2019	भारत और फिनलैंड के बीच रक्षा संबंधी उपकरणों के उत्पादन, खरीद, अनुसंधान और विकास और औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	फ़िनलैंड
2	22.03.2019	भारत गणराज्य सरकार और एस्विनी साम्राज्य सरकार (पूर्व में स्वाजीलैंड) के बीच सीमाओं की शर्तों के बिना कर निरीक्षक	एस्विनी साम्राज्य
3	20.08.2019	खाद्य सुरक्षा पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन	नेपाल
4	04.04.2019	कतर एमिरी नेवल फोर्स में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों/ नाविकों के रोजगार के लिए भारत और कतर के बीच समझौता ज्ञापन	कतर
5	01.01.2019	तुर्की गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच खसखस के व्यापार पर समझौता ज्ञापन।	तुर्की
6	05.04.2019	यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सरकार और उत्तरी आयरलैंड और भारत सरकार के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षमता सहयोग पर समझौता ज्ञापन	युनाइटेड किंगडम
7	05.08.2019	मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनआईएसए)	संयुक्त राष्ट्र
8	20.06.2019	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के संबंध में भारत गणराज्य और ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे सरकार के बीच समझौता	उरुग्वे

अनुलग्नक IV

पीपीएंडआर डिवीजन द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित सेमिनार, सम्मेलन, आदि:

क्रम सं.	संगोष्ठी/सम्मेलन	साझेदार/सहयोगी संगठन	तिथि, स्थान
1	5वां रायसीना संवाद	ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन	14-16 जनवरी 2020, नई दिल्ली
2	चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019	इंडिया फाउंडेशन	03-04 सितंबर 2019, मालदीव
3	तीसरा भारत-अमेरिका फोरम 2019	अनंता केंद्र	16-17 अगस्त 2019, नई दिल्ली
4	चौथा वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन	कार्नेगी इंडिया	04-06 दिसंबर 2019, बेंगलुरु
5	भारत सामरिक समूह की दूसरी बैठक 2019	कार्नेगी इंडिया	13-15 सितंबर 2019, लिस्बन
6	चौथा भू-आर्थिक वार्ता	पुणे इंटरनेशनल सेंटर	28 फरवरी - 1 मार्च 2020, पुणे
7	18वां भारत-कोरिया ट्रैक 1.5 वार्ता	अनंता केंद्र	08-09 नवंबर 2019, नई दिल्ली
8	दूसरा भारत-जापान इंडो-पैसिफिक फोरम 2019	दिल्ली नीति समूह	03-04 अक्तूबर 2019, टोक्यो
9	दूसरा भारत-कनाडा ट्रैक 1.5 वार्ता 2019	गेटवे हाउस	21-22 नवंबर 2019, मुंबई
10	भारत-म्यांमार सम्मेलन	इंडिया फाउंडेशन	10 जून 2019, इंफाल
11	'भारत की पड़ोसी प्रथम नीति : उदीयमान नए चलन	विद्या प्रसार मंडल अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (पंजीकृत)	4-25 जून 2019, मुंबई

क्रम सं.	संगोष्ठी/सम्मेलन	साझेदार/सहयोगी संगठन	तिथि, स्थान
12	"भारत-प्रशांत विचारधारा का प्रसार : भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई परिपेक्ष्य''	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	29-31 अक्तूबर 2019, मदुरै
13	"2वीं सदी के सामरिक सुरक्षा खतरों" विषय पर ट्रैक 2 वार्ता	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, बेंगलुरु	27-29 जनवरी 2020, बेंगलुरु

अनुलग्नक - V

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय - राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार

क्रम सं.	पासपोर्ट कार्यालय	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1	पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद	गुजरात
2	पासपोर्ट कार्यालय अमृतसर	पंजाब
3	पासपोर्ट कार्यालय बरेली	उत्तर प्रदेश
4	पासपोर्ट कार्यालय बंगलुरु	कर्नाटक
5	पासपोर्ट कार्यालय भोपाल	मध्य प्रदेश
6	पासपोर्ट कार्यालय भुबनेश्वर	ओड़िशा
7	पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़	चंडीगढ़
8	पासपोर्ट कार्यालय चैन्नई	तमिलनाडु
9	पासपोर्ट कार्यालय कोचीन	केरल
10	पासपोर्ट कार्यालय कोयम्बटूर	तमिलनाडु
11	पासपोर्ट कार्यालय देहरादून	उत्तराखंड
12	पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली	दिल्ली
13	पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
14	पासपोर्ट कार्यालय गोवा	गोवा
15	पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी	असम
16	पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद	तेलंगाना
17	पासपोर्ट कार्यालय जयपुर	राजस्थान
18	पासपोर्ट कार्यालय जालंधर	पंजाब
19	पासपोर्ट कार्यालय जम्मू	जम्मू-कश्मीर
20	पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता	पश्चिम बंगाल
21	पासपोर्ट कार्यालय कोझिकोड	केरल

क्रम सं.	पासपोर्ट कार्यालय	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
22	पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ	उत्तर प्रदेश
23	पासपोर्ट कार्यालय मदुरई	तमिलनाडु
24	पासपोर्ट कार्यालय मुंबई	महाराष्ट्र
25	पासपोर्ट कार्यालय नागपुर	महाराष्ट्र
26	पासपोर्ट कार्यालय पटना	बिहार
27	पासपोर्ट कार्यालय पुणे	महाराष्ट्र
28	पासपोर्ट कार्यालय रायपुर	छत्तीसगढ़
29	पासपोर्ट कार्यालय रांची	झारखंड
30	पासपोर्ट कार्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश
31	पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर
32	पासपोर्ट कार्यालय सूरत	गुजरात
33	पासपोर्ट कार्यालय तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
34	पासपोर्ट कार्यालय त्रिवेन्द्रम	केरल
35	पासपोर्ट कार्यालय विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
36	पासपोर्ट कार्यालय विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश

अनुलग्नक - VI

पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएसके की संख्या	पीएसके की अवस्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	4	विजयवाड़ा, तिरुपति, विशाखापट्टनम, भीमावरम
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	ईटानगर
3.	असम*	1	गुवाहाटी
4.	बिहार	2	पटना, दरभंगा
5.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र **	1	चंडीगढ़
6.	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
7.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ***	3	हेराल्ड हाउस, शालीमार प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस
8.	गोवा	1	पणजी
9.	गुजरात	5	अहमदाबाद I और II, वडोदरा, राजकोट, सूरत
10.	हरियाणा	2	अंबाला, गुड़गांव
11.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
12.	जम्मू-कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
13.	झारखंड	1	रांची
14.	कर्नाटक	5	बंगलुरु I और II, हुबली, मंगलौर, कालाबुरगी
15.	केरल	13	तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम (ग्रामीण), कोल्लम, कोचीन, एर्नाकुलम ग्रामीण, अलपुझा, कोट्टायम, मलप्पुरम, थ्रिसूर, कोझिकोड I और II, कन्नूर I और II
16.	मध्य प्रदेश	2	भोपाल, इंदौर
17.	महाराष्ट्र	8	मुंबई I,II और III, पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, सोलापुर

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएसके की संख्या	पीएसके की अवस्थिति
18.	मणिपुर	1	इम्फाल
19.	मेघालय	1	शिलांग
20.	मिजोरम	1	आइजोल
21.	नागालैंड	1	दीमापुर
22.	ओड़िशा	1	भुबनेश्वर
23.	पुदुच्चेरी	1	पुदुच्चेरी
24.	पंजाब	5	अमृतसर, लुधियाना, जालंधर I और II, होशियारपुर
25.	राजस्थान	4	जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर
26.	सिक्किम	1	गंगटोक
27.	तमिलनाडु	8	चैन्नई I, II और III, त्रिची, तंजावुर, मदुरई, तिरुनेलवेली, कोयम्बतूर
28.	तेलंगाना	5	हैदराबाद I, II और III, निजामाबाद, करीमनगर
29.	त्रिपुरा	1	अगरतला
30.	उत्तर प्रदेश	6	लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद
31.	उत्तराखंड	1	देहरादून
32.	पश्चिम बंगाल@	3	कोलकाता, बहरामपुर, सिलीगुड़ी
	कुल	**93**	

* आरपीओ गुवाहाटी, वर्तमान में पांच अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी कवर करता है।

* * आरपीओ चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों को कवर करता है।

* * * आरपीओ दिल्ली हरियाणा के कुछ हिस्सों को कवर करता है।

@ आरपीओ कोलकाता सिक्किम और त्रिपुरा को कवर करता है।

अनुलग्नक - VII

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार सूची

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
1	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2	बापटला	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
3	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
4	गुडिवदा	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
5	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
6	हिंदूपुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
7	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
8	कोदुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
9	करनूल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
10	नांदियाल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
11	नारसरोपेट	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
12	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
13	ओंगोल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
14	अमालापुरम	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
15	एलरू	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
16	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
17	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
18	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
19	विजियानगरम	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
20	येलमुसिली	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
21	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
22	खोंसा	अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी
23	बारपेटा	असम	गुवाहाटी
24	ढुली	असम	गुवाहाटी
25	डिब्रूगढ़	असम	गुवाहाटी
26	गोलपारा	असम	गुवाहाटी
27	गोलघाट	असम	गुवाहाटी
28	जोरहाट	असम	गुवाहाटी
29	कार्बी आंगलांग	असम	गुवाहाटी
30	करीमगंज	असम	गुवाहाटी
31	कोकराझार	असम	गुवाहाटी
32	मंगलदोई	असम	गुवाहाटी
33	नवांगांव	असम	गुवाहाटी
34	उत्तरी लखीमपुर	असम	गुवाहाटी
35	सिलचर	असम	गुवाहाटी
36	तेजपुर	असम	गुवाहाटी
37	तिनसुकिया	असम	गुवाहाटी
38	अराह	बिहार	पटना
39	औरंगाबाद	बिहार	पटना
40	बांका	बिहार	पटना
41	बेगूसराय	बिहार	पटना
42	बेतिया	बिहार	पटना
43	भागलपुर	बिहार	पटना
44	बक्सर	बिहार	पटना

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
45	छपरा	बिहार	पटना
46	डालमिया नगर	बिहार	पटना
47	डालसिंह सराय	बिहार	पटना
48	फारबिसगंज	बिहार	पटना
49	गया	बिहार	पटना
50	गोपालगंज	बिहार	पटना
51	हाजीपुर	बिहार	पटना
52	जहानाबाद	बिहार	पटना
53	जमुई	बिहार	पटना
54	कटिहार	बिहार	पटना
55	खगड़िया	बिहार	पटना
56	किशनगंज	बिहार	पटना
57	मधुबनी	बिहार	पटना
58	मनेर	बिहार	पटना
59	मोतिहारी	बिहार	पटना
60	मुंगेर	बिहार	पटना
61	मुजफ्फरपुर	बिहार	पटना
62	नालंदा	बिहार	पटना
63	नवादा	बिहार	पटना
64	पूर्णिया	बिहार	पटना
65	सहरसा	बिहार	पटना
66	समस्तीपुर	बिहार	पटना
67	सासाराम	बिहार	पटना

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
68	शेहर	बिहार	पटना
69	सीतामढ़ी	बिहार	पटना
70	सीवान	बिहार	पटना
71	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	रायपुर
72	दुर्ग	छत्तीसगढ़	रायपुर
73	जांजगीर-चांपा	छत्तीसगढ़	रायपुर
74	कोरबा	छत्तीसगढ़	रायपुर
75	रायगढ़	छत्तीसगढ़	रायपुर
76	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	रायपुर
77	सरगुजा	छत्तीसगढ़	रायपुर
78	सिलवासा	दादर और नगर हैवली	मुंबई
79	दमन	दमन	मुंबई
80	जनक पुरी	दिल्ली	दिल्ली
81	महरौली	दिल्ली	दिल्ली
82	नेहरू प्लेस	दिल्ली	दिल्ली
83	पटपड़गंज	दिल्ली	दिल्ली
84	यमुना विहार	दिल्ली	दिल्ली
85	मार्गाओ	गोवा	पणजी
86	अमरेली	गुजरात	अहमदाबाद
87	आनंद	गुजरात	अहमदाबाद
88	बारडोली	गुजरात	सूरत
89	भरूच	गुजरात	अहमदाबाद
90	भावनगर	गुजरात	अहमदाबाद

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
91	भुज	गुजरात	अहमदाबाद
92	छोटा उदयपुर	गुजरात	अहमदाबाद
93	दाहोद	गुजरात	अहमदाबाद
94	गांधीनगर	गुजरात	अहमदाबाद
95	गोधरा	गुजरात	अहमदाबाद
96	जामनगर	गुजरात	अहमदाबाद
97	जूनागढ़	गुजरात	अहमदाबाद
98	खेड़ा	गुजरात	अहमदाबाद
99	मेहसाणा	गुजरात	अहमदाबाद
100	नवसारी	गुजरात	सूरत
101	पालनपुर	गुजरात	अहमदाबाद
102	पाटन	गुजरात	अहमदाबाद
103	पोरबंदर	गुजरात	अहमदाबाद
104	राजपीपला	गुजरात	सूरत
105	साबरकांठा	गुजरात	अहमदाबाद
106	सुरेंद्रनगर	गुजरात	अहमदाबाद
107	वलसाड	गुजरात	सूरत
108	वेरावल	गुजरात	अहमदाबाद
109	भिवानी महेंद्रगढ़	हरियाणा	चंडीगढ़
110	फरीदाबाद	हरियाणा	दिल्ली
111	हिसार	हरियाणा	चंडीगढ़
112	कैथल	हरियाणा	चंडीगढ़
113	करनाल	हरियाणा	चंडीगढ़

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
114	नारनौल	हरियाणा	दिल्ली
115	पानीपत	हरियाणा	चंडीगढ़
116	रोहतक	हरियाणा	दिल्ली
117	सिरसा	हरियाणा	चंडीगढ़
118	सोनीपत	हरियाणा	दिल्ली
119	यमुनानगर	हरियाणा	चंडीगढ़
120	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला
121	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	शिमला
122	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	शिमला
123	मंडी	हिमाचल प्रदेश	शिमला
124	पालमपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला
125	ऊना	हिमाचल प्रदेश	शिमला
126	कठुआ	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
127	राजौरी	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
128	ऊधमपुर	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
129	अनंतनाग	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
130	बारामुला	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
131	लेह	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
132	बोकारो	झारखंड	रांची
133	छैबाहा	झारखंड	रांची
134	देवघर	झारखंड	रांची
135	धनबाद	झारखंड	रांची
136	दुमका	झारखंड	रांची

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
137	गिरिडीह	झारखंड	रांची
138	गुमला	झारखंड	रांची
139	हजारीबाग	झारखंड	रांची
140	जमशेदपुर	झारखंड	रांची
141	झुमरी तलैया	झारखंड	रांची
142	खूंटी	झारखंड	रांची
143	मेदिनीनगर	झारखंड	रांची
144	साहिबगंज	झारखंड	रांची
145	शिमारिया	झारखंड	रांची
146	अंकोला	कर्नाटक	बंगलुरु
147	बागलकोट	कर्नाटक	बंगलुरु
148	बेलागवी	कर्नाटक	बंगलुरु
149	बेल्लारी	कर्नाटक	बंगलुरु
150	बीदर	कर्नाटक	बंगलुरु
151	चमराजनगर	कर्नाटक	बंगलुरु
152	चन्नापटना	कर्नाटक	बंगलुरु
153	चिक्कालापुर	कर्नाटक	बंगलुरु
154	चिकोडी	कर्नाटक	बंगलुरु
155	चित्रदुर्गा	कर्नाटक	बंगलुरु
156	दावंगरे	कर्नाटक	बंगलुरु
157	गाडग	कर्नाटक	बंगलुरु
158	हासन	कर्नाटक	बंगलुरु
159	जलाहल्ली	कर्नाटक	बंगलुरु

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
160	कोप्पल	कर्नाटक	बंगलुरु
161	मदुर	कर्नाटक	बंगलुरु
162	मैसूर	कर्नाटक	बंगलुरु
163	रायचूर	कर्नाटक	बंगलुरु
164	रॉबर्टसनपेट	कर्नाटक	बंगलुरु
165	शिवामोग्गा	कर्नाटक	बंगलुरु
166	तुमाकु	कर्नाटक	बंगलुरु
167	उडुपी	कर्नाटक	बंगलुरु
168	विजयपुर	कर्नाटक	बंगलुरु
169	चेंगनूर	केरल	कोचीन
170	कट्टपना	केरल	कोचीन
171	नेमारा	केरल	कोचीन
172	पालकक	केरल	कोचीन
173	कसारगोड	केरल	कोझिकोड
174	अट्टांगल	केरल	त्रिवेन्द्रम
175	पठानमथिट्टा	केरल	त्रिवेन्द्रम
176	कावराती	लक्षद्वीप	कोचीन
177	बालाघाट	मध्य प्रदेश	भोपाल
178	बैतूल	मध्य प्रदेश	भोपाल
179	छतरपुर	मध्य प्रदेश	भोपाल
180	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	भोपाल
181	दमोह	मध्य प्रदेश	भोपाल
182	देथा	मध्य प्रदेश	भोपाल

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
183	धार	मध्य प्रदेश	भोपाल
184	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	भोपाल
185	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	भोपाल
186	जबलपुर	मध्य प्रदेश	भोपाल
187	रतलाम	मध्य प्रदेश	भोपाल
188	रीवा	मध्य प्रदेश	भोपाल
189	सागर	मध्य प्रदेश	भोपाल
190	सतना	मध्य प्रदेश	भोपाल
191	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश	भोपाल
192	उज्जैन	मध्य प्रदेश	भोपाल
193	विदिशा	मध्य प्रदेश	भोपाल
194	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	मुंबई
195	भिवंडी	महाराष्ट्र	मुंबई
196	भुसावल	महाराष्ट्र	मुंबई
197	धुले	महाराष्ट्र	मुंबई
198	जलगांव	महाराष्ट्र	मुंबई
199	राजापुर	महाराष्ट्र	मुंबई
200	सांताक्रूज	महाराष्ट्र	मुंबई
201	सियोन	महाराष्ट्र	मुंबई
202	वाशी	महाराष्ट्र	मुंबई
203	विक्रोली	महाराष्ट्र	मुंबई
204	अहमदनगर	महाराष्ट्र	पुणे
205	बारामती	महाराष्ट्र	पुणे

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
206	बीड	महाराष्ट्र	पुणे
207	इचाकरणजी	महाराष्ट्र	पुणे
208	जालना	महाराष्ट्र	पुणे
209	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	पुणे
210	लातूर	महाराष्ट्र	पुणे
211	माधा	महाराष्ट्र	पुणे
212	नांदेड़	महाराष्ट्र	पुणे
213	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	पुणे
214	पंढरपुर	महाराष्ट्र	पुणे
215	परभणी	महाराष्ट्र	पुणे
216	पिंपरी चिंचवाड	महाराष्ट्र	पुणे
217	सांगली	महाराष्ट्र	पुणे
218	सतारा	महाराष्ट्र	पुणे
219	शिरूर	महाराष्ट्र	पुणे
220	श्रीरामपुर	महाराष्ट्र	पुणे
221	अकोला	महाराष्ट्र	नागपुर
222	अमरावती	महाराष्ट्र	नागपुर
223	भंडारा	महाराष्ट्र	नागपुर
224	बुलढाणा	महाराष्ट्र	नागपुर
225	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	नागपुर
226	गडचिरोली	महाराष्ट्र	नागपुर
227	हिंगोली	महाराष्ट्र	नागपुर
228	कतोल	महाराष्ट्र	नागपुर

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
229	वर्धा	महाराष्ट्र	नागपुर
230	यवतमाल	महाराष्ट्र	नागपुर
231	कचिंग	मणिपुर	गुवाहाटी
232	तुरा	मेघालय	गुवाहाटी
233	अस्का	ओड़िशा	भुबनेश्वर
234	बालासोर	ओड़िशा	भुबनेश्वर
235	बरगढ़	ओड़िशा	भुबनेश्वर
236	बारीपदा	ओड़िशा	भुबनेश्वर
237	बरहमपुर	ओड़िशा	भुबनेश्वर
238	भद्रक	ओड़िशा	भुबनेश्वर
239	भवानीपटना	ओड़िशा	भुबनेश्वर
240	बलांगीर	ओड़िशा	भुबनेश्वर
241	कटक	ओड़िशा	भुबनेश्वर
242	ढेंकानाल	ओड़िशा	भुबनेश्वर
243	जगतसिंहपुर	ओड़िशा	भुबनेश्वर
244	जाजपुर	ओड़िशा	भुबनेश्वर
245	केंद्रपाड़ा	ओड़िशा	भुबनेश्वर
246	कोंझर	ओड़िशा	भुबनेश्वर
247	कोरापुट	ओड़िशा	भुबनेश्वर
248	नबरंगपुर	ओड़िशा	भुबनेश्वर
249	फूलबनी	ओड़िशा	भुबनेश्वर
250	पुरी	ओड़िशा	भुबनेश्वर
251	राउरकेला	ओड़िशा	भुबनेश्वर

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
252	संबलपुर	ओड़िशा	भुबनेश्वर
253	करीकल	पुडुचेरी	तिरुचिरापल्ली
254	बासी पटाना	पंजाब	चंडीगढ़
255	भटिंडा	पंजाब	चंडीगढ़
256	फिरोजपुर	पंजाब	अमृतसर
257	मलरकोटला	पंजाब	चंडीगढ़
258	मोगा	पंजाब	जालंधर
259	पठानकोट	पंजाब	जालंधर
260	पटियाला	पंजाब	चंडीगढ़
261	फगवाड़ा	पंजाब	जालंधर
262	रोपड़	पंजाब	चंडीगढ़
263	अजमेर	राजस्थान	जयपुर
264	अलवर	राजस्थान	जयपुर
265	बांसवाड़ा	राजस्थान	जयपुर
266	बाड़मेर	राजस्थान	जयपुर
267	भरतपुर	राजस्थान	जयपुर
268	भीलवाड़ा	राजस्थान	जयपुर
269	बीकानेर	राजस्थान	जयपुर
270	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	जयपुर
271	चूरू	राजस्थान	जयपुर
272	दौसा	राजस्थान	जयपुर
273	हनुमानगढ़	राजस्थान	जयपुर
274	जैसलमेर	राजस्थान	जयपुर

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
275	झालावाड़	राजस्थान	जयपुर
276	झुंझुनूं	राजस्थान	जयपुर
277	कंक्रोली	राजस्थान	जयपुर
278	करौली-धौलापुर	राजस्थान	जयपुर
279	कोटा	राजस्थान	जयपुर
280	कोटपूतली	राजस्थान	जयपुर
281	नागौर	राजस्थान	जयपुर
282	पाली	राजस्थान	जयपुर
283	प्रतापगढ़	राजस्थान	जयपुर
284	सवाई माधोपुर	राजस्थान	जयपुर
285	सिरोही	राजस्थान	जयपुर
286	श्रीगंगानगर	राजस्थान	जयपुर
287	आरानी	तमिलनाडु	चैन्नई
288	चैन्नई जीपीओ	तमिलनाडु	चैन्नई
289	चिदंबरम	तमिलनाडु	चैन्नई
290	कुड्डालोर	तमिलनाडु	चैन्नई
291	धरमपुरी	तमिलनाडु	चैन्नई
292	कलकुलुइची	तमिलनाडु	चैन्नई
293	कांचीपुरम	तमिलनाडु	चैन्नई
294	कृष्णगिरी	तमिलनाडु	चैन्नई
295	रानीपेट	तमिलनाडु	चैन्नई
296	तिरुवल्लूर	तमिलनाडु	चैन्नई
297	तिरुवनमलाई	तमिलनाडु	चैन्नई

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
298	वेल्लोर	तमिलनाडु	चैन्नई
299	विलुप्पुरम	तमिलनाडु	चैन्नई
300	कुन्नूर	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
301	इरोड	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
302	रसीपुरम	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
303	सलेम	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
304	बोडिनेनूर	तमिलनाडु	मदुरई
305	देवकोट्टाई	तमिलनाडु	मदुरई
306	कोडाईरोड	तमिलनाडु	मदुरई
307	नागोरकोइल	तमिलनाडु	मदुरई
308	राजपालयम	तमिलनाडु	मदुरई
309	रामाथपुरम	तमिलनाडु	मदुरई
310	थुथुकुडी	तमिलनाडु	मदुरई
311	विरुधुनगर	तमिलनाडु	मदुरई
312	करूर	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
313	परमबालुर	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
314	सिरकली	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
315	थिरुथुरुपोंडी	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
316	आदिलाबाद	तेलंगाना	हैदराबाद
317	भोंगीर	तेलंगाना	हैदराबाद
318	कामरेड्डी	तेलंगाना	हैदराबाद
319	खम्मम	तेलंगाना	हैदराबाद
320	महबुबाबाद	तेलंगाना	हैदराबाद

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
321	मनचेरियल	तेलंगाना	हैदराबाद
322	मेदक	तेलंगाना	हैदराबाद
323	मेदचल	तेलंगाना	हैदराबाद
324	महबूनगर	तेलंगाना	हैदराबाद
325	नालगोंड	तेलंगाना	हैदराबाद
326	सिडडिपेट	तेलंगाना	हैदराबाद
327	विकराबाद	तेलंगाना	हैदराबाद
328	वानापारथी	तेलंगाना	हैदराबाद
329	वारंगल	तेलंगाना	हैदराबाद
330	धर्मानगर	त्रिपुरा	कोलकाता
331	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	बरेली
332	बदायूं	उत्तर प्रदेश	बरेली
333	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	बरेली
334	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	बरेली
335	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	बरेली
336	रामपुर	उत्तर प्रदेश	बरेली
337	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	बरेली
338	अछनेरा	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
339	आगरा	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
340	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
341	बागपत	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
342	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
343	हाथरस	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
344	मेरठ	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
345	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
346	नोएडा	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
347	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
348	वृंदावन	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
349	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
350	अंबेडकर नगर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
351	अमेठी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
352	अयोध्या	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
353	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
354	बहराइच	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
355	बलिया	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
356	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
357	बांदा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
358	भदोही	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
359	चुनार	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
360	देवरिया	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
361	फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
362	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
363	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
364	गोंडा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
365	गोशी (मऊ)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
366	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
367	हरदोई	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
368	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
369	झांसी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
370	खीरी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
371	महाराजगंज	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
372	मिश्रीख	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
373	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
374	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
375	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
376	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
377	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
378	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
379	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	देहरादून
380	काठगोदाम	उत्तराखंड	देहरादून
381	नैनीताल	उत्तराखंड	देहरादून
382	रुड़की	उत्तराखंड	देहरादून
383	रुद्रपुर	उत्तराखंड	देहरादून
384	श्रीनगर	उत्तराखंड	देहरादून
385	अलीपुरद्वार	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
386	आम्टा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
387	अरामबाग	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
388	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
389	अशोक नगर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
390	बालुरघाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
391	बनगांव	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
392	बांकुड़ा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
393	बरधामन	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
394	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
395	बशीरहाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
396	बेदोन गली	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
397	बिष्णुपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
398	बोलपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
399	कैनिंग रोड फेरी घाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
400	चिनसुराह	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
401	कूचबेहार	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
402	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
403	डॉयमंड हार्बर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
404	दमदम	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
405	घटल	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
406	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
407	जादवपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
408	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
409	झरग्राम	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
410	जियागंज	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
411	काकडवीप	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
412	कांथी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट कार्यालय
413	कटवा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
414	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
415	कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
416	मखदुमपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
417	उत्तर दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
418	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
419	रघुनाथगंज	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
420	रामपुरहाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
421	राणाघाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
422	समसी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
423	सेरमपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
424	तामलुक	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

अनुलग्नक - VIII

पासपोर्ट सेवा परियोजना के साथ एकीकृत विदेशों में मिशन/पोस्ट

क्रम सं.	मिशन/विदेश में पोस्ट	आधिकारिक 'गो लाइव' तिथि
1	यूनाइटेड किंगडम-लंदन	25 अक्तूबर 2018
2	यूनाइटेड किंगडम-बर्मिंघम	27 अक्तूबर 2018
3	यूनाइटेड किंगडम-एडिनबर्ग	30 अक्तूबर 2018
4	यूएसए-न्यूयॉर्क	21 नवम्बर 2018
5	यूएसए-वाशिंगटन डीसी	24 नवम्बर 2018
6	यूएसए-अटलांटा	25 नवम्बर 2018
7	यूएसए-सैन फ्रांसिस्को	27 नवम्बर 2018
8	यूएसए-ह्यूस्टन	28 नवम्बर 2018
9	यूएसए-शिकागो	30 नवम्बर 2019
10	सऊदी अरब-रियाद	20 फरवरी 2019
11	सऊदी अरब-जेद्दा	25 फरवरी 2019
12	ओमान-मस्कट	27 फरवरी 2019
13	कुवैत-कुवैत सिटी	12 मार्च 2019
14	बहरीन-मनामा	17 मार्च 2019
15	यूएई - दुबई	3 अप्रैल 2019
16	यूएई - अबू धाबी	4 अप्रैल 2019
17	कतर - दोहा	21 अप्रैल 2019
18	सिंगापुर - सिंगापुर	20 मई 2019
19	थाईलैंड - बैंकॉक	22 मई 2019
20	मलेशिया - कुआलालंपुर	30 मई 2019

क्रम सं.	मिशन/विदेश में पोस्ट	आधिकारिक 'गो लाइव' तिथि
21	कनाडा - टोरंटो	11 जून 2019
22	कनाडा - वैंकूवर	11 जून 2019
23	कनाडा - ओटावा	24 जून 2019
24	श्रीलंका - कोलंबो	19 मार्च 2019
25	ऑस्ट्रेलिया - सिडनी	24 जून 2019
26	ऑस्ट्रेलिया - मेलबर्न	7 जुलाई 2019
27	ऑस्ट्रेलिया - पर्थ	7 जुलाई 2019
28	ऑस्ट्रेलिया - कैनबरा	7 जुलाई 2019
29	चीन - बीजिंग	7 जुलाई 2019
30	स्पेन-मैड्रिड	5 अगस्त 2019
31	फ्रांस-पेरिस	5 अगस्त 2019
32	न्यूजीलैंड-वेलिंगटन	6 सितम्बर 2019
33	रवांडा-किगाली	19 सितम्बर 2019
34	श्रीलंका-कंडी	14 अक्तूबर 2019
35	रूसी संघ-मास्को	14 अक्तूबर 2019
36	चीन-हांगकांग	31 अक्तूबर 2019
37	मेक्सिको-मेक्सिको सिटी	31 अक्तूबर 2019
38	इटली-मिलान	6 नवम्बर 2019
39	रूसी संघ-व्लादिवोस्तोक	6 नवम्बर 2019
40	युगांडा-कंपाला	6 नवम्बर 2019
41	रूसी संघ-सेंट पीटर्सबर्ग	14 नवम्बर 2019
42	म्यांमार- यंगन	15 नवम्बर 2019
43	स्विट्जरलैंड-जिनेवा	21 नवम्बर 2019

क्रम सं.	मिशन/विदेश में पोस्ट	आधिकारिक 'गो लाइव' तिथि
44	श्रीलंका-हम्बनटोटा	25 नवम्बर 2019
45	नाइजीरिया-लागोस	29 नवम्बर 2019
46	वियतनाम-हो ची मिन्ह सिटी	6 दिसम्बर 2019
47	चीन-शंघाई ब्रुनेई	6 दिसम्बर 2019
48	दारुस्सलाम-बंदर सेरी बेगावान	9 दिसम्बर 2019
49	इंडोनेशिया-जकार्ता	13 दिसम्बर 2019
50	इंडोनेशिया-बाली	13 दिसम्बर 2019

अनुलग्नक - IX

मुख्यालय और विदेशों में मिशनों में 2019-20 के दौरान कैडर की संख्या (वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बजट किए गए पदों, गैर-संवर्ग के पदों और एमओआईए और पीओई से संवर्ग के पदों सहित है)

क्रम सं.	कैडर/पद	मुख्यालय में पद	मिशन में पद	कुल
1	ग्रेड I	5	28	33
2	ग्रेड II	6	40	46
3	ग्रेड III	38	138	176
4	ग्रेड IV	58	152	210
5	कनिष्ठ प्रशासन। ग्रेड/ सीनियर स्केल	117	246	363
6	(i) जूनियर स्केल	10	37	47
	(ii) परिवीक्षाधीन रिजर्व	62		62
	(iii) छुट्टी रिजर्व	15		15
	(iv) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	19		19
	(v) प्रशिक्षण रिजर्व	7		7
	उप कुल I	**337**	**641**	**978**
	आईएफएस (बी)			
7	(i) ग्रेड I	118	125	243
	(ii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	6		6
8	(i) एकीकृत ग्रेड II और III	359	241	600
	(ii) छुट्टी रिजर्व	30		30
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	16		16
	(iv) प्रशिक्षण रिजर्व	25		25

क्रम सं.	कैडर/पद	मुख्यालय में पद	मिशन में पद	कुल
9	(i) ग्रेड IV	214	545	759
	(ii) छुट्टी रिजर्व	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	54		54
10	(i) ग्रेड V/VI	173	84	257
	(ii) छुट्टी रिजर्व	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	14		14
11	(i) साईफर कैडर का ग्रेड II	47	47	94
	(ii) छुट्टी रिजर्व	5		5
12	(i) स्टेनोग्राफर कैडर	383	550	933
	(ii) छुट्टी रिजर्व	47		47
	(iii) प्रशिक्षण रिजर्व (हिंदी)	10		10
	(iv) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	12		12
13	दुभाषिया कैडर	9	26	35
14	एलएंडटी कैडर	20	3	23
	उप कुल II	**1662**	**1621**	**3283**
	कुलयोग (उपयोग I+II)	**1999**	**2262**	**4261**

अनुलग्नक-X

विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त आईएफएस अधिकारियों की संख्या: (02.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	भाषा	अधिकारियों की संख्या
1	अरबी	118
2	बहासा इंडोनेशिया	10
3	बहासा मलय	03
4	बर्मी	08
5	चीनी	96
6	चेक	02
7	फ्रांसीसी	108
8	जर्मन	35
9	हिब्रू	08
10	इतालवी	01
11	जापानी	31
12	कजाख	01
13	स्वाहिली	02

क्रम सं.	भाषा	अधिकारियों की संख्या
14	कोरियाई	09
15	नेपाली	01
16	पश्तो	02
17	फारसी	23
18	पोलिश	03
19	पुर्तगाली	27
20	रूसी	113
21	सिंहली	10
22	स्पेनिश	98
23	तुर्की	07
24	यूक्रेनी	01
25	वियतनामी	03
	कुल	**720**

अनुलग्नक-XI

एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया

क्रम सं.	देश	अवधि	टिप्पणियां
1.	चीन	शांति और समृद्धि के लिए घनिष्ठ विकास सामरिक साझेदारी और सहकारी साझेदारी	2014 2005 से 2014 तक
2	जापान	विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी	2014
3	दक्षिण कोरिया	विशेष सामरिक साझेदारी	2015
4	इंडोनेशिया	व्यापक सामरिक साझेदारी	2015
5	वियतनाम	व्यापक सामरिक साझेदारी	2007 से सामरिक साझेदारी, 2016 में व्यापक सामरिक साझेदारी में संवर्धन
6	ऑस्ट्रेलिया	सामरिक साझेदारी	2009
7	मलेशिया	सामरिक साझेदारी	2010
8	अफ़गानिस्तान	सामरिक साझेदारी	2011
9	सिंगापुर	सामरिक साझेदारी	2015
10	मंगोलिया	सामरिक साझेदारी	2015
11	आसियान	सामरिक साझेदारी	नई दिल्ली में आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2012 में भारत-आसियान संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप

क्रम सं.	देश	अवधि	टिप्पणियां
1	अमेरिका	वैश्विक महत्व की सामरिक साझेदारी	2014
2	फ्रांस	सामरिक साझेदारी	1998
3	जर्मनी	सामरिक साझेदारी	2000

क्रम सं.	देश	अवधि	टिप्पणियां
4	ब्रिटेन	सामरिक साझेदारी	2004
5	कनाडा	सामरिक साझेदारी	2015
6	यूरोपीय संघ	सामरिक साझेदारी	2004

खाड़ी

क्रम सं.	देश	अवधि	टिप्पणियां
1.	सऊदी अरब	सामरिक साझेदारी परिषद समझौता	अक्तूबर 2019
2	संयुक्त अरब अमीरात	व्यापक सामरिक साझेदारी	2018
3	ओमान	सामरिक साझेदारी	2008
4	इज़राइल	सामरिक साझेदारी	2017

मध्य एशिया

क्रम सं.	देश	अवधि	टिप्पणियां
1.	रूस	विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी	2000 के बाद से, हमारी सामरिक भागीदारी थी और 2020 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति से इसका संवर्धन किया गया
2	कज़ाकस्तान	सामरिक साझेदारी	2009
3	उज़्बेकिस्तान	दीर्घावधि और सामरिक साझेदारी	2011
4	ताजिकिस्तान	दीर्घकालिक सामरिक साझेदारी	2012

एलएसी

क्रम सं.	देश	अवधि	टिप्पणियां
1.	ब्राज़ील	सामरिक साझेदारी	2006
2	अर्जेंटीना	सामरिक साझेदारी	2019
3	मेक्सिको	विशेषाधिकार प्राप्त भागीदारी	2007

अफ्रीका

क्रम सं.	देश	अवधि	टिप्पणियां
1	दक्षिण अफ़्रीका	सामरिक साझेदारी	1996
2	नाइजीरिया	सामरिक साझेदारी	2007
3	रवांडा	सामरिक साझेदारी	2017
4	अफ्रीका (सभी 54 राज्यों को कवर)	सामरिक सहयोग के लिए भारत अफ्रीका संरचना	2015

टिप्पणियाँ

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर भारत और फिनलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की 70 वीं वर्षगांठ और महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर अल्लोट्रिया पार्क, हेलसिंकी में महात्मा गांधी की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण करते हुए।

विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट की डिजिटल कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट: www.mea.gov.in पर देखी जा सकती है। इस वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) देहरादून के सहयोग से एक ऑडियो बुक (हिंदी में) के रूप में भी प्रकाशित किया गया है।

Designed and Produced by
creativEdge
ce@aravalifoundation.in
www.creativedge.in